सर्वाधिकार सुर्राज्ञत

प्रथम सस्करण १६५३ द्वितीय सस्करण १६५५ त्रितीय सस्करण १६५७ चतुर्थ सस्करण १६५६

श्रध्याय १

भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ

श्रयंशास्त्र को श्रध्ययन की सुविधा के लिए दो मागों में बाँटा गया है जिनमें से एक माग 'सैंद्रान्तिक श्रयंशास्त्र' (Theory of economics) श्रीर दूसरा माग 'व्यवहारिक श्रयंशास्त्र' (Applied economics) कहा जाता है। सैद्रान्तिक श्रयंशास्त्र में हम कुछ ऐसे श्राधारभूत सिद्रान्तों का श्रध्ययन करते हैं जो श्रावश्यकताश्रों (wants) की पूर्ति के सम्बन्ध में मनुष्य के व्यवहार की विवेचना करते हैं जब कि उद्देश्य दिये हो श्रीर उनकी पूर्ति के साधन श्रप्यांत हों तथा उनके विभिन्न प्रयोग हो। श्रयंशास्त्र में हन श्राधारभूत सिद्रान्तों को हम उत्पादन, उपभोग विनिमय श्रीर वितरण के श्रन्तर्गत श्रध्ययन करते हैं। सीमात उपयोगिता के हास का नियम, उत्पादन के नियम, लगान का सिद्रान्त श्रीर रोजगार तथा व्यवसाय चक के सिद्रान्त श्रयंशास्त्र के हन श्राधारभूत सिद्रान्तों के ही उदाहरण हैं। हम सिद्रान्तिक श्रयंशास्त्र का श्रव्ययन या तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं या विश्लेषणात्मक दृष्टि से। यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से श्रध्ययन किया जाय तो इसका रूप 'श्रयंशास्त्र की विचारधारा का इतिहास' जैसा हो जाता है श्रीर दूसरी स्थिति में विश्लेषणात्मक श्रयंशास्त्र भी कहते हैं। Economics) जैसा हो जाता है जिसे संज्ञेप में केवल श्रयंशास्त्र भी कहते हैं।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र सेद्वान्तिक अर्थशास्त्र से बिल्कुल भिन्न है। इसमें उन समस्यात्रों का अध्ययन किया जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयक्तों के बीच पैदा हो जाती हैं, जैसे कृषि और उद्योग की समस्यायें, उत्पादन, आयात और निर्यात, बैंक और मुद्रा व्यवस्था, आर्थिक नियोजन, आदि। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र की मॉति, व्यवहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण् से भी कर सकते हैं और ऐसी स्थित में अर्थशास्त्र 'आर्थिक इतिहास', (Economic History) का रूप धारण कर लेता है। यदि विश्लेषण की दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो यह 'वर्तमान आर्थिक समस्याओं के अध्ययन' का रूप ले लेता है।

सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति वास्तव में मनुष्य के व्यवहार के कुछ आधारमूत सिद्धान्तों और जनता की आर्थिक स्थिति के आवार पर होती है। उदा-हरण के लिये, प्राचीन अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो पर हगलैंड की १८ वीं शताब्दी की परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पदा। इसके बाद जनता वी श्राधिक रिगति में श्रानेक परिवर्तन हुए श्रीर उन परिवर्तनों के पलरवर प्रशाविक विद्यानों में भी संशोधन परिवर्दन होते गये। जैसे ही नयी परिस्थितिकों उत्पाद हैं उनकी न्यारपा करने के लिये या तो पहले के श्राधिक सिद्यान्ती था विस्तार विया गया वा नये सिद्धान्ती का जन्म हुशा। हम वर्तमान भी श्राधिक ममस्यात्रा गा श्रप्यान करने के लिये या त्राधिक हतिहास लग्नने के लिए श्र्यंशान्त व सिद्धान्ती मा उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तक और न्याहा कि गर्थशान्त में परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है।

भारतीय छार्यशार्त्र—भारतीय य्ययाम्य धाराम्य प्रमाण प्राप्त सार्यां स्वार्त्त वर्तमान रामय की विभिन्न पार्थित समकारा गा प्राप्ययन किया जाता है, जैसे, जमकरी, भूमिन्न गा, मैनेनिन एनेन्सा मनानी, ह यादि य्रोर साथ ही उनका उत्पत्ति कारणों का भी किन्न । प्राप्त जाता है। इस प्रम् में भारतीय प्रार्थाास्त्र का प्रत्ययन विश्लेषणा मा ही जाना है। इसमें यह प्राप्त किया जाता है कि वर्तमान छार्थिक पनिक्षित्रों हा सही सरा जिए अन्तृत किया जाय, विभिन्न घटनायों के कारणों का समकाया जाय प्रीर यह भी नताया नाम किमय की समस्यायों के उत्त्यत होने की सम्भावना थी, यह प्या नहीं की सम्भावना स्वा की समस्यायों का छह्ययन करने प्रीर हमस्यायों का छह्ययन करने प्रीर हमस्यायों का छह्ययन करने प्रीर हमस्यायों का छह्ययन करने प्रीर हमकी मार्या प्रवृत्तियों का प्रवाता सेते हैं। यदि अर्थशास्त्र के सिद्यात । भन्न-भिन्न हों हम जिन परिलामों पर पहुँचते हैं वह भी अवस्य भिन्न होंगे। इसलिये भागतीय अर्थशास्त्र का प्रवासन बहुत कुछ हमारे सेद्यां के अर्थशास्त्र के कान पर निर्भर रस्ता है।

जैसा कि इस पहले यह जुके हैं भारत में विभिन्न श्रार्थिक समस्पाश्रों के पेतिहासिक विकास का प्रध्ययन 'मारत का श्रार्थिक इतिहास' कहा जाता है। श्रार्थिक इतिहास में घटनाने नमानुसार लियी जाती हैं। भारतीय श्रार्थशास की श्रानेक पाठ्य पुरतकों में "भारत का श्रार्थिक इतिहास" श्रीर "भारतीय श्रार्थशास" को साथ-साथ दिया गया है श्रीर पाटक को इन दोनों श्र्यों का साथ-साथ श्रद्धयन करना पड़ता है। इससे पाटक के लिये शावश्यक श्रीर सम्मित्वत समन्याश्रों को समझना श्रीर वर्तमान समस्याश्रों पर प्यान ने न्द्रित करना फाइन हो जाता है। यह बात निस्तन्देह सही है कि भारत के श्रार्थिक इतिहास के श्रद्धयन ने श्राधार पर ही वर्तमान श्रार्थिक समस्याश्रों का सही श्रद्धयन किया जा सकता है, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि यदि हम भारत ने श्रार्थिय इतिहास श्रीर मारतीय

श्रर्थशास्त्र को एक मे मिला दे तो वर्तमान श्राधिक समस्याएँ, जिन पर पाठ्क को ध्यान देना श्रायश्यक है, भारत के श्राधिक हतिहास के विस्तृत विवेचन में लुप्त हो जाती है। इसलिये इस पुस्तक में यह प्रयत्न किया गया है कि भारतीय श्रथशास्त्र की समस्याएँ श्राधिक इतिहास के विस्तृत वर्णन में खो न जायँ। जहाँ श्रावश्यक प्रतीत हुश्रा है वहाँ तुलनात्मक श्रध्ययन के लिये श्राधिक हतिहास का कुछ विश्तृत वर्णन किया गया है। परन्तु विशेष जोर मारत की वर्तमान श्राधिक समस्याश्रों के विवरणात्मक श्रोर विश्लेषणात्मक श्रध्ययन प्रदिया गया है।

अन्य परिभाषाये—पूर्व लिखित परिभाषा के अनुसार भारतीय अर्थशास्त्र भारत को वर्तमान आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। परन्तु भारतीय अर्थशास्त्र की इसके अतिरिक्त तीन और परिभाषाये दी गयी हैं:—

- (१) भारत की आर्थिक विचारधारा के विकास के अध्ययन को भारतीय अर्थशास्त्र कहा गया है। प्राचीन भारत में मैहान्तिक अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया था। भारतीय आर्थिक विचारधारा पश्चिमी आर्थिक विचारधारा के साथ-साथ विकास नहीं कर सभी है। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के चेत्र में भारत ने अवश्य कुछ योगदान किया है। यदि इस पर विचार न किया जाय तो भारतीय आर्थिक विचारधारा पूर्णत्या प्राचीन भारत की देन है। यदि यह मान भी लिया जाय कि भारतीय आर्थिक विचारधारा आधुनिक सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र के साथ विकास कर सकी है तब भी हम उसे भारतीय अर्थशास्त्र का नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक अर्थ है जब कि आर्थिक विचारधारा का इतिहास, चोहे वह भारतीय हो या यूरो-पीय, 'सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र' के अन्तर्गत आता है।
- (२) यह कहा गया है कि भारत की सामाजिक श्रीर घामिक स्थिति एक विशेष प्रकार की है, उसकी गठन श्रीर उसमें निहित विचारघारा श्रन्य देशों से भिन्न है इसिलये भारतीय परिस्थितियों के श्रनुकृत्त हमे बिल्कुत्त ही नये प्रकार के श्रार्थिक सिद्धान्तों का सुजन करना चाहिए श्रीर उसे 'भारतीय श्रथंशास्त्र' कहना चाहिए। न्यायाधीश रानाडे ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्थिति पश्चिमी देशों से नितान्त भिन्न है, प्रतियोगिता (Competition) से कहीं श्रिषिक प्रभावशाली यहाँ के रीति-रिवान श्रीर राज्य के नियम हैं, साथ ही किसी सममौते की श्रपेक्षा समाज में सम्मान श्रिषक प्रभाव रखता है। यहाँ न पूँजी गतिशील है श्रीर न श्रम श्रीर न इनमे इतना उत्साह (enterprising) श्रीर बुद्धि ही है कि गतिशील वनें। मजदूरी श्रीर लाम भी निश्चत है, जनसख्या

श्रपने नियम के श्रनुसार उढती जाती है परन्तु जीमारियां ग्रीर ग्रकाल से उसमें कमी भी होती रहती है, उत्पादन वी माधा प्राय स्थिर है, यदि एक वर्ष फसल श्चच्छी हो गयी तो वह अगले वर्ष के श्रनिश्चित मोष्ठम से होने वाली हानि की पूर्ति का साधन बन जाती है। इसके ग्राधार पर न्यायाधीश रानाढे इस परिणाम पर पहुँचे कि श्रादुनिक श्रर्यशास्त्र के मिद्धान्तों में जिन वातों को निश्चित श्राधार मान लिया गया है वह भारत म लागू ही नहीं होती बल्कि वह वास्तव में गलत दिशा की श्रोर ले जाती है। इससे कुछ लोग इस परिगाम पर पहुँचे कि भारत की ग्रार्थिक स्थिति को समझने के लिये नये ग्रार्थिक सिदानती की ग्रावश्यकता है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। कोई भी श्रार्थिक सिद्धान्त, चाहे वद पश्चिमी देशों में विकसित हुआ हो या पूर्वी देशों में, ज्यापक रूप में सारे विश्व पर लागू होता है। यार्थिक सिदान्त मनुष्य के स्वमाव पर ग्राधारित होता है श्रीर मनुष्य का स्वभाव सर्वत्र समान होता है। यदि श्रार्थिक सिद्वान्त का उचित निरूपण किया गया है तो वह सर्वत्र लागू होगा । परन्तु यह मानना पढ़ेगा कि आर्थिक विद्यान्त स्थिर विद्यान्त नहीं होता और न वह अपरिवर्तनशील ही होता है। यदि श्रार्यिक स्थिति में परिवर्तन हुया तो श्रार्थिक चिद्रान्त में भी परिवर्तन होगा। इगर्लंड में पाचीन सेटान्तिक ग्रर्थशास्त्र का जो निकास हुग्रा वह इंगर्लंड की उस समय की आर्थिक हिपनियों पर आधारित था। वह यह मान्य नीति (Laissez faire) श्रौर स्नतन न्यापार (Free trade) के सिद्धान्तों पर श्राघारित या। परन्तु बाद में जब विशेष रूप में युरोपीय देशों म यह पता चला कि स्वतन्न न्यापार आर्थिक परिस्थिति के प्रतिकृत है तो फीड्रिन लिस्ट तथा अन्य अर्थ-शास्त्रियों की त्रालोचना के ब्राघार पर स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त में ब्रावश्यक सशोधन किया गया श्रोर कम विकछित देशों के सरहरण के लिये तटकरों (Tariffs) तथा अन्य उपायों का महत्व स्वीकार किया गया । सोनियत सच की परिस्थितियों में परिवर्तन के साय समाजवाद श्रोर ग्रार्थिक नियोजन के सिद्धान्तों मे भी परि-वर्तन होता गया। इघर कुछ वर्षों से पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के छार्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए चेत्रों की अगर्यिक समस्यात्रों के कारण श्राधिक सिद्धान्तों में परिवर्तन-परिवर्झन हो रहा है। भारत मे श्रान्यात्मिक विचारघारा से प्रमावित 'श्रावश्यकता' का एक विल्कुल नया सिद्धान्त निकसित हो रहा है निसे 'श्रावश्य-कता रहित होने का सिद्धान्त' (Theory ef wantlessness) कहा जाता है। यह पश्चिम के छावश्यकता के सिद्रान्तों से नितान्त भिन्न है। यह समव है कि विभिन्न देशों की बदलती परिहियतियों से प्रभावित हाकर, जिनमें भारत भी समिलित है, भविष्य में अर्थशास्त्र के सिदान्तों मे और भी सशोधन हो । परन्त

जातिवाद, सयुक्त-परिवार की प्रया, अम और पृजी में गतिशीलता का श्रमाव, इत्यादि इस बात को सिद नहीं करते कि इस देश के लिये नये प्रकार के श्रार्थिक सिदान्तों की श्रावश्यकता है। माँग श्रोर पूर्ति का सिदान्त जितना भारत में लागू होता है उतना ही श्रन्य देशों में भी लागू होता है। इसलिये हमारी भारत की भिन्न परिस्थितियों के कारण नये प्रकार के श्रार्थिक सिदान्तों का विकास करने की माँग उचित नहीं है, साथ ही इन विशेष सिदान्तों श्रीर नियमों को जो केवल मारत में लागू होंगे 'मारतीय श्रर्थशास्त्र' का नाम देना न्यायसगत नहीं है।

(३) यह भी कहा गया है कि यदि उपभोग, उत्पादन, विनिमय स्नौर वितरण के स्नार्थिक सिद्धान्तों का विवेचन भारतीय उदाहरणों के साथ किया गया हो तो उसे भारतीय स्नर्थशास्त्र कहा जाना चाहिये। किसी भी सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समकाने के लिये निश्चय ही कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है परन्तु इससे ही वह 'भारतीय स्नर्थशास्त्र' नहीं हो जाता। यदि कोई पाट्य पुस्तक स्नग्नेज विद्यार्थियों के लिये लिखी जाय तो यह स्वाभाविक ही है कि 'उसमें स्नमेजी या हगलैंड के उदार हरण दिये जायेंगे। इसी प्रकार यदि कोई पाट्य पुस्तक भारतीय विद्यार्थियों के लिये लिखी जाय तो उसमें भारत के उदाहरण दिये जायेंगे। परन्तु इतने से ही वह 'स्नमेजी स्नर्थशास्त्र', या 'भारतीय स्नर्थशास्त्र' नहीं बन जाते। इन परिरिधतियों में वह केवल सैद्धान्तिक स्नर्थशास्त्र रहता है चाहे उसमें किसी भी देश के उदाहरण दिये गये हों।

इससे स्पष्ट है कि भारतीय अर्थशास्त्र भारत की वर्तमान आर्थिक समस्याओं का ठीक वैसा हो अध्ययन है जैसा अन्य देशों में किया जाता है। वर्तमान आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अन्य देशों की माँति ही भारत में भी हम देश की समस्याओं पर उन आर्थिक सिद्धान्तों को लागू करते हैं जो सर्वत्र सत्य सिद्ध हो चुके हैं या उन्हें सभी स्वीकार करते हैं। इसलिये अर्थशास्त्र के आर्थिक सिद्धान्तों को भारत की आर्थिक स्थित पर लागू कर हम जिन परिणामों पर पहुँचते हैं तथा जिन प्रवृत्तियों का पता लगाते हैं उनको भारतीय अर्थशास्त्र' कहते हैं तो यह नितान्त न्यायसगत है।

भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता

(१) यदि इम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सही सही समम्मना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इम भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करें। इसके अध्य-यन से इम यह जान सकते हैं कि इम प्रगति कर रहे हैं या नहीं, यदि कर रहे हैं तो किस सीमा तक और यदि प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण क्या हैं। (२) भारतीय श्रयंशास्त्र के श्रध्ययन से इम श्रपने देश जी ग्रन्य देशों के साथ बुलना कर सकते हैं ग्रोर इस प्रकार की बुलना से यह जान सकते हैं कि इम किम प्रकार तथा किस दिशा में सिक्य होकर अपनी किमयों को दूर कर सकते हैं ग्रीर श्रायिक उर्जान के ग्रमीष्ट स्तर की प्राप्त कर सकते हैं। (३) भारतीय ग्रयंशास्त्र का श्रध्ययन कर के ही इस भिविष्य के लिये ग्रपनी नीति निष्धारित कर सकते हैं। पद्म-वर्षीय योजना तैयार करने में ग्रोर योजनाओं को प्रमुखता देने में योजना श्रायोग को भारतीय ग्रयंशास्त्र के ग्रथ्ययन पर ही श्रपने निर्णाया को श्रायारित करना पड़ा। भारत के ग्रायिक प्रमान में को श्रुद्धां रह गरी है तथा श्रायोग ने ग्रायिक प्रगति की वाछित गिन से उन्हें दूर कर देने के सुकाय भारताय श्रयंशास्त्र के श्रथ्ययन के ग्राधार पर हा दिये हैं।

अध्याय २

1

प्राकृतिक साध**न**

भौगोलिक स्थिति

किसी देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति तथा उनके व्यवसायों पर उस देश की भौगोलिक स्थिति, भूमि की उपजाक शक्ति, वर्षा, जलवायु ओर उसकी बनस्पति तथा उसके वन्य एवम् पालत् पशुओं का विशेष प्रमाव पड़ता है। इसिलिये भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है।

भौतिक विशेषताएँ—भारतीय सब का च्रेजिकल १२६६६४० वर्ग मील है। उत्तर से दिन्न तक इस देश की लम्बाई २००० मील छीर पूर्व से पिश्चम तक १७०० मील है। इसकी भौतिक सीमा ८२०० मील छीर सामुद्रिक सीमा ३५०० मील है। कर्क रेखा इसकी बीचों-बीच से दो मागों में बॉटती है। उत्तरी माग शीतोष्ण किटबन्ध में छीर दिन्नणी उल्ला किटब्ध में स्थित है। जम्मू और काश्मीर तथा अन्द्रुवर १६५३ में निर्मित झॉध राज्य सिहत मारत सब में राज्यों के पुनर्स्वुवन के पूर्व २६ राज्य थे। १ नवम्बर १६५६ में राज्यों का पुनर्स्वाटन होने के पक्षात् अब भारत सब में १४ राज्य यथा ऑध प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई, मैस्र, उझीसा, पजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी चङ्गाल, जम्मू और काश्मीर, तथा केन्द्रीय प्रशासन के दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, अडमन-निकोबार द्वीप समूह और लेकडिव, मिनिकाय, अमिन्दिवी द्वीप समूह नामक ६ प्रदेश हैं।

भारत उत्तर में हिमालय, उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में पर्वतश्रेणियो, दिल्ण में बगाल की खाडी श्रीर हिन्द महासागर श्रीर पश्चिम में श्ररव सागर द्वारा घरा हुश्रा है। भारत को चार विभिन्न भीगोलिक भागों में बॉटा जा सकता है (१) हिमालय, (२) गङ्गा का मैदान, (३) दिल्लाणी पटार, (४) तटवर्ती प्रदेश। हिमालय की श्रेणियाँ १५०० मील की लम्बाई में श्रीर १५० मील से लगा कर २५० मील तक की चौड़ाई में फैली हुई हैं। हिमालय उत्तर की वर्फीली वायु से तथा उत्तरीय विदेशियों के श्राक्रमण से भारत की सदा से रक्षा करता श्राया है। इसके कारण उत्तरीय सीमा के मार्गो से व्यापार में भी वाधा पहुँची है। मान-स्न को रोक कर भारत के उत्तरीय भाग की प्रचुर वर्षा का साधन हिमालय ही रहा है। मारत की श्रनेकों नदियों का उद्गम हसी भाग से हुश्रा है। यहाँ बहु- मूल्य वन पाये जाते हैं जिनका पूर्ण प्रयोग होना सभी वाकी है। इसका श्राध-काश भाग काश्मीर स्त्रीर जम्मू की घाटियों तथा पूर्वीय चाय क चेत्रों को छोड़ कर खेती के सायोग्य है।

गद्धा का मैदान पूर्व से पश्चिम की छोर लगभग १५०० मील लम्बा स्वीर उत्तर से दिल्ला की छोर १५० से लगाकर २५० मील तक चीड़ा है। यहाँ खनेको निद्याँ छपनी महायक निदयों के साथ महती है। यहाँ छी भूमि महुत उपनाक है छोर इसीलिए यहाँ की लनसंरया का घनत्व भी सनमे अधिक है। रेश के महुत बड़े-नड़े नगर इसी माग में स्थित है।

पठारी भाग को विष्याचल पर्वत शेणी के दक्षिण में स्थित है, दो भागा में बॉटा जा सकता है। (अ) मध्य भारतीय पठार और (ब) दिनगी पटार !

पटारी माग गद्धा के मेटान के निपरीत श्रनेकों पर्यंत के शियों में भरा हुआ है। इनकी ऊँचाई १५०० से ४४०० फोट तक है। उस माग के टोनों श्रोण पूर्वीय श्रोर पिश्चमीय घाट की पर्वत थे शिया है। पठार स्यय पर्गरीला जीर ऊँचानीचा है। इसका विस्तार पूरे दिल्लिया की पटा दियों तक है जो कटी-पटी पर ४००० फीट ऊँची हैं जैसे नील घाटी श्रीर कार्टमाम की पटा दियों। इस पटार से टोकर नर्मदा श्रीर तासी निदयों बहती हैं जो श्रद्र सागर में गिरती हैं जीर महानती, कृष्णा तथा कावेरी जो बगाल की खादी में गिरती हैं। बनो भी इस प्रदेश में कमी है पर खिनज पटार्थ पयास माना में मिलते हैं। समुद्री तट कटे हुए नहीं है। इसिलये स्वामाविक बन्दरगाह केवल विजगायहम, कोचीन श्रीर कालीकट हैं। पूर्वी श्रीर पश्चिमी तटों की भूमि उपजाक है। वहाँ पर्यास बर्गा होती है तथा चावल चाय श्रीर कहवा पटा होता है।

जलवायु घोर वर्षा—मारत की जलवायु मानत्नी तथा उप्ण प्रदेशीय है। यहाँ की तीन प्रमुख ऋतुर्ये निम्न हें (१) मार्च के आरम्भ ने जून के अन्त तक गमी की ऋतु, (२) जून के अत से चितम्बर के आत तक वर्षा ऋतु और (३) अवदूबर से फरवरी के अत तक शीत ऋतु । अभैल और मई के महीनों में सूर्य की किरणें चीची लम्बवत परती हैं और ये महीने देश ने चब से अबिक गर्म होते हैं। उत्तरी-पूर्वी भारत में मई के महीने का श्रीचत तापकम १००° फैरनहाइट होता है और गगा के डेल्टा में लगभग प्रभू फें। निन्हीं स्थानों पर तापकम ११७° ११८० फें। हो जाता है। जून के मध्य में मानस्नी हवायें चलने लगती है और विजली की चमक के साथ मूसलाघार वर्षा होती है। श्रीधकाश वर्षा दित्तिणी-पश्चिमी मानस्न के कारण होती है। उत्तरी-पूर्वीय मानस्न द्रावनकोर कोचीन तथा मद्रास के कुछ भागों में वर्षा का कारण होती है। श्रीवकाल में

जनवरी के महीने में उत्तर से दिल्णा के भागों में तापकम बदलता रहता है।

वर्षों के दृष्टिकोग से देश को चार मुख्य भागों में बॉटा जा सकता है। दिन गरम और राते उंडी होती हैं। (१) श्रात्यधिक वर्षा वाला भाग जहाँ हु॰" के लगमग वर्षा होती है जैसे श्रासाम, बगाल, उत्तरी बिहार, प्रायद्वीप का पश्चिमी तट ग्रीर कुछ पूर्वीय तट के भाग, (२) साधारण वर्षा वाले माग जहाँ ४०" से लगाकर ५०" तक वर्षा होती है जैसे उद्दीसा, दिश्वणी विद्वार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश श्रीर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ; (३) बहुत कम वर्षा वाले माग जहाँ २०" से ४०" तक वर्षा होती है जैसे मद्राप, मैसर, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान और पूर्वीय पजाब और (४) सूखे रेगिस्तानी भाग जहाँ २०" से भी कम वर्षा होती है जैसे राजपूताना का रेगिस्तान, पश्चिमी काश्मीर स्त्रीर पनात्र के माग। मारतवर्ष में वर्षा की मुख्य विशेषता उसकी भ्रमिश्चितता है। यह ठीक ही कहा गया है कि भारतीय कृषि 'वर्षा का जुम्रा' है। यदि वर्षा समय से पर्याप्त हो गई तब तो फसल अच्छी होगी, किसान प्रसन्न होंगे श्रीर श्रन्न पर्याप्त होगा। पर यदि वर्षा देर से हुई श्रीर श्रनियमित रूप से हुई, कहीं अत्यधिक और कहीं अतिन्यून, तो स्वा पहेगा बाढ आयेगी और लोगों

भूमि-भारत की भूमि को निम्न भागों मे बाटा गया है (1) कॉप मिट्टी की कठिनाइयों की सीमा न रहेगी। (11) कालां मिट्टी (111) लाल मिट्टी जिसमें लाल चिकनी श्रीर पीली मिट्टी मिली होती है (1V) लेटेराइट मिटी (V) रेतीली मिटी (VI) लवणयुक्त श्रीर चारिल मिटी श्रीर (vii) जीया मिट्टी। इनमे से प्रथम चार तो सुख्य है श्रीर दूसरी चार गीया जो कि कहीं-कहीं पाई जाती है। "प्रथम तीन प्रकार की मिहियों में पोटाश श्रीर चूना पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है पर उनमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन श्रीर स्मुस बहुत कम हैं। लेटेराइट मिट्टी में सूमल की मात्रा पर्याप्त है पर अन्य रसा-यनिक गुण कम हैं। कॉप मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ श्रीर बड़ी श्रासानी में काम में लाई जाने योग्व है। यह मिट्टी सम्पूर्ण सिंघ, गंगा के मैदान में तथा पूर्वी श्रीर पश्चिमी तट प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी जिसमें नमी को रोक रखने की शक्ति अपार होती है ख्रीर जो बहुत चिपचिषी होती है दिख्णी पठार के पश्चिमी भाग में पाई जाती है श्रीर लाल मिट्टी इसी भाग के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मध्यभारत, श्रासाम, पूर्वी-पश्चिमी घाट के किनारे पाई जाती हैं । जल ध्रीर विद्युत के साधन — चूंकि भारत में श्रनेक निद्या श्रीर

मरने हैं इसिलये यहाँ पानी श्रीर विद्युत के साधनों की कमी नहीं है परन्तु खेद है कि इन साधनों का श्रमी तक उचित रीति से उपयोग नहीं किया जा सका है। प्रति वर्ष भारत की नदियों में लगभग एक ग्ररा ३५ करोड ६० लाख एकर फुट पानी वह जाता है परन्तु इसमें से रेपल ७ मरोए ६० लाग एकए छट या मुल का केवल ५ ६ प्रतिशत विचार के काम में लाया जाता है। "मनुमान लगा,या गया है कि ४५ करोट एकड़ फुट पानी सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। संमव है प्रथम पचरर्पाय योजना की जानी योजनाएं। को प्रायान्त्रित कर देने से अधिक पानी का उपयोग किया जा चके श्रीर तब विजली का भी प्रधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सबेगा। इसके प्रतिरिक्त सिचाई की दृष्ट छोटी गोगनायें भी है जिनसे तालायों, सुत्रों त्रार नहरों का पानी भी सिचार के राम में लाया जा सकेगा। वर्तमाग समय मे ५ परोइ ८५ लाग एकट भूमि पर छिचाई होती है, जिसमें से २ ररोट १० लाख एकड़ भूमि नहरी द्वारा सीची जाती है, १ प्ररोड़ ५० लाख से उन्हें रम एमड़ भूमि अयों द्वारा भीची जाती है, ६० लाख एफड़ से बुद्ध रम माम कुछ। द्वारा सीची जाती है जोर लगमग ७० लाख एकए अन्य सावनों के द्वारा। कृषि की सबसे बढ़ी समस्या सिचाई के लिये उपलब्ध जल की मात्रा बढाना है। मुमि की उत्पादन शक्ति, खादाख, दालें, तथा कृषि के श्रन्य माल की कुल मात्रा, जिनका उत्पादन किसान कर सकता है, बहुत कुछ सिचाई की सुविधा पर निर्भर करता है। जन तक किमान के पाछ अपनी रोती में सिचाई करने के पर्याप्त सापन नहीं है तब तक चाहे वह किवना ही कुशल श्रीर साहसी नयों न हों, श्रपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकता है।

भारत में शक्ति के मुख्य साधन तेल, की नला श्रीर पानी हैं। भारत में पेट्रोलियम की कभी अवश्य है पर कीयले की रागने बहुत हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि खानों में कुल कीयला लगभग २० श्ररन टन होगा। इसका एक चोयां को यला बहुत श्रन्धा को यला है श्रीर उसका प्रयोग थातुश्रों ने सबंध में सीमत रहना चाहिये। निम्नकोटि के कोयले का प्रयोग शक्ति उत्पादन के लिये किया जा सकता है। परन्तु भारतीय उत्योगों श्रीर कृषि के लिये विद्युत शक्ति का समुचित प्रयोग श्रात्यन्त श्रावश्यक है। १६२५ तक वित्युत्वनन श्रोर विकास की यति बड़ी धीमी रही है। इस वर्ष तक के उल १६२३४१ किलोबाट निशुत शक्ति पेटा नी गई थी। १६३५ में यह शक्ति पचगुनी बढ़ गई श्रीर ६००४०२ किलोबेट हो गई। प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रारम्भ में २३ लाख किलोबाट विद्युत शक्ति के उत्पादन का प्रयन्य था। नई योजनाशों के फलस्वरूप यह बढ़ कर ३४ लाख किलोबाट हो गयी। इससे यह सिंद होता है कि देश को श्राधम विद्युत शक्ति प्रदान करने वाली पोजनायें सफल रही हैं। दितीन पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत ने भ लाख किलोबाट शक्ति के बढ़ाने का विचार किया है। जई सब दीर्घकालीन

योजनायें तीन या चार पचवर्षाय योजनाश्रों के श्रन्त तक पूर्ण हो जायंगी तब विद्युत शक्ति लगभग ७० लाख किलोबाट बढ जायगी। हमारे देश में समस्या केवल श्रिषक विद्युत शक्ति के उत्पादन की ही नहीं है बरन् यह भी है कि विद्युत शक्ति पर्याप्त मात्रा में इतने सस्ते मूल्य पर लोगों को शप्त हो सके कि किसान, फैक्ट्री वाले श्रीर श्रन्य सावारण कारीगर उसका श्रासनी से प्रयोग कर सकें।

वनस्पति श्रोर जानवर

विशाल चेत्रफल, विभिन्न भोगोलिक स्थितियों, विभिन्न जलवायु इत्यादि के कारण भारत में वे सन प्रकार के वन, फलों के नाग, और खेती की उपज जो आयः उच्छ, शांत श्रोर समशीतोष्ण जलवायु वाले भू-चेत्रा में पाये, जाते हैं प्राप्त हैं। देश में पालतू तथा वन्य पशु भी श्रनेक प्रकार के मिलते हैं।

वत—भारत में बनों का चेत्रफल लगभग १४ करोड़ ७७ लाख एकड है, जिसमें से ४ करोड़ ३५ लाख एकड़ जगल दिल्यों भाग में, ३ करोड़ ६७ लाख एकड़ मध्यम भाग में, ३ करोड़ ६४ लाख एकड़ पूर्वी माग में और ७ करोड़ ६८ लाख ७० हजार एकड़ उत्तरी-पश्चिमी भागों में स्थित है। दितीय महायुद्ध के समय और अनेक राज्यों में नमींदारी उन्मूलन के पूर्व बहुत बड़ी सख्या में वृद्ध काटे गए, जिसके परिणामस्त्ररूप देश के बन-प्रदेश का च त्रफल बहुत कम हो गया है। बनों से देश को बहुत अधिक लाभ होते हैं। उनमें डेंघन और इमारती लकड़ी तो प्राप्त होती ही है, इसके अतिरिक्त (१) वे औन्त्रोगिक उपयोग के लिए बाँछ, सवाई व अन्य घारों, लाख, गांद इत्यादि भी प्रदान करते हैं, (२) वे भूमि- च्या (Soil erosion) रोजते हैं, भूमि की उर्वरता को सुरिक्ति रखते हैं, और (३) पशुश्रों के लिए चरागाह भी प्रदान करते हैं।

वन राष्ट्रीय श्राय के अत्यन्त महत्वपूर्ण सावन है। उनसे उद्योगों के लिए श्रमेक कच्चे माल प्राप्त होते हैं। भारत क बनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याएँ यह हैं कि: (१) वनों के चेत्रफल म वृद्धि की जाय, (२) देश में जितने प्रकार के वृद्ध पाए जाते हैं उनका सरस्त्रण किया जाय श्रोर (३) यथासमय नई जाति के वृद्ध भी उगाने प्रारम्भ हों। भारत सम्कार ने वन नीति से सम्बन्धित मई १९५२ के प्रस्ताव में भारतीय वनों की सुरद्धा श्रोर उनके विकास की श्रावश्यकता पर ध्यान दिया। उस प्रस्ताव में यह लक्ष्य रखा गया कि देश की कुछ भूमि का एकतिहाई भाग वनों के रूप में रहे। हिमालय-प्रदेश, दक्षिण श्रोर श्रन्य पर्वतीय चेत्रों पर वना के श्रन्तर्गत कुल भूमि का द०%रहेगा, जब कि समतल चेत्रों में कुल भूमि २०% पर जगल उगाए जायेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों की विकास-

सम्बन्धी नीति के त्रम्तर्गत यह व्यवस्था रखी गई थी कि (श्र) पुद्ध के समय में जो भाग विल्कुल उजद गए थे, उनका नवकरण (renovation) हो, (व) जहाँ यधिक मात्रा में भूमि-सर्ग हुया था, वहाँ जगल लगाए जाय, (स) वनों में श्रावागमन के साधनों का विकास किया जाय, (ट) ईंधन के श्रमाव को दूर करने के लिए गाँवों में श्रिधिक बाग लगाए जायं, श्रीर (य) कई प्रकार की ऐसी लकड़ी, नो श्रव तक इमारती लकड़ी के रूप में काम में नहीं आरही थी, उसे ठीक दग से सिकाने श्रौर मसाला लगाकर मनवृत बनाने के बाद श्रिधकाधिक प्रयोग में लाया जाय। राज्य सरकारों की वन-सम्बन्धी नीति न तो मई १६५२ के वन-नीति से उम्बन्धित प्रस्ताव के विल्कुल श्रनुकूल है श्रार न वनों की वेन्द्रीय सिमात (Central Board of Forests) के अनुरूप है। इस वन केन्द्रीय सिमिति की वैठक जून १९५३ को देहरादृन में हुई थी जिसने कई प्रस्तात पास किए श्रीर जिनका उद्देश्य यह या कि राज्य सरकार भारत-सरकार की वन-नीति को कियात्मक रूप दें। १९५० में मारत-सरकार ने 'वन महोत्सव श्रान्टोलन' प्रारम किया, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत से जगलों का अभाव दूर किया जाय। कितु अभाग्यवश इस कार्य-क्रम के अतर्गत लगाए गए अधिकांश वृत्त पानी न मिलने श्रीर लाप्रवाही के कारण सूख गए । श्रधिक वृत्त लगवाना श्रीर जब तक वे काफी बढ़े न हो जाय इनकी देखमाल करते रहना तो श्रावश्यक है ही, किंतु उसके साय-साथ यह भी आश्यक है कि ईंघन अथवा अन्य किसी उपयोग के लिए खड़े वज्ञ न कटवाए जायं।

मछली-उद्योग—"मारत के लम्बे समुद्र-तट पर अस्व मुहाने, नमकीन पानी वाली मीलें श्रीर स्थिर जलाशय हैं, जिनमें काफी मछलियाँ प्राप्त होती हैं। नमकीन पानी वाला चेत्र लगभग १० करोड़ ६० लाख एकड़ है, जिसमें चिल्का कील मी शामिल है। यह चिल्का कील २,५६,००० एकड़ के विस्तार में फैली हुई है और इससे प्रतिवर्ष ३,००० टन मछली प्राप्त होती हैं। मछली-उद्योग से भारत की राष्ट्रीय-श्राय में प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपये श्राते हैं। यह मछली-उद्योग सुख्यत दो प्रकार का है (१) देश के अदर का मछली उद्योग (Inland fisheries), (२) समुद्री मछली-उद्योग (marine fisheries)। मछली पकड़ने के अकिं मारत में विश्वस्त रूप से प्राप्त नहीं हैं। भारत में प्रतिवर्ष समुद्री मछलियों का उत्पादन लगभग १०० लाख मन है श्रीर ताजे पानी की मछलियों का उत्पादन स्थान से कुछ कम होता है। श्रायात द्वारा प्राप्त मछलियों को मिलाकर भारत में प्रतिवर्ष २७० लाख मन की कुल पूर्ति होती है, जिसमें से ७०% मुद्दाने श्रीर समुद्र की मछलियों श्रीर श्रीर श्रीर श्रीर श्रीर समुद्र की मछलियों होती हैं।

इसका श्रियं यह है कि प्रतिवर्ण प्रति व्यक्ति को ३४ पंड मछली मिलती है, जो निश्चित रूप से अपर्याप्त है। उत्तरप्रदेश और पजाब की श्रिपेचाइत द्रावनकोर को चीन, पिश्चमी बगाल श्रीर बम्बई में प्रति व्यक्ति मछली का उपयोग श्रिक है।" यह श्रनुमान किया जाता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना के आरम्भ में मछलियों की कुल उत्पत्ति लगभग १० लाख मीट्रिक टन थी जिसका २०% घरेल् उपयोग के लिये थी श्रोर बाकी समुद्री मछली श्रयवा बेचने के लिये देश के अदर से प्राप्त मछलियों थी। प्रथम योजना के फलस्वरूप ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि मछलियों की उत्पत्ति १०% वह नायगी। १६५५—५६ में मछलियों की उत्पत्ति ११ लाख लाप मिट्रिक टन से कुछ श्रिक थी। दूसरी पचवर्षीय योजना में मछलियों का उत्पत्ति का उत्पत्ति का उत्पत्ति का सहिक टन हो जायगा। वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति मछलियों का वार्षिक उपभोग ४ पीएड से कम ही है। जनता का मोजन सहिलत करने के लिये यह आवश्यक है कि मछलियों का उपभोग बहाया जाय।

समुद्री मछलियों के उत्पादन को यदाने के लिए मछली पकड़ने में वैज्ञानिक यत्रों के प्रयाग करने की आवश्यकता है, क्यांकि आभी तक एक सीमित चेत्र में ही मछलियों का शिकार किया जाता है। जहाँ तक देश के अदर मछली पकड़ने का सम्बन्ध है, इस बात की आवश्यकता है कि मछलियों का पीपण करने और उनके शिकार करने का कार्य वैज्ञानिक रीति से किया। "भारत के वर्तमान जलायाों में प्रमुख रूप से तालान और कीलें आती है। कार्प (Carp) मछलियों बहुधा भारतीय समुद्रों में पीपित होती है। चूँकि यह बंधे हुये पानी में अडे नहीं देतीं, इमीलिये उन्हें प्रतिवर्ध पीपित करने की आवश्यकता होती है। यदि बँचे हुए पानी में कार्प मछलों के कृतिम अखडोत्पादन (artificial spawning) को विकित्त किया जाय, तो मछली-उद्योग का भी विकास होगा। मछलियाँ या तो ताजी खाई जाती हैं या उन्हें भविष्य में खाने के लिए धूप में मुखा लिया जाता है या नमक में जमा लेते हैं। शेप ऐसी मछलियाँ जो खाने के योग्य नहीं रह जाती हैं उनकी खाद बना लेते हैं। मछली-उद्योग के द्वारा हमें मछलियाँ तो प्राप्त होती हैं, इसके अतिरिक्त सर्द्रीन (Sardines), शार्क लिवर तेल (shark liver oil) जैसी अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं।

कृषि उत्पादन—भारतवर्ष में उष्ण कटिबन्घ, श्रर्घ उष्ण कटिबन्घ श्रोर समशीतोष्ण कटिबन्घ में उत्पन्न होने वालो निविध प्रकार की फछलें उगाई जाती हैं। इन फछलों में खाद्यान ग्रीर व्यवसायिक दोनों ही प्रकार की फछलें सिम्मलित हैं, किन्दु प्रमुख रूप से खाद्यान ही श्रिषक उगाए जाते हैं। उक्त कथन हसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि खेती की जाने वाली कुल भूमि के द्राप्त भाग पर छाद्यात्र का ही उत्पादन किया जाता है।

हमारे यहाँ रवी और खरीफ दो मुख्य फर्सलें होती हैं। प्रारीफ फर्सलों के अन्तर्गत मुख्यतः चावल, ज्वार, वाजरा, मक्का, कपास, गला और मूंगफली बोई जाती है और रवी फर्सलों में में हूं, जो, चना, मटर, अलसी और मरसों आदि की खेती की जाती है। "चावल की खेती गगा की घाटी, पजाब के पहाड़ी जिलां, उत्तर-प्रदेश, विहार, पश्चिमी बगाल, आसाम, पश्चिमी घाट और उदीसा न मद्रास के समुद्रतटीय भागों में होती है। पजाब, पेप्य, उत्तर-प्रदेश व मध्य प्रदेश के अधि-काश माग पर गेहूं की रतेती की जाती है। गन्ना गगा ने मैदान, मद्रास, मैन्द्र, उदीम, हैदराबाद और पंजाब में उगाया जाता है। मृगफली, अलसी, अटी, तिल्ली, तिलहन आदि मद्रास के उत्तरी भागों से और कपास दिल्ला प्लेटो के उत्तरी-दिल्ला मागा य पजाब में उगाई जाती है। चाय की रतेती विशेष कर टार्जिनंग, आसाम और नीलिगिरि की पहाड़िया पर होती है। जूट प्रमुख रूप से बगाल में पैटा होता है। कहवा, चाय, रवद, जाली मिर्च और इलायची के पेड प्रज्ञामनाई आर कार्टमन (cardamom) की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। मालाबार तट पर उने नारियल के घने-घने वृद्धों से गरी के गोले त्यार रिस्तयाँ बनाने के लिए जटाएँ प्राप्त होती हैं। इन्हीं चेन्नों से देश भर के लिए काजू की माँग पूरी की जाती है।"

१६५१ की गणना के अनुसार इस देश का मोगोलिङ स्त्रेडकल लगभग ६१ करोड़ २५ लाख एकड़ है, कितु इसमें से केवल ६२ करोड़ ३५ लाख एकड़ भूमि ही गाँव के पुराने लेखों (record) में दर्ज मिलती है। इस स्त्रेडकल में से लगभग २६ करोड़ ६५ लाख एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। यदि हम इस स्वेडकल में उन सेत्रों के मी अनुमानित आँकड़े जोड़ लें जहाँ से कोई स्चना पात नहां होता तो खेती की जाने वाली कुल भूमि लगभग ३४ करोड़ एकड़ हो

१ जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ है वहाँ खरीफ फसल जुन में, नहीं तो फिर बरसात शुरू हो जाने पर जुलाई में वोई जाती है श्रीर जाने में कारी जाती है। रवी फसल बरसात समास हो जाने पर अक्तूबर-नवन्यर में थोई जाती है श्रीर श्रीर श्रीर क्रिये मई में मारी जाती है। गन्ना जनवरी-फरवरी में थोया जाता है श्रीर श्रीर श्रीर श्रीक मई के कारखाने में पिराई होने के समय तक तैयार हो जाता। यह पिराई नवन्यर-दिसम्बर से श्रार में होता है। यद्यपि गन्ना रथी फसल समास हो जाने पर वोया जाता है, फिर मी इसे दारीफ की फसलों के श्रन्तर्गत इसलिए शामिल किया जाता है कि इसका कराई खरीफ की फसलों के साब ही होती है।

जायगी। १६५६-५७ में कुल श्रज की उपज ५७३ लाख टन हुई थी, जिसमें से चावल की उपन २८१ लाख टन, गेहूँ ६१ लाख टन, ज्ञार श्रीर बाजार १०३ लाख टन श्रीर श्रम्थ श्रज ६८ लाख टन थी। इसके श्रितिक ११४ लाख टन रालें, चना श्रादि की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार १६५६-५७ में कुल श्रम्न की उपज ६५७ लाख टन हुई थी। इतना श्रम्म मारत की जनता को खिलाने के लिये पर्याप्त नहीं था श्रीर इसलिये विदेश के श्रम्म पर निर्मर रहना पटा। पर इचित व्यवस्था से खाद्यान्न के सम्बंध में देश के श्रात्म निर्मर हो सकने की सम्भावना है। श्रम्म के श्रितिरक्त खेती से श्रमेक प्रकार के कच्चे माल की भी उपज होती है। १६५६-५७ में गन्ने की उपज ६५ लाख टन, जुट की ४२.५ लाख गाँठ, लई ४७.५ लाख गाँठ श्रीर तिलहन ६० लाख टन हुई थी। देश में जितना इन कच्चे मालों का उत्पादन होता है वह इमारी श्रावण्यकता के दृष्टिकीण से कम है। इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये काफी समय तक हमें श्रायात पर निर्मर रहना पढ़ेगा।

पशु पालन-मारत में पशुयो की बहुत य्रधिकता है। इनकी सख्या संवार के पशुद्रों की सख्या (लस के पशुद्रों को छोड़कर) का है है। १६५१ की पशु-गण्ना के अनुसार भारत में कुल २६ करोड़ २२ लाख ५० इजार पशु ई जिनमें से १५ करोड़ ५० लाख गाय-वेल, ४ करोड़ ३२ है लाख मैंस-भैसे, ३ करोड ६० लाख मेर्डे, ४ करोड़ ७० लाख वकरे-बकरियाँ, ४५ लाख से कुछ कम सुग्रर, १५ लाख घोडे, १२ लाख ५० इनार गमे, ६,२६,००० कॅट ब्रीर ६०,००० खबर हैं। इसके ग्रातिरिक्त ६ करोड़ ७१ लाख ३० इनार मुर्गे-मुर्गियाँ ग्रीर ६२ लाख ६० इजार बतर्खें हैं। किन्तु भारत के पशुश्रो की नस्त बहुत खराब है। यहाँ एक गुप्य श्रीवत से प्रतिवर्ष ४१३ पीड दूघ देती है, जब कि दूचरे देशों की गाएँ प्रतिवर्ष २००० से ७००० पौड तक दूघ देती है। भारत में कुछ श्रन्छी 🗥 नस्ल के भी पशु हैं, जैसे गुजरात की काँकरेज और सौराष्ट्र की गिरि गाएँ दूघ देने श्रीर श्रच्छे वछडे उत्पन्न करने के लिए ससार की सर्वोत्तम नस्लों में गिनी जाती है। किन्तु वेकार व निकम्मे पशुग्रों की सख्या अपेज्ञाकृत बहुत अधिक है जो किसानो के लिए तिनक भी सहायक सिद्ध नहीं होते हैं श्रीर उनके लिए भार-स्वरूप बनकर रहते हैं। भारत में विविध प्रकार के जगली जीव श्रीर पन्नी भी पाये नाते हैं, किन्तु ग्रमाग्यवश "हमारे यहाँ के शेर, गेंडा, चीता श्रादि प्रमुख नगली नीवों की नस्ल समाप्त हो रही है। भारतीय नीवों को सरज्ञ्ण देने, उनकी नस्ल को सुरिज्ञ्त रखने श्रीर उन्हें प्राकृतिक व मानवीय वातावरण में छन्तुलित रखने के लिए भारत-सरकार ने अप्रैल, १९५२ मे जगली जीवों के लिए एक

केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की"। पित्त्यों व सरस्या के लिए एक राष्ट्रीय सिर्मात (National Committee for Bird Protection) भी बनाई गई है। यह आशा की जाती है कि इन सस्थाओं से भारतीय पित्त्यों श्रीर जगली जीवों का सरस्या श्रीर विकास होगा।

खनिज-पदार्थ

किसी देश के श्रीयोगिक निमास के लिए उसकी पानिज सम्पत्ति का निशेष महत्व होता है। खनिज सम्पत्ति को निम्निलिपित वर्गों में बाँटा गया है.—(१) श्रवात खनिज (non-metallic minerals), (२) धात खनिज (metallic minerals) श्रीर (३) ईषन (fuels)। श्रवात पानिज के अन्तर्गत श्रिमृचिका, सीलीमेनाइट, मेगनेसाइट, वालू, चुना श्रीर नमक श्रादि श्राते हैं। धातु पानिज के श्रन्तर्गत सोना, चाँदी, जस्ता, राँगा, टिन, ताँवा, श्रादि श्राते हैं श्रीर ईंघनों के श्रन्तर्गत कोयला तथा पेट्रोलियम श्राते हैं।

भारत में कीयले, कन्चे लोहे, मंगनीज, बीमसाइट श्रीर श्रवरक जैसे खीनज पदायों की बहुतायत है, रिफ्त कररीज (refractories), एश्रेसिव (abrasives), चूना श्रोर जिप्सम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं श्रीर श्रवरक, टिटानियम श्रीर कन्चा थोरियम भी काफी वही मात्रा में पाया जाता है। परन्तु दुर्भाग्य से ताँवा, टिन, सीसा, जस्ता, गिलट, कोबाल्ट, गवक श्रीर पेट्रोल जैसे महत्वपूर्ण रानिजों की बहुत कभी है श्रोर इनके श्रमाव को पूरा करने के लिए इमें श्रिषकतर श्रायात पर निर्भर करना पड़ता है।

"लानों की दृष्टि से सबसे श्राधिक महत्वशाली माग छोटा नागपुर का पठार है, जिसे गोंडवाना भी कहते हैं, जिसमें दृष्ट्यिण विहार, दृष्ट्यिण पश्चिमी वगाल उत्तरी उद्दीसा श्राते हैं। कोयला, लोहा, श्रवरक श्रीर वांचा श्रादि श्रूष्टिकाश हसी माग से पाप्त होते हैं। कोयला विशेषकर करिया, रानीगज के सेत्रों से निकाला जाता है पर वशुश्रमार (Ligmit) के रूप में दृष्ट्यिणी पूर्वी हैदराबाद, दृष्ट्यिणी मन्य प्रदेश और दिल्लिणी पूर्वी मद्रास के समुद्री तट पर भी पाया जाता है। लोहा मैसर में श्रीर श्रवरक उत्तरी मद्रास और राजस्थान में पाया जाता है। हल्मेनाहट श्रीर मोनेजाइट (Ilmenite and Monazite) जो युद्र कालीन महत्ता रखने वाली घातुर्ये हैं, ट्रावन्कोर के तटीय प्रदेश की बालू में पायी जाती हैं। मेगनेखाइट मद्रास की खड़िया मिट्टी वाली पहाड़ियों पर श्रोर सोना मैस्र के कोलार स्त्रेष म पाया जाता है। बौक्साइट स्टीटाइटिजिन्सम इमारतों के बनाने में काम श्राने वाले पर्यार नमक, श्रिशिमुचिका, कोसन्डम फलर्स श्र्य श्रादि भी पर्याप्त

मात्रा में यहाँ पाये जाते हैं। ससार भर की अवरक की उत्पत्ति का ६०% भारत में उत्पन्न होता है। मेगनीज, इल्मेनाइट, मोनेजाइट, लाहा आदि ससार भर में सबसे अधिक भारत में ही मिलते हें। भारत की घातुओं को पूर्णरूप से काम में नहीं लाया गया है। देश में पेट्रोलियम की कमी है केवल आसाम में ही इसके कुर्ये हैं। इन कुर्यो से माप्त उत्पत्ति बहुत ही नगयय है। इसी प्रकार अन्य घातुओं की जैसे राँगा, गन्यक, चोदी, जस्ता, टिन, पारा आदि की उत्पत्ति देश की आवश्यकता से बहुत कम है।

अध्याय ३

जन संख्या

किसी देश के ग्रार्थिक विकास का वहाँ की जनसंख्या से धनिष्ट सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की सख्या, उनका स्वास्थ्य, श्रवस्था खी श्रीर पुरुप की सख्या का श्रनुपात, जन्म श्रोर मृत्यु दर श्रीर देश में प्राप्त खिनज पदार्थों के सम्बन्ध में उनके उद्योग श्रादि सब उनकी स्थिति श्राधिक निश्चित करते हैं। यह एक बढ़े विचार की बात है कि मारतवर्ष जो कि ससार का सबसे श्रधिक धना वसा देश है सबसे गरीब भी है। इसलिये यहाँ की समस्या जन सख्या के वृद्धि की दर में कमी श्रीर पाकृतिक साधनों के उपयोग में वृद्धि करने की है।

भारत की जनसंख्या १८६१ में २३ ५६ करोड थी, १६२१ में बढकर २४'८१ करोड हुई जो १६३१ में २७ ५५ करोड, १६४१ में ३१ २८ करोड़ और १६५१ में ३५ १८ करोड़ हो गई। १६२१ तक तो जनसंख्या की वृद्धि में अकाल और बीमारियो द्वारा कमी होती रही और अल की उपज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पूरी पख्ती रही। परन्तु १६२१ के पृश्चात जनसंख्या में अल की उपज की उपज की उपज की उत्ता तीवतर गित से वृद्धि हुई है जिसका स्त्रामादिक परिखाम यह हुआ कि देश को अल की कमी की किटनाइयों का सामना करना पड़ा। १६५१ की जनगणना रिपोर्ट, १६२१ को महान विभाजक (The Great Divide) के नाम से व्यक्त करती है, क्योंकि (१) इसके पहिले जनसंख्या न्यूनाधिक घटती हुई सी धी परन्तु इस वर्ग के बाद से निरन्तर बढ़ती रही है, और (२) इस वर्ष के पहिले तक भूमि का प्रयोग भी जनसंख्या ने वृद्धि के अनुक्ल ही बढ़ता रहा पर इसके बाद से अल को कमी हाती गई।

ें वृद्धि की दर—१९५१ तक के पिछले १० वर्षों में भारत की जनसख्या लगभग ४१४ करोड़ के बढ़ गई है जो १२३% की वृद्धि कही जा सकती है श्रयवा जिसे १६% प्रांतवर्ष की वृद्धि कह सकते हैं। यह वृद्धि विभिन्न भागों में विभिन्न गित से हुई है। पजाब, श्रयडमान श्रीर नीकोवार टापुश्रों में ०५ प्रतिशत श्रीर ६६ प्रांतिशत कमश कमो हुई है। यन्य राज्यों में से दिल्ली (६२°१%), कुर्ग (३०५%), त्रिपुरा (२१.६%), मैसूर (२१ २%), त्रिवकुर कोचीन (२१°२%) श्रीर बम्बई

^{ैं} इस सरया में जम्मू काश्मीर श्रीर त्रासाम के श्रादिवासियों की सख्या सम्मिलित नहीं हैं।

२० ८%) में सबसे श्रधिक वृद्धि हुई, हिमानल प्रदेश (२'७%), पेप्स् (२ ६%), विन्ध्य प्रदेश (६%), उड़ीसा (६'२%), मोपाल (७ २%), मध्य प्रदेश (७'६%) श्रीर विहार (१ ६%) में वृद्धि को गति श्रपेजाकृत कम रही।

जन्म और मृत्यु दर — जन सख्या में वृद्धि और कभी जन्म और मृत्यु दर के अन्तर पर निभर होती है। इधर पिछले वर्षों में भारत की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कभी हुई है। जन्म दर जो कि १६३१ में ३५ प्रति इजार थी घट कर १६४१ में ३२ ९ प्रति इजार, और १६५० में २४.८ प्रति इजार हो गई। मृत्यु दर जो कि १६३१ में २५ प्रति इजार हो, घट कर १६४१ में २१ ६ प्रति इजार और १६५० में १६ प्रति इजार हो। गई। इस प्रकार इम कह सकते हैं कि जन्म और १६५० में १६ प्रति इजार हो। गई। इस प्रकार इम कह सकते हैं कि जन्म दर में मृत्यु दर की अपेद्धा अधिक कभी हुई। चूँकि जन्म और मृत्यु के आंकडे विश्वस्त नहीं हैं इसलिए १६५१ की जनमयाना रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाय है कि १६४१-५० के बीच के दस वर्षों में जन्म दर का औसत इ० प्रति इजार प्रति-वर्ष जनसख्या में वृद्धि हुई है। यह बड़े दुर्भोग्य की बात है कि इमारे देश में विश्वस्त अपंकडे अप्राप्य हे पर इम यह तो कहसकते हैं कि जनसख्या की वृद्धि की दर बढ़ती गई है।

जन्म दर में कमी विवाह की अवस्था बढ़ाने, आत्म सबम और गर्म निरोध के कृत्रिम उपायों के अनुसार सम्भव हो सकती है। परन्तु जल्दी ताक्य्य अवस्था को प्राप्त करने तथा आधिक अपवा अन्य कारणों से विवाह की अवस्था बढ़ाना सम्भव नहीं है। देर में विवाह करने की प्रथा पढ़े लिखे लोगों में बढ़ रही है हतने पर भी उन लोगों में अभी भी विवाह की अवस्था कम हो है। आत्म-स्थम बहुत ही किठन है। उसके लिये पाय: हममें आत्मबल की कमी है जिसके कारण उसकी सफलता में सन्देह है। गर्भ निरोधक कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग निम्न कारणों में विशेष प्रचलित नहीं हो सका है. (१) उन के विश्व धामिक भावना, (२) उनका अधिक मूल्य, (३) जनता में उनके प्रयोग करने के ढगों के प्रति अनमिकता, (४) इस सम्बन्ध में परामर्श और शिक्षा देने वाले अस्पतालों की कमी। यदि कृत्रिम उपायों का प्रयोग प्रचलित करना है तो इन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करना आव्यन्त आवश्यक होगा।

डा॰ स्टोन का सुरक्षित काल प्रखाली ('Safe Period method') का प्रयोग भी सस्ता और सफाई की दृष्टि से उपयुक्त होते हुये भी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया है क्योंकि अधिकाश जनता इस प्रखाली का सफलतापूर्वक उपयोग करना नहीं जानती।

यह दुर्भाग्य की बात है कि जन सावारण (महुत से उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को संम्मलित करते हुये) परिवार नियोजन की आवश्यमता तथा उसके उपायों से अन्तम्भ हैं। वे सब बात भाग्य के मगेप छोड़ देते हैं। इसके कारण परिवार नियोजन का कार्य अपने देश में एक किटन समस्या के रूप में उपस्थित है। "प्रयम पचवधीय योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन काय के प्रांत जनता में सिवय सहानुभात की भावना जगाना और वर्तमान ज्ञान के आधार पर तरसम्बन्धी परामशं और सेवा के साधना वे विकास की और रहा है। साथ ही साथ इस सम्मन्ध में मेपाजक जेवकीय और साख्य के अन्ययन का कार्य भी किया गया। राज्यों, स्थानीय रस्थाओं, वैज्ञानिक सस्थाओं को ११५ परिवार नियोजक आप्रयालया और १६ सारयकीय तथा जैवकीय समस्याओं के प्रांत जोज करने वाली योजनाओं वो अनुटानो द्वारा सहायता दी गई। वृसरा पचवर्षीय योजना में इस कार्यकृप में वृद्ध करने का विचार किया गया है"।

"यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रांत ५०,००० व्यक्तियों के लिए प्रत्येक नगर श्रीर क्स्बों में एक श्रोपधालय खोला जाय। छोटे कस्बों ग्रोर गाँवों में घीरे-धीरे प्रारम्भिक स्वारम्य सस्याश्रों के सहयोग में ग्रीपवालय खोले जायं। इन श्रोपधालया का कार्य जनता में इस समस्या के प्रति जागरुरता उत्पन्न करना होगा श्रोर उन्हें इस सम्बन्ध में परामर्श श्रोर सेवा प्रदान करनी होगी। वगलीर में एक केन्द्रीय प्रशिष्टण विरुज्जलय (clinic) का खोला जाना विचाराधीन है। वम्बई में कृतिम उपायों का परीक्षालय स्थापित हो रहा है। प्रत्येक भपितक विद्यायियों श्रीर उपचारिकाश्रों को परिवार नियोजन की शिक्षा देना श्रावश्यक है प्रत्येक श्रोपधालय में परिवार नियोजन सेवा विभाग स्थापित होना चाहिये। यह भी प्रस्ताव किया गया है। क भैपाजक जैवकीय तथा ग्रांक्डों से सम्बन्धित श्रान्वेपण सस्था स्थापित की जाय। ५ करोड़ ६० का प्रयन्ध परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिये निश्चत कर दिया गया है। यह श्राशा की जाती है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के श्रान्त तक लगभग २०० विरुज्ञालय नगरों में श्रीर २००० विरुज्ञालय गाँवों में स्थापित कर दिये जायंगे?।

मृत्युसंख्या की दर-मृत्युसक्या की टर शारीरीक कारणों श्रीर वाता-वरण पर निर्मर करती है। शारीरिक दशा पोक्टिक तत्वा, स्वच्छता, चिनित्सा की सुविधा इत्यादि पर निर्मर करती है। वातावरण की दशा बाढ श्रकाल, युद्ध इत्याद पर निर्मर करती है। मृत्युसरया की दर प्रत्वेक वर्ष भिन्न-भिन्न रही है परन्तु प्राप्त श्रॉक्टों के श्रनुसार मृत्युसरया की दर घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि चिकित्सा की सुविधा बढ़ी है श्रोर सफाई की श्रोर श्रधिक व्यान दिया जाने लगा है। यह आशा की जाती है कि मित्रिंग में चिकित्सा की मुनिधा में चृढिहोने के साथ-साथ मृत्युसख्या की दर मीघटती जायगी। बहुमुनी योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद अकाल और बाद का जोर कम हो जायगा। भारत में चच्चों की मृत्युसख्या अधिक होने से मृत्युसख्या की दर अविक है। यह अनुमान लगाया गया है कि जुल जितने बच्चे पेदा होते हैं उनमें मे १५ प्रतिशत एक वर्ष की आयु होने से पहले ही मर जाते हैं। सरकारी तौर पर की गई गएना के अनुसार यह पता चना है कि इन बच्चों में से ५० प्रतिशत पैदा होने में एक महीने के अन्दर मर जाते हैं और ६० प्रतिशत पहले सप्ताह में ही मर जाते हैं।

भारत में प्रतिवर्ष अनेक वीमारियों जैसे हैजा, चेवक, प्लेग, ज्वर श्रीर डिसेन्ट्री इत्यादि से लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। हैजा, चेवक श्रीर प्लेग महा-मारियों हैं। सभी वीमारियों से कुल जितने लोगों की मृत्यु होती हैं उसका ५.१ प्रतिशत इन महामारियों के शिकार होते हैं। इससे प्रकट है कि महामारियों के कारण बहुत अविक मृत्यु नहीं होती है। विभिन्न बीमारियों में होने वाली मृत्युश्रों के ५७५ प्रतिशत का कारण अनेक प्रकार के ज्वर होते हैं। अस्पतालों की सुविधा बढा कर, स्वास्थ्य-सुधार की योजना लागू कर, लोगों की बीमारियों के आक्रमण से वचने की शक्ति बढाकर साथ ही लोगों को आत्मविश्वासी और माग्य पर कम निर्मर बनाकर मृत्युसख्या की ऊँची दर के कारणों को दूर किया जा सकता है।

स्त्री-पुरुपों का अनुपात—भारत में पुरुपों की सख्या सियों से अविक है परन्तु मद्राय, उड़ीसा, त्रिवाक्तर कोबीन और कच्छ में यह स्थिति विपरीत है। इन राज्यों में सियों की सख्या पुरुपों से अधिक है। १६५१ की जन-गणना के अनुसार कच्छ में सबसे अधिक सियाँ हैं। यहाँ प्रति हजार पुरुपों के पीछे १०७६ सियाँ हैं। कुर्ग में सियों की सख्या अन्य सब राज्यों से कम है। यहाँ प्रति हजार पुरुपों के पीछे दे० सियाँ हैं। इस स्थिति के अनेक सामाजिक, धार्मिक और (Biolgical) कारण हैं। प्राय: सभी वर्ग की जनता और विशेषकर हिन्दू समुदाय लड़की की अपेन्ना लड़के को अधिक चाहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि लड़कियों की उचित देख-रेख नहीं की जाती है और उनकी प्राय: मृत्यु हो जाती है। धार्मिक भावना के अतिरिक्त इसका एक कारण यह है कि समाज में शिन्ना का प्रसार कम है और लोग समाज में स्त्री के महत्व को ठोक-ठीक नहीं समक्त पाते हैं। इससे प्राय: लड़कियों की विशेष देख माल नहीं की जाती है। प्रसव के समय अनेक स्त्रियों की मृत्यु हो जाने से भी स्त्रियों की सख्या कम है।

अवरथा—भारत में बक्चे श्रीर नवयुत्रकों की जनसरया में प्रधानता है। १६५१ में १४ वर्ष तक के लोग २८ ३%, १५ में ३४ वर्ष तक के लोग ३३%, १५ से ५४ वर्ष तक के लोग २० ४% और ५५ वर्ष के ऊपर के लोग केवल ८ २% थे। श्रन्य देशों में, जैम फ्रान्स, इद्वलेग्ड, जर्मनी, उत्तरी श्रमरीका श्राटि में, दियति इसके निपरीत है। इन देशों में ५५ वर्ष श्रोर इसके ऊपर की श्रवन्था वाल व्यक्ति इल जनसंख्या के फ्रमश: २१ ४%, २१ १%, १६ १% श्रीर १६ ६% है।

घनत्व श्रोर वितर्ण-मारत में श्रीसत जनसंख्या वा धनत्व ३१२ प्रति वर्ग मील है। घनत्व की मात्रा एक प्रदेश से दृखरे प्रदेश में बटलती हुई है। एक श्रोर दिल्ली मे ३०१७, द्रायन्कार कोचीन में २०१५ प्रांत वर्ग मील है तो दृखरी श्रोर प्ररहमान निकाबार में १०, श्रोर उच्छ में ३४ प्रात वर्ग मील है। इस वटलते हुये वनत्व का कारण प्राकृतिक बनायट, भूमि तथा वर्षा है। इन कारणो पर ही भूमि के उचित प्रयोग की मात्रा निर्मर है। इस लो पनत्य की समस्या का अन्ययन प्राकृतिक मागो के आधार पर अधिक युक्तिसगत होगा। उस दृष्टिकीण चिन्यगगा के मेदान के निचले भाग में धनत्य ८३२ ग्रीर ऊपर के भाग में धनत्य ६८१, मालावार कोवन मे ६३८, टिस्ली मट्टास म ५५४, उत्तरी मद्रास श्रीर उदीसा के समुद्री तट पर ४६१ है। ये भाग बहुत श्रिषक धनत्व वाले कहे जा सकते हैं। दिल्ली भाग में, उत्तरी भाग में, गुजरात वाठियाताइ में, जहीं पर जनसङ्या का घनत्व साधारण को।ट का है, प्रतिवर्ग मील में कमरा ३३२, २४७. २४६ श्रीर २२६ व्यक्ति निवास करते हैं। टिच्चियी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में. उत्तरी केन्द्रीय पहाड़ियों में, पूर्वी पठार में, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों में, हिमालय, पश्चिमी हिमालय श्रीर रेगिस्तानी मार्गो मे जनसंख्या का घनत्व समश १६२, १६४, १६३, ११८ ६८ श्रीर ६१ व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। जनसङ्या के इस असमान वितरण के कारण प्रत्येक स्थान पर प्राप्त प्राकृतिक सुविधान्त्रों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाया है।

भूमि के प्रयोग सम्बन्धी आँकड़ों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि (अ) योक्प नहीं ससार भर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है भारत की दलना में अधिक आगे नहीं है। ओसत भारतीय अपनी भूमि का ४३% खेती के काम लाता है जब कि औसत योक्पीय वेवल ६० प्रांतशत ही काम में लाता है। (व) संयुक्त राज्य अमेरिका और सावियत रूस के व्यक्तियों के पास योक्प निवासियों और भारतीयों की अपेचा अधिक भृमि है। भारत में भूमि पर जनसंख्या के मार का कुछ अनुमान इस बात से लगता है कि बोये हुये खेतों में जनसंख्या के प्रांत व्यक्ति का औसत ० ८२ एकड़ है।

यदि कटिवन्घों के दृष्टिकोण से जनसङ्या के वितरण पर विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में केवल उत्तर प्रदेश की जनसख्या ६ ३२ करोड़ अयवा कुल जनसंख्या का १८% है। पूर्वी भारत की (जिसमें बिहार. उदीला, पञ्छिमी बगाल, आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा श्रीर सिकिम आते हैं) जन-सख्या ६ करोड़ या कुल जनसंख्या का २५% है। दिल्ला भारत (जिससे मद्रास, मैसर, ट्रायनकोर कोचीन श्रीर कुर्ग श्राते हैं) की जनसख्या ७५६ करोड़ या कुल जनसख्या की २१% है। पन्छिमी भारत की जनसख्या जिसमे वम्बई, सीराब्द्र श्लीर कच्छ श्राते हैं ४.०७ करोड़ या ११% है। मन्यमारत की जनसंख्या जिसके श्रन्त-र्गत मध्यभारत, हैदराबाद, मोपाल श्रीर विन्ध्य प्रदेश श्राते हैं ५.२३ करोड़ या १५% है । उत्तरी पश्चिमी मारत की जनसंख्या जिसके ब्रन्तर्गत राजस्थान, पंजाव, पेप्सू, जम्मू त्रौर काश्मीर (त्राकडे सम्मिलित नहीं हैं), त्रजमेर दिल्ली, विलासपुर, त्रौर हिमालय प्रदेश त्राते हैं, ३५ करोड़ या १०% है। यदि भूभागों के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी मैदान की जनसंख्या३६ १%, प्रायद्वीप पहाडियों ग्रीर दक्तिगी पठार की जनसख्या ३० ४%, पूर्वी घाट ग्रीर समुद्री तट की जनसङ्या १४ ५%, पश्चिमी घाट ऋौर समुद्री तट की जनसंख्या ११ २%, हिमालय के 'भूभाग की जनसख्या ४ ८% है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि देश के उपजाऊ मैदानों में श्रिधकाश जनसख्या वसी हुई है।

मध्यप्रदेश का चेत्रफल सबसे श्रिषक है, श्रर्थात् १३०२७२ वर्ग मील, तथा इसके पश्चात् राजस्थान है जिसका चेत्रफल १३०२०७ वर्ग मील है, जर्बाक जनस्थ्या उत्तर प्रदेश की सबसे श्रिषक श्रर्थात् ६.३ करोड़ है श्रीर इसके पश्चात् मद्रास, श्रिहार, श्रीर वस्वई हैं जिनकी जनसख्या क्रमशः ५७, ४ तथा ३ ५६ करोड़ है। विव्य प्रदेश तथा दिल्ली के श्रितिरक्त जिनकी जनसख्या क्रमशः ३५७ लाख तथा १७.४ लाख है—किसी भी स श्रीर द राज्य की जनसख्या १० लाख से श्रिषक नहीं है। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश श्ररहमन श्रीर निकोबार द्वीप है जिसकी जनसख्या केवल ३०६७१ है। भारत की श्रिषकतर जनता गावों में निवास करती है। ३५७ करोड़ की कुल जनसख्या में से केवल ६२ करोड़ श्रयवा १७३% नगरो ग्रीर कस्वों में (जिनकी सख्या ३०१८ है) रहती है श्रीर शेष २६५ करोड़ या ८२७% जनसख्या गावों में रहती है जिनकी सख्या भ्रद्राव्ह है। देश के श्रीद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप गाँवों की जनसख्या निरन्तर नगरों की श्रोर बढती जा रही है। १६२१ में ८६,७% जनसख्या गाँवों में निवास करती थी श्रीर ११२% नगरों में। १६४१ में ८६ १% गाँवों में श्रीर १३६% नगरों में निवास करने लगी श्रीर १६५१ में जैसा कि ऊपर बताया जा

चुका है, ८२'७% गाँवों में श्रीर १७ ३% नगरों में रहने लगी। दिल्ली श्रीर श्रज-मेर के छोटे राज्यों को छोडकर जहाँ कि शहर की यात्रादी कमश ८३% श्रीर ४३% हे, बढ़े राज्यों में नमबई श्रीर सीराष्ट्र के राज्य सबसे श्राधिनक हैं जहाँ ३४% श्रीर ३१% जनसङ्गा नगरों में रहती है।

भारत के ७३ शहरों की ग्राबादी एक लाख के ऊपर है। ग्रामाम ग्रोर पेप्स में ऐसा कोई नगर नहीं है। 'स' राज्यों के सात भागों केवल नई दिल्ली ग्राजमेर ग्रीर भूपाल ऐसे नगर हैं। देश के सबसे बढ़े नगरों में बम्बई की जनसख्या २८ ३५ लाख, है, कलकत्ता की २५ ४६ लाख, मद्रास की १४ १६ लाख, हैदराबाद की १० ८६ लाख, दिल्ली की ६ १५५ लाख, ग्रहमदाबाद की ७ ८८ लाख, ग्रीर बगलीर की ७ ७६ लाख है।

धर्म और विवाह— भारत में श्रनेक घर्मों के मानने वाले रहते हैं पर हिन्दुओं की सख्या प्रधान है। १६५१ में ३५७ करोड़ की श्रावादी में से ३०°३ करोड़ हिन्दू थे, ३५ करोड सुसलमान, ८२ लाख ईसाई, ६२ लाख सिन्ख, १६ लाख जैन २ लाख बोद १ लाख जोराष्ट्रियन (पारबी), १७ लाख श्राधवासियों के धर्मावलम्बी तथा १ लाख श्रन्य धर्मों के पालन करने वाले थे।

मारत में प्रति १०,००० व्यक्तियों (शरण्यियों को छोड़ कर) में प्रश्च पुत्रप तथा ४८६७ छी हैं। इनमें २५२१ पुत्रप व १८६६ छियाँ श्रविवाहित हैं श्रयांत् छियों ग्रीर पुत्रपों को मिलाकर कुल जनसंख्या ४४'१% श्रविवाहित हैं। बाल विवाह रोक कानून के होते हुए भी देश में श्रत्यिक बाल-विवाह होते हैं। १९५१ की जन गणना के श्रनुसार लगभग २८३३००० पुद्ध ११८००० विवाहित छियाँ, ६६००० विधुर श्रोर १३४००० विध्वाय प्रश्नोर १४ वप की श्रवस्था के बीच की थीं। इसी रिपोर्ट के श्रनुसार लगभग ६२०००००० विवाह वाल विवाह निरोधक नियम के प्रतिकृत हुये थे।

(९ व्यवसाय—देश भर के ७०% व्यक्ति कृषि पर और ३०% अन्य व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं। धौराष्ट्र, बच्छ, श्रुजमेर दिल्ली अन्डमान, नीक्षोबार में खेती करने वालों की सख्या की तुलना में अन्यप्रकार के व्यवसायियों की सख्या अधिक है। पिश्चमी बगाल ग्रोर वस्बई प्रदेशों में जो सबसे अधिक श्रौशोगिक प्रदेश हैं वहाँमों खेती करने वालों की सख्या व्यवसायियों से बढ़ी हुई है। हिमाञ्चल प्रदेश श्रौर सिकिम में कृषि करने वालों की सख्या इल श्रावादी की ६०% है। प्रत्येक १०० भारतवासियों में ४७ तो ऐसे किसान हैं जिनके पास अपने खेत हैं, ६ श्रासामी हैं, १३ विना सूमि के अमिक हैं, १ जमीन्दार है श्रयवा लगान पर/श्राश्रित हैं श्रौर १० उद्योगों में लगे हुए हैं श्रयवा कृषि के श्रितिरिक्त अन्य कार्य करते हैं,

६ व्यापार करते हैं, २ यातायात में लगे हें और १२ विभिन्न प्रकार की नौकरियों में लगे हैं। १६५१ की जनगणना के अनुसार ३५७० व्यक्तिमों में से २४% करोड़ किसान और १० ८ करोड़ खेती के अतिरक्त अन्य कार्य करने वाले लोग थे। २४६% करोड़ किसानों में से १६७३ करोड़ अपने निजी भेते वाले पे, ४८४ ५ करोड़ कृषि कार्य करने वाले में ते १६७३ करोड़ अपने निजी भेति करने वाले पे, ४८४ ५ करोड़ कृषि कार्य करने वाले मजदूर थे और ०५३ करोड़ खेती करने वाले वमींदार या लगान पर आश्रित व्यक्ति थे। १०८ करोड़ अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों में से ३० करोड़ कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्यक्ति के कार्य में लगे थे, २१३ करोड़ व्यापार में लगे थे, ०५६ करोड़ यातायात में लगे थे और ४३ करोड़ विभिन्न नौकरियों में लगे थे। १६

ग्रध्याय ४

सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ

सामाजिक ग्रीर घामिक व्यवस्था ग्री का जनता के ग्राधिक जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। यह भौतिक सुख समृद्धि ख्रीर सम्पत्ति के सग्रह के प्रति जनता के दृष्टिकोण को, साय ही इन उड़ेश्यों की पुति के लिए जनता के प्रयल्लों को निर्धारित करती हैं। यह व्यवस्थाएँ त्रोद्योगिक श्रोर वाणिष्य सगठनों को प्रभावित करती हैं साध ही व्यापार श्रोर उत्योग का किस प्रमार सगठन किया जाना चाहिये इस पर भी इन व्यवस्थात्रों का प्रभाव पढ़ता है। भाग्त में जाति प्रणाली ख्रोर संयुक्त परि-वार की प्रथाओं का भी देश के ग्रार्थिक सगठन पर काफी प्रमाव पढ़ा है, पर्दा-प्रथा, ब्रहिंसा पर विश्वास श्रोर धर्म क प्रति सामान्य जनता के दृष्टिकोण ने उनकी श्रायम-गतिविधि को निर्धारित एवम् सचालित किया है। पर्टा-प्रया के कारण उच-जाति की महिलाएँ देश के ऋार्थिक-कार्य में भाग नहीं लेती हैं स्रीर इस प्रकार जनता को निर्धन रखने में यह प्रथा सहायक सिंद होती है। ऋहिसा के र्दाष्टकोण श्रीर इस धार्मिक मावना से कि पन्टर श्रीर नील-गाय (जो वास्तव मे गाय नहीं है। पवित्र हैं इनको नए नहीं किया जा सकता। इससे फसल तथा श्रन्य मुल्यवान सम्पत्ति की मारी चति होती है । घामिक सस्यायों को जैसे मन्दिरों. मठों श्रीर प्रखाड़ों को जनता जो टान देती है उससे इन सस्पाश्रों ने बहुत श्रधिक मात्रा में सम्पत्ति का सप्रद कर लिया है जिसका परिखाम यह होता कि (१) इन सस्यायो को चलाने वाले पुनारी पागडे तथा श्रन्य लोग श्रालसी हा जाते हैं श्रोर वेकार पढ़े रहते हैं श्रीर इस प्रकार देश उनके अस का लाभ उठाने से विचत रह जाता है, (२) इस प्रकार जो धन इन्छा होता है वह तिजोरियों में बन्ट रखा जाता है श्रीर देश के श्राधिक विकास के कार्य मे इसका उपयोग नहीं होता है। विश्व के श्रम्य उन्नत देशों में जनता द्वारा की गई बचत काफो पहिले देश के श्रीद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए उपलब्ध हो गई श्रोर पृजी निर्माण की प्रति-किया को प्रोतसाहन मिला। परन्तु मारत में धार्मिक सगटनों के प्रमुत्व श्रीर शास्त्रों के इस ब्राटेश से कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी कमाई का कुछ ब्रश इन सस्यान्त्रों को दान देना चाहिए ग्रोर साथ ही मन्दिरों ग्रीर मठों के प्रति जनता की गहरी श्रद्धा होने से देश मे पूजी निर्माण का कार्य बहुत शिथिल पड़ गया। देश के उत्तराधिकार कानूनों से भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति का अनुचित रूप में छोटे-छोटे हिस्सों में विमाजन होता गया है। यदि भारत में सामाजिक श्रोर घामिक व्यवस्थाएँ भिन्न प्रकार होतीं तो देश की त्राथिक प्रगति भी भिन्न प्रकार की होती।

जातिप्रया-जाति प्रथा इमारे देश की प्राचीनतम प्रयात्रों में से है। एक परिभाषा के श्रनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक ऐसा सग्रह है जिसका एक नाम है, जो उसके श्रन्तर्गत श्रानेवाले लोगो के न्यवसाय सम्बन्धित होता है श्रीर इस नाम से ही उसके श्रन्तर्गत श्रानेवाले लोगों का व्यवसाय से मालूम हो जाता है। इसके साथ ही यह दावा किया जाता है कि किसी पीराणिक मानव या देवता से इसका वश चला है, इसके अन्तर्गत आनेवाले लोगों का एक पेशा है, श्रीर राय प्रकट करने के श्रधिकारी व्यक्ति इसे एक ही समुदाय समम्तते हैं जिसमे समानता है। हमें यह मालूम नहीं है कि जाति प्रणाली का विकास कैमे हुआ। जाति प्रया सभवतः श्रम-विभाजन श्रीर विशेषश्वा के सिद्धाव पर श्राधारित रही होगी। प्राचीनकाल में हिन्दू समाज चार भागों में विभक्त था, अर्थात ब्राह्मण जो श्राध्यामिक नेता, विद्वान श्रौर पुजारी होते थे, ज्ञिय जो योदा श्रौर प्रशासक थे, वैश्य जो व्यापारी ऋौर सौदागर थे, ऋौर शुद्ध जो निम्नकोटि के कार्य करते थे, अन्य लोगो की सेवा करते थे-इन अन्य लोगों मे अधिकार प्रथम तीनो वर्ग के लोग हो हाते थे। इस चार जातियो की प्रगाली से हमें कार्य का विमाजन स्रष्ट मालूम होता है । साथ ही यह प्रयत्न भी प्रकट होता है कि विभिन्न लोग विभिन्न कायों में दच्चता प्राप्त करें। श्रारभ में जाति प्रणाली वशगत या पुशतैनो नहीं थी श्रीर एक जाति का व्यक्ति अपने प्रयक्तों के बल पर श्रपनी जाति से उच्च जाति मे प्रवेश पा सकता था। परन्तु बाद में जाति प्रथा अत्यन्त कट्टर रूप धारण कर गई श्रीर निश्चित रूप वशगत हो गई। इसके श्रतिरिक्त श्रनेक उपजातियाँ श्रीर इन उपजातियों के भी श्रनेक निम्न रूपों को जन्म दिया गया जिसस यह सारी व्यवस्था ग्रत्यन्त जिंटल हो गई।

श्रारम्भ में जाति-प्रणाली से कुछ लाम थे: (१) इस व्यवस्था से किसी कार्य में श्रीर ज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त की जा सकती थी जिससे जो कुछ कार्य किया जाता था उसके गुण में बहुत सुधार होता जाता था। प्राया वेटा वहीं व्यवसाय अपनाता था जो उसका बाप करता था श्रीर इस व्यवसाय के लिए बाप उसे उचित शिक्ता दे देता था। इस प्रकार एक विशेष प्रकार का कार्य श्रीर तत्सम्बन्धी ज्ञान एक परिवार में वश्यत रूप से चला श्राता था श्रीर वेटा बाप से उस व्यवसाय की योग्यता प्राप्त कर कार्य श्रीर तत्सम्बन्धी कीन एक परिवार में वश्यत रूप से चला श्राता था। परिष्ठतों की सुप्रसिद्ध विद्वत्ता, भारतीय योद्धात्रों की श्रपूर्व सफलताएँ श्रीर उचकोटि की भारतीय दस्तकारी सभी श्राशिक रूप से इस विशेष योग्यता के ही फल थे जो स्वय इसी जाति-प्रणाली का परिणाम था, (२) जाति-प्रणाली ने उन कष्टमय तथा परेशानियां के दिनों में जब कि भारत पर विजातियों ने इसले किये थे हिन्दू-जाति की शुद्धता को

वनाये रखने में बहुत सहायता मिली। जाति-प्रणाली की कट्टरता के फलस्वरूप ही विजेतायों और विजितों के बीच आवश्यकता से अधिक रक्त-सम्मन्द नहीं हो पाया इसमें काफी रूकावट पड़ी, और (३) जाति प्रणाली ने आरम्भ से ही हिन्दुओं को अन्य लोगों के विश्वासों और धर्मों के प्रति सहिष्णु वने रहने का पाठ सिखाया है। इसी कारण विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग भारत में शांति और भाई चारे के साथ रहते आये हें इसमें तिनक भी असत्य नहीं है कि आरम्म में भारत में जांति प्रणाली ने पाय. उसी उद्देश्य की पूर्ति की जिसकी यूरोप में गिल्ड-प्रणाली (Guild System) ने की जिसके अन्तर्गत गिल्ड के सदस्यों को टैक्निकल शिद्या दी जाती थी ग्रोर उनके अन्य हितों की देखमाल की जातों थी।

परन्तु श्राधानक काल में जाति प्रशाली श्रश्ययन्त जटिल श्रौर श्रपरिवर्तन-शील हो गई है, उसमे एक प्रकार की कटरता आ गई है श्रीर फलस्वरूप इससे देश की आर्थिक प्रगति में सहायता मिलने की अपेन्ना हानि ही अधिक हुई है। वाति प्रणाली के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि: (१) यह आवश्यक नहीं है कि वैश्य का पत्र अञ्छा व्यापारी हो और ब्राह्मण का पुत्र अञ्छा पुजारी हो। यह बिल्कुल समय है कि बाह्यण या वैष्य के पुत्र में ऐसी योग्यता है कि वह श्रत्यन्त कुशल मोची वन सके। परन्तु जाति प्रया उच जाति के लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकती है जो कार्य छोटी जातियो को सौपे गये हैं। इसी प्रकार यदि कोई श्द्र बहुत शिक्षित श्रीर विद्वान मले हो परन्तु वह किसी मन्दिर का पुजारी नहीं बन सकता। यह जाति प्रथा ही उसके मार्ग में सबसे बढ़ी वाबा बन जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा किसी व्यक्तिको ऐसे उत्तम कार्य करने से रोकती है निसकी उसमे पर्याप्त ज्ञमता ग्रीर योग्यता हो। (२) ग्रस्पृश्यता ग्रीर इससे उदसुत ग्रन्य कठिनाइयों ने कारण जाति-प्रया जनता के सरल-स्वाभाविक प्रवाह में वाधक बन जाती है। किसी देश के यायिक विकास के लिए पजी और श्रम की निर्वाध गति-शीलता श्रत्यन्त श्रावश्यक होती है। जाति प्रथा ने इसकी रोक रखा है श्रोर इस सीमा तक हमारे देश में श्रीयोगिक तथा कृषि क्रातियों का श्रमाव रहा है। (३) क्टर जाति प्रथा के नारण इम श्रम-सम्मान (dignity of labour) को भूल गये हैं और इससे अन्य लोगों के विश्वासी, धर्मी क्रीर दृष्टिकोणों के प्रति हमारी सहिष्णुता की भावना भी कम हो गई है। इसीलिए इससे गतिरोध उत्पन्न हो गया है, इमारा समाज अस्थिर हो गया है ज्रोर इममें स्वय ज्रागे बढकर पथ प्रदर्शन करने तथा साहस की भावना लुप्त हो गई है।

सौमाग्य से गत कुछ वर्षा से जाति-प्रया टूट रही है। भारत में रेलों के निर्माण, इसके प्रसार, यात्रा की सुविधाओं में वृद्धि, रेल, वस या इवाई जहाज की यात्रा में विभिन्न जाति के लोगों से होने वाले श्रनिवार्य जन-मम्पर्क के फलस्वरूप जाति-प्रणाली की कट्टरता कम हो गई। अग्रेजी शिचा प्रणाली न्यीर अग्रेजी कानून के ब्रन्तर्गत सभी जातियों के साथ समानता का व्यवहार किया गया थोर सभी जातियों के लोगों को कोई भी व्यवसाय अपनाने की छूट दे दी गई। पेशा श्रपनाने मे जाति-प्रया की बाधा नहीं रही। शूद्र जाति के व्यक्ति श्रप्यापक, मजिस्ट्रेट ग्रीर उच्च सैन्याधिकारी वने श्रीर उच्च जाति के लोग जिन्हें ग्रपना कार्थ सिद्ध करना होता था इन प्रधिकारियों के सम्पर्क में श्राये श्रीर जाति प्रथा की कटरता का पालन नहीं कर सक । जाति-प्रथा के कारण ही अनेक (एन्दुयों ने श्रन्य घमों को स्वीकार कर लिया। इसकी स्वय हिन्दू-समुदाय में प्रतिक्रिया हुई श्रोर श्रर्थ-समाज जैसे सुधारवादो श्रान्दोलन हुए जिन्होने जाति-प्रया को तोहने में बहुत बड़ा कार्य किया है। मारतीय राष्ट्रीय काग्रेस इसके विरुद्ध संघर्ष करती रही े श्रीर भारतीय सविधान मे श्रस्पृश्यता को भारी श्रपराध माना गया है छोर उनको बरानार अवसर प्रदान किया गया है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अब परिगणित जाति के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति देने की नीति अपना रही हैं। इन सब प्रयत्नों से जाति-प्रथा की कष्टरता कम हो गई है ब्रीर मारत के त्रार्शनक नीजवान इसकी अधिक परवाह नहीं करते हैं। कुछ लोग या वह लोग जो ग्रमी ग्रपने गाँवो या कस्त्रों की सीमा से ग्रपने को मुक्त नहीं कर सके हैं श्रीर जिनका दृष्टिकीण श्रमी भी सकुचित बना हुया है, श्रव भी इस जाति-प्रथा की कट्टरता की भावना से प्रस्त है प्रन्तु इनकी सख्या धीरे-घीरे घटती जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि जाति-प्रथा समाप्त होती जा रही है परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अपन भी जार्ति-प्रथा का जोर है आर भारतीय आधिक प्रणाली को उससे बरावर चिति हो रही है।

संयुक्त परिवार की प्रथा (Joint Family System)—स्युक्त परिवार प्रया मारत की प्राचीनतम प्रथाओं में से एक है। देश में सामान्यतः श्राधिक इकार्ड एक व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है। बहुत में व्यक्तियों ने संयुक्त परिवार से श्रपना सम्बन्ध-विच्छेड कर लिया है श्रीर वह श्रलग रहने लगे है परन्तु फिर भी परिवार सगठन में स्युक्त-परिवार प्रया की पूर्ण प्रधानता है। समुक्त परिवार में सामान्यतया पिता परिवार का प्रधान होता है श्रीर परिवार के अन्य पुरुष तथा स्त्रियाँ उसके आवीन होते हैं। वह साथ रहते हैं साथ खाते-पीते हैं और पूजा-पाठ करते हैं, साथ ही समाज में समके समान सम्बन्ध होते हैं। यह ठीक कहा शया है कि छोटे पेसाने में संयुक्त-परिवार साम्यवाद का उदाहरस है। यदि संयुक्त परिवार का उचित सगठन किया जाय

तो वहाँ यह सिद्धान्त लागू होता है कि "प्रत्येक सदस्य सब के लिए श्रीर सारा परिवार प्रत्येक के लिए" (each for all and all for each) श्रयांत प्रत्येक व्यक्ति पूरे समूह के लिए उत्तरदायी है स्त्रौर पूरा समूह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है। सयुक्त परिवार प्रथा के कुछ आर्थिक लाभ हैं--(१) इससे रहन-सहन का न्यय घट जाता है क्योंकि खाना साथ पकाया जाता है, नौकर चाकर समान होते हैं श्रीर श्रन्य समी मुविधाश्रों का सयुक्त रूप से उपमोग किया जाता है। वह पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सभी सुविधाएँ इसमें निहित हैं। यदि लोग श्रलग-श्रलग रहते हैं तो रहन सहन का कुल न्यय परिवार के न्यय से बहुत अधिक होगा, (२) इससे सम्पत्ति और भूमि का छोटे-छोटे भागों में विभा-जन नहीं होता, भूमि पर मिलकर खेती की जाती है जिससे आर्थिक चेत्र में अनेक लाभ होते हैं और श्रन्य रूपों में भी काफी लाम होता है। सयुक्त परिवार की पूँजी निखरी हुईं नहीं होती विलिक एक साय जमा रहती है श्रीर उसको श्रन्य उत्पादन कार्यों मे या त्रागामी उत्पादन कार्य का प्रसार करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु यदि संयुक्त परिवार टूट जाय श्रीर लोग श्रलग-श्रलग रहने लगे तो यह समन है कि उनके पास पर्याप्त प्जी न हो, और (३) सयुक्त परिवार मथा बीमारी, मृत्यु या त्रन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनायों के श्रवसर पर एक प्रकार से वीमा का कार्य करती है। विधवात्रों, अनायो और वृद्धों का सयुक्त परिवार में अन्य सदस्यों की तरह ही पालन-पोपण होता है। गत कुछ वपों से पश्मि देशों मे वृद व्यक्तियों को, जो कार्य नहीं कर सकते श्रीर निर्धन हैं, उनकी सन्तानों ने उन्हें विना किसी सहारे के छोड़ देने की प्रकृति हो गई है। सयुक्त पिरवार प्रथा के श्रन्तर्गत ऐसा संमव नहीं है।

परन्तु सयुक्त परिवार-प्रणाली की अनेक हानियाँ भी हैं: (१) चूकि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, कपढ़े, रहने यादि की पूरी सुविधा उपलब्ध है इसिलए उन लोगो में जो चिरित्र की हिन्द से अब्छे नहीं कहे जा सकते हैं ओर जिनमें दूर हिए का अभाव होता है आलस्य पेटा हो जाता है। हन प्रथा से उनके आलसी स्वभाव को वल प्राप्त होता है। साम्यवाद के अन्तर्गत चूकि सुगतान कार्य के आधार पर नहीं बिल्क आवश्यकता के आधार पर किया जायगा अतएव तब यह किनाई उत्पन्न हो जायगी कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी इमता के अनुकूल उत्तम कार्य कैसे कराया जाय। इसी प्रकार सयुक्त-परिवार-प्रणाली में व्यक्ति को सभी आवश्य-कताओं की उसके द्वारा किये गये कार्य की गयाना किये बिना ही पूर्ति हो जाती है इससे कुछ लोगों में निटल्ले वेठे रहने और आलसी वन जाने की प्रकृति पेटा हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि स्पर्य का मूल्य वही व्यक्ति अव्छी प्रकार सम-

मता है जो रुपया कमाता है। इसलिए सयुक्त परिवार में आलसी और निठल्ले लोगों के फिज्ल-तर्च बनने की पूरी संमावना रहती है, (२) सयुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत लोगों की गतिशीलवा का हास हो जाता है और परिणाम स्वरूप उनमें आगे बढ़कर कोई कार्य करने की प्रवृत्ति का मी हास हो जाता है। लोगों को घर में बैठे रहने की आदत पह जाती है और फलस्वरूप साहसपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति से हाथ था बैठते हैं, उनमे वह स्फूर्ति, सिक्रयता और साहस नहीं रहता जो देश की आर्थिक उन्नति के लिये प्रावश्यक होता है, और (३) सयुक्त परिवार में छोटे-छोटे मगडे पैदा होते रहते हैं, ईच्यां-हेष बढ़ता है और इसके फलस्वरूप सुकदमेवाजी भी हो जाती है जो कि अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होती है।

इधर कुछ वर्षों से अयुक्त परिवार प्रया विशृक्तित हो रही है। यद्यपि श्रमी भी यह परिवार-सगठन का प्रधान रूप है फिर भी समुक्त परिवार त्याग कर श्रलग रहने वालो की सख्या बढ रही है। (१) शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात युवक शहरी जीवन का अभ्यस्त हो जाता है और किसी कारखाने में नौकरी कर लेता है या है शहर मे व्यापार कार्य में लग जाता है ग्रौर उसे सयुक्त परिवार से पृथक होकर रहना पड़ता है, (२) जीवन-सवर्ष में वृद्धि होने से ग्रीर जीवन-निर्वाह के साधनों को जुटाने की कठिनाइयों से न्यक्ति संयुक्त परिवार के बन्धन से मुक्त होना चाहता है। ऋपनी पन्नी ऋौर बचा का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त रपया कमा लेना संयुक्त-परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त रपया कमा लेने से कहीं श्रिधिक सरल होता है, (३) जहाँ तक धनवान व्यक्तियों का प्रश्न है आय कर कानून श्रीर हाल ही में सम्पत्ति कर (estate duty) कानून बन जाने से संयुक्त-परिवार प्रथा टूटने लगी है। यदि संयुक्त-परिवार के कमाने वाले सदस्यों की आय आयकर के लिये निर्धारित न्यूनतम आय से कम है तो वह एयुक्त-परिवार से अलग होकर आयकर के बोक से बच सकते हैं परन्तु यदि साथ रहें तो सभी की आय जोड़ कर इतनी हा सकती है कि आयकर से मुक्ति न मिल सके। उदाहरण के लिये यदि एक परिवार में चार पुरुष है और वह कुल ६ हजार रपया प्रति वर्ष कमाते है तो उनको आय-कर देना पहेगा क्योंकि कानून के श्चनुसार हिन्द्-संयुक्त परिवार की ८४०० रुपया वार्षिक श्चाय से श्रविक श्राय पर श्राय-कर देना पदता है। परन्तु यदि चारो व्यक्ति संयक्त-परिवार से सम्बन्ध विच्छेदकर ले श्रीर श्रलग-श्रलग रहने लगे तो प्रत्येक चार हजार चपया वार्षिक कमा सकता है श्रौर उसे श्राय-कर भी नहीं देना पडेगा क्योंकि कानून के श्रनु-सार व्यक्तिगत आय ४२०० रुपया वार्षिक होने पर ही आय-कर लगेगा। इसी प्रकार सम्पत्ति-कर कानून के श्रन्तर्गत न्यक्ति गत रूप से एक लाख की सम्पक्ति

पर श्राय-कर की छूट प्राप्त है परन्तु सयुक्त-परिवार में प्रत्येक पुरुप सदस्य को केवल ५० हजार रुपये की सम्पत्ति पर ही सम्पत्ति-कर से छूट प्राप्त है, इससे श्रिषक की सम्पत्ति होने पर कर चुनाना पहेगा परन्तु यदि वह सयुक्त-परिवार से श्रालग हो जाय तो एक लाख रुपये को सम्पत्ति पर उसे कोई कर नहीं देना पटेगा। इसके श्राति कि कि की मृत्यु हो जाने पर यह समव है कि संयुक्त-परिवार को सम्पत्ति कर चुकाना पढे जब कि पृथम रहने पर ऐसा होना इतना श्रिषक सम्भय नहीं है। कर-सम्बन्धी यह कानून घनवान वर्ग की सयुक्त-परिवार प्रथा को तोड रहे हैं।

पचायत (Panchayat)—प्राचीन भारत मे पचायत अत्यन्त महत्वपूर्ण् सस्या थी जिसे प्रशासन, न्याय और राजस्व सभी अधिकार प्रात थे। परन्तु जैसे- जैसे समय बीतता गया आर्थिक परिस्थितियों मे परिवर्तन होने से तथा प्रशासन और न्याय के केन्द्रीकरण से पचायता का महत्व घट गया और कमश वह नगयय हो गयीं। देश के कुछ भागों में पचायने स्थापित रहीं परन्तु केवल एक सामाजिक सस्था के रूप में जहाँ लोग आपस में मिल सकते, गप्प कर सकते और हुक्का पी सकते थे और कभी कभी छाटे-मोटे कगड़े भी तय कर लिये जाने थे। परन्तु पचायत ने प्रशासन और न्याय के त्रेत्र में अपना प्रभावशाली रूप खो दिया।

परन्तु इघर कुछ वर्षों से महात्मा गांधी श्रार राष्ट्रीय काग्रेस के द्वारा इस व्यवस्था के प्रति विशेष कि दिखायी जाने के कारण पनायत-प्रणाली की पुनजीवन प्रदान किया गया है श्रीर पनायतों को कानूनी मान्यता श्रीर कुछ प्रशासन
तथा न्याय श्रिषकार प्रदान करने के लिए कुछ राग्यों ने श्रावश्यक कानून भी
बनाये हैं। परन्तु श्रव तक पनायतें सन्तापजनक नार्य नहीं कर पानी है न्योंकि
जिन लोगों को पनायतो का कार्य सौंपा गया है वह निरन्तर हैं श्रीर प्रशासन तथा
श्रदालत की कार्य-प्रणाली नी उनको श्रावश्यक जानकारी नहीं है, साथ ही
उनके पास धन का भी श्रमाव है।

पचायतों का कार्यचेत्र बढाने का प्रयत्न किया जा रहा है श्रीर उन्हें श्राधिक नियोजन का प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयत्न हो रहा है। स्विधान के ४० वे श्रमुच्छेट में कहा गया है कि राज्य प्राम पञ्चायतों की स्थापना करने श्रीर उन्हें त्वशासन की इकार्ड बनाने के लिए श्रावण्यक प्रधिकार दिलाने के सम्बन्ध में कार्रवाई करेगा। राज्य सरकारों द्वारा पञ्चायतों को कुछ प्रधिकार प्रदान किये गये हैं परन्तु यह उतने नहीं हैं जितने की सविधान में व्यवस्था की गई है।

जून १९५४ में शिमला में स्वायत्त-शासन मित्रयों का सम्मेलन हुया था जिसमें यह सिंपारिश की गई कि पचानतों को ख्रियक प्रभावशाली बनाने के लिए छिंदिक न्यापक द्याधिक, प्रशासकीय ग्रीर न्याय ग्रीधनार दिये जाने चाहियें।

यह सुक्ताव दिया गया कि द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में 'नीचे से ऊपर की श्रोर' योजना बनायी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और ग्राम को ही नियोजन की इकाई बनाना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जुलाई १६५४ मे त्रपने ग्रजमेर ग्रधिवेशन में इस बात पर विचार किया ग्रौर श्रनुमान है कि उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । योजना में यह व्यवस्था की गई है कि पञ्चायतों को स्वशासन को प्रभावशाली श्राधारभृत इकाई श्रीर नीचे से योजना बनाये जाने के लिए आबारभून एजेन्सी बनाया जायगा। एक गाँव सभा का निर्माण सारा गाँव करेगा और निर्वाचन के आधार पर आम पचायत बनायेगा जो गाँव समा की कार्यकारिणी होगी। पचायत को जो कार्य मौपे जायँगे उनमे लगान वस्ली, भूमि सम्बन्धी कागजात रखने (इन्दराज), समान उप-योगिता की सरकारी जमीन का प्रबन्ध, काशत के लिए लगान पर जमीन देना, बहुधन्धी ग्राम सहकारी समितियों का विकास करना और अपने अधिकार चेत्र के अन्दर सार्व-जनिक उपयोग के कार्यों के लिए सब से अनिवार्यत. कार्य करना आदि काय सम्मिलित हैं। प्राम के विकास की नीति पचायत निर्धारित करेगी, प्रोर भूमिन्न-रण, वनो के विकास, इवन के सुरिचत सृष्ट जमा करने, बॉव श्रीर जलाशय बनाने, वयस्क शिज्ञा, अञ्छे बीजों की पूर्ति, और काश्त के नये और सुधरे हुए उपायों को लागू करने की समस्याश्रों पर भी पचायत विचार करेगी श्रीर इस विशा में श्रावश्यक कार्रवाई करेगी।

दितीय पचवर्णीय योजना नीचे से ऊपर की स्रोर बनाई गई है। राज्य सरकारों ने एक-एक गाँव के स्रयवा गाँवों के समूहों के लिये जैमे तहसील, तालुका, विकास-पीली की इकाइयों के स्राधार पर योजना बनवाई है। इस कार्य में पचायतों ने बहुत महत्वशाली सहयोग दिया है पर यह कहना कठिन है कि स्थानीय योजनास्रों के बनाने में वे यथार्थ में कार्यशील रही हैं स्थीर ये स्थानीय योजनायें इस योग्य रही हैं कि उनको राज्य द्वारा बनाई योजना में सम्मिलित कर लिया जाता। जो कुछ भी हो पचायत के सदस्या को यह जान हो गया है कि द्वितीय योजना की सफलता के लिये उनके सहयोग की स्थावश्यकता है। इससे स्थानीय लोगो का उत्साह स्रवश्य बढ़ा है और वे योजना के प्रति जागरूक हो गये हैं।

सरकार की नीति यह है कि "प्रत्येक गाँव में ख्रोर विशेषकर उन चेत्रों में जो राष्ट्रीय विस्तार सेवाछ्रो छोर सामुटायिक विकास योजनाछ्रो के लिए चुने गये हैं एक कानून के छावार पर पचायत की स्थापना की जाय। प्रयम पचवर्षीय योजना काल में पंचायतों की सख्या ८२०८७ से बढ कर ११७५६३ हो गई। कृतिय योजना के कार्यक्रम के छनुमार १६६०-६१ तक ग्राम पचायतों की सख्या

वढ कर २४४५६४ हो जायगीं । यह सीचना युक्तिसगत है कि भविष्य में पचायतों को अधिका।धक महत्ता दी जायगी और वे योजना की कार्य रूप में परिणित करने का एक प्रभावशाली सावन हो जायंगी। परन्तु ग्रभी तक तो प्राम पचारतों का कार्य बहुत ही प्रसतापजनक रहा है। इसके श्रानेक कारण हैं जैसे (१) "प्रास पचायतों के प्रभावशाली न हो सकने का सतम बढ़ा कारण उनके पास साधन का स्रभाव रहा है। बहुत सी पचायतो की प्रति व्यक्ति वापिक ग्राय २ ग्रा० या ३ श्रा० रही है" । टेक्जेशन इन्यवायम कमीयन (१६५३-५४) ने छपनी रिपोट मे इस बात की श्रोर व्यान श्राकापत किया था कि पादेशिक सरकारें "पचायतो को कुछ वरों के लगाने का ऋघिकार दे कर उन्हें अपने श्राप श्रपनी सहायता करने के लिये छोड़ देती है। इसका परिसाम यह होता है ि प्राय पचायतें ब्रारम्म होते ही करों के ब्रारम्भ करन के कारण जनता की कापमाजन उन जाती है छोर यदि करो का छारम्भ न उरें तो नि। फ्रय हो कर जनता की द्दांप्ट में नीचे गिर जाती हैं"। इसालये पचायता के कार्य का सफल वनाने के लिये सबने श्राविक श्रावश्यक बात यह है कि उन्टे पयाप्त विच मटान िन्या जाय। (२) दूसरी कटिनाई यह है कि पचायता के ऊपर उनके साधनों श्रीर शक्ति की श्रपेला श्रत्यांवक कार्य भाग डाल दिया गया है। प्रादेशिक सरकारे जिन्होंने धचायता को श्रानेक उत्तरदाधित स्वाप असी है पचायती मे त्रावश्यम्ता से त्रावक भाशा करती हैं। हिस्ट्रिक्ट बोट जीर पचायती के हित भी श्रापस में टकराते हैं क्यों कि टानों के कार्य सेत्र एक दूसरे की सीमा का श्रावितमण करते हैं। इस सम्बन्ध में टेक्जेशन इपन्यापरी कमीशन ने यह िषकारिश की है।क ग्राधिक चेत्र ग्रीर उत्पादन सम्बन्धी वार्य को सहकारी समातयो द्वारा श्राधक श्रन्छी तरह किये जा सक्ते हैं। उन्ह नियामत रूप से पचायतों के श्रन्तर्गत श्राये हुए कायों से श्रलग नर देना चाहिये। इम इसे भी श्रावश्यक समसत है कि पचायतों के लिये नियमावली म टिये गये श्रसस्य कार्यों के स्थान पर थोडे ने चुने हुये कार्य ही दिये जार्ने ताकि उनका जिला बोर्ड तथा श्रन्य स्थानीय श्राम बोर्ड के कार्यों से सामजस्य सम्मव हो सके। (३) पैचायतों के मेम्बरों को उन कार्यों की काई शक्ता नहीं ामली है जो उनको दिये गये हैं। उनके विचार प्राचीन हैं, उधर उनके मन में स्थानीय कारणों से उत्पन्न द्वेप भावना भरी है, इसालये जो समस्यायें उनन सामने श्रज्ञान ग्राशज्ञा त्रोर जात द्वेप के कारस उपस्थित हैं उनको दृर करने के लिये उनके विचार मे वे ही पुराने टग आते हैं जिससे वे अपना कर्त्तव्य सतीयजनक टरा से पूरा नहीं कर पाते।

श्रध्याय ५

कृषि उत्पादन और नीति

मारत कृपि प्रधान देश है। भारत का कुल चेत्रफल श्रन्तिम गणाना के श्रनुसार लगभग ८१ करोड़ २० लाख ५० हजार एकड है, परन्तु श्राधे से बहुत कम भूमि कृपि के काम श्रा रही है।

पथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाने के पिहले ही योजना आयोग ने कुछ प्रदेशों मे पिछले ४० वर्षों में विभिन्न फरालो के उगाने में लगी हुई भूमि की जॉच की। इससे यह पता लगा कि (१) खेती की जाने वाली भूमि का चेत्र-फल उत्तर-प्रदेश को छोडकर कही भी विशेष मात्रा में नहीं बढ़ा। एक से श्रिधिक फ्रेंग्ले उगाने वाले चेत्र मे २०% को वृद्धि हुई, परन्तु यह वृद्धि बढती हुई जनसख्या की तुलना में नगरथ थी, (२) सिचाई का चेत्रफल १०% बढा जो कि मुख्यत. नहरों के विस्तार का परिणाम था, (३) पग्ती छोड़ी हुई भूमि का चेत्रफल १६२०-४० तक के ही स्तर पर रहा । उसके बाद कुछ वृद्धि रुई का उत्पादन करने वाले चेत्रों में हुई क्यों कि यकायक रुई उत्पादन चेत्र मे कमी आ गई श्रीर खेत परती छोड़ दिये गये। किस प्रकार की फसलें उगाने की प्रवृति प्राय. लोगो की रही, इसका योजना श्रायोग ने अध्ययन किया श्रीर इस परिगाम पर पहुँचे कि (१) पिछले १० वर्षों मे यद्यपि दुइरी फमल उत्पन्न करने के कारण फसलों के अन्तर्गत कुल त्रेत्र में वृद्धि हुई पर कोई भी नया भूमि का भाग खेती के कार्य मे नहीं लाया गया. (२) मूल्यों में परिवर्तन के कारण फत्तलों की किरम में परिवर्तन स्रा गया यद्यपि स्रधिकाश ये फसले छोटे-छोटे खेतो मे उत्पन्न की जाती थीं (३) खाद्यान तथा व्यवसायिक फसलों के बीच श्रदला-बदला किसी विशेष ढग पर नहीं हुई वरन् मौसम फसलो के हेर-फेर, मूल्य परिवर्त्तन और किसान की श्रार्थिक शक्ति पर निर्मर रही।

खाद्यान श्रीर कच्चे माल में कमी—यह श्राध्यर्य की वात है कि कृषि-प्रधान देश होते हुए भी भारत में खाद्यान की कमी है और उद्योगों के लिए कच्चे माल का श्रभाव है। इन श्रभावा के मुख्यत तीन कारण हैं: (१) १६३६ में प्रमा को भारत से श्रलग कर देने के कारण देश के श्रन्दर ही प्राप्त हो जाने वाली खाद्यान की मात्रा में १३ लाख टन की कमी हो गई, (२) १६४७ में देश-विभाजन हो जाने के कारण उस मात्रा में ७५ लाख टन की श्रीर कमी हो गई, (३) देश की जनसल्या प्रतिवप १ रे प्रतिसत की दर से बढ रही है, परन्तु खाद्यान की माना
में इसी दर से वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान का श्रमाव हो
गया। सन् १६४६ ५० में देश को ४६० लाख टन ग्रन्न की उत्पत्ति श्रीर सरमारी
गोदाम तथा विदेशों से मॅगाये श्रम को मिलाकर प्रति वयस्क १३७१ ग्रोस श्रम
प्रतिदिन पडता था। यदि जनसख्या श्रिषक होती तो प्रति व्यक्ति श्रम का भाग
श्रार भी कम होता। पीष्टिक पदार्थ सलाहकार समिति के विचारानुसार प्रति स्वस्य
व्यक्ति (वयस्क) १४ श्रास श्रम प्रतिदिन ग्रावश्यक है। उसलिए प्रथम पञ्चनपीन
योजना ने ७६ लाख टन श्रम की उपन बहाने का निश्रय किया था।

पोष्टिक पदार्थ मलाइकार श्रीमित के सुकाव के अनुसार सन्तुलित मोजन के लिये प्रत्येक न्यक्ति का ३ श्रीस टाल प्रतिदिन प्रानी चाहिये। १६५०-५१ में देश लाप टन दाल पेदा हुई, जिसमें से सरकारी स्टाक, बीज इत्यादि के लिय २० प्रतिश्वत निकाल देने क प्रश्नात् प्रति वयस्क को प्रतिदिन २१ श्रीस टाल मिली। इस प्रकार प्रथम पञ्चवर्षाय योजना के अन्तगत बढी हुई जनसङ्या के अतिरिक्त श्रावश्यकता ५ लाख टन की योर ३ योस प्रति न्यक्ति के हिसाब से ४० लाख टन की अनुमानित की गई थी।

१६५०-५१ म ५१ लाख टन तिलह्न की उपज हुई जिसमें से लगभग १६ लास ६० इजार टन तेल माप्त हुआ। साबुन, रग तथा वार्निश बनाने के काम में प्रयुक्त तेल को त्रालग करने क पश्चात् शेष १६ लाख टन तेल घरेलू कार्यों के लिए बचा। इसके अनुसार प्रति वयस्क को प्रतिदिन ०५ ग्रीस तेल मिला, जो श्रावश्यकता से बहुत कम था ग्रीर इसलिए उसकी मात्रा बढानी श्रावश्यक सममी गई। नहाँ तक क्यास का प्रश्न है, १९५० ५१ में २९ लाख ७० इजार गाँठो का उत्पादन हुआ (प्रत्येक गाठ का वजन ३६२ पोड) जर कि खपत ४० लाख ७० हजार गाँठों की थी। उत्पादन श्रोर खपत के इस श्रन्तर को प्रतिवर्ष लगभग इजार गाँठों का आयात करके पूरा किया गया। अनुमान लगाया गया है कि १९५६ में ५४ लाख गाठों की ग्रावश्यकता होगी। जुट के उत्पादन के विषय में सरकारी तार पर यह अनुमान लगाया गया है कि १९५१-५२ में ३३ लाख कच्चे जूट की गाँठों का उत्पादन किया गया। श्रीर मेस्टा (Mesta) की ६ लाख गाँठें पेदा की गई, जो जूट से घटिया किस्म की उपज है और जिसका उपयोग जुट न मिलने पर किया जाता है। श्रानुमान है कि १९५६ में ७२ लाख गाँठों की त्रावश्यकता होगी। इस प्रकार माँग श्रीर पृर्ति में 33 लाख गांठों का श्रन्तर रह गया।

इस अध्ययन से यह प्रकट होता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना के भ्रारम

में खाद्यान श्रोर उद्योगों के लिए कच्चे माल ढोनों का ही श्रमान था। भारत को स्वावलम्बी बनाने श्रोर विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए यह निश्चित किया गया कि देश के श्रन्दर ही इनका उत्पादन बढाया जायगा। यदि समस्या केवल खाद्यान्न या न्यवसायी फसलों की पूर्ति की मात्रा बढ़ाने की होती, तो इसके लिये घीरे-धीरे एक फसल की जमीन को दूसरी फसन के उत्पादन के लिये न्यवहार में लाया जा सकता था। परन्तु समस्या दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने की थी, जिससे माँग श्रीर पृति के बीच का भारी श्रन्तर दर किया जाय।

खाद्यात्र जॉच कमेटी की रिपोर्ट-कमेटी, जिसके श्रन्यज्ञ श्री श्रशोक मेहता थे तथा जिसने नवम्बर १९५७ में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस निष्कर्ष पर पहुँची कि खाद्यान की कुल उत्पत्ति १६५३-५४ के ६८८ ७ लाख टन से घट कर १६५४-प्य में ६७१'१ लाख टन तथा १९५६-५७ में ६५२'६ लाख टन हो गयी। इसके ग्रनन्तर प्रवृत्ति मे परिवर्तन हुन्ना श्रीर १९५६-५७ में खाद्योत्पादन बढकर ६८६**-**९ लाख टन हो गया। खाद्यात्र के मूल्यों एवम् खाद्य सामग्री के श्रमान की वृद्धि निम्न कारणों से हुई। (1) कुषकों ने अपनी उत्पत्ति का अधिक भाग स्वय रख लिया । अतएव मूल्यों की वृद्धि में जितना विकीत-अतिरिक्त (marketed surplus) की कमी का हाथ या उतना उत्पादन की कमी का नहीं था। १९५५-५६ में मोटे अनाज (millets) की उत्पत्ति मे ३० लाख टन की कमी हुई जिसने मूल्य वृद्धि का क्रम प्रारम किया श्रीर १६५५-५६ में चायल तथा गेहूँ की मॉग बढने के कारण खाद्यान के मूल्य वहने लगे। यद्यपि बाद मे उत्पादन बह गया किन्तु मूल्यों में फिर भी वृद्धि होती रही। (11) द्वितीय योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय तथा बैंक उदार की वृद्धि ने भी मूल्य-स्तर के बढ़ाने में मदद की, तथा (111) "खाद्य स्यिति के बारे मे अत्यधिक आशावादिता ने अनेक राज्यों में खाद्यात्पादन की वृद्धि के प्रयक्तों को या तो शिथिल कर दिया या उनमें तीवता नहीं आने दी"।

भारत की जन सख्या की प्रतिवर्ष १३ - २ प्रतिशत वृद्धि के आधार पर कमेटी ने अनुमान लगाया कि खाद्याओं की मॉग में बहुती हुई जनसख्या के कारण १०% तथा आय की वृद्धि से ४.७ प्रतिशत वृद्धि होगी। इस प्रकार द्वितीय याजना में खाद्यानो की मॉग १४३ से १५ प्रतिशत तक बढ जायगी अर्थात् १६५५ ५६ में ६६० लाप टन से बढकर १६६०-६१ में ७६० लाख टन हो जायगी जबिक उत्पत्ति में केवल १०३ लाख टन की वृद्धि की आशा की जाती है जिसके फलस्ररूप १६६०-६१ तक उत्पत्ति बढकर ७०५ लाख टन हो जायगी। कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कुछ आगामीवर्षों में प्रतिवर्ष २०-३० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना आवश्यक होगा।

कमेटी ने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में मूल्य-स्पायित्व (price stabilisation) की नीति की विकारिश की। (1) इस हेतु उन्होंने उन्चाधिकारों से युक्त 'मूल्य-स्थायित्व परिपदं (Price Stabilisation Board) की नियुक्ति प्रस्तावित की जिसके कार्य महत्रनीति का निर्वारण तथा उमे लागू करने के उपायों का निर्णय करता था। (11) नीति को कायान्त्रित करने के लिए खाद्यान्न त्यापित्व सगठन (Foodgrains stabilisation Organisation) के निर्माण की भी िकपरिश की गई। यह सगठन खाद्य थ्रोर क्रांप मत्रालय का एक विभाग हो सकता है ना एक परिनियत निगम (Statutory corporation) यथवा स मित दायित्व वाली क्म्पनी का रूप भी ले सकता है। यह सगठन खाद्याल वाजार में एक व्यापारी की मौति काम करेगा श्रीर अन्त स्थ-स्यन्ध (bufferstock) का काम करेगा अर्थात मुल्य भारने पर खरीदेगा जो और बहने पर वेचेगा । (111) खाद्य मत्रालय तथा मुल्य स्यानित्व परिपट की सहायना के लिए केन्द्रीय खाद्य परामर्श समिति (Centralfood Advisory Council) के निर्माण की भी खिकारिश की गई। (vi) प्रसमानुकृत एवम् विश्वासनीय आँकडे एकत्र करने के लिए मूल्य-जानकारी-सैभाग (price Intelligence Division) की स्थापना की भी सिफारिश हुई। परामर्श समिति तथा जानकारी सभाग की सहायता से मूल्य-सामयित्व परिषद का उद्देश्य मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर सतर्कता वरतने तथा समय समय पर न केवल सामान्य मृल्य न्तर के त्थिर बनाये रखने वरन् विभिन्न वस्तु ग्री के मुल्यों में ग्रानु चित श्रन्तर को रोकने के लिये श्रावञ्यक कार्यावाही की विफारिश करना या।

इस बात को न्यान में रखते हुये कि वर्तमान परिस्पितियों में स्वतन्न व्यापार अवाछनीय है तथा पूर्ण-नियन्न (Full fledged Control) आर्थिक एवम् प्रशा- छनीय कठिनाटयों से भरा है, कमेटी ने एक मध्य-मार्ग की सिफारिश की जिसके अतगत नियन्न का कट्रील खुले बाजार में खाद्याक के कप विक्रय तक सीमित रहेगा, थोक व्यापार का अशत. समाजीकरण होगा, अनुजा (License) द्वारा शेष बाजार में कार्यशील व्यापारियों पर नियन्न होगा, गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक रखा जायगा तथा अन्य प्रक साथ सामनी के उपमोग और उत्पादन की वृद्ध के लिये प्रचार का सगठन किया जायगा।

जत्पादन मृतृत्ति—स्वतन्त्रता प्राप्त होने के उपरात भारत में खाद्यान्न श्रौर श्रन्य कृषि-सम्बन्धा कच्चे माल के उत्पादन में कभी श्रा गई है। १६५० ५१ में पाद्यात्र का उत्पादन ५०० लाख टन हुश्रा, जबकि १६४६-५० में इनका उत्पादन ५४० लाख टन हुश्रा था। कृषि-सम्बन्धी कच्चे मालों की उत्पादन प्रवृत्ति थोडी भिन्न थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के तुरन्त बाद उत्पादन में कमी आ गई, किन्तु तत्पश्चात् उसमें फिर वृद्धि हो गई। १६४८-४६ में तिलहन का उत्पान ४५ लाख टन, कपास का १७ लाख ७० हजार गाँठो और कच्चे जूट का २० लाख ७० हजार गाँठो तक ही घटकर रह गया। गन्ने का उत्पादन भी कम होकर ४८ लाख ७० हजार टन ही रह गया। किन्तु अगले वर्षों में इन कच्चे मालो के उत्पादन में वृद्धि हुई और १६५०-५१ में, जब कि खाद्यान का उत्पादन गिरता जा रहा था, उनकी उपज बहनी प्रारम्भ हुई।

'श्रिधिक-प्रज्ञ-उपजात्रो' श्रान्दोलन के बावजूद खाद्याज के उत्पादन में कमी श्राई। बहुत समव है कि खाद्याच उत्पादन के सरकारी श्राँक दे बिल्कुल सही न हो। परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सही श्राँक दे चाहे कुछ भी हों, श्रनेक कारणों से खाद्यान्न का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में काफी गिर गया:

- (१) देश के कुछ भागों में सूखा पहने और कहीं-कही बाढ श्रा जाने से खाद्यान्न के उत्पादन में श्राशिक कमी श्रवश्य हुई है, परन्तु केवल प्रकृति का कीप ही उत्पादन की गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- (२) यह भी सुकाव दिया गया है कि क्रिय-सामग्री की ऊँची कीमते भी कुछ अश तक क्रिय-उत्पादन घटने का कारण हैं। साधारण रूप से अधिक कीमत का अर्थ है अधिक उत्पादन, परन्तु जहाँ तक किसान का सम्बन्ध है आय की लोच (Elasticity) ऋणात्मक (negative) है। इसका तात्पर्य यह है कि किसान कुछ आय चाहता है और जब कीमतें अधिक होती हैं तो वह थोड़ा सा उत्पादन करके उसे प्राप्त कर लेता है, किन्तु जब कीमतें कम होती हैं तो उसे अधिक उत्पादन करना पड़ता है। इसिलये जैसे हो खाद्याल की कीमतें वहीं, उसने अपना उत्पादन कम कर दिया। चूंकि कीमतों और उत्पादन के पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तारपूर्वक अध्ययन नहीं किया गया है, इसिलए यह कहना सभव नहीं है कि यह सिद्दान्त भारत में कहाँ तक लागू होता है।
- (३) खाद्यान्न के उत्पादन में कमी श्राने का एक कारण यह भी है कि गन्ने, रुई श्रीर जूट की श्रविक श्रावश्यकता होने के कारण खाद्यान के उत्पादन में प्रयुक्त भूमि के कुछ भाग में श्रव व्यवसाई कसले वोई जाती है।

मारत-सरकार के 'अधिक-अन्न-उपजाश्रो' श्रान्दोलन से खाद्यान की कमी
पूर्ति करने की जो श्राशा की गई थी, उसमे श्राधिक सफलता नहीं हुई क्योंकि
(श्र) इस श्रान्दोलन में पहले से ही काश्त की जाने वाली जमीन में उत्पदन
बढाने की श्रपेद्या नयी भूमि को खेती के योग्य बनाने पर अधिक जोर दिया गया।
यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी श्रोर इससे निकट मिक्ष्य में उत्पादन बढाने की

श्राशा नहीं की जा संक्षी थी। 'प्रधिक-श्रव उपवाश्रा' श्रान्दोलन की नीति मे परिवर्तन कर एव श्रहपकालीन पोलनाओं पर जीर दिया गया है, जिसके सम्तर्भत सामान का उपादन बढ़ाने के लिए गीन थीर साद दी नाती के चीर साम ही साथ मिचाई की भी व्यवस्था था जानी है। प्रार्टन म यह श्रान्दोलन देग के उन भागा में चलाया गया था जहां विचाई की मुविधाएँ नहीं थी श्रीर इसितिए सन्तोपजन र परिसाम नहीं निक्ले। बाह पी नीत बहल दो गई श्रार वातनाश्रा को उन्हीं स्थला पर चलाया गया है जहाँ सिचाइ यो मुस्थि पहल ही मायी या सरलता से ज्ञावरपकतानुसार व्यवस्था की जा साती थी। इसमा परिगाम पह निक्ला कि 'ब्रधिक व्यस उपनाप्राः' प्यान्टोलन म सन्तोपलनक प्रगति हुई, (ब) यह 'प्रत्यन्त रोड का विषय है कि 'ग्रायिक-ग्रज्य-उपनाग्री 'ग्रान्नोरान का काव मार जिन ग्राधिकारियों को सावा गया है वह सर्वव ईमानदारी ग्रांग रागन से कार्य नहीं करते है। बहुत सी बातों में काम कुछ नहीं किया जाना, फैनल कागजी खाना पूरी कर दी जाती है छीर प्रतुत बार एसा भी होता है । क ो बीज या खाद प्रादि किसानों को मिलनी चाहिए था, उने या की बेच दिया गमा या उत्तका रुपया स्वय रख लिया गया। इस प्रान्दालन म या किछी भी नियोजन के अन्तर्गत याजना को सुवाद रूप में पार्यात्यत उनने ने लिए एक ऐसे सगटन की ग्रावश्यकता है जो कि सुसगीटत हो ग्रांर जिसके यमचारी पूर्णर प ने ईमान-दार हां. (स) रिसानों ने भी 'श्रधिय-श्राय-उपजाश्रो 'श्रान्दालन को उतना सहयोग नहीं दिया जितना उनसे आशा की जाता वी।

रेह्यप्रभ्य श्रीर रेह्यप्रभइ में हुई उत्पादन की थोड़ी खी वभी को छीड़ कर रह्य के उपरान्त खायान के उत्पादन में क्लोपननक वृद्धि हुई है। रह्य ०- पर में भारत में सायान का उत्पादन ४०० लाख दन था जो रह्य २-४४ में ६८० लाख दन हो गया। उनसे श्रीक वृद्धि चानल के उत्पादन में हुई श्रीर इसके बाद कमशाः गेहूँ, नाजरा, त्यार श्रीर जी की उपन बढ़ी। गायान के उत्पादन में यह वृद्धि इन कारणी से हुई, (१) मीसम की श्रमुक्त परिक्रिपतियाँ, (२) रह्य ० पर में पारम किए गए सब्दित उत्पादन पर्यक्रम (Integrated Production Programme) की समलता, (३) चानल उत्पन्न करने की जापानी पद्धि का प्रयोग, सिचाई की श्रीक मुंच्याएँ श्रीक किसानी को श्रायिक सहायता के रूप में रासायनिक साद (Fertilisers) श्राटि देना।

१६५४-५५ तथा १६५५-५६ में उत्पादन घटकर क्रमश ६७११ लाख टन तथा ६५२६ लाख टन होने के कारण (1) देश के कुछ भागों म सूखा, (11) उर्वरक तथा श्रच्छे वीनों का श्रभाव तथा (111) राज्य सरकारों द्वारा प्रयहों मे दिलाई देना था जो अशत. उनकी लापरवाही तथा अशत दितीय योजना के खायान की उत्पत्ति और कृषि पर अपर्याप्त त्यान देने के फलस्वरूप हुई। १६५६ ५७ में उत्पादन के ६८६.६ लाख टन तक बढ़ जाने के बावजूद भी पिछले दो वपों में उत्पादन के गिरने से मूल्य बढ़ गये जिसके फलस्वरूप सामान्य व्यक्ति को बड़ी विटनाई का समना करना पड़ा। खायान का श्रायात, जो १६५१ के ४७ लाख टन के ऊँचे स्तर से घटकर १६५४ में ८ लाख टन तथा १६५४ में ७ लाख टन हो गया था, पुन १६५६ में बढ़कर १४५ लाख टन तथा १६५७ में ३७ लाख टन हो गया।

कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति कुछ भिन्न ही रही है। १९५२-५३ में कई और जुट का उत्पादन पिछले वर्ष के ही स्तर पर (३२० लाख और ४६० लाख गाँठ कमशा.) रही पर तिलहन और गन्ने की उपन कमशा: ४७ लाख टन और ५० लाख टन हो गई। अगले वर्षों में जुट की छोड़कर इन सभी १९५६-५७ में अनुमान किया जाता है कि तिलहन ६० लाख टन, कई ४७५ लाख गाँठ जुट ४२५ लाख गाँठ और गन्ना ६५ लाख टन होगा।

प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रान्तर्गत—प्रथम पचवर्षाय योजना का ध्येय पाद्यान तथा उद्योगों में काम श्राने वाले कच्चे माल की उत्पत्ति इस दृष्टि-कोण से बढ़ाने का था कि (१) देश श्रात्म निर्मरता प्राप्त कर ले, (२) मारतीय उद्योगा को माँग पूरी हो सके श्रार (३) प्रति व्यक्ति श्रान्त का उपभीग बढ़ाया जा सके।

प्रथम पन्ववर्षीय योजना के लच्च

वस्तुये	ग्राधार माने हुये साल में उत्पत्ति	प्रस्ताथित घतिरिक्त उत्पत्ति	प्राप्त कर लेने	ग्राधार माने हुये वर्ष भी तुलना में प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान	५४० लाख टन	७६ लाख टन	६१६ लाख टन	१४
तिलइन	५१ लाख टन	४ लाख दन	५५ लाख टन	7
गन्ना	५६ लाख टन	७ लाख टन	६३ लास टन	१३
(गुड़) रुई	२६ लाख गाँठें	१३ लाख गाँउँ	४२ लाख गाठे	ጸቭ
जूट	३३ लाख गाँठें	२१ लाख गाँठे	५५ लाख गाँठें	६४

[्]रपांचाक्रों के लिए ग्राधार वर्ष १६४६-५० है ग्रीर ग्रन्य के लिये १६५०-५१ है।

खाद्यान में प्रस्तावित ७६ लाख टन की वृद्धि में से ४० लाख टन चावल, २० लाख टन गेहूँ, १० लाख टन चना और अन्य दालें और ५ लाख टन में अन्य अन्न हैं। जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है। उपन ६५० लाख टन हुई। (प्रनाय ६१६ लाख टन के जो कि लक्ष्य था) गेहूँ, चना और टालों के उपन की माना प्रस्तावित लक्ष्य से अधिक बढ़ गई है परन्तु चावल की उपन पिछले वर्ष में बढ़ने के पञ्चात् १६५४ ५५ में बाढ़ आदि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण घट गई। यह कमी ससार के सभी चावल उत्पन्न करने वाले देशों में हुई थी। पर १६५५ ५६ में किर उत्पत्ति कुछ बढ़ी। व्यवसायिक फसलों में से तिलहन और कई की उत्पत्ति योजना के अनुकूल बढ़ी पर जुट और गन्ने की उपन में कमी हुई।

प्रथम रोजना के काल मे अन की उत्पत्ति में वृद्धि सिंचाई की सुनिघाओं के बहने, पाट के प्रयोग म आधिक्य और वेकार भूमि को खेती के काम में लाने के लिये फिर से अधिकृत करने के कारण हुई, परन्तु यह बता सकना कठिन होगा क विस कारण से कितनी वृद्धि हुई है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—न्यिप दिवीय योजना नें उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है पर कृषि के प्रति उदावीनता नहीं दिखाई गई है। दितीय योजना में इस बात पर ध्यान रक्खा गया है कि प्रथम योजना के कार्य में विकास हो और कृषि उत्पत्ति तथा कच्चे माल की उत्पत्ति में हमारा देश यथासम्भव आत्मिनर्भर हो जाय। दूसरे, यह अब अच्छी तरह समक्त में आ गया है कि खेती का चेत्रफल बढा लेने मात्र में ही उत्पत्ति में आवश्यक वृद्धि न हो सकेगी। अन्त में यद्यि खायाल की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है पर दूसरी योजना में उन वस्तुओं की सख्या काफी वड़ी है जिनकी उत्पत्ति बढ़ाने का ध्येय है। ऐसी वस्तुओं में चान, काली मिर्च, लास, नारियल, वृक्कफल, सुपाड़ी मो सम्मिलित हैं। इससे भारतीय किसानों की उन्नति में ।स्थरता और विदेशी विनिमन से अधिक आय प्राप्त होगी।

यदि वर्तमान टर से ही श्रन्न का उपमाग चलता रहे तो योजना श्रायोग के श्रनुसार वढी हुई जनसंख्या को ७०५ लाख टन श्रन्न की श्रावश्यकता होगी परन्तु प्रति व्यक्ति श्रन्न का उपयोग १८३ श्रांस प्रतिदिन कर देने का विवार है, इसिलये कुल श्रन्न की श्रावश्यकता ७५० लाख टन होगी। इसी ग्राधार पर द्वितीय पचवर्णीय योजना में १६६०-६१ तक १०० लाख मेन की उपज बढाने का निश्चय किया गया। ग्रन्न की इस वृद्धि में चावल की ३० से ४० लाख टन, गेहूं की २० से ३० लाख टन, श्रौर श्रन्य श्रनों की २० से ३० लाख टन, श्रौर श्रन्य श्रनों की २० से ३० लाख टन श्रौर दालों की १५ से २० लाख टन वृद्धि सोची गई है। बाद मे ऐसा प्रतीत हुश्रा कि खाद्यान के

जान न के केवल उत्पत्ति न माना ही। यदि सनी मिन भगपर काम गरे तो उत्तर लगभग ७२ लाग जुड़ का बिटों हो न्यान्य क्रम होगी। इसक प्रतितिक १५०,००० गिंठ नित्र नामा के तिरे नादिते। (in) में ते ता ते गृह का उत्तर्व दन बढ़ा देने पर यह सम्भव हो करेना हि प्रांत जनमा प्रतिदेन १९०६ जीम का उपयोग वर सकेना। (iv) मानु की मान्यती के माना सम्भाह की इपर कई नमी ने उपन बड़े निम्मरादि की हुइ है जिस्त कारण उमकी जिता के दर्जा दामा पदी। इससे गोडामों में तन्याह तकाह करा के पर बढ़ जाने के कारण उमका मूल्य किर गया। इसलिये दिती जाना । उत्तर कार्य कि या साह के उत्तर पर जी दिशा गया है, न कि उत्तर हो के माना की वृद्धि पर।

वादान नीति

मूल्य नीति—पापानन व सम्बन्ध में सरवार की नीति है कि (१) भारत की सायानन वे सम्बन्ध में स्वावनलम्बी प्रनापा जाप, (२) प्रय नक त्यभाग की स्थिति रहती है तब तक सायानन क मूल्या और किल्या कर नन्यं पर असे पायान प्रया पाया, जिसमें उपभोक्ताश्चों की किल्नाई दर का पूर्वर पर्दी पर समा है देश के सभी भागों में समान प्राधार पर सभी की स्वायान मित्र सदे, प्रीर (३) किलान की उसके उत्पादन का उसित नूल्य बास ही सहे।

पचवर्षाय योजना मे पह टाय ही महा नया है वि "नूर्य " बढ्रेन-पटनै में खाद्यान्न पर प्रमुख रूप में प्रमान पड़ता है। याद मूहव पर नियमण राजना है ता यह क्यातस्यक है कि सायान्त हा भार पर स्तर रता अस सी देश की गरीब जनता की पहुँच के बाहर न हो। सारत ना उर्तमान स्थिति स पत्ट पालास्त की पूर्ति में योदी भी कमी श्राहे, तो भाग श्रपेसाहत श्रिषक चट्ट जायेंगे। गायान्त का मात्र बढ़ जाने से रहन-ग्रहन का रार्च बढ़ जाता है फ्रींग उत्पादन व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। इचलिए ऐसी नीति विसमे सभी त्रीर भाग बह ारे त्रीर रुपया लगाने का पार्यक्रम ही ठप हो जाय, उत्पाटक रे लिए पिछी भी स्व म लामदाक नहीं है। इस नारण छात्रान्न नीति निर्धान्ति करते समग इन समी वार्तो पर विचार करना आवश्यत है।" श्राहचर्य की बात है कि याजना श्रायाग द्वारा इस सही सिवान्त का प्रतिपादन किए जाने के बाद भी भारत सरकार की नीति इसके विल्कुल निषरीत है। सामान्न के भाव की रनी गए हैं, जिसस उपभोक्ताश्चों को कठिनाइयों का सत्मना करना पड़ा श्रीर उपलों के उत्पादन-व्यय में भी वृद्धि हुई। साद्यान्न ऊँचे भागों के समयन ने यह कहा गया है कि (१) यदि खाद्यान्न के भाव गिराए जार्ये तो किसान खाद्यान्न के स्थान पर गन्ना, क्रपास स्रोर जुट बोयेगा, जिनके भाव अपेज्ञाकृत श्रविक ऊँचे हैं। किसान स्वभा- नतः ही इन ऊँची भीमतों की ब्रार श्राकृष्ट होगा, श्रीर (२) खात्रान्न के भाव केवल भारत में ही ऊँचे नहीं हैं, बिल्क यह स्थिति खारे विश्व में है। जब तक विश्व के श्रन्य देशों में छात्रान्न के भाव नहीं गिरते हैं, तब तक देश में खाद्यान्न का श्रभाम होने के नाग्ण भाव नम नहीं किए जा सकते हैं।

इन नवीं में सत्य का श्रश बहत श्रधिक नदी है। प्रथम तर्क के सम्प्रन्य में यह ध्यान देने याग्य बात है कि गनने, क्यास और जूट की कीमत श्रधिक इमलिये है उयाकि सरकार ने इनकी कीमत केंची दर पर निश्चित कर रखी है। यदि छारम से ही व्यवसायी फमलो जार खाजारन के मूल्यों में कुछ सम्बन्ध निश्चित किया गया होता तो इस मकार की गरबही कभी नहीं होती। जैसा कि पहले कहा जा सका है सुपिसामग्री के सम्बन्ध में मूल्य चौर उत्पादन में उल्टा सम्बन्ध होता है। यहि न्यवसायो-फसल ग्रोर पायाच होनो के मूल्य रस रखे जाते तो होना के उत्पादन में युद्धि होती । परन्त सरकार द्वारा व्यवसायी-फराल का माव केंचा कर दिए नाने से सारी स्थित ही पटल गई स्रोर काफी स्रति पहुँची। इसका स्रव एक यह उपाय हैं कि कपास, जूट, गरने इत्यादि के मूल्य कम किए जार्ये। इससे दो लाम होगे . (१) उद्योगो का उत्पादन न्यय कम होगा और (२) खाद्याल के माव घर जायेंगे। नहीं तक तुनरे तर्क का सम्पन्ध है, मारन में खात्रान का भाव इसलिए जेंचा नहीं है कि विश्व के बाजारों के माब भी कॅचे है। उसका कारण तो यह है कि मारत का उत्पादन बहुत कम है। कुछ नमय पूर्व भारत मे खाद्यान का भाव विश्व-बाजार के मान की अपेचाकृत कहीं अधिक था। यदि यह तर्क सही है तो उस रमय भारतीय कीमतों को इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए था। भारत मे ऊँची कीमता की समस्या केनल दो उपायों से हल की जा सकती है-या तो उत्पादन बहाया जाय ग्रायात में वृद्धि की जाय । क्योंकि ग्राधिक व्यय होने के कारख खायान का अधिक आयात कर सकना समय नहीं है, इसलिए सबसे उपयुक्त विधि यही है कि देश में उत्पादन की वृष्टि की जाय। यदि खाद्याच ग्रोर व्यवसायी फरलों के लिए प्रयुक्त भूमि में पति एकड़ का उत्पादन बढाया नाय. तो दोनों फसलों का उत्पाटन बढ़ाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक फसल बोई जाने वाली जमीन पर दुसरी फराल बोई जाय । सिंचाई की व्यवस्था, अच्छे बीज श्रीर श्रधिक पाद के द्वारा प्रति एकइ उत्पादन बढा सकना समव है।

हितीय महायुद्ध के उपरान्त सबसे पहले १९५४ के मध्य में सरकार का ध्यान इस छोर आकर्षित किया गया कि वह ऐसी नीति कार्यान्यित करे जिससे 'किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके'। पिछले वर्षों में साद्याज के मूल्य ष्राधिक थे और सरकार उन्हें नियन्त्रित करने में प्रयमशील थी। किन्तु जन जुलाई १९५४ में नई कमल तेयार टोनर वाजार मे प्राई, तो पनान मे गेहूं का माव १० रुपए प्रति मन से भी कम हो गया। धपुर श्रादि उत्तर-प्रदेश को भी कुछ महिया में नेहूँ लगभग १० क्यया प्रति मा के हिसाव से क्रिक्ने लगा। मूल्यों में यह गिरायट उसलिए प्रार्वे कि (१) गे हैं उत्पन्न करन वाले श्रिधिकाश चेत्रों में पिछले वर्षों की अपेदाकृत अविक उत्तादन हुआ, (२) कर-सिक्त कम हो जाने के कारण बहुत से लोगों ने गेडू का उपयोग वरना बन्द कर दिया, निसके फलस्वरूप उसरी माँग में कमी आ गई, (३) यातायात के गायनों की अधिक सुविधाएँ प्राप्त न होने के कारण पह समय न था कि जिन नेवां में गेहैं का उत्पादन होता है वहाँ से वह उन रेन्डों को शीवतापूर्वर भेजा जा सके जहाँ उत्तरी खपत होती है। फलन मिडिया में उत्तरा माव गिर गया, योग (४) जिन श्रन्तराष्ट्रीय परिस्पितियों न नेहूं के भाव न। गिराने में सहायता ही, उनके पीछे एक मनावैज्ञानिक कारण भी या श्रोर वह यह कि विश्व भर में गेहूँ की पृति वह गई थी और उसक मूल्य में क्यी था गड़ थी। इस सकट को दृर करने के लिए पजाव सरकार ने स्वय १० वपया प्रति मन के हिसान से कुछ गेर् खरीदा । उत्तर-प्रदेश सरकार भी ऐसा ही करने के लिए तेयार थी, किन्तु कालान्तर में मूल्या मे वृद्धि हो जाने पर सरकार ने गेहूं परीटना ग्रमापश्यक सममा। जब कि गेहूँ श्रोर चने के मूल्य मे अत्यधिक नीचे गिरने नी प्रश्ति दिवाई पड़ने लगी तम चुनी हुई वस्तुम्रों के मूल्यों की सहापता देने की नीति (Selective price support policy) का अनुसरण किया गया और अप्रैल १६५५ में नेहूं, जुन में चना और अगस्त मे चावल इसके अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गरे। जुलाई १६५५ से खायात्रा के मूल्य ग्राविकार के नाहर जाने लगे क्यांकि बाढ ग्रावि प्राकृतिक प्रकोषा के कारण खरीफ की फसल बिलकुल नष्ट हो गयी थी। सरकार की मूल्य स्थिर रखने की नीति के काग्गा थोडे समय के लिये जन्न की पूर्ति में कमी आ गयी श्रीर जनता की घारणा कुछ ऐसी हो गई कि मूल्य वह गया।

यदि खाद्यान या उत्योगा में प्रयुक्त होने वाले कन्ने मालों के मूल्यों के एक निश्चत सीमा से श्रायक कमी हो जाय, तो उनका सरकार द्वारा खरीदना उसी मीमा तक उचित होगा जहाँ तक उससे किसानो का मला होता है, क्योंकि उनके दिनों को सुरक्तित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना श्रीमकों या उपमोक्ताश्रों के हितों की रज्ञा करना । किन्तु इस नीति से कई हानियाँ हैं (१) यदि मूल्य वरावर गिरते गए तो सरकार को मारी ज्ञित उठानी पड़ जायगी, (२) समय है कि सरकार जमा किए हुए गल्ले को वैंच न सके श्रीर उसे पर्याप्त समय तक स्टाक में ही रखना पढ़ेगा, श्रीर (३) यदि सरकार किसी ग्रानाज को एक ही मान पर

र्वेचने के लिए जोर देती है तो धामान्य मूल्य स्तर में कृत्रिमता उत्पन्न हो जायगी।
यदि कृषि सम्बन्धी उत्पादन का मूल्य गिर जाता है तो इसके फलस्वरूप श्रम्य
कोमतों में भी कमी श्रा जायगो। इस प्रकार क्रय-शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण
किसानों को तो लाभ होगा ही, उसके श्रातिरिक्त सम्पूर्ण श्रापिक व्यवस्था भी
लाभान्वित होगी क्योंकि खाटाच की कीमतों के गिर जाने से सामान्य मूल्य-स्तर
निश्चित रूप से कम हो जायगा।

नियन्त्रण (Controls)—वरकार की प्राचानन तथा श्रन्य वामिश्रयों पर नियन्त्रण लगाने की नीति की उण्योगिता पर बहुत विवाद चला था। नियत्रण लगाने का समर्थन करते हुए कहा गया है कि (१) गरीव जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ब्रौर अभाव अस्त च्रेत्रों को खाद्यान्न भेजते रहने के लिए सरकार द्वारा नियत्रण लगाना आवश्यक है। नियत्रण न लगाने से खाद्याल की कीमतें बढ़ेंगी श्रोर इससे निर्धन जनता को श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पडेगा, (२) योजना की सफलता के लिए नियत्रण श्रावश्यक है, क्योंकि नियोजन श्रोर विनियन्त्रण (De-control) साय-साथ नहीं चल सकते हैं। किन्तु इन तकों में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि स्वय नियत्रण लगाने से ही श्रभाव की स्थिति पेदा हो जाती है। यदि नियत्रण इटा दिया जाय तो बहुत समय है कि गल्ले इत्यादि के छिपाकर रखे गए स्टाक खुले बाजार में श्राने लगें श्रौर उनके वितरण में सुघार हो जाय जिसके फलस्वरूप श्रभाव की स्थिति भा द्र हो जाय। चॅिक खाद्यान क वही श्रांकिट प्राप्त नहीं है, इवलिए की कमी की मात्रा का ठीक पता चला चकता कठिन है। यह कहा गया है कि जिन श्रिधिकारियां पर खाद्यान्न-नियत्रण लागू करने का उत्तरदायित्व है वह श्रिभाव को श्रावश्यकता से अधिक ऑकते हैं जिससे वह काफी समय तक उस पद पर कार्य कर सके। यदि नियत्रण इटा दिया जायगा तो यह कृत्रिम स्थिति स्वय दर हो जायगी। जहा तक नियोजन का प्रश्न है, यह सच है कि विदेशी ज्यापार श्रीर विदेशी पूँजी पर कुछ सीमा तक नियत्रण रखना आवश्यक है, परन्तु यही तर्क खायान-नियत्रग पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह श्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस तर्क का कोई महत्व नहीं है कि योजना की सफलता के लिए नियत्रण का होना आवश्यक है।

यदि नियत्रण कुशलता पूर्वंक लागू िकए जाते श्रीर उनको प्रभावशाली बनाने के लिए कडे उपायों को श्रपनाया जाता तो स्पिति में सुधार होना सैमव था, परन्तु भारत में नियत्रण जितनी श्रिषक कठिनाइयाँ इल नहीं कर पाते उससे कहीं श्रिषक कठिनाइयाँ पेदा कर देते हैं। उपभोक्ताओं, ज्यापारियां श्रीर दुकान- टारां सभी को ग्रनेक फठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। यदि नियत्रण लाग् न हो ता विशेष हानि नहीं होती है, परन्तु वदि लागू करके भी उनका कुणलता पूर्वक सचालन न किया जाप तो सुविवा की श्रपेचा कप्ट श्रधिक बढ जाता है त्रोर हानि मी होती है। यदि उस प्रकार के नियत्रण को हटा दिया जाय तो निश्चन ही स्थिति म सुनार होगा। फिर जन तक नियनण लागू रहेगा, देश की ग्राथिक व्यवस्था प्रपन सामान्य स्तर पर नहीं श्रा सकती है। सामग्री नियत्रस् र्सामिति (Commodity Controls Committee) ने इस प्रात की स्रोर न्यान ह्या ग्रोर यह नताया कि "पात्राल में ग्राम भी कमी ननी हुई है। इसलिए जन तक यातापात सम्बन्धी कठिनाइपा है आर प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्यरूप दुभिन्न पड़ने भी सभापना बनी हुई है तब तक गाबाब की यनुभृति व उपलब्धि में सम्प्रान्यत आदेश (Foodgrains Licensing and Procurement Order, 1952) व अन्य पुरक आदेशा का पालन किया जाना अनिवार्य है"। जैसा कि बाद की स्थिति ने कात होता है, नियतरण ने स्वय ही सामान का अभाव उत्पन्न वर दिया था। यद्यपि सामनी नियनण समिति व श्रन्य लोगों का विचार था कि वर्तमान परिस्थिति मे नियत्रण हटाना सभव नहीं होगा, हिन्त उसे हटा देने से खाद्यान का स्थिति निश्चित रूप में सुधर गउँ है।

मारत के उस समय साय-मन्त्री स्वर्गीय श्री रक्षी ग्रहमद किदवई की यह वारणा थी कि सावान का नियत्रण कर देने से स्थिति सुधर जावागी। उन्होंने मई १९५२ को अपने एक सावजनिक भाषण में क्हा कि जिन राज्यों में साधान्न का उत्पादन उनकी आवश्यकता में ग्राधिक हो रहा है वहाँ में नियत्रण हट जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि जिन दो तीन राज्यों के अन्तर्गत देहातों में भी राशनिङ्ग (Rationing) है, वह भी हटा लेना चाहिये। किदवर्ड माह्य की इस घारणा का सरकारी और गर सरकारी दोनों ही सेत्रों में विगेध किया गया। किन्तु इस सम्बन्ध में श्री सी० राजगोपालाचारी ने श्रीगणेश किया और २६ जून १९५२ को मद्रास से खायान नियत्रण हटा लिया। यह विनियन्त्रण की दिशा में पहला कदम था। कुछ पारम्मिक कठिनाइयाँ अवश्य हुई किन्तु सादान विनियन्त्रण में पर्याप्त सफलता मिली। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि कई राज्यों ने मद्रास का

श सामग्री नियत्रण समिति की नियुक्ति २४ श्रवहूचर १६५२ को काउन्सिल श्रॉव स्टेट्स के उपसमापिन श्री एस० बी० इप्णमृति राव की श्रप्यक्तता में की गई थी। इस समिति ने खाद्याच का विनियत्रण त्रारम होने के थोडा पहिले ही २० जुलाई १६५३ को श्रपनी रिपोर्ट सरकार को डी थी।

श्रनुसरण किया श्रीर वितम्बर १९५२ तक यह विनियन्त्रण ६ राज्यों में लागू हो गया । धीरे-वीरे यह जोर पकड़ता गया स्त्रीर १६५३ तक केन्द्र व राज्य सरकारा ने खाद्यान के वितरण प्रोर उसके मूल्य पर से नियन्त्रण इटाने का काम बिल्कुल पूरा कर लिया ज्यार, बाजरा, मनका, जा जैसे मोटे श्रानाजों पर से १ जनवरी १६५४ को नियन्त्रण इटा लिया गया, इसके साथ ही इन मोटे अनाजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जा प्रतिबन्ध था वह सौराष्ट्र, मन्यभारत स्रोर उत्तर-प्रदेश के ११ जिला को छोड़कर सभी जगहीं से हट गया। बाद की यह प्रतिवन्य भी इटा लिया गया। चावल का विनियन्त्रण १० जुलाई १६५४ से लागू किया गया। उसे एक राज्य से दूधरे राज्य में ले जाने पर कोई प्रतिवन्य नहीं रहा है और अब देश के सभी भागों में उसका व्यागर स्वतन्त्रतापूर्वक किया ना सकता है। यभी तक चावन श्रनिवार्य रूप से प्राप्त करना पड़ता था, किन्तु विनियन्त्रण लागू होने से यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसके स्रतिरिक्त चावल के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण भी बन्द हो गया है।
"जिस क्रमिक विनियन्त्रण (Gradual de control) को राजा जी

१९५२ में प्रारम्भ किया था, वह चावल का पूर्ण विनियन्त्रण हो जाने के उपरान्त अपनी चरमावस्था पर पहुँच गया"। अतर-प्रदेशीय प्रतिनन्ध जो गेहूँ के एक स्थान से दूधरे स्थान पर ले जाने क सम्बन्ध में लागू किया गया था वह नियत्रण का अतिम का या और १८ मार्च ८६५५ मे वह मो उठा लिया गया। इसमे १०

वर्ष तक लागू नियन्त्रण का द्यात हो गया। विनियन्त्रण के समर्थकों ने यह द्याशा दिला रखी थी कि खादान्न-नियन्त्रण के फलस्यरूप श्रकाल, खाद्यात्र के सम्बन्ध में स्थानीय श्रभाव ((Local scarcity) श्रीर श्रन्य श्रापत्तियाँ उत्पन्न हो नायेंगी, किन्तु भाग्यवश ऐसा कुछ मी घटित नहीं हुआ। उन बात तो यह है कि खाद्यान नियन्त्रण के कारण स्रज के अप्रभाव को क्रात्रम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई भी अरीर जिन अधिकारियों को खाद्यान्न-नियन्त्रण का कार्य-भार सींपा गया था, स्वार्थरत होकर अपना हित साध रहे थे। नियन्त्रण हट जाने से (१) खाद्यान का श्रमाव होने की जो मन. स्थिति वन गई थी वह दूर हो गई। इस के श्रितिश्कि मुनाफा लारी श्रीर चोरवाजारी का भी श्रन्त हुआ, (२) देश में लाबान के वितरण की स्थिति सुधर गई, (३) जाबान का भाव कम हो गया जिसक फलर। रूप लाग। के रहन-सहन की लागत घटी श्रीर किसानों को भी श्रधिक उत्पादन करने में प्रवृत्त होना पड़ा, जिससे वे उतनी स्राय का उपार्जन कर सकें जो उन्हें पहले प्राप्त हो रही थी, (४) केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा खाद्यान नियन्त्रण व राशनिङ्ग पर जो व्यय होता या उसमें

कमी आ गई। विनियन्त्रण से यदि कोई हानि हुई है तो यही कि सायाज नियन्त्रण और राशनिङ्ग विभाग के कर्मचारी वहुत बड़ी सख्या में वेरोजगार हो गये और मुनाफासोरों व चोरवाजारी करने वालों की आप का एक बहुत बड़ा साधन छिन गया।

लाद्य स्थिति विगदते जाने के फलस्वरूप १६५६ में चानल तथा गेहूं के मगडल (zone) निश्चित करके, उचित मूल्य पर वेचने वाली दूकानों द्वारा विकी करके तथा खाद्यात्र के व्यापार एवम् लाने-ले जाने पर भतिवन्य लगा कर सीमत नियत्रण फिर से लागू किया गया। सरकारी प्रविकारिया का एक वर्ग पूर्ण नियत्रण के पन्न में है तथा योजना प्रायाग के प्रश्रंशान्त्रियों ने भी इस विचार का समर्थन किया। किन्तु, जैसा कि हम करण सकेत कर चुके हैं, खाद्यान लाँच कमेटी के नियत्रण के विरुद्ध सिफारिश की।

म्रध्याय ६

जमींदारी उनमूलन

त्राधिक दृष्टि से जमीदारी उम्मूलन का विशेष महत्व है। श्राखिल मारतीय काग्रेस क्मेटी की आर्थिक नीति का यह सदेव महत्वपूर्ण आवार रहा है। विशेषज्ञों की श्रनेक समितियों ने भी समय-समय पर जर्नोटारी का उन्मूलन करने की सिफारिश की। १६४७ में भारत को स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने जमीदारी उन्मूलन को श्रपने ग्राधिक कार्य-कम का महत्वपूर्ण श्रम बना लिया श्रोर धीरे-बीरे सभी सच्यों में इस नीति को लागू किया है। बहुत से राज्यों ने, जहाँ जमींदारी या दखी के अनुरूप कोई अन्य प्रधा प्रचलित यी, इन विशेषाबि-कारों का उन्मूलन करने के लिए कानून बनाए हैं और उत्तर प्रदेश तथा विहार ने तो जमींदारी का उन्मूलन कर उन पर अपना कन्ना भी कर लिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात ब्यान देने याग्य है कि इन मरकारों ने मुग्रावजा देकर जमींदारी-उन्मूलन करने की नोति श्रपनाई है श्रर्थात् सरकार ने जमींदार की उसकी जमीन के बदले उपयुक्त मुश्रावजा (Compensation) दिया है। ३१ मार्च १९५६ तक जमीदारी प्रया उन्मूलन हो गया तथा ४,३६ करोड़ एकड़ श्रथवा राज्य की ६६.८ प्रतिशन कृषि जोतो पर भूमि सुवार के उपाय लागू किये गये।

उन्मूलन के पन में तर्क जमीदारी उन्मूलन करने के समर्थन में भ्रातेक तर्क दिए गए हैं। यह कहा गया है कि जमीदार किसानी का शोपक (Parasite) है श्रोर उसने श्रपने कब्जे की जमीन में कुछ सुवार नहीं किया, भूमि की चक-बन्दी (Consolidation of holding) करने में सदीव दशानट डाली है छौर किसान को जा जमीन जोतता दोता हैं भूम सुधार के लिये अपनी अनुमित नहीं टी है। यटि जमीदार को इटा दिया जाय तो भूमि में सुवार किया जा सकेगा, खाद्याल के उत्पादन में वृद्धि हागी ग्रोर भूमि सुवार योजना को कायान्वित किया जा सकेगा जिसकी बहुत समय से प्रावश्यकता प्रतुमव को जा रही है। यह तर्क बहुत अशों में सही है, फिर भी इस तथ्य को टाला नहीं जा सकता है कि कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिन पर जमींदार का वश नहीं है ख्रीर यदि वह वश में रखना

जमीदारी उन्मूलन का समर्थन करते हुए यह भी कहा गया है कि इससे भी चाहे तो सफल नहीं हो सकता। राज्य की भू-राजस्व (Land revenue) आय बढ़िगी । यह तर्क बिल्फुल सही है चर्योकि १६५१-५२ में राज्यों की मृ-राजस्य ने प्राय ४० ६६ करोड़ रुपये यी जो चढ़ कर १६५७-५ में (बजट के अनुसार) ६२ ५४ करोड़ रुपये हो जायगी। इससे चाज्य सरकार मुखाबजे की किश्त चुकाने के बाद अपनी भृमि सुबार तथा आम-पुनर्निर्माण (Rural reconstruction) योजनाद्या को लागू कर सर्केंगी। परिणामस्त्रकर देश के प्रति ब्यक्ति की खाय में बृद्धि होगी और किसान की स्थिति में मुधार हो सकेगा।

जमीटारी उन्मूलन का प्रथन श्राधिक होने के माथ ही राजनैतिक मी बताया गया है। देश के मतटाताश्रों में किसानों की सख्या बहुत स्रिविक है। किसान वर्तमान स्थिति से बहुत स्रिसन्तुष्ट हैं स्रीर उनका विचार है कि उनको इस दयनीय स्थिति तक पहुँचाने के लिए केवल जमीटार हो। उत्तरदायी हैं। यह सर्वविदित है कि जनतत्र प्रणाली में बहुमन का निर्णय ही मान्य होता है चारे उनका हिष्टकोण कुछ मा हो। इस्रिल्ट किसानों क समन्तोय को कम करके उनका मत श्रमुक्त करने के लिए जमीदार। उन्मूलन को एक साधन बनाया गया है। पिछले वैर-माव की प्रतिक्रिया के रूप में किसान मिविष्य में लागू की जाने वाली किसी मी भूमि सुधार योजना में जमीदारों के साथ सहयोग नहीं करेंगे इस्रिल्ट भूमि सुवार योजनाएँ तभी सफल हा सकती हैं जब किसानों तथा राज्य सरकार के मध्यस्तों का उन्मूलन कर दिया जाय।

जमीदारी उन्मूलन के विरुद्ध तर्क—जमींदारी उन्मूलन के विरोध में भी अनेक तर्क दिये गये हैं परन्तु उनमें जान नहीं है! यह कहा गया है कि जमींदार के उन्मूलन से बहुत वही छएया में लाग वेरोजगार हो जायेगें, जैसे, जमींदार, उनके जिलेदार, कारिन्दे हतादि। इससे केवल जमींदारी की आय पर निर्मर करने वाला वर्ग वहुत किदनाहयों में पह जायगा। परन्तु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि किसी भी परिवर्तन के साथ कुछ किताई श्रीर अव्यवस्था का होना जलरी है ओर इस किताई तथा अव्यवस्था से उरकर परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। वास्तव में महत्व तो इस वात का होता है कि परिवर्तन से क्या लाभ होगा अथवा उसका क्या परिणाम होगा। यह सही है कि परिवर्तन से क्या लाभ होगा अथवा उसका क्या परिणाम होगा। यह सही है कि जमींदारी का उन्मूलन कर देने ने जमींदारी को कितनाहयों का समना करना पढ़ेगा परन्तु इसमें किसानों की दशा में सुधार भी होगा श्रीर दीर्घकालिक हिंदकाण से यह लाभदायक सिद्ध होगा। जमींदारों के कारिन्दे इत्यादि कर्मचारी आरम्म में वेरोजगार हो जायंगे परन्तु वाद में उन्हें रोजगार मिल सकता है क्यांकि सरकार को लगान वस्त करने के लिए नथा अन्य कार्यों के लिये कर्मचारी की श्रावश्यकता पढ़ेगी। जहाँ तक जमींदारों की कितनाहयों का प्रश्न है वारियों की श्रावश्यकता पढ़ेगी। जहाँ तक जमींदारों की कितनाहयों का प्रश्न है

सरकार जमींदारी के बदले उन्हें मुश्रावजा देगी श्रीर उन्हें श्रपने जीवन निर्वाह के लिये स्वय श्रन्य साधनों की स्त्रोज करनी चाहिए।

यह भी कहा गया है जमींदारी का उन्मूलन हो जाने से किसान को कई प्रकार से हानि पहुँचेगी। इस समय सामाजिक तथा ग्रन्य कार्यों के लिए जमींटार किसानों को ऋण देता है, लगान वस्ली में वह किसान की परिस्थितियों का ध्यान रखता है भ्रीर उसे भ्रटायगी के लिये समय देता है पर्न्तु सरकार के कर्म-चारी किसान को यह सुविधा नहीं देगे। केवल जमीदारी का उन्मूलन कर देने से ही भूमि सुधार सम्भव नहीं है, यदि सारी घटनायों को इसी प्रकार घटित होने दिया जायगा तो देश को लाभ होने की श्रपेत्ता श्रधिक हानि होगी। इसमें कुछ, सन्देह नहीं कि किसान की स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा परन्तु यदि कार्य का सुचार-रूप से सचालन किया गया तो किसान की दशा श्रीर अधिक विगढ़ जाने की कोई सम्भावना नहीं। श्रावश्यक्ता पड़ने पर क्सिन को कम सुद पर ऋष देने के लिये विशेष सस्थाएँ स्थापित की जा सकती हैं। यदि जमींदारी का उन्मूलन न किया गया तो जिस भूमि सुधार की बहुत समय से ब्रावश्यकता ब्रनु-भव की जाती रही है वह कभी लागू न हो सकेगा । जमींदारी उन्मूलन से जो श्रव्यवस्था पैदा होगी उसका सामना करना पडेगा श्रीर जितना शीघ यह हो सके उतना ही ग्रच्छा है। इससे सुघार करने के लिये मार्ग खुल जायगा श्रीर कुछ समय तक ग्रस्यायी ग्रन्यवस्था के पश्चात भूमि का उत्पादन बढेगा, किसान की दशा सुघरेगी श्रार देश की श्रार्थिक समृद्धि बढेगी।

उन्मूलन योजना—जमींटारी उन्मूलन कार्य "श्रस्थायी बन्दोबस्त वाले चेत्र में श्रपंत्राकृत सरल था, जैसे उत्तर प्रदेश श्रीर मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ श्रावश्यक लेखा तथा इस कार्य को करने याले श्राधकारी उपलब्ध थे। स्थायी प्रन्टोबस्त वाले चेत्रों में जेसे बिहार, उड़ीसा झोर पिन्छमी बगाल तथा जागीरदारी चेत्रों पैसे राजस्थान झोर सोराष्ट्र में सब लेखा तैयार करना झीर नये सिरे से श्रिधकारियां की नियुक्ति झावश्यक थी। जो कुछ भी हो मध्यस्थों को हटा देने के कानून झिकारा प्रदेशों में लागू कर दिये गये हैं"।

जमीं दारी उन्मूलन में साधारणतया निम्न उपायी का प्रयोग किया गया है: (१) वे भूमि के भाग जो परती पडे थे, जगल, श्राचादी के च्रेत्र, त्रादि जो यध्यस्थों के ग्राधिकार में थे, प्रवन्ध श्रीर सुधार के लिये सरकार के श्राधिकार में दे दिये गये! (२) खुट राश्त की भूमि तथा निजी फार्म के च्रेत्र, जिनकी देख-रेख स्यय जमींदार ही करने ये उन्हीं के ग्राधिकार में रहने दिये गये श्रीर वे काश्तकार जिन्होंने ऐसी भूमि पट्टे पर जमींदारों से ले रस्ती थी काश्तकार (tenant) की हैसियत से उन्हों के अधिनार में छोड टी गई। (३) बहुत से राज्यों में प्रधान आसामी जिन्हें मध्यस्यों म सीवे भूमि प्राप्त थी सीवे राज्य की सरकारों से सम्बन्धित कर दिये गये। बम्बई, हैटराबाट और मेन्स में इनामों ते प्राप्त भूमि के सम्बन्धि कर दिये गये। बम्बई, हैटराबाट और मेन्स में इनामों ते प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में यह बात नहीं लागू की गई थी। इन प्रदेशों में मध्यस्यों को ज्यासामियों से लेकर कुछ भूमि दी गई। कुछ प्रदेशों में आसामियों को स्थायी तथा इस्ताँतरण का अधिकार प्राप्त था, इसलिये प्रव यह आवश्यक नहीं था कि उन्तें और अधिक अधिकार प्रदान किये जार्ये। उत्तर प्रदेश, मन्य प्रदेश, हैटराबाट, मेसूर ख्रीर दिल्ली राजों में आसामियों को भूमिधारा अधिकार प्राप्त करने के लिये उसका मूल्य चुकाने का अवसर दिया गया। आन्ध्र, मद्रास्त, राजस्थान, मोराष्ट्र (राली चित्र) व मन्य मारत, हैटराबाट (जागीर चेत्र) आर अजमर में वा ता जासामियों के अधिकार बढा। टिये गये अथवा उनका लगान घटा दिया गया थोंग उनसे कोई मूल्य नहीं वस्ता गया"।

"मध्यस्पों को दिये जाने वाले मुत्रावजे श्रोर पुनर्गां में सहायता के रूप में दी जाने वाली रकम का श्रानुमान लगभग ४५० करोड़ रुपया लगाया गया है। इस रकम का ७०% के बल उत्तर प्रदेश श्रोर विहार में दिया जाने वाला मुख्रावजा है।

मुखावजे का खिवकार-विभिन्न जमींदारी उन्मूलन फानूनों में मुख्रावजे के विभिन्न आधार दिने गये हैं। ग्रासाम, विहार, उदीसा ग्रोर मध्य प्रदेश में सुग्रा-वजे का त्राघार भूमि ने प्राप्त होने वाली 'वास्तविक श्राय' (net income) है। उत्तर प्रदेश में यह श्राधार 'वास्तविक सम्मति' (net assets) श्रार मद्रास में मूल-भूत वाषिक द्याय' (Basic annual sum) है। वास्तविक प्राप्त द्योर वास्तविक सम्पत्ति के श्राबार लगमग नमान ही हैं। जमींदारी की उन्ल श्राय में से भूराजस्व उपकर (cess), प्रयन्य रा न्या, रैय्यत के लाम के लिये किये गये कार्यों में व्यय श्रोर कृ.प त्रायकर इत्यादि बटाकर ही वास्तविक ग्राय (net income) निकाली जाती है। प्रवन्य ओर रैच्यत (ryot) के लाम के लिये किये गए कार्य में जो रकम ब्यय की जाती है वह सभी राज्यों में समान नहीं है। वास्तविक छाय निश्चित करने के पश्चात् इमी श्राधार पर मुख्रावजा निर्घारित किया गया है। महास में 'मूलभूत वापिक अ। प' निकालने के लिए रैट्यतवाडी से प्राप्त वार्षिक त्रान के एक तिहाई भाग में स पाँच प्रतिशत कमचारियो पर व्यय करने स्रोर वस्ली न हो सकने के लिए श्रलग कर दिया जाता है ख्रोर ३ है प्रतिशत सिंचाई व्यवस्था को चलाने के लिये माट लिया जाता है। इससे जो आय शेष रहती है वही 'मूलभूत वापिक आय' कहलाती है। यह दग अन्य राज्या से भिन्न है क्योकि सुत्रावजा जमींदार से प्राप्त होने वाली वर्तमान वास्तविक श्राय पर श्रावारित न होकर रय्यतवादी प्रथा लागू होने के बाद भू-राजस्व के २५ प्रतिशत पर श्राघारित होगा।

उत्तर प्रदेश में मुत्रावजे की दर वास्तविक सम्पत्ति का श्राठ गुना है। इसके साथ ही जो जमींदार १०,००० रुपये से श्रिधिक भू-राजस्व नहीं देते उनको जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वास्तविक सम्पत्ति के २० गुने से लेकर एक गुना तक पुनर्वास श्रानुदान दिए जायँगे। यह श्रानुदान कम श्राय वाले जमींदारों के लिये समशः कम होते जायँगे मध्यस्थों को दिया जाने वाला मुश्रावजा तथा पुनर्वास श्रानुदान का श्रानुमान कमशः ७५ करोड रुपया तथा ७० करोड़ रुपया है।

मुत्रावजे के चुनाने में सबसे श्रधिक विचारणीय बात यह है कि मुश्रावजा नकट दिया जाय या वेचे न जा सकने वाले वाएडों के रूप में। जमींदारों के दृष्टि-कोण से यदि मुत्रावजा नकट दिया जाता तो सर्वोच्य होता क्योंकि इससे वह कोई नया कारोबार खोलते या उत्योगों में क्यया लगाते जिससे उन्हें बरानर श्राय होती रहती। परन्तु मुश्रावजे की रकम को नकद श्रदा करना समय नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें इतना श्रायक धन नकद देने की ज्यवस्था नहीं कर सकती है। उनके पास इसके मुगतान के लिए रुपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहा जमींदार उन्मूलन कोष का निर्माण किया गया है, किसानों को श्रपने लगान का १० गुना जमा कर भूमिधारी श्राधकार लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है किर भी श्रभी तक बहुत कम रुपया इकटा हो सका है। मुत्रावजा वेचे न जा सकने वाले बाएडों के रूप में दिया गया। परन्तु इस विधि से जमींदार के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं होता है क्योंकि जमींदारों को उनके मुश्रावजे की रकम श्रीर उस पर ब्याज का मुगत। काफी लम्बे समय में किया जायगा श्रीर इस बीच श्रपना वर्तमान खर्च चलाने में तथा कोई नया कारोगार स्थापित करने में जमीटारों को बहुत कठिनाई होगी।

श्रन्य प्रगाली—नमींदारी उन्मूलन कर देने से ही सारी समस्या का इल होना सभव नहीं है। यदि इसके वाद भूमि सुवार लागू नहीं किए तो जमीदारी उन्मूलन का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य समस्याएँ यह हैं (१) जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि पर श्रिषकार की ब्यवस्था, (२) कृषि के रूप (form of cultivation). श्रीर (३) भू-राजस्व वस्न करने के लिए श्रीर चरागाह, बंजर जैसी जमीन की देख रेख करने के लिए सरकार की श्रीर से निर्धारित उपयुक्त सस्था। श्रव तक भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य कृपक को स्वामित्व के श्रधिकार प्रदान करना था। भूमि के इस्तातरण के सम्बन्ध मे भूस्वामी के श्रधिकारों पर कुछ प्रतिबन्ध इसिलये रखे गये हैं ताकि जोते बहुत बड़ी या बहुत छोटी न हो कॉय और भूमि गैर-कृषकों के हाय न चली जाय। "भूमि सुधार के उपायों के लागू होने के बाद जमींदारी श्रौर जागीरदारी चेत्रों से श्रधिकाश कृपकों के भूमि सम्बन्धी स्वामित्व के, श्रधिकार प्राप्त कर लिये हैं। इस प्रकार मीठिसी रैय्यत (occupancy raryat), नियत लगान वाले रैय्यत श्राद्ध भू-स्वामी बन गये। गैर मीठिसी रैय्यत श्रीर रैय्यत के नीचे वाले किसान, सामान्यत मूल्य चुकावर ही मूस्तामी बन सकते हैं। यह सब तथा पूर्ववर्ती मध्यस्य जो श्रपनी सीर श्रीर खुदकाश्त के मालिक बने हुये हैं। श्राधिकतर राज्य के काश्तकार कहलाते हैं किन्तु वास्तव मे वे श्रपनी भूमि के स्वामी है श्रीर उनके श्रधिकार रैय्यतवारी चेत्रों के भू-स्वामियो की तरह ही हैं।"

श्रीषकाश राज्यों में भूस्वामियों को श्रपनी भूमि वेचने का श्राधकार है यद्यपि इस पर कुछ प्रतिवन्ध अवश्य हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि घर, मध्यप्रदेश में भूमि स्वामी श्रीर भूमिधारी, विहार में भू-स्वामी श्रीर मौक्सी काश्तकार, पश्चिमी वगाल में रैज्यत, श्रासाम में भू-स्वामी, विशेष श्राधकार प्राप्त रेज्यत, मैक्सी रैज्यत, लगान या सदैव के लिये निश्चित लगान देने वाले वाश्तकार, है दराबाद श्रीर बम्बई में भूमि वाले किसान, पनाब में भूस्वामी श्रीर मौक्सी काश्तकार, उड़ीसा में भू-स्वामी श्रीर मौक्सी काश्तकार, पण्यू में भू-स्वामी, राजस्थान में खातेदार काश्तकार, मध्यभारत में पक्के काश्तकार इत्यादि सभी को श्रपनी भूमि वेचने के श्राधकार प्राप्त हैं। भूमि वेचने पर इस प्रकार के प्रतिवन्ध श्रवश्य हैं जैसे (श्र) किस प्रकार के व्यक्तियों को भूमि वेची जा सकती है (ब) किस सीमा तक भूमि वेची जा सकती है, खरीदी भूमि के लिये श्राविक्ततम सीमा होती है तथा वेचने वाले के पास शेष भूमि के लिये निम्नतम सीमा होती है। "

"अनेक राज्यों में गैर-कृपको को भूमि वेचने की मनाही है। वस्वई हैटराबाद, मध्यभारत श्रौर सौराष्ट्र में कानूनन गैर कुपकों को भूमि वेचने की श्राशा नहीं है। वस्वई श्रौर पिश्चमी बगाल में श्रनुमित प्राप्त खरीदारों की प्राथमिकता का कम निश्चित है। प्राथमिकता में पहला नम्बर उन काश्तकारों का है जो मूमि पर वास्तव में काविज हैं। इसके बाद पढ़ोसी कृपको का नम्बर हैं तथा इसी तरह लोगों का कम निश्चित है।"

"उत्तरप्रदेश में यद्यपि भूमिषार को अपनी जोतो को वेचने का श्रिधिकार है किन्तु इस पर यह प्रतिवन्ध है कि घामिक संस्था के श्रलावा किसी श्रन्य व्यक्ति को बेचने पर खरीदने वाले की जोत ३० एकड से श्रिधिक न हो जाय । वम्बई में यह सीमा १२ एकड़ से ४८ एकड (जो भूमि की किस्म पर निर्भर है) है। हैटराबाद में यह सीमा परिवारिक जोत की तीन गुनी है। मध्यमारत में यह ५० एकड़, पश्चिमी बंगाल में २५ एकड़ (जिसमे घर से सलग खेत नहीं शामिल हैं) दिल्ली में ३० स्टेन्डर्ड एकड, राजस्थान में ६० श्रिसिंचत एकड या ३० सिंचित एकड़, श्रासाम में एक परिवार के लिये १५० बीघा (४६३ एकड़) तथा सोराष्ट्र में तीन श्रार्थिक जोत है।"

वम्बई, हैदराबाद थ्रोर मन्यमारत मे ऐसी कोई भूमि नहीं वेची जा सकती जो वेचने वाले की जोत को निर्धारित सीमा में कम कर दे। उदाहरण के लिये वम्बई में कोई भी जोत वेचकर या किसी अन्य प्रकार इस तरह विभाजित नहीं की जा सकती कि उसके (एक गुढा या चार एकट सीमा भूमि पर निर्भर है) टुकडे हो जॉय। हैदराबाद में एक (स्टेन्टर्ड) निश्चत चेत्रफल निर्धारित करने की व्यवस्था किसी भी हालत में भूमि इससे कम चेत्रों में नहीं विभाजित की जा सकती। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में परका काश्तकार अपनी भूमि तभी वेच सकता है जब कि वह अपनी कुल भूमि वेचने से तैयार हो श्रथवा बेचने के बाद उसके पास प्र सिचित एकड़ या १५ असिचत एकड़ भूमि बच रही हो।"

इन सब प्रतिवन्धों के बावजूद भी, श्रिधकाश राज्यों में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् क्षपकों का भू-स्वामित्व हो जायगा तथा प्रत्येक किसान श्रपनी जमीने जोतेगा। यदि ऐसा हुश्रातो बहुत बड़ी सीमा तक जमींदारी उन्मूलन के लाभ व्यर्थ हो जॉयगे। क्षपक के पास श्रपनी भूमि में सुधार करने तथा कृषि के सुधारे हुये दगों का प्रयोग करने के लिये साधन नहीं है।

भूमि से उत्पादन की मात्रा तभी बढाई जा सक्ती है जब बहे चेत्री में खेती की जाय श्रीर श्रावश्यकता पढ़ने पर मशीनो का उपयोग किया जाय। उत्पादन में वृद्धि होने से किसान की श्राय में भी वृद्धि होना स्वामाविक है। उत्तर प्रदेश कानून में दो तरह की सहकारी-कृषि प्रणालियों की व्यवस्था की गई है— (१) ५० एकड़ या श्राधिक के ऐसे छोटे फार्म जो १० या श्राधिक किसानों ने स्वेच्छा से समक्तीता करके बनाए हां श्रीर (२) श्राधिक हिण्ट से श्रनुपयुक्त जमीनों को मिलाकर सगठित सहकारी कार्म। यदि दृषरे प्रकार के कार्म के कुल सदस्यों के दो तिहाई यह माँग करते हैं कि इन छोटे फार्मा को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाया जाय तो शेष एक तिहाई को श्रानिवार्य रूप से यह माँग माननी पड़ेगी। परन्तु इससे समस्या नहीं सुलक्त सकती। सहकारी फार्म की प्रणाली लागू करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ेगा।

अध्याय ७

ें भूमि की चकवन्दी

भाग्त में भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में विमक्त कर देने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मारत के किसान मूमि के छोटे छोटे यलग-यलग विखरे हुए हुनडों में खेवी करते हैं जिससे खात्रान्न तथा अन्य सामग्री का उत्पादन कम होता है थ्रार किसान की गरीवी बढ़ती जाती है। इसक अनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं, (१) भूमि पर जनसँख्या का दवान और मौरुसी इक सम्बन्धी कानून । परिवार के प्रधान के मरने पर जमीन उसके पुत्रों तथा स्त्रन्य सम्बन्धियों में बॉट टो जाती है। वॉटने समय इस बात का व्यान नहीं रखा जाता है कि इन भूमि के छोटे-छोटे हिस्सा से हिस्सेदारी का जीवन-निर्वाह नहीं हो सकेगा, इनमे को कुछ उत्पादन होगा उससे वह अपना भरण-पोपण नहीं कर सकेंगे। (२) किसान क ऋगी होने तथा श्रन्य कारणों से भूमि का विक जाना। भारत के किसान भ्रम्ण के बोम से टब जाने के कारण ग्रपनी जमीन रेहन रख देते हैं श्रीर ऋण न बुका सकने पर उस जमीन को ऋग्यदाता वेच देता है या स्वय ले लेता है, इससे जो जमान पहले से ही छोटे छोटे टुकडा मे थी श्रव श्रोर श्रिधक विमक्त हो जाता है। यदि किसान के संयुक्त परिवार के एक सदस्य का हिस्सा ऋण न चुका सकने श्रथवा श्रन्य किसी कारण में वैच दिया जाता है तो शेप भूमि कम हो जाती है श्रोर जब उसका विमाजन किया जाता है तो वह श्रीर छाटे छोटे दुक बो में वॅटनी जाती है। (३) किसान इस बात से अनिभन्न है कि भूमि का छोटे-छोटे हिस्सों में बैंट जाना बुरा है। यह श्रातुमव किया गया है कि किसान भूमि की चकवन्टी क लिये श्रीम तैयार नहीं होता। इसके लिये उसे काफी समसना पडता है ग्रीर टवाव ढालना पहता है। भूमि की चकवन्टी से उत्पादन वढता है तथा कृपक का चिता भी कम हो जाती है इससे हम छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त होने की गम्भीर समस्या को ही इल नहीं कर लेते बल्कि याम योजना मे, खेल के मेदान, स्कूल, गढे प्रादि बनाने में भी सहायता मिलती है।

हानियाँ—भूमि का विभाजन और उसका छोटे-छोटे दुकड़ों में वट जाना एक गम्मीर दोप है। इससे अनेक हानियाँ होती हें (१) इससे भूमि में सुधार नहीं किया जा सकता। भूमि छोटे टुक्डों में वॉटी होने के कारण किसान अपनी खेती के लिये न कुआँ खोट पाता है, न मशीनों का उपयोग कर पाता है और न अन्य प्रकार के सुधारों को ही लागू कर पाता है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ने पाती और उत्पादन गिरता जाता है। (२) भूमि के छो-छोटे दुकड़ों में बंटे रहने के कारण बहुत सी जमीन एक हिस्से को दूसरे हिस्से से ग्रलग करने के लिये मेढ़ वॉधने में व्यर्थ नष्ट हो जाती है और भूमि के टुकड़े विखरे होने के कारण किसान ग्रपनी खेती की अच्छी तरह देख-भाल भी नहीं कर पाता है। इसस फसल में गहरी हानि होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। और (३) किसान को एक भाग से दूसरे भाग में आने-जाने मे ही बहुत सा समय नष्ट करना पड़ता है।

यह कहा गया है कि भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में बॅटे रहने से किसान को लाभ है क्योंकि इससे गाँव के श्रनेक मागो में प्रत्येक किसान की कुछ न कुछ भूमि रहती है। यदि बाढ तथा टिल्डी इत्यादिका सकट आ जाय तो उसकी सारी भूमि नष्ट होने से बच जाती है। यदि एक भाग इस संकट से नष्ट भी हो जाय तो अन्य भाग दूर होने के कारण बचाये जा सकते हैं। दूसरा लाम यह बताया जाता है कि भूमि के इस प्रकार के बूँटवारे से गाँव की अधिकाश जनता के पास भूमि हो जाती है। यदि यह बॅटवारा न किया जाय तो बहुत से ग्रामीगा विना भूमि के रह जायेंगे। परन्तु ध्यान पूर्वेक श्रव्ययन करने से पता चलेगा कि यह दोनो लाभ काल्यनिक हैं। ऐसा बहुत कम समव है कि प्रकृति के कीप से गाँव का एक ही भाग नष्ट हो श्रीर शेप भाग बच जाय। यदि कमी ऐसा हुआ भी तो इससे किसान को बहुत कम लाम होगा, वर्षों से छोटे-छोटे दुकड़ों में खेती करने से कियानों को जो हानि होती है वह इस सभावित लाम की अपेदा कहीं अधिक है। श्रौर जहा तक मृमि-विहीन मजदूरों का प्रश्न है यह भूमि के बॅटवारे या उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त करने से इल नहीं किया जा सकता है। बास्तव में मुख्य समस्या यह है कि किसान को इस योग्य बनाया जाय कि वह रहन-सहन का एक उचित स्तर बनाये रख सके। कुल परिवार के पास समुक्त रूप से जितनी भूमि हे यदि उसका उसके सदस्यों में विभाजन कर दिया जाय श्रीर प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ भूमि दे दी जाय तो इसमे रहन सहन का उचित स्तर नहीं रखा जा सकता। इन छोटे-छोटे भागों से किसान अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकने में ग्रासमर्थ होता है। यदि भूमि का इस प्रकार बॅटनारा न किया जाता तो शायद वह श्रवमर्थ न होता। भूमि-विहीन मजदूरों की समस्या को इल करने के लिए सरकार को श्रन्य उपायो से काम लेना पडेगा।

यह खेद की वात है कि भूमि के बॅटवारे और उसके छोटे-छोटे भागों मे विभक्त हो जाने की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। कृषि सम्बन्धी रायल कमीशन (Royal Commission on Agriculture) की रिपोर्ट से ववल यह सूचना मिलती है कि विभिन्न राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति के पास ग्रौस्तन कितनी जमीन है। इस सूचना से समस्या की पूर्ण जानकारी नहा होती। किसानों के पास ग्रोस्त भूमि उत्तर प्रदेश, मद्राम, त्रिवॉक्ट्रकोर्च न ग्रौर हिमाचल प्रदेश में ग्रन्य चेत्रों की अपेद्या कम है। उत्तर प्रदेश में भूमि पास कुल व्यक्तियों में से ८१२ प्रतिशत के पास ५ एकड से कम भूमि है श्रौर यह कुल काइत नी जाने वाली भूमि का उद्भ प्रतिशत है।

मद्रास में ८२२ प्रतिशत के पास १० रुपया या इससे कम वापिक लगान की भूम है जो कारत की जाने वाली भूमि का ४१२ प्रतिशत है। त्रिवांकुर-कोचीन में ६४१ प्रतिशत के पास ५ एक्ड से कम भूमि है जो कुल कारत की जाने वाली भूमि ४४ प्रतिशत है। श्रान्य राज्यों में भी यह समस्या गम्भीर है। श्रीर इससे किसानों को श्राय में हानि सहनी पड़ी है।

रीति (Methods)—भूमि की चक्वन्टी करने की टां मुख्य रीतियाँ हैं:
(१) स्वय किसानां में परम्परा स्वेच्छापूर्वक सहयाग की मावना के द्वारा श्रीण (२) सरकार द्वारा चकवन्टी श्रानिवाय कर देने से। जहाँ तक स्वेच्छापूवक सहयोग करने का प्रशन है इसम काफी देर लगती है श्रीर चकवन्टी का कार्य श्रा श्रा में नहीं हो पाटा। कहीं कहां जमादार या महाजन चकवन्टी के कार्य में रुकावट पैदा कर देने हैं। इसके साथ ही किसानां का यह समझाना बहुत कठिन है कि चकवन्दी से उनका लाम होगा। किसान न तो श्रपनी भूमि छोड़ने के लिए तेयार होता है श्रार न इस काम में छाटा-मोटा ब्या करने को राजी होता है। परन्तु यदि भूमि की चकवन्दी श्रानिवार्य कर दो जाय तो किसान इसका विराध करता है। वह समझता है कि भूमि की चकवन्दी से उसके हितों को चोट पहुँचेगो। यदि चकवन्दी योजना को लागू करने वाले कर्मचारी कमजीर श्रीर श्राकुशल हुए हुए तो श्रानेक काठनाहर्या पेदा हो जाने की सभावना रहती है। परन्तु स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग करके भूमि को चकवन्दी कराने का परिखाम निगशाजनक ही रहा है इसलिए इस योजना को स्नावनार्य कर देने में हो श्राविक लाम हो सकने की समावना है।

इस दिशा में भूमि की चकवन्दी प्रथम प्रयास है। वास्तव में प्रयतन इस बात का करना है कि भूमि का श्रार बटवारा न हो श्रन्यथा चकवन्दी से कुछ लाम समव नहीं। यदि भूमि छोटे हुन्छ। में ब्टती गई तो चकवन्दी का उद्देश्य ही विफल हो जायगा। भूमि का चकवन्दी के प्रश्न का इस बात में गहरा सम्बन्ध है कि प्रत्येक ब्यक्ति श्रिधिक से श्रिधिक कितनी एकड भूमि रख सकता है। "उत्तर प्रदेश में कम से कम सीमा ६ है एकड़ भूमि प्रति न्यक्ति रक्खी गई है, मध्य भारत में यह सीमा स्विचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के लिये ५ एकड़ और जहाँ सिचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है वहाँ १५ एकड़ निश्चत की गई है। आसाम में पचायत एक्ट के अनुसार पचायत को अधिकार है कि यदि उन लोगों म स जिनके लिये यह निर्माण किया जा रहा है है इस बात पर राजी हो जाय ता प्रत्येक किसान के लिये कम से कम भूमि की सीमा १२ बीघा निश्चित कर सकते हैं। बम्बई, पजाब और पेग्स में चक्वन्दी एक्ट ने राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे जितना भो उपयुक्त समक्ते प्रति किसान भूमि की सीमा निश्चित कर दे। बम्बई की सरकार ने इसलिये भूमि की बिमिन्न न्यूनतम सीमाये १० गुन्ठे से लगा कर ६ एकड़ तक अपने विभिन्न जिलों में नियत कर दी हैं। इन सब राज्यों में ऐसे बटवारो पर रोक लगा दी गई है जिनके परिसाम स्वरूप बॅट कर न्यूनतम सीमा में कम हो जायगी"। यदि ये प्रतिबन्ध न लगाये जाय तो चक्वन्दी के लाम भविष्य में होने वाले बॅटवारे के कारस न मिल सकते।

कानून-वम्बई, मध्य प्रदेश, पजाब, उत्तर प्रदेश, पेन्यू, जम्मू श्रोर काश-मीर में चकबन्दी के सम्बन्ध में विशेष कानून पास किये गये हैं। देहली ने पजाब एकट को अपना लिया है और उडीका ने १६५१ के एग्रीकल्चर एक्ट मे कुछ चकबन्दी सम्बन्धी नियम जोइ दिये हैं। हैदराबाद, सीराष्ट्र, त्रिलासपुर श्रीर राज-स्थान में इस सम्बन्ध में कानून विचाराधीन है। आरम्भ में कानून अनुमति प्रदान करने वाले (Permissive) ये श्रीर विशेष पदाविकारियों के द्वारा श्रदला बदली में सहायता तथा छुट ग्रादि का प्रवन्ध करते थे। बड़ौदा एक्ट इसी ढग का था। सहकारो समितियाँ किसानों के लिये स्वेच्छा से चकवन्दी कराने में विशेष सहायक हो सकती थीं। जो कानून पास किये गये हैं उन्हें इम दो वगी में रख सकते हैं (१) वे कानून जो किछानों को यदि उस गाँव में निश्चित प्रतिशत किसान राजी हों तो चकबन्दी के लिये वाध्य कर सकते थे और (२) वे कानून जो राज्यो को यह अधिकार प्रदान करते थे कि वे अपनी और से चकबन्दी की योजनाओं को न्ताग करे। मध्य प्रदेश, जभ्म श्रीर काश्मीर के कानून पहिले वर्ग में श्रीर पजाब पेप्स, देहली श्रीर बम्बई के कानून वृत्तरे वर्ग में श्राते हैं"। मध्य प्रदेश के वानून के अनुसार यदि किसी महाल, पट्टी अथवा गाँव के कम से कम आधे निवासी जिनके हिस्से में गाँव की है मूमि ब्राती है मिलकर चकबन्दी की योजना के लागू कराने की प्रार्थना करें ग्रार यदि चम्बन्दी योजना पछी हो चुर्मा है तो सब समि पर श्रिधिकार रखने वालों को चकबन्दी योजना स्वीकार करने के लिये वाध्य किया जा सकता है। जम्मू श्रीर काश्मीर के एक्ट के श्रनुसार यदि दे किसान जिनके

श्रिविरार में किसी गाँव के हैं त्येत हैं श्रोर वे चरवन्दी की योजना स्वीकार करते हैं तो वह चोजना पक्षी मान ली जायगी श्रार लागू वर दी जायगी। हन कानूनों क स्वारण जा योड़े से ब्यक्ति योजना को श्रस्वीकार करते हैं उन्हें भी योजना के श्रन्तर्गत लाकर उनकी सफलता निश्चित कर दी गई है।

वत्तर प्रदेश के कानून—'देश में लागू किये हुये कानूनों की प्रवृत्ति के अनुसार ही उत्तर प्रदेश ने भी इस सम्बन्ध में एन नया कानून पास किया है जिसके अनुसार राज्य अपनी ओर ने अनिवार्य रूप में चकवन्दी लागू कर स्थान पर (जो चन्न्नन्दी अनिवार्य का ने लागू करने की नथी अनुसार देना था जा कि किसी गाँव के एक वार्य का ने लागू करने की नथी अनुसार देना था जा कि किसी गाँव के एक वर दिया गा है'। १६५३ क उत्तर प्रदेश भूमि चकवन्दी एक्ट में अनिवार्य कप के उस लागू करने की अनुसार प्राप्त है। यह कानून उ० प्र० की सरकार हारा कि उस लागू करने की अनुसार प्राप्त है। यह कानून उ० प्र० की सरकार हारा के कानून की दी तरह मा है।

रस कानून के प्रावार भून खिद्धान्न निम्न हैं—(१) प्रत्येक पट्टेदार की जहाँ तह नम्भव हा कि नहीं पर भूमि दो जान्नगी जिस जोत्र में उसकी प्रधिकाश मूमि है, (२) प्रत्येक गाँव नी भूमि का वर्गीकरण निम्न ज्ञेनों में किया जायगा, जिन, (ग) टा पत्थलों जेन, श्रोर (थ) कछार भूमि के ज्ञेन, (३) केवल उन्हीं पट्टे- (४) प्रत्येक पट्टेना को उस जैन मूमि दी जायगी जहां पर पहिले से ही उनकी भूमि है, (श्रायटों के ज्ञेन को छोड़ मन) बनाये गये हैं जम तक कि किसी गाँव में जेन एक ही जिन न हो प्रीर उस ज्ञेन की भूमि एक प्रकार की न हो; (५) एक पितार के पट्टेना को वसायमभान पर दूसरे के पहोंस में ही चक दिये जायगे, तो उन्हें चक्र देने ने इन नाता मा निशेष ह्यान रम्या जायगा, (७) यह कोई ज्ञा का किया जायगा श्रार न मी ही है एकड या प्रधिन है तो यथासम्भन वह न तो उस्ता जायगा श्रार न मीटा ही जायगा । इन सिद्धान्तों से न्यूनतम

इस कानून के अन्तगत नरवन्द्रों के कार्य को करने ना एक विशव क्रम विभा एम है। उसकी कार्यान्त्रत करने के पहिले प्रत्येक किसान के प्लार्टी का लिया उनके चित्रपलों के काम तथा प्रत्येक का लगान व मालगुजारी आदि के

सहित तैयार किया जायगा। एक ऐसी वालिका तैयार की जायगी जिसमे प्रत्येक पट्टेटार के कुल खेतों का चेत्रफल जो उनके पास विभिन्न प्रकार के ग्रासामी श्रिषकारों के श्रन्तर्गत है तथा उसे जितनी मालगुनारी श्रथवा उसका लगान देना पड़ता है, तैयार किया जायगा। जब यह हिसाब पक्के तौर पर तैयार हो जायगा तब किसानो को चक देन की शर्ते तैयार की जायगी जिसमे यह दिखाया जायगा कि कौन कौन से प्लाट प्रत्येक पटटेदार को उसके पुराने खेतों के बढ़ले में दिये जायॅंगे तथा यदि नये सिरे से दिये हुये प्लाट उसके पुराने प्लाटां ती दुलना मे कम मूल्य के हैं तो क्या मुख्रावजा दिया जायना श्रीर उसके कुल्लों, पेड़ो श्रीर इमारतों के बदले मे क्या मुखावजा दिया जायगा इत्यादि । इस प्रस्ताव पर किसानो को उजरदारी करने का अधिकार होगा। परन्त उजरदारी का जवाव दिये जाने पर प्रस्ताव पक्का हो जायगा श्रीर चक्रबन्धी योजना लाग हो जायगी। इसके पश्चात् चक को दिये जाने का हुक्म जारी हो जायगा जिसमे यह दिखाया जायगा कि योजना के अनुसार कौन-कौन से नये खेत किसके हिस्से मे आगए हैं श्रीर उन्हें उन पर श्रिधिकार दे दिया जायगा। इस बात का व्यान रक्ता जायगा कि किसानों को चक उसी चेत्र में दिया जाय जहाँ पर उनके श्रिषकाँश खेत हैं। भूमि पर क्रिधिकार के सम्बन्ध मे निर्णय ऐसे निर्णायक द्वारा किया जायगा जिसे सरकार उन न्याय-कार्य सम्बन्धी श्राप्तसरों में से नियक्त करेगी जिन्हें कम से कम ७ वर्ष तक का ख्रनमन है। किसानों से भी राय ली जायगी ख्रोर उन्हें ख्रापत्ति करने का अधिकार होगा परन्तु जब योजना पक्की हो जायगी तब सब को उसे मान लेना पढेगा। यह चकबन्दी योजना न्यायालयो के कार्य-चेत्र के बाहर इस्रिल्य मानी गई है कि इस सम्बन्ध में मुकदमेवाजी न हो। एक्ट के अनुसार चकवन्दी का खर्चा ४ २० प्रति एकड़ नियत कर दिया गया है जो योजना मे सम्मिलित विभिन्न व्यक्तियों में वॅट जायगा ताकि सरकार को यह खर्च न उठाना पढें। जिनके खेतो की चकवन्दी की जायगी उन्हें पैमाइश तथा अन्य प्रकार के शारीरिक श्रम वाले कार्य करने मे सहयोग देना होगा श्रीर जो यह न कर सकेंगे तो उन्हें २ रु द आना प्रति एकड़ के हिसाब से अम के बदले में खर्च के प्रति देना पहेगा। यह कानून मुजफ्फरनगर श्रोर मुल्तानपुर जिलो में लागू कर दिया गया है। थोड़ा अनुमन प्राप्त कर लेने के पश्चात् पहिले यह २० जिलों में ग्रीर लागू किया जायगा । आशा की जाती है उत्तर प्रदेश मे इस कानून के स्रन्तर्गत चकवन्दी का कार्य बहुत सुगम होगा।

कठिनाइयाँ—चकवन्दी-कार्य बहुत कठिनाइयों से भरा हुम्रा है। इन्छ कठिनाइयाँ तो मनोवैज्ञानिक हे श्रीर कुछ प्रयोगात्मक। (१) बहुत की जगहो पर भूमि श्राधिकारों का कोई लेखा प्राप्त नहीं है। पजाव में देश के वॅटवारे के पश्चात् सारे लगान सम्बन्धी लेखों के खो जाने के कारण बडी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

(२) चकबन्दी का कार्य छोद्यौगिक ढग का है। इसके करने वालों को वेमाइश, बन्दोबस्त, भूमि के वर्गीकरण, भूमि के मूल्याकन तथा पटटेदारी सम्बन्धी जान छावश्यक है। ऐसे कार्यकर्ताछों की कमी के कार्य चकबन्दी के कार्य में बाधा पड़ी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ प्रदेशों में ऐसे अफसरों को इस कार्य के लिये विशेष ट्रेनिंग देने जा छायोजन किया गया है।

(३) इस कार्य में किसानों की किंदवादिता श्रीर पीढियों से श्रिषकार में स्थित भूमि के प्रति मोह के कारण भी बाबा पढ़ी है। जमींदारों श्रीर श्रन्य श्रमामाजिक वर्गों द्वारा बाधा उपस्थित करने से भी काम में ककावट पहुँची है। शान्तिपूर्वक जनता में इस कार्य के प्रति प्रचार तथा जानकारी की वृद्धि द्वारा तथा जहां श्रावश्यक हो वहाँ श्रमिवाय कि सो लागु करने से ही इन बाधाओं

पर विजय पाई जा सकती है।

(४) चकबन्दी में रुपया खर्च होता है श्रीर रुपये के प्रवध के कारण भी हस कार्य में बाबा पहुँचती है। प्रादेशिक सरकारों के समज्ञ श्रमेक प्रकार की विकास योजनाय हैं इसिलये वे सदा इस कार्य के लिये पर्याप्त धन देने के लिये तैय्यार नहीं रह सकती। इस सम्बन्ध में खर्च पूरा करने के लिये तीन उपायों के काम में लाने की श्रमुमित दी गई हैं। (क) दिल्ली, मध्य प्रदेश श्रीर पजाब में खर्च का एक श्रश्च किसानों से चकवन्दी फीस के नाम पर वस्तु कर लिया जाता है। इस प्रकार कुछ श्रश्च तक व्यय सरकार द्वारा श्रीर कुछ श्रश्च तक किसान द्वारा पूरा कर लिया जाता है, (ख) बम्बई में सारा व्यय सरकार द्वारा सहन किया जाता है जहाँ पर किसानों के साथ रियायत के रूप में बिना फीस लिये काम किया जाता है, श्रीर (ग) उत्तर प्रदेश में जैसा कि कपर बताया जा चुका है पूरा खर्चा किसान से ४ द० प्रति एकड के हिसाब से यस्न कर लिया जाता है।

सफलता की मात्रा—चकबन्टी की सफलता विभिन्न प्रदेशों में कम ही रही है। केवल पवाब, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेप्सू छोर दिल्ली छादि ने कुछ सफलता इस सम्बन्ध में पास की है। पजाब में चकबन्दी का काम १६२० से श्रारम्म हुआ। और उत्तर प्रदेश में १६२४ से। उत्तर प्रदेश में १६५३ के चकबन्दी एक्ट के पास होन पर इस काम की गति बढ़ गई छोर छाने चलकर एक्ट में भी उपयुक्त सुधार कर दिया गया। मार्च १६५५ तक पंजाब में ४० लाख एकड़, मध्य प्रदेश में २५ लाख एकड़, पेप्सू में १० लाख एकड़ से श्रिषक भूमि

की चंकबन्दी की गई। बम्बई और दिल्ली में १०६० और २१० गाँवों में क्रमशः यह योजना पूर्णतया लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में २१ जिलो में यह योजना यह योजना पूर्णतया लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में २१ जिलो में यह योजना का कार्य को बढ़ाने का लागू है। अब भी विभिन्न राज्यों में इस योजना के कार्य को बढ़ाने का अवसर है।

ययि चमवन्दी का कार्य जरा घीमी गति से हुआ है और वहुत कम उन्नित इस छोर हो पाई है फिर भी इससे लाटों की सख्या कम हो गई है और उनका छोसत चेनफल बढ़ गया है। यदि प्लाटों की सख्या में कमी छोर खेतों के उनका छोसत चेनफल बढ़ गया है। यदि प्लाटों की सख्या में कमी छोर खेतों के चेत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से देखा जाय तो इम कह समते हैं कि सबसे अधिम उन्नित मध्य प्रदेश ने की है लहाँ विलासपुर, रायपुर छोर दुर्ग जिलों में प्लाटों उन्नित मध्य प्रदेश ने की है लहाँ विलासपुर, रायपुर छोर दुर्ग जिलों में प्लाटों उन्नित मध्य प्रदेश ने की है जहाँ विलासपुर, रायपुर छोर दुर्ग जिलों में प्लाटों उन्नित मध्य प्रदेश ने की है छौर उनका छोसत चेत्रफल ४००% बढ़ गया है। की सख्या प्रश्लित के सबसे कम उन्नित की है और वहाँ प्लाटों की सख्या में २०% इस छोर मद्रास ने सबसे कम उन्नित की है और वहाँ प्लाटों की सख्या में २०% है भी कम कमी हुई है।

से मी कम कमी हुई है।
खेतो की चकवन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक किसान को श्रार्थिक जोत
खेतो की चकवन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक किसान को श्रार्थिक जोत
(economic holding) प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि यटि किसी किसान के अधिकार मे
गॉव के विभिन्न भागों में छिटके हुये हैं तो चकवन्दी से किसान के अधिकार मे
गॉव के विभिन्न भागों में छिटके हुये हैं तो चकवन्दी से किसान को आर्थिक जोत देने
भूमि का चेत्रफल नहीं वढ सकता। इस लये प्रत्येक किसान को आर्थिक जोत देने
के लिये बहुत वढे प्रयत्न की आवश्यकता है।

श्रध्याय ५

भृमि-क्षरण

प्रथम पचवर्षीय योजना के अनुसार भूमिसरज्ञाण से अभिप्राय केवल ज्ञरण को रोक पाना ही नहीं है परन्तु अपने न्यापक अर्थ में भूमि सरज्ञण के अन्तर्गत वह सभी वार्ते शामिल हैं जिनका लक्ष्म भूमि की उत्पादन शक्ति को ऊँचे स्तर पर बनाये रखना है, जैसे भूमि की कमियों को दूर करने के उपाय, रासायनिक तथा देशी खाद का उपयोग, फसलों के बोने के कम का उचित सचालन, सिंचाई तथा नाली की व्यवस्था हत्यादि। इस कर में भूमि-सरज्ञ्चण का प्राय: भूमि के उपयोग के दगों में सुवार करने से निकट सम्बन्ध है। भूमि सरक्षण के सम्बन्ध में मारत की प्रमुख समस्या भूमि-ज्ञरण को रोकना है। भूमि ज्ञरण होते रहने से भूमि का बहुत बड़ा मांग कृषि के थोग्य नहीं रहता।

कार्य-भूमि चरण के श्रानेक कारण हैं परन्तु उनमें से मुख्य निम्न-लिखित हैं .—

- (१) वनों का काटना श्रीर वनस्यित का नष्ट हो जाना। जगल श्रीर वनस्यित हवा श्रीर पानी के वहाव को रोकते हैं जिससे भूमि का तल इनकी हानि-कारक शक्ति ने वच जाता है श्रीर उसका चरण नहीं हो पाता। यदि वन काट डाले जाय श्रीर वनस्यित नष्ट कर दी जाय तो भूमि पूर्ववत नहीं रहेगी, उसकी उत्पादन शक्ति घट जायगी। प्राय हैं धन या इमारतो के उपयोग के लिए वनों को काट लिया जाता है। श्रासाम, बिहार, उद्गीसा श्रीर मध्यप्रदेश के कुछ मागों में कवायली जनता (Tribal people) एक निश्चित स्थान पर खेती नहीं करती है। वह प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्रपने कृषि चेत्र बदलती रहती है जिसके लिए उसे पेड काटते रहना पडता है श्रीर इससे बनों का विनाश हो जाता है। इघर जमीटारी उन्मूलन होते ही श्रनेक जमीटारों ने इमारती लकडी से रुपया पैदा करने के लिए श्रपने चेत्र के पेड काट डाले हैं।
- (२) पशुत्रों श्रौर विशेषकर मेड वकरियों का वास-पत्ती इत्यादि चर जाना । इससे भूमि के कण परस्पर गुथे नहीं (रह)जाते श्रौर उसका द्वरण होने लगता है। वनस्पति का इस प्रकार चर लिया जाना भारत के लिए एक गम्भीर समस्या वन गया है। १९५२ में भारतीय कृष्टि श्रृनुसन्धान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) के तत्वावधान में उसके फसल श्रौर

भूमि विभाग (Crops and Soils Wing) की प्रथम वैठक में उस समय के खाद्याल मनी ने कहा कि भेड बकरियों को प्रथम देने का अर्थ है भूमि-त्त्ररण और महाविनाश। परन्तु गाय-भेंस को प्रथम देकर हम भूमि की सेवा कर सकते हैं और स्वय समृद्धिशाली वन सकते हैं। खाद्य मन्नी ने अधिक जोर देकर जरूर कहा है परन्तु यह सच है कि भेड वकरियों से भूमि को बहुत क्षति पहुँचती है। उचित यह होगा कि पशुयों को चारा दिया जाय और बिना रोक टोक के इधर-उधर, विशेषकर उन चेनों में जो इस कारण पहले ही च्यतिप्रस्त हो चुके हैं, चरने न दिया जाय।

(३) जिस भूमि में उत्पादक तत्वों की पहले ही से कमी है उसका शीष्ठ चरण हो जाता है। यदि भूमि उपजाऊ है और उसकी अच्छी तरह देखभाल की गई तो खराब भूमि की अपेजा इसमें भूमि-ज्ञरण कम होगा। काश्त की जाने वाली भूमि का भारत में पीढियों से बिना किसी रोक टोक के बराबर उपयोग होता रहा है और उसकी उत्पादन शक्ति की पूर्ति करने के लिए खाद इत्यादि या तो नहीं डाली गई है या अपर्याप्त रही है। इससे देश के बढ़े-बड़े भाग भूमि ज्ञरण के सकट से अस्त हो जुके हैं।

भूमि-च्ररण अनेक प्रकार का होता है परन्तु भारत में मुख्य प्रकार निम्न-लिखित हैं:---

- (१) तल च्ररण (Sheet Erosion)—पानी के तेज बहाय से या तेज हवा के बहने के कारण जब भूमि की ऊपरी उपजाक सतह बह जाती है तब तल-च्ररण होता है।
- (२) अन्त च्राण् (Gully Erosion)—पानी के तेज बहाब के कारण भूमि में गहरे नाले बन जाने से अन्तः च्ररण होता है। प्राय अन्तः च्ररण होने का कारण यह होता है कि बहुत समय तक तल-च्ररण होता रहे और उसे रोकने का काई उपाय न किया जाय। निवयों के आस-पास की भूमि में अन्तः च्ररण की अधिक सभावना रहती है क्यों कि बाढ आ जाने से तट की निकटवर्ती-भूमि का तल च्ररण होता रहता है और धीरे-धीरे गहरे नाले बन जाते हैं।
- (३) वायु क्षरण (Wind Erosion)—वायु च्ररण देश के मरु प्रदेश में जैसे राजस्थान थ्रोर पूर्वी पजाब में होता है। तेज वायु वहने से मरु चेत्र की वालू उड़ती रहती है ग्रोर निकटवर्ती हिस्सों में बैठती रहती है जैसा राजस्थान के मरु प्रदेश के निकट होता है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति को गहरी हानि पहुँचती है।

भूमि ज्रारा एक गभीर सकट है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम होती

है, भूमि ज्यर्थ हो जाती है ग्रीर जनता निर्धनता के चगुल में फस जाती है। इस देश के बढ़े बढ़े चित्र महस्थल में बदल नाते हैं। उन चित्रों में जहाँ नदी-घाटी योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे दामोदर घाटी, वहाँ पर भूमि चरण से निमित बाँघों को भय उत्पन्न हो जाता है। इस कारण इन बाँवा को देखमाल ग्रीर बचाव के लिए ग्राधिक ज्यय करना पड़ता है। यह ट्रमांग्न की बात हैं कि हमें ग्रापने देश में भूमि-इरण के प्रकार ग्रीर प्रसार के सम्म्य में मही-मही मचना प्राप्त नहीं है इस स्चना के प्राप्त हो जाने पर भूमि-चरण को गकने के लिए प्रभावशाली उपायों को लागू किया जा सकता है। पिछले उद्ध वर्षों में भूमि सरक्षण के लिए कुछ काम किया गया है, वम्नई में छाटे-छोटे बांध बाँधने श्रोर टेक लगाने (Terracing) से श्रोर वत्तर प्रदेश में नाला तथा उद्धों से पारपुत्रत भूमि पर छापि करके भूम सरहण किया जा रहा है। वांव वाधने ग्रार टेक इत्यादि का निर्माण करने में श्रोर कटी पटी भूमि को स्मतल बनाने के लिए टैन्टरो तथा श्रम्य वडी-वडी मशीनो का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु ग्रमी इस सम्हन्य में बहुत कुछ कार्य करना शेप है।

राजस्थान के महस्थल का ममश उत्तर की छोर विस्तार एक विशेष चिन्ता का विषय हो गया है छोर भारत सरकार ने उसकी रोकथाम के लिये निम उपाय किये हैं.—

- (१) "दस वर्ष के भीतर ही भीतर ४०० मील लम्बी और ५ मील मीतर को श्रोर चौड़ी जङ्गल की एक पट्टी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर लगा देना इसमें मेड, वकरी, गाय, देल, ठेंट, श्राद पर्शों के चरने की श्राझान होगी।"
- (२) मरुस्यल की भूमि में बालू के वर्णों को इरियाली द्वारा स्थिर करने में वैद्यानिक उपायो की खोल करना।
- (३) ऐसे नख लखतानों की व्यवस्था करना जहाँ से पेड़-पीचे फीजी नाकों, रेल के स्टेशनों, पुलिस के यानों, तहर्च लों श्रीर स्नूलों के हर्द-ागर्ट लें जाकर लगाये जा सके।
- (४) ऐसी जुनी हुई सहनों श्रीर रेल की लाइनो पर मनुष्यों की श्राबादी में श्रावास का प्रवन्य करना जो वायु के बहाव को काटती हुई बटती हैं।
- (५) पौधों क लगाने वाली एकान्सवा को बील छोर पौधों के बाटने का प्रवन्य करना।
- (६) उपयुक्त चरागाहा की स्थापना का प्रवन्य करना जो कि समय-समय पर श्रोर वारी-वारी से चरने के लिये छोले जायें।

इन उपायों से त्राशा की जाती है कि मरुत्थल की बाह दक जायगी त्रौर भूमि-ज्ञरण बन्द हो जायगा तथा भूमि की उर्वरता रिथर रह जायगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—प्रथम पचवर्षीय योजना में भूमि चरण को रोकने ग्रीर भूमि सरक्या की ग्रावश्यकता पर विशेष रूप से महत्व दिया गया था। भारत सरकार ने विशेषजों की एक तदर्ध-समिति (ad hoc Committee) बनाई थी जिसका कार्य पजान, पिटयाला सब उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र श्रीर कच्छ के निकटवर्ती उपजाक चेत्र में मरु प्रसार की समस्या का श्रव्ययन करना था। समिति ने एक विस्तृत कार्यक्रम की सिकारिश की है जिसमें यह सकाव दिया गया है कि (१) राजस्थान की पिश्चिमी सीमा पर वनस्पति का प्रमील चौड़ा किटबन्य लगाया जाय, (२) राजस्थान में वन चेत्र को बढ़ाने के लिए नये वन लगाये जॉय, (३) भूमि के उपयोग के तरीको में सुधार किया जाय। विशेष रूप से कुषक रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिये चृज्ञारोपण करें श्रीर रेगिस्तान को समस्या का श्रध्ययन करने के लिए श्रनुसवान केन्द्र (Research Station) स्थापित किया जाय। भारत सरकार ने इस सिमित की सिकारिशें मान ली हैं।

प्रथम योजना में भारत सरकार द्वारा २ करोड़ रूपये भूमि सरक्षण पर व्यय करने का आयोजन था। "भूमि सरज्ञ्ण कार्य जैसे बाँघ बाँघने, खाई खोदने, नाले पाटने (gully Plugging), भूमि पर मेड़ बाँघने, पानी के बहाब पर रोक लगाने, नदी की घारा को तथा खड़ों के बनने को नियन्त्रित करने आदि उपायों के अन्तर्गत जो प्रदेशीय सरकारो द्वारा किये जा रहे हैं लगमग ७००,००० एकड़ भूमि आ गई है जिसका दो तिहाई भाग केवल बम्बई प्रदेश के माग में आया है।

"प्रथम योजना मे ही भूमि सरज्ञ्या कार्य नियमित रूप से आरम्भ हो गया या। ज्ञा-मग २५० कृषि और वन विमाग के अधिकारियों को भूमि सरज्ञ्या उपायों की विशेष शिज्ञा दी जा चुकी है। १६५२ में जोषपुर में रेगिस्तान में वृज्ञा-रोषया सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई थी और प्रथम योजना के पिछले वर्षों में ही पाँच अनुसन्धान तथा प्रशिज्ञ्या केन्द्रों की भी स्थापना हो गई थी। ग्यारह अग्रगामी योजना केन्द्र बम्बई, आन्त्र, उद्दीसा, पिंच्छमी बगाल, मद्रास, पजाब, सौराष्ट्र द्रावनकोर, कोचीन, अजमेर, कच्छ और मीनापुर में स्थापत किये गये हैं। द्रावनकोर, कोचीन तथा मद्रास की ये आदर्श योजनार्ये विकास योजना केन्द्र में परिश्वित कर दी गई हैं।

इस समस्या को समुचित रूप से मुलकाने के विचार से मारत सरकार ने छ: भूमि सरज्ञण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रशिज्ञण केन्द्र देहरादून, कोटा, वसद (उत्तरी गुजरात) वेलारी, कटाकामगढ श्रौर जोघपुर में खोले हैं। इन केन्ट्रों ने वहत लामपद कार्य किया है।

हितीय पचवपीय योजना—में तो श्रीर श्रिधिक विस्तृत श्रायोजन किया गया है। भूमि सरहाय के लिये २० करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। लगमग ३० लाख एकड भूमि नहाँ पर भूमि ह्यरण वहुत दुरी तरह से हुश्रा है इस संरक्ष्य योजना के श्रन्तर्गत लाने का हरादा है। इस ३० लाख एकड भूमि में से २० लाख एकड तो दल्शा ऊँची नीची खेती के योग भूमि, ३५०,००० एकड महस्थल तथा करने वाले करार की मूमि, ३३०,००० एकड़ नदी की घाटी वाली मूमि, १७०,००० एकड़ पहाडी सूमि श्रीर १५०,००० एकड़ खडु वाला मूमि होगी।

मारत में सब से वड़ी कठिनाई यह है कि मूमि-चरण की समस्या की गम्मीरता का जनता को कुछ ज्ञान ही नहीं है। दुछ राज्य सरकारों ने मूमि सरज्ञ्या के लिए बहुत सीमित उपायों को लागू मिया है। जनता इस मारी सकट के प्रांत विल्कुल उदासीन है और इस बात की और उसका व्यान नहीं जाता कि भूमि चरण को रोकने से कितना लाभ हो सकता है। इस सम्बध में न्यवहारिक दृष्टि से विचार करके प्रथम श्रीर द्वितीय पचवर्षीय योजनाश्चों ने निश्चित प्रगति को है परन्तु इस कार्य के लिए जितना घन निर्वारित किया गया है वह श्रावश्यकता से बहुत कम है। इस कार्य में इससे कहीं श्रधिक स्पया न्यय होगा। राज्य सरकारों को अपनी वित्तीय कठिनाइयों के पश्चात् भी इस कार्य के लिये श्रिविक घन देना होगा । दीर्घकाल में इस व्यय से श्रवश्य लाम होगा क्योंकि मृमि की उत्पादन शक्ति बढेगी श्रीर इमारी श्रनाज, कपास, ।तलहन इत्यादि की अपन में वृद्धि होगी निषसे उत्पादन तथा उरमोग के बीच की वर्तमान खाई को पाटने में सहायता मिलेगी। केन्द्रीय भूमि सरह्य बोर्ड से यह आशा की जाती है कि भूमि सरज्ञण के उपायों के प्रयोग की प्रगति बढ़ाने में समर्थ होगा। यह बोर्ड "विभिन्न प्रकार की भीमयों के जो खेतो, जझल लगाने तथा चरागाह बनाने के काम श्रा रही है सरज्ञ सम्बन्धी श्रनुसन्धान कार्य का श्रारम्भ, सामजस्य तथा व्यवस्था करेगा श्रीर प्रादेश्यक राज्यों को तथा नदी घाटी योजनाश्रों को भूमि सरहण सम्बन्धी योजनाश्रों के बनाने में तथा तत्सम्बन्धी कानून बनाने में सहायता प्रदान करेगा"। यह बोर्ड भूमि सरक्षण सम्बन्धी जानकारी की वार्तों के म्राटान-प्रदान का केन्द्र होगा तथा तत्मम्बन्धो शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा ताकि मृमि सरल्या सम्बन्ध में आवश्यक कुराल व्यक्तियों का पेमाइश श्राटि कार्यों के लिये पूर्ति की जा सके।

ष्ट्रध्याय १० सिंचाई

वर्षा ही भारत में कृषि की भाग्य-विषात्री है। देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न मात्र में वर्षा होती है जिसमें काफी अन्तर रहता है। उदाहरणार्थ एक ओर तो चेरापूजी जैसे स्थान पर ४६० इन्च तक वर्षा होती है जिससे बाढ द्वारा फसलों इत्यादि की हानि होती है दूसरी ओर राजपूताना केवल ५ इन्च वर्षा होती हैं जहाँ पानी की कमी से फसलों नष्ट हो जाती हैं। चावल तथा गन्ने की खेती के लिये आवश्यक होता है कि पानी पर्याप्त मात्रा में निरन्तर नियमित रूप से मिलता रहे। इसलिए प्राकृतिक सुविधा प्राप्त न होने के कारण भूमि के सिचाई के लिए और निहयों के पानी को उचित उपयोग में लाने के लिए कृत्रिम उपायों का सहारा लेना पड़ता है।

मारत की निद्यों से प्राप्त १३,५६० लाख एकड़ फुट पानी में से श्रीसतन केवल ५ पर प्रतिशत का उपयोग १६५१ के पिहले तक किया जाता या श्रीर शेष बाढ द्वारा प्रायः हानि पहुँचाता हुआ समुद्र में गिरता था। उसके पश्चात पानी का उपयोग बढ़ा है। आशा की जाती है कि १६५६ में लगभग १,३६० लाख एकड़ फीट जल अथवा कुल का १०% कार्य में आ जायगा। पानी की इस मारी इति को रोक कर इसे स्वचाई के कार्य में लाग चाहिए जिससे बाढ का प्रवाह घटे, भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़े और साथ ही कृषि उत्पादन में बृद्धि हो।

सिचाई का स्रोत मारत में सिचाई के मुख्य साधन कुछाँ, तालाव छौर नहरे हैं। कहीं-कहीं नदियों से पानी खींचकर भी सिंचाई की जाती है। सिचाई के यह सभी स्रोत निम्न

चार्ट में दिये गए हैं:--सिचाई के साघन कुत्रा नहर तालाव बांढ निरोधक पक्का पाताल तोड कच्चा पक्का बारहमासी कच्चा नहरें नहरे तालाच कुत्राँ कुश्रॉ तालाब कुत्रो नलक्प घरती के नीचे के तालाव घरती के ऊपर के तालाक रहंट

एक एकड जमीन को एक फुट गहराई तक मरने के लिए जितने पानी की
 श्रावश्यकता होती है वह एक एकड फुट पानी कहलाता है।

कुएँ—भारत में िवाई के लिए कुएँ का प्राचीन काल से प्रयोग होता श्राया है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण साधन हैं। कुएँ मा तो कब्चे होते हैं या पक्ते। हमारे देश में कब्चे कुत्रा की सल्मा बहुत श्रविक है क्यों कि इनका निर्माण करने में न तो श्रिषक व्यय होता है श्रीर न विशेष कला के ज्ञान की ही श्रावश्य-कता है। इनसे पानी निकलने के लिये ढेक्ली का उपयोग होता है। पक्के कुएँ दो प्रकार के होते हैं, (१) ऐते कुएँ जिनका पानी खीचने के लिए रहट या चरस का उपयोग किया जाता है श्रीर (२) नलकूप (Tube-wells) जिनका पानी खींचने के लिये विजली के या डिजिल पम्पों का उपयोग किया जाता है।

कुएँ श्रधिकतर मैदानी माग में श्लोर विशेषकर ऐसे भागों में वनाये जाते हैं जहाँ पानी का तल बहुत गहरा नहीं होता है श्लीर जहाँ मूमि मुलायम होती है। पजाव, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बगाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग श्लीर कपास की कुषि के योग्य काली भूमि में श्लिषकतर सिचाई के लिए कुश्लों का ही उपयोग किया जाता है। यह कुएँ निजी भी होते हैं श्लीर सरकारी भी। उत्तर प्रदेश में लगभग दो हजार सरकारी कुएँ हैं।

कुश्रों के पानी से जिचाई करना लाभदायक है क्योंकि कुएँ के पानी में सोडा, नाइट्रेट, क्लोराईड श्लीर सल्फेट नाफी मात्रा में रहते हैं। इनसे मूभि की उत्पादन शांक म वृद्धि होती है। इसके लाय ही कुश्लों से सिचाई करने का एक श्लीर लाम भी है। नहरों से सिचाई करने में पानी एक स्थान पर एकत्र हो जाता है परन्त्र कुश्लों के उपयोग से ऐसा होना सम्भव नहीं है। यदि कुपकों को तकाबी स्थाप देकर और श्लिप पनके कुश्लों का निर्माण करने के लिये पोत्साहन दिया जाय तो श्लिक उपयुक्त होगा। उन्हें कुएँ खोटने की सुविधा दी जानी चाहिए श्लीर निजली के चलने वाले पम्म लगाने के लिए गाँव तक विजली पहुँचानी ही। विजली के पम्म सस्ते होते हैं श्लोर श्लम्य साधनों की श्लेपेसा प्रच्छे मों होते कारी सिनितियों के द्वाग किया जाना चाहिए।

तालाव—तालावं के द्वारा विचाई करने का अधिक पचलन टिचिए में छीर विशेषकर महाम तथा मैसर म है। वैमे बङ्गाल, बिहार, उद्दीसा, उत्तर प्रदेश छोर मन्य प्रदेश में भी छिचाइ के लिये तालावं का प्रयोग किया जाता है। कहीं यह तालाव काकी वहे हैं जिन्हें कील कहना अधिक उपयुक्त होगा और कहीं छोटे-छोटे हैं जैसे पाय: गाँवों में होते हैं। इनमें कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ का निर्माण किया गया है लो कच्चे-पनके दोनों प्रकार के हैं। पक्के तालाव भूमि के

नीचे और भूमि के ऊपर भी बनाए जाते हैं। यह तालाब वर्षा के पानी से भरते हैं और अन्य ऋतुओं में इनसे सिचाई के लिये पानी लिया जाता है।

कुश्रों के पानी की तरह तालाव का पानी भी उत्पादन शक्ति बढानेवाला है क्यों कि इसमें वर्षा का पानी श्रीर गन्दगी दोनों मिले होते हैं। यद्यपि तालाव सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं परन्तु इनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इनकी गहराई मिट्टी भग्ने से घोरे-घोरे पटती जाती है। इसिलये श्रावश्यकता इस बात की है कि पुराने तालावों को गहरा किया जाय श्रीर श्राधक नये तालाव लोदे जाय। चूं कि कृषक इस दिशा में श्राधक कार्य नहीं कर सकता है इसिलये तालाव खोदने के लिये सरकार को श्राधक संक्रय होने की श्रावश्यकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में १६४८ से कार्य कर रही। यह कार्य पंचायतो, स्थानीय सस्थाश्रो श्रीर सहकारी समितियों को सौपना चाहिये। पक्के तालावों का निर्माण करने में श्राधक क्या करना पड़ता है। परन्तु इनका श्राधक सख्या में निर्माण करना श्रावश्यक है क्योंकि इनमें पानी काफी समय तक सुरिज्ञत रखा जा सकता है। कच्चे तालावों की तरह इनका पानी श्रीष्ट सूल नहीं जाता। यदि इन तालावों से खेतो तक पक्षा नालो लगा दी जाय तो इससे पानी की पूर्ति में सुधार होगा श्रीर पानी व्यर्थ नहीं जायगा। जब यह तालाव खाली हो जाय तो सिंचाई की श्रावश्यकता न रहने पर नहरों के पानी से इन्हें मरा जा सकता है।

नहरे—नहर का पानी भारत में िंचाई का सबसे वहा साधन है। पजाब उत्तर प्रदेश, बगाल, बिहार, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश श्रीर उड़ीसा से नहरों का जाल बिछा हुआ है। नहरें दोप्रकार की होती हैं (१) बारहमासी और (२) बार्टिनरोधक। बाँधों में पानी का सम्रह करके बारहमासी नहरों का निर्माण किया जाता है। इन नहरों से वर्ष भर पानी प्राप्त हो सकता है। बूसरी श्रोर बार्ट निरोधक नहरों में निर्दियों का पानी एक स्तर से अधिक बह जाने के पश्चात् एकत्रित हो जाता है। बारहमासी नहरें श्रिधक अञ्छी होती हैं क्योंकि मूखा पड़ने पर जब बार्ट-निरोधक नहरों का पानी एख जाता है तो इन नहरों से सिचाई हत्यादि के लिये पानी प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक निर्माण न्यय का सम्बन्ध है बार्ट निरोधक नहरों के निर्माण न्यय का सम्बन्ध है बार्ट निरोधक नहरों के निर्माण नहरों का निर्माण करने में टेकनिकल कुशलता मशीनों और विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है।

नहरों से सिचाई करने से कुछ हानियाँ भी होती हैं। इससे पानी एक स्यान पर एकत्रित रहता है श्रीर खेत में पहुँचने से पूर्व काफी मात्रा में पानी नष्ट हो जाता है। परन्तु यह नड़ी समस्यायें नहीं है। नहरों को पद्या कर देने मे यह समाप्त हो जायेंगी।

सिचाई-कर—सिचाई नर की टर श्रोर उसकी वस्ली के ढग प्रत्येक फसल श्रोर प्रत्येक राज्य में भिन्त रहते हैं। नहर श्रार नलकृषों की सिचाई दर भी भिनन-भिन्न हैं। एक एकड़ भूमि में गन्ने की खेती में सिचाई करने की टर उत्तर प्रदेश में ५ क्षया श्रीर हैदरागद म ३३ क्षया है। क्षास के लिए पजान में ३१ क्षया श्रीर महास में १० क्षया है, चावल की प्रति एकड़ सिचाई दर ४ क्षये से १८ क्षये तक है श्रोर गेहूं की ढाई क्षये से १० क्षये तक है। इससे शात होता है कि व्यवसायी-फसल के लिए सिचाई कर की टर खादात्र की अपेसा श्रीधक है। टर का यह अन्तर इस भत पर शावान्ति है कि प्रति एकड़ व्यवसायी-फसल में खादान्त के प्रति एकड़ की श्रीका श्रीक लाभ होता है। शाजकल पानी की जो श्रनावश्यक चृति होती है उस बन्द करना चाहिए श्रीर यटि शावश्यक हो तो व्यय किये गए पानी की मात्रा के शाघार पर सिचाई कर लगाना चाहिए।

ांपछले कुछ वपाँ में कुछ राज्यों ने नई विकास योजनाओं की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अपनी सिचाई कर भी दरों को बढ़ा दिया है जिससे कुपक पर भार ओर बढ़ गया है। सिचाई के मार्य को भी अन्य साधारण कार्यों भी तरह चलाना चाहिए। सिचाई कर की दर केवल इतनी होनी चाहिए जिससे इस कार्य को चलाने में होने वाला व्यय निकल आए और योजना को कार्यान्वित करने में जो पूँजी लगाई गई है उसकी वसली होती रहे। सिचाई कर राज्यों क लिये आय का साधन न होना चाहिए, जेसा मि उत्तर प्रदेश में बना दिया गया है, क्योंकि इससे कुपक पर अनुचित भार पड़ता है और उत्पादन व्यय बहुत अधक बढ़ जाता है।

सगठन—१६१६ से िचाई व्यवस्था राज्य सरकारों के हाथ में आ गई है। प्रत्येक राज्य में एक िचाई विभाग है जो राज्य म िचाई के कार्यों के विकास के लिये उत्तरदायी होता है। अन्तर-राज्य िचाई व्यवस्था ना सचालन करने के लिए दो केन्द्रीय सस्थाएँ हैं। इनमें से एक केन्द्रीय जलविद्युत, सिंचाई और जलयान सम्बन्धी आयोग है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने १६४५ में की थी। इसका उद्देश्य जल शक्ति पर नियत्रण रखने, उसका उपयोग ओर सरक्षण करने के लिए योजनाएँ बनाना और सभी नाया को सुसम्बद्ध करके उन्हें कार्यान्वित करना है। इसके साथ हो इसको यह भी कार्य सोपा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित राज्य सरकारों स परामर्श करके कोई नई योजना तेयार करें। दूसरी सस्था केन्द्रीय सिंचाई-परिषद है। इसकी स्थापना १६३१ में हुई थी।

परिषद् को यह कार्य सीवा गया कि भारत के प्रमुखन्यान रेन्द्रों में सिचार्र तथा इसके सम्बन्धित यन्य विषया पर किये जाने वादी खान कार्यों का समन्वय वने। इन समन्यार्थों से सम्पर्क रसने वाली चिदेगी सस्यार्थों ने भी परिषद् श्रपना सम्भन्य बनाए रखती है। इनर श्वलाया पेन्द्रीय भौमिक जल सम (Central Ground Water Organisation) नाम की सत्या भी है जा १९४६-४७ म

१९५४ ने भारत सघ ैं, कृषि तथा गाप मजालय के यन्तर्गत नलकृत जल-स्रोती का ग्राप्यम कर रही है। योजनाम् के प्रशासक के निर्देशन ने एक नलक्ष विकास सब भी कार्य कर रहा है। यह उस्वा नहीं सटा वर्षा कम होती है पहा इस बात का पता लगायेगी कि भूमि के जन्तस्तल में कितना पानी प्राप्त कर लेने की नम्भावना है।

शिचाउँ की समस्या को दो दम की योजनायी द्वारा सुलकाने का प्रयक्ष किया गया है। प्रथम बहुनुत्ती नदी घाटी योजनाश्री हाग तथा छोटे-छोटे विचार के साधना द्वारा । बहुमुर्जा नटी घाटी योजना प्रत्य सामी के अतिरिक्त बहुत बहे क्केर को छिचाई के लिए पानी देती है। उन्हें छुटि छिचाई के सायन यप्पि देसने में इतने श्राकर्षक नहीं है किर भी कृपती को विचार्ड के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक पानी देने हैं। यह त्राशा की जातों है कि चन छन नदी घाटी थोजनायें पूर्ण हो जायँगी नो उनमें लगभग १६५ लाख एकर भृमि की खिचार हो खरेगी।

कठिनाइयाँ—मारत में सिचाई की व्यवस्था का विकास करने में भूने क

फिडनाइयां का सामना फरना पदता है जिनका पिवरण निम्नलियित है :--(१) वित्त की समस्या—सिचाई योजनायों को लागू करने में सबमें नही कठिनाई नित्त की है। इनके लिए बहुत ग्रधिक क्पर्यों की ग्रामश्यकता पड़ती है। प्रथम पचवर्णीय शोजना में करी सिचाई योजनाधी के लिए ५५८ करोड़ श्रीर छोटी सिचार्ट योजनाश्री के लिए ४७ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया था। इमके साथ ही कुश्री तथा तालाशी का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों प्रोर सहकारी समितियों को कुछ य्यतिग्ता धन की प्रावश्यकता होगी। यह धन माप्त करने के लिए पचवर्षीय योजना में भूग लेने, राजस्य की श्राय से सहायता लेने, विशेष श्रनुदानों, जलपृति यर प्रीर लगान में वृद्धि करने श्रोर सिंचाई तथा विकास कर लाग् करने की व्यवस्था की गई थी। परन्तु यह कर उसके भार की एम समय में बढ़ा देते हैं जब कि कर-भार स्वय काफी अधिक है। इसमे सन्देह नहीं कि इतना बन प्राप्त करने में जनता पर प्रमुचित भार पडेगा जिससे श्रयन्तोप पेलने की सम्मावना है।

(२) प्राविधिक (टेक्निकल) ज्ञान का स्त्रभाव-धन के ग्रभाव के

साय ही योजनात्रों को कार्यान्वित करने के लिए श्रपेचित प्राविधिक कर्मचारियों का भी श्रभाव है। प्रायः सभी वहीं योजनाश्रों में विदेशी प्रविधिजों को नियुक्त किया गया है श्रीर इससे श्रनावश्यक रूप से श्रिधिक व्यय करना पढ़ रहा है। इसलिये यह श्रावश्यकता है कि देश में भारतीयों के लिए श्रनुसन्धान श्रीर प्राश्चित्र के स्वर होले जाय।

- (३) श्रावण्यक सामान की कमी—भारत में इन योजनाश्रों के लिए श्रावण्यक इस्पात श्रीर सिमंट की भी कमी है। इसलिए यह श्रावश्यक है कि इन जा उत्पादन श्रीर बढाया जाय श्रीर जो कुछ सामान उपलब्ध हो सके उसको सबसे पहले सिंचाई के लिए निर्माण-कार्य में लगाया जाय।
- (४) पानी का अनुचित उपयोग और श्रवि—मारवीय कृपक पानी का उचित उपयोग नहीं करता। विभिन्न चेत्रों में विभिन्न फर्कों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। परन्तु भारतीय कृषक पानी का बिना सोचे-समके उपयोग करता है। पानी की अधिकता खेती के लिये उतनी ही हानिकारक है जितनी उसकी न्यूनता। एक समय में अधिक पानी देने की अपेचा बार-बार पानी देना अधिक लाभदायक खिद्र हुआ है। पानी की इस च्वि को कुछ सीमा तक नहरों को पक्का बनाने और काम में लाये गये पानी की मात्रा के आधार पर सिंचाई कर लागू करने से रोका जा सकता है।
 - (४) पानी का गलत वॅटवारा—भारतीय क्रथक बहुत समय तक अपने खेत को सींचने के लए वर्षा के आगमन की प्रतीद्धा करता है। जब वर्षा से देर हो जाती है तब वह सिचाई के लिये नहरों और नल कूपों से पानी लेने के लिए दौड़-वृप करता है। परन्तु सब क्रपकों को एक ही समय में नहरों और नल कूपों से आवश्यक पानी मिलना सम्भव नहीं है क्योंकि भारत मे नहरों और नल कूपों का पानी क्रपक की श्रीसत आवश्यकता में कम है। इस प्रकार की दौड़ वृप से सिचाई की व्यवस्था पर बहुत भार पहता है जिसको कम करने के लिए किसानों को अपनी आवश्यकताये पहले से दर्ज करानी चाहिये और रजिस्ट्री के कमानुसार उन्हें पानी मिलना चाहिए।

यह कठिनाइयाँ ग्रसाध्य नहीं हैं। उचित प्रयत्नों से इनको हल किया जा समता है। यदि कृषक सहयोग दे श्रोर पानी की उचित रूप से ज्यवहार में लाने की श्रावश्यकता को समर्के श्रीर बहुमुखी नदो याटी योजनाश्रों के साथ-साथ फली- भृत होनेवाजी योजनाश्रों पर जोर दिया जाय तो देश की सिंचाई ज्यवस्था संभल जायगी।

वहुउद्देशीय योजनाएँ श्रार वाढ् नियंत्रण कार्यक्रम

सिचाई श्रोर शक्ति उत्पादन योजनायें प्रथम श्रीर द्वितीय पंचवपीय योजनात्रों के मुख्य श्रम हैं। इनमें विद्युत शक्ति के उत्पादन श्रीर सिंचाई की मुविधा में वृद्धि होगी जिनका श्रमाव उत्रोगों श्रोर कृष्य की उन्नित में बावक रहा है। इन योजनाश्रों में बाद पर नियवण, मलेश्या के फेलने में रुमावट, तथा देश को अन्य श्रनेकों लाभ होंगे। प्रथम श्रार हितीय योजनाश्रों के श्रन्तर्गत तीन प्रकार की सिचाई योजनाश्रों की व्यवस्था है। (१) बहु उन्हेंगीय योजनायें, (२) बड़ी तथा साधारण सिचाई की योजनायें ।

इन नोजनात्रों की तीन विशेषतार्ये हैं। (क) इनमें ने अनेकों तो पचय-पींय योजना के आरम्भ होने के पूर्व ही से चल रही थी। "द्वितीय महासमर का अन्त होते ही बहुत सी परियोजनार्ये जिनमें कई बहुउद्देशीय योजनार्ये भी थीं आरम्भ कर दी गई थी। इनमें से कुछ तो ऐसी थीं जिनका कार्य तो बिना उनके सम्बन्ध में आवश्यक प्राचीिक और आर्थिक छान बीन के ही आरम्भ कर दिया गया था। १६५१ में जन सिचाई और शक्ति उत्पादन की योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा था, उनके पूर्ण होने में कुल ज्यय ७६५ करोड़ चपये होने का अनु-मान था" इसमें से १५३ करोड कपया तो इन अपूर्ण योजनाओं पर ज्यय हो चुका था क्योंकि ऐसा विचारा जाता था कि जितना शीध हो सके उतना शीध ये योज-नार्ये पूर्ण की जोय जिससे कि जो कुछ घन इन पर ज्यय किया जा चुका है वह सार्थक हो और उसका यथा-सम्भव लाभ बढी हुई मात्रा में अन की उत्पत्ति के रूप में शीध मिल जाय।

(ख) प्रथम योजना के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं को आरम्म किया गया या उन पर पुन: विचार किया गया और िचाई तथा शक्ति उत्पादन की योजना पर ब्यय ५५८ करोड़ रुपये में बढ़ाकर ६७७ करोड़ रुपया कर दिया गया। जो अन्य मह्त्यशाली परिवर्तन किये गये वे निम्न हैं। (१) १६५१ में योजना निर्माण के समय सदा से कमी के चेच की आवश्यकताओं की आर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इन चेंनों की जनता के निर्धन होने तथा उनके आर्थिक कार्यों म निग्न्तर प्राकृतिक बाधा की उपस्थित के कारण निरन्तर सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती थी। इस्र लिये १६५३-५४ में इन चेंनों के स्थायी विकास के

लिये कार्यक्रम निश्चित किए गए श्रीर इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के कुल व्यय में ४० करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। इन योजनाश्रों का ध्येय या कि वे जनता के पास धन की वृद्धि करेगी श्रीर वे मविष्य के विकास कार्यक्रम में उसमें सहायता दे सकेगे। (२) १६५४ ५५ में छोटी छोटी शक्ति उत्पादन की योजनाश्रों इसमें सम्मिलित कर लीं गई जिन पर २० करोट ६० इस विचार से व्यय करने का निश्चय किया गया कि उनसे छोटे-छोटे करनों श्रीर गाँवों में जनता को कार्य पाने का प्रवस्त पास हो मकेगा, श्रीर (३) बाढ पर नियत्रण रखने का १६५४-५५ में क्रम बनाया गया जिसपर १६९ करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया।

(ग) इन योजनाश्चों का कार्य इतना श्रिधिक था छोर घन तथा छन्य श्रावश्यक नाधनों का इतना श्रमांच था कि समको कार्याविन्त करना सम्भव नहीं हो सका । इसलिए सम्पूर्ण कार्यक्रम को श्रशों में विमाजित करना श्रावश्यक हो गया। प्रथम योजना म यह निर्णय निया गया कि सम्बल, कोसी, कृष्णा, कोयना श्रोर रिहन्ड योजनाओं को सम्पूर्ण योजना के श्रान्तिम काल में श्रारम्भ किया जार।

इस प्रकार द्वितीय पचवर्षीय योजना मे यह निर्णय किया गया है कि कुछ बड़े काम जैसे त्रान्त्र की वमसाधरा योजना, विहार की कन्सई योजना श्रीर वम्बई की उमाई नर्मटा, माही, खहरावासला, गिरना श्रोर बनस योजनायें, मध्य-प्रदेश की वावा योजना श्रीर पिन्छमी बगाल की कगसाबाती योजना सम्पूर्ण योजना काल के श्रन्तिम भाग में कार्यान्वित की जायेंगी।

योजना के श्रन्य कार्यक्रमों की ग्रिपेक्षा िंचाई श्रीर शिक्त उत्पादन योज नाओं पर वजट में निश्चित व्यय कहीं श्रिधिक व्यय किया गया। यह एक सती-प्रमद बात है, क्योंकि इसमें भारतवर्ष की श्राधिक स्थिति सुघरेगी श्रोर उद्योगों तथा कृषि में तीव गित से विकास सम्मव होगा। प्रथम योजना के तीन वर्ष व्य-तीत होने के पूर्व ही भारतवर्ष यदि ग्रज के लिये श्रात्म निर्मर हो सका है तो किसी सीमा तक इसका कारण सिंचाई तथा शिक्त उत्पादन योजनायों है। प्रथम योजना के प्रथम चार वर्षों में ६७७ नरोड मी व्ययस्था में से ४४५ करोड़ रुपया व्यय किया जा सुका था। बहुउद्देशीय योजनाश्रों पर १८७ २४ करोड़ रुपया जो कि कुल व्यय का ७६% हैं, गिक्त उत्पादन योजनाश्रों पर, ११२ ७५ करोड़ रुपया जो कि दह% है, सिचाई योजनाश्रों पर (जिनमें कभी के स्त्रों का कार्यक्रम सिम्मिलत हैं) १३३ ३७ करोड़ रुपया जो कि ६४% हैं, व्यय किया, जायगा। १९५४-५५ के श्रन्त तक कृषि के श्रन्तर्गत लाया गया श्रतिरिक्त स्त्रेय ४० लाख एकड़ था जर कि लक्ष्य ५७ लाख एकड़ था। लम्बे शक्ति उत्पादन के स्त्रेम में

६६२००० किलोवाट शक्ति उत्पादन किया गया, जब कि ध्येय ८८१००० किलोवाट उत्पादित करने का था।

बहुत सी बड़ी योजनाश्चों पर बहुत उन्नति की जा चुकी है, श्रीर यह श्राशा की जाती है, कि वे द्वितोय योजना काल में पूर्ण कर दी जायँगी। इन योजनाश्चों में भाकड़ा, हीराकुण्ड, कोयना, चम्बल ग्रीर रिहेन्ड योजनाये श्राती हैं। इन सबसे १७ लाख किलोगट विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकेगी।

बहुउद्देशीय योजनाएँ

कुछ बहुउईंशीय योजनाश्चों जैमे माक इन नागल, हिराकी, दामोटर घाटी श्चीर हीग कुण्ड ग्रादि ने पचनपीय योजना के प्रथम चार वर्षों में सतोषप्रट उन्नित की श्चोर योजना मे निश्चित २८२०२ करोड वपए में से उन पर १६७२६ करोड़ वपया न्यय किया जा चुका है, इसके फलस्वरूप ६ लाख एक इ ग्रतिरिक्त भूमि की सिचाई सम्भव हो सकी है, श्चोर २०२००० किलोबाट विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकी है।

भाकड़ा नागल याजना—गह योजना पजाय, पेप्स ब्रोर राजस्थान को सुनिधाय पहुँचायेगा। इसके अन्तर्गत (१) सतलज नदी के ब्रारपार भाकड़ा बॉव बनेगा, (२) नागल बॉध नदा मे बहाब की ब्रोर प्रमील तक बनेगा, (३) नागल नहर बनेगी, (४) दो नागल पावर हासउ बनेंगे ब्रोर (५) भाकड़ा नहर व्यवस्था बनेगी। यह योजना १६४६ में ब्रारम्भ की गई थी, श्रीर श्रव तक नागल बॉध नहर-नियामक (canal regulator), नागल जल द्वार तथा पजाब में भाकड़ा नहर की खुराई पूर्ण हो चुको है। हमारे प्रधान मत्री ने प्रजलाई १६५४ को इस नहर व्यवस्था का उद्यादन किया था। भाकड़ा बॉध को चूने द्वारा ठोस करने के कार्य का उद्यादन १७ नवम्बर १६५५ मे किया गया।

दामोटर घाटी योजना—योजना काल के प्रयम चार वधा में इस योजना पर ५८ १३ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था, श्रीर १ १ लाख एक इ श्रितिक भूम की सिंचाई श्रीर १ ५ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति का उत्पादना होने लगा। दामोदरघाटी योजना एक ऐसे महत्वशाली श्रीयोगिक चेत्र को मुविघाये पहुँचाती है, "जहाँ से देश में प्राप्त कुल कोयले की मात्रा का ८०% अभक्त का ७०%, कोमाइट का ७०%, फायरक्के का ५०%, लोहे का ६८%, ताँवे का १०० प्रतिशत श्रीर कामोनाइट का १००% प्राप्त होता है"। जन यह योजना पूर्ण हो जायगी तब यह देश के श्रोयोगिक तथा कुपि सम्बन्धी विकास में काफो मात्रा में सहयोग प्रदान करेगी।

हीरा कुएड योजना—नह योजना उद्दीसा राज्य को सुनिधा प्रदान करेगी,
श्रीर इस योजना की प्रारम्भिक श्रवस्था में (१) महानदी की घाटी में एक बाँध
ककड़ पत्थर श्रीर मिट्टी का, (२) दोनो किनारा पर मिट्टी के जल धरण (dykes)
(३) दोनों किनारा पर नहर, (४) वाँध पर एक पावर हाउस १८२००० किलोबाट
विद्युत उत्पन्न करने के लिये श्रीर (५) ट्रान्सिमगन लाइन्स वनाई जायेगी।
रोता में नालिया को खुदवा देने से श्रिधकाधिक क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा
हो सकेगी श्रीर इस प्रकार १६५८-५६ तक कुल ४५४ लाख एकड क्षेत्र सीचा
वा सफेगा।

विभिन्न प्रदेशों में योजनात्रों की प्रगति

राज्यों में खिचाड योजनायों नी प्रगति बहुउद्देशीन योजनायों की तुलना में कम हुई। १६५१ से ५५ तक चार वर्षों में वास्तिक ज्यय १८८० ८ करोड़ रुपया हुया जब कि सम्पूण योजना के पुनरी ज्ञुण के पश्चात् २०७६८ करोड़ रुपये के ज्यय करने की ज्यवस्था को गई थी। ख्रांतिरिक ज्ञेत्र जिसपर खिचाई की गई यह केवल ३५ लाख एकड था, जन कि योजना मे ६४ लाख एकड़ ख्रांतिरिक भूमि पर खिचाई करने का त्येय था। इन योजना ख्रों की प्रगति 'क' राज्यों क कुछ भागों में तथा 'ख' राज्यों के खिकाश भागों में वीमी ही रही है। इसका कारण सगठन का ख्रभान, प्रशासनों ख्रोर काम करने वालों का ख्रभाव ख्रीर योजना में वार-वार परिवर्तन मरना रहा है।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत—द्वितीय पचवर्षीय योजना मे सम्मिलित नई सिचाई योजना थ्रो का कुल व्यय लगमग ३८० करोड रुपये हैं, इसमें से १७२ करोड रुपया द्वितीय योजना काल में व्यय किया जायगा, शेष घन तीसरे तथा अन्य मिविष्य में होने वाली पचवर्षीय योजना थ्रों के काल में व्यय होगा। वहें और साधारण श्रेणी के सिचाई सावनों पर द्वितीय पचवर्षीय योजना में कुल ३८१ करोड रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ३५ करोड रुपये की और व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त ३५ करोड रुपये की और व्यवस्था की गई है जिससे कि सिन्यु नदी नी योजना अने यस्था यस्था योजना श्रों तथा अन्य ऐसी योजना श्रों के जिनके सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हो पाया है, प्राप्त जल वा प्रयोग करने वे लिये अन्य नई योजनाये पूर्ण करवाई जा सकें। द्वितीय योजना काल में जो २८० लाख एउड मूम सींचा जा सकेगी उसमें से लगमग १२० लाख एकड मूम सींचा जा सकेगी उसमें से सुविधा प्रात होगी और लगमग ६०० लाख एकड़ भूमि को छोटी सिचाई की योजना श्रों से यह सुविधा प्राप्त होगी।

श्रिषक्तांश अतिरिक्त िसचाई (लगभग ६० लाख एकड) जो बडे श्रोर साधारण श्रेणी की योजनाश्रों से होगी वह उन कार्यकर्मों की पृति हो जाने के कारण होगी जो कि प्रथम योजना से ही चल रहे हैं। द्वितीय योजना में सम्मिलित नई योजनाश्रों से लगभग ३० लाख एकड़ म्मि सींची जायगी। द्वितीय योजना के अन्तर्गत बड़ी श्रोर साधारण श्रेणी की योजनाश्रों के पूर्ण हो जाने पर उनकी सीचने की शक्ति लगमग १६० लाख एकड़ होगी।

द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत विद्युत-शक्ति उत्पादन के विकास-कायक्रम के तीन ध्येय हैं: (क) वर्त्तमान पावर हाउसों पर बढ़े हुये सामान्य मार को वहन करना, (ख) पूर्ति के तेत्रों के युक्ति सगत विकास के लिये श्रावश्यक विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और (ग) द्वितीय पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत नवीन श्रारम्म किए हुए उद्योगों की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करना।

वाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम

सरकार ने समन्वित श्राधार पर बाढ की समस्या के निराकरण का अत्यन्त महत्वशाली निर्णय किया है। प्रथम योजना के श्रारम्भ में बाढ नियत्रण की कोई भी निरिचत व्यवस्या नहीं की गई थी। उस समय बाढ नियत्रण योजनाएँ नदी पाटियों के विकास सम्बन्धा बहुउद्देशीय योजनाओं के श्रन्वर्गत रखी गई थी। १६५४ को श्रपूर्व बाढों ने प्राण सम्पति तथा यातायात को विशेषकर देश के उत्तर-पूर्वी माग में, बहुत हानि पहुँचाई। इस कारण बाढ की समस्या पर स्विद्यंद्र श्रीर विद्युत शक्त उत्पादन कार्यकर्मों से श्रवण स्वतत्र रूप से विचार करना श्रत्यन्त श्रावश्यक हो गया। प्रदेशों द्वारा तात्कालिक बाढ नियत्रण के लिये उपायों के प्रभावशाली सिद्ध न होन के कारण १६५४ में यह निणय किया गया कि एक व्यापक बाढ नियत्रण कार्यक्रम हस समस्या को उचित दग से सुख्याने के लिये बनाया जाय। १६५ करोड़ रुपये की योजना में इसीलिये १६.५ करोड़ रुप की व्यवस्था श्रोर कर दी गयी। बाढ नियत्रण के काय पर दितीय क्वर्यीय योजना में श्रिधक ध्यान दिया गया है।

२ ३१ करोड रुपये का ऋगु प्रदेशों को १९५४-५५ में दिया गया श्रीर केन्द्रीय सरकार के १९५१-५६ के वजट में १० करोड रुग्ये को व्यवस्था इसके लिये कर दी गई है। जिससे कि ऋगु को सहायता प्रदान की जा सके। मार्च १९५५ कि विभिन्न प्रदेशों में जो सफलता मिलो है, उसका विवस्ण निम्नलिखित है। पंजाब—निम्न कार्य पूरे किये गये (१) ४३ मील लम्बा ढेरा बाबा नानक से आकर मन्ज तक रावीं नदी के किनारे आधार बाँच का बनवाना, (२) देहली अदेश में जमुना नदी के किनारे जो पतली दारार पाई गई थी उनकी बन्द कर-वाना और टकोला बाँच बनवाना, (३) कर्नाल जिले में वाबैल से धानसीली तक जमुना नदी के दाहिने किनारे बाढ रोकने के लिये बाँच बनवाना, और (४) जमुना नदी से ताजेवाला शीर्ष कम से नी के श्रीर वाँच बनवाना, ।

यह तो सर्व विदित है, कि बाद न तो सदा के लिये रोकी जा सकती है, श्रीर न रोक देना उचित ही है। इन बाढ़ों से बारीक मिट्टी वह कर श्राती है, जिससे पानी इब जाने वाले चेत्रों की उपज वह जाती है। उन वर्षों में जब कि बाढ ग्रसमान्य हो जाती है, उनसे बहुत हानि पहुँचती है ग्रीर जनता को कष्ट पहॅचता है। बाढ का पाय ज्याना जोर उसके द्वारा हानि को कम करने के लिये वाढों के घनत्व पर नियत्रण रखना ख्रावश्यक है। इसके लिये कमबद्ध कार्य-कम बनाने की प्रावश्यकता है। जिन उपायों से प्राय काम किया जाता है. वे निम्न हैं। (१) किनारे पर बॉब वॉधना (२) सम्रह जलाशय, विशेषकर सहायक धाराश्चों पर (३) श्रवरोधन गढा बनवाना जहाँ पर बाढ का पानी एकत्रित करके थोडे समय के लिये रोका जा सके, (४) नदी की घारा को मोड़ देना जिससे कि एक नदी का पानी दूसरी नदी में पहुंच जाय , (५) नदी का ढाल बढाना उसमें त्र्यारपार द्वार खुदवा कर, (६) निदयों तक ले जाने वाली धाराश्चों को जिनमें मिट्टी मर गई है, खुदवाना और उसकी मिट्टी निकलवाना, (७) स्थानीय रज्ञा के उपाय जैसे पक्की दीवार श्रीर कॅचे टीले ब्रादि बनवाना ताकि भूमि कटने न पावें, श्रौर (८) वन लगाना श्रौर स्थान-स्थान पर बहाव की तीवता रोकने के लिये बाँघ बाँधना ।

सिंचाई श्रीर शिक्त मत्रालय द्वारा कुछ दिन पूर्व ही बाढ रोकने के कार्यक्रम की कारेखा बनाई गई है। इसके तीन भाग हैं। (क) तात्कालिक—इसके
अन्तर्गत अन्वेपण योजना बनाना श्रोर समय का श्रनुमान करना होगा। दीवार
बनाना श्रीर वॉघ श्रादि भी विशेष स्थानो पर बनाये जा सकते हैं, (प) श्रव्यकालीन—इसके श्रन्तर्गत वॉघों श्रीर नालो श्रादि का सुधार किया जायगा।
इस प्रकार की रज्ञा के उपायों का प्रयोग उन चेत्रों में विशेष रूप से किया
जायगा जहाँ बाढ श्रिषक श्राती हैं, (ग) दीर्घ कालीन—इसके श्रन्तर्गत निदयों
तथा उनकी सहायक घाराओं के जल सचय का कार्य सिंचाई श्रीर विश्रुत शिक्त
उत्पादन योजनाशों के कार्य के साथ किया जायगा।

द्वितीय योजना मे ६० करोड़ रुगये की व्यवस्था तत्कालीन और

श्रल्यकालीन योजनात्रों के लिये की गई है। इसमें ५ ररोड़ रुपया परीच्या तया तत्सम्मन्धी स्चना सामग्री एकत्रित करने के लिये नियत किया गया है। वनों का लगाना श्रीर भूमि सरच्या के उपायों का कार्य में लाना, बाढ निययण के महत्वशाली उपाय है, इनको बाढ नियत्रण के कार्यकम में विशेष स्थान मिलना चाहिए।

वेन्द्रीय बाद निरोधक मंडल ने जून १६५५ को प्रपनी पाँचवीं समा ने १६ बाद नियत्रण योजनायों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें बाँघ बाँघना, नगरों की रत्ता के उपायों ग्रीर गाँवों की स्थिति के स्तर को ऊँचा करने के उपाय श्रारि समितित है। इनमें से प्रत्येक योजना पर १० लाय रुपये से प्रधिक व्यय होगा, श्रीर ७ ५ करोड़ रुपये का श्रनुदान प्रादेशिक सरकारों को बाद रोकने के कार्य क्रमों को कार्यान्वत करने के लिये दिया गया है। बोर्ट ने यह मी सिफारिश की है कि प्रत्येक प्रदेश के बाद रोकने के कार्यों को प्रदेशीय बाद निरोधक विमाग के नियत्रण में कर देना चाहिये। इससे कार्य में समन्वय श्रार उसकी गति में वीवता होगी।

आलोचना-वाढ नियत्रण की यह योजना जनता के प्राण, सम्पत्ति श्रौर फरल की हानि को रोन ने मे श्रमी तफ रफल नहीं हो पाई है। इसका कारण सरकारी कार्यक्रम के दोप हैं। मुख्य दोप निम्न हैं। (१) श्रमी तक जो प्रयतन सरकार द्वारा किये गये हैं, वह सर्वथा अपर्याप्त है। योजनाएँ बनाने तथा प्रशा-सन कार्य करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं हो पाया है। जो व्यय नियत किया गया है, वह बहुत ही कम है। द्वितीय पाजना में भी केवल ६० करोड़ इपये के व्यय की व्यवस्था की गई है, जब कि कम से कम इसका द्वाना घन उपयुक्त होता। (२) जल विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान के ग्रामाव के कारण योजनायें दोषपूर्ण हो वन पाती हैं। प्राय प्रयत्न विफल हो जाते हैं, ग्रोर परिसाम प्रयत्न की तुलना में कुछ भी नहीं होता (३) बाढ़ों को रोकने के लिये अभी तक तटवेंघों पर अधिक निर्भर रहे हैं। बाद द्वारा लाई हुई मिट्टी तटबन्घों के किनारे जमा हो जाती है इससे तटबन्घों को ऊँचा करने का श्रथवा मिट्टी खुदवाने की समस्या सदैव बनी रहती है। श्रौर यदि बाट बहुत तीत्र हुई तो तटबन्धों के बह नाने का भी डर रहता है। श्रधिक श्रव्छा उपाय तो भूमि के संरक्षण का है, इससे बाढ की तीव्रता कम ही जायगी। इससे एक श्रीर भी लाभ यह इंगा कि वाढ पीडित स्थानों उपजाक भूम के वह जाने भी समस्या भी मुलम जायगी।

कठिनाइयाँ—विचाई अरे विद्युत शक्ति उत्पादन योजनाओं को कार्या-न्वित करमें में निम्नलिखित अनेक विठनाइों का सामना करना पड़ा है।

- (१) दोषपूर्ण योजना श्रोर श्रक्तशल प्रवन्न के कारण बहुत सा धन श्रीर प्रसाधन निष्फल हा गये। राव समिति में दामोदर घाटी कारपोरेशन के कार्य की परीज्ञा की श्रोर इस परिणाम पर पहुँची कि केवल कोनार योजना के कुप्रवन्य के कारण १ ६४ करोइ रुपये की हानि हुई। सिचाई श्रोर विद्युत शक्ति उत्पादन योजनाये जैसे बढ़े कार्य में धन का पोड़ा बहुत नष्ट होना तो श्रवश्यम्मावी था स्योक्ति कर्मचारीगण श्रनुभवहीन थे, श्रीर ऐसी स्थिति में मूल होना स्वामाविक या परन्तु वास्तविक हानि श्रनुमान से कहीं श्रीषक हुई इसलिये मिवष्य में इस बात का ध्यान रखना पढ़ेगा कि बनता का धन व्यर्थ न जाय।
- (२) "स्थिरयत्रों श्रोर प्रसाधनों के कय के सम्प्रन्थ में निश्चित नीति के प्रभाव के कारण समय-समय पर विभिन्न प्रकार के यत्रों का कय किया गया। सिंचाई, शक्ति श्रौर योजना मत्रालय द्वारा १९५३ में नियुक्त प्लान्ट श्रौर मशीनरी कमेटी ने सिफारिश की है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए मुख्य-मुख्य यात्रिक प्रसाधनों को एक ही प्रमाप का होना चाहिए।
- (३) अपेद्यित योग्यता और सनद प्राप्त इंजीनियर श्रोर विशेपज्ञों के श्रमाव के कारण भारत की नटी घाटी तथा श्रन्य योजनाश्रों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पहता है। यह समस्या दो प्रकार की है, (क) विशेषज्ञों का श्रमाव तथा (ख) जो ब्यक्ति टामोदर घाटी तथा श्रन्य योजनाश्रों का कार्य कर रहे हैं, वे श्रपने भविष्य के बारे में सशक हैं कि इन योजनाश्रों का कार्य जब समाप्त हो जायगा तब उनका क्या होगा। एक समय भारत सरकार श्रिखल भारतीय सिचाई तथा शक्ति विशेषज्ञों का एक विशेष सेवा वर्ग बना रही थी, श्रयवा इसके स्थान पर ऐसे कर्मवारियों का जो विभिन्न प्रदेशों से श्राये थे एक सचय (deputation pool) बनाने का विचार कर रही थी।
- (४) िंचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायें सुधार-कर लगाने अयवा िंचाई की दर बढाने को बाध्य करती हैं। सुधार कर एव िंचाई की बढी हुई दर के कारण कुछ प्रदेशों के कृषकों को अधिक मार बहन करनापड़ा है। इसिल्ये यह आवश्यक है, कि इन करों के आरोपित करने के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रक्खा जाय कि कृषकों की कर क्षमता कितनी है। यदि राज्य सरकारें सिंचाई की दर, सुधार-कर तथा शक्ति की दर (Power rate) निश्चय करते समय कृषकों की देय-ज्ञमता को भी ब्यान में रखें तो बड़ा ही अञ्छा हो।

श्रध्याय ११

सामुदायिक विकास योजनाएँ

मारतीय क्रपकों की नि वनता श्रोर श्रायिक दृष्टि से विछ्टे होने का प्रमुख कारण है कि वे नई प्रणालियों श्रीर लीवन के नवीन उपायों के प्रति उदासीन हैं। उनके सम्मुख जो जटिल समस्याएँ हैं उन्हें इल करने के लिए वे सुसंगठित रूप में पयल भी नहीं करते। सामुदायिक विकास योजनार्थो के कार्य क्रमों ग्रीर राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं (National Extension Service) का उद्देश्य पह है कि उनके द्वारा "जनता के मानसिक दृष्टिकी से पारवतन हो, उनमें जीवन के उच्चतर स्तर तक पर्चने का महत्वाकाची श्रीर साथ ही साथ उस स्तर की प्राप्त करने के लिए इड निर्ण्य श्रीर इच्छाशक्ति उत्पन्न की जाय। प्रामी में निवास करने वाले ७ करोड़ पारवारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, नवीन जान व जीवन के नवीन उपायां के प्रति उत्साह उत्सन करना श्रीर श्रेष्टतर जीवन व्यतीत करने के लिए उनके हृदय में श्रमिलापा व हृढ़ इच्छा-शक्ति का सचार-यह वास्तव में एक मानवीय समस्या है।" इस उद्देश्य के पूर्ण होने के लिए इस बात की श्रावश्य-कता है कि निकास कार्य-क्रम ग्रामीण जनता के ऊपर बलपूर्वक न लादे जाये. वरन् इस वात का प्रयास किया नाय कि उन लोगों में ही श्रात्मावश्वास का उदय हो श्रीर वे नियोजन के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से विच ले उकें। सामुद्रायिक विकास योजनाम्नां के श्राधारभूत सिद्धान्त निम्न हैं :---

- (श) "विकास कार्यं के लिए प्रेरक-शक्ति स्वय प्रामवासियों से श्रानी चाहिए। श्रामों में विपुत शक्ति निष्किर रूप में विखरी पदी है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। श्रवएव इस बात की श्रावश्यकता है कि वह शक्ति कियात्मक कार्यों के लिए नियोजित की जाय श्रोर प्रत्येक परिवार के सदस्य क केवल श्रपने हित के लिए कार्यं करें वरन् सामुदायिक कल्याण् के लिए भी समय दें।"
- (न) "सहकारिता के सिद्धान्त को विविध रूपों में लागू होना चाहिए, जिससे आम्य-जीवन की अनेक समत्याएँ इस की जा सर्वे।"

सामुटायिक विकास योजनाश्चों के तीन उद्देश्य हैं. (१) कृषि, बागवानी, पशु-पालन, मछली-पालन श्चादि में वैश्वानिक विधियों को लागू करके श्रीर अन्य पूरक धर्षों व कुटीर-उद्योगों को प्रारम करके वेरोजगारी दूर की जाय श्रीर उत्पादन में वृद्धि की जाय (२) जनता के सहयोग से प्रत्येक ग्राम या कई ग्रामों को मिलाकर कम में कम एक बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्या होनी चाहिए जिसमें कृषि करने वाले लगभग सभी परिवारों के प्रतिनिध हो, (३) गाँव की सहकों, तालाबों, पाठ-रागलाखों, स्वास्थ्य-नेन्द्रों छ। दि सार्वजनिक हित के निर्माण-कार्यों के लिए सुसगठित प्रयास होना चाहिए। इसके प्रतिरिक्त ग्रामोण जनता में प्रगतिशील दिष्टकोण उत्पन्न करने की भी छावश्यकता है।

यह सामुदायिक विकास योजना २ श्रक्तूबर १९५२ को प्रारंभ की गई थी, जिसके अन्तर्गत ५५ केन्द्रों में सामुदायिक विकास योजनाएँ प्रचालित की गई'। इन योजनाश्चों का कार्यक्रेत्र लगभग ३०,००० ग्रामों तक विस्तृत है जिनकी जनसञ्या लगमग १ करोड़ ६८ लाख है। कालान्तर में ग्रोर मी ग्रधिक सामदा-यिक विकास योजनाएँ चलाई गई श्रोर २ श्रक्तूबर १६५३ को राष्ट्रीय प्रसार सेवा के ग्रन्तर्गत प्रसार-महलों (Extension Blocks) का भी समारभ किया गया । इस प्रकार इस समय दो योजनाएँ साथ-साथ चल रही हैं, जिनमें से प्रथम हैं सामदायिक विकास योजनाएँ श्रीर दितीय हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवाएँ। 'इन राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के भी वही उद्देश्य हैं जो सामुदायिक विकास योजनाओं के हैं। कृषि, पश्-पालन, शिचा, स्वास्थ्य श्रादि चेत्रों में दोनों के कार्य-क्रमों में पर्याप्त समानता है। उनमें यदि कोई मेद है तो यही कि सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्य-क्रम विस्तृत है श्रीर इसके श्रन्तर्गत स्थानीय कार्यों पर पर्याप्त धन-राशि मी न्यय की जायगी योजना में यह न्यवस्था की गई है कि जिन विकास-मंहलो की प्रगति पर्यात रूप से संतीयजनक होगी श्रीर जहीं जनता का सक्रिय सहयोग श्राप्त होगा. उन्हें सामुदायिक विकास योजना के श्रन्तर्गत सुसगठित के लिए चन लिया जायगा।

संगठन—समुदायिक विकास योजना की न्यवस्था पचायतों श्रीर इसी उद्देश्य के लिए निर्माण की गई श्रन्य उच्च संस्थायों द्वारा की जाती है। "जनता श्रीर उसके श्रनेक प्रतिनिधियों में माफी विचार-विमर्श करने के उपरान्त विकास कार्य-क्रम निश्चित िया जाता है। गाँव के स्तर पर नियोजन का कार्य भार पचायत पर ही रहता है। वही विकास कार्यन्म को कार्यान्वित मी करती है। जिन चेत्रों में या तो पचायतें विल्कुल है ही नहीं या उनका श्रिषक प्रभाव नहीं है, वहाँ यह प्रयास किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण विकास सिन्तियों की स्थापना की लाय, जिन्हें ग्राम-विकास महल, ग्राम महल समिति, ग्राम सेवा सब श्राद कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इन्हीं सस्थाश्रो के द्वारा नियो-जन के कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने के लिए जनता का सिक्य सहयोग प्राप्त

होता है। विकास मडल के स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जाती है, जिसमें ग्राम समितियां के प्रांतनिधि, विवान-परिषद, विधान-समा व ससद के सदस्य, महकारी समितियों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषक आदि समिन लित होते हैं। यह परामर्शदात्री समिति ग्राम सस्थात्रों द्वारा तैयार की गई योज-नाश्रों पर विचार करती है। फिर इस परामर्शदात्री समिति द्वारा निर्माण की गई महल की विकास योजनाओं को जिला विकास समिति के द्वारा जिले की विकास-योजना के कार्य-क्रम में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस जिला विकास समिति में प्रमुख गैर सरकारी व्यक्ति श्रीर जिले के श्रनेक टेक्निकल विमागों के श्रध्यक्त र्चाम्मलित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विकास योजना तैयार करने श्रीर उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकारी और गैंग्सरकारी सगठन साय-साय कार्य करते हैं । इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि "वर्तमान शासन-सम्बन्धी सरकारी ढाँचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जा रहा है कि वह जन-कल्याया के टायित्व का भी ।नवांद्दकर सके, जिसका परिशाम यह है कि सामान्य प्रशासनयत्र से भिन्न एक पृथक जन-कल्याण विभाग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रशासन-यत्र (administrative machinery) की रचना राजस्व-सम्रह (revenue collection) का निरीक्षण श्रीर नियम व न्यास्या की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी, उसने परि-वतित होकर कल्या एकारी शासन का रूप ग्रहण कर लिया है और सरकार के विकास-सम्बन्धी सभी विभागों के साधनों का उपयोग ग्राम-विकास की समस्याओं को इल करने के लिए किया जा रहा है।"

विकास-सम्बन्धी नीति के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राप्य में एक राप्य विकास सिर्मात (State Development Committee) की स्पापना की गई है, जिसमें मुख्य मनी श्रीर विकास-कार्य ने सम्बद्ध श्रनेक विभागों के श्रध्यस्त सिर्मालत होते हैं। डेवलपमेन्ट कमिश्नर इस सिर्मात का मनी होता है श्रीर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वह सरकार के विकास के सम्बन्धी अनेक विभागों के श्रध्यस्त श्रीर मिन्त्रयों के दल का प्रधान भी होता है। जिले, तहसील श्रीर महल के स्तर पर ऐसा ही समन्वय स्थापित करने के लिए डेवलपमेन्ट कमिश्नर से समान ही कमश क्लास्टर श्रीर महल-विकास श्रिधकारी (Block Development Officer) को भी उसी प्रकार के कार्य सौपे गए है। विकास-सम्बन्धी शासन की इस शृ खला में प्राम-सेवक श्रन्तिम कड़ी के समान होता है श्रीर जिले के शासन का एक श्रम समक्ता जाता है। श्रीर वहु-उद्देशीय कार्य करमें पड़ते हैं। शासन के ढाँचे को निर्माण करने का उद्देश्य यह है कि

श्रिधिकारी अधिक से अधिक कार्यज्ञमता मे काम करें त्रोर जनता से अधिकतर

योजना के अन्तर्गत-राष्ट्रीय विस्तार श्रोर सामुदायिक विकास योजनाय प्रयम पचवर्णीय योजना की देन है। कार्य की इकाई एक विकास मडल है, सहयोग उपलब्ध है। जिसके ग्रन्तर्गत लगभग १०० ग्राम भ्राते हैं, जिनकी जनसङ्या २०,००० से लगाकर ७० ००० तक होती है, ग्रोर उनका चेत्रफल १५० में १७० वर्गमील तक हो सकता है, १६५२ में जन से यह कार्यक्रम ग्रारम्म हुआ है, समुटायिक विकास योजना के अन्तर्गत ३०० महल और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत Eoo सहल बना लिए गये हैं, श्रीर इस प्रकार १९५६ तक विस्तार महली का योग १२०० हो गया है। इसके अन्तर्गत तालिका नं०१ के अनुसार १२३००० माम श्रीर द करोड व्यक्ति श्रा जार्येने।

तालिका न० ?

मीम आर -	तालिका न०	?		त्या गया
विकास मजल का कार्य जो	प्रथम पचवर्षीय	योजना काल र	SHAM .	जोड
विकास मज्य नः १६५२-५३	१६५३.५४	१ हत्र ४-४५	1544-44	
				₹००
विकास मडल	ુ પૂર	2013	३६६	800
सामुदायिक विकार	२५१	२५३	385	१२००
राष्ट्रीय विस्तार	80 30X	२५3		
जाइ				३२,६५७
म्राम संस्था सामुदायिक विकास २५,	२६४ ७,६६३	, र्मे ^{,३००}	३६६००	£0,000
खानुदारिक	२५, १०	The state of the s	38,400	१,२२,६५७
जोड़ र्य	36 R 35 VE			२०.४
जनसंख्या (टस लाख में)		٧.٥		- 4.4
सामुदायिक विकास	१६.४	१६६ १६.	, २६.	
		२०६ १६	७ २६	
जोड़ '	79.8	कलो को ग्राव	(म्म करना	ग्रार प्रदेश
जोड़ जोड़ विकास चेत्र में मरी स्कूलों को वेसिक लिये शिचा नेन्द्रों का	१४००० मप	वितित किया	जाना है,	ग्रीर ५१५४ प्राइ- ३५००० वयस्तों के वयस्क साद्यर किये
मरी स्कूलों को वेसिक	रक्षा ज्यापित करनी	जिनके हार	(90,200	
लिये शिचा मन्द्रा का	Zan.			

गये हैं, तथा ४०६६ मील पक्ती श्रीर २८००० मील कभी सहक का बनवाना श्रीर ८०,००० शीचालयों का गाँवों में निर्माण करवाना स्थानीय विकास के उदा- हरण हैं। विनका सामाजिक प्रभाव बहुत ही महत्वशाली होगा। इस कार्य में बहुत श्रिविक श्रशा तक सहायता जनता तथा विस्तार योजनाश्रों को कार्यान्वित कराने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। यह त्राम उद्योगा तथा सहकारिता के चित्र में सकलता कम प्राप्त हुई है, इसका कारण यह सम्पूर्ण देश के हिन्दकीण से ही देखा जाय तो सहकारिता तथा नवीन उद्योगों की कार्य व्यवस्था का दोष है, जिसमें सुवार करना चाहिए।

"राष्ट्रीय विकास परिपद् ने सितम्बर १९५५ में यह स्वीकार कर लिया था कि द्वितीय पचवर्षीय योजना में समन्त देश राष्ट्रीय विकास देवा योजना के प्रन्तर्गत ब्रा नायगा ब्रोर ना राष्ट्रीय विस्तार महल समुदायिक विकास महलों में परिणत कर दिये नार्येंगे, ब्रार उनकी सख्या ४०% से कम न होगी। यदि पर्राप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हा सकेगी तो सम्मवत यह सख्या ५०% मी हो जाय। द्वितीय योजना म ३८०० नये विकास महल राष्ट्रीय विस्तार योजना के कार्यक्रम के ब्रान्तर्गत ब्रारम्म किये नाने वाले हैं ब्रीर यह ब्राशा की नाती है कि इनमें से ११२० समुदायिक विकास महलों में परिणित कर दिये नार्येंगे। योजना के इस कार्य के लिए २०० करोड़ रुपयों का भी प्रसन्ध प्रवन्ध किया गया है।"

'सामुदायिक योजना प्रशासन के निश्चित किए हुये कार्यक्रम के श्रनुसार दितीय पचवर्षीय योजना में, प्रत्येक वप, राष्ट्रीय विस्नार महल तथा उनके सास-टायिक विकास महलों में परिणान किये जाने का कार्य किया जाया करेगा।" जैसा कि तालिका न० २ में टिखाया गया है।

तालिका न० ? विस्तार महलो की संख्या

वर्ष	राष्ट्रीय विस्तार सेवा	सामुदायिक विकास महलों में परिवर्तन	
१६५६-५७	400	२५०	
१९५७-५८	६५०	₹00	
१९५८-५९	OKO	2६ ०	
₹ E4E-€0	- 003	300	
१६६० ६१	१०००	३६०	
	3500	११२०	

द्वितीय पचवर्षिय योजना के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में यह मावना उत्पन्न करनी होगी कि अपने रहन-सहन के स्तर को सुधारना तथा एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करना और उसमें सहयोग देना उनका कर्चन्य है। यह आशा की जाती है, कि राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा और अन्य अनुप्रक कार्यक्रम द्वारा आगामी कुछ वर्षों में ही कृषि उत्पत्ति में वृद्धि के अतिरिक्त निम्न अन्य चैत्रों में उन्नति होगी। (१) सहकारिता के कार्य में जिसमें सहकारी कृषि भी समित्तित हैं विस्तार होगा। (२) ग्रामोन्नति में सक्रय उत्तरदायित्व खनेवाली संस्थाओं के रूप में ग्राम प्चायतो का विकास होगा, (३) भूमि की चकन्दरी, (४) प्राम के छोटे उद्योगों का विकास होगा, (५) ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना हागा जिनमें गाँव के पिछड़ी हुई जनता को जैसे छोटे-छोटे कृषक, भूमिहीन कृषक, कृषि कार्य करने वाले मजदूर एव शिल्पी हत्यादि, (६) छियो और नवयुवकों की उन्नति के लिये श्रीर पिछड़ी जातियों के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाये जार्येंगे।

"देसे बहुमुखी कार्यक्रमो को कार्यान्वत करने के लिये जिसके अन्तर्गत उद्योग, सहकारिता, कृपि उत्पादन, भूमि सुघार, तथा सामाजिक सेवाये आवी हैं. जो चेत्र राष्ट्रीय विस्तार तथा सामूदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिये चुने जायेंगे, उनके शीघ ही उन्नांत करने की बहुत श्रिधिक सम्मावना होगी। जब इन कार्य-कर्मों को खयोजित रूप से कार्यान्वित किया जाता है, स्रीर स्थानीय संस्थात्रा का सहयाग व्यवस्थित रूप से प्राप्त होता है, तो एक कार्य में सफलता दुसरे में सफलता के लिए अवसर प्रदान करती हैं। और इस प्रकार सम्पूर्ण चेत्र में आपिक व्यवस्था हु हो जाती है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत विकास वार्य-क्रम में क्रांव उत्पादन को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। इसके पश्चात ग्राम की सबसे अधिक महत्वशाली आवश्यकता कार्यं करने के पर्याप्त अवसरों का प्रदान करना है। सतुलित ग्राम्य श्राधिक व्यवस्था में यह श्रावश्यक है, कि श्रीद्योगिक कार्यों के अवसरों की कृषि कार्यों को अपेद्धा दृढतर गति से वृद्धि की जाये। इाल के ग्राम तथा छोटे उद्योगो के विकास कार्य-क्रामों के सम्बन्ध में जो अनुभव इन्ना है उससे यह सकेत मिलता है, कि ऐसी विस्तार सेवा की श्रावश्यकता है, जिसका सम्पर्क ग्रामीण शिल्पकारों से हो श्रीर जो उन्हें श्रावश्यक पथप्रदर्शन कर सके. सहायता दे सके, उनकी सहकरिता के आधार पर न्यवस्था कर सके और अपने माल को गाँव में तथा बाहर बेचने में सहायता दे सके। इसका प्रारम्भ २६ श्रमगामी योजनाश्रों को कार्यान्वित करके किया जा चुना है। यह त्रावश्यक है

कि यथासम्भव शीव्र प्रत्येक विस्तार तथा सामुटायिक विकास चेत्र मे एक प्रवीख प्रशिक्षित इन ग्राम उद्योगो के कार्यक्रम को चलाने के लिये नियुक्त किया जाय।

वित्त की व्यवस्था—इन विकास कार्य कम के लिए वित्त की व्यवस्था समुदायिक योजना प्रशासन (Community Project Administraton), रात्य सरकारों ख्रोर जनता के द्वारा की जाती हैं। सी० पी० ख्राधिक रूप से वित्त का प्रवन्ध तो करता ही है, इसके अतिरिक्त उस पर विशेष यन्त्रों व नत्सम्बन्धी ख्रन्य साम्राध्यों को उपलब्ध करने का भी टायित्व है। इस विकास कार्य-कम को कार्यान्वत करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने पर जितना व्यय होगा, उसका ख्राधा धन राज्य सरकारों को नेन्द्रीय सरकार द्वारा आधिक सहायता के रूप में प्राप्त होगा केन्द्रीय सरकार यह प्रयास भी कर रही है कि योजना की अवधि समात होने तक सहकारी ख्रनदोलन और अन्य एजेन्सियों के द्वारा अल्पकालीन, ख्रीसतकालीन और दीधकालीन ऋण के रूप में कमश्र १०० करोड, और २५ करोड़ रुपये का धन प्रति वर्ष प्राप्त होने लगे। सामुदायिक विकास योजना के कार्य-कम पर जो धन-राशि व्यय होती है उसकी लगभग १०% भारतीय-छमरीको टेकनिकल सहयोग योजना द्वारा यन्त्रों और टेकनिकल परामर्श ख्राटि के रूप में प्राप्त होती है।

सामुटायिक योजनाओं और विकास महलों के लिए १६५२-५३ से लेकर १६५५-५६ तक कुल मिला कर ३२६० करोड़ रुपये घन का वजट में स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार माच १६५४ तक प्रथम १८ महीनों में न्यय के लिए १६.३० करोड़ रुपये निर्धारित थे, किन्तु इस अविध में वास्तव में जो घन राशि न्यय की गई वह केवल ५६५ करोड रुपया थी। इसके अतिरिक्त इस अविध में नकट धन, अम, सामग्री आदि की ऐन्छिक सहायता के रूप में कुल मिलाकर २६३ करोड रुपया का घन प्राप्त हुआ, जो सरकारी न्यय के घन के आपे से योझा ही कम है। प्रारम्भिक काल की अनेक कितना अर्थों के कारण योजना की प्रगति धीमी रही, किन्तु जब हम इस तथा पर ध्यान केन्द्रित करते हैं कि जून १६५४ तक न्यय की कई धनराशि ८१० करोड़ रुपये तक पहुँच गई, तो भविष्य में अधिक जीख प्रगति होने की सभावना प्रकट होती है।

वीमी प्रगति के कारण्—सामुदायिक योजनात्रो की प्रगति का मूल्याक्त करने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन के सह्योग से एक कार्य-मूल्याक्त संस्था (Programme Evaluation Organisation) की स्थापना की गई है। सामुदायिक योजनात्रों को कार्यान्वित करने के मार्ग में निम्न कठिनाइयाँ हैं—

(१) प्रारम्भिक अवस्था में प्रगति के अवस्द होने का कारण यह था कि

जनता उदासीन थी श्रीर श्रन्य लोकप्रिय व्यक्तियों ने भी योजना के कार्य-क्रम में सिक्तय रूप से भाग नहीं लिया। इस स्थिति में किसी सीमा तक सुधार ग्रवश्य हुआ है, किन्तु फिर भी शामवासियों का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। प्रगति के धीमी श्रीर श्रनिश्चित होने का यह एक प्रमुख कारण था।

- (२) पचायतों श्रयवा विशेष कर इसी उद्देश्य से स्थापित की गई श्रन्य लोक प्रिय सस्थाश्रों से जो सहयोग प्राप्त हुया है, वह श्रपर्यात है। पचायतें सभी चेत्रों में नहीं हैं श्रोर जहाँ हैं भी, वहाँ उनमे गुटवन्दी के कारण प्राय: समर्थ चलता रहता है। सहकारी सस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं, किन्द्र विकास योज नाओं के सम्बन्ध में उनकी उपयोगिता सीमित ही है। उनके नियमों के श्रतुसर सामन्य रूप से सदस्य भी नहीं बनाए जा सकते, वयोंकि उनका सुनाव किया जाता है। सहकारी सस्थाओं की रचना ही कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है जिससे उनके कार्य सीमित होते हैं। विकास कार्य-क्रम की सहायता के लिए श्रतेक परामर्श्वरात्री सस्याओं की स्थापना की गई है जिनके मिन-भिन्न नाम है श्रोर जो कुशल श्रधिकारियों के निर्देशन में सन्तोपजनक कार्य कर रही हैं। किन्द्र भी यह श्राश्यका बनी हुई है कि जब सरकारी श्रधिकारी हटा लिए जायेंगे, तो समन है कि ये सस्थाएँ कार्य करना बन्द कर दे।
- (३) धीमी प्रगति के लिए उचित योजना का अभाव भी अधिक सीमा तक उत्तरदायी है। विकास की प्रगति इसलिए धीमी नही रही है कि आवश्यक वित्त का अभाव था, वरन् उसका कारण यह था कि प्रारम्भिक अवस्था में अधिकारियों-द्वारा बजट में कोई निश्चित मात्रा निर्धारत नहीं की गई। इसके अतिरक्त अन्य कारण भी थे। बजट बहुत जल्दी में तथा अस्पष्ट विचारों के साथ वैयार किए जाते थे तथा धनराशि को मजूरी देने के पूर्व विवरण जानने में समय समता था।

(४) कार्य-कम की इस धीमी प्रगति और अनेक भूलों के लिए प्रशिज्ञण-प्राप्ति कर्मचारियों का श्रभान बहुत बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। किन्तु अब अधिक सख्या में कर्मचारियों को प्रशिज्ञण देकर यह अभाव शीवता से दूर किया जा रहा है।

पी० ई० श्रो० की तीषरी सफलताकन रिपोर्ट (Evaluation Report) ने कार्य को समुचित रूप से चलाने के सम्बन्ध में श्रानेक प्रयागात्मक सुकाव ादये हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्य-क्रम को आशानुक्ल सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि (१) औद्योगिक विभागों को प्रत्येक दिशा में

श्रीर प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में दृढ बनाया जाय । श्रनेक स्थानी पर प्रत्येक चेत्र तया जिला सम्बधी त्रोयोगिक विभागीय व्यवस्था की समता तथा सख्या में सुघार करना आवश्यक हो गया है, (२) इसके अतिरिक्त अन्वेषण के कार्य की मुविधात्रों का विस्तार किया जाय, भूमि के श्रास-पास के गवैपणागारों को विस्तत किया जाय श्रोर इस बात का विशेष ध्यान दिया जाय कि खेतों से सब सूचनायें गवेषस्पारों तक पहुँच जॉय, (३) विभिन्न विषयों के विशेषजों पर चेत्र विकास वर्मचारी के नियन्त्रण (जो ज्ञावश्यकता से अधिक हो सकता है) तथा जिलों के श्रन्य पाविधिक श्रिधिकारियों के दुहरे नियन्त्रण की व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही है। (४) निर्माण कार्यों ने ग्रामों मे कार्य करने वाले कर्मचारियों का जिनको कृषि तथा कृषि विस्तार नी प्रारम्भिक शिक्षा मिली है श्रौर जिनका सबसे श्रधिक श्रावश्यक कर्त्तन्य कृषि उत्पादन बढाने का है, श्रधिकाश समय ले लिया है, (५) ग्राम पचायतों को श्रपने वृद्धिमान उत्तरदायित्व को जो कि उनके ऊपर डाल दिया गया है पूर्ण करने के लिये सदैव पथ प्रदर्शन तथा सिक्य सहायता मिलनी चाहिए, (६) कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने मे श्रावश्यकता से श्राधिक महत्व मोतिक श्रौर श्राधिक सफलताश्रो पर दिया गया है, जैसे निश्चित किये हुये कार्य हे, व्यय श्रीर भवन निमाण के व्येनों को पूरा करना इत्यादि, श्रीर जनता को नये दम से कार्य करने की शिज्ञा देने तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सुघार श्रीर विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के पूर्ण करने के लिये, जो राष्ट्रीय प्रादेशिक वोजना के श्रन्तर्गत है, एक प्रमावशाली साधन बनाने की श्रोर कम यान दिया गया है।

कार्य करने में त्रुटि—णमुदायिक विकास योजनाश्चों ने श्रामीण जनता में श्रात्मिवश्वास उत्पन्न करने में बहुत कुछ योग दिया है। उसने श्रामिवासियों को इस बात का श्रामास दिया है कि श्राम्य-जीवन में निश्चित रूप से कुछ गड़-वड़ी है जिसका पारस्परिक सहरोग के श्राघार पर ही सुधार किया जा सकता है। श्रामी इतना श्राधिक समय नहीं हुश्रा है कि इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निकर्ष पर पहुँचा जा सके, किर भी इतना वो कहा ही जा सकता है कि सामुदायिक विकास योजनाशों ने उत्पादन वढ़ाकर श्रीर वेरोजगारी कम करके श्रामों में रहन नहन का त्तर किंचा किया है। किन्तु जिस रूप में कार्य-कम को नार्यान्वित किया जा रहा है उसमें कई दोप हैं। (१) भूमिहीन खेनिहर मजदूरों के श्रम का उपयोग करने की समुचित व्यवस्था नहीं है। कृषि के चेत्र में उत्पादन-वृद्धि श्रीर कृषकों के लिए कार्य के श्रवसर उत्पन्न करना ग्रह्मत महत्वपूर्ण है, किन्तु भूमिहीन मजदूरों को वसाने की व्यवस्था भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब कभी विकास योजनाश्चों

के श्रन्तर्गत त्रास्थायी रूप से मजदूरी देकर कार्य करने की श्रावश्यकता पड़ती है तभी इन्हें योडा-बहुत कार्य मिलता है। इसके अतिरिक्त वे नि:सहाय, वेरोजगार श्रोर उपेद्वित-से रहते हैं, (२) यदि दूसरे दिष्टिकीश से देखा जाय वो सामुदायिक निकास योजनात्रों के कार्य-कम मे एक और टोज प्रकट होगा। वह यह है कि खेतिहर मजद्रों को पूरक कार्य उपलब्ध कराने के लिए ग्राम्य-उद्योगों की स्थापना करने पर विशोध ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में पी० ई० श्रो० की यह घारणा है कि "प्रामीण उत्योग-घन्धो की ग्रानिश्चित समावना के पीछे चाहे जो मी कारण हों, किन्तु तथ्य तो यह है कि सामुदायिक विकास योजनात्रों के वर्तमान स्वरूप श्रीर साधनों से भूमिहीन मजदूरो की वेरोजगारी की समस्या हल करने की थ्राशा नहीं की जा सकतीं"। किन्तु पीo ईo स्रोo का यह दृष्टिकीं गलत है। चिक सामुदायिक विकास योजनात्रों का उद्देश्य है कि उत्पादन कार्य प्रौर प्रामीख जनता की श्राय में वृद्धि हो श्रीर आमवासियों में नई श्राशा का संचार किया जाय, इसलिए गैर खेतिहर वर्ग की वेरोजगारी को समस्या को उपेजा की दिव्ह मे देखना उचित नहीं है ऐ. हा करने पर सामुदायिक विकास योजनात्रों की उपयो-गिता बहुत कुछ कम हो जायगी, (३) सामुदायिक यिकास योजना के अन्तर्गत भूमि की समस्या को सुलकाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। चकम्दी का कार्य एक अन्य सगठन द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इसने अभी श्रविक सफलता नहीं पास की है। वस्वर्ड, उत्तर-प्रदेश ग्रीर सीराष्ट्र को छोड़कर सहकारी कृषि के चेत्र मे श्रिधिक प्रगति नहीं हुई है ग्रीर इन राज्यों मे भी यह श्रान्दोलन श्रपनी प्रार्राम्मक श्रवस्था में ही है। बहुत से कुपकों के पास कृपि के लिये इतनी कम भूमि है कि उस पर कृषि करना ग्रार्थिक दृष्टि से लाभ-पूर्ण नहीं है। जब तक कृषि की इकाई के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि का चेत्रफल नहीं भढाया जाता और निम्नतम लागत से अधिकतम उत्पादन नहीं होगा, तब तक किसान खेती की विकसित प्रणालियों का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकेरी, छोर (४) सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्रम में अब तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे जन-सख्या की वृद्धि पर नियत्रण रखा जाय श्रौर परिवार-ग्रायोजन (Family Planning) का सुचारु प्रमन्य हो सके। जब तक यह कार्य नहीं हो जाता तब तक भारतीय ग्रामीण जनता की जठिल समस्यार्थी को सन्तोपजनक रूप में इल करने की त्राशा करना न्यर्थ है। उत्पादन बढाकर श्रीर जन-सख्या की वृद्धि को नियन्नित करके ही आमवासियों के रहन सहन का स्तर ऊँचा किया जा सकता है।

श्रध्याय १२

सहकारी आन्दोलन

भारत में सहकारी श्रान्दोलन का विकास २० वीं शनाब्दी में हुशा। सहकारिता का अर्थ है किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर प्रयत्न
करना। समान उद्देश्य की दृष्टि से यह व्यक्तिगत प्रयत्न श्रीर सहायता से बिल्कुल
भिन्न है। श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सब की परिभाषा के श्रनुसार सहकारी समिति ऐसे
व्यक्तियों की सस्या है जिनकी श्राधिक स्थिति श्रव्छी नहीं है श्रीर जो समान
श्रिषकार तथा उत्तरदायित्व के श्राधार पर स्वेच्छा-पूर्वक सगठित होकर श्रपनी
ऐसी समान श्राधिक श्रावश्यकताश्री की पूर्ति का भार एक सस्या को सीप देते हैं
जिनको वह श्रपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा पूर्णत सन्तुष्ट कर सकने में श्रसमर्थ
होते हैं। यह लोग श्रापस में मिलकर इस सस्या का प्रवन्ध करते हैं श्रीर समान
मौतिक एवम् नैतिक लाभ उठाते हैं। इस प्रकार सहकारी स्विति समान हितों का
सब है, यह समान श्रिषकार प्राप्त सदस्यों का स्वेच्छा से निमित एक ऐसा श्रायिक
सगठन है जो श्रपने सदस्यों की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करता है श्रीर उनके
समान हितों की रह्या करता है।

सहकारी समितियाँ दो प्रकार की हैं—(१) रेफिजेन (Raiffeisen type) श्रीर (२) शुल्ज ढेलिरज (Schulze Delitsch type)। इन दो प्रकार की सहकारी समितियों में जिन व्यक्तियां का नाम सम्मिलित है वह जर्मनी में सहकारी श्रान्टोलन के प्रऐता थे। प्रथम प्रकार की सहकारी समिति के सिद्धान्तों का उपयोग प्राम में सगितित की जानेवाली समितियों में किया जाता है श्रीर दूसरे प्रकार की समितियों के सिद्धान्तों का उपयोग नगरों में किया जाता है। रेफिजेन-सिर्मितियों का कार्य चित्र प्राय एक प्राम तक सीमित रहता है श्रीर इनके सदस्यों का उत्तरदायित्व श्रीमित होता है। इन समितियों से केवल सदस्यों को ही श्रुण विया जाता है श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलिस्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलिस्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलिस्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलिस्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलिस्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलिस्ज समितियों का कार्य सेत्र श्रीर वह भी सेवश श्रुक्क वस्त्ल करती है श्रीर विना श्राय वाला व्यक्ति इस सा सदस्य नहीं वन सकता है।

वित्त, उत्पादन, वितरण इत्यादि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन समितियों को समिठित किया जा सकता है परन्तु भारत में ऋण देने वाली साल समितियों का ही प्रमुत्व है। वास्तव में भारत में सहकारी आन्दोलन आरम करने का निश्चित उद्देश्य गामों में ऋण की भयानक समस्या को हल करना और गामीणों को मुविधा जनक रीति से ऋण देना था। भारत में जून १६५५ में सब प्रकार की २,१६,२८८ समितियों की तुलना में जून १६५६ में २,४०,३६५ सहकारी समितियों थीं। कृषि साख समितियों ही प्रमुख थीं। इनकी संख्या कुल समितियों की ६७३% तथा कृषि समितियों की ८०३% थी। आन्दोलन अब भी साख-प्रधान है।

विकास—भारत में सहकारी आन्दोलन के इतिहास की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण घटना १६०४ का सहकारी साख-सिमित श्रिधिनयम है। इस नियम के बनने
से पूर्व भी मद्रास में सहकारिता के सिद्धान्तों का महत्वपूर्ण विकास हो रहा था।
वहाँ साख-सिमित्यों का कार्य 'निधियाँ' करती थी। देश में सहकारिता के विभिन्न
पहों का श्रध्ययन करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम १६०१ में एक सिमित नियुक्त
की। इस सिमित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब तक सरकार अधिनियम
नहीं बनाती इस दिशा में विशेष प्रगति की समावना नहीं है। इसी रिपोर्ट के
आधार पर सरकार ने सहकारी साख-सिमित अधिनियम पास किया। इसमें केवल
साख-सिमित्यों की अपवा की गई थी। इस प्रकार अन्य देशों की अपेचा मारत
में सर्वप्रथम साख-सिमित्यों का ही विकास हुआ। नियम लागू होने के परचात्
यह अनुभव किया गया कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। साख-सिमतियों के पास प्राम में भ्रुण प्रथा समाप्त करने के लिए आवश्यकता से बहुत कम
पंजी थी।

इस नियम के दोषों को दूर करने के लिए १६१२ में दूसरा सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया। इस नियम में क्रय-विक्रय करने वाली अन्य प्रकार की सहकारी समितियों का सगठन करने को व्यवस्था की गई। नगर और प्राम समितियों के अदर को मिटा दिया गया। सोमित उत्तरदायित्व और असीमित उत्तर-दायित्व के आधार समितियों को अधिक वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया। नियम में यह निश्चत कर दिया गया कि जिन समितियों के सदस्य रजिस्टर्ड समितियों हैं वह सीमित उत्तरदायित्व वाली समितियों होंगी और साख-समितियाँ तथा ऐसी अन्य समितियों जिनके अधिकाश सदस्य कृषक हैं असीमित उत्तरदायित्व साली समितियों होंगी। इस नियम से सहकारी आन्दोलन के विकास में सहायता मिली। उत्पादन के विकाय के लिए, पशु-बीमा, दूध की पूर्ति और खाद इत्यादि क्रय के लिए नई प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई।

मैकलैगन समिति की रिपोर्ट के आवार पर सहकारी आन्दोलन के विकास

में एक और प्रयास किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर १६१६ के सुधार अधिनियम (Reform Act) के द्वारा सहकारी आन्दोलन का कार्य राज्य-सरकारों को सीप दिया गया। राज्य सरकारों ने कुछ वर्षों तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की परन्त १६२५ में वम्बई की सरकार ने अलग से सहकारी सिति अधिनियम नियम बनाया। इसके पश्चात अन्य राज्यों में भी आवश्यक कानून बनाये गये।

सहकारिता श्रान्दोलन के विकास का कुछ श्रनुमान इस बात से लग सकता है कि १९५१-५२ में समितियों की सख्या, सदस्या सख्या तथा कुल चालू पूँची क्रमशः १९८५ लाख, १३७ ६२ लाख तथा ३०६ १३४ करोइ ६० यी । १६५५-५६ में यह बढ कर कमशं २४० लाख, १७६°२ लाख श्रीर ४६८ ८२ करोड़ ६० हो गई। विभिन्न प्रकार की समितियों के दृष्टिकोग् से अन्य समितियों की अपेन्ता क्रिय साख समितियों में वृद्धि अधिक हुई है। पिछले वर्षों की ही तरह साख समितियाँ ही अधिक प्रधान रही और कुल चालू पूँची का ७५% साख चेत्र में ही था। यह मानते हुए कि मारतीय परिवार के सटम्यों की श्रीसत सख्या ५ है हम कह सकते हैं कि रेट्यूप्र-पूर्व में ८ ८ करोड़ व्यक्ति प्रथवा जनसंख्या के २३ प्रति-शत व्यक्ति सहकारी श्रान्दोलन के सम्पर्क में ग्राये। १६५१-५२ में ६६ करोड़ व्यक्ति अथवा १६ प्रांतशत जन सक्ता सम्पर्क मे आई थी। इसीप्रकार (प्राइमरी) मायसिक समितियों, जो स्नान्दोलन का प्राधार प्रस्तुत करती है, द्वारा १६५१-५२ में दिया हुआ ६७ ६५ करोड ६० था। १६५५-५६ में यह राशि बहुकर १४० ७८ करोइ र० हो गयी। दिये गये ऋण की हस वृद्धि से भी प्रगति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता हैं। चिन्ता का विषय तो यह है कि वकाया ऋ णाँ के प्रतिशत के रूप में कालातीत ऋगों में कुछ कमी अवश्य हुई है किन्तु उनका श्रनुपात श्रव भी बहुत अधिक है।

प्रगति के इस सिक्ता सर्वेन्नस्य म इस इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि (क) सहकारिता से जनसख्या का बहुत छोटा अश लाभ उटा रहा है, (ख) जनसख्या की वृद्धि के अनुकूल अनुपात में सहकारिता का विकास नहीं हुआ है, (ग) यद्यपि गैर साल सिमितियों की सख्या में वृद्धि हुई है, किर भी सास सिमितियों का ही अधिक विकास हुआ है। इसलिये सहकारिता आन्दोलन को ज्यापक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सहमारी सिमितियों में साद के अतिरिक्त अन्य पन्नों पर भी आवश्यक न्यान देना चाहिये।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ — चहकारी आन्दोलन न तो सारे देश में समान रूप से फैला है आर न सभी जगह इसका सङ्गठन समान है। सहकारी आन्दोलन ने खरह 'क' के कुछ राज्यों में विशेष प्रगति की है परन्तु अन्य राज्यों में इसका उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है। खरह 'ख' और 'ग' राज्यों में से कुछ में इस आन्दोलन का विल्कुल विकास नहीं हुआ। सम्पूर्ण देश में कुल जितनी सहकारी समितियों हैं उनका ३८ प्रतिशत और प्रारम्भिक समितियों के लगमग ४६ प्रतिशत सदस्य केवल बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में हैं जबिक उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बङ्गाल, पञ्जाव तथा हैदरावाद में कमशः ६१ तथा ६५ प्रतिशत है। परन्तु देश में जहाँ जनसख्या तथा चेत्रफल में मारी अन्तर है सहकारी समितियों की प्रगति की जॉच करने के लिए समितियों की सख्या उपयुक्त नहीं है। यह जानना आवश्यक है कि इन समितियों से कितने प्रतिशत जनता लाम उठाती है। कुछ खरड 'ख' और 'ग' राज्यों में सहकारी समितियों का कार्य सन्तोप-जनक रहा है। रिजर्व बैक्क ने सम्बन्ध दिया है कि शहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में समितियों के कार्य-चेत्र पर और खरड 'ख', 'ग' और 'घ' राज्यों में उनकी कार्य कुशलता पर विशेष महत्व दिया जाय। सक्क न सम्बन्ध दिया में उनकी कार्य कुशलता पर विशेष महत्व दिया जाय।

सङ्गठन—सहकारी सिमितियों का सङ्गठन वास्तव मे शुडाकृति (Pyramid) के समान है। इस सङ्गठन का आधार वह प्रारम्मिक सहकारी सिमितियों हैं जिनको सङ्गठित करने के लिए कोई भी टस व्यक्ति सहकारी सिमितियों के रिजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दे सकते है। विभाग के निरीक्त द्वारा आवश्यक जॉच-पड़ताल के पश्चात् सिमिति स्थापित करने की अनुमिति दी जाती है। इन सिमितियों की चालू पूँजी, प्रवेश शुल्क, सरकारी ऋण, केन्द्रीय सिमितियों तथा राज्य वैद्धों से ऋण लेकर एकत्र की जाती है। इनमें से कुछ सिमितियों के पास शेयरों की पूँजी भी है। केवल साख सिमितियों को छोड़कर इन सिमितियों का उत्तरदायित्व सीमित है और सारी व्यवस्था प्रवन्धक सिमित तथा आम-सभा के हाथ में होती है।

इन प्रारम्भिक समितियों के ऊपर केन्द्रीय समितियां और राज्यीय सहकारी समितियां होती हैं। प्रारम्भिक समितियों के सङ्गठन से केन्द्रीय समितियां बनती हैं और इन (केन्द्रीय) समितियों के सङ्गठन से राज्यीय समितियां जन्म लेती हैं। सम्पूर्ण आन्दोलन इसी प्रकार परस्पर गुँथा हुआ है। यनि केन्द्रीय साख-समितियों को अपनी पूँजी का अधिकाश भाग रिजर्व बैङ्क से अल्पकालीन ऋण के रूप में प्राप्त होता है किर भी इनकी और प्रदेशीय समितियों की व्यवस्था तथा वित्त की आवश्यकता की पृति इत्यादि कार्य प्रारम्भिक समितियों को ही तरह होते हैं। पहले केन्द्रीय समितियों को रिजर्व बैङ्क से प्राप्त होने वाले अल्पकालीन ऋण की अविष ह महीने यी परन्तु अब इसे बढाकर १५ महीने कर दिया गया है। ऋण के

धन पर न्याल की दर छेट रुपया प्रतिशत है। यह दर बैह्न के न्याल की दर से दो प्रतिशत कम है।

सहकारी समितियों के शुहाकृति की व्यवस्था में शीर्ष पर सहकारी सन्ध नाम की श्राखिल भारतीय सस्या है। इस सस्या का प्रथम सम्मेलन करवरी १६५२ में वस्वई में हुआ था।

साख-समितियाँ—प्रारम्भिक कृषि साख समितियों की सख्या जो कि सहकारी ऋण व्यवस्था का मूलाधार है, जून १६५५-५६ में १३ लाख यी श्रौर उनका सदस्यों की सख्या ७८ लाख थी।

तालिका नं० ३ प्रारम्भिक ऋषि सास समितियों का कार्य (श्रव्र वेंक श्रीर भूमिवंघक वेंकों को छोड़कर)

	१६५१-५२	१६५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५
समितियों की सख्या	१,०७,६२५	१,११,६२८	१,२६,६५४	१,४३,३२०
सदस्यों की सख्या	४७,७६, ८१ ६	प्र१,२६,००२	५८,४ ६,३८०	६५,६५,४१६
वर्ष के अन्तर्गत	(करोइ	र रुपये में)		
दिये हुए भूग की				
घन राशि	२४ २०	२५ ६९	२६ ६४	३५.१८
वर्ष के भीतर				
ऋण में वस्त की				
धनराशि	१८ ६७	२१ २१	२६ ४८	२८ ६१
वर्ष के श्रन्त में वस्त				
होने वाला ऋग	३३ ६६	39 85	४१•प्र६	४८ ५३
वर्ष के श्रन्त में				
शेष ऋग	= ५२	१० ४७	१२००३	१ ४°७०
निजी कोष	१७ ६७	१९ २७	२१ ५५५	२३•६६
जमा धन	ሄ ሄ የ	૪ % १	४६१	પુ 😘
ऋग में लिया हुन्ना घर	न २३१५	38 8E	२८ २४	३३ ५२
चालू पँजो	४५ २२	86.12	48 88	६२६३
	r v	~ ~		•

प्रारम्भिक साख समितियाँ श्रार्थिक हिंग्ट से निर्वल हैं श्रीर इस कारण कुषक को उतना लाम नहीं पहुँचा पातीं जितना कि चाहिये। गालिका न ३ सहकारी वैंकों के लिये वही कार्य करते हैं जो केन्द्रीय सहकारी बैंक छोटी सहकारी समितियों के लिये करते हैं। शीर्प बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं और अधिक आय वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की आतिरिक्त आय से घाटे में चलने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता करके सन्तुलन स्थापित करते हैं। लोगा को घन जमा करने की प्रेरणा देकर तथा ज्यापारिक बैंकों, रिजर्व बैंक और सरकार से ऋण लेकर यह द्रव्य बाजार और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बीच सबन्ध स्थापित करते हैं और इस धन से केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता करते हैं।

१६०४ के सहकारी समिति कानून में जो १६१२ में सशोधन किया गया उसके पश्चात् केन्द्रीय यूनियनों, केन्द्रीय सहकारी वैकों ख्रीर स्वींच्च बैंको ने काफी प्रगति की है। १६०४ के कानून में सशोधन करके इन केन्द्रीय सहकारी सस्याख्रों को मान्यता प्रदान की गई। फिर भी इन केन्द्रीय सस्याख्रों की सख्या ख्रीर भारतीय कुषकों को इनसे मिलने वाली वित्त सहायता पूर्णत्या ख्रप्यांस है। सास्तव में इस बात पर जोर देना चाहिये कि इन सस्याख्रों की सख्या में वृद्धि हो, इनके साधन बढाये जाय जिससे ये कुषकों के लिये ख्रिषक लाभदायक सिद्ध हो सके।

शीर्ष नैक—सहकारी अधिकोषण द्वारा की गई प्रगति का अनुमान इसी से लग सकता है कि १६५०-५१ से १६५५-५६ के बीच १० नई राज्यीय सहकारी बैकों की स्थापना की गई तथा ३० जून १६५६ को देश मे २४ ऐसी बैंके थी। केवल पाँच राज्यो—कच्छ, मनीपुर, पाँडुचेरी, त्रिपुरा अडमन और निकोशार,—मे अब तक राज्योय बैंक नहीं है। इन बैकों की सदस्यता बढकर इ६,३६४ (जिसमे ११,७४३ व्यक्ति, और २४,६५१ बैंक तथा समितियाँ थीं) तथा चालू पूँजी बढकर ६३ ३४ करोड़ द० हो गई।

शीर्ष सह कारी बैक दो प्रकार के होते हैं, मिश्रित और श्रामिश्रित । मिश्रित बैकों के शेयर व्यक्ति तथा सहकारी सस्थाये दोनो ही ले सकते हैं परन्तु श्रमिश्रित में केवल सहकारी सस्थाये ही शेयर ले सकती हैं। यदि प्रत्येक शीर्ष वैंक श्रमिश्रित दग के ही होते तो सहकारिता आन्दोलन की भावना के सर्वथा अनुक्ल होता। परन्तु श्रमिश्रित बैक तो केवल श्रान्ध्र, पजाब, पाच्छमी बङ्गाल श्रीर मैस्र ही में प्रचलित हैं। शेष सब राज्यों में मिश्रित बैक ही हैं।

१६५५-५६ में शीर्ष वेकों की चालू पूँजी में (जो ६३.३४ करोड़ रुपए थी) निजी कोष १२.१%, जमा धन ५७ ६% तथा अन्य आतो से प्राप्त ऋगा ३०% था जब कि १६५१-५२ में यह प्रतिशत क्रमशः ११४,५७७ और ३० ८ थे इन वैंकों के निजीकोय का इतना कम होना नही चिन्ता रा विषय है ययोकि निना निजी कोप में बृद्धि के इन में स्थिरता श्राना सम्भव नहीं।

ये वैंक वर्तमान समय में ऋणा श्रीर जमाधन पर श्रपना रार्म चलाने के लिए निर्भर रहते हैं। १९५५-५६ में ३६ ६७ करोड़ का के जमान्वन में १८-८५ करोड़ का गैर-सहकारी स्रोतों से प्राप्त किया गया रिवर्व वैंक श्रीर सरकार से लिये नये ऋणा की मात्रा कमशः २२'२ करोड़ का तथा ७% करोड़ का थी। १९-२ करोड़ का की शन्य ऋणा की राशि में व्यापारिक वंगों से लिया गया ऋणा १,०५१,००० का तथा सहकारी वैंकों से लिया ऋणा ८८,००० था। इसमें व्यापारा वैंकों पर निर्भरता घटती श्रीर सरकार, रिजिय वैंक तथा सहकारी ने को पर चढती दिखाई पढ़ती है। इन वैंकों का लगमग १८'३६ करोड़ कपया सहकारी तथा श्रन्य प्रतिभृतियों (हस्टी सिवयोरिटीज) लगा हुश्रा था।

"गायीय सहकारी वैंकों द्वारा दिये गये श्राप्तम (advance) की माता १९५४-५५ के ५० १४ करोड़ कपया से गढ़कर १९५५-५६ में ६७ ६० ररोड़ क० हो गई। यह वृद्धि वैंकों तथा समितियों को दिये गये श्राप्तम में श्राप्तक दर्शनीय थी। व्यक्तियों को दिये गये श्राप्तम की मात्रा १९५४-५५ में घट गई पी किन्तु विपाद का विपय तो यह है कि १९५५-५६ में इसमें २३० मरोड़ क० की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों को दिये गए श्राप्तम की मात्रा बढ़कर ६ ७६ ररोड़ क० हो गई।"

केन्द्रीय सहकारी चेंक—मेन्द्रीय वैंमों की सख्या १६५४-५५ में ४८५ थी। १६५५-५६ में यह घटकर ४७८ हो गई। "यह कभी कुछ राप्यों में नेन्द्रीय विसीय एजेन्सियों के युक्तिकरण की नीति बरतने के परिणाम स्वरूप हुरे है। उटाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश में राज्य की दो प्रविश्व वेंकिंग यूनियन राप्यीय सहकारी वैंक में विलयित हो गई। जम्मू श्रीर काश्मीर में तीन जिला वेंकें जम्मू केन्द्रीय सहकारी वैंक में विलयित हो गई। जम्मू श्रीर काश्मीर में तीन जिला वेंकें जम्मू केन्द्रीय सहकारी वैंक में विलयित हो गई। केन्द्रीय वेंकों की सख्या में कभी होने के वावजूद भी उनकी सदस्य सख्या १६५४-५५ के अत में २,७२,००० (१,३२,२७२ व्यक्ति तथा १,३६,७२८ समितियाँ) से बढकर १६५५-५६ में २६६, ५५५ (१,४४,००६ व्यक्ति तथा १,५५,५४६ समितियाँ) हो गई।" प्रान्न, श्रासाम, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, हैटरावाद, जम्मू श्रीर काश्मीर, मध्यभारत, मैस्र, सीराष्ट्र श्रीर भोपाल में मिश्रित ढङ्ग के श्रीर त्रिवकुर कोचीन में श्रमिश्रित ढङ्ग के केन्द्रीय वेंक थे। शेष प्रदेशों में जैसे वम्बई, उड़ीसा, पक्षाव उत्तर प्रदेश, पश्चिमी वङ्गाल, पेप्स, राजस्थान, श्रजमेर, हिमाञ्चल प्रदेश में मिश्रित श्रोर श्रमिश्रित दोनों ढङ्ग के केन्द्रीय वेंक थे।

केन्द्रीय सहकारी वैकों के कुल सदस्यों में से पूर प्रतिशत बैंक ग्रौर समितियाँ हैं ग्रीर ४८ प्रतिशत न्यक्ति हैं। इन वैकों की चालू पूँजी ६२ ६७ करोड़ क्ष्मचे हैं जिसमे से १६ ४ प्रतिशत निजी पूँजी हैं, ६० १ प्रतिशत जमाधन है, श्रीर २३ प्रतिशत ग्रन्य होतों से लिया गया भ्राण है। १६५१-५२ में यह प्रतिशत क्रमशः १६ र , ६३ प, २० १ थे। सर्वोच्च बैकों की तरह इन बैकों की निजी पूँजी का अनुपात पिछले वधों की अपेचा कुछ बढ रहा है पर किर भी निजी पूँजी का अनुपात बहुत कम है। इससे इन बैकों का कार्य अस्थिर रहता है। मिविध्य में इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनकी हिस्सा पूँजी और सुरिचत कोष की पूँजी बढ़ाई जाय जो इन बैकों की निजी पूँजी होती है। १६५५ ५६ में नमाधन का ६७ प्रतिशत विभिन्न व्यक्तियों से झौर ३० प्रतिशत प्रारम्भिक समितियों से तथा ३ प्रतिशत सहकारी बैकों से प्राप्त हुआ। इन्होंने ऋण अधिकतर सहकारी वैकों से प्राप्त किये। सहकारी वैका पर निर्भरता स्वामाविक ही है क्यों-कि जिन राज्यों में सर्वोच्च बैक हैं वहाँ केन्द्रीय सहकारी वैकों को सर्वोच्च वैंको के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से अपूर्ण लेने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

केन्द्रीय सहकारी बैका के कार्य की एक विशेषता यह थी कि व्यक्तियों को दिये जाने वाले अभिम में कमी आ गई। १९५५ ५६ मे वैकों तथा समितियों को दिये जाने वाला श्रमिम द्र प्रतिशत तथा न्यक्तियों को दिया जाने वाला श्रमिम १२ प्रतिशत था जनकि इससे पहिले वर्ष के प्रतिशत क्रमशः ८१ तथा १६ थे। बुरे तथा सन्देहात्मक ऋगों का अनुपात अब भी अधिक है हालाँकि इस दिशा

समान विशेषताएं—सर्वोच श्रीर केन्द्रीय सहकारी बैंकों में बहुत छुछ में भी कुछ सुवार हुआ है। समानता पाई जाती है, (१) इन दोनों सस्थाओं की हिस्सा पूँजी और सुरिहत निधि (अर्थात् निजी पूँजी) अपर्याप्त हैं। केन्द्रीय सहकारी बैकों की स्थिति इन्छ अञ्ची है, परन्तु उनमें भी हिस्सा पूँजी अ्रीर सुरक्षित कोष का धन पर्याप्त नहीं है इसका एक कारण तो यह है कि इन वैंकों का जिन लोगों से सम्बन्ध रहता है वह निर्धन है और इनको लाभ भी बहुत कम होता है जिससे सुरचित कोष में पर्याप्त धन-राशि एकत्रित नहीं हो पाती। यह खेद का विषय है कि द्वितीत महायुद के समय त्रोर महायुद्ध के तुरन्त पश्चात् जब कृपकों की वित्तीय स्पिति सुघरी थी, इन वैंको की हिस्सा पूँजी बढाने का अवसर खो दिया गया। इन देकों की हिस्सा पूँजी मे तभी वृद्धि की जा समती है जब कि कुषकों की वित्तीय स्थिति में सुघार हो प्रथम व द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनास्रो की समाप्ति तक कृपको की वित्तीय स्थिति सुधर जायगी श्रीर तन वैंकों की हिस्सा पूँजी में वृद्धि को जा सकेगी।

(२) दोनों सस्याओं में कुछ मिथित तथा ऊछ ग्रामिथित वैंक हैं। ग्रामिथित वेक सहपारिता के सिद्धान्त के अधिक अनुकूल होते हैं। परन्तु मिश्रित प्रकार के वेनों से यह लाम है कि इनका अधिक वित्त आप्त हो सकता है स्त्रोर साथ ही उन लोगों या ग्रविक सहयाग मिल सकता है जिनका कृषि से सम्बन्ध नहीं है। उस बात को ध्यान मे रखते हुये कि भारतीय कुषक श्रमी श्रविकिति श्रवस्था में है यह बहत बढ़ा लाभ है। मिश्रित बेंकों से केवल यही हानि नहीं हैं कि इनका ब्बवसाय सहकारिता के नियमों के अनुसार सामान्य नहीं होता बल्कि साथ ही इसका कमी-कभी हानिकारक परिखाम भी होता है। विमिन्न व्यक्तियों को इन वैकों के शेयरों को कय करने का अधिकार है इसलिये इन वैकों से ऋण लेने का भी श्रविकार है। व्यक्तियों को कृषि की उत्पत्ति के श्राघार पर भ्रुग देना सहकारिता के नियमां के अनुकृल नहीं है क्यों कि इससे ये दैक उन दलालों की भी सहायता करते है निनको सहकारिता श्रान्दोलन समाप्त करना चाहती है। साथ ही इस प्रकार की सहायता से सहकारी विकय व्यवस्था के विकास में वाघा पहॅचता है। इसलिए यह उद्देश्य होना चाहिने कि 'मिश्रित' समितियों को कुछ समय तक रहने दिया जाय और बाद में क्रपकों की आर्थिक स्थिति की सुधारने के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा इन सस्थाओं को वित्तीय आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर इन्हें श्रमिश्रित छमितियों में बदल दिया जाय।

(३) वेन्द्रीय सहकारी वैक श्रविकतर निश्चित समय के लिये जमा श्रीर वचत को स्त्रीकार करते हें परन्तु सर्वोच्च वेक इनके अतिरिक्त चालू खाते में धन र्त्रीकार करते हैं। सर्गेच्च बैंक श्रीर कुछ सीमा तक केन्द्रीय सहकारी वैक साधारण व्यापारिक वेकों का व्यवसाय करते हैं। यह वैक ब्राफ्ट देते हैं, हुएडी, चेक ब्रोर ऋ गपत्रों का नय-विकार करते हैं श्रीर सामान को सुरिच्चित रखते हैं। यह प्रश्न काफी विवाद प्रस्त है कि सहकारी सस्याश्रों का कार्य-चेत्र केवल सहकारी वैंकों के न्यवसाय तक ही सीमित रखा जाय या वे न्यापारिक वैकों का न्यवसाय भी करें। वर्तमान समय में सहकारी वैंकों का कार्य उनको न्यस्त रखने के लिये पर्याप्त नहीं है इसिलिये उन्हें न्यापारिक वेंकों का भी कार्य करना पदता है । यदि यह

व्यवसाय न किया जाय तो वैकों की श्राय बहुत कम हो जायगी।

(४) इन सस्यात्रों को बहुत कम लाम होता है। इन सस्यात्रों का लाभ श्रीर सदस्यां का दिया गया लाभाश भारत के अन्य वैका का श्रपेका कम है।

व्याज दर-भाग्तीय रिजर्व वेक की हान की रिपोर्ट में वताया गया है कि अनेक राज्या में छाटी सहकारी समितियों के न्याल की दर काफी अविक है। केवल वम्बई श्रोर मद्रास में जहा सहकारी श्रान्दोलन काफो सगठित हैं श्रीर

काफी विकसित है व्याज की दर कुछ कम रखना संमव हो सका है। अपनेक समितियों ने इस सिद्धान्त पर जोर दिया है कि योग्य कृषकों को दिए जानेवाले ऋग पर ग्रल्पकाल तथा मध्यकाल के लिए ६३ प्रतिशत से ग्रधिक व्याज न लिया जाय श्रीर दीर्घकालिक ऋगा के लिए व्याज की दर ४ प्रतिशत होनी चाहिए। यह सिद्धान्त मद्रास श्रीर बम्बई में लागू रहा है। इन राज्यों की सरकारें घाटे की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देकर सहकारी बैकों को कम ब्याज पर ऋण देने में सहायता कर रही हैं। इसके लिए सरकार बैक प्रशासन का कुछ भार स्वय चैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाले ज्याज की दर श्रिधिक होने के कुछ कारण निम्न हैं—(१) सह मारी समितियाँ स्थानीय तौर पर पर्याप्त पूँ जी का सप्रह करने मे असफल रही हैं, (२) वम्बई श्रीर मद्रास को छोड़कर केन्द्रीय सहकारी बैक साधारणतः छोटे हैं, इनके प्रवन्य का न्यय ग्रधिक है श्रीर त्रार्थिक दृष्टि से यह श्रतुपयुक्त हैं। यह श्रपना कारोबार तभी चला सकते हैं जब ऋगा लेने श्रीर देने की व्याज की दर में काफी अपन्तर हो, और (३) विभिन्न राज्य जो ऋण तथा त्रार्थिक सहायता से त्रान्दोलन की सहायता करते रहे हैं त्र्रव द्रव्य वाजार से **आवर्यक ऋग् ए**कत्रित करने में और परिगाम स्वरूप उसे कम व्याज पर विभिन्न सङ्कारी कार्यों में लगाने में विशेष कठिनाई श्रनुमन कर रहे हैं। रिजर्व बैक के भतानुसार निम्नलिखित प्रयत्नों से न्याज की दर कम की जा सकती है--(अ) सहकारी त्रान्दोलन का दृढ बनाया जाय, उसकी कार्य कुशलता में सुघार किया जाय ख्रौर ग्राम्य चेत्रों की बचत को सम्रहीत करने पर जोर दिया जाय, (ब) श्रार्थिक दृष्टि से उपयुक्त इकाई का रूप देने के लिए सहकारी वैंकों श्रीर समितिया को एक में मिला दिया जाय श्रौर समितियों के कार्यचेत्र का न्यापक प्रसार किया जाय श्रीर (स) ग्रारम्भ में राज्य सरकारें बम्बई की तरह ग्राधिक सहायता दें जिससे सहकारी वैकों को कम ब्याज लेने से जो घाटा होता है उसकी पृति की जा सके।

रिजर्व वैंक से ऋगा—रिजर्व बैक एक्ट की धारा १७ (२) (ब) श्रीर १७ (४) (स) के श्रनुसार यह बैक सहकारी बैंको को कृषि उत्पादन श्रीर फसल वेचने के लिए विना घरोहर के श्रल्प कालिक श्रीर मध्य-कालिक ऋग देता है। धारा १७ (४) (श्र) के श्रन्तर्गत सरकारी प्रतिभृतियों श्रीर मृमि वन्धक वैंकों के ऋग्णपत्रों की जमानत पर भी ऋग्ण देता है। भन् १९५५ की फर्वरी से रिजीव वैंक ने धारा

१ विस्तार पूर्वक अध्यन के लिये 'आम्य वित्त व्यावस्था' का श्रध्याय देखिये

१७ (४) (ग्र) के श्रन्तर्गत तीन वर्ष की श्रवधि के लिये मध्य कालीन भ्रमुख देना ब्रारम्भ कर दिया है। १६५३ के रिजर्व वैंक ब्राफ इन्डिया एक्ट के सशोधन के कारगा यह सम्भव हो गया है कि १५ महीने से लगाकर ५ वर्ष तक की श्रविध के लिये ऋगा दिया जा सके। इस नियम का प्रयोग करने के विचार मे ही वैंक ने तीन वर्ष की अवधि के स्थायी अपृत्ता, एक्ट की धारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत देना आरम्म कर दिया है, यद्यपि अधिक लम्बी अविध अर्थात् ५ वर्ष तक के श्रावेदनो पर श्रावश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता था। ऐसे श्रमुणों पर ब्याज कीर दर बैंक की दर से २% कम निश्चित की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा दी हुई गारन्टी श्रौर ऋग लेने वाले पेन्द्रीय सहकारी वेंक श्रथवा समिति द्वारा लिये हुये प्रतिज्ञा पत्र ही इन ऋगों की जमानत थे। जिन कायों के लिये मध्य कालीन ऋगा दिये जा सकते थे वे वेकार भूमि को पुन. अधिकृत करना, बाँध बनाना श्रयवा भूमि में किसी श्रन्य प्रकार का सुधार करना, वैल श्रादि जानवर परीदना, कृषि सम्बन्धी श्रीनार खरीदना तथा जानवरों को वाँघने के वाढे श्रीर खेतो में गोदाम बनाना इत्यादि थे। रिजर्व बेंक द्वारा राष्यीय सहकारी बैंक की दिये गये श्रिप्रिम की राशि १६५१-५२ में ११ २६ करोड़ रु० थी। १६५७-५८ में यह बढ़कर ५७ १२ करोड़ ६० हो गई। इस अपधि के शन्त में देय आखो की राशि ७ द१ करोड़ र• मे बढ़ कर ३५ ११ करोड़ र० हो गई। १६५७-५८ में दिये गये ५७११ करोड़ रु० के कुल श्रिप्रम में से ४१% १ करोड़ रु० घारा १७ (४) (स) के अन्तर्गत, १२'७२ करोड़ ६० घारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत तथा २ ६६ करोड़ ६० धारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत दिये गये।

श्रिखल भारतीय प्रामीण साख सर्वेज्ञण समिति की सिफारिशों के श्रान-सार १० करोड़ ६० की प्रारम्भिक राशि से राष्ट्रीय कृषि साख (दीवैकालीन) कीप का निर्माण ३ फरवरी १९५६ को किया गया ताकि "राज्य वरकारी, (जिससे वे सहकारी समितियों की हिस्सा पूँजी में योग दे सकें) राज्यीय सहकारी वैंकों श्रीर भूमिवन्यक वैंकों को दीर्घ एवम् मध्यकालीन ऋगा दिये जा सकें।" जून १९५६ में इस कीष में ५ करोड़ ६० के वार्षिक अनुटान से वृद्धि की गई। मार्च १९५७ के श्चन्त तक २६८ करोड़ र० का ऋण् ११ राज्यों को टिया गया ताकि वे सहकारी सस्यात्रों की हिस्सा पूँजी में योग दे सके।

ग्रध्याय १८ कृपि नियोजन

भारत की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ने कृषि नियोजन पर विशेष महत्व दिया था। प्रथम योजना के श्रन्तर्गत २३५६ करोड़ रुपये के कुल न्यय में से १५.९% (३५७ करोड़ रु०) कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनात्रों, तथा २८१% (६६१ करोड़ रुपये) सिंचाई तथा विद्युत शक्ति योजनात्रों पर न्यय के लिये निरिचत कर दिये गये थे। द्वितीय पञ्चपपर्णीय योजना के श्रन्तर्गत कृषि नियोजन का स्थान महत्वपूर्ण है, पर श्राधिक जोर श्रोद्योगिक विकास पर दिया गया है। इस प्रकार प्रथम योजना में जो श्रस्तुलित होने का दोप श्रा गया था उसे दूर कर दिया गया है। दितीय योजना में विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ रुपये के कुल न्यय में से कृषि तथा मामुदायिक विकास योजनात्रों को १६% (६१३ करोड़ रुपये) मिले हैं।

प्रथम योजना में कृषि पर विशेष महत्व देने के सम्बन्ध में योजना श्रायोग न टा तर्फ टिये थे-(१) जा योजनाएँ पचलित है उनको पूर्ण करने की श्रावश्य-कता है ग्रोर (२) जब तक खादान का श्रीर उद्योगों के लिये ग्रावश्यक खनिज पदाथा का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर लिया जाता श्रीद्योगिक विकास के कार्यक्रम में विशेष प्रगति ला सकना सम्भव नहीं है। इसमे सन्देह नहीं कि उद्योगों का विकास करने के लिये पानिज पदायां श्रोर पायान्न की श्रावश्यकता होती है। र्याट यह सामांप्रयाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जॉय तो भारतीय उद्योग को विकसित करने मे निश्चय ही सहायता मिल सकती है। इसके साथही भारत की अधिकाँश जनता कृषि कार्य करती है। कृषि में मुधार करने से इनकी श्राय में वृद्धि होगी श्रीर परिणाम स्वरूप रहन सहन में सुधार होगा। परन्तु इतने पर भी योजना श्रायोग द्वारा कृषि को प्रधानता दिये जाने की कड़ी श्रालोचना की गई थी। भारत की श्रार्थिक व्यवस्था अधन्तुलित है, क्योंकि उद्योगों का विकास करने की पूर्ण सम्भावना होते हुये भी भ्रव तक उद्योग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। इस तथ्य की ह्योर ध्यान न देकर निरन्तर इस वात पर महत्व दिया जा रहा है कि कृषि का विकास करने की विशेष श्रावश्यकता है। पचवर्षीय योजना के पूर्ण हो जाने पर इस असतुलित व्यवस्था के दूर होने की सम्भावना नहीं है। वास्तव मे

सम्भावना में इस वात की है कि योजना के परिखाम स्वरूप यह व्यवस्था दृढतर हो जायगी। यदि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण करते समय उद्योगों पर श्रिधक ध्यान दिया गया होता तो इस टोप के दूर हो सकने की आशा थी श्रौर भारत का श्रौर श्रिधिक सन्तृतित विकास हो सकता था। यदि योजना श्रामोग उद्योगों के विकास पर महत्व देता तो इससे कृषि के विकास की समुचित व्यवस्था करने में उसको किसी बाधा का सामना नहीं करना पडता। दूसरे, पह बिल्कुल सहीं है कि भविष्य में ब्रोद्योगिक विकास करने के लिए इंड ब्राधार का निर्माण किया नाय परन्तु इस वात पर केसे विश्वास कर लिया जाय कि मारत की कृषि का पूर्ण विकास हो जाने के पक्षात् उन्नोगों का इस स्तर तक विकास कर लिया जायगा कि उसमें उस समय उत्पादित कच्चे माल श्रीर विनली इत्यादि का पूर्ण उपमोग हो सकेगा। यह बहुत सम्मव है कि उस समय तक भ्रन्य देशों ने उद्योग भ्राधक शक्ति शाली हो जार्येंगे श्रीर मारतीय उद्योग के लिये नवीन समस्याएँ उत्पन्न कर दें। योजना श्रायोग उद्योगों का श्रोर श्रविक विकास करने और भारतीय कृषि से उपलब्घ न हो सकने पर खात्राझ तथा कच्चे माल का आयात करने की व्यवस्था कर सकता था जैसे जापान भीर ब्रिटेन ने किया। यदि उद्योग श्रोर क्लांप दोनों का साथ साथ विकास किया जाय तो भारत का आर्थिक विकास और अधिक सन्तु लित हो जायगा श्रोर उद्योग तथा कृषि के विकास का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव हो जायगा। योजना में कृषि पर श्रावश्यकता से श्रिविक महत्व दिये जाने से कृपि तथा उद्योग के विकास में सन्तुलन स्थापित कर उनका सुनियोजित विकास करने में बाघा पहुँचेगी जब कि नित्रोजन का आघार ही सन्तुलित और कम वड विकास करना है।

प्रथम योजना—प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि की सर्वतीन्मुस्ती उन्नित का प्रवन्न किया गया था। उसके अन्तर्गत कृषि उत्पत्ति के अतिरिक्त पणु-सुधार, सहकारी आदोलन का विकास, गन्यशाला, वन, भूमि सरस्चण तथा पचायतों के विकास और सुवार की योजनाएँ सम्मिलित थीं। भारत को केवल खाद्यानों और उद्योगों के लिये कन्ने माल के उत्पादन में ही आत्म निर्भर बनाने पर विशेष व्यान नहीं दिया गया था, वरन आमीण जनता के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने तथा प्रति न्यक्ति वाधिक उत्पादन में भी वृद्धि करने का विचार किया गया था। प्रथम योजना में कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाओं पर न्यथ किये जाने वाले ३५७ करोड़ रुपये में से १६७ करोड़ रुपये कृषि सम्बन्धी कार्य क्रमों पर, ह० करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर तथा सामुदायिक योजना स्रेजों पर, २१ करोड़ रुपये पालन पर, १५ करोड़ रुपये दायिक योजना स्रेजों पर, २१ करोड़ रुपये पालन पर, १५ करोड़ रुपये दायिक योजना स्रेजों पर, २२ करोड़ रुपया पशु पालन पर, १५ करोड़ रुपये दायिक योजना स्रेजों पर, २२ करोड़ रुपया पशु पालन पर, १५ करोड़ रुपये

स्थानीय सुघार कार्यों पर, ११ करोड़ आम पचायतों पर, १० करोड़ बनो पर, ४ करोड मछली पकड़ने के कार्यों पर, ७ करोड़ सहकारिता पर छीर १ करोड़ रुपये ग्रन्य वार्तों पर ज्यय करने के लिये नियत किये गये थे।

प्रथम योजना का िखाई सम्बन्धी तथा विद्युत शक्ति के विकास का कार्यक्रम बहुत ही विशद था। यह कार्यक्रम उन योजनाश्रों पर श्राधारित था जो योजना के पूर्व से ही प्रचलित थीं। योजना में इन योजनाय्रो की ग्रागे बढ़ाने का प्रवन्ध किया गया था। परन्तु इनकी सख्या इतनी आधक थी कि सम्पूर्ण योज-नात्रों को एक साथ नहीं लिया जा सकता था। इसलिये यह निर्णय किया गया कि कासी, कोयना, कृष्णा, चम्बल श्रीर रिहन्ड योजनाश्री को योजना काल के श्रतिम भाग में लिया जायगा। ६६१ करोड़ रुपयो के कुल व्यय में से ३८४ करोड़ सिंचाई के लिये, २६० करोड़ विद्युत योजना के लिये श्रीर १७ करोड़ बाढ नियत्रण तथा श्रन्य खोज कार्यों के लिये नियत किये गये। प्रथम योजना का लहर सींची जाने वाली भूमि का चेत्रफल ५१० लाल एक ह से, जो कि १६५०-५१ में था, बढ़ा कर ६७० लाख एकड़ १९५५-५६ तक करने का श्रोर विद्युत शक्ति का उत्पादन २३ लाख क्लोबाट से बढाकर ३४ लाख किलोबाट कर देने का था। यदि इस विकास योजना को दीर्घ कालीन दृष्टि से देखा जाय तो यह त्राशा की जा सकती थी कि २० वर्षों के अन्तरौत ही ४०० लाख मे लगाकर ४५० लाख एकड़ तक ग्रतिरिक्त भूमि सिंचाई के ग्रतर्गत ग्रा जायगी श्रीर वर्तमान विद्युत शक्ति की मात्रा जो उत्पादित की जा रही है उसमें ७० लाख मिलीवार की स्त्रीर स्रिविक वृद्धि हो जायगी। यह कार्यक्रम का वटा ही श्रेष्ठ श्रादर्श है श्रीर यदि पूर्ण हो गया तो भारतीय ग्राम्य श्रार्थिक व्यवस्था की रूप रेखा बदल जायगी।

प्रथम योजना में कृषि नियोजन की तीन प्रमुख विशेषताएँ थीं—(१) सम्पूर्ण कार्य केवल राज्य सरकारों द्वारा सचालित किया जायगा छोर उद्योगों के विपरीत निजी व्यवसाय का इसमें कुछ हाथ नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के कार्य में काफी दीर्घ अविध के पश्चात् लाम अजित किया जा सकता है और रुपयों के रूप में तुरन्त लाभाश प्राप्त नहीं होता। विगत वपो में निजी उद्योग इस प्रकार के कार्यों से पृथक रहा है। इसलिये स्वाभाविक ही योजना छायोग ने इस कार्य का सचालन करने के लिये निजी उद्योगों को उपयुक्त साधन नहीं समका। आयोग को निजी उद्योगों की कार्यच्चमता पर विश्वास नहीं हो सका। योजना के अनुसार राज्य सरकार विभन्न राज्यों के इस कार्य में उचित सम्बन्ध स्थापित करेगी और केन्द्रीय सरकार विभन्न राज्यों के इस कार्य में उचित सम्बन्ध स्थापित करेगी तथा अन्य सामान्य सहायता देगी, (२) दीर्घकालीन योजनाओं पर

तिशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार की योजनायों में होने वाले लाम का अनुभर १५ में २० वर्ष के पश्चात् विया जा सकेगा जब कि भागत की कृषि का पूर्ण विकास हो चुकेगा। यद्यपि दीर्घवालीन योजनायां पर महत्व दिया गया है, किर भी यल्पकाल में त्याचान्न तथा उत्योग के लिये त्यावश्यक उच्चे माल के उत्यादन में वृद्धि करने भी समुचित व्यवस्था की गई है। जैसा कि 'कृषि उत्यादन यार नीति' शीर्षक अध्याद में बताया गया है, वह आशा की गती है कि त्याचान के सन्वत्व में भारत को याजना की य्यवि में ही स्मावलम्बी बनाया जा सकेगा आग क्यास तथा तथ्द के सम्बन्ध म मारत की विदेशों पर निर्मरता को कम किया जा सकेगा, (३) इस पाजना का उद्देश्य नेयल कृषि उत्यादन में वृद्धि ही नहीं यिनक प्राप्य-जीवन का बहुमुनों विकास भी करना है।

दितीय योजना—प्रथम योजना का ग्रमाव दितीय योजना में पूर्ण कर दिया गया त्रार उत्रोंगों को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो कि न्यायपृष्ण ग्रोर उाचत था। इसने भारत के विकास की ग्रस्तुलित ग्रास्था सुघर जायगी श्रीर राष्ट्रीय ग्राय में ग्राधिक तीन गिन में वृद्धि हागी ग्रोर कार्य करने के श्रिषक श्रवसर प्राप्त हो सकेंगे। दितीय योजना के ग्रन्तर्गत ४=०० वरोड़ कपयों के विकास कार्यक्रमों पर नियत कार्य म में १८५% उत्रोंगों ग्रीर प्रान खाड़ने पर, २८६% सचार तथा याता गत पर, ११८% (५६= कगेड़ क०) कृषि तथा सामुदायिक विकास पर, ग्रार १६% (६१३ करोड़ कपये) सिचाई तथा विश्वत श्राक्त के उत्पादन पर क्या कारगा। यद्यपि दितीय योजना में उत्रोंगों ग्रीर प्रातायात को ग्रीधक महत्ता ही गई है पर कृषि तथा सिचाई को छोड़ नहीं दिया गया है। दितीय योजना में कपि नियोजन की मुक्त विचारसीय गातें नियन हैं—

(त्र) कृषि सुवार सम्बन्धो कार्य कमा ने यह आशा की जाती है कि वढी हुई जनस्त्या के लिये पर्याप्त पाय सामग्री तथा विकसिन उद्योग व्यवस्था के लिये नक्षा माल दे सकेंगे प्रार इतनी कृषि उत्यक्ति वच रहेगी कि उसना नियांत मो निया ला सकेंगा। इसलिये यह कहा ला सनता है कि दितीय योजना ने प्रथम योजना की प्रपेना कृषि तथा श्रन्य उद्योगों के विकास कार्यक्रम में अविक पारस्परित निर्मरता का श्रायोजन किया गया है। इन व्येयों को प्राप्त करने के कार्यक्रमा को निर्माण करत समय दीर्घकालीन हिष्टकोण रखना श्रावश्यक है ताकि भोतिक साधनो प्रोर मानव अम का सर्वोत्तमप्रयोग, कृषि ना सर्वतीनमुखी सत्रुलित विकास श्रार प्राप्त वासियों की श्राय में तथा रहन-सहन के स्तर म प्यात वृद्धि सम्भव हो सके। राष्ट्रीय हिष्टकोण से कृषि विकास सम्पन्धी नार्यक्रम निर्माण करने में यह श्रावश्यक है कि श्राम के सन्भुख एक ऐसा श्रादर्श उपस्थित नर दिया

नाय निसे प्राप्त करने में वे प्रयन्नशील हो सर्कें। द्वितीय योजना निर्माण के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यह त्रादर्श १० वर्ष के श्रन्तर्गत ही उत्पादन को निसमें -खाद्यान, तिलहन, कपास, गन्ना, पशु पालन से प्राप्त वस्तुएँ इत्यादि सम्मिलित होंगी दुगनी कर देगा।

- (व) कृषि उत्पत्ति को अनेक-रूपता प्रदान करना श्रोर खाद्यात्र सम्बन्धी फसलों को अब तक ना प्रधानता दो जाती थी उसे बदलना आदर्श होगा। द्वितीय योजना मे ऐसी फसलों की वृष्टि भी है जैसे सुपाडी, नारियल, लाख, काली मिर्च, वृक्कफल हत्यादि जिनकी श्रोर प्रथम योजना मे कोई विशेष व्यान नहीं दिया था।
- (व) क्रांप के चेत्रफल की वृद्धि करने की सम्मावना तो बहुत सीमित है। जो थोडी बहुत वृद्धि कृपि के चेत्रफल में सम्मव होगी उससे मोटे छन्न के ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी। जैसे-जैसे राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होती चलंगी वैसे-वैसे मोटे श्रन्न की माँग गेहूँ श्रीर चावल की माँग में बदल ही जायगी। ऐसी स्थिति में कृपि उत्पत्ति में वृद्धि का मुख्य स्रोत श्रिषक कुशल, लामटायक तथा धनी खेती ही होगा।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत कृषि नियोजन की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं—(१) सूमि के प्रयोग का नियोजन, (२) दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों का निश्चित करना, (३) उत्पादन लक्ष्यों तथा भूमि प्रयोग योजनास्त्रों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देना, और (४) उपयुक्त मूल्य नीति का निर्धारण करना।

द्वितीय योजना में ५६८ करोड़ रुपयो के न्यय में से १७० करोड रुपये कुषि कार्यक्रमों पर, २०० करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं पर, ५६ करोड़ रुपये पशुपालन पर, ४७ करोड़ रुपये वनो और भूमि सरस्या पर, १५ करोड़ रुपये स्थानीय विकास पर, १२ करोड़ रुपये पचायतो पर, १२ करोड़ रुपये मछली पक-इने के न्ययवसाय पर, ४७ करोड़ रुपये सहकारिता पर जिसके अन्तर्गत भाणडागार तथा विक्रय सुविधाये भी सम्मिलित होगी, और ६ करोड रुपये अन्य विविध बातों पर न्यय किये जायेगे। इस प्रकार प्रथम योजना की तुलना में कृपि पर कुल न्यय कम हो गया है। स्थानीय विकास कार्यों तथा आम पचायता पर लगमग समान ही है और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं तथा सामुदायिक योजनाओ, पशुपालन, वन तथा भूमि संरच्या और सहकारिता पर पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो गई है।

कठिनाइयाँ—मारत में कृषि नियोजन को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं योजना को सफल बनाने के लिये सर्व प्रथम कृषक का स्वेच्छा से सिक्तय सहयोग आवश्यक है, परन्तु भारतीय कृषक अधिकतर रूढिवादी है और प्रत्येक बात पर परम्परागत दृष्टिकोण से ही विचार करता है। वह इस बात के लिये प्रस्तुत नहीं कि परम्परा की रूढि छोइकर कुछ नवीन प्रयोग किये जॉय । अतीत में कपकों की स्थिति में सुधार करने के लिये अनेक प्रयक्त किये गये परन्त क्रमको की उदासीनता के कारण उनमें से अधिकाश असफल रहे। पचवर्णीय योजना में कहा गया है कि कृषि के चेत्र में विकास कार्यक्रम को **एफल बनाने के लिये और** निर्धारित लस्य तक पहुँचने के लिये यह ग्रावश्यक है कि जनता सहयोग दे। बिना जन-सहयोग के समाज कल्याण की योजना सफल नहीं हो सकती। कृपि विकास कार्यक्रम उसी सीमा तक सफलता पूर्वक कारात्वित हो सकता है जहा तक जनता उत्साह श्रीर त्वेच्छा से उसके लिये कार्य करने को प्रस्तुत हो। कृपकों का सिक्य सहयोग प्राप्त करने के लिये यह त्रावश्यक है कि (१) विभिन्न उपायों से कृषकों को यह विश्वास दिलाया जाय कि योजना उपयुक्त है श्रोर इसके कार्नान्वित होने से उनका लाभ होना निश्चित है, (२) योजना लागू करके श्रीव ही ऐने परिखाम निकाले जाने चाहियें जिनसे कपकों में विश्वास उत्पन्न हो श्रीर उन्हें प्रेरणा मिले श्रीर जिनको वह स्वय श्रांंंंबों ने देख श्रीर परख सकें। यदि योजना का उद्देश्य दीर्घकालीन लध्य की प्राप्ति करना हो तो क्रषकों में योजना की निश्चित उपयोगिता के प्रति विश्वास उसन करना कठिन हो नायगा। मृत्य श्रधिक होने से, वेरोनगारी में वृद्धि से श्रीर व्यापक श्रापिक कठिनाइया के कारण वही योजनाश्रों को सफलता पूर्वक लागू करने में सरकार की समर्थता पर कुषकों में विश्वास घटता जा रहा है, श्रीर (३) जनवा में योजना लागू करने के लिये उत्तरदायी पूर्ण श्रिषकारियों की ईमनाटारी और समता पर विश्वास उत्पन्न किया जाये। यदि जनता प्रशासन के इर त्तर पर भ्रष्टाचार देखे, उते सब स्थानो पर कार्य में श्रनावञ्यक देरी तथा श्रकुशलता का सामना करना पढे श्रीर यदि उसे यह मालुम हो कि समाज का शोपण कर समाज की हानि से लाभ उठाने वाले हानिकारक वत्वों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जा रही है तो जनता को उत्साहित कर उसका सिकय सहयोग माप्त कर सकना श्रत्यन्त कठिन हो जायगा।

कृपि नियोजन की सफलता श्रन्य योजनाओं की तरह सम्बन्धित श्रांध-कारियों की कार्यक्षमता श्रोर ईमानदारी पर निर्मर करती है। योजना श्रायोग ने बताया है कि कार्यक्रम की सफलता की गति प्रशासन संगठन, उसकी कार्य-कुलता श्रोर उसके द्वारा पेरित जनता के सहयोग पर निर्मर करती है। प्रशासन को श्राल गत वर्षों की श्रपेक्षा श्रिषक बड़ी श्रोर जाटल समस्ताश्रों का सामना करना पह रहा है। यह समस्याएँ बढ़ी श्रोर जाटल श्रवश्य हैं, परन्त श्राज इनके महत्व में श्रीत की श्रपेक्षा कहीं श्रिषक वृद्धि हो गई। योजना के कार्य का सफलतापूर्वक सचालन करने के लिये शिच्चित, कुशल श्रीर ईमानदार श्रिध-कारियों का श्रमान है। कार्य बहुत निशद है, परन्तु निभिन्न योजनाश्रों का कार्य सॅमालने के लिये शिद्धित कर्मचारी पर्याप्त सख्या से नहीं हैं। केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के श्रनेक जिला, राजस्व तथा श्रन्य श्रधिकारी हैं, जिनमें से कुछ बहुत कुशल और परिश्रमी हैं, परन्तु खेट है कि इन श्रधिकारी मे से श्रनेक प्राचीन प्रया के अनुकूल चलते हैं ख्रीर कृपकों से अपने को काफी दूर रखते हैं। इन अधि-कारियों की दृष्टि में रचनात्मक कार्य की श्रपेद्धा कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने का श्रधिक महत्व है, इससे यह अधिकारी योजना को कार्यान्वित करने के लिये उपमुक्त रिद्ध नहीं हो सकते । 'ग्रधिक-ग्रन उपनात्रो' नथा ग्रन्य ग्रान्टोलनो के सम्बन्ध में अनेक ऐसी घटनायें प्रकाश में आई है जिनसे पता चलता है कि श्रिधिकारियों ने बीज, खाट तथा रूपया कुपकों तक पहुँचाने को श्रिपेत्वा केवल कागजा मे खाना पूर्ति की श्रीर रुपयां को स्वय इड्रप लिया। इससे योजना को सफल बनाने में सफलता नहीं मिल सकती और जनता का उस पर में विश्वास उठ जाता है। पचवर्षीय याजना में इस बात पर महत्व दिया गया है कि सर्वप्रथम प्रशासन में निष्ठा, कुशलता, बचत श्रीर सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने की स्रावश्यकता है। याजना मे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सनेक सुकाव दिये गये हैं। इनकी पूर्वि मे अवश्य काफी समय लगेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को छाँटने श्रोर उनको उचित ट्रेनिंग देने के साथ ही पचवर्षीय योजना मे सम्यन्धित श्रधिकारियों की कार्यज्ञमता, निष्ठा श्रीर ईमानदारी मे सुधार करने के लिये अनेक सुमाव दिये गये हैं इनमें से कुछ सुमाव इस प्रकार हैं-(१) प्रशासन सम्बन्धी, राजनीतिक तथा अन्य पदों पर कार्य करने वाले श्रिधिकारियों पर भ्रष्टाचार के श्रारोपों की जॉच करने के लिये उपयुक्त न्यवस्था की जाय । यदि अपराध स्पष्ट हो तो तथ्यों का पता लगाने श्रोर अपराध सिद्ध करने के लिये तुरन्त जॉच की जाय। (२) वर्तमान कानून में ऐसे मामलों के लिये व्यवस्था की गई है जिनमे सरकारी कर्मचारी आय के गैर कानूनी साधनों का उपमोग करता है श्रीर उन साघनों के सम्बन्ध में सन्तोपजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता । परन्तु वर्तमान कानून के श्रानुसार ऐसे मामलों की जाँच करने की व्यवस्था नहीं है जिससे यह जात हो कि अपन सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार एकाएक घनवान कैसे हा गये। इसिलये कानून के इस अभाव को पूरा करने के लिये श्रध्ययन किया जाय श्रीर उपयुक्त कानून बनाया जाय। (३) ऐसे श्राधिकारी को जिसकी ईमानदारी पर सन्देह किया जाता है बढ़े उत्तरदायित्व के पद पर नहीं नियुक्त करना चाहिये।

भारतीय ग्राम्य जीवन की कुछ ऐसी विशेषवाएँ हैं जिनमें कृपि नियोजन के वार्च में बाघा पहुँचती है। ग्रामों में श्रब्छी सबकों, सिचाई तथा श्रन्य सुवि-भाग्नों का अभाव है। कृपकों के इन अभावों की शीव पूर्ति करने की आवश्य कता ई, परन्तु यदि इन कार्यों पर अधिक व्यान दिया जाय तो बहुमुखी ज्यापक कार्यक्रम को लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ पेटा हो जायँगी। यदि टीर्धकालीन योजनायों पर श्रिविक व्यान दिया गया तो स्थिति में सुधार करने की शीघ फल-टायक योजनाएँ लागू करने की सम्भावना कम हो जायगी। यह सम्भव है कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन टोनो प्रकार की योजनाओं पर व्यान दिया जाय परन्तु इससे प्रगति की गति मन्द हो जाती है और कार्य तजी से आगे नहीं वह पाता है। जमींदारी, जागीरदारी तथा इसी प्रकार की त्रान्य प्रथाल्लों के उन्मूलन से अने क नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई है। ग्रामो से महाजनों श्रीर साहकारों के घीरे बीरे समाप्त हो जाने से नई कठिनाइयों में चृद्धि हुई है। इससे एक खाई उत्पन्न हो गई है जिसको श्रमी तक नई व्यवस्था से पाटा नहीं जा सका है। भारतीय कृषक एक दुष्चक में फला हुआ है। वह निर्धन है क्योंकि अच्छे प्रकार का बीज, अब्छे पशु श्रौर खाद इत्यादि खरीदने के लिये उसके पास द्रव्य नहीं है, श्रौर जब तक वह घनी नहीं वन जाता तब तक वह इन वस्तुश्रो का कप कर सकने के साधन नहीं जुटा सकता है। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि कृपको की ऋरण लेने की ज्ञमता नहीं है। वह जमानत न रख सकने के कारण सहकारी वेंकों तथा ऋण नहीं देने वाली भ्रन्य सत्याश्रो से ऋण नहीं ले सकता है। श्रौर जब नक क्रपको को श्राधिक व्यवस्था श्रच्छी नहीं हो जाती वह इन सायनों को नहीं सुटा सकता है। यही कारण है कि शताब्दियों से भारतीय कृषक निर्धनता श्रौर दुखों में फसा हुया है। कृपि नियोजन को सफल बनाने के लिये क्रपकां की इन कठिनाइयों को दूर करना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।

श्रथ्याय १६ वड्डे पैमाने के उद्योग

भारत में श्रनेक बढ़े उद्योग हैं परन्तु श्रीद्योगिक द्वेत्र में श्रमी विटेन में १८ वीं शताब्दी में हुई श्रीद्योगिक कान्ति के समान श्रोद्योगिक कान्ति यहाँ नहीं हुई है। भारत में प्रति ब्यक्ति श्रीद्योगिक उत्पादन की मात्रा बहुत कम है श्रीर इन उद्योगों में देश की जन संख्या का बहुत कम माग लगा हुत्रा है। भारत के कारखानों में प्रदिदिन कार्य करने वाले श्रामकों की श्रीसत सख्या १९३६ में १६ लाख थी जो बढ़कर श्रम २५ लाख हो गई है। देश की ३८ करोड जनसख्या को देखते हुये यह बहुत कम है। देश में नवीन उद्योगों का विकास करने के लिये काफी वहा द्वेत्र खुला पड़ है श्रीर वर्तमान उद्योगों के उत्पादन में भी श्रिषक वृद्धि की जा सकती है।

दितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएँ थी—
(श्र) कुछ उद्योगों में जैसे स्ती कपडा श्रीर चीनी उद्योग में बहुत श्रिक श्रीक कार्य करते ये श्रीर ये उद्योग श्रावश्यकता से श्रीवक उत्पादन करते ये, (व) इसके साथ ही वहें रसायनिक, इजीनियरिंग श्रीर इसी श्रेणी के श्रन्य उद्योग थे ही नहीं। युद्दोत्तर काल में कुछ सीमा तक इन दोपो को दूर कर दिया गया है। यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुश्रों के लिए भारत को श्रायात पर निर्भर करना पड़ता है फिर भी देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुश्रों का उत्पादन प्रारम्म हो गया है। इन वस्तुश्रों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है श्रीर ऐसी सम्भावना है कि भविष्य में श्रपनी श्रावश्यकता की पूर्ति करने के लिये इनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा। श्राशा की जाती है कि भाग्तीय श्रीद्योगिक विकास में जो ग्रभाय शेप हैं उनको पचवर्षीय थोजना के श्रीद्योगिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करके पूर्ण कर दिया जायेगा।

सूती कपडा उद्योग

भारतीय स्ती कपड़ा उद्योग की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका युद के पश्चात् विशेष रूप से विकास हुआ है। विश्वयुद्ध के पश्चात् कपड़ो की मिलो की सख्या मे काफी वृद्धि हुई है। देश का विभाजन हो जाने से मिलो की सख्या १६४७ मे ४२३ से गिरकर १६४८ मे ४०८ रह गई थी परन्तु नवीन मिलो की स्थापना से और प्रचीन मिलों मे मशीन इत्यादि बढ़ा देने से भारतीय

स्ती मिला की उत्पादन शक्ति में काफी वृद्धि हो गई है। १९५१ में मारत में ४४५ मिलों थी जिनमें १ करोड़ १२ लाख ४० इजार तकुए (Spindles) श्रोर २,०१,४८४ वर्षे थे पर १९५७ के श्रन्तर्गत में ४६६ मिलों हो गई जिनमें १२६ लाख तकुए श्रोर २०६,१२६ कर्षे हो गये। कई नई मिलों स्थापित की जा रही हैं श्रोर श्राणा की जाती है कि इन मिलों द्वारा उत्पादन श्रारम्म होने पर मारतीय स्ती मिला की वाम्तविक उत्पादन शक्ति में मुख्यत कताई मिलों (spinnig mills) में, श्रीर वृद्धि हो जायगी।

कुछ मिलों में नेवल सत नाता जाता है श्रीर अन्य में सूत की कवाई और वुनाइ टाना होती है । युद्ध के पश्चात् काल की योजना समिति ने श्रनुमान लगाया कि अधिक दृष्टि से कताई-बनाई टाना कार्य करने वाली अनुकूलतम त्राकार की मूता मिल मे २५ हजार तकुए श्रार ६०० करघे होने चाहिये । परन्तु दभाग्यवश श्राधिकाश मिलें । जनमें कताई बनाई दोनों कार्य होते हैं श्रीर जिनमें केवल-कताई होती है आर्थिक हिन्द से अनुक्लतम आकार की मिलें नहीं कही जा सकती। स्त्री कपडा उत्रीग की वाकड़ पार्टी के अनुमान के अनुसार लगम्ग १५० मिलों में अनार्थिक हैं। इसके साथ ही अधिकाश मिलों में पुरानी और घिसी पिटी मशीनें हैं। बस्बई मिल-मालिक सघ के अनुमान क अनुसार बम्बई की मिलो में ६०% मशीने २५ वर्ष से मी अधिक पुरानी है। सुती कपड़ा उद्योग के सम्मुख सब से बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान मिलो को ब्रायिक दृष्टि से उपयुक्त स्तर पर लाया जान, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई श्राधुनिक मशीनें लगाई जाय श्रीर उन्हें त्रावर्यक त्रोद्योगिक प्रसाधनों से सुसल्जित किया जाय। दूसरी ध्यान देने योग्य वात यह है कि देश के अन्य मागों जैसे मद्रास, मन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मन्य भारत में इस उद्योग का विकास हुत्रा परन्तु फिर भी यह उद्योग बम्बई में ही अविक केन्द्रित है। कुल उद्योग में जितने तकुए श्रीम करचे उपयोग में लाये जाते हैं उनके ६० प्रतिशत केवल वम्बई में हैं। इसलिए भविष्य में विकास करते समय उद्योगों के स्थान-निर्धारण की समस्या पर विशेष ध्यान देना पहेगा। स्थानी करण की स्थिति में सुधार श्रावश्यक है।

उत्पादन की प्रवृत्तियाँ—१६४४ में सूती कपडे श्रीर १६४६ में सूत का उत्पादन श्रिषकतम श्रयांत क्रमश. ४८५२० लाख गज श्रीर १६८५० लाख मीरह था। यह उत्पादन १६५० में गिरकर २६६५० लाख गज श्रीर ११७५० लाख पौरह हो गया। १६४६ श्रीर १६५० में उत्पादन के गिरने के मुख्य तीन कारण ये—(१) १६४७ में देश का विभाजन हो जाने से कच्चे माल की कमी हो गई श्रीर पाकिस्तान तथा श्रन्य देशों से रूई का श्रायात करने में श्रनेक कठिनाइयाँ

उत्पन्न हो गई, (२) उद्योगों में श्रीमकों के कागडे में वृद्धि हुई, श्रीर (३) विद्युत शिक्त पर्याप्त न होने के कारण बम्बई मिलों को दीं जाने वाली विद्युत कम कर दी गई। घीरे घोरे इन कठिनाइयों को दूर करके उत्पादन में वृद्धि होने लगी। सूती कपड़ा उद्योग में श्रीमक तथा मालिकों के सम्बन्धों में सुघार हुआ, उत्पादन शक्ति में वृद्धि की गई श्रीर देश में कपास की उत्पत्ति में वृद्धि से कच्चे माल की पूर्ति में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप १६५१ में सूती कपडे श्रीर सूत का उत्पादन कमश: ४०७६० लाख गज श्रीर १३०४० लाख पीएड श्रीर १६५२ में ४५६८० लाख गज श्रीर १४५०० लाख पीएड हो गया। मिलों द्वारा कपास के क्रय पर से नियंत्रण के इटनाने के कारण, रई श्रीर कपड़ों के यातायात के लिये मालगाड़ियों के मिलने तथा माँग की वृद्धि से उत्पादन में श्रीर श्राधिक वृद्धि हुई है। इसके परि-णाम स्वरूप सूती कपड़ों श्रीर सूत का उत्पादन बढकर १६५७ में कमश: ५३१५० लाख गज श्रीर १७७६० लाख पीएड हो गया।

भारत की स्ती मिलों में पहले मोटे कपढे का ही ऋषिकतर उत्पादन किया जाता या परन्तु प्रशुल्क मराइल (टिरिक्नोर्ड) की सिफारिशों के अनुसार उत्तम प्रकार के कपढे का उत्पादन धेटीने के लिए १६२५ से १६४० तक काकी रुपया लगाकर अनेक टेकनिकल सुधार किये गये परन्तु उद्योग का पुनर्संकटन कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध के लिए सैनिक मागों तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उद्योग को फिर मोटे तथा माध्यम वर्ग के कपढे का उत्पादन करना पड़ा। इसमें कुछ और रुपया लगाना पड़ा जिससे उद्योग पर काफी मार पड़ा। परन्तु इधर कुछ वर्षों से मोटे और अत्युक्तम प्रकार के कपढे के स्थान पर मध्यम और उत्तम प्रकार के कपड़ों के उत्पादन में वृद्धि की गई। यह एक वान्छनीय प्रवृत्ति है और इम यह आशा कर सकते. हैं कि मविष्य में देश की माग पूरी करने तथा निर्यात के लिए इस उद्योग को महीन और मध्यम श्रेणी के कपड़ों की उत्पत्ति बढ़ानी पढ़ेगी।

करना माल श्रपनी पूर्ण वास्तविक उत्पादन शक्ति के बराबर उत्पादन करने के लिये मारतीय स्ती का कपड़ा उद्योग को लगमग ५२ ५ लाख गाठ कपास की श्रावरयकता होती है। विमाजन होने स्देश में कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था। मारतीय मिलों को श्रावरयकता पूरी करने के साथ ही विदेशों को भी कपास निर्यात किया जाता था जिससे उत्योग को कच्चे माल के श्रमाव की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। देश विमाजन के पश्चात स्थित में परिवर्तन हो गया। देश में कपास का उत्पादन गिर गया। १९४७-४८ में २२ लाख श्रीर १९४८-४६ में १० लाख गांठों का उत्पादन किया जा सका। इससे

उद्योग के सम्मुख कन्ने माल के श्रमाव का गमीर सकट उत्पन्न हो गया। सामान्य स्थिति में कपास का श्रायात करके इस सकट को दूर किया जा सकता था परन्तु पाकिस्तान ने भारत को श्रावश्यकता के श्रनुसार कपास नहीं दिया। पाकिस्तान के श्रतिरिक्त श्रन्य देशों की कपास का भाव वहुत श्रिष्ठक था श्रीर मारतीय स्ती कपड़ा उद्योग के श्रनुकूल नहीं था। परन्तु १६५७-५८ में कपास का उत्पादन ५० लाख गाठें से कुछ ही कम था श्रीर इस प्रकार श्रमत कन्ने माल की कमी पूरी हो गई। द्वितीय पद्मवर्षीय योजना के श्रतगंत कपास के उत्पादन में श्रीर भी वृदि होने की सम्भावना है। इससे स्ती कपड़ा उद्योग के कन्ने माल की किटनाई को बहुत कुछ दूर किया जा सकेगा।

निर्यात—१६४८-४६ के विषरीत १६५०-५१ में स्ती कपड़े श्रीर स्त के निर्यान में श्रपेज्ञाकृत वृद्धि हुई है। १६४८-४६ में ३४१० लाख गज कपड़ा श्रीर ७४ लाख पीयह स्त देश से बाहर मेजा गया। १६५०-५१ में १२६६५ लाख गब कपड़ा श्रीर ७४५ लाख पीयह स्त विदेश मेजा गया इस वृद्धि को कारण यह है कि भारतीय माल का मूल्य श्रपेज्ञाकृत कम रहा ग्रीर साथ ही विदेशी वाजार पर श्रिष्कार जमाने के लिये भारतीय मिल मालिकों ने जोरदार प्रयक्ष किये।

परन्तु बाद में स्थिति फिर बटली श्रोर निर्यात की इसी स्तर पर स्थिर नहीं रखा ना सका। १६५२ ५२ में निर्यात की मात्रा घटनर ४२३७५ लाख गज कपडे श्रीर ६२% लाख पोयड सूत तक पहुंच गई। इस कमी के कारण निम्न-लिखित हैं -(१) स्ती कपटे श्रीर स्त के उत्पादन में कमी श्राजाने से श्रिविक माल का निर्यात नहीं क्या जा सका श्रीर सरकार ने क्पडे-के निर्यात पर प्रति-बन्घ लगा टिये। (२) निर्यात कर लगाने से मारतीय स्ती माल का मूल्य बढ गया। मारतीय स्ती उद्योग ने बरावर यह माग की है कि निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिये सरकार निर्यात कर को समाप्त कर दे। (३) मारतीय माल को निदेशों नापान, ब्रिटेन श्रीर श्रन्य देशों की बढती प्रतियोगिता का सामना बरना पड़ा। भारतीय सूती मिलें सरकार भी श्रनिश्चित नीति के कारण श्रपने निर्यात की मात्रा पूर्ण नहीं कर सकी श्रीर भारतीय माल की प्रकार, पैकिंग इत्यादि निर्यात की शतों के श्रनुक्ल नहीं हो सके। इसके परिणाम स्वरूप निदेशी बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति गिरती चली गई। निर्यात के बढ़ाने के सम्बन्ध में श्रनेकों उपायों का श्रनुसरण किया गया जैसे निर्यात कर की दरों में कमी करना, निर्यात किये जाने वाले कपड़ों के बनाने में काम आने वाली विदेशी रुई पर लगाये गये श्रायात कर में छूट देना, १ मार्च १६५४ से श्रायात-कर को ही वद कर देना श्रीर निर्यात पर नियत्रण कम करना इत्यादि। इनके परिणाम स्वरूप स्ती कपड़ों का निर्यात बढ गया है। १९५६ व १९५७ में भारत ने क्रमशः ६८४० लाख गज तथा ८५४० लाख गज कपडे का निर्यात किया। किन्तु विश्ववाजार में प्रति स्पर्धा बढ़ने तथा श्रायात करने वाले देशों में लगे प्रतिबन्धों के कारण १९५८ में निर्यात घटकर ६५०० लाख गज रह जाने की संभावना है। मुख्य प्रकार के कपडे जो भारत से निर्यात किये जाते हैं वे चादरें, कमीज श्रीर कोट के कपडे, वायल ननजेव श्रीर छोंट श्रादि हैं।

कर—केन्द्रीय सरकार स्ती कपडे पर उत्पादन कर श्रीर निर्यात कर लगाती है। सितम्बर १९५६ में उत्पानकर में बहुत वृद्धिकर दी गई। इससे उत्पादन-लागत बढ़ गई। इसके श्रातिरिक्त राज्य सरकारें स्ती कपडे श्रीर स्त पर विकी कर लगाती हैं। इससे उत्पादन लागत में श्राधिक चृद्धि हो गई है।

१९५२ में वेन्द्रीय सरकार ने इयकर्घा उद्योग श्रयवा बुनकरों की सद्दायता के लिये ६ करोड़ रुपये का कोष एकत्र करने के लिये मिल के बने सभी कपड़ों पर ३ पाई प्रति गज की दर से एक उप-कर लगा दिया। यह वास्तव में अपनी प्रकार का विल्कुल नवीन उपाय था। इसके ग्रानुसार यह पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। क उद्योग को बहुत श्रिधिक लाम हो रहा है श्रीर वह इस नवीन कर का भार वहन कर सकने में समर्थ है। इन सभी प्रकार के करों से स्नी मिल उद्योग को अपना उत्पादन व्यय कम करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पढ़ रहा है। इस-स्थिति में सुधार करने के लिये यह त्रावश्यक है कि कर कम किये जाय श्रीर मशीनों की टूट फूट के लिए जिस दर से धनराशि दी जाती है उसके प्रति उदार नीति श्रपनाई जाय जिससे स्ती मिल उद्योग पुरानी श्रीर टूटी मशीनों के स्थान पर नवीन मशीनें लगा सके श्रीर कारखानों में श्राधुनिक टेकनिकल सुविधाएँ प्रदान कर एकें। मशीनों की टूट फूट के लिये जो धनराशि निश्चित की गई है वह अपर्याप्त है। नवीन मशीनों को लगाने के लिये इस बात की श्रत्यन्त ग्रावश्यकता है कि सरकार कम ब्याज पर उद्योग को ऋग दे ग्रीर मशीनों की टूट फूट के लिये निश्चित धन के प्रति उदार नीति श्रपनाये । भारतीय स्ती कपड़ा उद्योग में युक्तीकरण की श्रात्यन्त श्रावश्यकता है। परन्तु यह निम्न वीन बातों पर निभैर हैं, (१) आवश्यक धन की प्राप्ति, (२) आवश्यक मशीनों की प्राप्ति और (३) इस समस्या के प्रति अभिकों का विचार। फिर मी सरकारी कर नीति इस सम्बन्ध में सबसे श्राधिक विचारणीय है क्योंकि वही युक्तिकरण के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने का श्रोत है।

एकत्रित सामग्री का संकट-१६५७ के प्रारम्म से स्तीवस्त्र उद्योग गम्भीर सकट का सामना कर रहा है। लगमग २६ मिलें, जिनमें से १६ उत्तर प्रदेश में हैं, वन्द होगई है तथा १७ मिले केवल अगत कार्य कर रही हैं। अप्रैल १६५८ के अन्त में मिलों के पास जिना जिके कराड़े की एकजित सामग्री ५०५३०० गाँठे यो। अनेक मिलों को हानि उठानी पढ़ी है तथा, मिलों के अनेक मनतूर वेकार हो गये हैं। इस सकट के मुख्य कारण निम्न हैं (१) साद्यान्न तथा नीजन की अन्य आवश्यकताओं के मूल्य अत्यधिक कॅचे होने के कारण लोगों की मय शिक घट गयी निसके फल स्वरूप पिकी कम होगई। साथ ही १६५८ में निर्यात में कमी आगई। (२) कपडे पर लगे उत्यादकर की कॅची टर के फलस्वरूप उत्यादन-लागत बरावर कॅची बनी हुई हैं। (३) उद्योग का मनदूरी-वित्त बहुत अधिक है। लागत के घटने का कोई सहन उपाय भी नहीं दिस्ताई देता क्योंकि मशीनें घिसी पिटी तथा पुरानी हैं तथा उत्यादन के युक्तीकरण में देर होती रहती है। उद्योग के बरवादी से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि उत्यादन कर १६५५-५६ के स्तर पर कर दिया जाय तथा उत्यादन का युक्तीकरण किया जाय।

उद्योग के सम्मुख दो कठिनाइयाँ हैं। एक श्रोर उत्पादन पर नियत्रण लगा दिया गया है तथा दूसरी श्रोर इयकर्षा उत्पादकों के हित में मिल उद्योग पर १ ली दिसम्बर १६५२ से प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं जिनके श्रनुस्त्र घोतियों के उत्पादन के १६५१-५० के मासिक श्रीसत के ६०% पर मिलों का घोतियों का उत्पादन निश्चित किया गया है तथा साहियों का रगना निषिद्ध घोषित कर दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना के व्यन्तर्गत—प्रथम पचवर्षीय योजना के ब्रन्तर्गत स्ती कपड़ा उद्योग की उत्पादन शक्ति को १६५५-५६ तक ४७७-० लाख गढ़ कपडे श्रीर १७२२० लाख पोड स्त तक बढ़ाने का श्रमुमान या श्रीर वास्तिविक उत्पादन ४७००० लाख गज कपडे श्रीर १६४०० लाख पीड स्त का करने का या। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति को १५ गज कपड़ा प्राप्त हो सकने का या। प्रथम योजना के श्रन्त तक वास्तिविक उत्पादन श्रीर उत्पादन शक्ति दोनों ही लक्ष्य से श्रागे वढ गये।

दितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया है कि कुल कपढें के उत्पादन की मात्रा (भिल और इयक्षें और शक्ति चचालित कर्षे से बने कपढें मिलाकर) को ६८५ करोड़ गज से, जितना कि १६५५-५६ में या, १६६०-६१ तक ८५० करोड़ गज कर दिया जाय और स्त का उत्पादन १६३ करोड़ पींड से १६५ करोड़ पींड कर दिया जाय। इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति कपढें का उपभोग १८ गज तक बढा देने का है और लगमग १ अरब गज़ कपडें का निर्यात करना है। द्वितीय योजना में कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में दो मुत्य दोष हैं—(१)
मिविष्य की कपड़े की माँग का कम श्रुनुमान करना, क्योंकि धम्धई के मिल
मालिकों की एसोसियेशन के मतानुसार यह माँग ८५० करोड़ गज नहीं वरन्
१००० करोड़ गज होगी; ग्रौर (२) मिलां के विस्तार पर इस विश्वास से प्रतिनन्ध
लगाना कि इससे इथम्पों के प्रयोग को सहायता मिलेगी। इथकर्षा उद्योग को
सहायता मिलों की उत्पत्ति को कार्वे कमेटी के श्रनुसार ५०० करोड़ गज तक
श्रिथवा किसी श्रन्य मात्रा तक मीमित कर देने में नहीं मिलेगी वरन् इथकर्ष से
बने कपड़े श्रिथक श्रन्छे बनाने श्रोर उसके मूल्य के घटाने से मिलेगी।

जुट उद्योग

भारत में जूट की ११२ मिलें हैं जिनमें लगभग ७२,३६५ कर्घे चलते हैं। इनमें से ४५% कर्घे जूट के टाट छीर ५५% वोरे इत्यादि बनाने के लिये हैं। छनुमान लगाया गया है कि यदि उद्योग में केवल एक शिफ्ट में कार्य चलाया जाय छीर प्रति सप्ताह ४८ घटे उत्पादन किया नाय तो प्रतिवर्ध १२ लाख टन उत्पादन किया जा सकता है। जूट उद्योग छाधिकतर पश्चिमी बगाल में केन्द्रित है। मारत की कुल रिजस्टर्ड ११२ जूट मिलों में से १०१ मिलें पश्चिमी बंगाल ही में स्थित है। शेप मिलों में से ४ छान्छ में, ३ निहार में ३ उत्तर प्रदेश में छीर १ मध्य प्रदेश में ही।

भारतीय जूट उद्योग श्रन्य सब उद्योगों से श्रिषक सुसगिठत है परन्तु दुर्भाग्यवरा इसकी मगीन इत्यादि श्राधुनिक नहीं है श्रीर साथ ही यह मशीनें वनाये हुये माल की वर्तमान माँग के टिन्टकोण से श्रिषक मी हैं। भारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि करने के लिये यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उसकी पुरानी मशीनों के स्थान पर श्राधुनिक मशीनें लगाई जाँय श्रीर इस प्रकार उत्यादन व्यय घटाया जाय। परन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि उद्योग का युक्तीकरण करने में ४० से ४५ करोइ कपये तक की पूँजी लगानी पड़ेगी श्रीर वर्तमान में उद्योग इतनी पूँजी लगा सकने की ज्ञाता नहीं रखता। "श्रिभनवीकरण (modernisation) के लिये राष्ट्रीय श्रीयोगिक विकास निगम द्वारा श्रुण दिये ला रहे हैं। मार्च १९५८ के श्रन्त तक ह मिल कम्पनियों के लिये श्रुण स्वीकृत हो चुके हैं जिनमें से ७ को १,१६ करोइ इ० दिया भी जा चुका है। वर्तमान स्थित यह है कि ८२ जूट मिल कम्पनियों में से ४४ ने ३० सितम्बर १९५७ तक कताई सम्बन्धी श्राधुनिक मशीनों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णतः तथा कुछ ने श्रातः श्रीमनवीकरण कर लिया था। पुराने तकुशों में से ४% के स्थान पर नये तकुये लगाये जा चुके तथा लगाये जा रहे हैं।

चत्पादन की प्रवृत्ति--जूट उद्योग में उत्पादन १६४५-४६ में उद्यस्तर तक पहुँच चुका था जनकि ११ ४ लाख टन माल का उत्पादन किया गया। इसके पश्चात् १६४६ तक उत्पादन दस लाख टन प्रतिवर्ष के लगभग रहा। परनु १६४६-५० में उत्पादन ८६ लाख टन तक गिर गया । इसके पश्चात् उत्पादन में कुछ सुघार श्रवश्य हुश्रा परन्तु फिर भी उत्पादन पूर्व स्तर तक नहीं पहुच पाया । १९५४-५५ में उत्पादन बढ़ कर १०, ४३,४०० टन हो गया था। उत्पादन में कभी का मुख्य कारण कच्चे माल की कभी थी वयों कि देश का विभावन हो जाने के पश्चात् पूट का उत्पादन करने वाले ऋधिकाश चेत्र पाकिस्तान में चढे गये। इस अभाव को पूरा करने के लिये देश में ही जुट उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया। तब से देश में जुट के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप जूट के माल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जूट उद्योग में प्रति सप्ताह केवल १२% धन्टे उत्पादन कार्य हो रहा या श्रीर उद्योग के कुल कर्षे के १२% प्रतिशत बन्द पढे हुये थे। परन्तु श्रवहूबर १६५४ से ४८ घन्टे प्रति सप्ताह कार्य श्रारम्म हो गया श्रीर १९५६ के मार्च तक वन्द कर्षों में से ७३ प्रतिशत चालू हो गये थे। १९५६-५७ में उत्पादन १,०२५,२०० टन था तथा श्राशा की जाती है कि १६५७ ५८ में भी लगभग इतना ही होगा।

कच्चा माल-उद्योग की इस समय सबसे बड़ी कठिनाई कच्चे माल की कमी है। यदि सब मिलें शक्ति भर कार्य करें तो भारतीय जुट उद्योग के लिये प्रतिवर्ष पटसन की ७५ लाख गाँठों की श्रावश्यकता है। परन्तु भारत में १६४७ ४८ में १५ लाख गाँठों से पुछ श्रधिक, १९४८-४९ में २० लाख गाँठ, १९४६-५० में २० लाख गाँठ श्रीर १९५० ५१ में २२ लाख गाँठ से कुछ स्रधिक का उत्पादन किया गरा । भारत चरकार ने पाकिस्तान चरकार से चमसौता कर पटचन के स्रायात की व्यवस्था की, परन्तु श्रायात का यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पाकिस्तान से बहुत थोड़ी मात्रा में जुट का आयात किया गया। फलस्वरूप भारतीय जूट उद्योग के कच्चे माल की श्रावश्यकता पूर्ण नहीं की जा सकी। इघर हाल के वर्षों में भारत में कच्चे जूट का उत्पादन वढ गया है। १९५६-५७ में इसका उत्पादन ४२ ५ लाख गाँठे थी। १९५७-५८ में इससे घट-कर ४० लाख गाठे (४०० पो० की एक गाँठ) रह जाने की श्रावश्यकता है। कच्चे जूट के विषय में श्रात्मनिर्भरता पास करने के लिये किये जाने वाले गहन प्रयत्नों के सदर्भ में १९५७-५८ में उत्पादन की यह कमी शोचनीय विषय है। द्वितीय योजना के श्रन्त तक भारत को पाकिस्तान से जूट मगाना ही पडेगा। किन्तु उन पर हमारी निर्मरता नहुत कुछ कम हो जायगी श्रोर यह सम्मव हो

सकेगा कि भारत में चूट उद्योग पाकिस्तान से जूट जिना पाये मी संतोधप्रद ढग

निर्यात—भारतीय जूट उद्योग अधिकतर अपने माल के निर्यात पर निर्मर करता है। १६४८-४६ में भारत में ११ लाख टन उत्पादित माल में से में चले। £३०,००० टन माल का विदेशों को निर्यात कर दिया गया । यद्यपि निर्यात की मात्रा पूर्व की अपेक्षा घटकर १९५६-५७ में इप्रह्००० टन हो गई है फिर मी यह

कुल उत्पादन का बहुत बड़ा भाग है । कुल उत्पादन का बहुत बड़ा भाग है । भारतीय जुट के टाट के हो बड़े बाजार यूनाइटेड स्टेटस तथा यू० के० हैं। १९५६ ५७ में इन देशों को गये निर्यात में क्रमशः ५% श्रीर ५०% की कसी हुई। यद्यपि यूनाइटेड स्टेट्स को किये जाने वाले निर्यात की कमी से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी अमेरिका में व्यापारियों ने टाट सामग्री कुछ कम कर दी थी; किन्छ यह पूर्ण सत्य नहीं है। अधिक महत्व की बात तो यह है कि १९५६-५७ में टाट के उपमोग में (यू॰ एस॰ में) १२% को कमी हुई। उपमोग की यह कमी येले बनाने के लिये टाट का प्रयोग कम करने के कारण हुई । सन्तोष का विषय है कि श्रीद्योगिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिये जूट का प्रयोग बढता रहा । यू० के० में अहुट के उपमोग में हुई मारी कमी वहाँ पर लागू जूट-नियन्त्रण के कारण हुई।

जूट से बनने वाले थैलों से यह लाम होता है कि यह अपेचाकृत सस्ते होते हैं और इनका अनेक बार उपयोग किया जा सकता है जब कि पैकिंग के लिये कागज के थैलों तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं का केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु जूट के येंलों के स्थान पर कागज तथा अन्य प्रकार की वस्तु प्रों के प्रयोग से जूट के माल की साँग काफ़ी गिर गई है थ्रौर यह लूट उद्योग के लिये चिन्ता का कारण बन चुकी है। फिर भी यदि उचित प्रयत्न किये जाँय तो अन्य वस्तुओं की अपेना बढ़ का माल अपने लिये आवश्यक स्थान बना सकता है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जूट उद्योग का उत्पादन व्यय घटाया जाय, उत्पादन बढाया जाय थ्रौर उत्पादित

मारत सरकार ने लूट के माल पर बहुत श्रिधिक निर्यात कर लगाया जिस माल की प्रकार में सुधार किया जाय। से कि माल के मारतीय तथा विदेशी मूल्य का श्रन्तर सरकारी खजाने में जमा हो जाय। यदि यह कर न लगाये गये होते तो उद्योग श्रपने श्राधुनिकीकरण तथा पुरानी विसी पिटी मशीनों के बदले नई मशीनें लगाने के लिये पर्याप्त सुरिचत कोष का समह कर सकता था। निर्यातकर से बहुत हानि उठानी पढ़ रही थी। कोरिया सुद्ध के कारण हुई महंगी के काल में जूट के बने कपड़ों पर तो यह कर

1

१५०० ६० प्रति टन श्रीर वोरों पर ३५० ६० प्रति टन तक वह गया था। श्रगस्त १६५५ में पाकिस्तानी ६पये की विनिमय दर घटने पर यह कर हटा लिया गया। हटाते समय टाट पर यह कर १२० ६० प्रति टन श्रीर वोरों पर ८० ६० प्रति टन था। निर्यात कर के हटा देने का परिशाम यह हुत्रा कि मूल्यों में कमी हो गई श्रीर निर्यात वह गया तथा घरेलू माँग भी वह गई।

जूट जॉच आयोग-जूट जाँच श्रायोग ने जिसके श्रध्यज्ञ के श्रार पी० ग्रायगर ये श्रपनी १६५४ में प्रकाशित रिपोर्ट में यह पाया कि ७५% मिलें लगमग १२ मैतेजिंग एजेन्सियों के हाथ में थी, जिनमें से चार के अन्तरर्गत ४५% कर्षे थे। मैंनेजिंग एजेन्टों के हाथ में सारे व्यवसाय के केन्द्रित होने श्रीर जुट उद्योग के भूतकाल में जॅची दर पर श्राय प्राप्त करने के कारण इन मैनेकिंग एजेन्सियों के शेयर बहुत ही आकर्षक हो गए ये ग्रीर उनके खरीदारों की सख्या बढ गई थी। चॅ्कि बूट उद्योग के वर्तमान सयत्र की उत्पादन शक्ति वर्तमान और मिष्य की सम्मावित माँग से कहीं श्रधिक है इसलिये श्रायोग ने श्रौर नई मिलों की स्थापना को पसन्द नहीं किया । उसने मिलों को अपने स्यत्रों को आधुनिक वनाने की सिफारिश की। इन्डियन जुट मिल एसोसिएशन की यह योजना होते हुए मी, चॅ्कि इसका परिगाम विनाशकारी प्रतिद्वन्दिता श्रौर उद्योग की श्रव्यवस्थर होगी, श्रायोग ने यह सिफारिश की कि काम के घन्टों के सम्बन्ध में जो समक्तीता हुआ है जिसके अनुसार सप्ताह के अन्दर कार्य के बन्टे सीमित कर दिये गये हैं और मशीनों को अशतः चालू करना बन्द कर दिया गया है उसे आगे लागू नहीं रखना चाहिये। इस सममीते के अनुसार अकुशल मिलें भी चलती रही हैं छोर इधल मिलों को अपना उत्पादन ज्यय कम करने में वाघा पहुँची है। इससे पाकिस्तान तथा भ्रन्य विदेशी मिलों को लाम पहुँचा है। श्रायोग की यह सिफारिश **चर्चया युक्तिसगत है और इससे आशा की जाती है कि कुशल मिलें अधिक** श्रच्छा कार्यं कर सकेगी। श्रायोग ने सिकारिश की है कि भारत को कच्चे जूट की पूर्ति के लिये निरमेह के वनाय सामेहिक श्रात्मनिर्मरता का लक्ष्य सामने रखना चाहिये। हमें पाकिस्तान से उस प्रकार का ज्य श्रायात करना चाहिये जिसका उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता श्रीर श्रन्य प्रकार के जूट की स्त्रय उत्पादित करना चाहिये। जूट की विस्तृत खेती के बजाय गहन खेती तथा किस्म के सुधार पर अधिक जोर देना चाहिये।

श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि नियमित वाजारों में नियमों का लागू करना, सहकारी समितियों की व्यवस्था करना, तथा श्रन्य सिफारिशों को कार्या-न्वित करना दीर्धकालीन इष्टि कोण्य से उत्पादकों के लिए श्रिषक लाभकारी सिक्ष होगा। मूल्य नियन्त्रण के उपायों के प्रयोग को श्रस्वीकार करते हुए भी निर्यात बढ़ाने के लिए तथा घरेलू माँग बढ़ाने के लिये श्रायोग ने मूल्य स्थिर रखने का

थोजना के अन्तर्गत-जूर उद्योग के सम्बन्ध में समस्य । उत्पादन शक्ति प्रयत्न करने की सलाह दी। बढाने की नहीं है क्योंकि बाजार की माँग की तुलना में तो भारतीय जूट मिलों के साधन आवश्यकता से कहीं अधिक हैं। वास्तविक समस्या तो कब्चे माल की पूर्ति बढाने श्रीर उद्योग को उत्पादन में श्रपनी वर्तमान शक्ति के श्रनुकूल वृद्धि करने की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसीलिये श्रीहोगिक प्रसाघनों की दृद्धि के बजाय उत्पादन में वृद्धि करने की सिकारिश की गई थी।

जूट उद्योग की (rated) प्रत्यिकत उत्पादन शक्ति १२ लाख टन थी परन्तु कच्चे माल के श्रमाय के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका है। प्रथम योजना में जूट के उत्पादन को ५१ लाख गाँठों तक ग्रीर जूट के बने माल का सम्पूर्ण प्रत्यिह्नत शक्ति भर श्रमीत् १२ लाख टन तक बढाने का प्रबन्ध किया गया था, जिसमें से १० लाख टन विदेशों को भेज दिया जायगा। परन्तु ये लक्ष्य

हितीय योजना में भी जूट मिलो की प्रत्यकित शक्ति बहाने की तिफारिश प्राप्त नहीं किये जा छके। नहीं की गई है। केवल आधाम में १२ करोड़ क्पर्यों के व्यय से एक मिल खोलने का प्रस्ताव है। प्रयत्न यह होगा कि जुट के बने माल की १६५५-५६ की १,०४,००० टन की उत्पत्ति को बहाकर १६६०-६१ मे १,१००,००० कर दिया जाय। बट का उत्पादन ४० लाख गाँठों से जो कि १६५५.५६ में या वढ़ा कर १६६०-६१ में ५० लाख गाँठ कर दिया जाय। इस प्रकार भारतीय मिलो को आयात किये हुये जूट पर भविष्य में कुछ काल तक निर्मर रहना ही पड़ेगा।

निराकम्य (Tariff) सरज्ञण तथा सरकारी नियोजन के फलस्वरूप भारत में चीनी की मिलों की सख्या १६३१-३२ में ३२ से बढ़कर १६५५-५६ में १६० हो गई । इनमें से १३६ तो १९५४-५५ में उत्पादन कार्य कर रही थीं श्रीर उन्होंने १६ लाख टन से कुछ ही कम चीनी का उत्पादन किया। १९५५-५६ मे १३७ मिले उत्पादन कार्य कर रही यीं ग्रीर उन्होंने १७ लाख टन चीनी का उत्पादन किया। १६४८ में सरकार ने चीनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने का निश्चय किया श्रीर नवीन मिलों की स्थापना की स्वीकृत दी। पूप नई पैक्टरियों, जिनमें इद सहकारी इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं, की स्थापना तथा वर्तमान ६६ मिलों की उत्पादनशक्ति के विस्तार के लिये श्रनुशा पत्र (लाइसेन्स) दे दिये गये हैं। लाइसेन्स दी हुई उत्पादन इकाइयों में चार ने १६५५-५६ में उत्पादन प्रारम्म किया तथा पौच ने १६५६-५७ में। १६५७ के श्रन्त में प्रत्यकित उत्पादन शक्ति २,०१०,००० टन थी। १६५७ ५८ में नौ श्रीर इकाइयों ने भी उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इसके परिशाम स्वरूप फैन्ट्री निर्मित चीनी की उत्पत्ति १६५६-५७ के २०३ लाए टन से बहुकर १६५७ ५८ में २१३ लाख टन होने की सम्भावना है।

चीनी उद्योग के विकास की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिएित एँ—(१) चीनी उद्योग विशेषकर उत्तर प्रदेश श्रीर निहार में केन्द्रित है परन्तु देश के श्रन्य भाग जैमे वम्बई, मद्रास, मैसूर ग्रीर हैदराबाद श्रादि भी चीनी उद्योग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यहाँ गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन श्रिषक है श्रीर गन्ना परने का कार्य भी वहाँ श्रपेद्वाकृत श्रिषक समय तक किया जा सकता है। (२) प्रचलित कारखानों ने कभी भी श्रपनी पूर्ण शक्ति से उत्पादन नहीं किया। इनमें में कुछ तो निल्कुल वन्द रहे जिसके फलस्वर्प उत्पादन सदा वास्तिक उत्पादन शक्ति से कम रहा। (३) चीनी उद्योग में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जो श्रमुक्ततम शक्ति से नीचे हैं। एक श्रीस्त कारखाने को श्रपनी पूर्ण उत्पादन शक्ति का लाम उटाने के लिये प्रतिदिन ८०० टन गन्ना पैरना चाहिये परन्तु श्रमुमान लगाया गया है कि लगभग ८० कारखाने इस स्तर से नीचे हैं। इससे भारत में चीनी का उत्पदान व्यय श्रिषक होता है श्रीर श्राधिक हिट से श्रमुपयुक्त कारखानों का लाम भी कम हो जाता है।

खत्पादन की प्रवृत्तियाँ—मारत में चीनी के उत्पादन में काफी उतार-चढाव श्राता रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीनी का उत्पादन गन्ने की पूर्ति की मात्रा, गला पेरने की श्रविध श्रोर गन्ने से प्राप्त चीनी के प्रतिशत पर निर्मार करता है। चीनी का उत्पादन, १६४८-४६ में १०°०६ लाख टन था जो गिरकर १६४६-५० में ६ ७६ लाख टन हो गया क्योंकि (श्र) १६४७ ४८ में मिलों के लिये गन्ने का भाव २ कण्ये प्रतिमन से घटाकर १६४८-४६ में उत्तर प्रदेश में १ रुपया १० श्राना प्रति मन श्रोर निहार में १ क्पया १३ श्राना प्रतिमन कर दिया गया। गन्ने का मूल्य घटाने का उद्देश्य चीनी का भाव ३५ क्पया ७ श्राना प्रतिमन से घटाकर २८ क्पना ८ श्राना प्रतिमन करना था। गन्ने के भाव में इस कमी से १६४६-५० में कारखानों के लिये गन्ने की पूर्ति में कमी हो गई श्रौर परिगाम स्वरूप उत्पादन भी गिर गया, (ब) गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत मात्रा १६४८-४६ में ६-६७ से गिरकर १६४६-५० में ६-६६ हो गई श्रोर गन्ना पेरने की श्रौसत श्रयिम मी १०१ दिन से घटकर ६१ दिन तक श्रागई। इस कारण चीनी के उत्पादन में कमी हुई जबिक कारखानों की सख्या १३४ से बढ़कर १३६ होगई थी।

परन्तु क्रमशः स्थिति बदली श्रीर उत्पादन बढकर १९५०-५१ में ११'०१ लाख टन ग्रीर १९५१-५२ में १४'८३ लाख टन हो गया। १९५०-५१ ग्रीर १६५१-५२ में चीनी का अधिक उत्पादन होने के तीन मुख्य कारण हैं. (१) मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की छूट दे दी गई। इसके श्रनुसार कारखानों को १९४८-४६ या १९४६-४० में से जिस वर्ष का उत्पादन कम हो उसके १०७ प्रतिशत से स्रिधिक उत्पादित चीनी को खुले बाजार में उस समय के भाव के अनुसार विकय करने की अनुसति दे दी गई। इसके पूर्व कारखानों को श्रपना सम्पूर्ण उत्पादन नियन्त्रित माव पर वेचना पहता या जिससे उन्हें श्रिधिक लाम नहीं हो पाता था। इस कारण उत्पादन वृद्धि की श्रोर उनकी प्रवृत्ति नहीं रही। खुले बाजार में श्रुतिरिक्त चीनी का विकय करने की छूट देने के फलस्वरूप कारलाने ऋषिक उत्पादन का लाम उठा सकते थे इसलिए स्वामाविक ही उत्पादन में वृद्धि हुई, (२) चीनी के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि की गई परन्तु गन्ने का माव १६४८-४६ के स्तर पर ही रहा। कारखाने से बाहर चीनी का नियन्त्रित भाव २८ रुपया ८ स्त्राना स्थिर रखा गया परन्तु पहले यह डी॰ २४ नम्बर की चीनी का माव था और अब ई० २७ नम्बर की चीनी इस माव से विकय होने लगी। चॅिक ई० २७ नम्बर की चीनी डी० २४ नम्बर की चीनी से घटिया प्रकार की है इसिलए यह कहना अनुचित न होगा कि कारखानों ने गत वर्षों की अपेस्ना चीनी का श्राधिक मुल्य वसल किया। उत्तर प्रदेश में १६५०-५१ में गन्ने का भाव २ ह्या । प्रतिमन बढाकर १ रुपया १२ ह्याना प्रतिमन निश्चित किया गया। कारलाने के बाहर ई० २७ नम्बर की चीनी का मान बढाकर २६ रुपया १२ आ० प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसका मिल मालिको पर प्रतिकृत प्रमाव नहीं पहा क्योंकि एक मन चीनी का उत्पादन करने में १० मन गन्ना लगता है श्रीर इस त्राधार पर उत्पादन व्यय १ रुपया ४ श्राना प्रतिमन बढा श्रीर मूल्य भी इतना ही बढ़ा, (३) गन्ना पेरने की अविध में भी वृद्धि की गई। १६४६-५० में गन्ना पेरने की श्रविध ६१ दिन थी जो १६५०-५१ में बढकर १०१ श्रीर १६५१-५२ में १३३ दिन हो गई। यद्यपि यह सत्य है कि गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत मात्रा १० ०३ से घटकर १ ५५७ हो गई परन्तु कारखानों को अधिक समय तक चाल रखने के कारण चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई।

चीनी की उत्पत्ति १६५२-५३ में गिरकर १३ १४ लाख टन और १६५३-५४ में १०'०१ लाख टन हो गई। इसके कारण निम्न हैं, (१) उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों की सख्या जो कि १६५१-५२ में १३६ थी १६५२-५३ और १६५३-५४ में घटकर १२४ हो गई श्रीर कार्य करने के दिनों की श्रीसत सख्या १३३ से घटकर क्रमश∙ ११३ छीर ⊏६ हो गई, (२) १९५२-५३ मे कारखानों में पिछला बचा हुआ माल श्रिषिक मात्रा में या और श्रनेकों मिलें समय से कार्यारम्भ मी न कर सकी जिसके फलस्वरूप जितना उत्पादन करने की उनमें शक्ति थी उतना मी उत्पादन न हो सका, (३) बहुत सी मिलों में यत्रादि घिसे पिटे श्रीर प्राचीन ढग के थे जिनके कारण उत्पादन शक्ति का पूर्ण प्रयोग होना सम्भव नहीं या, श्रीर (४) श्रवैध सम से शाराव खींचने के कार्य में लाने के लिए वढी हुई गुड़ की माग को पूर्ण करने के लिये कुछ गन्ने का प्रयोग गुड बनाने में कर लिया गया। १६५२-५३ की फरल के लिए गनने का मूल्य घटाकर १ ६० ५ ग्राना प्रति मन श्रीर चीनी का नियत्रित मूल्य २७ क० प्रतिमन कर दिया गया। गन्ने का प्रतिमन मुल्य इतना कम हो जाने से कारपानो को पर्याप्त मात्रा में गन्ना ही न मिल सका । १९५३-५४, १९५४-५५ श्रीर १९५५-५६ की फसलों के लिये मारत की सरकार ने गन्ने का मूल्य १ ६० ७ ग्रा० प्रतिमन कर दिया। इस समय चीनी के मूल्य पर कोई नियत्रण नहीं हैं, केवल यह प्रतिबन्ध है कि फ़सल की उत्पत्ति का २५% 'बुरज्ञित माल' समका जाय जिसमें से सरकार चीनी पिछले नियत्रित मूल्य पर अर्थात् २७ र० प्रतिमन पर वेचती है। कुपकों के दृष्टिकीया से गन्ने का १ र० ७ श्राना प्रति मन मूल्य श्रपर्याप्त है श्रीर इसी कारण फैक्ट्रियों की पर्याप्त मात्रा में कचा माल मिलने में कठिनाई पड़ती है।

१६५६-५७ में चीनो की उत्पत्ति २०० लाख टन थी। १६५७-५८ में इससे बढकर २१५ लाख टन होने की सम्भावना है। इसका कारण वर्तमान फैक्ट्रियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि तथा नई फैक्ट्रियों की स्थापना है।

उत्पादन चमता—चीनी उद्योग की मुख्य समस्या उत्पादन व्यय की अधिकता है। उत्पादन व्यय अधिक होने से उपभोक्ता पर अनावश्यक भार पहता है और अन्य देशों की अपेक्ता भारतीय चीनी का मूल्य अधिक होने के कारण निर्यात की मात्रा मी नहीं बढ पाती। भारतीय चीनी का उत्पादन व्यय अधिक होने के अनेक कारण हैं। इसकी कम करके चीनी का मूल्य घटाने के लिये काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। चीनी-उद्योग के सम्बन्ध में प्रयम किटनाई यह है कि कृषकों के हितों की रक्ता के लिये सरकार गन्ने का मूल्य अधिक निश्चित करती है और वेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों उद्योग पर अनेक कर लगाती हैं। गन्ने का अधिक मूल्य, अधिक मजदूरी और अधिक कर का फल यह होता है कि चीनी का उत्पादन व्यय कम होने की अपेक्ता बढता जाता है। चीनी के मूल्य को घटाने के लिये यह आवश्यक होगा कि गन्ने के मूल्य को घटाया जाय। चीनी उद्योग की जींच करने वाले प्रशुक्त मगढल ने सुक्ताव दिया था कि

१६४६-५० में गन्ने फे मूल्य में ३ श्राना प्रतिमन कमी की जाय, १६५०-५१ में भी इतनी कमी त्रोर की जाय जिससे भाव १ क्पया ४ श्राना प्रतिमन तक श्रा जाय। यदि सुक्ताव को लागू किया जाता तो इससे प्रतिमन चीनी में गन्ने का मूल्य ३ काया १२ श्राना कम हो जाता। यदि प्रशुल्क मण्डल के सुक्ताव के श्रनुः सार माल तैयार करने की मद मे भी २ काया ६ श्राने की कमी कर दी जाती तो इससे १६५०-५१ मे चीनी का भाग २२ कपया ४ श्राना प्रतिमन हो जाता। यह खेद की बात है कि सरकार ने प्रशुल्क मण्डल के सुक्तावों के श्रनुसार कार्य नहीं किया श्रीर गन्ने का भाव घटाने के बजाय बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप चीनी के मूल्य में श्रीर वृद्धि हो गई। १६५२-५३ में गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार में घटाकर १ क्पया ५ श्राना प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसके पद्धात् भारत सरकार द्वारा फिर से बढ़ाकर १ क्पया ७ श्राना प्रतिमन कर दिया गया।

गन्ने की उत्पत्ति—गन्ने के मूल्य की समस्या सन्तोषजनक दङ्ग में तभी सुलमाई जा सकती है जनकि प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति में वृद्धि की जाय। भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति से वृद्धि की जाय। भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति ससार में सब से कम है श्रीर निरन्तर कम होती जा रही है। स्यूचा में प्रति एकड़ उत्पत्ति १७'१२ टन, मारिशस में १६'६२ टन, श्रास्ट्रेलिया में २१'३४ टन, प्युरटोरीको में २४'१६ टन, जाना में ५६ टन, श्रीर हवाई में ६२'०५ टन है। गन्ने के प्रत्यादान की प्रतिशत स्यूचा में १२'२५, मारिशस में १२'०८, ग्रास्ट्रेलिया में १४'३३, प्युरटोरीको में १२ २३, जाना मे ११'४६ श्रीर हवाई में १०'४६ है श्रोर भारत में १०% है। कृपक को तो भूमि से श्रपनी साधारण ग्राय चाहिये श्रीर यदि गन्ने का मूल्य घटा दिया जाय श्रीर यदि गन्ने में प्राप्त प्रति एकड़ ग्राय बढ़ जाय तो कृपक के लिये चिन्ता की कोई धात न होगी।

वर्तमान समय में चीनी तैयार करने के लिये कुछ कारलाने सल्फीटेशन मोसेस श्रीर कुछ कारलोनेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। दोनों ही प्रकार के विधायन में गन्थक का उपयोग होता है जिससे चीनी के कारलानों का ज्यय बढता है क्योंकि गन्धक का भारत बहुत प्रविक मूल्य पर श्रायात करता है। कारबोनेशन प्रोसेस में ० ० ० २% मे ० ० २ ५ % तक गन्धक लगता है श्रीर सल्फीटेशन प्रोसेस में इसकी मात्रा • • ० ५ % ते ० ० ८ % तक है। इसिलिये हन दोनों में से कारबोनेशन प्रोसेस का प्रयोग करना श्रावश्यक है क्योंकि इससे उत्पादन व्यय पटेगा। हिस्डयन इन्स्टीट्यूट आव शुगर टैकनालाजी के सचालक श्री जे० एम० साहा ने बिना गन्धक का प्रयोग किये चीनी बनाने की नई प्रक्रिया खोज निकाली है। इस नई

प्रक्रिया से श्रिषिक सात्रा में चीनी उत्पन्न होती है श्रोर चीनी का प्रकार मी श्रपेदाकृत श्रच्छा है। पटना माइन्स कालेज के श्री ढी० एन• घोष ने एक नई रीति
निकाली है जिससे बिना किसी रसायनिक या ताप की सहायता के जिजली के
द्वारा गन्ने का रस साफ किया जा सकता है। इन दोनों प्रणालियों का श्रमी तक
व्यवसायिक पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इनसे
चीनी बनाने के व्यय में कमी श्रवश्य होगी। चीनी उद्योग में श्रच्छी मशीनों के
लगाने से भी उत्पादन व्यय में कमी की जा सकती है।

स्थिति-उत्पादन व्यय ग्राधिक होने का एक कारण कारखानों का श्रातु-पयुक्त स्थानों पर स्थित होना मी है। यद्यपि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश श्रीर विद्दार में श्रिधिकतर कारखाने स्थित हैं परन्तु यदि कारखाने बम्बई या दिख्या मारत में होते तो अधिक उपयुक्त होता । वम्बई तथा दिल्ला के अन्य चेत्रों में गन्ने का पति एकड़ उत्पादन अधिक है और वहाँ गन्ने नी पिराई भी अधिक समय तक होती है। यदि उत्तर भारत की श्रपेज्ञा उद्योग दिज्ञण में ही विकसित होता तो चीनी का उत्पादन व्यय श्रवश्य कम होता। परन्तु श्रव यह है कि चीनी-उद्योग श्रिषि-कतर उत्तर प्रदेश श्रीर विदार में केन्द्रित हो गया है। १९५१ के उद्योग (विकास एवम् नियमन) कानून के अतर्गत नियुक्त लाइचेंचिन्ग समिति ने कुछ कारखानी को एक साथ नये स्थानों में ले जाने की सिफारिश की भी परन्तु यह समस्या का उपयुक्त इल विद नहीं हुया क्योंकि (१) यदि यह योजना लागू की जाय तो एक कारलाने को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने में १० से १५ लाख रुपया व्यय हो जायगा श्रीर यातायात की व्यवस्था में व्यय होगा। इसके साथ ही कारखाने को इटाने की अविध में उत्पादन बन्द रहेगा; (२) जिन चेत्रों से कारलाने इटाये जायंगे उनकी श्राधिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायगी श्रीर उनका श्रन्य चेत्रों से सम्बन्ध टूट जायगा। इसलिये उद्योग की स्थिति में सुभार करने का सबसे श्रव्छा उपाय यही है कि नवीन श्रीर उपयुक्त स्थानों में बीरे-बीरे नवीन कारखाने स्थापित किये जायं और अनुपयुक्त स्थानों में स्थित कारखाने जब पुराने पड़ जायँ श्रीर पुनर्निर्माण की श्रावश्यकता हो तब उनका पुनर्निर्माण न करने दिया जाय।

निर्मात—प्रतीत में चीनी के लिये मारत विदेशों पर निर्मर था। १६२६-३॰ में भारत ने लगभग ६३ लाख दन चीनी का आयात किया। परन्तु हाल में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है लिएके फलस्त्ररूप अब आयात केवल नाम मात्रकों होता है। यह बहुत समव है कि भविष्य में भारत चीनी का आयात करने की अपेद्धा निर्यात करने लगेगा। हवायन अवर्षिष्ट्रीय चीनी सम्मेलन के कथनानुसार "बहुत

समय तक भारत को चीनी का निर्यात करने की अनुमित नहीं दी गई, यहाँ तक कि १६३६-४० में जब देश में चीनी का उत्पादन आवश्यकता से कहीं अधिक हुआ था, अतिरिक्त चीनी का भारत से निर्यात नहीं किया जा सका। कुछ समय से यद्यि भारत चीनी का निर्यात कर सकता है परन्तु निर्यात की मात्रा पर नियत्रण है। कुछ पड़ोस के देशों को भारत केवल कुछ हजार टन चीनी प्रतिवर्ष मेज सकता है।"

चीनी का निर्यात बढाने में सबसे बड़ी किंठनाई मारवीय चीनी का अपेबाकृत अधिक मूल्य है। मारत में कारखाने के बाहर चीनी का भाव (ex-factory price) २७ घपया प्रति मन है जब कि अन्य देशों में २१ से २३ घपया प्रति मन है। इसिलए जब तक सरकार या तो चीनी के निर्यात के लिये आर्थिक सहायता नहीं देती या विदेशों को कम मूल्य पर निर्यात करने और घाटा पूर्ति के लिये देश में अधिक मूल्य पर वेचने की अनुमति नहीं देती तब तक चीनी का निर्यात बढ़ा सकना असमव है। परन्तु वर्तमान स्थित में उक्त दोनों साधन अव्यवहारिक हैं। इन कारणों से चीनी का निर्यात बहुत कम होता है और जब तक चीनी का उत्पादन व्यय नहीं घटाया जाता तब तक मविष्य में भी निर्यात में वृद्धि की कोई आशा नहीं दिखाई देती।

योजना के अन्तर्गत—प्रथम पश्चवर्षीय योजना के आरम्म में चीनी के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि का कोई भी प्रवन्य नहीं किया क्योंकि यह आशा की जाती यी कि १५. प्र लाख टन की उत्पादन शक्ति का अनुमान और १६५५ ५६ तक १५ लाख टन का वास्तिविक उत्पादन उपयुक्त होगा। परन्तु १६५४-५५ में ही चीनी का उत्पादन १६ लाख टन के लगभग हो गया, अर्थात् योजना के लक्ष्य से १ लाख टन अधिक हो गया। इसलिए प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य १८ लाख टन अधिक हो गया। इसलिए प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य १८ लाख टन कर दिया गया। इस ब्येय से सरकार ने ३७ नई मिलों को और ४० प्रानी मिलों के विस्तार के लिये लाइसेन्स प्रदान किये। इससे ५१ लाख टन तक की उत्पादन शक्ति बढने और वास्तिविक उत्पादन १९ लाख टन वढने की आशा है।

दितीय पञ्चवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि उत्पादन शकि १७'४ लाख टन से जितने का १६५५ ५६ में अनुमान किया गया है, १६६०-६१ तक २५ लाख टन कर दी जाय और चीनी का उत्पादन १६५५-५६ के १७ लाख टन से बढ़ाकर १६६०-६१ तक २२ई लाख टन कर दिया जाय। उत्पादन की इस वृद्धि में से सहकारी चीनी के कारखाने ३ई लाख टन उत्पादित करेंगे। दितीय योजना में उत्पादन की बढ़ी हुई मात्रा का लक्ष्य उपयुक्त है। इस्डियन शुगर मिल्छ एसोसिएशन ने श्रपने स्मारकपत्र में जो उसने सरकार को मेना या यह लिखा या कि वर्तमान चीनी के कारखाने पहिले से लाहसेन्छ प्राप्त कारखानों को सम्मिलित करते हुये १६६०-६१ तक २७ लाख टन तक चीनी का उत्पादन करने में समर्थ हैं नविक योजना का लक्ष्य केवल २२३ लाख टन ही उत्पादन करने का है। यदि भविष्य की कठिनाइयों जैमे वर्षा का न होना, बाढ का श्राना इत्यादि को विचाराधीन रख लिया जाय तब १६६०-६१ तक वर्तमान कारखाने पहिले से लाइसेन्स प्राप्त कारखानों को मिलाकर प्रति वर्ष २५ लाख टन चीनी का उत्यादन कर सर्केंगे जो कि लक्ष्य से २६ लाख टन श्रिषक होगा। इस बात को सोचते हुये सरकार के लिए यह श्रावश्यक है कि नई फैक्ट्रियों को लाइसेन्स देने में सावधानी करें नहीं तो भारतीय चीनी उद्योग में उत्पादन शक्त का श्राधिक्य हो जायगा श्रीर सम्भवत उत्पादन मी श्रावश्यकता से श्रिषक होगा।

कोयला उद्योग

मारत में कोयले के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। १६६० का २४० लाख टन का उत्पादन १६५७ में बढ़कर ४३५ लाख टन हो गया। चन् १६५० तक कोयले का उत्पादन लगमग ३०० लाख टन तक बढ़ पाया था पर १६५० में सर्व प्रथम उत्पादन बढ़कर ३२३३ लाख टन हो गया था। आगामी वर्षों में उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। १६५१ में ३४६ ६५ लाख टन, १६५२ में ३६३३४ लाख टन, १६५२ में ३८३ श लाख टन, १६५२ में ३८३ श लाख टन, १६५५ में ३८० लाख टन तथा १६५७ में ४३५ लाख टन हुआ था। उत्पादन में यह वृद्धि वर्तमान खानों की अधिक धनी खुदाई करने तथा कोयले की माँग में वृद्धि होने के कारण नई खानों की खुदाई का कार्य आरम करने के कारण हई है।

उत्पादन क्षमता—यद्यपि भारत में कोयले के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु कोयले की खानों के उद्योग की उत्पादन इमिता बहुत कम है। बहुत सी खानों इतनी छोटो हैं जिन्हें आर्थिक हिंदि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। खानों के यन्त्रीकरण में भी विशेष प्रगति नहीं की गई है। कोयला उद्योग में जितने अभिक कार्य करते हैं उनकी सख्या आवश्यकता से अधिक है। साथ ही अन्य देशों के विपरीत भारतीय खदान-अभिक की कार्य इमता कम है और प्रति अभिक उत्पादन भी कम होता है। उद्योग में कार्य करने वाले अभिकों की सख्या १६४१-५१ के मध्य ५८% वद्ध गई है परन्तु कोयले के उत्पादन में केवल ३२% की ही वृद्धि हो पाई है इससे अभिकों की उत्पादकता में हास प्रगट होता है। यह प्राविधिक (टैक्निकल) पिछड़ापन और कार्यक्षमता में कमी, कोयले के उद्योग की स्पर्ध शक्ति और लाम को नीचे स्तर पर रखने के लिये उत्तरदायी है।

च्योलोजिकल, माइनिंग और मैटालर्जिकल सोसाइटी की २८ वीं वार्षिक वेटक में यह बताया गया कि भारत में प्रति श्रमिक आठ घटे की एक शिफ्ट में २'७ टन कोयले का उत्पादन होता है जब कि ब्रिटेन में ६'२६ टन, जर्मनी में २'७ टन कोयले का उत्पादन होता है। इसका ८६६ टन और अमरीका में २१'६८ टन कोयले का उत्पादन होता है। इसका तात्र्य यह है कि उत्पादन ब्या कम करने के लिए और उद्योग की वित्तीय स्थित तात्र्य यह है कि उत्पादन ब्या कम करने के लिए और उद्योग की वित्तीय स्थित तात्र्य यह है कि उत्पादन ब्या कम करने के लिए और उद्योग का श्रमिनवीकरण करने की आव-१ एकता है। कोयला उद्योग का यन्त्रीकरण करने में दो कठिनाइयो का समना श्यकता है। कोयला उद्योग का यन्त्रीकरण करने में दो कठिनाइयो का समना श्यकता है करना पहला है—(१) इस प्रक्रिया में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है करना पहला है—(१) इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं ध्योंकि इस योजना को लागू और (२) श्रमिक इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं ध्योंकि इस योजना को लागू करने से भूनेक श्रमिक वेरोजगार हो जायँगे। उद्योग की उत्पादन-इसता में सुधार करने के लिए इन दोनों कठिनाइयो को दूर करना आवश्यक है।

परिरक्ष्य (Conservation) — वर्तमान समय में धातुशोधन के कार्य में भ्राने वाले उत्तम श्रेगी के कीयले की काफी चृति हो रही है। इस कीयले का कुल जितना उत्पादन होता है उसका ४० प्रविशत माग रेलवे के कार्य में आता है, २१ प्रतिशत के लगमग लोहे और इस्पात उद्योग में और १३ प्रतिशत का निर्यात और नहाजों में प्रयोग होता है। इस्पात उत्तोग में इस प्रकार के कोयले की बहुत आवश्यकता होती है इस्रिलये इस उद्योग के उपयोग के लिये इसका सरदाण करना पड़िगा। मेटालर्जीकल कोल कमेटी (१६४६) अपनी जांच पहताल के पश्चात् इस परिखाम पर पहुँची कि प्रत्येक वर्ष पूर्व की कुल खपत में से (उद्योग को बिना कुछ हानि पहुँचाये) आगामी ५ वर्षों में बीरे धीरे १० प्रतिशत की कमी की जा सकती है और इस प्रकार घातुशोधन के कार्य में आने वाले उत्तम श्रेणी के कोपले का उत्पादन बटाया जा सकता है। इस समिति ने सुमाय दिया है कि (म्र) किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के कीयले की खानें न खोली जाय । यदि पुनः प्रचलित करने में अधिक घन न लगे तो उत्तम श्रेणी के कोयले की कुछ खानों को वन्द किया जा सकता है, (व) कोयले के चट्टे लगाने, मिलाने ग्रीर धोने को कानूनी रूप से श्रानिवार्य कर देना चाहिए, श्रीर (स) खराव कोयला छोड़कर श्रन्छ। कोयला निकालने की रीति को वन्द कर देना चाहिए। योजना श्रायोग ने सुमाव दिया है उत्तम श्रेगी के कीयले का सरक्षण किया जाय आरे कीयले तथा कोयला समिति से सम्बन्धित सभी विषयों पर परस्पर उचित संबन्ध स्थापित करने वाली नीति श्रपनाई जाय । सरकार ने वातु शोवन के कार्य में श्रानेवाले कोयले के उत्पादन की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर दी है। १६५३ उत्पादन की अविकतम मात्रा १५१ द लाख टन, १६५४-५५ में १४३ द लाख टन, १६५६ में १५४ १ लाख टन तथा १६५७ में १६० लाख टन कर दी गई।

सरकार की इस नीति की दो आधारों पर आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि (आ) उत्तम प्रकार के कोयले के उत्पादन की मात्रा पर प्रतिचन्ध लगाना समस्या का उचित हल नहीं है। सरक्षण करने का अर्थ है रोकी जा सकने वाली इति होने की सारी संमावनाएँ समाप्त करना, उत्पादन में अधिक उपयुक्त साधनों तथा उपायों का प्रयोग करना और कोयले के व्यय में वचत करना इत्यादि। इसके साथ ही सरकार की नीति को व्यापक होना मी आवश्यक है, (व) कोयले के चट्टे लगाने, मिलाने और घोने में और सरक्षण की नीति को लागू करने में आतिरिक्त व्यय करना पहला है जिसका उत्पादन व्यय पर प्रभाव पहला है। सरकार न तो उद्योग को आवश्यक वित्त की सहायता देती है और न अति-रिक्त व्यय का घन वस्त्व करने के लिये कोयले के मूल्य में वृद्धि करने देती है। उद्योग पर उक्त प्रतिवन्ध लगाना सरकार की न्यायसगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। इस अभाव की पूर्ति किये विना सरकार की कोयला सरक्षण नीति से उद्योग को और अधिक हानि होने की सभावना है।

परिवहन—कोयला उद्योग की एक सबसे बड़ी किटनाई परिवहन के साधनों का अभाव है। कोयले को अन्यत्र मेजने के लिए पर्याप्त सस्या में गाड़ियाँ या मालगाडी के डि॰वे नहीं मिलते हैं। गाडियाँ मिलने में बहुत देर होती है जिससे खानों के समीप कोयले के देर लग जाते हैं। इससे खानों के कार्य में बहुत किटनाई होती है। बँगाल और विहार के कोयले की खानों के केत्र में (जो देश के ८०% कोयले के उत्पादन के लिये उत्तर टायी है) प्रतिदिन लादी जाने वाली मालगाडियों के डि॰वे की श्रीसत सख्या १९५७ में २६६७ थी, जब कि १९५६ तथा १९५२ में यह सख्या क्रमश ३४०५ तथा ३१६३ थी। इससे उन्नित की प्रवृत्त प्रदिश्त होती है परन्तु खेद है कि कोयले की खानों को उपलब्ध माल गाड़ियों की सख्या न तो आवश्यकता के अनुक्ल ही रही है और न रेल विभाग की शिक्त के ही अनुक्ल।

कोयले के लिये मालगाहियों के हिन्मों की पृति में वृद्धि आवश्यक है ताकि उद्योग द्वारा मोयला श्रीवता में श्रीर मम मृल्य पर वेचा जा सके। मालगाड़ी के हिन्मों की पृत्ति में वृद्धि के लिये रेलवे के प्रसाधनों में वृद्धि आवश्यक होगी। इसमें निश्चय ही समय लगेगा। परन्तु कुछ श्रन्य मी उपाय हैं जिनसे कोयले की खानों के लिये मालगाड़ी के डिन्मों की पृति में विद्ध की जा सकती है। वर्तमान मालगाड़ी के डिन्मों के आवेटन की प्रणाली वड़ी ही जटिल है जिससे देर मो लगती है श्रीर खानों पर अत्यधिक कोयला भी एक ति हो जाता है। दूसरी समस्या ढोने की दर की है। भारत सरकार ने कोयले के माड़े की दर में ३० प्रतिशत वृद्धि कर दी है। भाड़े की वृद्धि कोयला उद्योग के सम्बन्ध में नियुक्त की गई वर्किंग पार्टी के सुकाव के अनुसार की गई है। इस वृद्धि से कोयले के परिवहन व्यय में वृद्धि हो गई और इस प्रकार कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों का उत्पादन व्यय भी वढ गया। भारतीय उत्योगों का विकास करने के लिए कोयले का परिवहन व्यय कम करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

कोयले के निर्यात में कमी की समस्या भारत सरकार ने १६५४ में नियुक्त एक कमेटी के सम्मुख रक्खी थी जिसने यह रिपोर्ट दी कि भारत के कोयले के मुख्य बाजार पड़ोसी देशों में ही हैं। इस लिये बरमा, लका, पाकिस्तान, दिल्ली पूर्वी एशिया के कुछ देशों को ही भारत को अपना स्वाभाविक बाजार समक्ता चाहिये। १६५१-५२ में जो यूक्प को अधिक निर्यात हुआ। या वह यूक्प में कोयले के अभाव, दिल्ली अफीका में यातायात की कठिनाईयों, आस्ट्रेलिया में नियित्रत उत्पादन और कीरिया के युद्ध जिनत कारणों से था। १६५३ में ये १६५१-५२ की अपनादी स्थिति समाप्त हो गई ओर जो नवीन बाजार भारत को प्राप्त हो गये थे वे सामान्य स्थिति होने पर फिर समाप्त हो गये। कोयले का निर्यात बढ़ाने के विचार से कमेटी ने निम्न सिफारिशें कीं: (१) कोयले का सरकारी क्य विकय बन्ट होना चाहिये, (२) कोयले की विभिन्न प्रकारों पर जो नियत्रण लगा हुआ है उसे कम करना चाहिये, (३) कोल अदिग बोर्ड को वे ही ग्रेड बनाने चाहिये जो कन्ट्रोल आर्डर में दे दिये हैं, और (४) कलकत्ते के बन्टरगाह पर अधिक सुविधाओं के देने के उपाय करने चाहिये।

योजना के श्रन्तर्गत — द्वितीय पच वर्णीय योजना में कोयला उद्योग को प्रमुख स्थान दिया गया है। घीरे घीरे इसे सरकारी चेत्र में ले श्राया जायगा। कोयले का उत्पादन ३६७.७ लाख टन से जो कि १९५४ में था बढ़ाकर १६६०-६१ में ५६७.७ लाख टन कर दिया जायगा।

१६४८ के श्रीद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा गया या कि प्रत्येक कोयले की नवीन खान सरकारी चेत्र में ही श्रारम्भ होगी, ऐसी स्थिति के श्रातिरिक्त जहाँ कि राष्ट्रीय दृष्टिकीण से सरकार व्यक्तिगत व्यवसायियों का सहयोग श्रावश्यक सममती है। श्रारम्म में इस नीति के व्यवहार में कुछ शियिलता दिसाई गई परन्तु श्रव यह निश्चय कर लिया गया है कि भविष्य में कोयले के उद्योग के नवीन उपक्रमों को सरकारी चेत्र में ही रखने का प्रयत्न किया जायगा श्रीर विद्य हुई माँग को पूर्ण करने के लिए श्रातिरिक्त कोयले का उत्पादन द्वितीय योजना काल में श्रीधकतम स्तर तक सरकारी चेत्र में ही किया जायगा।

लोहा खाँर इस्पात उद्योग

भारतीय लोहे श्रीर इस्पात उत्योग के च्रेत्र में तीन मुख्य उत्पादक हैं, टाटा श्रायरन एएड स्टील कम्पनी, इण्डियन ग्रायरन एएड स्टील कम्पनी (इसमें स्टील कारपोरेशन श्राफ बगाल भी सम्मिलित है) ग्रीर मेस्र ग्रायरन स्टील वर्मा । इन कारखानों में कच्चे लोहे का इस्पात बनाया जाता है श्रीर इस्पात से श्राय-श्यक वस्तुर्ये तैयार की जाती हैं। इनके श्रातिरिक्त लगमग ६४ छोटे कारपाने हैं जो व्यर्थ लोहे से ग्रीर लोहे के छड़ों से जो उत्पादकों द्वारा प्राप्त होते हैं या श्रायत होते हैं, इत्पात तेयार करते हैं।

भारतीय इत्यात उद्योग एशिया में सबसे बड़ा है श्रीर ससार के सर्वोत्तम इत्यात उद्योगों में मे एक है। १६२४ में सरस्यण मिलने के पश्चात् इसने महत्व- पूर्ण प्रगति की है। उद्योग की उत्यादन समता में इतनी नृष्टि हुई कि १६४१ में सरस्यण की कुछ श्रावश्यकता नहीं रही। इस्पात का उत्पादन १६४७ में दृष्ट लाख टन था जो बढ़कर १६५२-१६५५ तथा १६५७ में नमशः ११ लाख टन श्रोर १३ लाख टन हो गया। १६५६ में उत्यादन की मात्रा ४५ लाख टन श्रात्मानित की गई है। १६५३ में इस्पात श्रीर उले हुए लोहे का उत्यादन १६५२ की श्रपेसा कम हो गया। इसका कारण किसी सीमा तक तो श्रीमों के कगावे थे श्रीर किसी सीमा तक यन्त्रों के श्रीमनवीकरण के कारण उत्यादन १६५२ की श्रपेसा का सहस समा के लिए कारखानों को सन्द रखना श्रावश्यक हो गया था। इसके श्रान्वत उत्यादन में वृद्धि हुई श्रीर भविष्य में इसके श्रीर श्रिषक बढ़ने की समावना है। मारत के इस्पात श्रीर लोटे के उद्योग की मुख्य समस्याएँ (श्र) इस्पात के उत्यादन में वृद्धि करना, (व) ढले हुए लोटे के उद्यादन को काउन्द्रांथों के लिये बढ़ाना है।

लोहे श्रोर इस्पात उद्योग के लिए श्रावश्यक कच्चा माल भारत में ही प्राप्त है। जितना कच्चा माल वर्तमान समय में प्राप्त है उतने से ही उद्योग के लिए इस्पात वढ़ा लेना सम्भव है।

इस्पात का मूल्य—देशी इस्पात का मूल्य श्रायात किये हुये इस्पात से बहुत कम है। मूल्यों में समानता लाना बहुत श्रावश्यक है। यह मूल्य के नियत्रण द्वारा ही (युद्धकाल से श्राज तक) सम्मव हो सका है। १ श्रवह्मर १६३६ से ३० जून १६४४ तक युद्ध के लिये क्रय किये जाने वाले इस्पात के मूल्य पर नियन्त्रण था। परन्तु इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं था। इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं था। इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर परिनियमित रूप से नियन्त्रण १ जुलाई १६४४ से श्रारम्म हुश्रा। इस सम्पन्ध में सरकार जिस प्रणाली का श्रवसरण करती है उसके

अनुखार प्रत्यारच्य मूल्य (retention price) नियत कर दिया जाता है जिस पर मुख्य-मुख्य उत्पादक इस्पात विकय करते हैं, ग्रीर उपभोक्ताग्रों के लिये मूल्य की एक अन्य कॅची दर नियत होती है जिस पर वे क्रय करते हैं। दोनों मूल्यों के अन्तर से प्राप्त घन समानता स्थापित करने नाले कोप (equalisation method) में जमा कर दिया जाता है जिसमें से इस्पात के आयात में सहायता प्रदान की जाती है श्रीर इस्पात उत्पादकों के ग्राप्तनयीकरण तथा विकास के कार्यक्रमों में शाधिक सहायता दी जाती है। एक जुलाई १९४४ और ३१ मार्च १९४६ के मध्य इस्पात के हो प्रत्यारच्या मूल्य निर्धारित किये गये थे। एक युद्ध के लिये क्रय हस्पात के हो प्रत्यारच्या मूल्य निर्धारित किये गये थे। एक युद्ध के लिये क्रय इस्पात के हो प्रत्यारच्या मूल्य निर्धारित किये गये थे। एक पुद्ध के लिये क्रय इस्पात के हिये अपित है। परिस्थिति के परिनर्वत के साथ प्रत्यारच्या मूल्य और विकय मूल्य निर्धारित है। परिस्थिति के परिनर्वत के साथ प्रत्यारच्या मूल्य और विकय मूल्य वदलते रहते हैं।

प्रशुक्त मराहल की विकारिशों के अनुवार सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली है कि १६५५-५६ से १६५६-६० तक की अवधि के लिये ३६३ ६० प्रति टन के प्रत्यारज्ञण मूल्य की एक ही दर टाटा कम्मनी और इन्डियन ग्रायरन एएड स्टील कम्मनी के लिये नियत की जानी चाहिये। इस पुनर्निश्चित मूल्य के लागू करने के लिये सरकार का प्रस्ताव करवरी १६५६ में पास हुआ। इसी समय १६५४-५५ के लिये पुनर्परिज्ञित प्रत्यारज्ञण मूल्य ३४३ ६० प्रति टन का टाटा आयरन एएड स्टील कम्मनी के लिए नियत किया गया। इस बात को सब ने स्वीकार कर लिया कि १६५४-५५ का समायोजित प्रत्यारज्ञण मूल्य और ३६३ व० प्रति टन के समान प्रत्यारज्ञण मूल्य का ग्रन्तर प्रत्येक कम्मनी अपने विकास की में दे देगी।

भूतकाल में इस्पात का मूल्य व्यवई, कलकत्ता, मद्रास, जमशेदपुर श्रीर वरनपुर में ५०० कपये प्रति टन था, श्रीर श्रन्य स्थानों पर उपभोक्ताश्रों को उसके साथ परिवहन व्यय मिला कर देना पढ़ता था। इसका श्र्म यह था कि (१) उत्तर प्रदेश, पजाब श्रीर उत्पादन केन्द्रों तथा बन्टरगाहों से दूर स्थित नगरों के उपभोक्ताश्रों को श्रिषक मूल्य देना पढ़ता था, श्रीर (२) वन्दरगाहों के निकट उद्योग किन्द्रत होते जा रहे थे स्थोंकि उन्हें वहीं इस्पात सत्ता मिलता था। सरकार की वृत्त १९५६ की नई नीति के श्रनुसार इस्पात का एक ही मूल्य (५२५६० प्रति टन) जिसमें रेल का किराया सम्मिलित होगा रेल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगा। इस प्रकार कपर बताये हुए पंची स्थानों पर उपमोक्ताश्रों को २५ ६० प्रति टन श्रांतिरक्त मूल्य देना पढ़ेगा श्रीर उन उपभोक्ताश्रों को जो श्रमृतसर श्रीर कानपुर ऐसे स्थानों में हैं लगमग ३५ ६० प्रतिटन कम देना पढ़ेगा। पहले मूल्य

में समानता लाने के लिये सिद्धान्त का प्रयोग केवल इस्पात के सम्बन्ध में ही लागू किया गया था। यन यह सिद्धान्त ढाले हुए लोहे के सम्बन्ध में भी लागू किया जायगा। इस नई नीति के कारण इस्पात श्रोर लोहे के मूल्य में भारत के उत्तरी भाग में रहने वाले व्यक्तियों के लिये कभी हो जायगी ग्रोर दुर्लभ वस्तुयें प्रत्येक को युक्ति सगत मूल्य पर प्राप्त हो सर्केंगी।

इस्पात के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण उपभोक्तात्रों के लिये लाभकारी िस हुत्रा है क्यों कि तिना इस नियन्त्रण के उन्हें ये वस्तुय अधिक मूल्य पर प्राप्त होती। परन्तु कम प्रस्थार ज्ञण मूल्य के नियत किये जाने से उत्पादकों को हानि हुई हैं। यदि उत्पादकों को उँचा मूल्य मिला होता तो वे अवश्य उत्योग के विस्तार करने में तथा श्रमिनवीकरण में व्यय किया जाता। अय उन्हें इस काय के लिये सरकार से ऋण लेना पढ़ा है श्रीर सरकार ने मूल्य समीकरण कोप (equalisation fund) से यह ऋण दिया है। दूसरे शन्दों में हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने टाटा सम्पनी श्रीर स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल को तथा अन्य इस्पात के उत्पादकों को वह धन ऋण के रूप में दिया है लो कि न्यायत उन्हीं का था। यदि इस्पात कम्पनियों को ऐसे श्रयसर पर जब कि इस्पात का मूल्य वहा हुशा है श्रीधक मूल्य का लाम न उठाने दिया जायगा तो आर्थिक मन्दी के समय जब मूल्य उत्पादन व्यय से कम होता है वे हानि का सामना कैसे करेंगे।

भविष्य की मोग —लोहा श्रीर इस्रात मेजर पेनेल ने १६४६ में अनुमान लगाया कि भारत में २० लाए टन इस्रात की खपत है, जब कि युद्ध के पूर्व केवल दस लाख टन की खपत थी। परन्तु १६४७ में परामर्शदात्री नियोजन परिषद ने श्रनुमान लगाया कि देश में सामान्य स्थित में १५ लाख टन इस्रात की खपत है। कृषि तथा श्रीद्योगिक विकास पर विचार करते हुये योजना श्रायोग ने श्रनुमान लगाया कि १६५२ में कुल ३२ लाख टन की श्रावश्यकता होगी ग्रीर १६५७ तक २८ लाख टन की श्रावश्यकता होगी ग्रीर १६५७ तक २८ लाख टन की श्रावश्यकता हो जायगी। लोहा श्रीर इस्रात पेनल ने श्रनुमान लगाया है कि भारत को फाउन्ड्रियों के लिये प्रतिवर्ष ३ लाख टन ढले हुये लोहे की श्रावश्यकता होगी। वाण्विष्य मन्त्रालय के छोटे श्रीर बढे इजीनिरिंग उद्योग के जाँच करने वाले पेनेल ने १६५१ में वताया कि मारत को ४ लाख से ४.२ लाख टन तक ढले हुये लोहे की श्रावश्यकता थी। द्वितीय पचवर्षीय योजना का श्रनुमान है कि १६६०-६१ में इस्रात की माँग लगभग ४५ लाख टन की श्रीर फाउन्ड्रियों के लिये ढले लोहे की माँग लगभग ७५ लाख टन की होगी। मुख्य उत्पादकगण ढला लोहा श्रपने प्रयोग के लिये तथा फाउन्ड्रियों के लिये ही

उत्पादित करते हैं। इसलिये फाउन्ड्रियों के लिये ढले लोहे की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये प्रमुख उत्पादकों को अपने उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी।

योजना के अन्तर्गत—दितीय पचवर्षीय योजना ने भारत में इस्तात के उत्पादन के विकास पर विशेष महत्व दिया है। उद्योगीकरण की वर्तमान बढ़ी हुई प्रगित को बनाये रराने के लिये थ्रीर भारत में यन्त्रों के निर्माण करने वाले उद्योग को स्थापना करने के लिये यह श्रावश्यक होगा कि इस्तात के उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाय। दितीय योजना में १६६०६१ तक ४३ लाख टन इस्पात के उत्पादन का प्रवन्व किया गया है। इसमें से वर्तमान तीन प्रमुख उत्पादक श्रपने विस्तार के कार्य कम को पूर्ण कर लेने के पश्चात् लगभग २३ लाख टन की पूर्ति कर सकेंगे। सरकारी चेत्र में तीन नये स्थापित प्रमुख उत्पादक लगभग २० लाख टन का उत्पादन १६६०-६१ तक कर सकेंगे यद्यपि उनके उत्पादन की चरम सीमा कहीं श्रविक होगी।

लोहे श्रीर इस्पात के उत्पादन को प्रधानता देने के निर्णय के श्रनुकृत द्वितीय पचवर्षीय योजना में सरकारी चेत्र के अन्तर्गत तीन इस्पात के कारखानी की त्थापना का निश्चय है जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख टन होगी, श्रीर इन तीन में से एक को ३-५ लाख टन फाउन्डियो के प्रयोग में श्राने वाला ढला हुश्रा लोहा तेयार करने की सुविधार्य पास होंगी। रूरकेला में खोले गये कारखाने में १९५६-६१ में १२८ करोड़ रुपये के विनियोग का श्रनु-मान है। यह त्राशा की जाती है कि ७.२ लाख टन इस्पात की चपटे स्त्राकार की वस्तुत्रों का उत्पादन करेगा। दूसरा कारखाना, जो कि मध्य-प्रदेश में भिलाई स्थान पर स्थापित किया गया है, उस पर लगभग ११० करोड़ रुपया व्यय किये नाने का अनुमान है। उससे हम आशा करते हैं कि ७'७ लाख टन विकय योग्य इस्रात तथा वजनी श्रीर मध्य श्रेणी की वस्तुत्रों का उत्पादन हो चकेगा जिसमें १.४ लाख टन पत्रक का भी रि-रोलिङ्ग उद्योग के लिये उत्पादन सम्मिलित होगा। तीसरा कारसाना दुर्गपूर में, जो कि पश्चिमी बगाल में स्थिति है, खोला गया है जिसमें लगभग ११५ करोड़ रुपये के व्यय होने की आशा है। यह कारखाना ऐसे प्रसाधनों से युक्त होगा कि वह इल्की श्रीर मध्य श्रेणी की इत्पात तथा पत्रक की वस्तुत्रों का निर्माण ६.९ लाख टन तक प्रतिवर्ध कर सकेगा।

सरकारी चेत्र के समान ही न्यक्तिगत चेत्र में भी हस्पात श्रीर लोहे का स्थान श्रोचोगिक योजना में एक बहुत वड़ी महत्ता रखता है। इस उचोग पर न्यक्तिगत चेत्र में लगभग ११५ करोड़ रुपये के विनियोग का विचार किया गया है। प्रथम योजना के श्रन्तर्गत न्यक्तिगत चेत्र में लोड़े श्रीर इस्पात उचोगों के विस्तार सम्बन्धी विनियोग तथा जो कुछ न्यय द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत िकया गया है उस सन का फल १६५६ के मध्य से मिलना प्रारम्भ होगा जबिक टाटा श्रायरन एएड स्टील कम्पनी तथा इचिउयन श्रायग्न एएड स्टील कम्पनी की समुक्त उत्पादन शिक्त वर्तमान १२५ लाग टन के स्थान पर २३ लाख टन के लगभग हो जायगी।

दितीय पचवपीय योजना ने इस्पात श्राँर लोधे के उत्पादन के बढ़ाने पर टिचत ही ध्यान दिया है। इस्पात श्रधिक मात्रा में श्रीदोगीकरण का श्राधार है श्रीर इस्पात के उत्पादन की वृद्धि श्रीयोगिक उन्नति के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है। लोदे का उत्पादन बढ़ाने में सरकारी चेत्र पर बहुत श्रधिक विश्वाय है। २८ मई, १९५५ को वेन्द्रीय सरकार ने लोटे श्रीर इस्पात के लिये एक मवालय की नियुक्ति की जिस पर लोहे श्रीर इस्पात के उत्पादन सम्बन्धी सरकारी कार्यों का तथा सरकारी फाउन्ड्रीयों की देखभाल का भार राया गया। हुछ लोगों के मत में यह श्रधिक श्रन्छा होता यदि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने का मार मुख्य रूप चे वर्तमान उत्पादकों के ऊपर ही छोड़ दिया गया होता ययोकि उन्हें इस बात का श्रायश्यक श्रनुभव था श्रीर सम्भवतः वे श्रविक श्रीवता से श्रीर कम लागत पर उत्पादन की वृद्धि करने में सफल भी हुये होते।

सीमेन्ट उद्योग

सीमेन्ट के उत्पादन में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। १६४८ में केवल १५ लाख टन का उत्पादन था जो १६५७ में बढ़ कर ५६ लाख टन हो गया। १६५२ में भारत में केवल २३ फेन्ट्रियाँ थीं, जिनकी उत्पादन शक्ति ३७ ६ लाख टन थी। १६५७ में २६ फेन्ट्रियों थीं जिनकी स्पापित सामध्यें ६६३ लाख टन थीं। भारतीय सीमेन्ट उद्योग की वास्तविक उत्पादन शक्ति में नह फेन्ट्रियों की स्थापना तथा एवं की फेन्ट्रियों के विस्तार के कारण वृद्धि हुई है। सीमेन्ट उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा है, (१) मृतकाल में उत्पादन की मात्रा उनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति से बहुत कम थी और १६५० में जब कि वास्तविक उत्पादन शक्ति ३१ २ लाख टन थी उस समय उत्पादन केवल २६ १ लाख टन था। परन्तु इधर हाल में इस दोष का किसी सीमा तक निराकरण कर दिया गया है, (२) बहुत फिन्ट्रियॉ अनुकृलतम उत्पादन शक्ति से बहुत नीचे स्तर पर हैं, नवीन फैन्ट्रियॉ उपयुक्त आकार की हैं और अध्ठतम यन्त्रों का प्रयोग कर रही हैं। (३) सीमेन्ट उद्योग को आवश्यक सख्या में मालगाड़ी के डिक्वे नहीं प्राप्त होते जिनसे कच्चा माल लाया जा सके और तेयार सीमेन्ट उपभोग केन्द्रों को शीवता पूर्वक भेजा जा सके, और (४) सीमेन्ट का नियिष्ठत मूल्य सव फैन्ट्रियों के शीवता पूर्वक भेजा जा सके, और (४) सीमेन्ट का नियिष्ठत मूल्य सव फैन्ट्रियों के

हिण्डिकोण से न्यायोचित नहीं रहा है, न्योंकि अन्य फैक्टिनों में तन्तनायें जो अधिक व्यवस्थित थीं कुछ फैक्टिनों का उत्पादन व्यय अधिक रहा है।

टघर हाल में स्थित में घोर परिवर्तन हुआ है। मीमेन्ट दुर्लभ ही नहीं वरन् वहुत महगा भी हो। गया है। इस बात को विचाराधीन करते हुये सरकार ने सीमेन्ट का क्रय विकय अपने हाथों में ले लिया है और उसके लिये एक विकय मूल्प १ जुलाई १९५६ से लागू कर दिया है। सब सीमेन्ट के उत्पादकों को अप अपना सीमेन्ट स्टेट ट्रेडिझ कारपीरेशन आफ इन्डिया (प्राइवेट लि०) के दाथ फेक्ट्री के बाहर उपभोग केन्द्रों तक पहुँचाने में लगे रेलवें के किराये के आधार पर नियत मूल्य पर वेचना होगा। यह कारपीरेशन सीमेन्ट १०२ ६० द आने प्रति टन के मूल्य पर वेचता है। मई १९५७ में सीमेन्ट पर लगा उत्पादन कर ५ ६० प्रति टन के बढ़ाकर २० ६० प्रति टन कर दिया गया। सीमेन्ट का मूल्य भी इतना ही बढ़ गया।

देश के विभाजन के फलस्वरूप कुछ सीमेन्ट की फैरिट्रयॉ पाकिस्तान में चली गर्छ। यही कारण था कि १६४७ में उत्पादन घट कर १५ लाख दन हो गया जब कि १६४५ में २२ लाख टन था। परन्तु देश ने बहुत शीघ ही विभाजन के प्रभावों से मुक्ति पा ली श्रीर उत्पादन में वृदि श्रारम्भ हो गई जो श्राज तक निरन्तर चल रही है। युदोत्तर काल में सीमेन्ट उद्योग की विकास सम्बन्धी उल्लेखनीय विशेषताएँ यह हैं, (१) १६३६ में धीमेन्ट उन्होंग प्राय मध्य प्रदेश श्रीर मध्य मारत में ही केन्द्रित था। परन्तु एसोशियेटेड सीमेन्ट रम्पनी द्वारा युक्तिकरण् की योजना के लागू किये जाने के कलस्वरूप कुछ फेक्ट्रिय को नये स्याना पर म्यापित किया गया। युद्दोत्तर काल मे इस उद्योग का विकास स्रधिक **चन्तु**लित ढग पर हुत्रा और नवीन स्थानो पर कारसाने स्थापित हुये। इसका परिणाम यह हुआ कि सीमेन्ट के कारसाने सम्पूर्ण देश में फेले हैं। इससे देश के विभिन्न भागों में प्राप्त होने वाले कब्चे माल का भी उचित प्रयोग सम्भव हो गया है। साथ ही यातायात में बहुत सा व्यर्थ व्यय जो उत्रोग के किसी एक स्थान पर केन्द्रित होने के कारण करना पड़ता वह भी बच गया। (२) भृत काल में सिमेन्ट उद्योग व्यक्तिगत उपक्रम था, परन्तु अब सरकार ने भी इस उपक्रम में भाग लेना ग्रारम्म कर दिया। मैसूर राज्य की फैन्ट्री के ग्रतिरिक्त, जिसकी उत्पादन शक्ति ३६ इजार टन से बढ़ा कर ६० इजार टन कर दी जायगी, उत्तर प्रदेश की राजकीन फेन्ट्रो पिपरी में स्थापित की है जिसकी उत्पादन शक्ति रई लाख की है। (३) भूतकाल मे अधिकाँश कारसाने ८००० टन ही के श्रनाधिक से भी कम उत्पादन वाले थे। परन्तु हाल में जो कारराने स्थापित किये गये हैं वे आर्थिक

दृष्टि से उपयुक्त हैं श्रीर प्राय सभी कम मात्रा में उत्पादन करने वाले कारखानों ने अपनी उत्पादन शांक्त में वृद्धि की है।

सीमेन्ट की श्रान्ति साँग उसकी पूर्ति से श्रिषक होगई। देश में उत्पादन की वृद्धि के श्रालावा १६५६ के प्रारम में यह निश्चय किया गया कि उस वर्ष विदेशों से ७ लाख टन सीमेन्ट का श्रायात किया जाय। राज्य-क्यापार निगम (State Trading Corporation) ने इस मात्रा के श्रायात के लिये टढ व्यवस्था कर रखी थी किन्तु बीच में स्वेज का सकट उपस्थित हो जाने पर १६५६ में केवल १०८,००० टन सीमेन्ट हो श्रा सका। १६५७ में ३२१,००० टन सीमेन्ट श्रीर श्राया। १६५८ में श्रायात और कम होगा। इसका कारण विदेशी विनियम का सकट तथा देश में उत्पादन का तीवता से बढ़ना है।

योजना के अन्तर्गत-प्रथम योजना में यह प्रस्ताव किया गया था कि सिमेट के कारखानों की सख्या १६४०-५१ में २१ से बढ़ाकर १६५५-५६ में २७ कर दी जाय। साथ ही इनकी ३३ लाख टन की उत्पादन शक्ति तथा २७ लाख टन उत्पाटन बढाकर १९५५ ५६ में क्रमश ५३ लाख टन श्रौर ४८ लाख टन कर दिया जाय। मध्य प्रदेश, मध्यभारत ग्रौर ट्रावनकोर कोचीन में सिमेंट के कारखानों को अनुगरियत शक्ति में वृद्धि का कोई नियोजन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा श्रीर बम्बई में नवीन कारखाने खोले जाने वाले थे। बिहार, राज-रथान ब्रोर मद्राप्त के कारखानों की शक्ति में वृद्धि करना श्रस्यन्त श्रावश्यक था जो पूर्व के कारखानों में श्रातिरिक्त नवीन मशीनों के प्रयोग से ही सम्भव था। इस कार्य के करने में प्रधान कठिनाई घन के अभाव की थी। कारखानों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने श्रोर उन्हें १३ लाख दन प्रति वर्ष उत्पादन करने योग्य बनाने के लिए बहुत श्रिधिक मात्रा में धन की श्रावश्यकता है। उत्तर प्रदेश की सिमेंट फोर्झी की स्थापना में, जो कि मिर्जापुर जिले में चुर्क में है, ४३ करोड रुपये की लागत लगी थी। उसकी उत्पादन शक्ति २५२ लाख टन प्रतिवर्ष की है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की फैन्ट्री का कुल ब्यय सरकारी कर्मचारियों की श्रनुमवहीनता के कारमा बहुत श्रधिक हो गया है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की वह सर्वोचम फैक्ट्रियों में से एक है।

मथम योजना में श्रमुगियत उत्पादन शक्ति तथा वास्तविक उत्पादन के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाये थे, परन्तु काफी हृद तक सफलता श्रवश्य मिली थी। १९५५-५६ में टीमेंट की उत्पादन शक्ति श्रीर उत्पादन कमशा ४७४ लाख टन श्रीर ४४ लाख टन थी जबकि प्रथम योजना में क्रमशा: ५३ लाख टन श्रीर ४८ लाख टम का लक्ष्य था। देश के श्रीयोगीकरया में उन्नति हो जाने पर सीमेंट

की मौग मे वृद्धि होगी। इसलिये द्वितीय योजना ने १६६०-६१ तक उत्पादन शिक्त को १६० लाख टन तक (जिसमें से भ्र लाख टन सरकारी जेत्र में बढेगा) त्रोर वास्तिविक उत्पादन को १३० लाख टन वढाने का लक्ष्य वनाया है। त्रव तक भारत सरकार द्वारा ५४ स्कीम जिनमे २५ नई हैं तथा २६ वर्तमान उत्पादन इकाइया के विस्तार से सम्बन्धित हैं, मज्द की गई है। यह स्कीम प्रगति के विभिन्न स्वरों पर हैं। इनमें से १५ स्कीम (४ नई तथा ११ विस्तार सम्बन्धी) जिनकी कुल उत्पादन शिक्त १९ श्रोर स्कीम पूरी हो जाँयगी तथा श्राशा की जाती है कि इस समय तक कुल उत्पादन शिक्त १०४ लाख टन हो जायगा। शेय स्कीम १६६० ६१ तक पूरी होगी।

कागज उद्योग

वर्तमान समय में भारत में कागज की १९ मिलें हैं जिनकी स्थापित उत्पादन शक्ति २५०,००० टन है। कागज उन्तोग को १६२५ में १६४७ तक सरक्षण दिया गया था। इस उत्योग ने नि:सन्देह उल्लेखनीय प्रगति की। १६५२ में भारत में केवल ६ मिलें थीं जिनकी उत्पादन-शक्ति २७ इज़ार टन थी। १९५६ में २१ मिलें यी तथा उनकी उत्पादन शक्ति २११,६०० टन थी। १६५७ में मिलों की सख्या घटकर १६ होगई क्योंकि उत्पादन की दो इकाइयाँ जो बन्द सी ही थी सची में से हटा दी गई। किन्त विस्तार की योजना श्रो के पूरी हो जाने के कारण उद्योग की स्वापित उत्पादन शक्ति बढ़ कर २३ लाख टन हो गई है। कागज उद्योग की तीन श्रेणियाँ हैं (१) कागज ख्रीर पटा, (२) श्रखनारी कागज की स्खी दफ्ती तथा श्रन्य प्रकार की दिस्तयों। कागज तथा पह के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूली दिक्तयों तथा श्रन्य प्रकार की दिक्तयों के उत्पादन मे विशेष प्रगति हुई है। परन्तु देश में श्रखनारी कागज का बहुत श्रभाव है। भविष्य में कागज उद्योग का विकास करते समय श्राखनारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने की सस्मया पर विशेष ध्यान देना पडेगा । युद्ध के उत्तर काल में (श्र) यह उद्योग नवीन स्थानों पर भी श्रारम्म हो गया है श्रीर श्रधिकाँश प्रदेशों में श्राज कागज बनाने वाली मिल हैं, (ब) श्रव श्रनेक प्रकार के कागज तथा दिक्तयों का उत्पादन होने लगा है यहाँ तक की इप्ले श्रीर ट्रिप्ले टिम्तयों तथा क्राफ्ट लपेटने के कागज के उत्पादन में तो विशेष प्रगति हुई है।

कागज उद्योग की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उत्पादन शक्ति की बहुत श्रिधिक प्रतिशत मात्रा का उत्पादन हुआ है। १६४८, १६४६ श्रीर १६५० में कमश: ६७,००० टन, १०३,२०० टन श्रीर १०८,६१२ टन का उत्पादन हुआ था जो कि उत्पादन शक्ति का लगभग दृह%, ६४% श्रीर दृश होता है। १६५७ मे २१०,१२५ टन का उत्पादन हुआ जो कि उत्पादन शक्ति का दृश था। यह सब होते हुये भी कागज उद्योग को अभिकों के मगढ़े तथा पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के न्यायोचित मूल्य पर न मिल सकने की किटनाइयों का सामना करना पढ़ा है और निम्न स्तर के कोयले का जिसके लिये इन्जनों के बायलर अनुपयुक्त हैं, प्रयोग करना पढ़ता है। बाँस और घास के मैदानों के न्यायोचित मूल्य पर दीर्घमालीन पट्टों पर न उटाये जाने के कारण हानि उटानी पढ़ी है। इसके अतिरिक्त जब से रेल विमाग ने अपनी अधिमान्य पढ़ित (Preferential System) को माल के यातायात सुविधा के सम्बन्ध में परिवर्तित कर दिया है कागज उद्योग को जो प्रधानता मिलनी थी उसका अन्त हो गया है और अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ उसे भी यातायात सुविधा पाने में प्रतीहा करनी पढ़ती है। इन किटनाइयों के कारण ही कागज उद्योग की उत्पादन लागत तथा उत्पादन मात्रा कम हो गई है।

कचा माल-कागज श्रीर पट्टा श्रयवा टक्ती उन्रोग श्रपने कच्चे माल के लिये बाँग छोर सबई घाम का उपयोग करता है। इसके श्रतिरिक्त कुछ, कार-खाने चियहे, रही कागज, चोनी की सीठी इत्यादि का उपयोग करते हैं। भारत में ऐसे कच्चे माल का कुछ ग्रभाव नहीं, परन्तु उद्योग के उपयोग के लिये इनकी पूर्ति का सगठन करने की आवश्यकता है। कागज उद्योग में अनेक रसायनों जैसे चूना, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, न्लोरीन, गधक आदि का भी उपयोग किया जाता है। गधक को छोड़ कर श्रन्य सब रसायनिक भारत मे ही मिल जाते हैं। ऊछ चीमा तक कास्टिक चोहा और चोडा ऐश का विदेशों से श्रायात करना पहता है। मन्य प्रदेश के कागज के कारखाने सवाई की लकडी का प्रयोग करते हैं। परन्तु इसके साय ही चीड़, देवदार, श्रीर एक प्रकार के सरो के वृज्ञ की कोमल लकडी का भी उपयोग किया जा सकता है जिसकी भारत में बहुतायत है। यदि मुलायम लक्ड़ी के बनों का विकास किया जान, लकड़ी को कारखानों तक पहुँचाने के लिये यातायात की उचित व्यवस्था की जाय श्रीर एक कारखाना त्रखबारी कागज श्रौर केमिकल पल्प बनाने के लिये स्थापित किया जाय तो श्रखवारी कागज उद्योग के लिये ग्रावश्यक कच्चे माल की पूर्ति को बढ़ा सकता सम्भव है। कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में योजना आयोग ने निम्नलिखित सुक्ताव दिये थे, (१) कागज उद्योग के काम ग्राने वाले पेडों के वनों की सुरह्या की जाय ग्रीर इनका उपयोग कर सकने के लिये उद्योग को दीर्घकालीन पट्टे के अधिकार दिये जॉय (२) वॉस श्रीर सबई वास के सारे देश में एक तर्क सगत श्राधार पर मूल्य

निर्धारित किये जाँय जिससे उत्रांग को फच्चा माल निरतर प्राप्त हो सके। राज्य सरकारों के हितों की रक्षा करने के लिये कच्चा माल एक निश्चित मूल्य पर उनोगों को दिया जाय श्रीर इसके साथ ही उनके तैयार माल की विकय मूल्य से सम्बन्दित प्रन्यानि (premium) की कोई मात्रा लाभाश में से उनसे वसूली नाय, (३) यातायात की सुविधा के लिये जगलों में सहकों बनाई जीय, त्रोर (४) कपटों की कतरन, पटसन भ्रोर जूट तथा रही कागज का निर्यात विल्कुल बन्ट

यह खेट की बात है कि बन विकास के सबन्ध में राप्य सरकारों की कोई सुसाद नीति नहीं है श्रोर कागज की मिलों को जगल पट्टें पर देने में बहुत श्रधिक कर दिया जाय। मूल्य वस्त करती हैं। रेल परिवहन के भाडे की दर भी श्रधिक है। मारत सर-कार पुराने श्रखवारों की रही के त्र्रायात पर मारी श्रायात कर वस्त करती है श्रीर ग्रपनी रही का स्टाफ िना किसी बात का व्यान किये ठेकेदारों को वेच देती है, जो उसे पैकिंग इत्यादि के लिए बाजार में वेच देते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की नीति में परिवर्तन करने से उद्योगी को कचा माल पर्याप्त मात्रा

योजना के अन्तर्गत - विभिन्न कागज की मिलों के प्रधार कार्यक्रम को में दिया जा सकता है। लागू फरने से यह आशा की जाती है कि प्रथम योजना काल में उद्योग की उत्या-टन शक्ति २११,००० टन कागज श्रीर दिक्तयाँ श्रीर ३०,००० टन श्रखनारी कागज की हो जायगी श्रीर १९५५-५६ तक २००,०००टन कागज श्रीर दिक्तयाँ श्रोर २७,००० टन श्रखवारी कागज का वास्तविक रूप से उत्पादन हो जायगा। भूसे इत्यादि से वनने वाली दिपतयों के उत्पादन सवन्ध में अनुमानत: १९५५-५६ क उद्योग को वार्षिक उपादन शक्ति ५८,५०० टन हो जायगी श्रीर वारतिवक

काराज श्रीर काराज की दिम्तियों के उद्योग के सबन्ध में प्रथम योजना के उत्पादन ५२,००० टन होगा। लक्ष्य लगभग पूरे हो गये । श्रखनारी कागज का उत्पादन करने वाली सर्वप्रथम मिल ने १९५५ में कार्य भ्रारम किया। यद्यपि इसका उत्पादन श्रमी बहुत कम है पर श्राशा की नाती है कि नय यह मिल शक्ति भर उत्पादन करेगी तब ३०,००० टन ग्रखनारी कागज का उत्पादन सभव हो सकता। द्वितीय योजना मे यह प्रस्ताव किया गया है कि १९६०-६१ तक स्थापित उत्पादन शक्ति तथा कागज श्रोर कागज की दिप्तियों का वास्तविक उत्पादन बढ़ा कर कमश ४५ लाख टन और ३५ लाख टन कर दिया जाय श्रीर श्रखनारी कागज के स्थापित उत्पादन शक्ति तथा वास्तविक उत्पादन बढाकर ६०,००० टन तक कर दिया जाय। द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्य को पूर्ण कर सकने के लिये यह आवश्यक होगा कि (१) कागज उद्योग के कार्य को सरलता से चलाने के लिये देश का आर्थिक वातावरण अनुकूल बनाया जाय, (२) कच्चे माल तथा तैयार माल के यातायात के लिये मालगाडी के डिट्नों की पूर्त बढाई जाय, और (३) कच्चे माल की पूर्त बढाई जाय। मारत में चीनी उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में होने के कारण गन्ने की सीठी का कागज बनाने के लिए प्रयोग बढे लाम के साथ किया जा सकता है। १६५५ के अन्त में जर्मनी के विशेषजों का एक दल मारत में इस विषय का परीच्या करने तथा रिपोर्ट देने के लिये आया था। पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म से सीठी पर आधारित १०० टन प्रतिदिन का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाई की स्थापना पर बातचीत चल रही है।

श्रन्य उद्योगों की भाँति कागज उद्योग के उत्पादन के प्रकार तथा उत्पादन व्यय कम करने के लिये उपाय करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। योजना श्रायोग ने यह श्रिमस्ताव किया है कि कागज उद्योग को श्रपने उत्पादन की प्रविधि को श्राधुनिक बनाना चाहिये जिससे वह निम्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, (१) ईघन तथा कच्चे माल के प्रयोग में कभी करके कागज की उत्पादन लागत में कभी, श्रीर (२) विभिन्न प्रकार के कागजों, विशेषकर रैपिंग श्रीर काफ्ट कागज, की प्रकार में उन्नति। यदि यह सुधार सम्भव हो सके तो कागज उद्योग में स्थायित्व श्रा जायगा।

छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कटीर उद्योग

मारत की श्रीयोगिक न्यतस्था में छोटे पेमाने पर उत्पादन करने वाले ग्रीर कुटीर उद्योगों का स्थान सदा से ही महत्वपूर्ण रहा है। शिल्पकारों की एक बहुत बड़ी संख्या सदैव इन उद्योगों पर ही अपनी जीविका के लिये निर्भर रही है। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने छोटी मात्रा में उत्पाटन करने वाले तथा कुटीर उन्त्रोगों को भारत में वेकारी की कठिन समस्या को इल करने के साधन के रूप में रत कर इनकी श्रोर श्रधिक घ्यान श्राकित किया है। इसके पूर्व कि द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत इन उत्रोगों के विकास कार्यक्रम पर विचार करें यह भ्रावश्यक होगा कि इन उद्योगों की कठिनाइयों का परी इण किया जाय।

उद्योगों को प्राय: तीन वर्गों में विमाजित किया जाता है, (१) वडे पैमाने पर उत्पादन करने वाले ग्रथवा बडे उत्रोग, (२) छोटे पेमाने पर उत्पादन करने वाले श्रयवा छोटे उद्योग, (३) कुटीर उत्योग। इन उद्योगो को विभिन्न प्रकार से परिमापित किया गया है। एक मत के अनुसार कुटोर उन्होंग वे उद्योग हैं जो शिल्पियों द्वारा स्वय ग्रापने ग्राप ही प्रयान किसी कारखानेदार के निर्देशन में घर पर ही किये जाते हैं। यदि कार्य छोटे कारखाने में किया जाता है छौर उसका निर्देशन उत्योगपति द्वारा किया जाता है तो उसे इक छोटा उत्योग कह सकते हैं नाहे शक्ति सन्वालित मशीनों का प्रयोग न मी किया जाय। एक ग्रन्य मत के श्रनुसार घरेलू उद्योग वह है "जो श्रमतः मुमवा पूर्णतः परिवार के ही सदस्यों की। सहायता से चलाया जाता है चाहे वे सम्पूर्ण दिन कार्य करें या थोड़ी देर ही। नित्य कार्य करें"। श्री चिन्तामणि देशमुख के मतानुसार "घरेलू घ्टोग्" प्रायः हम उन सन उत्पादन के उपक्रमों को कहते हैं जो बड़े-बड़े व्यवस्थित कारखानो के श्रितिरिक्त हैं। जो व्यक्ति इन उपकर्मों में लगे हुये हैं मुख्यतः श्रपने ही प्रयत्न ग्रीर कीशल पर निर्मर रहते हैं, सीच-सादे ग्रीजारों का प्रयोग करते हैं ज्रीर श्राने घर पर ही कार्य करते हैं। विशिष्ट श्रावश्यमतात्रों के कारण इस प्रकार के ऋछ उद्योग हाल में ग्रारम्भ हुये हैं। ये उद्योग प्रधानत परम्परागत हैं स्रोर वर्तमान उत्पादन प्रविधि से स्पर्धा करते हुये अपनी रहा में प्रयक्षशील है। छोटे पेमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग "धरेलू तथा प्राम्य उद्योगों से इस ग्रथ में भिन्न हैं कि उनको सचालित करने वाले उद्योगगित होने हैं जो पारिश्रमिक पर रमसे हुये अमिकों से कार्य लेते हैं।"

उपर्वक्त परिभाषात्रों को विचाराधीन रखते हुये इम यह कह सकते हैं कि वरेलू उन्नोग की निन्न विशेषतार्थे हैं, (१) ऐसे उन्नोगों को घर पर ही बिना श्रीमकों की सहायता के स्वय चलाया जाता है, (२) इनमें परम्परागत टंग का ही श्रनुसरण किया जाता है, श्रौर (३) इनका स्वतंत्र तथा पूर्ण समय का कार्य होना त्रावश्यक नहीं हैं, ये कृषि तथा किसी ग्रन्य व्यवसाय के सहायक हो सकते हैं। ह्योटे उत्योग ग्रथवा थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की मुख्य विशेषता यह है कि ये कार्य करने वालों के घर में नहीं चलाये जा सकते श्रौर कार्यक्त्तां के श्रावरपक स्रोत नितानत सीमित होते हैं। योड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों के कार्य करने वाले अमिकों की सख्या १० से ५० तक सीमित है। हमारे देश में उपर्युक्त दोनों वर्गों में ख्रानेवाले ख्रनेक उद्योग हैं जैसे कर्घा, कन, रेशम, गुड, राब, तेल पेरने, ताले बनाने के कार्य इत्यादि। इन उद्योगों में काम में सहायता देने वाले परिवार के सदस्यों श्रीर समय पर इनमें कार्य करने वाले उन व्यक्तियों की चल्या को छोड़कर जो कृषि आदि अन्य मुख्य व्यवसाय में सलग्न है, लगभग २० लाख व्यक्ति कार्य करते हैं। इन दोनों प्रकार के उद्योगों का प्रामों श्रीर नगरों टोनों में ही पूर्ण श्रयवा श्राशिक समय के लिये श्रनुसरण किया जाता है। हैएडी क्रैफ्ट का उत्रोग जैसे वेल-त्रूटे काढने का कार्य, पीतल का कार्य, रेशम बनाने का कार्य इत्यादि पूर्ण समय के कार्य है श्रीर इन कार्यों में सलग्र व्यक्तियों ने उत्क्रध्य ज्ञमता भी प्राप्त कर ली है।

लाभ मि (१) घरेल् उद्योग श्रोर छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्योगों का सबसे बड़ा लाम तो यह है कि वे बहुत बड़ी सख्या में कार्य का श्रवसर प्रदान करते हैं। कितने व्यक्ति कुटीर श्रीर छोटे पैमाने के उद्योगों में कार्य करते हें श्रीर वे कितना कितना उत्पादन करते हैं इस सम्बन्ध में ठीक ठीक श्रॉकडे प्राप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय श्राय समिति ने यह श्रनुमान लगाया था कि १६५०-५१ में छोटे उत्योगों का उत्पादन ६१० करोड़ रुपये का हुश्रा या श्रीर लगभग ११५ लाख व्यक्ति उनमें कार्य करते ये जबिक फैक्ट्रयों में लगभग ३० लाख व्यक्ति कार्य करते ये श्रीर उनके कुल उत्पादन का मूल्य लगभग ५५० करोड रुपया था। इन छोटे उद्योगों में बुटीर उत्योग भी समितित थे पर वे छोटे छोटे कारखाने जो फैक्ट्रा एउट के श्रवर्गन श्राते थे। इनमें समितित नहीं किये गये थे। समिति ने उन्हें फेक्ट्रियों में समितित किया था। यदि इम इन छोटे छोटे कारखानों को भी घरेलू श्रीर छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्येगों में समितित कर लें श्रीर हाल में जितने लोग इनमें कार्य कर रहे हैं उनकी बढी हुई सख्या को भी वचाराधीन रख लें तो कुल कार्य करने वालों की सख्या लगभग २०० लाख श्रीर

कुल वार्षिक उत्पादन का मृल्य लगभग १२०० करोड़ रुपये के हो जायेगा। पर यह सब गणना अनुमान मात्र है इसलिये विश्वस्त नहीं कही जा सकती। इन श्रॉकड़ों से घरेलू श्रीर छोटे उद्योगों के विस्तार श्रीर मावी सम्मावना का ही कुछ त्रातुमान ही मिल सकता है।

- (२) कुटीर उद्योग की यह विशेषता है कि इसमें मूल्यवान् मशीने नहीं लगाई जाती हैं. इसके लिये किसी बड़ी इमारत इत्यादि की आवश्यकता नई। होती है इसिल्ये इसको चलाने में अधिक पॅजी नहीं लगानी पड़ती। भारत में पॅजी का अमाय है और इमें कुछ ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है जिनमें पॅजी कम लगे और श्रमिक श्रधिक।
- (३) इसके विपरीत वडे पैमाने के उद्योग में वैज्ञानिक श्रीर टेकनिकल शान की विशेष श्रावश्यकता होती है। परन्तु वर्तमान समय में (टेकनिश्चियन) प्राविधिजों का भारत में श्रमाव है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में यही लाभ है कि इनमें श्रविक पाविधिक (टेकनिकल) ज्ञान श्रीर पाविधिजो की श्रावश्यकता नहीं होती है।
- (४) छोटे पैमाने के श्रीर कुटार उद्योग बढे पैमाने के उद्योगों की तरह किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित नहीं है बलिक सम्पूर्ण देश में विस्तृत हैं। इनमें इमारत, सफाई, स्वास्थ्य इत्यादि की समस्या नहीं होती है, जिनका बढे पैमाने के उद्योगों को सामना करना पहला है। इसके साथ ही युद्ध के समय इनके विनाश का मय भी कम रहता है। बढ़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों का तुल-नात्मक ग्रध्ययन करते समय श्रीर इनके लाम-हानियों का विवेचन करते समय हमें उक्त सामाजिक व्यय का मी विचार करना चाहिये।
- (५) बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा छोटे पेमाने और कुटीर उन्योगों में रोजगार में श्रस्थिरता बहुत कम होती है। इमारे देश के ग्रामीण व्यक्तियों का मुख्य उद्यम कृषि करना है ख्रौर वे सहायक व्यवसाय के रूप में रस्सी बनाने, गुड़ बनाने, कपड़ा बुनने इत्यादि कार्यों को करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन सहायक उद्योगों में मंदी ह्या जाय तो श्रमिक ह्यथवा कारीगर को उतनी ह्यधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पढेगा जितना किसी श्रीद्योगिक श्रमिक को मदी के कारस नोकरी छट जाने पर करना पहता है।

कुटीर ब्रीर छोटे पैमाने के उद्योगों से बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेस्ना कुछ अधिक लाभ होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगी को कोन सा स्थान देना चाहिए। वित्त श्रायोग (१६४६-५०) के श्रनुसार इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित बातों पर विचार करना श्रावश्यक है:

- (१) उद्योग के प्रकार,
- (२) उद्योग में टेकनिकल व्यवस्था,
- (३) उद्योग के संगठन के लिए आवश्यक अम और पूँजी,
- (४) त्रायिक दृष्टि से उत्पादन का किस सीमा तक उचित इकाइयों में विकेन्द्री करण किया जा सकता है केवल व्यक्तिगत व्यय को ही नहीं वरन् सामाजिक व्यय को भी विचाराधीन रखते हुए।

जहाँ तक उद्योग के प्रकार का प्रश्न है उसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, (१) ऐसे उद्योग जिनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से कुछ निश्चित लाम है श्रोर जिनको छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है, जैसे लोहा श्रोर इस्पात उद्योग, सीमेंट, मारो रसायनिक श्रीर खदान उद्योग इत्यादि। इन उद्योगों को कुटीर में श्रयवा छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है इस्रिलए इस चेत्र में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता है, (२) ऐसे उद्योग जिनका छोटे पैमाने पर उत्पादन करके कुछ निश्चित लाभ उठाया जा सकता है, जैसे ताला मोमवत्ती, बटन, चप्पल, खाद्यान इत्यादि उद्योग। इनमें से कुछ में छोटे पैमाने पर उत्पादन करने में उत्पादन व्यय कम होता है। खाद्यान के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जब वस्तुएँ हाथ से तैयार की जाती हैं तो उनमें पौष्टिक तत्व श्रिक रहते हें, (३) ऐसे उद्योग जिन्हें बड़े श्रीर छोटे पैमानों पर चलाया जा सकता है। इन उद्योगों के सम्बन्ध में चुनाव का प्रश्न उठता है।

टेकिनिकल व्यवस्था के आधार पर उद्योग को निम्नलिखित मागों में विमाजित किया जा सकता है—(१) ऐसे उद्योग जिनमें बढ़े पैमाने के उद्योगों और कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगों में कोई प्रतियोगिता नहीं हैं, जैसे मधु मक्खी पालन, गुड़ बनाना तथा अन्य दस्तकारी के कार्य इत्यादि। (२) ऐसे उद्योग जिनमें छोटी मात्रा के और कुटीर उद्योग बढ़े पैमाने के उद्योगों के सहायक हैं, इनमें उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी बढ़े पैमाने के उद्योगों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यकता होती है। बढ़े पैमाने के उद्योगों को उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया में कुछ अशों का उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया में कुछ अशों का उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया में कुछ अशों का उत्पादन छोटे उद्योगों में किया जाता है, और (३) ऐसे उद्योग जिनमें बढ़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रतियोगिता होती है, जैसे, कमों में बुना कपड़ा, खायहसारी चीनी, चमड़े का सामान इत्यादि। प्रथम वर्ग के अतर्गत आने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है परन्तु दूसरे वर्ग के अन्तर्गत छोटे तथा वढ़े पैमाने के उद्यागों में परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करके इनकी किसी भी

समस्या को सुगमता पूर्वक सुलमाया जा सकता है। तीसरे वर्ग के उद्योगों के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

कठिनाइयाँ

कच्चे माल, उत्पादन की प्रविधि, वित्त, विकय, कर इत्यादि के सम्बन्ध में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों को नहीं कठिनाइयों का सामना करना पहता है। इन उद्योगों को प्रायः उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिनका नहें उद्योगों में उत्पादन किया जाता है। कथीं उद्योग पूर्णतया सतीं मिल द्वारा उत्पादित स्त पर निर्मर करता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय स्त मिलने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि जितने स्त का उत्पादन किया जाता था उसका अधिकाँश मिलों की ही आवश्यकता पूर्ति में लग जाता था। उस समय अधिकतर मिलों में कताई और बुनाई साथ-साथ होती थी। केवल कताई करने वाली मिलों को सख्या बहुत कम है। कर्घा उद्योग को अधिक स्त उपलब्ध कराने के लिए स्त की कताई करने वाली कुछ और मिलों की स्थापना की गई हैं और इनमें उत्पादित सत का कुछ प्रतिशत कर्घा उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दलालों के कारण कुटीर उद्योग को आवश्यक कच्चे माल का अधिक मृत्य चुकाना पहता है। इस कठिनाई को सहकारी समितियों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है। इस कठिनाई को सहकारी समितियों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है।

प्रविधि और प्रामाली—इन उद्योगों में बिस ढग से श्रीर जिन साधनों से उत्पादन किया जाता है वह प्राचीन हो चुके हैं श्रीर वर्तमान में उनकी उपयोगिता बहुत घट गई है। खोज कार्य करने श्रीर कारीगरों के शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था न होने से उत्पादन के प्रकार में बहुत श्रात हुई हैं। श्रीमकों को उचित शिक्षा देने श्रीर उत्पादन के प्रकार में सुधार करने के लिए बहुत योड़ी ऐसी सस्याएँ हैं जो श्राच्छा कार्य कर रही हैं, जैसे श्रीखल मारतीय प्राम उद्योग संघ, श्रीखल मारतीय कताई संघ, खादी प्रतिष्ठान श्रीर हाल ही में स्थापित खादी श्रीर श्राम उद्योग विकास बोर्ड।

श्रन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने, जिसको कोर्ड काउन्हेशन ने नियुक्त किया या, जिसने छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा छुटीर उद्योगों का श्रध्ययन करने के लिये तथा उनके पुनरत्थान के सुमाव देने के लिये भारत का टीरा किया, १९५४ में श्रपनी रिपोर्ट दी जिसमें उसने यह सिफारिश की कि चार शिल्प कला शान सम्बन्धी सस्थायें स्थापित की जानी चाहिये जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिये कि वे सम्पूर्ण मारत की सेवा कर सकें। भारत सरकार ने यह

विकारिश स्वीकार करली है। पर खोज का कार्य करेंगी श्रीर श्रपनी जोज के परिणामों को तथा नई उत्पादन विवियों, नये श्रीजारों, श्रीर नई प्रविधियों की स्वना उत्पादकों तक पहुंचायेंगी।

कार्य करने वालों को प्रोत्याइन देने की श्रावश्यकता है जो कि उचित शिक्षा प्रचार तथा प्रत्येक टस्तकारी के लिये स्थानीय परिषद के स्थापित करने से सम्भव हो सकता है।

वित्त व्यवस्था—छोटे उयोगों और उद्योगपितयों की उदी कि कि नाहयों में वित्त की किटनाई प्रमुख है। मशीन और आवश्यक श्रीजार क्रय करने के लिए उसे टीर्षकालीन पूँजों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कच्चा माल क्रय करने के लिए और पारिश्रमिक इत्यादि जुकाने के लिए अल्प्यालीन पूँजी की आवश्यकता होती है। छोटे उत्पादकों में अधिकतर निर्धन हैं और ऋण के लिए आवश्यक प्रतिभूति नहीं दे पाते। साथ ही ऐसे उपाटका की आवश्यकताएँ भी कम होती हैं, इन्हें अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए वडे उयोगों को विचीय सहायता देने वाले व्यवसायी बैक इनको अप्रण इत्यादि देने में कुछ लाम नहीं सममते। बहुत कम ऐसी सस्पाएँ हैं जिनसे इन उत्पादकों को विच की सहायता मिल सकती है। इन्हें अधिकतर नामीय साहुतारों और कारप्वानादारों पर निर्मर करना पड़ता है। कारपानेटार इस सर्त पर ऋण देते हैं कि उत्पादित माल उनको बेचा जायगा। उत्पादित माल का मूल्य ऋण देते समम निश्चत कर लिया जाता है। इससे उत्पादक को अपने माल का उचिठ मूल्य नहीं मिल पाता।

श्रन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने यह सिफारिश की कि (१) व्यापारिक वैंकी को प्रपनी शाखात्रों को श्रिधिक श्रृण देने की श्रनुमित देकर इन्हें दिये जाने वाले श्रृण की मात्रा बढ़ा देना चाहिये, (२) सहकारी वेंकों को इन उद्योगों की विच सहायता करने की श्रोर श्रीर श्रिषक ध्यान देना चाहिये, (३) प्रत्येक प्रदेश में एक राज्यीय विच निगम स्थापित किया जाना चाहिये जिसके कीय को इन छोटे उद्योगों की ही सहायता के लिये सुरिक्तत कर देना चाहिये, श्रीर (४) वास्तविक सम्पत्ति की प्रतिभृति पर श्रृण देने की प्रणाली प्रचलित की जानी चाहिये।

व्यक्तिगत चेत्र की वित्त सहायता के लिये शीफ कमेटी ने भी रिजर्व वैक को जून १९५४ में टी हुई श्रपनी रिपोर्ट में उन छोटे उद्योगों के विषय में विचार फिया है जिनकी सम्पत्ति १० हजार कार्ये श्रीर ५ लाख कपये के श्रन्दर है। कमेटी ने कृषि के सहायक उद्योगों को श्रपनी परीक्षण परिधि के श्रन्टर समितित नहीं

किया। चालू पूँजी के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सिकारिश की थी कि इन उद्योगों से सरकार द्वारा क्रय किए गये माल के मूल्य का मुगतान करने मे देर नहीं होनी चाहिये। इसके श्रांतिरिक्त कमेटी ने यह भी सिकारिश की कि व्यक्तिगत सस्याश्रों द्वारा लिखे हुये इकरारनामों की रजिस्ट्री की कीस भी कम कर देनी चाहिये ताकि उनको वैंकों से ऋगा लेने में श्रधिक सुविधा मिले । दीर्घ कालीन पॅजी की श्रावश्य-कताश्रों के लिये यह सिफारिश की कि प्रादेशिक सरकारों को इन उद्योगों को 'स्टेट एड ट इग्डस्ट्रीज एक्ट' के अन्तर्गत अधिकाधिक सहायता देनी चाहिये ! इसलिये इन उद्योगों को श्रिधिक ऋण देने की सुविधा प्रदान करने के लिये यह ग्रावश्यक होगा कि प्रादेशिक वजट में इस पर न्यय करने के लिये ग्रधिक धन का श्रनुटान किया जाय श्रीर भूगा देने की प्रणाली को श्रधिक सरल बनाया जाय। कमेटी ने यह समाव दिया है कि 'प्रादेशिक वित्त कारपोरेशन' को छोटे उद्योगों को ऋण देना चाहिये। इसके साथ ही उसने यह सिफारिश की कि छोटे उद्योगों की सहायतार्थ एक विशिष्ट विकास निगम की भी स्थापना होती चाहिये जिसकी प्रारम्भिक रोयर पँजी ५ करोड़ रुपया हो जो कि भारत के रिजर्व वॅंक, व्यवसायिक वेंकों, बीमा कम्पनियों, तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा प्राप्त होनी चाहिये।

वाजार—दितीय युद्ध के समय त्रोर युद्ध के पश्चात् कुछ वर्षों तक बहुत से उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के विकय की कोई समस्या नहीं यी क्यों कि माँग पूर्ति से श्राधिक थी परन्तु किर भी दलालां के कारण श्रीर उत्पादित माल घटिया होने के कारण उत्पादक को श्रपने परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता या। इघर कुछ वर्षों से इन उत्योगों की विकय समस्या गमीर होती जा रही है। काश्मीर का शाल श्रीर बनारस की सिल्क जैसे मूल्यवान सामानों का उपमोग नहीं हो पा रहा है क्यों कि राजात्रों तथा जमींदारों की श्रव पहले जैसी स्थित नहीं रही। राजाश्रों की गही त्रीर जमींदारी का उन्मूलन हो चुका है। जनता की क्रयशिक में कभी होने के कारण माँग घट गई है। समस्या यह है कि बाजार में उत्पादित माल की माँग बढाई जाय श्रीर उचित मूल्य बस्ला जाय। माँग में बृद्धि तभी की जा मकती है जब या तो निर्यात किया जाय या बडे उत्योगों द्वारा उत्पादित माल के बदले इनका उपभोग किया जाय। कुटीर उद्योगों से उत्पादित माल का उपभोग कनाहा, श्रमरीका, न्यूजीलेयट, श्रास्ट्रेलिया श्रीर मध्य पूर्वी देशों में बहाया जा सकता है। यह देश पूर्व से ही माल कय करते रहे हैं श्रीर दस्तकारी की वस्तुत्रों, कलापूर्ण कपड़ो, लाख तथा खेल के सामान इत्यादि के विषय में पूछताछ करते रहे हैं परन्तु इन देशों को बड़ी मात्रा में एक साथ श्रीर नमूने के

अनुरूप माल की आवश्यकता है। उत्पादित माल का बड़ी मात्रा में श्रीर ठीक नमूने के अनुरूप निर्यात करने के लिए विकय समितियों का विकास करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार छोटे पेमाने के श्रौर कुटीर उद्योगों पर कर कम लगाने की नीति श्रपनाती हैं। उदाहरणस्वरूप खण्डसारी चीनी पर कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी की श्रपेक्षा कम उत्पादन कर देना पडता है। इस समस्या का एक दूसरा पक्ष भी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सुक्ताव दिया गया है कि छोटे पैमाने के श्रीर कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों पर कर लगाया जाय। कर्षा उद्योग का विकास करने के लिए ६ करोड क्या एक करने के लिए स्त्री मिलों में तीन पाई प्रांत गज के हिसाब से यह कर लगा भी दिया गया है। बड़े पैमाने के उद्योगों पर पूर्व ही से बहुत कर लगे हुए हैं यदि यह नया कर श्रौर लगा दिया गया तो इससे उद्योग के विकास में वाघाए उत्पन्न हो जायेंगी। सभी प्रकार के बड़े, छोटे श्रीर कुटीर उद्योगों के विकास का उद्येश्य इस प्रकार की कर-नीति से पूर्ण नहीं हो सकता है।

छोटे ग्रीर कुटीर उद्योगें के सामने विगुत ग्रीर यावायात के ग्रभाव की मी समस्या है। इनकी स्थिति सुघारने के लिए सस्ती विगुत ग्रीर सस्ते यातायात की सुविधा देना ग्रावञ्यक है।

कार्ये कसेटी रिपोर्ट—योजना श्रायोग ने कार्वे कसेटी, श्रयवा श्राम्य उद्योग श्रोर छोटे उद्योग कसेटी, की नियुक्ति जून १६५५ में इन उद्योगों की समस्याश्रों का परीइण करने श्रोर एक ऐसी योजना प्रस्तुत करने के लिए की जिससे (१) द्वितीय योजना काल में उपमोग की वस्तुश्रों की वटी हुई मांग का श्रिषकाश इन्हीं उद्योगों से पूर्ण किया जा सके, (२) उनसे उत्तरोत्तर कार्य करने के श्रिषक श्रवसर प्राप्त हो सकें श्रोर (३) उत्पादन श्रोर विनिमय की व्यवस्था सहकारिता के श्राष्ठार पर व्यवस्थित हो सके।

कमेटी को यह स्पष्ट हो गया था कि आम्य तथा छोटे उद्योगों की उपेहा बहुत दिनों से होती या रही है। प्रथम योजना में जो उनके प्रति ध्यान दिया गया था वह पर्याप्त न था। प्रथम योजना के परिणामस्वरूप इन उद्योगों के विकास के लिये छ॰ विशिष्ट बोडों की स्थापना है। इन बोडों ने १६५१-५२ में १४ ३२ लाख रुपया ज्यय किया था जो कि १६५४-५५ में बढ़कर ६ ७३ करोड़ रुपया हो गया ख्रोर १६५५-५६ में १५ ४२ करोड़ रुपया, परन्तु यह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ। किमटी ने २६० करोड़ रुपये के विनियोग की सलाह दी अर्थात् द्वितीय योजना काल में प्रति वर्ष ५२ करोड़ रुपया ज्यय किया जाय।

कार्वे कमेटी ने उन छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले थ्रोर कुटीर उत्योगों के विकास की सिफारिश की थी जो नित्यकार्य में थ्राने वालो वस्तुश्रों का उत्पादन करते ये जैसे सूनी कपदे, उन्नो कपदे, हाथ के कुटे चावल, वनस्पति तेल, गुड़ खोर खरडसारी, चमटे के जुते छोर दियासलाई इत्यादि । साथ ही रेशम के कोडे पालना, रेशम खुनना, हथकर्षा उद्योगों की नारियल की जटा का कातना श्रीर खुनना, श्रादि उत्यागों की श्रोर कमेटी ने अपना ध्यान दिया। कमेटी द्वारा दितीय याजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कुल २६० करोड स्पए के ब्यय से श्राशा की जाती है कि अधिक समय के लिये, योजे समय के लिये श्रारा की जाती है कि अधिक समय के लिये यह उद्योग ५० लाख व्यक्तियों को कार्य करने का श्रवस प्रदान करने। कपडे के उद्योगों को कमेटी ने सब से श्रविक महत्ता दी । इनमें विकेन्द्रित सून कातने श्रीर विनने का काम मी सिम्मलित है। इस उद्योग पर लगमग कुल ब्यय का ४४% ध्यांत् ११३ करोड़ क्या व्यय किया जायगा। श्राशा को जातो है कि यह उद्योग लगभग ३० लाख व्यक्तियों को कार्य प्रदान कर सकेगा।

कमेटी ने तीन मुख्य ध्येय अपने समस् रक्खे थे। (१) द्वितीय योजना काल में ययासम्भव श्रीद्योगिक वेरोजगारों में बृद्धि न होने देना जो कि प्राय परम्परागत आम्य उद्योगों में हुआ करती है; (२) श्रिषक से श्रिषक सख्या में लोगों को योजना काल में प्राप्य श्रीर छोटे उद्योगों द्वारा कार्य करने का श्रवसर प्रदान करना, श्रीर (२) विकेन्द्रित समाज की स्पापना के लिये एक श्रापार प्रदान करना तथा सृद्धि-मान गति से श्राधिक विकास करने की सुविधा देना। कमेटी ने समृद्धि का जो काल्यनिक चित्र श्रायन मन में रक्का था उसकी प्राप्त कर लेने के विचार से निम्न सुमाव दिसे हैं—

- (१) प्रादेशिक सरकारों को सहकारों समितियों को धन तथा प्रत्याभृति द्वारा सहायता देनी चाहिये जिससे वे प्राम्म श्रोर छोटे उद्योगा की श्रीधक सहायता कर सकें। कमेटो ने रिजर्व वैंक श्रोर स्टेट वैंक श्राफ इंग्डिया को प्राम्य श्रीर छोटे उद्यामों की सहायता देने के श्रनेक ढगों का सुक्ताव दिया। उसने यह भी सिका-रिश को कि जा तक हन उद्योगों के लिये एक नई सपूरित सस्यागत श्रूण की व्यवस्था न हो जाय तथ तक श्रांखल भारतीय बोडों, प्रादेशिक वित्ताय निगमों तथा राजकीय विभागों को ग्रावश्यक सहायता देते रहना चाहिये।
- (२) प्रदिशिक सरकार। हारा दिये हुये श्रनुदानों का श्राम्य श्रोर छोटे उद्योगों की सहायता करने के स्थान पर कमेटी ने यह श्रधिक श्रन्छा सममा कि सरकार द्वारा सहकारिता के श्राधार पर उत्यादित कुछ वस्तुश्रों का निम्नतम

मृत्य निश्चित कर दिया जाय जिस पर वे वेची जाँय । मृत्य मे कम पर वेचने में जो घाटा हो उसे राज्य को पूरा करना चाहिये।

- (३) ग्राम्य और छोटे उन्नोगों को विस्तार का श्रवसर प्रदान करने के विचार से कमेटी ने यह विचिन सुमाव दिया कि फेन्ट्री उन्नोगों के श्रधिकतम उत्पादन की मात्रा नियत कर देनी चाहिये श्रीर जितना भी मींग इसके उपगन्त बढ़े उसे पर्यात, श्रथवा श्रशत ग्राम्य उन्नोगों से पूर्य करना चाहिये।
- (४) समा फेन्ट्री उत्योगों के सम्बन्ध में कमेटी ने एक उपकर शारोपित करने की सिफारिश की निस्ता प्रयोग प्राम्य और छोटे उत्योगों के विकास श्रीर उत्पत्ति के लिये किया जाय ।
- (५) कमेटी ने सुक्ताव दिया कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में एक प्रथक मत्री ब्राम्य त्रोर छोटे उन्त्रोगों के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये । इस मत्री को सहयोग देने के लिये मित्रमण्डल के स्टस्यों की एक कमेटी होनी चाहिये जिसका काम भारत सरकार की श्रीद्योगिक नीति में सामजस्य स्थापित करना होगा।

समालोचना-कार्वे कमेटी की रिकारिशों में निग्न गमीर टोप हैं।

- (श्र) कमेरी ने प्राम्य श्रोर छोटे उद्योगों का श्रार्जनकीकरण तथा श्रमिनवी करण तमी करने की छिकारिश की है जब कि उससे वेकारी न बंदे परत यह श्रसम्भव है।
- (व) मिल उद्योगों के उत्पादन की श्रधिकतम खीमा निर्धारित करने का श्रर्थ यह है कि आम्य श्रीर छोटे उद्योग उपयोग की वस्तुश्रों की वही हुई माँग को पूर्ण करने में समर्थ होंगे, जो कि जनसस्या के बहने तथा राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि के कारण होगी '। जिन व्यक्तियों को आम्य श्रीर छोटे उद्योगों का जान है वे यह श्रव्धी प्रकार जानते हैं कि श्रसम्मव है।
- (स) कार्वे कमेटी का श्रन्ताहित विचार यह है नि ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों की मिल उद्योगों की स्पर्धा से रज्ञा होनी चाहिये श्रीर उनको श्रपने माल को वेचने की त्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। परन्तु इस सम्प्रन्थ में केवल देश के मिल उद्योग का ही विचार नहीं करना है वरन विदेशी मिले भी स्पर्धा करेंगी।
- (द) कमेटी की इस सिफारिश के फलस्त्ररूप कि राज्य सहकारिता के सिद्धान्त पर उत्पादित वस्तुत्रों के कय त्रोर विकय मूल्य का श्रन्तर सहन करे श्रीर एक नया मन्त्रालय स्थापित करे, माग्त में राज्यों का ज्यय बढ जायगा । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक राज्यों के इतने बडे ज्यय तथा त्राय स्रोतों को देखते हुये इस सुमाव को ज्यवहारिक नहीं माना जा सकता।

योजना के अन्तर्गत-यह वहे सौभाग्य की बात है कि योजना श्रायोग

श्रीर सरकार ने कार्वे कमेटी की सब सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया विवाद ग्रस्त प्रश्न मिल उत्योगों के उत्पादन की श्रीधकतम मात्रा नियत करने का था, उस पर श्रमी निर्णय नहीं किया गया है। यह वहे दुर्माग्य की बात है कि उपकर कुछ उद्योगों पर तो लगा ही दिया गया है श्रीर श्रम्य पर लगाये जाने की सम्मावना है। परन्तु श्रमी तक तो कार्वे कमेटी की शिफारिशे उस सीमा तक स्वीकार नहीं की गई हैं कि भारतीय श्राधिक व्यवस्था को श्रसाध्य हानि पहुँच जाय।

प्रथम पचवर्षीय योजना में दस उद्योगों के लिये एक योजना निर्माण की गई यी—प्राम्य तेल उद्योग, नीम के तेल का सातुन बनाना, घान क्टना, खजूर का गुड़ बनाना, गुड़ और खग्टकारी उद्योग, चमडे का उद्योग, कन के कम्बल बनाना, हाथ से अच्छे प्रकार का कागज बनाना, शहद की मक्सी पालना और कुटीर दियासलाई उद्योग। यह योजना इस विश्वास पर निर्माण की गई थी कि इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार १५ करोड़ कपया और प्रादेशिक सरकार १२ करोड़ काया व्यय करेगी। प्रथम योजना काल में जो धनराशि वास्तव में इन उद्योगों पर व्यय की गई है वह ३१ २ करोड़ कपये है। इसमें से इयकर्ष उद्योग पर ११ करोड़ कपये और छोटे उद्योगों पर ५१ करोड़ कपये व्यय हुये।

् दो बढे मह्त्वपूर्ण कार्य प्रथम योजना काल में किये गये ! उनमें से एक तो केन्द्रीय सरकार द्वारा माम्य और छोटे उद्योगों के विकास के लिए एक वड़ी मात्रा में घनराशि का अलग निकाल देना या और दूसरा विभिन्न उद्योगों के लिये अलिल मारतीय बोडों की स्थापना था । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण, तथा अलिल मारतीय बोडों की कार्य परिधि के विस्तृत हो जाने के कारण, अनेकों उद्योगों का उत्पादन तथा उनमें कार्य करने वालों की सख्या मे वृद्धि हुई है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात सरकार द्वारा स्टोर्स परचेज कमेटी की उन सिफारिशों की स्वीकृति हैं जो स्टोर्स की कुछ प्रकार की वस्तुत्रों का केवल ग्राम्य श्रीर उद्योगों से ही खरीटा जाना श्रानिवार्य करते हैं, श्रीर बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की तुलना में उन वम्तुश्रों के मूल्य के अन्तर को ग्राम्य उत्योगों को देने के लिये बाध्य करते हैं।

दितीय पंचवर्षीय योजना मे प्रथम योजना की श्रिपेद्धा छोटे उद्योगो पर श्रिषिक घन मुख्यतः इस्रुलिये व्यय किया जायगा कि उससे भारत में वेकारी की समस्या इल होगी। कार्वे कमेटी की २६० करोड इपया व्यय किये जाने की िषफारिश के विपरीत द्वितीय योजना ने केवल २०० करोट रुपयों के न्यय की न्यवस्था की है। आशा यह की जाती है कि जब प्रादेशिक योजनाओं का पुनर्परीक्य होगा तो यह धनराशि श्रवश्य वह जायगी।

२०० करोड़ रुपया के विनियोग में से वेन्द्रीय सरकार २५ करोड़ रुपये करेगी श्रीर प्रादेशिक सरकार १७५ करोड़ रुपया क्याय करेंगी। योजना में साम्य श्रोर छोटे उनोगों के लिये निश्चित किये हुए २०० करोड़ रुपयों के श्रितिरिक्त ११ करोड़ रुपया कुटीर ग्रीर मध्यवर्ती उद्योगों के विकास के लिये श्रीर श्रीद्योगिक श्रूण के लिये, श्रीर ७ करोड़ रुपया विभिन्न लोगों के पुनवास के कार्यक्रम के श्रून्तर्गत श्रीशोगिक तथा व्यवसायिक शिज्ञा के लिये निश्चित किया गया है। सामुदायिक विकास चेत्रों के बजट में ऐसे उन्योगों के लिये प्रत्येक चेत्र में ११ लाए रुपये के व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है। पिछड़ी जातियों की सुर मुविधा के लिये गनाये कार्य-क्रम में भी कुछ चुने हुये उद्योगों से सम्बन्धित व्यवसायिक श्रीर श्रीशोगिक शिज्ञा का प्रगन्ध किया गया है।

दितीय पचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में छोटे पैमाने के उत्रोगों तथा कुटीर उद्योगों में कुछ प्रगति हुई है। इन पर ५६ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है श्रीर श्राशा की जाती है कि तीवरे वर्ष की समाप्ति तक यह ६१ करोड़ रुपया हो जायगा। इस व्यय का ४० प्रतिशत खादी श्रीर त्रामोधोगों के लिये, २५% से कुछ श्रीघक छोटे पेमाने के उद्योग तथा श्रोद्योगिक वस्तियों (Industrial estates) के लिये तथा २०% के लगमग हाय के कर्षे तथा शक्तिचालित कर्षों के लिये था। पहली दो योजनाश्रों में की गई व्यवस्था राज्य तथा केन्द्र की अनुमानित व्यय-समता पर श्राधारित थी। १६५६-५६ एक श्रन्य कारण भी महत्त्वपूर्ण हो गया। केन्द्र श्रीर राज्यों के पास योजनाश्रों को लागू करने के लिये धनराशि सीमित थी।

६२ श्रीयोगिक वस्तियों में से, ११ पहले दो वर्षों में पूरी हो गई तथा श्रन्य १६ के १६५८-५६ तक पूरी होने की श्राशा है। १६५७-५८ के श्रन्त तक छोटे उद्योगों का प्राविधिक तथा विकय सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये, ४ प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा सस्थान (Small Industries Services Institutes), १३ बढे सस्थान, २ उप सस्थान तथा २७ प्रसार-केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे। १६५८ के एक श्रीर प्रादेशिक लघु उद्योग सस्थान तथा ३३ प्रसार वेन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

१९५६-५७ में इथकर्षे का उत्पादन १६००० लाख गज था नो १९५५-५६ के उत्पादन से १३०० लाख गज अधिक था। १९५७-५८ में अनुमानित उत्पादन १६५००लाख गज था। श्रव तक की प्रगति लक्ष्य से कहीं कम है। १६५७ के अन्त तक अम्बर स्त से उत्पादित कपड़ा ७० लाख गज था। ऐसा प्रतीत होता है कि १५०० लाख गज का संशोधित लक्ष्य योजना काल के अन्त तक पूरा नहीं होगा। प्रानो ढग की खादी का उत्पादन ३५० लाख गज के आवार भूत उत्पादन से ५० लाख गज प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। खादी उत्पादन के लिये कई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया था। शक्तिचालित कर्षां की स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त लक्ष्य भी श्रव तक नगएय हैं।

श्रध्याय २१

श्रोद्योगिक उत्पादन श्रीर नियोजन

प्रथम पचवर्षीय योजना मे राजकीय तथा निजी उत्रोग चेत्र में श्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धिकरने की व्यवस्था की गई थी। ऋतर केवल इतना था कि राजकीय उद्योग चेत्र में उत्पादन मे वृद्धि करने का सम्पूर्ण उत्तरटायित्व सरकार ने ग्रपने कपर हो लिया था परन्तु निजी उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन के लक्ष्य निर्घारित कर दिये गये थे। यह श्राशा प्रकट की गई यी कि निजी उद्योग योजना की श्रविध समात होने तक इन लक्ष्यों तक पहुँच जाँयेगे । पुर्नपरी ज्ञित योजना को कार्यान्यित करने के लिये निर्घारित २३५६ करोड़ रुपयों में से १७६ करोड़ रुपया श्रर्थात् कुल व्यय का ७.६% उद्योगों स्त्रीर खान खोदने पर व्यय करना या जिसमें से बड़े स्त्रीर मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर १४८ करोड़ रुपया, खानों के सुधार पर १ करोड़ रुपया श्रीर छोटे उद्योगों पर ३० करोड़ रुपया व्यय परना या। इक्षन बनाने के चितरजन कारखाने ह्यौर रेल के लिये इस्पात की कोच बनाने के कारखाने में जो कुछ घनराशि लगाई गई वह रेलवे विकास योजन का एक अग थी। इस प्रकार श्राचार भृत उद्योगों श्रीर यातायात के लिये निर्घारित ५० करोड़ की धनराशि पृयक करके सम्पूर्ण राजकीय विकास कार्य क्रम मे ५ वर्ष के अन्दर ६४ करोड़ रुपया निर्घारित किया गया। राजकीय औद्योगिक देत्र मे जो रुपया लगाया गया उससे लोहे तथा इस्पात के नये कारखाने, इखन बनाने के चित्रखन कारखाने, मैसर में मशीन श्रीजार बनाने के कारखाने, सिन्द्री के रसायनिक खाद के कारखानों श्रीर पेनिसिलिन, डी॰ डी॰ टी॰, यन्त्र, टेलीफीन इत्यादि बनाने के कारखाने की विभिन्न योजनाश्चों को कार्यान्वित किया गया। जितने उद्योगों की सरकार सरलता से व्यवस्था कर सकती थी उन पर अधिकार कर लिया गया श्रीर शेष निजी चैत्र के लिये छोड़ दिये गये। इस मिश्रित श्रर्थ व्यवस्था से यह लाभ है कि राजकीय उन्नोग चेत्र का उस सीमा तक प्रसार किया जा सकता है जितना न्यवहारिकता हिंग्ट से सम्भव है और निजी उद्योग को श्रपने साधनों, कुशलता एवम् अनुभव के द्वारा देश का औरोगिक विकास करने का अवसर मिलवा है।

योजना श्रायोग ने श्रनुमान लगाया था कि योजना में उत्पादन के निर्घा-रित लध्य तक पहुँचने के लिये निजी उद्योग च्रेत्र में पाँच वर्ष के श्रन्दर कुल २३३ करोड़ रुपया लगाना पढेगा। यदि इसमें मशीनों को परिवर्तन तथा उद्योग का श्राधुनिकीकरण करने के लिये १५० करोइ श्रोर चालू पूँजी के लिये ३२४ करोड़ की धनराशि समिनित कर दी जाय तो पाँच वर्ष में निजी उद्योग चेत्र में कुल ७०७ करोड़ रुपया लगाया जायगा। मारतीय उद्योगपितयों ने इस योजना की श्रालोचना की । उनका कहना या कि (श्र) उद्योग के श्राधुनिकीकरण के लिये १५० करोड़ रुपया श्राप्यांत है क्योंकि श्रधिकाश उद्योगों की मशीनें प्राय व्यर्थ हो गई हैं। योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिये श्रावश्यक मशीनों का प्रवन्ध करने में इससे कहीं श्रधिक रुपयों की श्रावश्यकता होगी, (ब) सम्कार ने केवल श्रावश्यक धन की माझा बता टी है, परन्तु उसकी प्राप्ति की व्यवस्था नहीं की है। उद्योगों के पास ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे यह कार्य किये जा सकें, मारतीय पूँजी बाजार की ऐसी स्थित नहीं है कि इतना धन प्राप्त किया जा सकें श्रीर विदेशी पूँजी मो प्राय. उपलब्ध नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने से आत होता है कि निजी उद्योगों का योजना में निर्धारित उत्यादन के लक्ष्यों को पूरा कर सकना सम्भव नहीं है।

योजना में उत्योगों को जिस कम से प्राथमिकता दी गई थी उससे स्पष्ट है कि प्राधारमृत एवम् प्रमुख उद्योगों के साथ ही ऐसे उद्योगों को श्रिषक महत्व दिया गया जिनका श्रिपेबाकृत बहुत कम विकास हुश्रा था। यदि राजकीय तथा निजी उत्योग चेत्रों को एक साथ मिला कर देखा जाय तो यह ज्ञात होगा कि कुल ज्यय का रह प्रतिशत घातु शोधन उद्योगों के लिये, २० प्रतिशत पेट्रोल शोध-शालाश्रों के लिये, १६ प्रतिशत इजीनियरिंग उत्योगों के लिये, प्रप्तिशत स्ती उद्योगों के लिये, ५ प्रतिशत सीमेंट श्रीर लगभग ४ प्रतिशत कागज, पट्ठे तथा श्राखनारों कागज उद्योग के लिये निर्धारित किया गया था। इसका श्राय यह या कि जिन उत्योगों का स्त्रमी विकास नहीं हो पाया था उन पर श्राधक व्यय किया जाय। यर्तमान उद्योगों को छोड़ा नहीं गया था बल्कि उनके लिये कम बनराशि निर्धारित की गई थी। ऐसा उचित मी था। देश के सभी उपलब्ध सावनों का श्रच्छे से श्रच्छा उपयोग करने के उद्देश्य से ही यह व्यवया की गई थी। श्रीद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिये योजना में निम्नलिखित प्राथमिकता-क्रम दिया गया है।

- (१) ज्र श्रीर प्लाइबुड जैसे उत्पादक वस्तु उद्योग श्रीर स्ती कपडे, चीनी, चाबुन, बनस्पति, रग श्रीर वानिश जैसे उपभोग की वस्तुश्रों के उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाय।
 - (२) लोहे तथा इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, रक्षानिक खाद, भारी

रसायनिक, मशीनों के श्रीजार इत्यादि उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति की बहाया जाय।

- (३) जिस उद्योग को श्रारम करने के लिए कुछ पूँजी लगा दी गई है उसे पूरा किया जाय।
- (४) देश के श्रौद्योगिक ढाँचे को श्रधिक शक्तिशाली बनाने के लिए श्रपने साधनों को ध्यान में रखते हुए नये कारखाने स्थापित किये जायँ जैसे जिप्सम से गन्यक का उत्पादन किया जाय।

प्रथम योजना में उद्योगों के तीन वर्ग किये गयेथे। (१) जूट श्रोटोमाँबाइलस, मशीन व ग्रीनार कपडे की मशीन तथा चूड़ी के उद्योगों के सम्बन्ध में जिनकी उत्पादन शक्ति प्रयोग्न थी, इस बात पर महत्व दिया गया कि वे श्रपना उत्पादन वढाकर श्रपनी श्रनुमानित शक्ति के स्तर पर ले श्रावें जो बटली नहीं जायगी, ढले हुये लोहे, इस्पत, चीनी, सीमेंट, कागज और कागज के पट्टे, दियासलाई तया कुछ रसायनिक वस्तुत्रों का उत्पादन करने वाले उद्योग जिनके सम्बन्ध मे यह निर्णय किया गया या कि उनकी अनुमानित शक्ति बढाई तो जायगी पर १०० प्रतिशत से कम। इनके अन्तर्गत सीमेंट, सलफ्यृरिक ऐसिड, दला हुआ लोहा, तैयार इस्पात, कागज श्रौर कागज के पटटे, दियासलाई, स्टोरेज बैटरी ग्रौर विजली के पखे बनाने वाले उद्योग भी सम्मिलित कर लिये गये थे. (३) विजली से चलने वाले पम्पों, डिज़िल इननों, सीने की मशीन, बाइसिकिलों इत्यादि उद्योगों का जिनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति माँग के अनुपात में कम है काफी प्रसार करने की योजना बनाई गई थी। इसी श्रेगी में अन्य उद्योग भी आते हैं जैसे काटन लिन्टर्स, केमिकल पल्प, कुछ दवाइयाँ इत्यादि जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता या परन्तु श्रव इनके उत्पादन की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार पचवर्षीय योजना में देश के श्रौद्योगिक विकास की कमी को पूरा करने का प्रयन किया गया था।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रीद्योगिक श्रोर खिनज पदार्यों के विकास को प्रथम योजना की श्रपेद्या श्रिषक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वास्तव में द्वितीय योजना श्रीद्योगिक विकास पर केन्द्रित है। द्वितीय योजना में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से ८६० करोड़ या १८५५% उद्योगों पर व्यय किया जायगा जब कि प्रथम योजना के कुल २,३५६ करोड़ रुपयों के व्यय में से उद्योग पर १७६ करोड़ रुपये या ७६% व्यय किया जाना था। द्वितीय योजना प्रथम की श्रपेद्या श्रिषक विस्तृत है श्रीर इसमें व्यय भी बहुत श्रिष्ठ किया जा रहा है। उद्योगों को श्रिषक महत्व देने का कारण देश

के श्राधिक विकास की श्रधिक सतुलित करना, राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि श्रीर वेकारी ब्राटि को कम करना है। द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत कार्यक्रम मे प्रायमिकता निम्न प्रकार दी गई है।

- (१) लोहे और इस्पात तथा भारी रखायनिक उद्योगों का निर्माण करना जिसमें नाइट्रोजन युक्त खाद श्रीर इन्जीनियरिंग तथा मशानो के निर्माण सम्बन्धी उद्योग सम्मिलन है।
- (२) विकास सम्बन्धी वस्तुओं तथा उत्पादन में कार्य श्राने वाली वस्तुओं, जैसे श्रलमोनियम, सीमेंट, रसायनिक पल्प, रग, फास्फेट युक्त खाट श्रीर श्रत्यन्त श्रावश्यक दवाईयाँ श्रादि की उत्पादन शक्ति में विस्तार करना।
- (३) महत्वशाली राष्ट्रीय उद्योग, जो स्थापित हो चुके हैं, जैमे जुट ग्रौर स्ती कपढे बनाने तथा चीनी उद्योग ग्रादि, उनके प्रसाधनों की वृद्धि ग्रौर उनका श्रभिनवीकरण।
- (४) उन उद्योगो की उत्पादन शक्ति में जिनकी उत्पादन शक्ति श्रीर वास्त-विक उत्पादन में श्रन्तर है वृद्धि करना ।
- (५) साधारण उत्पादन के कार्यक्रमों तथा उद्योगों के विकेन्द्रित ग्रश के उत्पादन लक्ष्य के अनुसार उपमोग की वस्तुश्रों के उत्पादन में वृद्धि करना।

श्रौद्योगिक विकास के कार्य क्रम के दृष्टिकोग्य से दिवीय योजना की अनेकों विशेषतायें हैं :--

(१) इसमें राजकीय चेत्र को व्यक्तिगत चेत्र से अधिक महत्ता दी गई है। दितीय योजना की नवीनता इस बात में है कि राजकीय चेत्र में औदोगिक और खिन उद्योगों के विकास के कार्यक्रमो को प्रधानता दी गई है। भारत में कृषि, बिद्युत शक्ति, यातायात, तथा सामाजिक सेवाओं के विकास के सम्बन्ध में राजकीय चेत्र के अन्तर्गत किये गये विनियोग में उद्योगो और खिनज सम्बन्धी योजनाओं को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त हुआ था। प्रथम योजना में राजकीय चेत्र में बढे उद्योगों की स्थापना के लिये केवल ६४ करोड़ रुपयों के विनियोग का प्रबन्ध किया गया था, जबकि व्यक्तिगत चेत्र में २३३ करोड़ रुपयों के विनियोग का अनुमान किया गया था। दितीय योजना के अन्तर्गत राजकीय चेत्र में बढे उद्योगों और खिनज के विकास के लिये (वैज्ञानिक अन्विष्ण कार्य पर व्यय सिम्मलित करते हुये) ६६० करोड़ रुपयों की व्यक्तिगत

चेत्र में उद्योगों श्रोर खानों पर न्यय किये जाने के लिये केवल ५७५ करोड रुपयों का ही प्रवन्ध है। न्यक्तिगत चेत्र को यद्यपि देश के श्रीयोगिक विकास में एक बहुत वहा भाग लेना है फिर मी यह प्रत्यक्ष है कि राजकीय चेत्र की योजनाश्रों पर न्यक्तिगत चेत्र की योजनाश्रों से श्रापेक्षाकृत श्रिषक महत्व दिया गया है।

(२) योजना की दूसरी विशेषता यह है कि मुख्य श्रीर श्राघार उद्योगों का विकास उपमोग की वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की श्रपेक्षा श्रिषक किया जायगा। प्रतिष्टापित उत्पादन शक्ति के श्रायोजित विकास तथा प्रस्तावित उत्पादन सम्बन्धी १६६०-६१ के श्रांकडे यह प्रकट करते हैं कि लोहे श्रीर इस्तात, इन्जीनियरिंग तथा रसायनिक उद्योगों के श्रांकितम प्रधार का श्रायोजन किया गया है। भारत में प्रथम बार मशीन निर्माण उद्योग के विकास का श्रायोजन किया गया है। सत तथा जूट विनने की मशीनों के तथा सीमेंट श्रीर चीनी बनाने की मशीनों के श्रीर छोटे छोटे श्रीजारों के उत्पादन के उद्योग तो भारत में पिहले से ही स्थित हैं, पर उनका बहुत श्रिषक विस्तार कर दिया जायगा। कागज तथा छपाई उद्योग के उत्पादन का मूल्य १६६०-६१ तक क्रमशः ४ करोड़ रुपये तथा २ करोड़ रुपये तक हो जायगा। वर्तमान समय मे तो इन वस्तुश्रों का उत्पादन नगएय ही है।

वहें उद्योगे श्रोर खनिज उद्योग पर जो ६६० करोड रुपया व्यय किया जाने वाला है वह लगभग पूर्ण रूप से मूल उद्योगों के विकास के लिये है, जैसे लोहा इस्ताठ, कोयला, खाद, इन्जीनियरिंग तथा बड़े वहें विजली के प्रधाधन इत्यादि। योजना में तीन इस्पात स्थानों की स्थापना रूरकेला, मिलाई, श्रोर दुर्गपुर में होगी जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख टन इस्पात पिएडों की होगी। इसके श्रातिरिक्त इनमें से एक स्थान्त ती ३५०,००० टन ढला हुआ लोहा विकी के लिये उत्पादित करेगा। राजकीय चेत्र के श्रन्तर्गत सब योजनाश्रों से श्राशा की जाती है कि कुल इस्पात की उत्पादित मात्रा लगमग २० लाख टन दितीय योजना के श्रन्त तक हो जायगी।

इन्जीनियरिंग के बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम में चित्तरन्जन लोकोमोटिव फैक्ट्री में एक बड़ी इस्तात फाउन्ड्रों की स्थापना भी सम्मिलित है। इस बात का प्रवन्ध किया जा रहा है कि बड़े बड़े जिजली के प्रसाधनों का निर्माण राजकीय चेत्र में हो। इसलिये चित्तरन्जन लोकोमोटिव फैक्ट्री का विस्तार होना परमावश्यक है ताकि वर्तमान समय के १२५ इन्जिनों के वार्षिक उत्पाटन के स्थान पर ३०० इन्जनों का प्रतिवर्ष उत्पाटन हो जाय। टि इन्टीगरल कोच फैक्ट्री जिसने उत्पादन कार्य १६५५ में आरम्म किया लगमग ३५० कोच प्रतिवर्ष १६५६ तक उत्पादित कर सकेगी । एक नई मीटर गेज कोच फैक्ट्री की स्थापना का भी प्रबन्ध कर दिया गया है।

(३) द्वितीय-योजना में ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों को प्रथम योजना की श्रूपेचा श्रूपिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है श्रीर यह प्रस्ताव किया गया है कि उन पर प्रथम योजना के ३० करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर श्रव २०० करोड़ रुपया व्यय किया जाय । ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों को इतना महत्व देने का मुख्य कारण यह है कि देश की श्राधिक व्यवस्था के विकेन्द्रित भाग में कार्य करने के श्रिषक श्रवसर प्रदान कर सर्केंगे।

समालोचना—दितीय योजना प्रथम योजना की श्रपेता श्रधिक विचार पूर्ण है। इस योजना में यह उचित ही है कि कुषि की तुलना में श्रीद्योगिक विकास पर श्रिक महत्व दिया गया है। इससे देश का सतुलित विकास सम्भव हो सकेगा श्रीर जो देश की द्यार्थिक व्यवस्था में श्रमाव रह गए ये वे पूर्ण हो जायेंगे। यह भी बहुत उपयुक्त है कि बड़े मूल श्रीर मशीनों के निर्माण के उद्योगों के प्रति विशेष ध्यान दिया है। इन्हा के श्राधार पर मारत का मावी श्रीद्योगिक विकास सम्भव हो सकेगा। यह सब होते हुए भी द्वितीय योजना में श्रनेकों गम्भीर दोष रह गये हैं।

- (१) राजकीय चेत्र का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया है। यदि चरकार के पाल घन के खात, औद्योगिक ज्ञान, उत्योगों के आरम्म करने की ज्ञमता आदि होतो तव तो इलमें कोई हानि की सम्मावना न होती, परन्तु सरकार के पास तो ये पर्याप्त मन्ना में नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेकों उद्योग जो राजकीय चेत्र के अन्दर सम्मिलित कर लिये गये हैं उनमें राजकीय चेत्र से जितना साहस प्राप्त हो सकता है उसकी अपेचा अधिक जोखिम उठाने और साहस की आवश्यकता है। अन्त में यह भी कहा जाता है कि राजकीय चेत्र को आवश्यकता से अधिक विस्तृत कर देने से ज्यक्तिगत चेत्र के लिये सुगमता पूर्वक कार्य करते रहने के लिये जितने साहस की आवश्यकता है उससे बहुत कम का 'अवसर छोड़ा गया है। इसमें साहर रूप से यह भय लिच्चत होता है कि राजकीय चेत्र अपने निर्धारत लक्ष्य को पूर्ण न कर सकेगा।
- (२) यद्यपि न्यक्तिगत स्त्रेत्र पर कुछ वस्तुश्रों की एक निश्चित मात्रा के उत्पादन करने का उत्तरदायित्व डाल दिया गया है, परन्तु इसके लिये न ती पर्याप्त मात्रा में जित्त की उपनिवास का कोई प्रवन्य किया गया है धीर न ऐसी सुविधाये ही प्रदान की गई हैं जैमे अवस्थिय के लिये वृद्धि अथवा करों से छूट आदि, जो कि न्यक्तिगत सेत्र के सरनता से कार्य करते रहने के लिये आवश्यक

हैं। राष्ट्रीय श्रीत्रोगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) जिसकी १९५४ में स्थापना की गई थी व्यक्तिगत जैन में उद्योगों के विकास में सहुत सहायता पूर्ण कार्य कर रहा है। दितीय योजना में भी यह सस्था व्यक्तिगत जैन में सहायता का नार्न परती रहेगी। यह सन होते हुये भी यह निश्चत रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत जैन को नित्त सकट उठाना पढ़ रहा है, जिससे श्रीदोगिक विकास में नाधा पढ़ रही हैं।

(३) भारत के श्रीयोगिक सगटन में महत्वपूर्ण स्थान रराने के कारण यह सर्वया उपयुक्त है कि माभ्य श्रीर छोटे उपोगों के विकास का प्रयत्न किया जाय, परन्तु यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि करे उपोगों पर उपकर श्रारोपित किया जाय श्रयवा उनके उत्पादन की माभा पर प्रतिनम्भ लगा दिया जाय, जिसले कि माम्य श्रीर छोटे उचोगों की रक्षा हो मके। इसने कार्याग्मम का नाइस नष्ट हो जाता है श्रीर कोई प्रभावशाली सहायता भी ग्राम्य श्रयवा छोटे उपागों की नहीं मिलती। इन उपोगों की समस्या को उनके हारा उत्पादित पत्तुश्री के गुणों की उनके हारा उत्पादित पत्तुश्री के गुणों की उनके मुल्य को घटा कर करना चाहिये न कि वरें उपोगों पर प्रतिन्य हारा।

हितीय योजना के योजोगिक विकास कारमम में उपर्युक्त दोषां के होतें हुये भी यह याचा भी जाती है कि इससे योजोगिक विकास की गति में प्रमस्य बुटि होगी, तथा छोजोगिक विकास सगटन के जभावां को पूर्ण करके यह योजना संग्रतन स्थापित करेगी योर ससार में भारत का पाणेगिक स्तर संसा उठायेगी।

योजना की प्रगति—" १६५७ ५८ तक पहली योजना में प्रारम्भ की गई प्रमेक प्रोद्योगिक योजनाएँ पूर्ण हो गई। इन योजनाओं में श्रालवेर का डी॰ डी॰ टी॰ का कारराना, दिल्ली के डी॰ टी॰ टी॰ कारराने का विस्तार, हिन्दु-रतान एन्टीवायोटिंग्स (कारराने) का विस्तार, मेसूर में सरकारी पोर्सलीन फेन्ट्री की पोर्सलीन इन्सुलेटर्स स्कीम, मेसूर श्राइरन एर्ड स्टील वर्कस का spun-pipe का कारखाना, विहार की सुपर फासफेट फेन्ट्री तथा NEPA कारराने में समुलन उपस्कर की व्यवस्था श्राद सम्मिलत थे। इन योजनाओं के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप डी॰ डी॰ टी॰ निर्माण करने की श्राक्त में २१०० टन की, पैन्सि-लीन के सम्बन्ध में १६२ लाख मीगा इकाइयों की तथा सुपर फास्फेट की उत्पादन श्राव्म में ३३,००० टन की वृद्धि हो गई। NEPA ने प्रतिवर्ण ३०,००० टन श्रारवारी कागज या उत्पादन करने की श्राप्ती पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लिया। २५०० टन इन्सुलेटर्स के निर्माण की शांक्त श्रयवा सामर्थ्य की भी स्थापना हुई। द्वितीय योजना में इन स्कीमों पर उत्पादन कर वेड क० व्यय परने की व्यवस्था थी।"

आशा की जाती है कि १६५८-५६ में निम्न औद्योगिक स्कीम पूरी हो जाँयगी।

वॉयगी।			
योजना	नयी श्रयवा श्रतिरिक्त शक्ति या सामर्थ्य		
1. सिन्द्री (खाद) कारखाने का विस्तार	४७,००० टन नाइट्रोजन		
2. मिलई ऋौर रुरकेला में पहलो	७००,००० टन प्रतिवर्ष दला लोहा		
महियाँ (Blast furnaces)	(pig iron)		
3. दुर्गापुर, की योजना (Coke-	२८५,००० टन कोक		
oven project >	(hard coke)		
4. हिन्दुस्तान मशीन टूल्फ, (milling			
machines or lathes) वे उत्पादन में वृद्धि ।	drilling machines)		
5. Hindustan cables Co axial	५३० मील केविल श्रीर ३०० मील		
cables project	co axial cables.		
इन योजनात्रों की कुल लागत ल	गमग २१ करोड ६० है तथा १२ करोड़		
रु का विदेशी विनियम अपेक्तित है।			
निम्न श्रौद्योगिक योजनाएँ द्वितीय	। योजना काल मे पूरी हो जॉयगी।		
योजना	नई ग्रयवा ग्रातिरिक्त सामर्थ्य		
१ मिलाई, रुरकेला, और दुर्गपुर	२२ लाख टन स्टील, तथा ६००,०००		
स्टील वर्कस	टन दला हुन्ना लोहा (pig Iron)		
२ नागल खाद योजना	७०,००० टन नाइड्रोजन (fixed)		
३. लिग्नाइट योजना उत्खनन सम्बन्धी	३५ लाख टन लिगनाइट		
४. हिन्दुस्तान एन्टीवायोटोनिस की	४५००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन		
स्ट्रेप्टोमाइसीन योजना	47 10 000		
५. मैस्र श्राइरन श्रीर स्टील वन्सं का	१५००० टन फैरो-सिलीकन		
फेरो-छिलकिन का विस्तार	, ,		
६ विहार की पोर्शकित इन्सुलेटर्स की	२००० दन इन्सुलेटर्स		
योजना	८-१२ जहाज प्रतिवर्ध बनाने की इसता		
७. हिन्दुस्तान शिपयार्ड	के लिये विस्तार,		
 प्• पी० सरकार की सीमेन्ट फैक्ट्री 	२३१०० रन सीमेन्ट,		
का विस्तार			

चध्याय २२ सरकार की श्रोद्योगिक नीति

भारत सरकार की ओट्योगिक नीति का आघार १६५३ के थ्रोट्योगिक (विकास और नियमन) स्थोधन कानून द्वारा स्थोधित १६५१ का औद्योगिक (विकास थ्रोर नियमन) कानून है। सरकार की नीति 'मिश्रित य्रार्थिक व्यवस्था' पर आधारित है जिसमे राजकीय उद्योग तथा निजी उद्योग टोनों का स्थान है। इस कानून मे भारत सरकार ने जिस श्रोट्यागिक नीति का निरूपण किया है वह मारत सरकार के उस बक्तव्य से बिल्कुल मिन्न है जो उसने समद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के रूप में ६ अप्रैल १६४८ को दिया था।

श्रीयांगिक नीति का उद्देश्य देश के श्रीयोगिक साधनों का यथा सम्भव गित ने चन्त्रुलित विकास करना होना चाहिये। यदि यह कार्य पूर्णतया निजी उन्होगों को ही उमर्पित कर दिया जाय तो यह उद्देश्य पूर्णत: प्राप्त नहीं किया जा चकता क्योंकि पूँजी का अभाव, उत्रोग के लिये आवश्यक सामान और मशीनों का ग्रमाव, ग्रीयोगिक कुरालता का ग्रमाय ग्रीर उद्योगपति की शीघ लाम उठाने की श्रमिलापा इस दिशा में बाधक बन जाते हैं। इस कारण श्रव तक उपमोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उन्नोगों पर मशीनों इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्यागों को ग्रपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता रहा है इसीलिए निबी उद्योगों पर नियत्रण रखा नाना और साथ ही राज्य के त्तेत्र में उद्योग पर स्वालन तथा प्रवन्ध त्रावश्यक प्रतीत होता है। बहुत समय से इस नीति का समर्थन किया जाता रहा है कि राज्य को निजी उद्योगों पर नियमण रखना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही यह मी श्रावश्यक है कि निजी उद्योगों को सहायता दी नाय, उनको विकास के लिये प्रोत्साहित किया नाय, राजकीय उद्योग का चैत्र निश्चित किया जार, निजी उद्योग को अनुचित कठिनाइयों और उल्कानों में न पढने दिया जाय श्रीर एक श्रीद्योगिक सस्या को दूसरी श्रीद्योगिक संस्या का शोषण न करने दिया जाय। परन्तु भारत सरकार की भ्रीयोगिक नीति इसके विपरीत है। इससे मारत के उपयुक्त श्रौत्रोगिक विकास की सम्मावना नहीं है। इस नाति को नहारात्मक नीति कहा जा समता है। इसमे निजी उदागों के सम्बन्ध में उन बातों का उल्लेख किया गया है जिनको करने के लिये राज्य श्रव-मित नहीं देगा। इसमें यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि राज्य निजी उद्योगों को सहायता देने के लिए क्या करेगा। यह नीति यथार्थवादी नहीं है क्यों कि

इसमें भारत में निजी उद्योग की वर्त्तमान स्थिति और उसके सगठन तथा आकार-प्रकार पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विषरीत निजी-उद्योग चेत्र में कुछ ऐसी बातें लागू की गई हैं जिनकी उपयोगिता पर सन्देह प्रगट किया जा सकता है, जो देश के औद्योगिक विकास में सहायक होने की अपेन्ना बाधक हो सकते हैं।

६ अप्रैल १६४८ का श्रीद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव— १६४८ में घोषित श्रीदोगिक नीति में 'मिश्रित' शर्य व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। परन्तु राष्ट्रीयकरण का विषय इसमे विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। वास्तव में 'मिश्रित ऋर्थ व्यवस्था' के सिद्धान्त में ही 'राष्ट्रीयकरण' का विचार निहित है। परन्तु सरकार ने अपनी घोषणा में इसकी चर्चा करके इसे श्रधिक स्पष्ट कर दिया। इस घोषणा में उद्योगो को तीन श्रेणियों में विमाजित किया गया था। (१) प्रथम श्रेणी के उन्तोगों में इथियारी ह्रौर गोला-बारूद का उत्पादन, श्रग्ण-शक्ति का उत्पादन श्रौर नियत्रण श्रौर रेलवे परिवहन का प्रवन्ध तथा स्वामित्व सम्मिलित किये गये थे। इन उद्योगों पर राज्य को पूर्ण एकाधिकार दिया गया । इस न्यवस्था से विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि ये उद्योग पहले से ही राज्य के श्रिधकार में श्रीर इस बात की बहुत कम सम्मायना है कि भारत में निजी उद्योग इनमें से किसी एक को भी अपनाने के लिये तैयार होगा। वास्तव मे द्वितीय और तृतीय श्रेगी के उद्योगों पर ही इस श्रोद्योगिक नीति का महत्व निर्भर करता है। (२) द्वितीय श्रेगी के उद्योगों में कोयला, लोहा, इस्पात, विमान-निर्माण जलयान-निर्माण, टेलीफोन, तार तथा वेतार के तार के यत्रों का निर्माण और पेट्रोल इत्यादि खनिज तेल सम्मिलित किये गये हैं। इन उन्योगों के सम्बन्ध में यह कहा गया या कि इस श्रेगी के नवीन कारखानों को स्थापित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल राज्य पर होगा और जो वर्तमान समय में चालू कारखाने हैं उनकी दस वर्ष में पुन जॉच की जायगी श्रीर यदि श्रावश्यक हुश्रा तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा। इस व्यवस्था का निजी उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया। उद्योग में सुवार करने के लिये जो कुछ रुपया लगाया जायगा उसका लाम उठा सकने के लिये १० वर्ष राज्य ने स्वीकार कर लिया, इससे इस श्रेणी के उद्योगों में निजी उद्योग के मालिको की रूचि कम हो गई इस द्वेत्र मे उनका सम्पूर्ण उत्साह समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप श्रीद्योगिक उत्पादन घट गया, पूँजी निर्माण की प्रक्रिया योमी पड़ गई श्रीर श्रीद्योगिक चेत्र में कुछ सीमा तक मन्दी श्रा गई। यटि

राज्य नवीन कारणाने स्थापत कर उत्पादन कार्य ग्रारम्भ कर देता तो इससे विशेष हानि की समावना नहीं थी। परन्तु मारत सरकार छीर राज्य सरकारों के पास इस कार्य के लिये जावश्यक बन, साहस शोर कुशल कर्मचारियों का ग्रमाव है। फल स्वरूप देश भी छोद्योगिक स्थित प्रगति करने की श्रपत्ता ग्रवनत होती गई। (३) शेष उल्लोगों को तीमरी श्रेणी में रणा गया। यल्ली इस श्रेणी के उद्योगों को निजी उल्लोग दोन के लिये छोड़ दिया गया परन्तु यह भी कहा गया कि राज्य इस चेन में भी गमश भाग लेगा। परन्तु सामनो के श्रमाव के कारण राज्य इस चेन में सिक्त नहीं हो सका।

नवीन औद्योगिक नीति—३० अप्रैल १९५६ को घोषित नवीन अोदोगिक नीति १९४८ के योदोगिक नीति सम्म्थी प्रस्ताव की रूपरेक्षा से मिलती जुलती है, योर उद्योगों को राज्य द्वारा उनमें मान लेने के आवार पर ३ वर्गों में विभाजित करती है। प्रयम वर्ग में १७ उद्योगों की गणना की गई है जिनमें कोयला, लोहा आर इस्पात, गनिज-तेल, सामान्य प्रोर विद्युत इन्जीनियरिंग के उन्छ अया और परिवहन सम्म्थी कुछ ऐसे उद्योग आते हैं जिनके मावी विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य के कार है। द्वितीय वर्ग में लगभग एक दर्जन उद्योग सम्मिलत किये गये हैं, जेसे मशीन के यन्त्र, अलमुनियम, पाद, सहक और समुद्री परिवहन इत्यादि जिनमें व्यक्तिगत योर राजकीय उपक्रम साथ साथ चलेंगे परन्तु यह कमश राजकीय अधिकार में आ जायेंगे, इस लिये इन में नवीन उपक्रमों के स्थापित करने में राज्य अग्रगणी होगा। शेष उत्योग जैसे सूती कपड़े, सीमेंट, चीनी इत्यादि तीसरे वर्ग में रक्यों गये हैं। इनका भावी विकास सामान्यत व्यक्तिगत स्त्रेत से उपलब्ध कार्यारम्भ साहस पर निर्मर करेगा। राज्य को यह भी आधकार होगा कि इस वर्ग के उत्योगों को भी आरम्भ कर सके।

उत्योगों के इस त्रिवर्गीय विमाजन में कोई दोष नहीं है। १६४८ के श्रीद्योगिक नीति प्रस्ताव के श्रनुसार स्तोष प्रद ढग से कार्य हुया है। परन्तु नवीन श्रीद्योगिक नीति के त्रिवर्गीय विभाजन में कुछ दोष श्रा गये हैं।

(१) राजकीय चेत्र के विस्तार में बहुत श्रिषक वृद्धि कर दी गई है श्रोर व्यक्तिगत चेत्र को अत्यधिक सकुचित कर दिया गया है। इससे झानि यह होगी कि श्रौद्योगिक जान वाले कर्मचारिया, सगठन करने की ज्ञमता, पूँजी तथा अदुमव के श्रमाव में राज्य उन उत्योगों का प्रवन्ध न पूर्णत और न श्रिषकाँश ही कर सकेगा जिन्हें उसने श्रपने लिये सुरिज्ञत कर रक्खा है। व्यक्तिगत उपक्रम इस कठिनाई को सुवार सकने में श्रसमर्थ होगा क्योंकि नवीन नीति के श्रनुसार उन्हें यह कर सकने का कोई श्रिषकार ही न होगा श्रीर यदि सरकार उन्हें श्रामन्त्रित

भी करेगी तों उनमें इतना श्रात्म विश्वास न होगा कि वे ऐसा कर सके। इस नीति के निर्माता इस कठिनाई से अनिमन नहीं थे। जो न्यक्ति न्यक्तिगत उप-क्रमों की कार्य प्रणाली ग्रीर १६४८ के श्रोद्योगिक नीति प्रस्ताव के प्रमाय से परिचित हैं वे समक सकते हैं कि इस प्रयोगात्मक परिस्थिति में ब्यक्तिगत उपक्रम सम्मुख त्राने का साइस न कर सकेगें। प्रथम दोनों वर्गों में सम्मिलित व्यक्तिगत उद्योगों को सरलता से कार्य करते रहने के लिये श्रावश्यक वातावरण का श्रभाव है। यदि गत पाँच वर्षों के अनुभव का मरोसा करे तो यह आशा करना कि यदि राजकीय उपक्रम वाञ्छित लक्ष्य को पूरा न कर सके तो उनका स्थान व्यक्तिगत उपक्रम ले लेंगे, युक्ति सगत नहीं है। यदि प्रथम वगो में गिने गये कुछ उद्योगो को तीसरे वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता, जिसमें कार्यारम्म का मार व्यक्तिगत उपक्रमों पर है, तो निश्चित रूप से यह सम्मव होता कि वे किसी न किसी प्रकार ब्रीद्योगिक ज्ञान, पूँजी तथा अनुभव के श्रमाव को पूर्यों कर सकते जैसा कि गत २०० वर्षों से देखने में त्राया है। यह कोई तर्क नहीं है कि स्रोद्योगिक इमता, पूजी, अनुमव आदि का सर्वधा अपाव है, आरे इस लिये राजकीय उपक्रम अधवा व्यक्तिगत उपक्रम द्वारा इस समस्या को सुलमाने में कोई श्रन्तर नहीं पडता बहुत वहा अन्तर तो यह है कि व्यक्तिगठ उपक्रमो के पास उत्साह श्रीद्योगिक चुमता श्रीर कार्य करने की शक्ति है श्रीर राजकीय उपक्रमों के पास इनका श्रमाव है। नवीन ऋषोशिक नीति के कारण विकास की गति बढने के स्थान पर अवरुद

- (२) १९४८ की त्रोद्योगिक नीति में वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये रे वर्ष की श्रविध निश्चित की गई थी, श्रीर तीसरे वर्ग के उद्योगों के लिये यह स्पष्ठ रूप से कह दिया गया था राज्य उन्हीं उद्योगों को इस्तगत करेगा जिनकी प्रगति सतोषपद नहीं रही है। इससे व्यक्तिगत उपक्रमों को कुछ आशा बन्गी। परन्तु अब राज्य को अत्यधिक अधिकार देकर व्यर्थ में व्यक्तिगत उपक्रमों की सुरह्मा की मावना का अपहरण कर लिया गया है। यह राज्य के विचार अपवा अविचार से कार्य करने का प्रश्न नहीं है वरन् यह तो व्यक्तिगत उपक्रम में विश्वास श्रीर सदेह की भावना उत्पन्न करती है तो उससे इस सतोषप्रद परिणाम
 - (३) व्यक्तिगत उपक्रम को बहुत ही संकुचित चेत्र प्रदान किया गया है की ग्राशा नहीं कर सकते। जिसके कारण वे सरलता से कार्य नहीं कर सकते। मारत की स्रोद्योगिक नीति में जिस प्रकार राजकीय चेत्र का निश्चित स्थान है वैसे ही न्यक्तिगत चेत्र का भी है। व्यक्तिगत चेत्र के विस्तार को कम करने के किसी भी प्रयत्न का स्वामाविक

परिशास मारत के श्रीधोगिक विकास को कम करना है। वर्तमान समय में प्रचितत आय और सम्पत्ति के अन्तर को कम करने, व्यक्तिगत एकाधिकार को रोकने ग्रोर ग्रायिक शक्ति को थोडे से व्यक्तियों के हाथ मे केन्द्रित होने से वचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह तर्क ग्रासगत है। इस बात को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत में राज्य की जो श्राधकार श्राज प्राप्त हैं उनके द्वारा उद्योगों के व्यक्तिगत चेत्र में रहने पर भी वह एकाधिकार तथा श्रार्थिक शक्ति का केन्द्रित होना न रोक सके। जहाँ तक श्राय के श्रन्तर का सम्बन्ध है वह तो आधिक तथा अन्य उपायों रे पहिले ही काम किया जा चुका है। फिर यह कैसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उद्योगों को राजकीय त्तेत्र में रखने से आ्राथिक शक्ति केन्द्रित न होगी। य्रन्य देशों के अनुभव के अनुसार इसका परियाम श्रिधिक हानिकारक होगा। दूसरा कारण जिसके श्राघार पर वड़ी मात्रा में बत्पादन करने वाले उपकमों का विस्तार व्यक्तिगत जेन में सकुचित किया गया है वह कुटीर, ग्राम्य श्रीर छोटे उन्नोगों की वडे उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिवन्त्र लगाकर श्रीर भिन्न करारीप द्वारा श्रयवा प्रत्यन्त श्रवदानी द्वारा बहायता करना है। मारत में प्राम्य ग्रौर छोटे उन्नोगों को प्रोत्साहन देने में कोई दोष नहीं है। वास्तविक वात तो यह है कि इनका मारत की श्रौद्योगिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु वहे उद्योगों की हानि पहॅचाकर छोटे उद्योगों की प्रगति करना सर्वथा श्रविचारपूर्ण है। मारत की राष्ट्रीय श्राय श्रीर श्रीद्योगिक विकास में वृद्धि वहे उद्योगों से ही सम्भव है। द्वितीय योजना का ध्येय प्रति न्यक्ति दाषिक स्थाय बढाना स्त्रीर वेकारी घटाना है। यदि वहे उद्योगों का काल्पनिक श्रादर्शों के लिये उत्सर्ग कर दिया गया तो वह ध्येय कमी पूर्ण नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत चेत्र के विस्तार को सकुचित कर देने का परिशाम यह होगा कि व्यक्तिगत उपक्रम उचित रीति से कार्य न कर सकेंगे।

नवीन श्रीधोगिक नीति में वे गुण तो नहीं है जो कि १६४८ के श्रीशोगिक नीति प्रस्ताय में थे, परन्तु उसके सब टोप उसमें वर्तमान हैं। १६४८ की
नीति नकारात्मक थी श्रीर उसमें व्यक्तिगत उपक्रमों पर लगाये गये प्रतिबन्ध का
ही केवल वर्णन था। राज्य से उन्हें क्या सहायता प्राप्त होगी इसके प्रति कोई
एकेत नहीं था। यही दोप नवीन श्रीशोगिक नीति में जनता को महान प्रतीत
होने वाले निर्यंक श्रादशों के सम्मक्ष्य के रूप में है। व्यक्तिगत उपक्रम की
श्रत्यिक कर, श्रायकर के नियमों के श्रनुकूल उनके लिये पर्याप्त मात्रा में
श्रवस्थिष कर, श्रायकर के नियमों के श्रनुकूल उनके लिये पर्याप्त मात्रा में
श्रवस्थिष कर, श्रायकर के नियमों के श्रनुकूल उनके लिये पर्याप्त मात्रा में
श्रवस्थिय वृत्ति का प्रवन्ध, श्रीर सरकार की श्रम श्रीर मृत्य नीति के कारण सदैव
बढते हुये उत्पादन व्यय से रहा श्रावश्यक है। राज्य को इस हिंटकोण से

व्यक्तिगत उपक्रमों को निश्चित सहायता प्रदान करनी चाहिये जिससे वे सफलता-पूर्वक ग्रपना कार्यं कर सकें। सहायता का क्या रूप होगा ग्रीर वह किस विधि से दी जायगी आदि वाते सरकार की औद्योगिक नीति का एक आवश्यक अग बन जानी चाहिये जिससे कि वे सम्मव हो सके।

१६४१ का उद्योग कानून-११५१ का उद्योग (विकास और नियमन) कातून प्रथम अनुसूची में दिये गये उन ३७ उद्योगों पर लागू होगा जिनमें १ लाख से अधिक पूँजी लगाई गई है। यह व्यवस्था की गई है कि हन सभी श्रीद्योगिक सस्थानों को श्रनिवार्य रूप से श्रपनी रिजस्ट्रो करानी पढेगी। कोई नवीन कारखाना स्थापित करने के लिये ग्रथवा वर्तमान कारखानों का प्रसार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करना पढेगा ।

कानून के अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अनुत्चित उद्योग की जाँच करा सकती है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। इन निर्देशी का पालन न करने पर चेन्द्रीय सरकार संगूर्ण उद्योग को या उसके किसी भाग को एक निश्चित काल के लिए किसी न्यक्ति, बोर्ड या विकास-परिपद् के हाथ में सौंप सकती है। परन्तु यह अविध ५ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यह व्यवस्थाएँ श्रस्पष्ट श्रीर विस्तृत हैं। यह खेद का विषय है कि ससद ने जिस दितीय प्रवर-समिति को यह विधेयक विचारार्थ सौपा उसने प्रथम प्रवर-समिति की रिपोर्ट में दी गई उन शतों को रह कर दिया जिनके त्राघार पर राज्य इस्तचेष कर सकता था। प्रथम प्रवर समिति ने विकारिश की थी कि यदि उद्योग के प्रवन्त में अधिक अव्यवस्था फैली हो, वस्तुओं के माव में अनुचित उतार-चढाव हो, वस्तुत्रों का अभाव हो, अभिको में अशाति एवम् श्रसन्तोष हो श्रीर यटि सम्बन्धित उद्योग के कार्य मे श्राने वाले कच्चे माल का श्रमाव श्रीर उसकी शीघ्र समान्ति को रोकना राष्ट्र हित में हो तमी राज्य को अपने नियत्रण और इस्तिनेप के अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इन शर्तों से निजी उद्योग सन्तृष्ट या और यदि विषेयक हुनी रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो यौद्योगिक विकास को हानि न उठानी पहती परन्तु दितीय प्रवर-समिति द्वारा इन निश्चित शतों को रिपोर्ट में से निकाल देने के कारण फिर वही श्रनिश्चितता फैल गई जो सरकार की स्तपूर्व श्री गोगिक नीति से फैली थी।

इस कानून में केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद त्रीर विकास-परिषदे स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् में उद्योगपतियो, कर्मचारियों और अनुमूचित उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के उपभोक्ताओं के प्रति-निधि होते । इनके साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति मी इस परिषद् में समिलित किए जा सकेंगे जिन्हे केन्द्रीय सरकार उचित समकेगी। अध्यज्ञ को छोड़ कर परिषद् की सदस्य सख्या ३० मे अधिक नहीं होगी । केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषट् अनु-स्चित उत्योगों के विकास और नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सुकाव देगी।

किसी भी श्रनुसचित उद्योग श्रथवा उत्योगों के समृद्द के लिए विकास-पिषट स्थापित की जा सकती हैं। विकास परिपद में उद्योगपतियों, कर्मचारियों श्रार उन उत्योगों द्वारा उत्यादित माल के उपभोक्ताश्रों के प्रतिनिधि होंगे। इसमें ऐसे उ्यक्ति भी सदस्य बनाये जा सकेंगे जिन्हें सम्पन्यित उत्योग श्रथवा उद्योगों के त्रारे म विशेष टेमिकल शान हो। विकास-परिपद का कार्यचेत्र बहुत व्यापक बनाया गया है। सुख्यत विकास परिपट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करेंगी, उत्पादन-कार्य में सामजस्य स्थापित करेंगे के लिए सुक्ताय देंगी श्रोर समय समय पर उद्योग श्रथवा उत्योगों की प्रगति की समीन्ना करेंगी, इसके साथ ही न्नित रोकने के लिए कुशलता के मान निर्धारित करेंगी, श्रधिकतम उत्पादन करने, उत्पादन व्यथ करने श्रोर उत्पादित वस्तु भी प्रकार में सुधार करने के लिए सुक्ताव देंगी। विकास परिषद उत्पादित वस्तु भी प्रकार का एक निश्चित स्तर निश्चित करेंगी श्रोर विकास की व्यवस्था करेंगी श्रीर ऐसे उपाय सुक्तावेगी जिनसे श्रीमकों की उत्पादन-शिक्त में वृद्धि हो। जैसा पहले कहा जा चुका है सरकार उत्योग की पूर्ण व्यवस्था श्रथवा उसका कुछ माग श्रधिक से श्रिष्ठ स वर्ष के लिए इन विकास परिपदों के हाथ सौप सकती है।

विकास-परिपटो से यह आशा की जाती है कि वह निजी उद्योग के लिए एक परिचारिका का कार्य करेंगी। १९५३ में ऐसी दो विकास परिपटें स्थापित की गई। वाद में अन्य विकास परिपटें स्थापित की गई। १९५७ के अन्त में १२ विकास परिपटें निम्न उद्योगों के लिये काम कर रहीं थीं।

- (१) भारी विद्युत् उद्योग,
- (२) इलका वियुत् उद्योग
- (३) Internal Combustion Engines तथा शक्तिचालित पग्प

१ ८ मई १६५२ को कान्न लागृ होने के साथ ही केन्द्रीय परामशंदात्री परिपद् स्थापित की गई, वाणिज्य तथा उद्योग-मन्त्री इसके अध्यक्ष है। १६५४ में इसका पुर्नसगटन किया गया और इसके सदस्यों की सख्या २६ कर दी गई जिनमें से १४ उद्योगपतियों के प्रतिनिधि (भ्रजुस्चित उद्योग के), ५ कर्मचारी, ५ उपमोक्ता, भ्रौर ५ अन्य व्यक्ति जिनमें प्रारम्भिक उत्पादक सम्मिलित है। इससे यह परिपद् पूर्ण रूपेण प्रतिनिधि परिपद् वन गई है।

- (४) साइकिल
- (५) ग्रम्ल (acid) ग्रीर उर्वस्क
- (६) द्वार (alkali) तथा सम्बन्धित उद्योग
 - (७) टवाइयॉ
 - (८) जनी कपहा
 - (E) कलापूण रेशमी अपडा
 - (१०) चीनी (शकर)
 - (११) ग्रलौह धातुये ग्रौर मिश्रित घातुये, तथा

इन परिपटों का कार्य अपने-अपने उद्योगों की समस्याओं पर विचार करना। इनका ध्येय है उत्रोगों को अपनी पूर्ण शक्ति मर उत्पादन कर सकते की सुविषाये प्रदान करना, उनकी (रेटेड) ऋकित शक्ति को ग्रावश्यक स्तर तक

विकास परिपदों की सत्या इस लोगों ने ब्रिटेन से अनुसरण की है जहाँ वहाना, ग्रीर उत्पाटन व्यय को कम करना है। पर इनकी स्थापना अनेकों उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में की गई थी। वहाँ

ये परिपद असफल सिंह हुये पर हम लोग अब भी इनको अपनाए हुए हैं। व्यक्तिगत उपक्रमों के सफलता प्रवंक कार्य करने के लिये यह श्रावश्यक हैं कि उन्हें नित्य मित के कार्यों में प्रबन्ध कर्ता से पर्याप्त मात्रा में स्वतत्रता प्राप्त हो । उपक्रमो को कार्यारम्म करने का साइस श्रीर उत्साह होना चाहिये। यही एक श्राधार है जिस पर व्यक्तिगत उपक्रम से इस सफलता की आधा कर सकते हैं। प्रशन्ध करने में स्वतन्त्रता की मात्रा में कमी करने के मय, इन परिषदों की कार्यप्रणाली की अनिश्चितता तथा किसी उपक्रम के भ्रावश्यकता पड़ने पर सरकारी प्रबन्ध में ते लिये जाने की श्रमिश्चित शर्ते (जैसे विकास परिघद के निर्देशों का किसी उप-क्रम द्वारा उलान) ये उपक्रमी वर्ग के मन मे सदेह की मावना भर दी है। इसके श्रतिरिक्त परिषद एक ही प्रकार की सस्थाये तो है नहीं जो अपने अपने उद्योगो में से विकिसत हुई हो, इसिलिये वे मनोवाछित विकास नहीं कर सकती। यह भी सम्मव है कि विकास परिषद का इस्ता लेप सरकारी नियन्त्रणों से ग्रस्त उपक्रमों के

१६५३ का उद्योग (विकास और नियमन) संशोधन कानून-भारत-विनाश का ग्रन्तिम कारण सिद्ध हो। सरकार को १६५१ के उत्योग (विकास और नियमन) कानून को लागू करने के एक वर्ष पश्चात् ही सशोधन कानून का आधार लेना पड़ा। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मात की खोबोगिक नीति कितनी अनिश्चित है। ऐसी स्थिति किसी प्रकार भी लामकर नहीं कही जा सकती है। सशोधन कान्न का विश्लेषण करने से जात होगा कि उसकी न्यवस्थाएँ पूर्व की अपेन्ना अधिक टोषप्ण हैं। सशोधन कान्न के अनुसार किसी भी उत्योग पर सरकार परामर्शदात्री परिपद् से पूछे तिना अधिकार कर सकती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सरकार निर्देश दे और उत्योग को स्पष्टीकरण का अवसर है। सरकार के इन नवीन अधिकारों को प्राप्त करने से व्यापारों में उत्योगों के सम्बन्ध में और अनिश्चितता फैली है और इससे देश की औत्योगिक प्रगति अवस्छ हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं।

श्रव यह कातून ४२ उद्योगों पर लागू है, जिनमे असली रेशम, नकली रेशम, रग बनाने की वस्त्ये, साबुन, प्लाईबुड, फेगेमेगेनंज ब्रादि ६ नवीन उद्योग भी सम्मिलित हैं। स्थाधन द्वारा स्रकार की यह श्रिष्ठकार प्राप्त है कि वे यि वाह तो ५ वर्ष के पश्चात् भी (जो श्रवधि एक्ट में टी हुई यी) किसी उपक्रम का प्रबन्ध श्रपने हाथों में रख सकती हैं। इसके लिये यह श्रावश्यक होगा कि नियत्रण की श्रवधि बढ़ाने की एक विज्ञित पार्लियामेट के समन्न उपस्थित कर दी जाय। स्रवारी उपक्रमों को नई वस्तुश्रों के उत्पादन के लिये लाह सेन्स लेने से छूट दे दी गई है, यद्यि एक्ट मे टी हुई प्रथम तालिका में श्रनुस्चित उपक्रमों को लाइसेन्स लेना श्रीकार है। स्रकार को यह श्रधिकार है कि वह जिन उद्योगों को श्रपने श्रधिकार में ले उनके सगठन की सात्रों श्रीर वियमावली के विपरीत भी यि वाह तो कार्य कर सकती है। इस श्रधिकार से हिस्सेदारों के सामान्य श्रधिकारों को श्राधात पहुँचता है।

इन संशोधनों से उद्योग (विकास श्रीर नियमन) कानून बहुत कड़ा कानून अन गया हैं। श्रय केवल यह श्राशा की जाती है कि कानून को लागू करने वाले श्रिषकारी सन्तुलित दृष्टिकोण से कार्यवाही करेंगे श्रीर भारत के श्रीद्योगिक ढाँचे को सदैव के लिए नष्ट हो जाने से बचाएंगे।

राष्ट्रीयकरण की नीति—राष्ट्रीयकरण की नीर्त अप्रत्यज्ञ रूप से भारत सरकार की श्रीयोगिक नीति का एक अग है। इसका सकेत उद्योग (विकास श्रीर नियमन) कानून की उस व्यवस्था से मिलता है जिसके अनुसार सरकार टुछ स्थितियों में निजी उद्योगों पर अपना श्रीषकार कर सकती है।

गष्ट्रीयकरण का यार्थ है कि उत्पादन के साधनों पर जनता का श्रिषिकार हो। राज्य या तो श्रपने उद्योग स्थापित कर सकता है या चालू निजी उद्योगों को श्रपने श्रिषिकार में ले सकता है। राष्ट्रीयकरण का देश की सामाजिक, राजनैतिक, आयिक स्थितियों से निकट सम्बन्ध है। राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाय यह उस देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है।

सिद्धानत रूप में राष्ट्रीयकरण की नीति ना कई श्राधारों से समर्थन किया जा सकता है। प्राय यह कहा जाता है कि निजी उद्योग देश के सभी उपलब्ध साधनों का न तो पूर्ण उपयोग करना चाहता है और न वह ऐसा कर सकने में समर्थ ही है, इसिलए बिना राजकीय उद्योगों में तीवता से प्रगतिशील श्रीद्योगी-करण नहीं किया जा सकता। निजी उद्योगों द्वारा उद्योग के श्राधुनिकीकरण श्रीर युक्तिकरण (Rationalisation) की श्रोर ध्यान न देने की प्रवृत्ति की श्रालोचना करके भी राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया जाता है। यह कहा जाता है। का राष्ट्रीयकरण हो जाने से श्रीमक-मालिक के सम्बन्धों में सुधार होगा श्रीर श्रीमकों के दूने उत्साह से कार्य करने के कारण उत्पादन भी बढ़ेगा। राष्ट्रीयकरण के समर्थका का यह भी विश्वास है कि उद्योगों पर सरकार का श्राधकार हो जाने से बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायगी।

परन्तु यह तर्क सन्तोपजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय करण की किसी भी योजना को लागू करने से पूर्व यह त्रावश्यक है कि राज्य के पास पर्याप्त पंजी हो श्रीर उसे प्रशासन तथा सभी कुशल पाविधिक सेवाएँ प्राप्त हो। राष्ट्रीय करण के पश्चात् श्रमिक ग्रौर उद्योग के प्रबन्धको के सम्बन्धों में ग्रौर तनातनी होने की सभावना हे क्योंकि वर्तमान में इन दोनों के बीच राज्य सतुलन स्थापित करता है . श्रीर जब कभी इनके बीच कगढे उत्पन्न होते हैं राज्य उनमे हस्तत्तेप करता है। परन्तु यदि राज्य ही उद्योग का अधिकारी हो तो इस प्रकार के कगड़ों में राज्य स्वय एक पत्त हो जायगा और इस कारण मन्यस्थता नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय-करण हो जाने से श्रीद्योगिक सम्बन्धों में सुघार होने का सिद्धान्त इस बात पर श्राचारित है कि जनतन्त्र में अमिक यह सममता है कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसी के हाथ में है। इसलिए उसका राज्य से कोई फगड़ा नहीं होगा। परन्तु यह केवल सिद्धान्त की बात है। यह विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं है कि केवल राष्ट्रीयकरण हो जाने से ही श्रमिकों का स्वमाव बदल जायगा श्रीर वह श्रघिक कुशलता से श्रघिक परिश्रम कर उत्पादन बढ़ा देंगे। <u>उत्पादन तमी</u> बढ सकता है श्रीर वेरोजगारा को तभी कम किया जा सकता है जब राज्य जाल उदागों को श्रपने श्रधिकार में करने की श्रपेक्षा नये उद्योगों को श्रारम्भ करे।

राष्ट्रीयकरण की अपनी उपयोगिता होनी चाहिए। उसकी अपनी निशेष-ताएँ होनी चाहिए। केवल निजी उद्योगों में दोष होने के कारण ही राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाना उचित नहीं है। राष्ट्रीयकरण के विषद अनेक तर्क दिये जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप यह वहा जाता है कि अग्रोगों पर राज्य का ग्रिधिकार हो जाने से प्रवन्ध की कुशलता में ग्रमाव ग्रा जाता है स्वांकि राजकीय श्रिधिकारी उतने सतर्क श्रीर उत्साही नहीं होते हैं जितना निजी उद्योगपितयों ते श्राशा की जाती है। राष्ट्रीयकरण क्ये गये उद्योगों में प्रवन्धनों को सरकार कर्मचारी होने के कारण उत्योग से निजी लाभ उठाने की समायना ही नहीं होती, इसलिए उन्हें न तो व्यवसाय बढाने की इच्छा होती है श्रीर न इस श्रोर कोई ग्राम्पण होता है। जिन उगयोगों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है उनका विकास करने के लिए ग्रावश्यक पूँजी प्राप्त करने में ग्रिविक कर लगाने की श्रावश्यक पूँजी प्राप्त करने में ग्रिविक कर लगाने की श्रावश्यक पूँजी जनता करते हैं है श्रीर यह समय है कि श्राधिक हिए से श्रविकितन देश की जनता करण के इस ग्रिविक्त भार का बहन करने में श्रविक्ति है।

भारत में वेन्द्रीय तथा राज्य सरकारें कुछ उद्योगों की अधिकारिणी हैं और उन्हें चलाती हैं जिनमें रेलवे, डाक-तार, प्रतिरह्मा सम्प्रच्यी कारपाने, टेली-फोन कम्पनियाँ और कुछ निजली की कम्पनिया सम्प्रिलित हैं। गत कुछ वर्षों से ओद्योगिक चेत्र में राज्य का प्रवेश वटता गया है। प्रीफेटीकेटेड हाउधिंग फेक्टरी १६४६ में स्थापित की गई और अगस्त १६५० से इसका उत्पादन कार्य प्रारम्भ हुआ, चितरन्जन लोकामादिव फेक्ट्री ने १६५० ने कार्य आरम्भ किया। यह सभी राज-कीय उद्योग हैं। इनके अतिरिक्त हिन्हरतान विमान निर्माण उप्योग, प्रिसीजन हन्त्र्र्मेट फेक्टरी, नेशनल न्यूजप्रिन्ट और पेपर मिल्ल लिमिटेड मी राजकीय उप्योग हैं। राज्य ने कुछ वर्तमान उद्याग को भी अपने अधिकार में कर लिया है। १६५३ के विमान निगम कान्त के अन्तर्गत सरकार ने विमान उद्योग पर अधिकार कर लिया है।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। ताष्ट्रीयकरण होने से कम उत्पादन न्यय पर श्रिषक श्रीर श्रन्छा उत्पादन होना चाहिए। परन्तु भारत सरकार की राष्ट्रीकरण की नीति से यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुश्रा है। इसके विपरीत इन उद्योगों में जनता के घन की श्रपार चिति हुई है श्रीर उत्पादन में श्रनुचित देरी हुई है। इस सम्बन्ध में सिन्द्री खाद कारखाने का उदाहरण दिया जा सकता है। पहले यह श्रनुमान लगाया गया था कि १० ५३ करोड़ रुपये में कारपाना स्थापित हो जायगा परन्तु श्रन्त मे इस पर २३ करोड़ रुपया न्यय किया गया श्रीर स्थापित होने के सात वर्ष पश्चात् इसमें उत्पादन कार्य श्रारम्भ हो सका प्रोफेर्जिकेटेड हाउसिंग फैक्टरी हारा उत्पादित माल देश

ाप्त कच्चे माल के भार को निर्मित वस्तु के भार से विभाजित करने मे प्राप्त होता है। यदि 'माल का इन्डेक्स' किसी उद्योग के सम्बन्ध में बड़ा है तो इसमें इस सम्मना चाहिये कि कच्चे-माल की प्राप्त का स्थान श्रिधक प्रभावशाली हारण है श्रीर उद्योग की स्थापना के लिये वह स्थान श्रिधक उपयुक्त होगा परन्तु दि 'माल का इन्डेक्स' छोटा है तो उससे यह समम्मना चाहिये कि कच्चेमाल ही प्राप्ति कोई विशेष महत्यशाली बात नहीं है श्रीर उद्योग की स्थापना श्रच्छी ।कार बाजार के निकट की जा सकती है।

परन्तु जैसा इस सिद्धान्त में बताया गया है उसके अनुसार जहाँ न्यूनतम रिवहन व्यय हो वहाँ सर्वदा उद्योग स्याण्ति नही किये जाते । इसके कई कारण ं, जैसे (१) उद्योगपतियों को कच्चे माल की प्राप्ति के स्त्रोतो ख्रौर बाजारो का एएँ जान नहीं होता कि वे ठीक-ठीक स्नावश्यक स्ननगणन कर सके। होता यह कि यौसत दर्जे का व्यवसायी वर्तमान उद्योगों की स्थिति का अनुमान लगा तेता है और जहाँ पर उसकी समक में यह ज्ञाता है कि वह ज्ञिघकतम लाभ उठा सकेगा वहीं श्रपना कारखना खोल देता है। सामान्यतः वे उद्योग जो किसी थापन विशेष में केन्द्रित हो गये हैं कुछ ऐसी लामकारी स्थिति वहाँ उत्पन्न कर ते हैं जिनके कारण नवीन कारखाने वही स्थापित होने लगते हैं जिससे वहाँ स्थोर प्रविक स्थानीयकरण हो जाता है, (२) उद्योगपितयो के समज्ञ स्थान निर्धारण मे दा श्रार्थिक ही कारण नहीं रहते। वे सामाजिक सुविधाये तथा जीवन की श्रन्य अविधायों की प्राप्ति का भी विचार करते हैं जो नगरो में सुगमतापूर्वक प्राप्त । इस कारण से भी वे बहुधा बडे-बडे नगरों में या उनके आसपास अपने गरायानों के खोलने का निश्वय करते हैं चाहे ऐसा करने में उन्हें प्राम में शरसाना खोलने की अपेज्ञा लाम कुछ कम ही क्यों न प्राप्त हो, और (३) युद-गल में हवाई हमला से रच्चा का भी व्यान रखना आवश्यक होता है इसलिये बहुषा उद्योगों की स्थापना खुले हुये नगरों से दूर तथा नदी के किनारो से दूर रेश के ब्रान्तरिक भाग में करना पहला है चोहे इसमें ब्रार्थिक हानि ही क्यों न उटानी पडे ।

प्रवृत्ति—भारत में उद्योगों का स्थान-निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। एक ब्रोर मि कि वस्वई, पश्चिम वगाल ब्रौर विहार में अपेद्धाकृत ब्रधिक ब्रौद्योगीकरण ज़्या है तो दूसरी ब्रोर ब्रन्य राज्यों में ब्रौद्योगोकरण के प्रायः सभी साधन होते ए भी विशेष विकास नहीं हो पाया है। इसके साथ ही दूर ब्रामों की अपेद्धा गर के पढ़ोस में ही उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से भारत के बढ़े नगरों का निर्वित प्रसार हो गया है।

तातिका १ भारत के छाँछोगिक श्रमिकों की कुल संख्या का श्रतिशत

१६२१९३	१६: ६क्षे	\$EX3\$	१६५१
६२१	५६ २	५७ ६	ብጹ »
⊏३ १	न्द्र ह	ድ ሪ፡ሄ	تر ب
१६ ह	१४'१	१५ ६	११ ६
	६२ १	६२१ ५६२ ८३१ ८५६	६२१ ५६२ ५०६ ८३१ ८५६ ८४४

क्षुत्रिमाजित भारत के **याँक**डे

तालिना १ के अनुसार १६५१ म भारत के कुल श्रोद्योगिक श्रिमिकों वे ५४'३ प्रातशत बंगाल श्रोर त्रमर्फ के दा राज्यों में नार्च परते ये श्रीर द्रदा प्र प्रांतण्यत वंगाल श्रोर त्रमर्फ के दा राज्यों में नार्च परते ये श्रीर द्रदा प्र प्रांतण्यत वंगाल, त्रम्ब के महास, उत्तर प्रदेग श्रीर तिहार के पांच राज्यों में कार्य करते ये। इसका अर्थ है कि श्रीन्योगिक विनास की हिन्द से ग्रन्य च्रेत्र विख्ड हुए हैं जिनमें कुल श्रीद्योगिक श्रीमिकों के वेचल ११'६ प्रतिणत कार्य घरते हैं। यह घ्यान देने योग्य वात है कि त्रम्पई श्रीर बगाल च्रेत्र में कुल श्रीद्यागिक श्रीमिकों की मस्या ४६२१ में ६० १ प्रतिशत थी को घटकर १६५१ में प्रभु अपित्रात हो। गर्ड जब कि महास, उत्तर प्रदेश श्रीन निहार में इनकी मख्या १६२१ में कुल श्रीमिकों के २१ प्रतिणत से बढ़नर १६५३ में २६'द श्रीर श्रीमिक श्रीमिकों की सख्या १६२१ में १६'६ प्रतिशत यी जो घटनर १६५३ में १५'६ प्रतिशत श्रीर १६५१ में ११'६ प्रतिशत हो। गर्ड । इसका यह श्रर्थ है कि बगाल श्रीर बम्बई तथा देश के श्रन्य चेत्रों को श्रमेना महास, उत्तर प्रदेश श्रीर निहार में उद्योग श्रीपक केन्द्रत हुने हैं।

तालिका २ भारत के कुछ नगरों की जनसंख्या (लायों में)

	9 = 3 9	\$838	१६५१
कलकत्ता	33.4€	30 85	રૃપ ૪٤
वम्बर्ड	१ १६१	१६•६५	२८,३६
कानपुर	₹ '88	とっての	٧٠٠ <u>٠</u>
महाम	६ ४७	৬ ৬ ৬	१४ १६
दिल्ली	₹ ४७	५.२१	 દ શ્પ્ર

तालिका २ के ग्रॉकडों को देखने से पता चलता है कि १६२१ से १६५१ के बीच के ३० वर्षों मे मारत के बहे नगरों कलकता और वम्बई की जन-सख्या में बहुत श्रिधिक वृद्धि हुई है। कलकत्ता श्रीर वस्वई की जन-सख्या श्रपने दो गुने से भी श्रिविक हो गई है जब कि कानपुर की जन-सख्या तीन गुनी हो गई है। इसका एक कारण तो यह है कि अन्य नगरों की भाति गाँव से लोग आकर इनमें इसते गये हैं अग्रीर साथ ही इन चित्रों में उद्यागों के विनद्रत हो जाने से भी

हानियाँ - नगरो श्रीर वहे कस्वीं में उद्योगी के केन्द्रित हो जाने से श्रमेक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। हानियाँ हातो हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं --(१) इससे जन-संख्या स्थान के अनुपात में बहुत अधिक वह जाती है ज्ञोर इससे मोड एवम् विच-पिच हो नाती है। इसका जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है, सफाई नहीं रह पाती, रहने के लिए घरों का अभाव हा जाता है और इन केत्रा में अनेक सामा-जिम नुराईयों कि वृद्धि श्रीर उनका प्रधार होने लगता है। यदि उद्योगा को उचित रूप से विभिन्न उपयुक्त स्थानों में स्थापित किया जाता तो इनमें से बहुत सा बुराईशो से बचा जा सकता था; (२) उद्योग केवल बढे कस्बो श्रीर नगरों में दी विन्द्रत नहीं हुए हैं वरन् कुछ मुख्य प्रकार के उद्योग खास-खास रास्यों में केन्द्रित हुए हैं। चीनी उद्योग श्रिकतर उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार में, स्ती उद्योग बन्नई, मन्य-प्रदेश ग्रोर उत्तर प्रदेश म, लोहा श्रीर इस्पात उद्योग विहार में, जूट बगाल में और कायले की खदानों की उद्याग बगाल और बिहार में केन्द्रित हैं। इसका एक कारण तो यह है कि इन चेत्रों में अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल और विजली मिल जाती है और दूसरा कारण उद्योगपितयों की चिन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति से यह झानि होती है कि यदि इनमें से किसी उद्योग में मदी आ जाये तो उसका उस चेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पहता है। यदि चीनी के उद्योग में मटी त्र्या जाय तो इससे उत्तर प्रदेश ग्रीर विहार की जनता पर विपात का पहाइ ट्रूट जायगा श्रीर स्ती उन्नोग में मदी श्राने से वम्बई, मध्य प्रदेश स्रोर उत्तर-प्रदेश की जनता सकट में पढ़ जायगी। यदि उद्योग देश में चारों श्चीर वितरित हुए होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती । यह विल्कुल संभव है कि एक उद्योग में मदो त्राते ही दूसरे उद्योग में भी मदी नहीं त्रा जाती है त्रीर यदि उद्योगों को उचित रीति से सम्पूर्ण देश में फैला रखा हो तो मंदी त्राने से उद्याग को चित अपेचाकृत कम होगी, (३) इन्हीं कुछ चुने हुए चेत्रों में उद्योग। के केन्द्रित हो जाने से अन्य देशों की प्रायः उपेक्षा की गई है। यह हो सकता है कि ग्रान्य दीत्र इनके समान उत्तम सिंह न हो फिर भी उनमें उद्योगों की स्थापना से कुछ श्राधिक लाभ होने को सभावना है। इन च्रेगों को सामाजिक सुविधारों श्रोर उत्योग के लिए ग्रावण्यक प्राकृतिक साधनों का प्राप विल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। इन च्रेग की जनता श्रपेक्षाकृत श्रधिक वेरोजगार है श्रीर जीविका की उपयुक्त व्यवस्था न होने से उनके रहन-सहन का स्तर भी निम्न है। यदि इन च्रेग में उद्योगों का चाल किया जाता, जैमे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, दिल्ला भागत ग्रोर पजाव के कुछ क्थान, तो देश म उपलब्ध गावनों का श्रीर ग्रब्हा उपयोग किया जा सकता था, (४) हमारे देश में उप्योगों की जैभी व्यवस्था है वह युद्धकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। युद्ध के समय बमार्गा में इमिन भारी च्रति होने की सभावना है। यदि उत्राग कुछ क्थाना पर केन्द्रित होने की श्रपेक्ता वहें चेत्र में वितरित हाता तो इस प्रकृत का भय ग्रपेनाकृत कम रहता।

श्राधुनिक प्रवृति-यद्यवि स्थानीकरण की दृष्टि में भारतीय उद्योग में प्रनेक टोप हैं परंनु इधर कुछ वर्षों से स्थिति में नुधार होने की समावना दिगाई देती है। सूती उद्योग के लिए ज्यारभ में प्रमाई नगर जोर उनका समीपवर्ती जैप विरोप महरवपूर्ण समका जाता था परन्तु धीरे-घीर मन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश श्रोर ग्रन्य स्पानों में सती उन्नेग के नने कारमाने नोले गये हैं। इसमें बम्बई का महत्व कमश कम होता गया। यत्रवि वस्पई ग्राम भी पहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है अन्य स्थाना ने भी श्राना महत्त्र पटा लिया है। चीनी उद्योग ने सम्प्रध मे यन मी उत्तर प्रदेश स्रोर निहार प्रमुख है परन्तु मद्रास, नम्पर्ड श्रीर मृतपूर्व रियासतों में भी इस उदाग की श्रोर श्राकर्पण बढा है। १६३१-३२ में कुल ३२ चींनी के कारपानों मे २६ कारपाने उत्तर प्रदेश श्रीर विहार में थे परन्त १६४२-५१ में कुल १३४ कारलानों मे ने इन दोनो राज्यों मे केवल ६३ कारताने ये। १६३१-३२ श्रोर १६५२-५३ के बीच मद्राप्त मे चीनी के कारसानों की संख्या २ से बढकर १३, बम्नई में १ से बढकर १४ श्रोर खण्ड 'ख' रास्यों में जहीं एक मी कारखाना नहीं या १२ हो गई। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश श्रीर निहार श्रव भी महत्वपूर्ण राज्य है परन्तु श्रन्य राज्यों में भी चीनी के कारखाने खुल गये है स्रोर उनका भी महत्त्व कुछ बढ गया है।

जहीं तक नागज के उद्योग का प्रश्न है इसके कारखानों की स्थापना सर्व-प्रथम बगाल में हुई जिसका मुख्य कारण कोयले की पूर्ति की सुविधा थी। कारखानों में कागज वनाने के लिए हिमालप के पहाड़ी च्रेत्रों से प्राय ६०० मील दूर से सवाई धास लाई जाती थी परन्तु चूँ कि एक टन कागज बनाने में २३ टन घास श्रीर ५ टन कोयले की आवश्यकता होती थी इसलिए कोयले को प्रायमिकता दी गई। कोयले के चेत्र के निकट कारखाना स्थापित करना श्रिषक उपयुक्त सममा गया। परन्तु वीरे-घीरे वॉस श्रीर विजली का प्रयोग होने खगा। इससे कागज के कारखाने श्रान्य स्थानों को हटाये गये। सिमेट उद्योग सर्वप्रथम मन्य-प्रदेश श्रीर राजपूताना में स्थापित किया गया परन्तु घीरे-घीरे सिमेट उद्योग के कारखाने उन चेत्रों में स्थापित होने लगे जो या तो सिमेट का उपभोग करनेवाले चेत्र हैं या सिमेट का उपभोग करनेवाले चेत्र हैं या सिमेट का उपभोग करनेवाले चेत्रों के निकट पडते हैं।

उद्योगों की स्थागना में उपर्युक्त वितरण के अने क कारण है जैसे (१) स्वदेशी बाजार का महत्व बढना, परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि तथा देश के आन्तरिक मागो में उन्य बाजार की सुविधाओं की प्राप्त, (२) उत्पादन प्रविधि में विकास जैसा कि कागज के उत्पादन के उन्यन्ध म हुआ, (३) उत्पादकों का विनाशकारी स्पर्धा नीति का सविचार त्याग तथा उद्योगों की स्थापना में सुधार की प्रवृत्ति जैसा कि सिमेन्ट के उद्योगों में दिखाई पढ़ा है, (४) देशी रियासतों का जो कि 'ल' राज्य कहलाते हैं उद्योगों को अपनी और आकृष्ट करने की नीति का अनुसरण करना जिसके अन्तर्गत सब प्रकार की सुविधाये प्रदान करना जैसे अम सम्यन्थी उदार-कानून बनाना, तथा उनकी पूँजी में भाग लेना आदि, और (५) हाल में लागू नी हुई उद्योगा को इन्डस्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये जाने की सरकार की नीति इत्यादि।

सरकार की नीति १६५१ के उद्योग (विकास एवम् नियम) कान्न के श्रनुस्त मारत सरकार का उद्योग के स्थान-निर्धारण पर पूरा नियत्रण रखने का श्रविकार है। कारखानों को श्रपनी रिक्ट्री करनी पढ़ती है श्रीर श्रपना उत्पादन या उत्पदान शक्ति में वृद्धि करने से पूर्व श्रावश्यक श्रनुमित लेनी पहती है। प्रत्येक श्रीशोभिक इकाई श्रथमा कारखाने के पास लाइसेन्स होता है। लाइसेन्स देने-वाली समिति लाइसेंस देते समय उद्योग कान्न के श्रतर्गत कारखानों के श्राकार-प्रकार श्रीर स्थान इत्यादि का निश्चित विवरण देती है। चीनों के कुछ कारखानों को श्रनुक्ल स्थानों पर ह्याने के लिए यह समिति पहले ही श्रनुमित दे चुकी है श्रीर स्ती मिलों को कपड़े की बुनाई के लिए वहीं नयी शाखा खोलने की श्रनुमित देना श्रस्वीकार भी कर चुकी है।

कुछ उद्योगों का लाइसेन्स इसिलये श्रस्थीकार र दिया गया है कि जहाँ नम कारखाना खोलने का निश्चय था वहाँ पहले से ही श्रिषक कारखाने या तो रिपत ये श्रयवा जो स्थान ग्रावेटन पत्र में कारखना खोलने का बताया गया था लाडसेन्स देने वाली समिति द्वारा उपयुक्त नहीं समक्ता गया। लाइमेन्स देने में उन श्रावेदनों को प्राथमिकता दी जाती है जो किसी नये उपयुक्त स्थान

पर कारखाना सोलने के लिये होती है। उद्यागों के स्थान-निर्धारण की सदकारी नीति का उद्देश्य बड़े करनों श्रोर नगरों में उद्योगों के श्रधिक जमाव को पटाना है। सरकार का उद्देश्य है कि जिन राख्यों में पहले ही श्रपेन्नाकृत श्रिधर कारखाने खोले जा चुके रें वहां श्रीर श्राधिक कारखानों को स्थापित न होने दिवा जात । इसके विपरीत नये कारगानों को उन चेत्रों की छोर छारूष्ट फिया जान जिनका ग्रभी विशास नहीं हुया है। परन्तु भाग्तीय उन्नेगों के उचित स्थानीय-करण की ममस्या केवल लाइनेन्स देने की व्यवस्था में ही इल नहीं की जा सकती है। उद्योगपति पिछडे हए श्रीर कम विकसित चेत्रां में नए कारपाने पोलना नहीं चाहते हैं इसना एक कारण तो उनकी पूर्व धारणा है। मकती है परनत वास्तव मे बात यह है कि इन चेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए न निजली की मुविवा मिलती है, न कच्चे माल की श्रीर न उपयुक्त अम की । इन पिछ्टें श्रीर विरक्षित चेत्रों ती श्रान उपोगों को श्राकृष्ट करने के लिये यह श्रावश्यक है कि (१) इन चेत्रों रा विकास किया जाय जिसमें उद्योगपति इनकी श्रीर श्राकुष्ट हो सकें स्रीर (२) स्रारम्भ में उद्योगपतियों का कम से कम कुछ सुविवार्यें दी जार्य, जैसे भूमि रियायती टर पर दी जाय, रेलवे का माझा रम किया जाय, श्रीर जहाँ त्रावश्यक हो नगट द्रवा ने महायता की जाय। भारत में उन्योगों के स्थान-निर्वारण की समस्या तभी इन वी जा सकती है जन सरकार इन सन वालीं को व्यान में रखनर एक उत्तरोत्तर निकासमान नीति श्रवनाये।



म्प्रध्यारा २७

युक्तिकरण

युक्तिकरण उद्योग की कार्यन्नमता में वृद्धि करने श्रीर उत्पादन व्यय को घटाने की लम्बी प्रक्रिया है। किसी उद्योग के युक्तिकरण से श्रमिप्राय यह है कि कारखाने में पुरानी मग्रीनो के स्थान पर श्राधुनिक मशीने लगाई जाएँ, नए टेविनकल सुवार किए जाएँ, अमिकों की नख्या कम करने के लिए अम बचाने के उपायों तथा स्वचालित मशीनो का उपयोग किया जाए ग्रीर उद्योग को व्यर्थ की प्रतियोगिता से बचाने के लिए उसके सगठन में सुघार करके तथा उसकी व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार पर सर्गाठत करके उत्पादन कार्य की गति में वृद्धि की जाय। "युक्तिकरण का यर्थ यह है कि कार्य करने की प्राचीन परिपाटी, निश्चित क्रम तथा श्रवुमविक नियमो श्रीर शोधनो के स्थान पर ऐसे ढग का प्रयोग होने लगे जो कि वर्षों के वेज्ञानिक अध्ययन के परिखाम हैं श्रीर जिनका ध्येय साधनों को साध्यों के साथ ग्राधिकतम उपयुक्तता के साथ सयोजित करने का है जिससे कि उत्पत्ति के प्रयत्न की प्रत्येक इकाई का श्रिषकतम लाभकारी परिगाम हो। 133

युक्तिकरण का उद्देश्य उत्पादन-व्यय घटाना, उत्पादित वस्तु की प्रकार में मुघार करना श्रीर उत्पादक को हानि उठाने से बचाना है। यदि उद्योग का प्रबन्ध उचित रीति से किया जाय तो युक्तिकरण उपमोक्ता तथा अमिकों स्रौर उत्पादकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परन्तु वास्तव में यह देखा गया है कि युक्तिकरण से प्राप्त लाभ को उत्पादक स्वय ले लेते हैं ग्रीर वस्तुन्त्रों की प्रकार म सुधार करके तथा मूल्यों मे कमी करक उपमोक्ताश्रो श्रीर पारिश्रमिक बढाकर श्रमिको को लाम नहीं उठाने देते। श्रमिक युक्तिकरण का विरोध करते हैं, इसकी योजना से उनमे ऋसतीय फैलता है क्योंकि इसका परिणाम बेरोजगारी होता है। अमिक यह नहीं चाहते कि स्वचालित मशीनों से तथा अम बचाने के अन्य प्रयत्नी को श्रपनाकर श्रीर पुरानी मशीनों के स्थान पर नवीन श्राधुनिक मशीनों का उपयोग कर अनेक श्रमिको को वेरोजगार कर दिया जाए। इसी कारण श्रमिको ने प्रायः युक्ति प्रस्मा का विरोध किया है। श्रमिकों की यह माँग बहुत कुछ न्याय सगत है क्योंकि अतीत में युक्तिकरण का वह पूर्ण लाभ नहीं उठा छके हैं। परन्तु षदि उत्योग के युक्तिकरण से पारिश्रमिक बढना है श्रीर उपभोक्ताश्रों को कम नृत्य पर वस्तु मिल सन्ती है तो फिर श्रमिकों द्वारा इस प्रक्रिया के विरोध होने का कोई कारण नहीं रह जाता। बढे पैमाने के उद्योग केवल युक्तिकरण के द्वारा ही उन्नति कर सकते हैं और तभी श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं की स्थिति सुघर सकती है। वह सत्य है कि युक्तिकरण की योजना लागू करने से आरम्भ में कुछ वेरोज-गारी फैलतो है परन्तु उत्पादन व्या और वस्तु का मूल्य कम हो जाने से भविष्य में उपभोक्ताओं की मॉग में वृद्धि होगी। इस माग की पूर्ति के लिए उद्योग में ग्रीर ग्राधिक लोगों को रोजी मिलेगो। इससे सफ्ट है कि युक्तिकरण योजना लागू होने से फैलने वाली वेरोजगारी ऋल्पकालीन होती है और उद्योग के उन्नित करने क साथ इसे दूर किया जा सकता है। समस्या वास्तव में अमिक की आय और रहन-सहन के स्तर की है। यदि युक्तिकरण के साथ पारिश्रमिक में भी वृद्धि होती है तो इससे अभिनो की ऋाय में वृद्धि होती है और रहन-सहन के स्तर में भी सवार होता है। इस रूप में इस प्रक्रिया का उद्योग चेत्र में स्वागत करना चाहिए। ग्रात में यह एक महत्वपूर्ण एवम् विचारणीय प्रश्न है कि यदि भारतीय उद्योग का युक्तिकरण न किया गना तो विश्व बाजार की प्रतियोगिता मे यह विदेशों की सुसगठित उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना नही कर सकेगा। यदि श्रीमक युक्तिकरण का विरोध करते हैं तो इसका एक ही परिणाम हो नकता है कि यनेक कारखाने नष्ट हो जाएँगे, उनका बन्द करना पढ़ेगा श्रोर इससे श्रनेक अमिक वेरोजगार हो जाएँगे। वास्तव मे हमारे सम्मुख दो स्थितियाँ हैं कि या तो इम इस बात का समर्थन करें कि युक्तिकरण की योजना लागू कर अमिका तो सनियोजित एवम् नियत्रित श्राधार पर नौकरी से पृथक किया जाए श्रीर क्रमश नवीन कार्यों में स्थान दिया जाए या कडी प्रतियोगिता का सामना न कर सकने के नारण अनेक कारखाने बन्द करके बड़ी सख्या में अभिको को देरीजगार होने दिया जाए। हमारे सम्मुख समस्या रोजगार ऋोर वेरोलगार की नहीं विलेक एक प्रक्रिया लागू करने से योडे श्रमिकां की यांडे समय के लिए वेरोजगारी और दूसरी प्रक्रिया द्वारा प्राय सभी श्रमिको की ऋषिक समय तक वेरोजगारी की है। इसे इन दो प्रक्रियात्रों में से एक को चुनना है।

भारत में जब तक उत्पादित माल की खपत समन यी श्रीर पूर्ति के श्रमान के कारण उपभोक्ताश्रों को निभिन्न वस्तुश्रों के लिये श्रिषिक मूल्य देना पड़ता या तब तक युक्तिकरण की समस्या सम्मवत. इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। यदि वस्तुश्रों का मूल्य श्रिषक रहता तो मिल मालिकों को युक्तिकरण की श्रावश्यकता का श्रानुमव नहीं होता। मिल मालिकों ने प्रति मशीन श्रिषक व्यक्तियों को कार्य में लगाया श्रीर पुरानी तथा व्यर्थ हुई मशीनों से कार्य लेकर भी लाभ उठाया।

परन्तु जब से बाजार में बस्तुयों की पूर्ति में वृद्धि हुई है ग्रीर उपमोक्ता वस्तुय्रों का ग्राधिक मूल्य देने को प्रश्तुत नहीं है तम से युक्तिकरण की ग्रावश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। मिल मालिक ग्रापन। ग्रावश्यकता से ग्राधिक श्रमिकों को भाग दे सकने में ग्रामभर्थ में श्रीर श्रमिकों के स्थान पर मशानों का उपयोग ग्रानिमार्य हो गया है। यदि अपभोक्ता वस्तुश्रों का ग्राधिक मूल्य देने को प्रस्तुत होते तो यह स्थित उत्पन्न नहीं होती परन्तु उपभोक्ता उसके लिए प्रस्तुत नहीं है इसलिए उत्पादित वस्तु का मूल्य कम करने के लिये उत्पादन-ज्यय कम करने श्रीर ग्रपने लाभ के ग्रश में वृद्धि करने की हिए से उत्पादक को युक्तिकरण का सहारा लेना पहता है।

श्रीद्योगिक विकास समिति की योजना—श्रीद्योगिक विकास समिति ने १६५१ के श्रारम्भ म युक्तिकरण् की समस्या पर विचार किया श्रीर इस बात की स्वीकार किया कि उत्पादन न्यय घटाने श्रीर भारतीय उद्योग की कार्य ज्ञमता में वृद्धि करने के लिए युक्तिकरण् श्रावश्यक है। परन्तु कमिति ने इसके साथ ही इस बात की भी माना कि श्रमिकों के दिलां की रक्ता करना श्रावश्यक है तथा युक्तिकरण् की प्रक्रिया की तीम गति से नहीं लागू किया जाना चाहिये। समिति ने निम्नलिसित निग्य किए:—

- (१) युक्ति करणा योजना लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इससे वेरोजगार होन वाले अभिकों की सख्या यथासम्भव कम करने के लिए कार्यवाही की लावे। युक्तिकरण के फलस्वरूप होने वाली छटनी छोर वेरोजगारी को कम करने के लिए समिति ने यह सुमाव दिये हैं कि (छा) कर्मचारी को मृत्यु, पदनिवृति इत्यादि के कारण रिक्त स्थानों का पूर्ति कुछ समय के लिए स्थिगत कर वो लाय, (व) अन्य निमागों म कार्य करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों को बिना वेतन में कभी किये हुये श्रीर निना गत नौकरी के कम को वोहे हुये कार्य दिया जाये, (स) स्वेन्छा से कार्य छोड़ने वाले कर्मचारियों को उचित मुआवजा दिया जाये, (स) स्वेन्छा से कार्य छोड़ने वाले कर्मचारियों को उचित मुआवजा दिया जाये और (द) टेक्सनकल सुधारों के कारण बेरोजगार हुये अभिकों को खपाने के लिये जहाँ समय हो कार्य में वृद्धि की जाय।
- (२) प्रति इकाई उत्पादन की स्टैन्डर्ड मात्रा निश्चित की जानी चाहिये श्रीर श्रीमको का प्रमाणीकरण होना चाहिये। यदि किसी प्रकार का मतमेद हो तो उसकी जाँच होनी चाहिये श्रोर स्टेन्डर्ड होनो पहाँ के विशेषको द्वारा निश्चित किया जाना चाहिये।
- (3) सम्मन्वित उद्योग की रियति श्रोर कार्य की मात्रा इत्यादि को श्रोर समान उत्योगों के श्रनुभयों को ध्यान में रखते हुये नई प्रकार की मशोनी को

लगाने से उत्पन्न टेकनिक्ल परिवर्तनों का कुछ समय तक परीइण किया जाना चाहिये।

- (४) जिन श्रमिको की छुटनी की जाय उनके पुनर्वास के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। श्रमिकों को ट्रेनिंग देने ख्रीर ट्रेनिंग की प्रविध में जीवन-निर्वाह की न्यवस्था करने की योजना मालिको तथा श्रमिकों द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण की जानी चाहिए।
- (५) वेतन अथवा पारिश्रमिक में वृद्धि करके श्रामिक को भी युक्तिकरण के लाम में से भाग देना चाहिए।

इस योजना में युक्तिकरण के महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है परन्तु उसके दुष्परिणामी जैसे वेरोजगारी, श्रीमको का शोपण श्रीर प्रधिक कार्य लेकर भी वेतन में वृद्धि न करने की समस्या को टालने ना प्रप्रत्न किया गया है। मालिकों तथा श्रीमको के प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। विभिन्न राज्य सरकार श्रीपने-श्रपने लेनों में उत्योगों के युक्तिकरण की पोजनाश्री का परीक्षण कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस समस्या पर त्रिदलीय श्रम सम्मेलनों में विचार किया गया है श्रीर स्ती तथा चीनी उद्योग के युक्तिकरण का विशेषजों ने वैज्ञानिक श्राधार पर श्राध्ययन किया है।

श्रपील पंचन्यायालयों के निर्णय—भारत में श्रम श्रपील पचन्यायालय के निर्णुयों में दिये गये सिदान्तों के आधार पर ही भारतीय उद्योगों में अमिकों की छटनी की जाती है। इन्हीं चिद्धान्तों के अनुसार यह निरुचय किया जाता है कि किस प्रकार त्रोर क्तिने अभिनों की छटनी की जाय। पचन्यायालय के निर्णयों मे कहा गया है कि छटनी करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के व्यवस्थापकों पर है। यदि उद्योग के व्यवस्थापक युक्तिकरण श्रथवा वचत करने या श्रन्य पर्याप्त कारणों के त्रावार पर यह सिद्ध कर देते हैं कि छटनी की जानी चाहिए तो इसके परचात् इस परन पर विचार करना श्रावश्यक है कि किसी सीमा तक छटनी की जायगी, इस विषय में इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या व्यवस्थापको द्वारा श्रमिको की छटनी न्यायसगत कार्यवाही है, वहीं वह अपने अनुचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो छटनी नहीं कर गहे हैं। छटनी करने के परिणाम स्वरूप बचे हुये कार्य करने वाला पर प्रार्व भार बढ़ाना मिल मालिकों की श्रमिकों के प्रांत श्रनीति श्रोर श्रन्याय तथा स्वार्थ का एक उदाहरख है। छटनी करने की श्रनुमति नेवल तभी दी जाती है जब यह खिद हो जाता है कि व्यवस्था-पकों की मोंग न्यायसगत है, उसका उद्देश्य अनुचित स्वार्थ साधन नहीं है श्रीर किसी गुप्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए छटनी नहीं की जा नहीं है।

इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि छटनी लागू करने में व्यवस्थापकों को दो महत्वपूर्ण सिद्धान्ता को मानना पडेगा-(१) नई मर्ती के अमिक की छटनी पहले की जायगा और (२) यदि उत्रोग में नई मर्ती हो और यटि छटनी में निकाले गये योग्य अभिक प्राप्त हो सके तो नियुक्ति में उन्हें प्राथिमकता दी जायगी। अपील पचन्यायालय के निर्णयों में यह िखान्त प्रतिपादित ।कया गया है कि कोई कम्पनी केवल लामाश कम हो जाने के कारण श्रपने श्रमिकी की छटनी नहीं कर सकती है यदि वाजार में उत्पादित माल की माँग कम है या कब्चे माल के ग्रमाव के कारण व्यापार में ग्रल्पकालीन गतिरोध श्रा जाय वो ऐसी स्थिति में मालिक को श्रमिको की छटनी कर उनकी श्राय छीन लेने की अनुमित नहीं दी जा सकती है। यदि उद्योग अथवा कम्पनी के स्थायी आदेशों में व्यवस्था हो तो मालिक ऐशी स्थिति में मास में कुछ दिन कारखाने में बैठकी करा सकता है। स्थायी आदेशों के अनुसार वैठकी कराने से ३३ वीं घाग का उल्लंघन नहीं होता है। घाटे पर चलने वाले कारखाने को बन्द कर देने का मालिक को पूरा त्राघिकार है परन्तु यदि पचन्यायालय के सम्मुख मामला प्रस्तुत होने की अविध में ऐसी दिथति आ जाय तो कारखाना वन्ट करने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी भ्रावश्यक है।

श्रपील पचन्यायालय के निर्णयों के आधार पर विकसित प्रणाली काफी सितोषजनक रही है परन्तु श्रमिकों की शिकायत है कि (श्र) मालिक श्रपनी स्पिति का दुरुपयोग करते हैं और श्रावश्यकता न रहते हुए भी श्रमिकों की छटनी की काती है श्रीर (व) इससे काफी बड़ी सख्या में श्रमिक वेरोजगार हो गये हैं। इसके जाती है श्रीर (व) इससे काफी बड़ी सख्या में श्रमिक वेरोजगार हो गये हैं। इसके विपरीत मालिकों की शिकायत है कि उन पर श्रनेक ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं विपरीत मालिकों की शिकायत है कि उन पर श्रनेक ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिससे उत्पादन ब्यय को कम नहीं किया जा सका है श्रीर श्रावश्यकता न रहते हुए भी उन्हें श्रिधक श्रमिकों को कार्य पर लगाये रखना पड़ता है।

सरकारी नीति—मारत सरकार की नीति युक्तिकरण को प्रोत्साहित करने की है (आ) यदि किसी उत्पादन इकाई के मालिक और अमिक टोनो परस्पर करने की है (आ) यदि किसी उत्पादन इकाई के मालिक और अमिक टोनो परस्पर इस बात को स्वीकार करते हैं अथवा (ब) औद्योगिक विकास समिति की योजना इस बात को स्वीकार करते हैं अथवा (ब) औद्योगिक विकास समिति की योजना के अनुसार युक्तिकरण आवश्यक है और अपील पचन्यायालय के निर्णयों के अग्रनकुल है। इन निर्णयों में यह भी दिया हुआ है कि अमिक को आल्पकाल के अग्रनकुल है। इन निर्णयों में यह भी दिया हुआ है कि अमिक को आल्पकाल के लिये कार्य से प्रथक कर देने के बदले में अथवा छटनी कर देने के बदले में लिये कार्य से प्रथक कर देने के बदले में अथवा छटनी कर देने के बदले में हिला मालिक आवश्यक हरजाना देता है हरजाना देना पडेगा। जब तक कोई मिल मालिक आवश्यक हरजाना देता है अग्रेर दी हुई सपूर्ण बातों को स्वीकार करता है तो युक्तिकरण में कोई आपित नहीं की आर दी हुई सपूर्ण बातों को स्वीकार करता है तो युक्तिकरण में कोई आपित नहीं की जा सकती। मार्च १६५४ में लोक सभा के तरकालीन विच मन्त्री श्री चिन्तामणि जा सकती। मार्च १६५४ में लोक सभा के तरकालीन विच मन्त्री श्री चिन्तामणि

देशमुख ने केन्द्रीय सरकार के प्रजट पर वार्टायवाद का उत्तर देते हुय कहा था कि ---

"सगीत उद्योगा में २५ लाख में कुछ थाडे ने श्रविक व्यक्ति लगे हुये हैं जिनक सम्यूष में युक्तिकरण मा प्रश्न उठाया जाता है। यह तो स्मिनिदित है कि उद्योगों में रोजगार के प्रमुखों की पर्याप्त मृदि किये बिना मुगल व्यवस्था की प्रवृत्ति प्रदेने के मारण तथा जन सख्या की वृष्ट के फलस्प्तक्त श्रमिकों की निरन्तर बढ़ती हुई सदया मो कार्य देना सम्भव न हा सकेगा। इसके श्रतिरिक्त प्राप्य शार्यिक व्यवस्था के श्रन्तर्गत श्रर्थिक सख्या में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हे पूर्ण शाक्त भर कार्य करने का श्रवसर नहा प्राप्त है। इस मात से तो सभी सदमन होगे कि प्राचागिक विकास के प्रति अदूरदर्शिता का परिचय देते हुये कार्य करने के श्रासर में वृद्धि करना उचित न होगा। मेरा ऐसे निश्मास है कि युक्तिकरण द्वारा श्रर्थायी ह्य से स्थानान्तिक व्यक्तियों का जी ज्ञति हाती है यह जनता के हित के लिये श्रार्थिक व्यवस्था के प्रसार को नीति द्वारा पूर्ण हो जाता है। यह इस बात का एक श्रोर उटाहरण है जिसमें सामाजिक न्याय की यांछनीयता को श्रार्थिक महत्ता के श्रार्थ सुरुमना पहता है। ।

"सभासदों का यह ता जात होगा ही कि हाल में ऐसे कानून बना दिये गये हैं जिनके श्रन्वर्गत श्रीमकों का खायकारा प्राप्त करने पर सदायता तथा कार्य करने के काल में यदि श्रस्पायी रूप में काय से प्रयक्त होना पहें तो भी उसका हरजाना दिया जायगा। सभा सदो को स्मरण हागा कि एक उद्याग निशेष में ऐसी स्थिति उला हो गई थी कि सरकार ने लाक सभा की बेठक का समय न होने के कारण श्रम्यादेश द्वारा इन कानूनों का प्रचलित कर दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार ऐसे श्रमिकों के हित की रज्ञा के लिये जो छटनी के अन्तर्गत आ गये हैं बहुत श्रिषिक महत्व देती हैं। मने पहिले भी कहा है कि अस्थायी रूप से श्रपने कार पर से इटाये हुये अभिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जा कुछ सम्भव हो, किया जाना चाहिये, पर मेरा मत है कि हमें ऐसी नीति का श्रनुसरण न करना चाहिये जिससे प्रौद्योगिक विकास अवस्द हो जाय श्रीर कार्य करने के त्रवसरों का विकास भी बक जाय। किसी भी समय हर उद्योग में विभिन्न ज्ञमता चाले अनेक उपक्रम उत्पादन-कार्य करते रहते हैं। उनमें से कुछ तो हाल में ही श्रारम्भ िये हुये होते हैं या श्रारम्भ होते रहते हैं, तुछ मे प्रसरण फ्रीर कुछ मे एकुचन की प्रति लिखत होती है और कुछ की ऐसी स्थिति होती है कि उनका श्चन्त होता रहता है। इसलिये उद्योग के समुचित विकास श्रीर वृद्धि के लिये यह श्रावरपक है कि प्रत्येक उपकम द्वारा श्रपनी परिस्थिति के श्रनुसार नियुक्त श्रमिकी की सख्या के सम्बन्ध में कुछ लोच श्रवश्य रहे। हमें कुल कार्य करने के श्रवसरी के योग पर विशेष ध्यान देना चाहिये। वह नीति जो श्रपने श्राश्वासनों द्वारा छटनी श्रसभव करती है नये दगों से श्रन्य उपक्रमों द्वारा उत्पादन के विकास श्रीर वृद्धि को निश्चयं ही रोक देगी श्रोर समयत उसके द्वारा देश की श्रार्थिक व्यवस्था को जिसमें अमिक श्रवश्य सम्मिलित हैं उस ज्ञति की तुलना में जिसे बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है कहीं श्रिषक ज्ञति पहुँचावेगी"।

मारत के विस्त मन्त्री द्वारा स्थिति का यह ऐतिहासिक वर्णन इस बात को स्पन्ट करता है कि हमें एक या दो उपक्रमो मे छुटनी किये जाने से चिन्तित नहीं होना चाहिये, वरन् हमें सम्पूर्ण स्थिति को विस्तृत हिन्दिकीण से देखना चाहिये। यदि हम ऐसा करेंने तो युक्तिकरण हमारे लिये (१) बढती हुई जन-सख्या के लिये कायं के श्रवसर प्रदान करने का, (२) श्रमिकों की श्राय तथा उनके रहन-सहन के स्तर को बढाने का श्रीर (३) उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने तथा प्रौद्योगिक विकास निश्चय करने का साधन होगा। परन्तु यह श्रावश्यक है कि व्यक्तिगत श्रमिकों की श्रावश्यक कठिनाइया से रच्चा की जाय। इस सबन्ध में कार्य से प्रथक किये जाने पर हरजाना देने का कानून द्वारा ही प्रवन्ध कर दिया है श्रीर उस श्रमिक विशेष के लिये श्रन्थ कोई कार्य द्व द लेने का भी प्रयस्न किया जाना चाहिये।

सूती मिल उद्योग—१६२६-२७ में प्रशुक्त मण्डल ने इस श्रोर ध्यान श्राकिपित किया कि सूती मिल उद्योग में श्रावश्यकता से श्रिषक पूँ जी एकत्र हो रही है श्रीर उसमें श्रावश्यकता से श्रिषक श्रीमक लगे हुए हैं। बोर्ड के कथनान्तुसार १६१७ श्रीर १६२१ के मध्य उद्योग की इल पूँ जी २० ८४ करोड़ से बढ़-कर ४० ६८ करोड़ हो गई जो उस समय उद्योग की मशान इत्यादि सपत्ति को देखते हुए बहुत श्रिषक थी। बोर्ड इन सब बातो का श्रध्ययन कर इस परिणाम पर पहुँचा कि भारतीय सूती मिलों में श्रम का पूर्ण उपयोग नही किया जा रहा है। भारत में एक श्रीमक १८०० तकुश्रों में कार्य करता है जब कि जापान का श्रीमक १४० में, इक्क्लैंड का श्रीमक ५४० से ६०० में श्रीर श्रमरीका का श्रीमक ११२० तकुश्रों में कार्य करता है। मारत में प्रत्येक बुनकर के पास श्रीसत न कर्घ हैं जब कि इनकी सख्या जापान में २३, विटेन में ४ से ६ श्रीर श्रमरीका में ६ हैं। इन दोषों के कारण भारतीय सूती मिलों में उत्पादन ब्यय श्रीषक होता है। प्रशुक्त महल की सिफारिशों के श्राधार पर सूती मिल उद्योग ने बनई की कुछ मिलों में लागु करने के लिए श्रीककरण की एक योजना निर्माण की। इस योजना की विशेषता यह थी कि एक ब्यक्ति एक के स्थान पर दो कातने की मशीन चलाएगा श्रीर

एक बुनकर टो के स्थान पर ३ या ४ क्यें चलायेगा। परन्तु श्रमिकों ने इस योजना का विरोध किया श्रीर इसे लागू नहीं किया जा सका। १६३२ में जाँच करने के पश्चात् प्रशुल्क मण्डल ने पता लगाया कि यदि यह योजना लागू की गई होती तो उत्पादन न्यय में १७ से २० प्रतिशत तक कमी हो जाती। स्ती मिल उद्योग ने उत्पादिन वस्तु के प्रमाणीकरण, क्रय श्रीर विक्रय, न्यवसाय के पुर्नसगठन श्रीर श्राधिक हिंद्र से श्रमुपयुक्त मशीनों को ग्रलग करने के लिए ७ मेनेजिंग एजेन्सियों को एक में एकत्रित करने की योजना निर्माण की। इन एजेन्सियों के पास ३४ मिल थीं। इस योजना में यह न्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक मिल को पूर्व निर्धारित मूल्य पर ले लिया जायगा, मूल्य साधारण श्रेयरों में दिया जायगा, न विके हुये माल का स्टाक बाजार भाव पर क्रय कर लिया जायगा श्रीर नाम के जिए कुछ धनराशि नहीं टी जायगी। परन्तु विक्त के श्रमाव के कारण योजना कार्यन्वित नहीं की जा सकी।

इन योजनार्थ्यों के विफल हो जाने पर भी सूती मिल उद्योग ने निरन्तर युक्ति नरण योजना लागू करने का प्रयत्न किया है। बम्पई श्रम समिति द्वारा प्रचलित की गई प्रश्नायली के उत्तर में बम्बई मिल मालिक छष ने इस बात पर महत्व दिया कि भारतीय उत्रोग ने उत्पादन में सभी श्राधुनिक उपायों को अपनाया है। अपनेक स्ती मिलों की पूँजी भी घटाई गई ख्रौर १९२० श्रीर १९४० के बीच स्ती मिल उद्योग ने प्रशुलक मग्रहल के चुक्ताव के श्रनुसार मोटे श्रीर घटिया प्रकार के कपडे के स्थान पर श्रब्छे प्रकार के कपडों का उत्पादन बढ़ाने की नीवि श्रपनाई। परन्तु इस सुघारों के होते हुये भी स्ती कपड़ा उद्योग की उत्पादन च्मता कम है श्रीर उसके युक्तिकरण की श्रावश्यकता है। स्ती मिल उद्योग सम्बन्धी वर्किंग पार्टी ने १९५२ में यह पता लगाया था कि लगभग १५० वर्तमान स्ती मिलें जो कि कुल मिलों की सख्या की लगभग ३३६% थीं, ऋार्यिक दृष्टि-कोण से श्रनुपयुक्त श्रीर हीन समता वाली मिलें थीं। ब्लोरूम के वाहन्डिंग विमाग में तथा रगाई विमाग से जिन मशीनों का प्रयोग हो रहा है वे अनुपयुक्त थीं। इस प्रकार कर्षों की सख्या के सम्बन्ध में जो प्रत्येक श्रमिक की देखरेख में या वर्किंग पार्टी ने पता लगाय। या कि दिक्षी की एक मिला में श्रौर मद्रास की दो मिलों में स्वचालित कर्षे ही लगाये गये हैं श्रौर एक एक विनने वाला अमिक ४, ६, ८ स्रौर १६ कघों पर कार्य करता है। स्रहमदाबाट की एक मित्त में १८ कर्षों पर एक अभिक और वम्बई की एक अन्य मिल में ६ कर्षे पर एक अमिक कार्य करता है। फिर भी श्रघिकाश मिलें उत्पादन ज्ञमता में हीन हैं श्रीर पुरानी मशीना का प्रयोग करती हैं।

वर्किङ्ग पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि उन मिलों का कार्य जो स्वचालित कर्षों का प्रयोग कर रही है सतोषननक हैं। अन्य मिलों में भी स्वचालित कर्षों के 'आधुनिक और मशोनों के प्रयोग किये जाने तथा उत्पादन का युक्तिकरण करने की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। सितम्प्रर १९५४ में कानूनगो कमेटी ने यह सिकारिश की यी कि उनोगों के सभी विभागों जैसे मिलों, शिक्त स्वालित कर्षां, हाथ कर्षों आदि का युक्तिकरण १५ वपा के अन्तर्गत हो जाना चाहिये। विकिंग पार्टी ने युक्तिकरण की अविष केवल १० वर्ष ही रक्खी थी।

उत्तर प्रदेश में कानपुर की मूती-मिलों को विशेष कठिनाइयों का समना इसलिये करना पढ रहा है कि उन्होंने श्रपनी श्रावश्यकता से श्राधिक श्रीमकों को लगा रक्ला है। इससे यहाँ की मिलों का उत्पादन व्यय देश के श्रन्य मागों की भिलों की श्रपेचा बहुत श्रिधक है। यदि इनमे युक्तिकरण न किया गया तो इन मिलो के बन्द हो जाने का सय है। यह बड़े सीभारत की बात है कि श्रमिक श्रोर मालिक दोनो ही ने जून १६५४ में नैनीताल में हुई त्रिदलीय समा में इस बात को स्वीकार किया था कि कानपुर की सूती मिला के उत्पादन का युक्तिकरण् किया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक अभिक, जैसा कि बम्बई में हों रहा है, दो कर्यों के स्थान पर चार कर्यों पर कार्य करेगा स्रोर कार्य भार की मात्रा में भी सामान्यत. वृद्धिहो जायगी। इससे मिलों का बन्द होना रुक जायगा श्रीर श्रमिकों को बरवस वेकार न रहना पडेगा। इस योजना के सम्बन्य में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अम मत्री सम्पूर्णानन्दजी ने कहा था कि, "हाल में सेन्ट्रल डिस्प्रट्स एक्ट में जो सुधार हुआ है उसने मालिकों के लिये अतिरिक्त अमिकों की छुटनी करना हरजाना देकर श्रपेज्ञाकृत श्रधिक सरल कर दिया है। श्रनेकों 'मिल मालिक इसमें श्रपना लाभ देखेंगे कि वे छटनी करके हरजाना देकर ग्रपने मिल में स्थायी बचत कर लें। हमारी समस्या उन श्रीमकों की किसी प्रकार रक्षा करने की है जिनके छॉट दिये जाने का भय है। सरकार को युक्तिकरण की ऐसी योजना बनाने के निर्णय पर, जिसके अन्तर्गत ५००० और ६००० के मध्य [।] अनुमानित छाट दिये जाने वाले श्रमिकों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके, इस पृष्ठभूमि के समज्ञ विचार करना चाहिये"। कानपुर की अनेक मिलें जो अभी त्तक बढ़ी कठिनाई से दो शिफ्ट में कार्य कर पा रही थी अब तीन शिफ्ट में कार्य कर सकेंगी जिससे कार्य करने के अधिक अवसर पाप्त हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त यक्तिकरण की यह योजना कानपुर के सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की श्रीसत पारिश्रमिक जिसमें मेंहगाई भी सम्मिलित होगी, द्यु रु से बढ़ाकर ११५ रु प्रति मास और विशेष ज्ञमता वाले अभिकों के लिये १५० रु० प्रति मास कर सकेगी।

जूट उद्योग—पूट उद्योग भारत का सर्वाधिक सुसगिटत उद्योग है श्रोर श्रारम्भ में ही इस उपाग ने यह नीति श्रपनाई है कि मर्रानी का प्रयोग रोक कर तथा प्रति सताह कम घन्टे कार्य कर उत्पादन की मात्रा को श्रावश्यकता श्राधक न होने दे ताकि जिना जिका माल स्टाक म एकपित न होने पाव । द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जूट उद्योग के पास श्राद्योगिक सावन वाजार की कुल सेमींग ने कहां श्रिष्व थे। यह श्रतुमान लगाया गया था कि जाजार की कुल मान को जूट उद्योग अपना कुल मशोनों में से कवल एक चीपार्व का उपयोग करके पूरा कर सकता है। परन्तु वर्तमान स्थित जिल्कुल मिन्न है। यह श्राशा की जाती है कि भविष्य में जूट के सामान की मान में वृद्ध होगी पार जूट मिलों में इस समय जितनी मशीने है उन सन का उपयोग करना पड़िया। परन्तु योजना श्रायोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना में जूट उद्योग का श्रीर प्रसार करने की कोई व्यवस्था नहीं की है। वार्षिक वास्तविक उत्पादन शक्ति १६५५-५६ में भी १२ लाए दन ही रहेगी। १६५० ५१ में भी उत्पादन शक्ति इतनी ही थी। यदि उद्योग श्रापनी पूरी शक्ति से उत्पादन करे तो सारा उत्पादित माल घरेलू माँग श्रीर निर्यात करने में स्थ जायगा।

१६४२ की गमियों में भारत सरकार ने भारतीय जुट मिल मालिक सप को सुमाव । दया था कि वोयले तथा परिवद्दन का सरज्ञाण करने के लिए उद्योग का युक्तिकरण श्रावश्यक है। सरकार के कथनानुसार रेलवे विभाग जूट उद्योग के कुल वास्तविक उत्पादन को पश्चिमी मागो तक ले जाने की व्यवस्था कर सकने में प्रसमर्थ था। जाँच करने पर पता चला कि जुट की वस्तुश्रों की कुल माग, जिनमें देश के अन्दर का उपभोग मी समिलित है, लगभग ५५ हजार टन प्रति मास होगी जब कि कुल ६५ इजार टन माल का उत्पादन किया जा रहा था। इससे सफ्ट या कि उत्पादन में कमी की जानी चाहिए। मारत सरकार ने सुक्ताव ।दया कि उत्पादन कम करने के लिए केवल उन्हीं मिलों में उत्पादन कराया जाय जिनमें विद्युत सवालित मशीने हैं। भारतीय जूट मिला ने इस सुकाव को स्वीकार नई। किया ग्रीर युक्तिकरण की एक नवीन योजना लागू कर टी जिसके अनुसार बाय की बचत करने के लिए कायले के केन्द्रीय स्टाक स्थापित किए गये श्रीर कोयले की उपलब्ध मात्रा की पूर्ति को नियन्त्रित किया गया। तदपश्चात् एक 'समह योजना' लागू की गई जो १ जुलाई १६४४ से ३१ मार्च १६४६ तक प्रचलित रही। युक्तिकरण की इस योजना से उद्योग कोयले के ज्यय में बचत करने में चफल हुआ और कुछ मिलों को युद्ध की परिस्थितियों से विवश हो कर जो हानि उठानी पदी उसका और श्रिथिक समान वितरण किया जा सका ।

वर्तमान समय में अपनी पुरानी और घिसी हुई मशीनों को परिवर्तन करने के लिए और अन्यदेशों के उद्योगों की मॉित उत्पादन के विल्कुल आधुनिक उपायों का उपयोग करने के लिए जूट उद्योग को युक्तिकरण की योजना लागू करने की अत्यन्त आवश्यकता है। चूँ कि मारत के जूट उद्योग को विदेशी उत्पादकों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इसलिए अन्य देशों द्वारा प्रयुक्त प्राविधिक कुशलताओं का यहाँ भी उपयोग किया जाना चाहिए। मारत की कुछ मिलों ने आधुनिक मशीनों का उपयोग आरम्भ कर दिया है। उत्पादन व्यय कम करने के लिए अन्य उद्योगों को भी ऐसा करने की आवश्यकता है। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में दो सब से बड़ी कठिनाहयों यह हैं कि (१) इनके लिए ४० से ४५ करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय से उपलब्ध कर सकना कठिन है और (२) इन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने से लगभग ४० हजार अमिक वेरोजगार हो जायेंगे।

कोयला उद्योग—कोयला उद्योग में कोयले की छोटी-छोटी श्रीर श्राधिक हिन्द से अनुपयुक्त खानों को सम्मिलित कर एक बडी हकाई का रूप देने, विभिन्न उपायों से धातुशोधन के कार्य श्रानेवाले बिद्धया कोयले का सर्व्या करने श्रीर कोयले की खानों में मशीनों का उपयोग करने के लिए युक्तिकरण की योजना लागू करना श्रावश्यक है।

कोयला उद्योग में मशीनो का उपयोग करने से श्रिमियाय यह है कि खान में कोयला काटने श्रीर उसे नियत स्थान तक ले जाने के लिए मशीनो का प्रयोग किया जाय श्रीर कोयला निकालकर नियत स्थान तक ले जाने की दोनों कियाएं एाय-साथ हों। भारत में मशीनों का प्रयोग श्रमी बहुत कम हुश्रा है। १६४४ में कोयला निकालने की २१० मशीनों थीं जिनसे २१ लाख टन कोयला निकाला जाता था। १६३६ में इस प्रकार की केवल १८६ श्रीर १६३५ में केवल ६५ मशीनों थीं। १६५१ के मध्य तक भारत में ३७४ मशीनों से प्रति मास लगभग ५ लाख ६० हजार टन कोयला (श्रयांत् ७० लाख टन कोयला प्रतिवर्ष) निकाला गया जो श्रीसत मासिक उत्पादन का लगभग १९६ प्रतिशत था। भारतीय कोयला-खान समिति ने १६४६ में सिफारिश की कि मारतीय कोयले वी खानो में मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि मशीनों के उपयोग से ही उत्पादन शीन्न बहाया जा सकता है जो कि भविष्य के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है। वर्तमान में मशीनों के उपयोग के प्रति थोड़ी प्रतिकृत्वता होने के कारण शायद सस्ते श्रम की उपलब्धि है। जब श्रम महँगा एइने लगेगा, पारिश्रमिक बढने लगेगा तो श्रवश्य ही इस प्रतिकृत्वता में परिवर्तन होगा श्रीर तब मशीन श्रीर श्रम के बीच

उपयोगिता की दिष्ट से विचार कर उपयुक्त साधन र्छीटने के सम्बन्ध में निर्ण्य किया जा सकेगा। कोयला उद्योग के सम्बन्ध में १६५० में विकिङ्ग पार्टी ने सुक्ताव दिया कि खानों में मशीनों का उपयोग करने से ही सुनियोजित उपाय से शीघ उत्पादन बढाया जा सकता है और मविष्य में देश के श्रौद्योगीकरण की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति को जा सकती है। सम्पूर्ण व्यवस्था का सन्तुलित विकास करने के लिए यानों में शीव ही मशीने नहीं लगानी चाहिएँ। इसके लिए एक श्रविध निश्चित की जानी चाहिए। यह उचित नहीं है कि एक साथ समी खानों में मशीनों की सहातता से उत्पादन आरम्म कर दिया जाय। इसके लिए एक एक खान करके प्रगति करनी होगी। कमशः मशीनों का उपयोग बढाने पर मी कोयले की खान के श्रमिकों में वेरोजगारी फैल सकती है। विकट्ग पार्टी इस परिस्हाम पर पहुँची कि खानों में मशीनों का उपयोग करने में वेरो नगारी के भय में वाबा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मशीनों के उपयोग से हानियों की श्रपेत्रा लाभ नहीं श्रविक है। इसकी सफलता के लिए वर्किद्व पार्टी ने सुकाव दिया है कि (१) छोटी छोटी कोयले की सानों को कम से कम १० हजार टन प्रति मास उत्पादन करने वाली इकाई के रूप में सगठित कर दिया जाय श्रीर (२) कीयले की खाना में लगाई जानेवाली मशीनों का भारत में ही निर्माण किया जाय !

भारत के श्राधिकाश उद्योगों में कम ने कम तीन चेत्रों में युक्तिकरण की योजना लागू करना अत्यन्त आवश्यक है (१) कारखानों के स्थानीनकरण में सुधार, जैसे चीनी ग्रोर कुछ सीमा तक लोहे तथा इस्पात के कारखानों में। १६५१ के उद्योग (विकास एवम् नियमन) कानून के अन्तर्गत स्यापित लाइ-से।न्संग सिमति ने पूर्व मे ही चीनी के कुछ कारखानों को अधिक अच्छे स्थान पर हरा लेने की अनुमित देदी है। लोहे श्रीर इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में श्राशा की जाती है कि नये लोहे और इस्पात के कारखानें नये स्थानों पर स्थापित किए जार्थेगे, (२) उत्पाटन के उपायों में सुधार, जैसे गन्धक का व्यय कम करने के लिए चीनी उद्योग में, घातुशोधन के काम आने वाले विदया कीयले की बचाने के लिए लोहे तथा इत्पात के उद्योग में श्रीर उत्पादित माल का प्रकार सुधारने तथा उत्पादन व्यय घटाने के लिये उत्पादन के ढग में सुघार करने की त्रावर्यक्ता है, (३) कारखानों का श्रार्थिक टब्टि से उपयुक्त ढाँचा निश्चित करने ने लिए प्रति मशीन पीछे कार्य करने वाले अमिकों की सख्या मे कमी करने की ग्रावश्यकता है। मारत के लोहे तथा इस्पात, चीनी, सूती, कपड़ा, जूट तथा श्रन्य उद्योगा में प्रत्येक मशीन पर श्रावश्यकता से श्रधिक श्रमिक नियुक्त किये जाते हैं जिसके परिशामस्वरूप उत्पादन ब्यय श्रिषिक होता है श्रीर उद्योग की

अध्याय २८

वेरोजगारी की समस्या

यह त्राश्चर्यजनक बात है कि आर्थिक हिंद से बहुत कम विकित्त देश में वस्तुओं और विमिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के स्रमाव के लाय वेरोजगारी हो और बहुत बड़ी मान्ना में श्रम-शक्ति स्रप्रयुक्त पड़ी हो। मारत आर्थिक हिंद से बहुत कम विकास कर सका है परन्तु यहाँ वेरोजगारी भीषण रूप धारण किए हुए हैं। इस कारण मारत की राष्ट्रीय स्राय बहुत कम है, रहन-सहन का स्तर बहुत निम्न है और जनता दुखी तथा स्रसन्तुष्ट है। मारत में केवल शिच्चित लोगों और उद्योगों तथा कृषि चेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को ही वेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है वरन नागरिक एवम् ग्रामीण चेत्र की प्रायः सम्पूर्ण जनता इसके चगुल में फॅसी हुई है। पाश्चात्य देशों में भी वेरोजगारी है परन्तु उसका कारण व्यापार में मन्दी स्त्रा जाने से कुछ समय के लिए वस्तुओं के माँग की कमी है। इसके साथ ही वहाँ कुछ ऐसे कारखाने हें जो वर्ष में कुछ मास चलने के पश्चात् शेष मास बन्द रहते हैं और इन मासों में वहाँ वेरोजगारी फैल जाती है। पाय एक कार्य छोड़ने के पश्चात् तुरन्त दूसरा कार्य नहीं मिल पाता और इस बीच की स्रविध में भी एक प्रकार की स्रस्थानी वेरोजगारी रहती है तथा स्रन्य प्रवार की स्रविध ने वेरोजगारी होती है।

मारत में वेरोजगारी तथा आशिक रोजगारी अधिकाश जनता के जीवन का स्थायी अग बन चुके हैं। इसका कारण यह है कि देश की जन-सख्या में निरन्तर दृद्धि होती जा रही है ओर देश के आर्थिक साधनो का बहुत कम विकास किया गया है। गत कुछ वर्षों से इस समस्या ने गम्मीर स्थिति उत्पन्न कर ली है। प्रथम पचवर्षीय योजना में इसके निम्नलिखित काग्ण बताए गए हैं.—

(अ) जन-सख्या की तीव्र गति से वृद्धि,

- (व) श्राम्य उद्योगों का नष्ट हो जाना जिनमें त्रामों के बहुत से व्यक्तियों हो श्राशिक व्यवसाय प्राप्त हो जाता था,
- (स) व्यवसाय की दृष्टि से कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन चेत्रों का पर्याप्त विकास (यद्यपि गत ४० वर्षों में काफी विकास हुआ है फिर भी १६११ प्रचात् कृषि चेत्र में व्यवसायों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ३ प्रतिशत रही है),

(द) देश-विभाजन के परिणाम स्वरूप जन-सख्या ना बहुत बड़ी सख्या मे विस्थापित होना।

श्राकडा के श्रभाव में यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि भारत में वेरोजगारों या श्राशिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की सख्या कितनी है। कुछ अधिकारियों का अनुमान है कि प्रामों में जन-सख्या का लगभग ३० प्रतिशत वेरोजगार है श्रीर ऐसे व्यक्तियों की सख्या बहुत श्रीधक है जो श्राशिक रूप से रोजगार पाए हुए है। श्रन्य श्रनुमानों के श्रनुसार देश की कुल जन-सख्या आमीण एव नागरिक दोनों चेत्रों में वेरोजगार श्रीर श्राशिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की सख्या ५ या ६ करोड़ के बीच में है। यह वेरोजगारी की बहुत बडी सख्या है। पश्चिम के कुछ काफी विकसित देशों में समृद्धि के समय कुल जितने व्यक्तियों को व्यवसाय प्राप्त है उनके एक से तीन प्रतिशत से भी कम व्यक्ति वेरोजगार रहे हैं। परन्तु भारत की स्थिति विल्कुल भिन्न है। भारत के समृद्धि काल में व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों के श्रनुपात में वेरोजगारों की सख्या पाश्चात्य देशों के श्रधिकतम मन्दी के काल की तुलना में कहीं श्रधिक है।

"भारतीय समस्या का सम्बन्ध देश की सम्पूर्ण द्रार्थिक व्यवस्था की प्रकृति से हैं। इसिलिये इस पर विचार इसी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये। शिक्षित वर्ग की वेकारी की विशेष महत्ता के प्रदर्शन से, जो कि स्वामायिक मी है, इस वर्ग के विशेष मुखरित होने त्रीर राजनैतिक प्रभाव डालने की ज्ञमता रखने के कारण हम भ्रान्ति में पढ़ सकते हैं। वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक हानि उठाने वाले भूमि हीन रूपि तथा गैर-कृषि प्राम्य अमिक, नगर में रहने वाले समयिक अमिक, ग्राम्य तथा नगर के छोटे-छोटे उद्योगो में कार्य करने वाले अमिक, तथा फुटकर कार्य करने वाले दस्तकार इत्यादि हैं। इन सब से वे अमिक जो आर्थिक तथा सामाजिक हिन्दकोण से हीन हे सबसे अधिक हानि उठाते हैं। सामाजिक हिन्दकोण से पद्दिलित जातियाँ, आदिवासी तथा निकृष्ट दस्तकारी का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं?।

पाश्चात्य देशों मे वेरोजगारी एक अस्थायी समस्या के रूप में होती है श्रोर सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा ठीक समय पर कार्यवाई कर देने से उसके हल हो जाने की आशा रहती है परन्तु पाश्चात्य देशों मे प्रयुक्त उपायों द्वारा भारत की समस्या का हल नहीं किया जा सकता। भारत में इस समस्या को दीर्घ कालीन हिंग्डिंगे से हल करने के लिए यह आवश्यक होगा कि कृषि की भूमि का चेत्रफल बढ़ाने के साथ ही जनता को सुनियोजित करने और उस पर नियन्त्रण रखने, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने तथा औदोगिक सम्मावनाओं को विकसित

करने की आवश्यकता है। किसी भी सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रतिवर्ष १३ प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली जन सख्या को व्यवसाय दे सकेगी जब कि व्यवसाय के साधनों में भी इसी गति से वृद्धि नहीं होती। चूँ कि प्रवास के द्वारा जन सख्या को समस्या को सुलक्ताया नहीं जा सकता है इसलिए मभी को व्यवसाय का न्याय सगत अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि पर और औद्योगिक साधनों पर जन सख्या के दबाव को कम करने के लिए जनसख्या से वृद्धि को रोका जाए। परन्तु इस व्यवस्था को लागू करने में अधिक समय लगेगा और वेरोजगारी की समस्या को इतने समय तक विना इल किए छोड़ देना समय नहीं है।

प्रथम पचवर्षीय योजना ने कुछ नये न्यवसाय के श्रवसर प्रदान किये थे। परन्त योजना के तीसरे वर्ष से निरन्तर वेकारी के बढ़ते रहने के कारण आयोग को यह स्पष्ट हो गया कि देश के श्रोद्योगिक श्रीर श्रार्थिक विकास द्वारा इस समस्या ने सुलमाने के उपाय को सर्व-प्रधानता देन्। श्रावश्यक है। इसी हिन्दकीण से प्रथम योजना पर व्यय की जाने वाली धन राशि श्रवटूबर १६५३ मे १८० करोड रुपया बढ़ा दी गई जिससे कि नवीन विशेष योजनाओं के लिए, जो कि व्यवसाय के अवसरों की वृद्धि करेंगी और बढती हुई वेकारी रोकेगी, पर्यात वित्त प्राप्त हो एके। इसके ग्रातिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम को १९५३-५४ के गत निर्णय के अनुसार अन्त कर देने के स्थान पर पूर्ण योजना काल तक चालू रखने का भी निर्णय किया गया। बेकारी की समस्या को इल करने के पुनर्परीचित कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया कि (१) राज्य-विच निगम स्थापित किये जॉय, (२) केन्द्र से राज्यों को देश की दरिद्रता कम करने के लिए नई योजनायों के चालू करने के लिए विचीय सहायता दी नाय, (३) सहकों के निर्माण के लिए तथा छोटी-छोटी शक्ति उत्पादन की योजनाश्चों को कार्यान्तित करने के लिये अनुदान दिये जाँग ख्रीर (४) श्रीद्योगिक शिचा की सुविधायों का विस्तार किया जार। पर जैसा भय था उसके अनुसार वह समस्या सुलकाने का याशिक प्रयत्न यसफल रहा। यामी श्रीर नगरा दोनीं स्यानों पर ऐसे व्यक्तियों की सख्या जो श्राशिक व्यवसाय प्राप्त या वेरोजगार है निरन्तर वढती जा रही है। यह ग्राशा की जाती है कि इस समस्या को वास्तविक रूप से सुलम्माने का पयत्न किया नायगा जिसमें देश के ब्रीदोगिक विकास पर ग्राधिक महत्व दिया जायगा श्रीर साथ ही साथ जन सख्या की वृद्धि पर कुछ. नियत्रण भी रक्ला नायगा । यही उपाय द्वितीय योजना का मुलाघार है ।

यदि भारत के कारखानो द्वारा निर्मित वस्तु के उत्पादन श्रीर विकय मे

वृद्धि हो तो श्रीयोगिक वेरोजगारी को कम किया जा सकता है । यह तभी सम्मव है जब प्रति हकाई उत्पादन ज्यय कम किया जाए । बहुत से उद्योगों में पारिश्रमिक उत्पादन ज्यय का एक महत्वपूर्ण ग्रग है । गत रे वर्षों में भारत के श्रमिकों के पारिश्रमिक में पूर्व स्तर से ३१ से ४८ गुना श्रिविक वृद्धि हुई है परन्तु इस वृद्धि के साथ ही श्रमिक की कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है । इसका स्वामाविक परिणाम यह हुशा कि कुछ कारखाने बन्द कर देने पढ़े जिससे श्रमिकों में वेरोजगारी फेली । यह स्थिति बहुत समय पूर्व ही श्रा गई होती परन्तु युद्ध के समय वस्तु ग्रों का श्रमाव हो गया था श्रीर वह श्रमाव युद्ध समाप्त हो जाने के परचात भी रहा । वस्तु श्रों का उत्पादन ज्यय श्रिषक होते हुए श्रीर मार्वों का स्तर श्रिषक रहते हुए भी श्रपने समान का वित्रय कर सकने में उद्योग सफल रहे । परन्तु अब उपमोक्ता इस स्थिति का श्रागे निर्वाह कर सकने में ग्रसमर्थ हैं । इसलिए वेरोजगारी को कम करने के लिए या तो भारत के श्रमिकों को कम पारिश्रमिक लेने के लिए परन्तुत रहना होगा या उन्हें कार्य ग्रिषक करना पड़ेगा ।

इसके साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाने से, विभिन्न सरकारी नियन्त्रणों छ्रौर निजी उद्याग मे छन्य प्रकार के प्रतिबन्ध लगा देने से भारतीय उद्योगा के उत्पादन व्यय में वृद्धि हो गई है। भारत के छीद्योगिक चेन्न में लग-भग निजी उद्योगों का ही नोल बाला है। इसलिए ख्रीदिक उत्पादन करने के लिए छीर उद्योगों में व्यवसाय की सभावना में वृद्धि करने के लिए निजी उद्योग चेन्न को सभी संभव सुविधाएँ और उसके मार्ग में सरकारी प्रतिबन्धों द्वारा बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि सरकार छपनी कर, अस तथा उद्याग सम्बन्धों नीतियों में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि के लिए उद्यागों को प्रोत्साहन मिल सके तो उद्योग चेन्न में बेरोजगारी बहुत छशों में कम की जा सकती है।

यह सुमाव दिया गया है कि भारतीय उद्योग चेत्र में युक्तिकरण की योजनाओं को लागू करने की अनुमति न दी जाय क्योंकि इससे उद्योग चेत्र में बेरोजगारी मे वृद्धि होती है। यदि यह सुमाव मान लिया गया तो श्रोद्योगिक चेत्र में बेरोजगारी घटने की अपेचा और अधिक बढेगी। जब बाजार में पृति माँग से कम हैं तो इस बात का विशेष महत्व नहीं है कि भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई का उत्पादन व्यय कितना है। परन्तु चूँ कि अब खरीबार अपनी व्यय शक्ति के अनुकूल क्रय करना चाहता है जिसके कारण बाजार की स्थित उसी हाथ में है, उद्योगों की परस्पर प्रतियोगिता शक्ति विशेष महत्व की बात हो हो गई है। यदि किसी कारखाने का उत्पादन व्यय भारत या विदेश में अपनी

प्रतिद्वन्दी कारताने के उत्पादन व्यय मे अधिक है तो वह कारताना श्रवश्य नष्ट हो जायगा युक्तिकरण उत्पादन व्यय मे कम करने का एक उपाय है। यदि युक्तिकरण की योजनाको को लागू किया नायगा तो उसमें कुछ वेरोजगारी अवश्य कैलेगी परना यदि युक्तिकरण योजनाओं में लागू ही न किया गया तो यह सम्भव हो समता है कि कारताना सदी के लिए बन्द कर देना पढ़े श्रीर पूर्व की अपेना कहीं श्राधिक संख्या में व्यक्तियों को वेरोजगारी का सामना करना पड़े।

कुछ व्यक्तियों का मत है कि मारत सरकार ने जून १६४४ में जो योजना प्रमाशित की यो ग्रोर जो ग्राम तक वैकल्पिक रही है उसे ग्रानिवार्थ कर देना चाहिए। इस योजना के श्रमुंसार वेरोजगार व्यक्ति को ग्रपने वेरोजगारी मास के पूर्वार्क्ष में पारिश्रामक की साधारण दर का ७५ प्रतिशत मिलेगा ग्रीर उत्तरार्थ में ५० प्रतिशत। इस योजना में पहले ही मान लिया गर्मा है कि भारतीय उत्योग इम ग्रातिरिक्त परिश्रामिक के घन मार वहन कर सकने में समर्थ हैं, परतु वास्तिविक स्थिति इसके जिपरीत है। भारतीय उद्याग को जितना लाम होता था उसकी मात्रा घट गई है ग्रोर यदि उत्योग पर श्राधिक मार पढ़ा तो वह बहन कर सकने में ग्रासम्य सिंद होगा। भारत के श्रानेक कारणाने पहले ही बन्द हो चुके हैं। यदि यह योजना श्रानिवार्य की गई तो कुछ ग्रोर कारखाने भी बन्द हो जायेंगे।

'प्रथम योजना काल के श्रनुमय से यह श्राप्तश्यक हो गया है कि वेकारी की समस्या पर केपल सामृहिक रूप में ही नहीं वरन् प्रामीण न्त्रीर नागरिक सेनी के हिन्दी वरन् प्रामीण न्त्रीर नागरिक सेनी के हिन्दी के सिस्या के विस्तार का, जा कि स्रागामी कुछ वर्षों में होगा, ठीक-ठीक स्रनुमान करने के लिये यह श्रावश्यक है कि देश के विभिन्न भागों के प्रामीण श्रीर नागरिक सेनों में इसकी वास्तिभिकता को समक्त लिया नाय। यह भी श्रावश्यक है कि शिच्चित वर्ग की वेकारी को श्रन्य लोगों की वेकारी से श्रलग कर लिया नाय?'।

"प्रथम योजना के आकड़ों के परी चुण से यह जात होता है कि आघी
योजना कार्यान्वित होने पर वेकारी निरन्तर बढ़ती जा रही थी। प्रथम योजना
काल में रिजस्टर किये हुये वेरोजगार लोंगों भी सख्या निरन्तर बढ़ती रही यह
मार्च ८६५१ में ३३७ लाख के तथा दिसम्बर १६५३ में बढ़कर ५२२ लाख
हो गई और १६५६ म मार्च म ७ •५ लाख हो गई। योजना आयोग की िकारिश के अनुमार नेशनल सैम्पिल सर्वे ने जो प्रारमिक परीक्षण नगरवासियों में
वेरोजगारों का किया या उसके परिणामों के हिस्टनी सु से यिट इन ऑकड़ां को

देखा जाय तो इनसे वि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पढ़ता है। इस सर्वे के अमुसार नागरिकों में वेरोजगार्र जी (१६५४) सख्या २२ ४ लाख आँकी गई थी। इस सर्वे ने वेकार लोगों की सख्या आर जिनका नाम रिकस्टर किया जा चुका या उनकी सख्या के बीच अनुपातिक मम्बन्ध मो स्थापित करने का प्रयत्न किया है। सर्वे का अनुमान था कि लगभग २५% वेरोजगार व्यक्ति एक्सचेन्न के दफ्तर में अपना रिजस्टर करवाने हैं। इस आधार पर नगरवासियों में बेरोजगारी की सख्या वर्तमान काल में २८ लाख के लगभग आती है। यह अनुमान सामान्यंत देश के विभिन्न भागों के नगर्रा में किये गये परोज्ञणों की रिपोर्टों के समान है। समिवक बेकारी, को जो कि विकासमान आर्थिक व्यवस्था में अवश्यमभावी है, खूट देते हुचे हम यह कह सकते हैं कि नगरवासियों में वेकार लोगों की सख्या २५ लाख के लगभग अनुमान की जाती है। इस सख्या में नगर के अमिकों की सख्या बढ़ाने के लिये नवीन आगन्तुकों को भी जोड लेना चाहिये। यह अनुमान किया जाता है कि आगामी ५ वया में लगमग ३८ लाए व्यक्ति इस कारण वेकारा में जोड़ दिये जायगे।

श्रागामी ५ वर्षों मे श्रिमको की गणना मे वृद्धि श्राने वाले नवागन्तुकों की सल्या १ करोह अनुमान की गई है। इस सल्या में से नागरिक श्रिमकों में नवागन्तुकों को अनुमानित ३८ लाख सल्या घटा कर १६५६-६१ के मध्य श्राम्य श्रिमकों की गणना में वृद्धि करने वाले नवागन्तुकों की सल्या ६२ लाख के लगमग श्रावेगी। निम्न तालिका यह बतलाती है कि द्वितीय योजना काल में यदि वेकारी को समस्या को समाप्त करना है तो कितने व्यवसायों के श्रवसर प्रदान करने पहेंगे .—

(१० लाख में सस्थार्वे) ग्रामी के नगरों के योग चेत्र में त्तेत्र में श्रमिकों में नवागन्त्रकों के लिये ६•२ ₹.८ वर्त्तमान श्रमिको मे वेरोजगार व्यक्तियों के लिये प् ३ ₹'5 ₹'५ १५ ३ योग 6.9 ६६

यांद इस प्रकार रोजगार के व्यवसरों को पैदा करना सम्भव भी हो सके तो भी श्राशिक रोजगार की समस्या को जो बेकारी की समस्या की ही तरह महत्व शाली है सुलक्षाया नहीं जा सकता। द्वितीय योजना का ध्यान प्रधानतः वेरोजगारी श्रोर ग्राशिक वेरोजगारी की समस्या पर है। इसलिये द्वितीय योजना में एम श्रोर वड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले समुक्त पूँजी वाले उपक्रमों के विकास के प्रति इस श्राशा से प्रधानता दी गई है कि ये किसी सीमा तक वेकारी की समस्या को मुलमा सकेंगे। सरकारी चेत्र में दुल व्यय लगभग ४८०० करोड़ क्यये का श्रमान किया गया है, जिसमें में केवल ३८०० करोड़ क्यये विनयोग दिखाने हैं। इसके श्रातिरक्त व्यक्तिगत चेत्र में विनयोग की मात्रा २४०० करोड़ क्यये श्रमान की गई है। राज्यों एय वेन्द्रीय मत्रालयों द्वारा पूरित श्रामझों तथा व्यक्तिगत चेत्र के लिए उत्पादन शक्ति में वृद्धि सम्बन्धी मान्यतात्रों को विचाराधीन रखते हुए जो ध्येय निश्चित किए गए हैं उनके श्राधार पर द्वितीय योजना द्वारा प्रदत्त रोज़ी के श्रातिरिक्त श्रवसरों मा श्रमान लगाया जा सकता है। निम्न तालिका में इन परिशामों का निष्कर्ष दिया गया है।

	(१० লাং	त की सख्या में
अनुमानित श्रतिरिक्त रोजी (वृत्ति) किृिष	को छोड़ क	₹]
१. निर्माण		२ १∙
२ िचाई तथा विद्युत योजनाएँ	•	"0ሂ
३ रेलवे		•રપ્
४ श्रन्य यातायात श्रीर सचार	• •	'१८
५ उद्योग तथा खनिज		હયૂ
६ कुटीर तथा छोटे उद्योग		४५
७ वन, मछली पकड़ना, राष्ट्रीय विकास		
योजना, तथा सम्बन्धित श्रन्य योजन	गऍ	४१
< शि न् ।		3 8
६, स्वास्थ्य		•१२
२० श्रन्य सामाजिक सेवाएँ		१४
११ सरकारी नौकरियाँ	**	. %3
योग (१ से ११ तक)		५.५०
१२ "श्रन्य" जिनमें वाणिच्य श्रीर व्यापार		•
जो कुल का ५२% है सम्मिलित		२•७०
कुल योग		080
_		

🚁 🖟 द्वितीय पचवर्षीय योजना द्वारा कितने नवीन व्यवसायों को श्रवसर प्रदान किया जा सकेगा उसका ठीक-ठीक श्रनुमान लगाना श्रभी तक सम्भव नहीं हो सका है। "ग्रायोग द्वारा परीचा करने से यह जात होता है कि प्रथम योजना काल में जो प्रत्यज्ञ व्यवसाय के श्रवसर सरकारी श्रीर व्यक्तिगत चेत्र में प्रदान किये गये उनकी सख्या ४५ लाख के लगभग थी। इस श्रुतमान में वाखिज्य श्रीर व्यापार श्रादि के चेत्र के श्रन्तर्गत श्रातिरिक्त व्यवसाय समिमलित नहीं किये गये हैं। विकास सम्बन्धी धयत्न को द्विगुणित करके जा द्वितीय योजना में अतिरिक्त न्यवसाय के अवसरों के प्रदान करने का ध्येय बनाया गया है वह कुछ विशेष श्रधिक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी व्यय प्रथम योजना काल के व्यय से कोई विशेष श्रधिक नहीं हो पायेगा, क्योंकि सम्कारी चेत्र में योजना का व्यय १६५५-५६ में ६०० से ६२० करोड़ रुपयों के लगमग निश्चित किया गया है, जब कि विकास योजनास्त्रों पर १९५०-५१ में २२४ करोड रुपया ही ब्यय किया गया था। प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष में सरकारी चेत्र में व्यय की मात्रा १६५०-५१ के व्यय की मात्रा से लगभग ४०० करोड़ वपये ऋधिक होने की सम्भावना है। यह भी सम्भव है कि प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में विकास योजनाश्ची पर व्यय में वृद्धि द्वितीय योजना के श्रन्तिम वर्ष में लगभग ६०० करोड़ रुपया हा। इसके श्रतिरिक्त द्वितीय योजना में विनियोग के ढग को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारी उद्योगों श्रीर यातायात पर, जो कि श्रल्पकाल में बहुत कम व्यवसाय के श्रवसर प्रदान कर सकते हैं, बहुत श्रिषक धन न्यय किया जाने वाला है।" इसका श्रर्थ यह है कि परम सीमाग्य होते हुये भी ८० लाख से आधिक व्यक्तियों के लिये (कृषि को छोड़ कर) द्वितीय योजना के उपायों द्वारा व्यवसाय प्रदान करना सम्भव न हो सकेगा जब कि वेकारी की समस्या को पूर्ण रूपेण इल करने के लिये १५२५ लाख व्यक्तियों के लिये व्यवसाय प्रदान करना श्रावश्यक है।

मई १९५० में योजना ग्रायोग द्वारा जारी की गई पुस्तिका 'द्वितीय पच-वर्षीय योजना की सम्भाननार्ये मूल्यांकन' के श्रनुसार "पहले दो वर्षों में कृषि के बाहर रोजी के २० लाख श्रवसर प्रदान किये गये। लगमग १० लाख श्रम-शक्ति १९५८-५६ में रोजी पा सकेगी। यह स्मरण रखना चाहिये कि योजना में ७९ लाख व्यक्तियों के कृषि के बाहर तथा १६ लाख व्यक्तियों के कृषि के श्रन्दर रोजी पाने की सम्भावना है। विभिन्न योजनाश्रों की लागत में वृद्धि हो जाने के फल-स्वरूप कृषि के बाहर सरकारी दोत्र में ४८०० करोड़ ६० के व्यय के श्रनुमान पर लगमग ७० लाख व्यक्तियों को रोजी मिल सकेगी। यदि यह व्यय ४५०० करोड़ र० हो तो रोजी पाने वालों की सख्या ६५ लाख के लगभग होगी। यह श्रानुमान बिल्कुल सही नहीं है किन्तु इनसे इतना तो पता चलता ही है कि हमारी श्रार्थ व्यवस्था में श्रम-शक्ति की वार्षिक वृद्धि के श्रानुरूप विनियोग नहीं हो रहा है।"

रोजगार के दफ्तरों का कार्य

मारत में रोजगार के दफ्तरों का एक जाल सा बिछा हुआ है जो वेरोजगार क्यित्यों के आवेदनों को स्वीकार करते हैं और उन रिक्त स्थानों के लिये उन्हें मेज देते हैं जो सरकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा विज्ञाप्ति किये जाते हैं। इसमें सदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तर वेरोजगारी कम करने में सहायक हैं, क्योंकि वे वेरोजगार क्यक्तियों का सम्बन्ध व्यवसाय प्रदान करने वालों से स्थापित कर देते हैं परन्तु ये रोजगार के दफ्तर ही मनुष्य की अप्रयुक्त शक्ति की समस्या को सुलक्तान के सफल उपाय तो नहीं हैं। इनका कार्य क्रेत्र प्रचलित आर्थिक आरेर सामाजिक स्थिति के अन्तर्गत ही सुविधार्य प्रदान करना है। ये दफ्तर नवीन व्यवसायों को तो उत्यक्त कर नहीं सकते। वे तो केवल वेरोजगार व्यक्तियों को जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं और करना चाहते हैं निर्देश मात्र ही दे सकते हैं। वे उन व्यवसावों के लिये जो निद्यापित हैं और जिनके लिये स्थान रिक्त हैं उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं हुढ सकते।

यह सब होते हुए भी बेरोजगार व्यक्तियों को प्राप्त स्थानों के लिये निर्देश देना भी बेरोजगारी की समस्या के सुलक्ताने में एक बड़ी सहायता है। इसके स्रातिरक्त यद्यांप रोजगार के दफ्तर में नाम रिजस्टर कराये हुए बेरोजगार व्यक्तियों से हमें बेकारी की समस्या का पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त होता, पर उसके नि.सदेह बेरोजगारी की बदलती हुई प्रवृत्ति ज्ञात होती है। यह बड़ी चिन्ता की विषय है कि रोजगार के दफ्तरों में राजस्टर किये हुये व्यक्तियों की सख्या १६५६ में ७,५८,५०३ थी। १६५७ में यह बढ़कर ६,२२,०६६ हो गई। १६५६ में केवल १,६८,८३१ हो गई।

रोजगार के दफ्तरों को श्राघक प्रभाव शाली बनाने के लिये यह श्रावश्यक है कि उनका पुनंसगठन किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण श्रीर व्यवसाय व्यवस्था समिति ने जिसे पाय बी० शिवा राव कमेटी कहते हैं भारत सरकार, की अप्रैल १६५४ में दी हुई रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें की:—

(१) रोनगार के दफ्तरों की न्यवस्था को विस्तृत करके उसे राष्ट्रीय सेवा का एक स्यायी व श्रिषक श्रिषकार प्राप्त विमाग बना देना चाहिये,

(२) प्रशासन निकेन्द्रित होना चाहिये। इसका यह अर्थ है कि नीति

चाहे सरकार द्वारा क्यों न निर्धारित की जाएँ पर उनका नित्य प्रति का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा होना चाहिये,

- (३) केन्द्रीय सरकार द्वारा रोजगार के दफ्तरों को जो अनुदान सहायतार्थ दिया जाता है वह चालू रहना चाहिये, पर उसकी मात्रा को चेत्रीय प्रधान कार्यालयो तथा राज्यों के रोजगार के दफ्तरों के कुल ज्यय के ६०% तक सीमित कर देना चाहिये, और १६५३-५४ के बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई हो अथवा १६५२-५३ में जो वास्तविक ज्यय किया गया हो, इन दोनों राशियों में से जो राज्य की सरकार के हिंदिकोशा से उसके लिये अधिक लाभकारी हो, उसे अनुदान की अधिकतम मात्रा नियत कर देनी चाहिये,
- (४) रोजगार के दफ्तरों के कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिये श्रीर उनके कार्यों में निम्न कार्यों को भी ध्राम्मिलित करना चाहिये (क) मालिकों श्रोर कार्य करने वाले वर्गों के साथ बहुत श्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये; उनको चाहिये कि व्यवसाय चाहने वालों के श्रावेदनों को स्वीकार करें श्रीर तब तक उनसे श्रपना सम्बन्ध रक्खें जब तक कि उस पर नियुक्ति न हो जाय, (ख) नाम रिजस्टर कराये हुये व्यक्तियों का निरीक्षण तथा सहायता करें श्रीर उनकी श्रावश्यक परीक्षा लें, (ग) रिजस्टर कराये हुए व्यक्तियों की फाहलें निर्माण करें, श्रीर योग्य श्रावेदकों के प्रार्थना पत्रों को कार्य देने वाले व्यक्तियों के पास मेर्जे श्रीर उनकी निर्मुक्त का लेखा निर्माण करें श्रीर सुरक्तित रक्खें, (घ) व्यवसाय के श्रवसरों का पता लगायें श्रीर व्यक्तियों तक इसकी स्चना पहुँचाने की सुविधायें प्रदान करें ताकि वेरोजगारों को व्यवसाय प्राप्त हो सके श्रीर मालिकों को उपयुक्त कार्य करने वाले इन टफ्तगे को चाहिये कि वे व्यवसाय सम्बन्ध ग्राँक से प्रकाशित करें श्रीर कीन सा कार्य कब तक चलेगा इसके सम्बन्ध में श्रपना मत भी अकाशित करें श्रीर कीन सा कार्य कब तक चलेगा इसके सम्बन्ध में श्रपना मत भी अकाशित करें.
- (५) श्रदत्त श्रमिकों को न तो रिजस्टर करने की श्रावश्यकता है श्रीर न उनके श्रावेटनो की। जो व्यक्ति ऐसे श्रमिकों की सेवाये चाहते हैं उनको घोषणा द्वारा या किसी श्रन्य रूप से सूचित कर देना ही पर्याप्त होगा। इसके पश्चात जो कार्य करना चाहते हैं उन्हें सीचे मालिकों के पास पहुँच जाना चाहिये। ऐसे व्यक्तिया के सम्मन्ध में जो प्रतिदिन रोजगार के दफ्तर पर इकड़ा होते हैं तथा घोपणा द्वारा जिन रिक्त स्थान्हें की स्चना दी जाती है उनके श्रांकडे तैयार करने की श्रावश्यकता नहीं है, श्रीर

(६) सरकारी तथा श्रर्ध सरकारी सस्याश्रों द्वारा नियुक्त किये जाने के

चम्बन्य में ये दफ्तर जो सिफारिशें करें उनके परिगाम की कुछ दिन तक जाँच करने के पश्चात् व्यक्तिगत चेत्र में भी इन दफ्तरों की सिफारिशों पर नियुक्त करना अनिवार्य कर दें।

सरकार ने बी॰ शिवाराव कमेटी के ग्रामिस्तावों को ग्राशिक रूप में स्वीकार कर लिया है ह्योर रोजगार के टफ्तरों को क्रि धिक प्रभावशाली बनाने के लिये निम्न उपायों को द्वितीय योजना में कार्यान्वित करने का निर्णय किया है. (१) रोजगार दिलाने के विभाग को १२५ नये रोजगार के दफ्तरों की स्थापना करके विस्तृत करना ताकि अन्य बहुत से व्यवसाय के केन्द्र इनके अवर्गत आ सर्कें; (२) व्यवसाय भी सूचनात्रों के एकत्रित करने तथा लोगों तक पहुँचाने भी योजना निर्माण करना, (३) चुने हुये व्यवसाय के दफ्तरों मे नवयुवक रोजगार सेवा सस्था की स्थापना करना तथा वयस्को के लिये व्यवसाय की सलाह देना तथा 'केरियर पेम्फलेट' ब्राटि उपयुक्त तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना, (४) रोजगार सम्बन्धी विश्लेपण तथा खोज के कार्य-क्रम बनाना ताकि विभिन्न व्यवसायों के नाम वथा परिमापा मान्य स्तर की वनाई जा सके, श्रीर (५) रोजगार के दफ्तरों मे व्यवसायिक परीच्चा सम्बन्धी कार्यक्रम बनाना । इन उपायों से भारत की व्यवसाय दिलाने वाली सेवात्रों की कार्य कुरालता श्रधिक बढ जायगी परन्तु यह तमी सम्मव है जब कि रोजगार के दफ्तर राष्ट्रीय सेवा विभाग के रूप मे विकिष्ठ हो जाँय श्रौर तमी उनके लिये वेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसाय दूढना श्रौर दिलानामी सम्मव हो सकेगा। कमेटी ने प्रशासन को विवेन्द्रित करने नी विकारिश की है क्योंकि ऐसा करने से राज्य सरकारों को भी इस सस्या के प्रति चहानुभृति उत्पन्न हो जायगी ऋौर वेरोजगार के दफ्तरों का राज्य की सरकार तथा राज्य के त्रान्तर्गत व्यक्तिगत मालिकों से सम्बन्ध स्थापित करने में भी यह चहायक भी चिद्र होगी । विकेन्द्रियकरण से प्रान्तीयता के बढने तथा श्रन्तरप्रान्तीय जनसङ्य के त्रावागमन में बाधा पहने का मन निर्मूल है क्योंकि इन रोजगार के दक्तरों की नीति तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निर्घारित होगी। इन सस्याय्रों के कार्यों के प्रसार के सम्बन्ध में जो सुमाव दिये गये हैं उनसे मालिकों तथा रोजगार के दफ्तरों के बीच श्रीर वेरीजगार व्यक्तियों श्रीर रोजगार के दफ्तरों के वीच श्रच्छा सम्बन्घ भी स्थापित हो सकेगा। श्रद्त श्रमिकों के सम्बन्ध में उनकी रिनस्ट्री न करने की सलाइ देने में ऐसा लगता है कि कमेटी इस कार्य के विस्तार तथा सम्भावित श्रधिक व्यय से विशेष प्रमावित हो गई थी। पर ऐसा करने से इसमें सदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तरों की वेरोजगारी की समस्या सुलक्ताने के सम्बन्ध में उपयोगिता श्रनश्य कम हो जायगी।

श्रायाय २६

श्रोद्योगिक गृह निर्माण

श्रोत्रोगिक यह निर्माण की समस्या श्रामका को कम किराये पर उपयुक्त श्रावास प्रदान करने की है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भी बढ़े-बढ़े करने श्रीर नगरों मे, विशेष कर श्रोद्योगिक नेन्ट्रों मे, रहने के लिये घरों का श्रभाव था। श्रमिक लाग चील तथा वस्तियों में बडे श्रम्बास्ट्य वातावरण में रहते हैं। गत कुछ वर्षों से जन सख्या मे वृद्धि होने, पाकिस्तान से शरणार्थियों के आने तथा व्यक्तिगत लोगो द्वारा कम सरुपा में नये घरो के निर्माण के कारण दशा छोर भी छाधिक शोचनीय हो गई है। १६३१, १६४१ श्रोर १६५१ की जनगणना के श्रनुसार जनसख्या मे कमण ११, १४३ श्रीर १३४ प्रतिशत दृदि हुई परन्तु नागरिक चेत्रों में यह वृद्धि क्रमश्र २१, ३२ श्रीर ५४ प्रांतशत हुई। पाकिस्तान से लगमग प्य जाम शरणार्थिया के था जान से नागरिक जेत्रों में जनसङ्या ना दवाय वढा जिसके प्रभाव से रहने की व्यवस्था जोर जरिल हो गई। शरणार्थिया ने गाँव की श्रपेजा बड़े करना श्रीर नगरां मे ही रहना ग्रधिक प्रसन्द किया। इसमे नगरों स्रोर कस्त्रो में रहने के लिए घरों की माँग बढ़ी परन्तु पूर्ति न हो सकने से यह श्रमाव की खाई चोड़ी होती गई। मॉग के श्रनुसार घरों की पूर्ति न हो सकने का कारण यह है कि इमारत बनाने के सामान का श्रधिक मूल्य होने के कारण श्रीर बाजार में सामान के श्रभाव के फलस्वरूप नई इमारतों को पर्याप्त मात्रा मे नहीं बनाया जा सका। इसके साथ ही मकानों को किराये पर देने श्रीर किराये की दरों पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाने से भी इम दिशा में प्रतिकृल प्रभाव पड़ा श्रीर इसी कारण बढती जनसंख्या के साथ मकानों की ब्यवस्था नहीं की जा सकी।

गृह निर्माण की प्रवृत्ति—वर्तमान मे मुख्य गृह निर्माण एजेन्सियाँ निम्निलिखित हैं:—(१) सरकारी अथवा अन्य एजेन्सियाँ, (२) उद्योगपित, (३) सहकारी सिमितियाँ, (४) अपने उपयोग के लिए मकान बनाने वाले व्यक्ति, और (५) निजी उद्योग। निजी उद्योग के मालिकों की और अपने उपयोग के लिए गृहिन्मीण कराने वाले व्यक्तियों की अब गृहिन्मीण की और गिति मन्द हो गई है। गत कुछ वर्षों में इस दिशा की और सरकारी तथा अन्य मिली-जुली एजेन्सियों, उद्योगपितयों और सहकारी समितियों की गित में विशेष रूप से वृद्धि हुई है।

प्रथम योजना काल मे ७६,६७६ किराये के वरों के निर्माण के कार्यक्रम

को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से १६,१६५ वम्बई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, ५,६२६ हैटराबाद में, ५,१८१ मध्यप्रदेश में, ३,४४४ मध्यभारत में तथा इसमें नम सख्या में श्रन्य राज्यों में बनवाये जाने वाले थे। जितने किराये के घरों का निर्माण प्रथम पचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पूर्व किया जा चुका था उनकी सख्या ४०,००० के लगभग थी। जितने किराये के घरों के निर्माण की श्रनुमित दी गई है उनमें से ६८,२०० श्रथना ८५% के लगभग राज्य सरकारी द्वारा, १०,१६१ स्रथवा १३% अभिकों के निजी उन्नोग द्वारा स्त्रीर १,३१८ या १.५% उद्योगों में काम करने वालों की सहकारी समितियों द्वारा बनवाये जा रहे हैं। जन यह योजना निर्माण की गई थी उस समय सहकारी समितियों श्रीर मालिकों के सहयोग की ग्रधिक आशा की थी। योजना के इस पद्म पर विचार किया ना रहा है श्रीर ऐसे उपाय सोचे जा रहे हैं जिनसे कि मालिकों श्रीर कारसानों के अमिकों की सहकारी समितियों का अधिक सहयोग प्राप्त हो। इनके श्रातिरिक्त पुनवांत, रज्ञा, रेलवे, लोहा श्रीर इस्पात, उत्पादन, यचना, निर्माण, यह निर्माण तथा पूरि श्रादि मत्रालयों द्वारा भी यह निर्माण के समुचित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। राज्य सरकारें श्रीर कुछ स्थानीय श्रधिकारियों के श्रपने निजी यह निर्माण के कार्यक्रम भी चालू हैं। यह अनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पुनर्वास मन्त्रालय ने नगरों में ३,२३,००० किराये के वर वनवाये श्रीर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों ने, निर्माण, गृहनिर्माण तथा पूर्वि के मन्त्रालयों को छोड़ कर लगभग ३००,००० गृहों का निर्माण करवाया। श्चन्य राहनिर्माण की योजनाश्चों को, जिनका कपर वर्णन किया जा चुका है, चिम्मिलित करते हुए चरकारी विभागों ने प्रथम योजना काल में लगमग ७,४२,००० गर्हों का निर्माण करवाया । व्यक्तिगत लोगों ने कितने गर्हों का निर्माण कराया उसकी सख्या नानना कठिन है। कर नौंच श्रायोग के इस सम्बन्ध में परीज्ञा करने से ज्ञात हुआ कि नगरों में गृहनिर्माण के सम्बन्ध में कुल विनियोग १६५३-५४ में लगमग १२५ करोड़ रुपया था। यदि इसे हम पाँच वर्षों की अवधि का श्रीसत मान लें श्रीर एक धर के बनवाने में श्रीसत ब्यय १०,००० र० के लगमग मान लें तो यह ज्ञात होगा कि प्रथम योजना काल में लगभग ६००,००० गृहों का निर्माण ल्यक्तिगत चेत्र में हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना वाल में लगभग १३ लाख घर नगरों में वनवाये गये।

प्रथम योजना काल में ग्रामों में भी रहने की स्पिति में सुधार के कुछ उपायों का प्रयोग किया गया है। सामुदायिक विकास योजना चेनों से ५८,००० ग्राम्य शीचालय, १६०० मील लम्बी नालियाँ श्लोर २०,००० कुँचे वनवाये गये हैं न्त्रोर लगभग ३४,००० कुँग्रां का जीखोंदार किया गया है स्रोर राष्ट्रीय विकास चेन्ना में ८०,००० माम्य शीचालय, २७०० मील लम्बी नालियाँ, ३०,००० नये कुँये श्रोर ५१०० पुराने कुँश्रों का जीगोंद्वार किया गया है। राष्ट्रीय विकास तथा सामुदायिक विकास योजनाश्रों के होत्रों म लगभग २६००० घरों का निर्माण हुआ है श्रीर लगभग उतने ही पुराने घरों का जीखोंदार किया गया है। अनेकों राज्यों में ग्रामों में ईंट क भटटे स्थापित किये जा रहे हैं। कहीं-कहीं पर सहकारी समितियों की सहायता इस कार्य में ली जा रही है। उदाहरखार्थ उत्तर प्रदेश में १६५०-५१ में १६ सहकारी ईंट के भट्टे खोले गये थे. १६५४-५५ तक उनकी सख्या बढकर ७५२ हो गई और भट्टों के श्रास-पास के ग्रामों में श्रिधिकाधिक नये दग के पक्के मकान बनते जा रहे हैं। बहुत से राज्यों में हरिजनों के स्त्रावास की स्थिति को, विशेष मृमि न्नेत्रों को उनके लिये नियत करके तथा सहकारी यहनिर्माण समितियों की स्थापना द्वारा, सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के श्रन्तर्गत निर्माण, पूर्ति तथा गृहनिर्माण मन्त्रालय ने श्राम्य यहिनमांग श्रागार की स्थापना की है जिसका ध्येय इस होत्र की विभिन्न समस्यात्रां का श्रध्ययन करना श्रीर एहों के नये-नये श्राकारों, श्रिभन्यासों, निर्माण के दगों तथा स्यानीय कच्चे माल के प्रयोग करने के उपायों की लोज करना है।

कठिनाइयाँ—ग्राधिक मकानों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं:

(१) प्राम श्रीर नगर में भूमि, इस्पात, ईंट, िसमंट, लकड़ी की चीखट इत्यादि के मूल्य में बहुत वृद्धि हुई। यह सभी चीजे मकान बनाने के लिए बहुत श्रावश्यक है। इन वस्तुश्रों के मूल्य श्रिषक होने पर भी ग्रह-निर्माण समय या परन्तु सबसे बड़ी किटनाई यह है कि इसके लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। दूसरी श्रोर यदि श्रिषक व्यय पर मकान बनाया जाय तो उसका किराया भी श्रिषक होना चादिए परन्तु ग्रह निर्माण का कार्य तीन्न गति से करने का सुख्य उदेश्य यह है कि श्रामकों तथा श्रन्य निर्धन श्रोर मध्यम श्रेणी के लोगों को सस्ते किराये पर मकान दिये जा सकें। इस्तिए समस्या यह है कि मकान बनाने के सामान का मूल्य घटाया जाय, महेंगे सामान के स्थान पर सस्ते मूल्य का कोई दूसरा उपयुक्त सामान लगाया जाय श्रीर श्रमकों हत्यादि के लिए सुखदाई परन्तु कम व्यय में मकान बनाने के लिए मकान के श्राकार-प्रकार श्रीर उसके ढाँचे इत्यादि के सम्बन्य में खोज कार्य किया जाय। परन्तु यदि ग्रह निर्माण के व्यय में पर्याप्त कमी भी कर दी जाय तब भी। ग्रह निर्माण योजना को कार्यान्वित करने के

लिए रिपये की आवश्यकता होगी और जब तक पर्याप्त धन, जो कम से कम १०० करोड़ रुपया होगा, प्राप्त नहीं होता तब तक सभी आवश्यकताप्रस्त लोगों के लिए मज़ानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। बाजार में रुपये की तगी है और जनता के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए घर बनाने के इच्छुक लोगों को कम व्याज पर रुपया देने के लिये कुछ उपाय खोज निकालना अत्यन्त आवश्यक है।

(२) मकानों का किराया बढ़ाने पर राज्य सरकारों ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। सरकार तथा अन्य एजेन्सी, उद्योगपित और सहकारी समितियाँ लाम की चिन्ता किये दिना यह निर्माण कार्य में वृद्धि कर सकती है। परन्तु किराये पर नियत्रण लग जाने से और नगरों तथा कस्त्रों में मकानों का एलीटमैन्ट करने की व्यवस्था से निजी उद्योगों के मालिक नये मकान बनवाने की और से लगभग निराश हो चुके हैं। कुछ राज्यों मे ऐसी व्यवस्था है कि एक निश्चित तिथि के पश्चात् बने नये मकानों पर यह नियन्त्रण लागू नहीं होते हैं इससे नये मकान बनवाने के कार्य को प्रोत्साहन मिला है।

१६५२ मे एशिया श्रीर सुदूर पूर्वी श्रार्थिक सम्मेलन का गृह निर्माण विषयक श्रिषिवेशन दिल्ली मे हुश्रा था। इस सम्मेलन मे सुकाव दिये गये थे कि (१) श्रादर्श योजनाएँ चालू की जॉय जिनमें इस्पात श्रीर इमारती लक्बी के स्थान पर बांस तथा श्रन्य लकिइयों के उपयोग की जॉंच की जाय श्रीर (२) इसी प्रकार की श्रन्य योजनाश्रों द्वारा ईट इत्यादि बनाने के लिए उपयुक्त चिकनी मिट्टी की मी जॉंच की नाय। इस प्रकार की श्रादर्श योजनाश्रों के द्वारा इम श्रमिकों तथा श्रन्य लोगों के लिये सस्ते श्रीर सुलदाई मकानों का निर्माण करने के उपाय खों सकते हैं।

सरकारी योजनाएँ—श्रौद्योगिक शाति प्रस्ताव में सुक्ताये गये गृह निर्माण कार्य कम के श्राधार पर भारत सरकार ने १६४६ में एक गृह निर्माण योजना तेयार की। इस योजना में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों इत्यादि के द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में जितना रूपया लगेगा उसका हो तिहाई केन्द्रीय सरकार व्याज मुक्त श्रूगुण के रूप में देगी, परन्तु इसके लिये मालिकों को भी कुछ शर्ते माननी पहेंगी। इस योजना के श्रनुसार मालिक तथा राज्य सरकारों को एक तिहाई व्यय की स्वय व्यवस्था करनी पस्ती है। केन्द्रीय सरकार से उन्हें केवल इतना ही लाम प्राप्त है कि श्रावश्यक पूँजी का है श्रूश व्याजयुक्त श्रुण के रूप में प्राप्त हो जाता है।

परन्तु इस योजना के असमल हो जाने पर भारत सरकार ने यह अनुभव

किया कि यह निर्माण कार्य को प्रोत्छ।हन देने के लिये राज्य सरकारों ग्रीर कारखाने इत्यादि के मालिकों को इसके लिये नकद आयिक सहायता देनी पडेगी। इसी विचार से एक योजना निर्माण की गई श्रीर उसे पायः सभी राज्यों की सरकारों के पास विचारार्थं मेजा गया। इस योजना मे यह प्रस्ताव रखा गया था कि गृह निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों तथा निजी उद्योगपतियो को भूमि, के मूल्य का अधिक से अधिक २० प्रतिशत केंद्रीय सरकार सहायता के रूप में देगी। परन्तु इसके लिए यह शर्ते लगाई गई कि (१) मकान वास्तव मे श्रिमको को किराये पर दिया जायगा, (२) किरायेटार से घर की कुल लागत का, जिसमें म्मि का मूल्य भी सम्मिलित है, केवल ढाई प्रतिशत ही वस्त किया जायगा परन्तु यह किराया श्रमिक की आय के १० प्रतिशत से श्रधिक नहीं होना चाहिये. (३) पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आकार प्रकार के बनने चाहिएँ और (४) घर का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के निरीक्षकों श्रोर यह-निर्माण बोर्ड को सभी श्रावश्यक सुविधार्ये दी जानी चाहिएँ। इस योजना का कार्यचेत्र सीमित था श्रीर राज्य सरकारो ने इस श्रीर विशेष «यान नहीं दिया। इसलिये भारत सरकार ने १९५२ के अत मे एक अधिक व्यापक योजना तैयार की जिसके अन्तर्गत यह ब्यवस्था की गई कि केन्द्रीय सरकार यहनिर्माण कार्य को पोत्छान देने के लिये राज्य सरकारी और यहनिर्माण बोर्ड को कुल व्यय का ५० पितशत तक सहायता के रूप में देगी। इसमें भूमि का मूल्य मी सम्मिलित किया 🦯 जायणा । शेष ५० प्रतिशत के लिये सरकार ४३ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देगी। जिसे १५ वर्ष के अन्दर चुकाया जा सकता है। सहकारी समितियों के सम्बन्ध मे यह रूपवस्था की गई कि गृह निर्माण के कुल व्यय का २५ प्रतिशत सरकार सहायता के रूप में देगी और साथ ही कुल निर्माण-न्यय का ३७ई प्रतिशत धन ४ है प्रतिशत वाषिक ब्याज पर ऋगा देगी जिसे १५ वर्ष के अन्दर चुकाया जा सकता है। उद्योग के मालिको को सरकार कुल लागत का २५ प्रतिशत श्राधिक सहायता के रूप में और कुल व्यय का ३७३ प्रतिशत तक ४५ प्रतिशत वाधिक व्याज की दर से ऋग्ण देगी। यह ऋग्ण १५ वर्ष के अन्दर चुकाना होगा। इन सब के सम्बन्ध में ऋगा तथा अनुदान की मान्ना स्टेन्डर्ड लागत के आधार पर श्रनुगिष्ति मात्रा पर ही सीमित कर दी जायगी। बम्बई श्रीर कलकत्ता के सम्बन्ध में १ कमरे बाले कई मजिले मकानों की स्टेन्डर्ड लागत ४५०० रुपया श्रीर श्रन्य स्थानों में २७०० रुपया श्रांकी गई है। दो कमरे वाले कई मिलले मकानो की वम्बई ग्रीर कलकता में लागत ४५३० रुपया (जो कि ग्रव बढाकर ५६३० रुपयाः

कर दी गई है) श्रोर श्रन्य स्थानों में ३४६० रुपया श्रॉकी गई है। एक मिलले मकानों के लिये स्टेन्डर्ड लागत का श्रनुमान कम धन राशि है।

इस पुर्नपरोच्चित योजना की दो मुख्य विशेषतायें हैं (१) सहकारी समितियों को व्यय की ५०% तक ऋण रूप से सहायता मिल सकेगी जबिक मूल योजना के अन्तर्गत केवल ३७६ ही मिल सकती थी और १५ वर्षों में ऋण के चुकता करने के स्थान पर श्रव २५ वर्ष का समय भी मिल जायगा, और (२) स्टेन्डर्ड किराया विभिन्न प्रकार के मकानों के लिये वम्बई तथा कलकत्ता में १० रुपये मे लगाकर ३० रुपया तक छोर अन्य नगरों और कस्बों में १० रुपये से लगाकर १६ रुपया तक नियत कर दिया गया है। इससे योजना श्रिषक पूर्ण बन गई है। यह आशा की जाती है कि एह निर्माण कार्य को इस योजना के अन्तर्गत अधिक प्रोत्साहन भी मिलेगा।

त्रार्थिक सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना के श्रन्तर्गत, जो सितम्बर । १९५२ में लागू हुई, १९५७-५८ केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूर की गई धनराशि २५ ७६ करोड़ ६० थी जिसमें १३-२८ करोड़ ६० श्रृण के रूप में तथा १२-५१। करोड़ ६० श्रार्थिक सहायता के रूप में थे। इसके श्रन्तर्गत ६१,२५० घर थे। । नवम्बर १९५७ तक पूर्ण हुये मकानों की सख्या ६६,७०० थी तथा शेष निर्माण के निमित्त चरणों में थे।

दितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक तथा अन्य गृह निर्माण योजनाओं के लिये अधिक धन सहायता में देने का निश्चय किया गया है। प्रथम योजना में अद्भ करोड़ रुपयों की सहायता का प्रवन्ध किया गया था परन्तु द्वितीय योजना में १२० करोड़ रुपयों की सहायता का निम्न तालिका के अनुसार प्रवन्ध किया गया है —

सहायता प्राप्त श्रीयोगिक गृह निर्माण	४५ करोइ रुपये		
निम्न श्राय-वर्ग के जिये गृह निर्माण	80	,,	23
प्राम गृह निर्माण	१०	32	37
बस्तियों की सफाई श्रोर भियां के लिये गृह निर्माण	२०	27	32
मन्य वर्ती त्राय वर्ग के लिये यह निर्माण .	ą	77	27
रोपणोद्योग के लिये यह निर्माण	ર	33	"
योग	१२०	2)	77

द्वितीय योजना के अन्तर्गत व्यय की योजना अधिक विस्तृत है और अनेकों नये व्यय के शीर्ष उसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं जो कि प्रथम योजना में नहीं ये और कार्य का ब्येय निम्न हैं ---

		गृहों की सख्या
₹.	सहायता प्राप्त श्रीद्योगिक घर	875,000
₹.	निम्न श्राय वर्ग के लिये घर	६८,०००
₹.	बस्तियों मे रहने वालों के लिये नये घर	(y · · ·
	जिनमे भगी भी सम्मिलित हैं—	११०, ०००
٧.	मध्य वर्ती स्राय वर्ग के लिये घर	4,000
પ્ર	रोपग उद्योग के श्रमिकों के लिये घर	११, ० ००
ξ.	प्रामीण गृह निर्माण योजना	१,३३,०००
	योग	Y-44-000

श्रन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा, राज्य सरकारो तथा स्थानीय श्रधिकारियों द्वारा तथा कोयले की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये गृह निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनवाये बरो के श्रितिरिक्त ७५६,००० गृहों का (जिनकी सख्या ८००,००० के लगमग द्वितीय योजना काल में श्रांकी गई है) निर्माण होगा। इस प्रकार द्वितीय योजना में कुल १६ लाख घरों के निर्माण का श्रमुमान है जबकि प्रथम योजना काल में केवल १३ लाख घरों का ही निर्माण हुआ था।

Ĺ

दितीय योजना के पहले तीन वर्ष में ग्रह निर्माण के ऊपर किये जाने वाले कुल व्यय का अनुमान ४० करोइ है। "आधिक सहायता प्राप्त औद्योगिक ग्रह निर्माण योजना के अन्तर्गत १६५६-५६ इन तीन वर्षों में ४२,६०० इकाइयों के निर्माण की व्यवस्था है। निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत २२,००० इकाइयों के निर्माण की तथा भगियों के ग्रह निर्माण के अन्तर्गत २२००० इकाइयों के निर्माण की व्यवस्था है। प्रामीण ग्रह निर्माण योजना १६५८-५६ में प्रभावपूर्ण ढग से लागू की जा रही है। चूंकि दितीय पचवर्षीय योजना में काट-छॉट हो रही है अतएव ग्रहिनर्माण के लिये सशोधित राशि १०० करोड़ र० होगी जो प्रारम्भिक राशि से २० करोड़ र० कम है। ४५०० करोड़ र० के कुल व्यय में ग्रह निर्माण पर किया जाने वाला व्यय ८४ करोड़ र० है। इसमें ६४ करोड़ र० राज्यों के लिये है तथा २० करोड़ र० केन्द्र के लिये हैं।"

श्रद्याय ३० श्रम की कार्यच्या

यह लाक प्रसिद्ध है कि भारतीय श्रमिक निपुण नहीं है। उसकी प्रति घटा उत्पादन शक्ति भी बहुत कम है। यदि पाश्चात्य देशों के उसी प्रकार के श्रमिकों की उत्पादन शक्ति से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि भारतीय श्रमिकों का उत्पादन बहुत गिरा हुआ है। जापान, ब्रिटेन और श्रम्रीका के श्रमिक की अपेज़ा उतने ही ममय में भारतीय श्रमिक बहुत कम कार्य कर पाता है।

स्ती मिल उत्योग सनन्वी प्रशुल्क मण्डल (१९२६-२७) ने वताया कि भारतीय श्रमिक श्रयवा श्रापरेटर ने १८० तकुत्रों पर कार्य किया जब कि इतने ही समन में जापान के अमिक ने २४०, इगलैंड के अमिक ने ५०० से ६०० के वीच श्रीर श्रमरीकी श्रमिक ने ११२० तकुश्रों पर कार्य किया। मारतीय वुन कर श्रीसतन २ कर्षे चलाता है जब कि जापान का बुनकर २३, ब्रिटेन का ४ से ६ तक थ्रोर अमरीका का ६ कर्षे चला लेता है। इससे मारतीय अभिक की सापे सिर कार्यक्तमता का आभाग मिलता है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि गत कुछ वर्षों से कतिपय स्ती मिलों में कार्यच्चमता में काफी वृद्धि हुई है। स्ती उद्योग सम्बन्धो विकेङ्ग पार्टी (१९५२) ने जाँच करके पता लगाया कि दिल्ली की एक श्रीर मद्रास की दो मिलों में एक बुनकर ४, ६, ८ श्रीर १६, श्रहमदाबाद की एक मिल मे १८ श्रीर वम्बई की एक मिल में ६ कर्षे चला लेता है। कार्यसमता में इस वृद्धि का कारण यह है कि इन मिलों मे स्वचालित आधुनिक मशीने लगी हुई हैं जिससे अभिक अधिक काम कर सकता है परन्तु कार्य से इतनी प्रगति होते हुए भी ब्राज तक यह बात साय माना जातो है कि मारतीय श्रीमक ब्रिटेन या जापान के अपने ही प्रकार क अमिक से कम निपुण है। कायला-खदान उद्योग के सम्बन्ध में मारत की जिश्रोलोजीक्ल, माहनिंग और मेटालर्जीकल सोशाइटी के रूप वे वार्षिक श्रिधिवेशन के श्रध्यक्त के मापण में बताया गया कि भारत में एन श्रमिक का उत्पादन र ं उटन है जब कि ब्रिटेन के मजदूर का ६ र्ट टन, नर्मनी के श्रमिक का ८ ६ टन और अमरीका के अभिक का २१ ६८ टन है। मारतीय अभिक का प्रतिषरटा उत्पादन गत कुछ वर्षों में गिरा है। योजना आयोग ने बताया है कि कोयला खदान उद्योग में कार्य करने वाले अमिकों की सख्या १६४१ में २, १४, २४४ से बढ़कर १६५१ में ३,४०,००० हो गई है जब कि इसी अवधि में कोयले

का उत्पादन २ करोड़ ५८ लाख ६० इनार टन से बहकर ३ करोड ४० लाख टन हो गया। इस प्रकार जब अभिकों की सख्या में ५८ प्रतिशत वृद्धि की गई तो उत्पादन केवल ३२ प्रतिशत बढ़ा है परन्तु अभिक का प्रतिघरटा उत्पादन १२७ टन से गिरकर लगभग १०० टन हो गया।

यद्यपि सभी उद्योगों के सम्बन्ध में विस्तृत स्वना प्राप्त नहीं है फिर भी शह्म में प्रकाशित कतिपय उद्योगों की उत्पादकता और अर्जित आय के परिवर्तनों से निम्न वार्ते जात होती हैं:

- (1) कोयला उद्योग में १९५१-१९५४ के बीच खोदने तथा लादने वालों की उत्पादकता में ० ०७६ प्रति माह वृद्धि हुई जबकि प्रति सप्ताह नकव ग्राय में ० १२६ की वृद्धि हुई।
- (11) कागज उद्योग में, १६४८-१६५३ के बोच मजदूरों की श्रीसत श्राय में तो चृद्धि हुई किन्तु इनकी उत्पादकता बढ़ने का कोई चिन्ह नहीं था।
- (111) जूट उद्योग में १६४८-१६५३ के बीच उत्पादकता की वृद्धि २६ प्रतिवर्ष थी जबिक श्रार्जित श्राय की वृद्धि ३७ थी तथा,
- (1v) स्ती वस्त्र उद्योग में उत्पादकता की वृद्धि की वार्षिक दर १६४८-१६५३ के बीच २.२८ थी जबकि अर्जित आय की वृद्धि १ १४ थी।'

इसके विपरीत श्रमरीका श्रीर ब्रिटेन के श्रमिक की कार्यच्चमता में निरन्तर
चृद्धि होती जा रही है। श्रमरीकी श्रमिक की प्रतिष्या उत्पादन च्चमता में १६१०
तया १६४० के बीच द्र प्रतिशत वृद्धि हुई । विगत १५ वर्षों में इसमें श्रीर श्रिषक
चृद्धि हुई है। यह बताया गया है कि यदि उत्पादन चमता इसी श्रनुपात में बढ़ती
गई तो ३० वर्ष में टोगुनी हो जायगी । उत्पादन शक्ति की जाच करनेवाली एक
श्राग्ल-श्रमरीकी परिपद् ने ब्रिटेन के लोहे श्रीर इस्पात के कारखाने के कुछ
विमागों की जाच की । परिषद् की रिपोर्ट में बताया गया है कि १६१६ से १६५२
के बीच स्टील फोडिंग में १५ से २० प्रतिशत की श्रीर ड्राप-फोडिंग में १० प्रतिशत
की वृद्धि हुई है। ऐसे ही श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। श्रनेक कारणों से
भारतीय श्रमिक की कार्यच्चमता निरन्तर घटती जा रही है। यहाँ यह बता देना
श्रमुचित न होगा कि कार्यच्चमता में कभी होने के लिये केवल भारतीय श्रमिक ही
उत्पद्धि नहीं है। इसका बहुत कुछ कारण खराब मशीनें श्रीर दोप पूर्ण अर्थों नहीं है। परन्तु इसका परिणाम यह श्रवश्य हुशा है कि भारतीय
अर्थोगिक सगठन है। परन्तु इसका परिणाम यह श्रवश्य हुशा है कि भारतीय
अर्थोत्त की प्रतियोगिता शक्ति घट गई है श्रीर विश्व बाजार में श्रपने माल की
निकासी करने में उसे श्रत्यन्त कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है।

कार्य-अमिक की कार्यच्मता अथवा उसकी निपुण्ता की परिभाषा करना बहुत फाउन है श्रीर यह श्रनेक बातो पर निर्भर करती है। अमिक की कार्यज्ञमता की जाँच करने का एक व्यवहारिक दुग श्रमिक के प्रतिघएटा उत्पादन की जाँच करना है। एक अभिक की एक शिफ्ट के कुल उत्पादन के हिसाब से भी कार्यज्ञमता का पता लगाया जा सकता है। एक शिफ्ट में ७३ या द घएटा कार्य होता है। इसके साथ ही अमिक के वार्षिक उत्पादन की मात्रा को भी इसका साधन बनाया जा सकता है। श्रमिक की कार्यज्ञमता केवल श्रमिक के श्रम पर ही निर्मर नहीं रहती है। कच्चे माल के प्रकार, मशीनों के प्रकार और उनकी हिथति श्रीर संपूर्ण श्रोद्योगिक सगठन का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अकुशलता श्रयवा निपुर्ण न होने के लिये सारा टोप भारतीय श्रमिक पर ही नहीं मढा जा सकता। कुछ दोष ग्रवश्य अभिक का भी है परन्तु जिस प्रणाली के श्रन्तर्गत वह कार्य करता, है उसे इस ग्रारोप से वंचित नहीं किया जा सकता। जब इस भारतीय अमिक की कार्यचमता श्रीर ब्रिटेन, श्रमरीका या श्रन्य देशों के अमिकों की कार्यज्ञमता की तुलना करते हैं तो हमें दोनो देशों के कारखाने में लगी मशीनों श्रीर कार्य की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। परन्तु फिर भी इन सभी बातो पर विचार करने के बाद भी यह सही है कि भारतीय श्रमिक की कार्यज्ञमता श्रमरीकी तथा ब्रिटिश श्रमिक की कार्यचमता से कम है।

मारतीय श्रमिक के श्रकुशल होने के श्रनेक कारण वताये गये हैं: (१) श्रमिक की श्रस्वस्थता, (२) कुशलता का श्रमान, (३) उसका प्रवाजी स्वभाव, (४) जलवायु, (५) श्रामिक का कम वेतन, (६) मारतीय उद्योग द्वारा प्रयोगत्में लाये जाने वाले कच्चे माल का घटिया प्रकार, (७) टूटी-फूटी और पुरानी मशीनें श्रीर बहुत से कारखानों मे दोष पूर्ण श्रमिन्यास श्रीर (८) श्रकुशल श्रीद्योगिक सगठन।

दुर्वेल शरीर तथा बुरा स्वास्थ्य—इसमें कुछ सन्देह नहीं कि भारतीय अभिक का स्वास्थ्य विदिश या श्रमरीकी अभिक की अपेदा गिरा हुश्रा है। प्रश्न मारतीय अभिक और विदिश श्रथवा श्रमरीकी अभिक को काम करता है वह उस काम के लिये उपयुक्त है या नहीं। यदि वह उस काम के लिये उपयुक्त है वा नहीं। यदि वह उस काम के लिये उपयुक्त है तो यह कहना उचित नहीं कि विदिश अथवा अमरीकी अभिक की अपेदा स्वास्थ्य अधिक खराब होने के कारण भारतीय अभिक की कार्यच्चमता अपेदाकृत कम है। स्वास्थ्य उतिक न रहने पर विदिश, अमरीकी प्राय. सभी अभिको का उत्पादन गिर जाता है, उनकी कार्यच्चमता कम हो जाती है। इसलिये भारतीय अभिक की श्रकुशसता का कारण उसकी बीमारी या दुर्वलता नहीं हो सकते हैं।

- (11) प्रवासी प्रवृत्ति—भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति से भी उसकी श्रकुशलता नहीं सिद्ध की जा सकती क्योंकि जनतक श्रमिक काम करता है तनतक श्रीयोगिक केन्द्रों में रहता है श्रीर इस बीच वह श्रपनी सम्पूर्ण योग्यता के श्रनुकूल कार्य कर सकता है। बीच-बीच में गाँव चले जाने से एक निश्चित लाभ यह होता है कि कारखाने के काम से कुछ दिन का श्रवकाश ले कर कारखाने के नियमित कार्य से श्रजग हो जाने के कारण एक नई शक्ति प्राप्त करता है इससे पुन. कारखाने लीटने पर वह पहले की श्रपेचा श्रीयक कार्य कर सकता है।
- (111) कुरालता का प्रभाव—इसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि कुरालता न होने के कारण ही उसकी कार्यज्ञमता कम है, क्यों कि यदि श्रमिक एक विशेष कार्य करता है तो इसका कारण ही यह है कि वह इस कार्य को श्रन्य कार्यों की अपेज्ञा श्रव्छी प्रकार कर सकता है। कुशलता का श्रमाय तभी होता है जब कुशल टेकनीशियनों का श्रमाय हो परन्तु जहाँ कुशल टेकनीशियन काम करते हैं वहाँ उनकी कार्यज्ञमता उतनी ही शिक्षा पाये हुए श्रन्य देशों के टेकनीशियनों से कम नहीं होनी चाहिये। जहाँ तक ऐसे कार्य का सम्मन्य है जिसको करने में विशेष कुशलना की श्रावश्यकता नहीं होती है वहाँ कुशलता के श्रमाय का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (1V) कम मजदूरी यह कहा जाता है कि पारिश्रमिक कम होने के कारण ही अमिक की कार्यद्ममता कम है। इसके समर्थन मे यह तर्क दिया जाता है कि कम पारिश्रमिक होने से श्रमिक ग्रपना श्रीर ग्रपने परिवारका ठीक से भरण-पोषण नहीं कर पाता है। इससे उसकी कार्यज्ञमता पर बुरा प्रभाव पहला है। परन्तु यह जानना चाहिए कि इन सब बातो का कारण पारिश्रमिक कम होना नहीं है वरन् मूल्य स्तर की तुलना मे पारिश्रमिक का श्रमाव है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक कम हो श्रीर जिन वस्तुश्रों पर वह अपना पारिश्रमिक व्यय करता है उन के मूल्य ख़ौर भी कम है। तो उसे ख्रपने परिवार का भरख-पोष्या करने में कुछ कठिनाई नहीं होगी। वह अपनी आवश्यकता पृति के लिए सभी वस्तुएँ क्रय कर सकता है। वास्तव में मुख्य समस्या यह है कि पारिश्रमिक वस्तुत्रों के मुल्य की श्रुपेचा कम है। इसी कारण श्रिमक श्रवने परिवार को पेट भर भोजन नहीं दे पाता है और उसकी श्रन्य श्रावश्यकताएँ भी पूर्ण नही हो पाती। इससे उसकी कार्यज्ञमता की ज्ञति होती है। प्रश्न पर्याप्त भोजन न पाने आरे जीवन को सुखी बनाने के प्रसाधनों को न पाने का नहीं है। बास्तव में श्रमिक बस्तु हों के मूल्य की त्रपेक्षा पारिश्रमिक कम होने के कारण परिवार का ठीक तरह से प्रबन्घ भी नहीं कर्पाता । इससे उसे सदैव चिन्ता लगी रहती है जिससे ऋत मे उसकी कार्यसमता

पर प्रभाव पहला है। इस प्रकार एक दुष्चक स्थापित हो जाता है; उसकी कार्यच्रमता घट जाती है श्रीर उत्पादन कम हो जाता है। पारिश्रमिक होने से कार्यच्रमता घट जाती है श्रीर उत्पादन कम हो जाता है। पारिश्रमिक होने से कार्यच्रमता नहीं बढ़ पाती है श्रीर जब तक कार्यच्रमता में वृद्धि नहीं होती पारिश्रमिक नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि भारतीय श्रमिक इतने वर्षों के परचात् भी श्राज निर्धन ही बना हुश्रा है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक वढ जाय श्रीर इसके फलस्वरूप उसकी कार्यच्रमता में भी वृद्धि हो तो वह भविष्य में श्रीर श्रमिक पारिश्रमिक कमा सकता है। जहां तक पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, दितीय महायुद्ध से श्रमकों की स्थित में सुधार हुश्रा है। १९४२ से १९५२ के बीच भारतीय श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई परन्तु दुर्माग्य से पारिश्रमिक बढ़ने के साय-साय वस्तुश्रों के मूल्यों में मी वृद्धि हुई ग्रीर श्रमेक वस्तुश्रों की कीमतों में मजदूरी की श्रपेचा बहुत श्रषिक वृद्धि हुई। १९४२ श्रीर १९५२ के बीच मजदूरी की बास्तविक पारिश्रमिक में वहुत वृद्धि नहीं हुई। जब तक वास्तविक पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं होती श्रपीत् श्रपने द्राज्यिक पारिश्रमिक से वस्तुश्रों श्रीर सेवाश्रों को श्रियक मात्रा में नहीं खरीद पाता श्रमिकों की कार्यच्यमता में वृद्धि नहीं हो छकती श्रीर यह द्रष्चक नहीं दृर सकता।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय अभिक की मजदूरी कम हैं। यद्यपि हाल में द्राञ्यिक तथा वास्तविक मजदूरी में दृद्धि हुई है किन्तु इसके साथ भारतीय अभ की श्वमता में वैसी वृद्धि नहीं हुई है। अस-मजालय के अस-कार्यालय द्वारा १६५६ में फैक्ट्री की अर्जित आय सम्बन्धी प्रकाशित विवरण से निम्न रोचक निकर्ष निकलते हैं:—

१—मारत में फैन्ट्री में काम करने वालो की कुल अर्जित श्राय (रेलवें वर्कशाप धिम्मिलित नहीं है) १६४७ में १३७३ करोड रु० यी जो १६५५ और १६५६ में बढकर कमश. २४५ करोड रु० २६६ ५ करोड रु० हो गई। स्थायी उद्योगों में लगे तथा २०० रु० प्रति माह से कम पाने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय १६४७ में ७३७ रु० थी। १६५५ और १६५६ में बंदकर यह क्रमश. १,१७४ रु० तथा १२१३ रु० हो गई।

२-१६४७ से १६५६ तक दस वर्षों में भारतीय उद्योगों में मजदूरों की वापिक श्राय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। चमड़ा उद्योग में ४% तथा छीमेन्ट उद्योग में १६३% हुई है। छम्पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुये कहा जा सकता है कि प्रति मजदूर वार्षिक श्राय में ६६% की वृद्धि हुई है।

३—अम कार्यालय द्वारा प्रकाशित श्रॉकडे वास्तविक श्राय श्रयवा रहन-सहन के स्तर में कोई सुघार नहीं प्रकट करते। १६४७ से १६५६ के बीच में अभिक वर्ग से सम्बन्धित मूल्यों में २१% की वृद्धि हुई है तथा सामान्य मूल्य स्तर में ३२% की वृद्धि हुई है जब कि श्रौसत द्राव्यिक मजदूरी में ६३% की वृद्धि हुई है। इससे रहन-सहन के स्तर में होने वाली वृद्धि का श्रानुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि द्राव्यिक एवम् वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई है किन्तु भारतीय श्रम की उत्पादकता में उस श्रानुपात में वृद्धि नहीं हुई है।

- (v) जलवायु—श्रिमिक की कार्यज्ञमता में कमी होने का एक महत्वपूर्ण कारण भारत की जलवायु है। वर्ष के श्रिषकाश भाग में न केवल श्रीचोगिक श्रिमिकों को यरन सभी लोगों को श्रालस्य श्रीर शिथिलता वेरे रहती है। इससे कठिन परिश्रम का काम एक प्रकार से श्रममंग हो जाता है। ब्रिटिश तथा जापानी श्रमिक की श्रपेज्ञाइत श्रिषक कार्यज्ञमता का एक कारण उन देशों की जलवायु भी है। भारत में भी विभिन्न ज्ञेत्रों के श्रमिकों की कार्यज्ञमता में जलवायु के श्रमुरूप श्रतर है।
- (v1) भारतीय उद्योगो द्वारा घटिया माल का उपयोग—मारतीय श्रमिक की कार्यक्रमता कम होने का दूसरा महत्यपूर्ण कारण यह भी हैं कि भारतीय उद्योग प<u>टिया प्रकर के कच्चे</u> माल का उपयोग करते हैं, कारखानों मे पुरानी श्रीर विसी टूटी मशीने हैं, मिलो के नियोजन में टोप हैं श्रीर श्रीसोगिक सगटम खराव है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मिल-मालिको पर है। यदि वह श्रुच्छे प्रकार का कच्चा माल दें और कारखानो मे अच्छी मशीनें लगाये तो भारतीय अमिक की कार्यज्ञमता बढेगी और श्रमिक के प्रति वरुटा उत्पादन की मात्रा भी पहले की श्रपेचा श्रधिक होगी। कारखानों में पुरानी मशीनो के स्यान पर्श्राष्ट्रिक मधीनों को लगा सकना वर्तमान में सुभव नहीं हो सका क्योंकि (१) इसके लिए आवश्यक वित्त का अभाव है, (२) मशीनों इत्यादि ओर टेकनिकल सामान का उपलब्ध हो सकना कठिन है, (३) मारतीय मिल-मालिक आधुनिक मशीनों के लाभ से ऋपरिचित हैं श्रोर (४) कारखानों के युक्तिकरण का अमिकों द्वारा विरोध किया जाता है। भारतीय अभिक मशीनों के युक्तिकरण का श्रोर पुरानी घिसी मशीनों को वदलने का तीव विरोध करता है। अमिकों का कहना है कि इससे वेरोजगारी होतो है। भारतीय अमिक की कार्यंत्तमता कम है क्योंकि कारखानों की मशीनें पुरानी और घिसी-पिटी हैं इसलिए जब अमिक इन मशीनों को बदलने का विरोध करता है तब वास्तव में वह अपनी कार्यद्ममता में मुधार को रोकता है। युक्तिकरण के श्रम्याय मे बताया गया है कि मशीनो के युक्तिकरण से वेरोजगारी फैलना आवश्यक नहीं है, यदि बेरोजगारी फैलती है तो सभी लोगों की तरह श्रमिकों को भी प्रगति के लिए यह कष्ट फेलना ही पडेगा। यदि मर्शीनो

में मुधार होने से वेरोजगारो फैलती है श्रीर श्रिमकों की कुछ ज्ञति होती है तो दीर्घ काल मे श्रिमक की कार्यज्ञमता में वृद्धि होने से श्रीर श्रिमक पारिश्रमिक मिलने से यह हानि लाम में बटल जाती है।

श्रीमक की कार्यचमता की कमी बहुत कुछ उसकी मान्सिक रिग्रति पर निर्भर करती है। कार्यचमता में कमी होने के सभी कारणों में प्रमुख यह है कि मारतीय श्रीमक विलास प्रिय है श्रीर उसमें अनुशासन का श्रभाव होता है। जब तक श्रीमक श्रपने उत्तरदायित्व को नहीं समसता श्रीर जब तक मिल-मालिक के श्रीर श्रपने हितों को समान नहीं समसता तब तक वह श्रपनी पूर्ण योग्यता एवम् चमता से कार्य नहीं करता है। उत्पादन शक्ति रखते हुए भी श्रपनी कार्यचमता में कमी बनाये रहता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद श्रमकों की विचार घारा में पहले की श्रपेचा श्रीर बुराई ग्रा गई है। श्रमकों ने कारखानों में काम धीरे करने की नीति ग्रपना ली है जिसका श्रर्थ यह है कि कार्य करने के लिए निर्धारित समय में श्रमिक उचित परिश्रम करने के स्थान पर कार्य श्रद्यन्त धीरे-घीरे करके श्रपना समय नष्ट करता है। श्रमिक द्वारा 'काम धीरे-चीरे करें नीति श्रपनाने का एक कारण मालिकों को श्रपनी माँगें मानने के लिए मज़बूर करना है। परन्तु इस उद्देश्य के पूरे होने के स्थान पर इसके विपरीत उत्पादन कम हो गया है ग्रीर इससे उसकी स्थिति श्रीर भी विग्रस गई है।

मारतीय श्रमिकों में श्रनुशासन के श्रभाव को गत कुछ वधों में (१) उत्पादन के श्राधार पर नहीं बिल्क केवल उपस्थित के श्राधार पर महगाई मचा, बोनस हत्यादि देने से बढावा मिला है। महगाई मचे को श्रमिक के रहन-सहन के ब्यय में सम्मिलित कर दिया गना है। श्रमिक चाहे श्रपना कार्य पूर्ण करे या न करे उसे महगाई मचा मूलन के देशनाँकों के श्रनुकूल श्रवश्य मिलता है। इस कारण श्रमिक श्रपने उत्पादन श्रयवा श्रपने कार्य की किचित् मात्र भी चिन्ता नहीं करता है। यदि महगाई भचे को उत्पादन पर श्राधारित कर दिया जाता तो श्रमिक ऐसा नहीं करता। साथ ही निर्धारित मात्रा से श्रिषक उत्पादन करने पर श्रमिक का नोनस श्रीर महगाई भचा बढता श्रीर उत्पादन बहता, (२) इन्हिस्ट्रयल हिस्प्रूट्स एक्ट के पास होने के पहिले तक श्रीन्त्रोगिक कनास्त्रों पर समक्तीते श्रीर पन्चिनर्ण्य प्रणाली के श्रन्तर्गत उद्योग श्रथवा कारखाने के मालिक को श्रपने कर्मचारी को निकालने का श्रिकार नहीं था, चाहे कर्मचारी श्रकुशल हो या काम लापरवाही से करता हुशा पाया गया हो। ऐसे मामलों में नौकरी से ग्रलग करने का निर्णय समकौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, या श्रीद्योगिक न्यायालय करते

थे । इसके परिखाम स्वरूप कार्यज्ञमता को ज्ञित पहुँची है श्रीर अभिक के प्रति घन्टे उत्पादन की मात्रा गिरी है।

दोष दूर करने के उपाय-भारत में श्रमिकों की कार्यसमता की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है श्रीर इसको सुधारने के लिए सरकार को, मिल-मालिकों श्रीर श्रमिक नेताओं को बहुत श्रधिक परिश्रम करने की श्रावश्यकता है। यदि इस टिशा में पूरी शक्ति से प्रयत्न नहीं किया गया अीर केवल शाशिक प्रयत्न किए गये तो समस्या सुलक्तने की समावना कम है। भारतीय अभिक की कार्यज्ञमता बढ सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि (१) महगाई भत्ता, बोनस इत्यादि उत्पादन के ग्राधार पर दिए जार्चे। यह श्रावश्यक है कि अमिक का म्यूनतम पारिश्रमिक श्रीर उसके कार्य की मात्रा निश्चित कर दिए जॉय। श्रमिको के लिये एक न्यूनतम पारिश्रभिक इस शर्त पर निश्चित कर दी जाय कि वह एक निश्चित मात्रा में कार्य करे। इसके उपरान्त पारिश्रमिक मे वृद्धि हो सकती है पर वृद्धि का अनुगर्यन ऐसे सूत्र के आचार पर होगा जिसमे रहन सहन की लागत श्रीर श्रमिक की उत्पादकता दोनों ही बातों का विचार सम्मिलित हो। इससे श्रमिकों के हित की रज्ञा यदि रहन सहन के व्यय में वृद्धि हो गई तो होगी श्रोर साथ ही साथ यदि उनकी उत्पाटकता घट जायगी तो मिल मालिकों का मी हित उपेज्ञित न हो सकेगा, (२) काम धीरे करों नीति को श्रीवोगिक क्रगड़े के श्चन्तर्गत समक्तना चाहिए। यदि अमिक 'काम घीरे करो' नीति श्चपनाएँ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मिल-मालिक सममीता बोर्ड इत्यादि के द्वारा अपनी शिकायत दूर करा सकें, (३) यदि श्रीमक अञ्च्छी प्रकार कार्य न करें अपीर निर्धा रित मात्रा में उत्पादन न करे तो उद्योगपित अथवा मिल-मालिक को उन्हें निकालने का ग्रिषकार दिया जाना चाहिए, (४) आलस्य, उत्तरदाथित्व को टालने की मावना श्रीर अनुशासन के श्रमाव को दूर करने के लिए सरकार को श्रीर अभिक नेताग्रो त्रादि को निरन्तर प्रचार कार्य करते रहना चाहिए। यदि उसका ध्यान बारम्बार इस दृश्य की स्रोर श्राकषित किया जायगा कि उसकी कार्यवाही से वह उद्योग नष्ट हो सकता है जिस पर उसकी समृद्धि निर्मर करती है तो अवश्य ही श्रमिक की स्थिति में सुघार होगा और उसका दृष्टिकीण बदलेगा। यद्यपि यह कार्य बहुत धीरे-धीरे होगा परन्तु दीर्घकाल मे श्रमिक की कार्यज्ञमता वढाने मे इसका बहुत अधिक प्रभाव पहेगा, (५) श्रमिक की उत्पादन शक्ति का अन्ययन करने के लिए और उसको प्रोत्साइन देने के ब्रिटिश पोढिरिटविटी कौंसिल के समान एक विशेष सगठन भारत में भी स्थापित करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ के उत्पादन शक्ति का श्रध्ययन करने वाले दल ने वम्बई स्ती मिल उद्योग में जो कार्य किया है उससे भारतीय स्ती उद्योग का उत्पादन बढ़ने की समावना है। इस दल ने सुक्ताव दिया है कि कारखानों में सभी कार्य श्राधुनिक रीति से किया जाय श्रीर वर्तमान स्थित का गंभीर श्रध्ययन करने के बाद उद्योग के सगठन की योजना बनाई जाय। श्रीद्योगिक कार्यज्ञमता में वृद्धि करने के लिए श्रावश्यक सुक्ताव देने को विभिन्न उद्योगों में तत्सम्बन्धी श्रस्थयन की ब्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्याय ३१

श्रोद्योगिक सम्बंध

श्रीयोगिक उत्पादन गढाने, श्रीमकों की श्रार्थिक स्थित को सुघारने श्रीर देश को श्रार्थिक दृष्ट में समृद्रणाली बनाने के लिये श्रीयोगिक शांति का श्रत्यन्त महत्य है। यदि दृदतालें होती हैं, मिलो-कारपानों में तालाबन्दी की जांती है श्रीर श्रीयोगिक शांति भग की जांती है तो उत्पादन घटने लगता है, उत्पादन व्यय में वृद्धि होने लगती है श्रीर श्राय कम हो जाने से श्रमकों को श्रनेक किंदिनाइयों का समना करना पहता है। बाजार में वस्तुश्रों की पूर्ति नियमित रूप से न होने या उनकी पूर्ति में किंसी प्रकार की बाधा श्रा जाने से उपभोक्ताश्रों को भी किंदिनाइयों का समना करना पहता है। श्रीयोगिक चेंत्र में श्रशांति होने ने सम्पूर्ण देण की शांति भग हो जाती है श्रीर इससे किंसी को लाम नहीं होता। पूर्जीबादी व्यवस्था में तालाबटी का होना श्रावश्यक नहीं है। यदि उचित ध्यान रपा जाय श्रीर व्यवस्था ठीक हो तो हन बाधाश्रों को पूरी तरह समाप्त न भी किया जा सके तो रम से कम टाला श्रवश्य जा सकता है।

श्राधुनिक प्रवृत्तियाँ-मारत के श्रीद्योगिक होत्र में शांति बनाये रखना सदैव सभव नहीं रहा है। द्वितीय विश्व यद के काल में श्रीद्योगिक कगड़ों की **ग**ण्या श्रीर इन कगड़ा के कारण नष्ट हुए कार्य के दिनों की वंख्या काफी कम रही है। आँकड़ो से प्रकट होता है कि १६४३ में जब कि युद्ध अपनी चरम सीमा पर था हड़ताल एवम तालावन्दियों से केवल २३ लाख कार्य के दिन नष्ट हए। १६४४ में यह सख्या नदकर ३४ लाख दिन स्रोर १६४५ में ४१ लाख दिन हो गई। यह सख्या फिर भी श्रपेनाकृत कम रही, इसकी अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है। युद्ध के समय ग्रीन्त्रोगिक सम्बन्ध काफी ग्राच्छे रहे क्योंकि (१) श्रमिक ने सरकार को लड़ाई में सहयोग देने का वचन दिया श्रीर वह यह नहीं चाहते थे कि उत्पादन में किसी प्रकार की गांधा पड़े श्रीर यद का सफल सचालन कर सकने में किसी प्रकार की बाधा पड़े। (२) उस समय वस्तुत्रों के भाव में तथा रहन-सहन के न्यय में वृद्धि की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। इसी समस्या से ही बाद में ख्रीद्योगिक मगडे उत्पन्न हुए। १६ अगस्त १६३६ को समाप्त होनेवाले सप्ताइ को श्राधार मानते हुए १६४१-४२ श्रीर वाद के चार वर्षों में सामान्य मूल्य के देशनाक क्रमशः १३७ ०, १७१ ०, २३६ ५ २४४ २ श्रोर २४४ ६ रहे। वस्तुत्रों के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी परन्तु इसी समय वेतन में भी त्राशिक वृद्धि हो गई थी। इसमें मालिक तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध विशेष खराव नहीं हुए, (३) युद्ध के समय भारतीय प्रतिरक्षा नियम की घारा दश-ए लागू थी जिसके श्रमुसार श्रौद्योगिक सगडों का निपटारा करने के लिए सरकार को सकट कालीन श्रिष्ठकार दिये गये थे। सरकार श्रशाति के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने को स्वतत्र थी।

परन्तु युद्ध के समाप्त होते ही, श्रीर विशेषकर स्वतन्नता प्राप्त होने के पश्चात श्रीद्योगिक मगर्डों की छख्या वही श्रीर उत्पादन मे कमी श्रा गई। १६४६ श्रीर १६४७ में कमश १ करोड़ २७ लाख श्रीर १ करोड़ ६८ लाख कार्य के दिन नष्ट हो गये जब कि १६४५ में केवल ४१ लाख कार्य के दिन नष्ट हुए । श्रीद्योगिक कगड़ों मे इतना वृद्धि होने का कारण यह था कि (स्त्र) स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पर्चात् श्रिमिक के दिल में नई आशाएँ जगी थीं। श्रिमिक अपनी आर्थिक स्पिति को सुघारना चाहते थे त्रौर इसी के परिखाम स्वरूप इइताले हुई। सरकार की थम नीति ने मी जिसका उद्देश्य श्रमिकों का पारिश्रमिक बढाना श्रौर कार्य की स्थिति में सुघार करना था, इसमें काफी योगदान दिया, (ब) युद्ध काल की ऋषेज्ञा चीजों के माव में अधिक वृद्धि हुई। १६४५-४६ में थोक विकी के माव का देशनाक र४४ ९ या परन्तु १९४६-४७ में वढ कर २७५ ४ त्रोर १९४७-४⊏ में ३०७ हो गया। वस्तुर्यों के मूल्यों में तो वृद्धि हुई परन्तु वेतन ऋथवा प।रिश्रमिक में इसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। इससे अमिक को अनेक कठिनाट्यों का नामना करना पड़ा । परिगामत्वरूप अमिकों ने वेतन अथवा पारिअमिक बढवाने के लिए इडताले कीं, (च) मारतीय प्रतिरत्ता नियम के लागून रहने से अमिको ने एक छूट का त्रनुमव किया। त्रव श्रमिकां की इच्छा भी युद्ध के समय की तरह कटोर परिश्रम करके उत्पादन बढाने की नहीं रही थी।

रियति काफी गभीर रूप घारण करती गई और १६४७ के दिसम्बर में मारत सरकार नो श्रौद्योगिक शांति सममौता कराने के लिए हस्तचेप करना पड़ा। इससे भारत में श्रौद्योगिक सम्बन्ध सुधारने में काफी सहायता मिली। श्रीमक के श्रान्दोलन और सरकार के हस्ताचेप करने में पारिश्रमिक में वृद्धि हुई, में हगाई भत्ता, बोनस और लामाश में श्रीमकों के माग में भी वृद्धि हुई। यह कहा गया कि द्रव्य में श्रीमक का पारिश्रमिक बढ़ने में श्रीमक का वास्तविक पारिश्रमिक नहीं बढ़ा और यदि रुपये को क्रय शक्ति की हिष्ट से देखा जाय ता ज्ञात होगा कि श्रीमकों की स्थिति युद्ध से पूर्व के वर्षों की श्रुपेज्ञा कहीं श्रीधक विगइ गई। इस तर्क में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गगा है कि मूल्य बढ़ जाने से केवल श्रमिक को ही नहीं बल्क सभी वर्गों की जनता को कितनाइयों का सामना करना पड़ा।

प्रश्न यह नहीं है कि असिक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या नहीं; धास्तव में विचारणीय बात यह है कि क्या श्रमिकों को समाज के ग्रन्य लोगो की अपेदा अधिक कष्ट सहने पहे १ यद्यपि अमिकों के कुछ वर्ग ने अधिक वेतन श्चथवा पारिश्रमिक की मांग करते हुए आन्दोलन जारी रसा परन्तु जहाँ तक पूरे अमिक वर्ग का प्रश्न है वह सन्तुष्ट रहा और इहतालों की सख्या भी घट गई। मिल मालिकों ने तालाइन्दी घोषित नहीं की क्यों कि पारिश्रमिक में वृद्धि होने के साथ ही उत्पादित माल के मूल्य में भी वृद्धि हुई श्रीर बाजार विकेता के श्चनुक्ल हुढ होने के कारण भिल मालिकों को श्राधिक हानि नहीं उठानी पडी। इसके साथ ही श्रीद्योगिक कगडे सम्बन्धी कानून के ख्रन्तर्गत कगडे सुलकानेवाली उस्था क्रमशः अधिक प्रभावशाली बनाई गई श्रीर समसीते तथा अनिवार्य पचित्रांप के द्वारा अनेक होने वाले श्रीहोगिक मगडों को जो श्रवश्य उत्तन होते रोक लिया गया । १६५० में कुल नब्ट हुए अम-टिनो की सख्या १२८ १ लाख हो गई परन्तु इसका कारण सर्वत्र त्रीद्योगिक सम्बन्धां का विगड़ना नही बल्कि सूती मिल उद्योग की लम्बी इडताल थी। कुल नष्ट हुए १२८१ लाल दिनों में से १३ लाख दिन अनेले स्ती उद्योग में ही नष्ट हुए। अप्रौद्योगिक समसौते के पश्चात् से मारत में श्रीद्योगिक शांति श्रविक मग नहीं हुई है श्रीर उक्त तालिका के श्रमुसार नष्ट हुये श्रम-िटनों की सख्या घटकर १६५१ मे ३८२ लाख, १६५२ में ३३ ४ जाल, १६५३ में ३३ ५ लाख हो गई। १६५६ मे ६८ ६ लाख अम दिन नव्ट हुये। श्रीद्योगिक क्तगबो की सल्या १,२०३ तथा उनसे सम्बन्धित श्रमिको की सख्या ७१५,१३० थी। १६५७ मे ६४ लाख अमदिन नष्ट हुये तथा श्रीद्योगिक सगडों की सख्या २,०५६ तथा उनसे सम्बन्धित असकों की संख्या १,०१८,६२५ थी। नष्ट हुये ६४ लाख अस-दिनों मे स्ती वस उद्योग मे १५ लाख दिन, कोयला तथा अन्य खदान उद्योगो में लगभग १० लाख, रोपण तथा जूट उद्योग मे लगभग ५ लाख अम दिन नष्ट हुवे।

कानूनी व्यवस्था—एक जनतत्रवादी देश में जहाँ उद्योग स्वतत्र है श्रपनी मॉग के श्रतुसार उचित वेतन श्रथवा पारिश्रमिक न मिलने पर श्रमिक को अन्य उपाय असफल रहने के पश्चात् अत में हडताल करने का अधिकार है ग्रीर यदि मालिक अभिकों के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हो तो उस भी तालावन्दी घोषित करने का पूर्ण अधिकार है। यद्यपि जनतत्री शासन व्यवस्था मे यह श्रिधिकार निहित हैं फिर भी बिना सार्वजनिक हित पर विचार किये इन श्रिविकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इइताल होने से या तालावन्दी घोषित की जाने से उपभोक्ता को भी अनेक कठिनाइयाँ उठानी पहती है। अभिक तथा मिल मालिकी द्वारा कमश इइताल श्रीर तालाबन्दी के श्रपने मूलभूत श्रिषकारों के प्रयोग के प्रति जनता श्रीर सरकार उदासीन नहीं रह सकते । उचित रीति से समक्तीता वार्ता चलाने श्रीर एक दूसरे की किठनाइयों को समक्ती हुए श्रीयोगिक क्ष्मांडे को सुलक्काना सदैव सभव है। श्रीयोगिक क्षमांडे सम्बन्धी कानून का उद्देश्य यह है कि क्षमांडा होने पर मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच समकीता करने के लिए साधन खोजा जाय। इस कानून में विभिन्न परिस्थितियों के श्रानुक्ल भिन्न भिन्न साधनों की ज्यवस्था की गई है श्रीर किसी भी श्रीयोगिक क्षमांडे मे समक्तीते तथा पचनिर्णय में जितना समय लगना चाहिए उसकी श्रविध भी निश्चित कर टी गयी है। इसमें मामले पर विचार करने की पूर्ण विधि विस्तार से दी गई है। भारत तथा ससार के श्रनेक देशों में यह देखा गया है कि कार्य की श्रविषट रूपनेखा के कारण श्रम उत्पन्न हो जाता श्रीर इससे श्रीयोगिक मतभें हो जाता है। श्रम कार्यन का यह उद्देश्य है कि इस प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न होने ले रोका जाय श्रीर यदि भ्रम उत्पन्न हो गया है तो उसे दूर किया जाय।

१६२६ का भारतीय व्यापारिक विग्रह कानून—इस कानून में सार्व-निक उपयोगिता की सेवायों तथा श्रन्य उन्योगों के लिए पृथक व्यवस्था की गई थी। मार्वजिनिक उपयोगिता सेवार्ये जैसे रेलवे डाक तथा तार, विजली श्रीर जल पूर्ति विभाग के कर्मचारियों तथा भगियों इत्यादि की इइतालों पर प्रतिवन्घ लगाया गया था। ये कर्मचारी मालिक को १४ दिन पूर्व नोटिस देने के पश्चात् ही हडताल कर सकते थे। प्रन्य उद्योगों में हडताल अपना तालावन्दी को घोषित किया बी चकता था परन्तु इन कगडों को सुलकाने के लिए एक निश्चित साधन निसुक किया गया था। श्रौतागिक कगडों के सम्बन्ध में तदर्थ जाँच समिति श्रौर समकौता परिपद् नियुक्त करने की भी व्यवस्था की गई थी। जाँच समिति में एक या एक से अधिक निष्पद्म व्यक्ति रखे जायंगे। यह समिति मामले की जाँच करने के पश्चात् श्रपनी रिपोर्ट नियुक्त करने वाली सरकार के सामने पस्तुत करेगी। समकोता परिषद् इस बात का प्रयक्ष करेगी कि दोनों पन्न साथ नैठकर श्रंपने मतमेदों को दूर करके सममीता कर लें। सममौता न हो सकने पर मामले की रिपोर्ट सरकार के पास मेज दी जाती थी। इस कानून में श्रुनिक्सर्य पचनिर्णय की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अनुसार सरकार ने केवल यही प्रयत्न किया कि दोनों पद्य एक दूसरे के और श्रिषिक निकट आ जाएँ और मामले तथा उर भगडे के कारणो को जनता को बतावे जिससे सममोता करने के लिए जनता क राय का भी बल प्राप्त हो। जनहित की सुरच्चा के लिए कानून की दृष्टि में वे इड़तालें श्रीर तालावन्दियाँ गैर कानूनी थो (क) जिनका उद्देश्य उन्नोग के श्रान्य मगडे का प्रधार करने के श्रातिरिक्त कुछ श्रीर भी हो या (ख) जिनका उद्देश्य जनता पर श्रनेक कठिनाइयाँ लादकर सरकार की विशेष कार्यवाही करने की मजबूर करना हो।

यह कानून उपयुक्त िस्द नहीं हुआ। श्रीयोगिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिए यह पर्याप्त नहीं या क्योंकि (१) समकौता श्रिधकारी श्रयना कगड़े का श्रीम निपटारा करने वाली श्रम्य सस्याश्रों के स्थान पर तदर्थ सार्वजनिक जॉच को श्रिधिक महत्व दिया गया श्रीर (२) स्याई श्रोद्योगिक न्यायालय की स्थापना के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई।

बम्बई मे १६३४, १६३८ श्रीर १६४६ मे श्रीवोगिक विग्रह कानून बनाकर उक्त कानून के दोपों को कुछ सीमा तक दूर कर दिया गया। इन कानूनों के श्रन्तर्गत मालिको द्वारा श्रमिक छघो को मान्यता दी जाने की व्यवस्था की गई थी। इन कानूनों में कराडों को मुलकाने की पूरी विधि और निश्चित अवधि दी गई थी। केवल सार्वजनिक जॉच करने की अपेदा सममौते श्रीर मगडा सुलमाने पर प्रधिक महत्व दिया गया। इस बात का निशेष ध्यान रखा गया कि कार्य की शर्ते श्ररपष्ट श्रीर श्रनिश्चित न हो क्यों कि इससे मगडे उत्पन होते हैं। इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि समकौते की शर्ते और स्थायी सभायें लिखिन भीर रिजस्टर्ड हो । क्रान्य प्रमावशाली साधनों के साथ ही स्थायी क्रीद्योगिक न्यायालय का विकास हुन्ना है। पहले के कानूनों में न्याय का मानना ऋनिवार्य नहीं था परन्तु इडताल अथवा ताले-बन्दी से पूर्व सम्पूर्ण मामले शातिपूर्ण उपाय से मुलमाने के लिए प्रस्तुत करने श्रावश्यक थे। परन्तु बम्बई के १६४६ के कानून मे पचिनर्गाय के लिए मामला प्रस्तुत करना श्रनिवार्य कर दिया गया श्रीर श्रपील करने के लिए एक अप्रालत की व्यवस्था की गई। वास्तव मे बम्बई ने इन कानूनों का बनाकर भविष्य में श्रक्षिल भारतीय पैमाने पर श्रिधिक उपयुक्त कानून बनाने के लिए मार्ग दर्शाया।

भारतीय प्रतिरत्ता नियम के अन्तर्गत कार्यवाही—पहले कहा जा चुका है कि युद्ध काल मे ओद्योगिक मगडो को हल करने के लिए सरकार ने सद्भट कालीन अधिकार प्राप्त कर लिये थे। मरतीय प्रतिरत्ता नियम की घारा दृश् (ए) के अन्तर्गत, जो जनवरी १६४२ में लागू की गयी थी, यह व्यवस्था की गई थी कि बिटिश भारत की प्रतिरत्ता के लिए, सार्वजनिक सुरत्ता के लिये, शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये युद्ध का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिये समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक सामान की पूर्ति जारी रखने के लिये सामान्य अपवा विशेष आदेश द्वारा वेन्द्रीय सरकार तालावन्दी तथा हडताल पर रोक

लगा सकती है श्रोर श्रोत्रोगिक मगटों को सममति या श्रदालती कार्यवाही के लिये मेज सकती है श्रोर श्रदालत के निर्णय को लागू कर सकती है। उस कानून में यह भी व्यवस्था की गई थी कि हदताल श्रथवा तालवन्दी की पहले से सूचना दी जाय। सममति की कायवाही की श्रविय में हदताल श्रथवा तालेकन्दी पर रोक लगा दी गई थी। स्थोकि सरमार को श्रदालती निर्णय श्रिववार्य का से लागू कर देने का श्रिवकार प्राप्त था इसलिये हम कह समते हैं कि इस नियम के द्वारा पचनिर्णय श्रिववार्य कर दिया गया था।

१६४७ का खाँचोगिक विम्रह कानून करवरी १६४७ में बेन्द्रीय सरनार ने क्रोनोगिक विम्रह कानून स्वीकृत किया। इस कानून ने बन्दें के अनुभव का लाम उठाकर १६२६ के औनोगिक निम्रह कानून के कुछ दोगों को दूर कर दिया। इस कानून में कार्य समिति, नमकीता श्रांधकारी, समकीता बोर्ड श्रीर जिन्द-श्रदालत नियुक्त करने की व्यवस्था है। इसके श्रितिरिक्त दम कानून में श्रस्थायी श्रीद्यागिक न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें उच न्यायालय के न्यायाशिश होंगे। इस कानून में परस्पर समकीता करने पर अधिक महत्व दिया गया है। पहले कानून में केवल जाच कार्य को ही महत्व दिया गया था। कार्य समितियां का कार्य परस्पर वातचीत करके मालिक तथा कर्मचारी के नीच का मतमेत दूर करने श्रोर समकीता पटाधकारियों तथा समकीता बोर्डों का कार्य दोनों पन्नों में समकीता कराना है। परन्तु यद्दि यह प्रयत्न सफल न हो तो मामले को श्रोनोगिक न्यायालय में प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। सरकार को इन न्यायालयों का न्याय पूर्ण या आशिक रूप में लागू करने का श्रांधकार प्राप्त है। इस प्रकार इस कानून में भी अनिवार्य पचिन्दार्य की व्यवस्था है।

१६५१ मे श्रीशोगिक विग्रह (संगोधन) ग्रध्यादेश जारी करके इस कानून की कुछ कियों को दूर कर दिया गया। इस श्रध्यादेश के द्वारा वे श्रीत्रांगिक इकाइयाँ मी श्रदालती नार्यवाही के त्रेत्र में श्रा गई जिनमें श्रा तक कोई क्तगढ़ा नहीं हुआ था परन्तु भविष्य में होने की समाजना थी। भविष्य में एक ही बात पर श्रन्य श्रीशोगिक इकाइयों में कागड़ा न होने देने के लिए यह श्रध्यादेश श्रावश्य के समक्ता गया। १६५० के श्रीशोगिक विग्रह (श्रम श्रपील न्यायालय) कानून से श्रम श्रपील न्यायालय स्थागित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें श्रिमनों श्रीशोगिक पच न्यायालयों, श्रोशोगिक श्रदालतों, वेतन परिपदों इत्यादि के फैसले पर की गई श्रपीलों की मुनवाई होगी। श्रम श्रपील न्यायालय के किसी श्रदालत फैसले श्रयवा निश्चय के विष्ट की गई श्रपीलों पर विचार करने का श्रधिकार है परन्तु इसकी दो शर्ते हैं (१) फैसले श्रयवा निश्चय में कोई विशेष कानूनी पैंच

हो या (२) उसका धवन्ध वेतन, वोनस, छुटनी इत्यादि से हो। विभिन्न राज्यों में त्र्योद्योगिक न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी फैसले दिये जाने के कारण जिसस देश में त्रोद्योगिक सबन्ध अधिक जिंटल होते जाते ये श्रम ग्रापील न्यायालय स्थापित करने की त्रावश्यकता श्रनुभव हुई। इसके साथ ही त्रापील करने के लिए कोई न्यवस्था न होने के कारण यह श्रीद्योगिक श्रदालते उदार निरक्कश शासक की तरह ग्राचरण करने लगी थीं। इस प्रकार की निरक्तशता और स्वच्छन्दवा जन-तत्री शासन प्रणाली के अनुकृत नहीं है। मूल कानून की ३३ वीं घारा मे यह व्यवस्था की गई थी कि समसौते के लिए किसी भी सगड़े के विचाराधीन होने के काल में कोई मालिक समभौता अधिकारी, बोर्ड अथवा पचन्यायालय की लिखित अनुमित प्राप्त किये विना न किसी कमचारी को दरह दे सकता है और न नि नाल सकता है, साथ ही मामला प्रस्तुत होने के ठीक पहले की नौकरी की हालत में वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस धारा की च्यवस्थात्रों को धारा ३३ (ए) जोडकर श्रीर बढ़ा दिया गया है। घारा ३३ (ए) में यह व्यवस्था की गई है कि यदि मालिक धारा को भग करता है तो उससे पीड़ित कर्मचारी विधिनत लिखित रूप में श्रपनी शिकायत उस पच श्रदालत के सामने पेश कर सकता है जिसमें मामला विचाराघीन है। वह पचश्रदालत उस शिकायत पर उसी रूप में विचार करेगी जैसे वह कानून की व्यवस्था के श्रनुसार पच श्रदालत में पेश किया गया श्रीद्योगिक क्रगडा हो। इस सशोधन के श्रनुसार पीड़ित कर्मचारी को मामले के विचाराधीन होने के काल में नौकरी की हालत मे परिवर्तन, छटनी, दराड इत्यादि के मामलों को छीषे पचन्यायालय में विचारार्थ अस्तुत कर सकने का श्राविकार प्राप्त है। इससे पचन्यायालय मे प्रस्तुत होनेवाले मागड़ों की सख्या भी श्राधिक बढ़ने से बच जायगी श्रोर निर्णाय भी शीव हो जायगा।

श्रा बी० वी॰ गिरि का दृष्टिकोग्र —भारत के श्रम-मन्नी श्री गिरि ने अवदूबर १६५२ में नैनीताल में हुए भारतीय श्रम-सम्मेलन के १२ वे श्रिष्वेशन में, फरवरी १६५३ में नई दिल्ली में हुए राज्य श्रम-मन्नी सम्मेलन में श्रीर श्रमेक सार्वजनिक भाषणों में बराबर इस बात पर जोर दिया है कि श्रीद्योगिक कमड़ों को वर्तमान व्यवस्था के श्रमुसार श्रमिवार्य पचनिर्णय के द्वारा नहीं बल्कि परस्पर सम्मौता करके स्वेच्छिक पचनिर्णय से इल करना चाहिए। इस योजना के अन्तगत सार्वजिक उपयोग सेवाश्रो के सबन्य में श्रमिवार्य पचनिर्णय लाग् रहेगा परन्तु ग्रम्य सस्याश्रों या उद्योगों में समक्तौता श्रयवा स्वेच्छिक पचनिर्णय लागू रहेगा। परन्तु सकटकाल में श्रीर केन्द्रीय सरकार से पहले विचार विमर्श कर लेने के बाद राज्य सरकारों को श्रोद्योगिक मामला श्रमिवार्य पचन

निर्ण्य के लिए सीपने का अधिकार होगा। श्री गिरि का मत था कि अम अपील न्यायालय को समाप्त कर दिया जाय क्यों कि कागड़ों को खापस में सलका लेने के पश्चात् इस न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं ग्रह जाती। श्री गिरि द्वारा सकाई गई योजना के अन्तर्गत मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच के सभी मत्राही पर स्वेब्छा से समसीता करना होगा। समसीता वार्ताक समन्य मे भगडे से सबन्वित कोई भी पन्न सममीता श्रिषकारी की सहायता लेने को स्वतन होगा श्रोर दुसरे पन्न को यह स्वीकार करना पडेगा। यदि इस प्रकार की समझौता वार्चा असफल हो जाती है और दोनों पत्त मामले को पर्चानर्णय के लिए सीपने को प्रस्तुत हों तो पचा का निर्णय दोनों पत्नों को मानना पड़ेगा। पटि पच परसर सहमत नहीं हो तो फगडे से सबन्धित पार्टियाँ एक निर्णायक छाँट सकती हैं जिसका फैसला दोनो पत्नों को मान्य होगा। यदि दोनो पार्टियों में निर्णायक छाँटने के प्रश्न पर मतमेट हो तो वह दोनों एक गय से मामला पच ग्रदालत को साप सकते हैं। सममीते की इन विभिन्न स्थितियों के लिए ग्रविध निश्चित होगी। राज्य सरमार्थे केवल सकट काल में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर गेर चार्वजनिक उपयोग के उद्योगों के मामलों को अनिवार्य पच-निर्णय के लिए सोप सकती हैं। परन्तु यह श्रविकार श्रन्य उद्योगों पर लागू नहीं होगा । गिरि-योजना के अन्तर्गत शमिक समितियाँ, समसीता श्रविकारो, समसीता बोड, श्रीचोगिक न्यायालय श्रीर पच श्रदालत पूर्ववत् रहेंगी परन्तु क्षम श्रपील-न्यायालय खत्म हो जायगा ।

इससे दो मुख्य प्रश्न उठते हैं (१) षथा श्रनिवार्य पचिनर्श्य हो या स्वैिच्छक पचिनर्श्य श्रोर (२) क्या अम श्रपील न्यायालय रहना चाहिए या नहीं ?

श्रानिवार्य पंचितिर्ग्य—यह कहा जाता है कि श्रानिवार्य पचितिर्गय श्रीयोगिक चेत्र में शान्ति बनाए रखने में सहायक नहीं है। स्थायी तौर पर शान्ति वर्मा रह सकती है जन परस्पर यार स्वैन्छिक समीते किये जायँ। यह भी बताया गया है कि श्रानिवार्य पचितिर्ग्य से श्रीयोगिक क्रगड़ों को प्रोत्साहन मिला है श्रीर भारत में इससे अभिक स्व क्रमजोर हो गए हैं। "अभिक सघ की व्यवस्था पर इससे कुठाराबात होता है। अभिक सघ के सदस्यों में एकता निजी स्वार्थ का ही परिणाम है। यदि अभिकों की समक्त में यह श्रा जाय कि एकता के सत्र में वँघ जाने से ही उनके स्वार्थ की सिद्ध हो सकती है तो उनके सयुक्त होने के लिये श्रन्य किसी प्रेरणा की श्रावश्यकता नहीं रह जाती। श्रानिवार्य पचितिर्ग्य उनको इस बात के लिये कोई कारण नहीं उपस्थित करता कि उनमें इस प्रकार की एकता हो '। श्रानिवार्य पंचितर्ग्य, श्रार्थिक व्यवस्था को एक ऐसी कठोरता

प्रदान करता है जिससे अन्तर्रास्ट्रीय बाजार में विकने वाली वस्तुओं के लिये

परन्तु ग्रनिवार्य पचिनिर्णय का समर्थन भी किया गया है। कहा गया है बहुत फाठनाई उपस्थित हो जाती है। कि अर्थिक दृष्टि से कम विकसित देश में श्रीद्योगिक मनाडों के कारण यदि उत्पादन कक जाता है तो इससे राष्ट्र के हितां की हानि होने की सभावना है। उत्पादन में गिरावट रोकने के लिए श्रीर परिणामतः राष्ट्रीय श्राय कम न होने देने के लिए श्रनिवार्य पचनिर्णय को लागू किया जाना चाहिए। पचनिर्णय की सफलता के लिए यह त्रावश्यक है कि (१) मालिकों तथा अभिनो के कुशल सगउन हो श्रीर (२) समसौते की कार्यवाही में उत्तरदायित्व समस्तेन वाले अनुमवी नेताओं को भाग लेने दिया जाय। चूँ कि भारत से अभिक सगठन ग्रव भी बहुत कमजीर है, ग्रीर समझीते तथा पचिनग्रिय के लिए निष्पत्त व्यक्तियों का श्रमाव है इसलिए यह समव है कि स्वैन्छिक पचनिर्णय से सन्तोषजनक परिसाम

इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम इस परियाम पर पहुँचते है कि यद्यपि सर्विज्ञनिक उपयोग के उद्योगों के लिए अनिवार्य एचिनिर्ण्य आवश्यक है न निकले। श्रीर स्कट काल मे भी यह लाभवायक साधन सिंद हो सकता है परन्तु श्रीद्योगिक मगड़ों को सुनमाने का यह सन्तोषजनक दम नहीं है। इससे प्राय ग्रीबोगिक कगढे उत्पन्न होते रहते हैं, अमिक संगठन कमजोर होते जाते हैं ग्रीर देश की

परन्तु श्री गिरि का श्रपील न्यायालय को समाप्त कर देने का सुमाव ग्राधिक व्यवस्था कठोर होने लगती है। पूर्णतया सत्य नहीं है। देश के विभिन्न भागों में समान अम स्थिति उत्पन्न करने में ग्रापील न्यायालय विशेष सहायक रहा है। वेतन, बोनस, कार्य की स्थिति इत्यादि प्रश्नों पर अपील न्यायालय के पैसलो से श्रीद्योगिक पच अदालतों को काफी लाम पहुँचा है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि प्रस्तर समसीता करके या स्वेन्छिक पर्चानर्श्य द्वारा मामला तय करके ऐसी स्थिति श्रा सकती है कि भविष्य में श्रपील न्यायालय की श्रावश्यकता न रहे परन्तु जब तक श्रीग्रोगिक पच-ग्रदालत है तब तक देश के विभिन्न भागा में अम सम्बन्धी समान स्थिति लाने भ्रौर निमन्न उद्योगों में भी एकरूपता लाने के लिए अपील न्यायालयों को समाप्त

१९४६ का औद्योगिक विम्रह कानून-एक बिल अमिकों के सम्बन्ध विषयक संसद में १६५० में रक्खा गया, पर उस पर कार्यवाही नहीं हो सकी, न किया जाय। क्योंकि मिल मालिकों भ्रीर श्रमिकां के नेताओं ने उसका बहुत विरोध किया । शह्मभू के खितम्बर में पुनर्पगेनित रूप में एक विधेयक १९४७ के श्रीयोगिम विमह कानून का खरोधन परने के लिये लोक सभा में मन्तुत किया गया श्रीम १९५६ में श्रीयोगिक निमह (संगोधन तथा निभन्न सर्तों के खाय) कानून पास किया गया। यह बढ़े तुर्भाग की बात है कि इस जानून में श्री गिरि के विचारों को बहुत ही सीमित मान्ना में सम्मिलित किया गया है। ऐसा लगता है कि उसमें श्रोयोगिक कागहा में विस्तार होगा श्रीर समझीता पठिन होगा। इस कानून के मुख्य प्रविधान, जो कि बम्बई के १९४७ के कानून के श्रानुरूप हैं, निम्न हैं —

- (१) अमिकों की परिमापा विस्तृत कर दो गई है, खोर छार छी योगिक कर्मचारी तथा देख रेख करने वाले पदाधिकारी भी जिनका वेतन ५००) माधिक से अभिक नहीं है अमिकों के अन्तर्गत रिमलित कर लिये गये हैं। उर्योकि बहुत से इस प्रकार का कार्य करने वालों को गोपनीय और सगठन सम्बन्धी कार्य दिया माया है छीर वे अभिकों की अपेक्षा मालिकों के ही विशेष छान है, इससे यह भय है कि मालिका को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़िया।
- (२) १९५० के यांचागिक नियह (श्रामील न्यायालय) कानून का प्रत्यानयन कर दिया गया है श्रीर श्रीमकों के प्रपील न्यायालय को समाप्त कर दिया गया है। इस न्यायालय के कारण देश के निभन्न भाग में श्रीमकों की हिष्यति में समानता ह्या गई थी श्रीर इसने अनेकों ऐसे लाभदायक सामान्य नियम बना दिये थे जिनके विरान्डन से मविष्य में गभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसते इम केवल एक ही अञ्छाई की आशा कर सकते हैं कि अपील न्यायालय के अभाव में सम्भवत मालिकों और श्रीमकों को स्थिति की वास्तिनिकता पर विचार करने की प्रेरणा मिले।
- (३) इस कार्न के अनुसार तीन प्रकार के मीलिक न्यायालय बनेंगे।
 (अ) अम न्यायालय, (व) ओनोमिक न्यायालय और (स) राष्ट्रीय न्यायालय। अम
 न्यायालयों को ऐसे औद्योगिक मनदों के निर्णय करने का अधिकार है जो मालिकों
 की ऐसी आजाओं के सम्बन्ध में उत्पन्न हुये हैं जिनका ओवित्य तथा नियमानुक्लता सिंदग्य है और जो स्थायी आशाओं के अन्तर्गत है तथा कर्मचारियों को
 निराले जाने के सम्बन्ध में और इस्ताल अथवा तालाबन्दी के सम्बन्ध में हैं।
 औद्योगिक न्यायालय ऐसे मनदा मा निर्णय करगा जो कि पारिअभिक, कार्य के
 बन्दे, बोनस, युक्तिकरण और छड़नी क सम्बन्ध में हैं। राष्ट्रीय न्यायालय ऐसे
 मनदों का निर्णय करेगा जो कि सरकार के मत मे ऐसे मामले हैं जिनकी राष्ट्रीय
 इिडकोण से महत्ता है, अथवा ऐसे मामले हैं जिनका सम्बन्ध एक से अधिक

राज्यों से है। इन तीन न्यायालयों के निर्णय पर अपील करने का कोई अवसर नहीं है इसिलये इनके कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी योग्यता पर विशेष न्यान दिया गया है। यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय न्यायालय अपील न्यायालय का स्थानापन नहीं है।

- (४) यह कानून स्यायी आशाओं के सम्बन्ध में आपित्तजनक परिवर्तन करता है। मालिको की किन्ही विशेष मामलों में कार्य करने की स्थिति के सम्बन्ध में बिना उन श्रीमकों को, जिनसे इसका सम्बन्ध है, २१ दिन पूर्व अपने विचारों की स्वना दिये परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह कानून श्रीध गिक रोजगार (स्थायी आशास्त्रों) कानून का संशोधन करता है और प्रमाण पत्र देने वाले विशेष पदाविकारी को तथा अन्य श्रीकारियों को इस बात का श्रीमकार प्रदान करता है कि वे प्रमाण पत्र देने के पूर्व स्थायी आशाशों की युक्तिसंगतता तथा न्याय पूर्णता पर विचार कर ले। पहिले केवल मालिक को ही स्थायी आशाशों में परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने का श्रीमकार प्राप्त था। यह कानून श्रीमकों को भी मालिकों के ही समान प्रमाण पत्र देने वाले अधिकार प्रदान करता है।
- (५) मालिकों के साथ एक विशेष ियायत की गई है, जिसे इम रियायत के स्थान पर यदि न्याय का प्रदर्शन कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। इसके अन्तर्गत मालिक को किसी कर्मचारी को, जब कि सगड़ा, निर्णयार्थ विचाराधीन हो, इस सगड़े से असम्बद्ध किसी दुराचार के लिये निकाल देने अथवा सजा देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थित में मालिक को आमिश्रुक्त अमिक को एक मास का पारिअमिक देना पड़ेगा और अपनी आजा के लिये अधिकारियों की अनुमित लेनी होगी। इससे कारखानों में अनुशासन ठीक रहने की आशा की जाती है।

इस कानून का सबसे बड़ा दोष यह है कि सरकार की श्रीशोगिक निर्ण्या को परिवर्तित कर देने का श्रिषकार दे दिया गया है। बड़ी कठिनाइयों के पश्चात् मालिकों श्रीर श्रिमकों के पारस्परिक विरोधी हितों पर सममौता हो पाता है श्रीर यदि ऐसे सममौतों को बदल देने का श्रिषकार सरकार को प्राप्त है तो इससे मामलों के श्रीर श्रिषक उलम जाने का भय है। कानून में ऐसा प्रबन्ध है कि सरकार को परिवर्तन सम्बन्धी श्राजाश्रों को ससद के समझ १५ दिन की श्रवधि तक के लिथे रक्खा जाय जिसके मीतर प्रस्ताव द्वारा ससद उसे स्वीकार करे श्रयवा श्रस्थीकार कर दे, इससे स्थिति के सुवार की श्राशा नहीं की जा सकती। वास्तिविक वात तो यह है कि यह जानते हुये कि संरकार को अपने इच्छानुकूल निर्णय बदल देने का अधिकार प्राप्त है मगड़ा जिन पत्तों के बीच है वे अपनी बात पूरी-पूरी व्यक्त न करेंगे और जल्दी समम्मीता न करेंगे। कानून की अव्छी बात यह है कि अब मगड़े में पड़े हुये टोनों पत्तों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे किसी समम्मीते के निर्णय पर इस्तान्तर कर सकते हैं। इस मगड़े को किसी पत्त निर्णायक को फैसला करने के लिये सींप सकते हैं। इस प्रवन्ध के अतिरिक्त यह कानून गिरी द्वारा प्रस्तावित संयुक्त रूप से समम्मीता करने की योजना को कोई स्थान नहीं देता। यदि गिरी के अभिस्ताव इसमें समिलित कर लिये गये होते तो अभिक और मालिक के हितों को बिना कोई हानि पहुँचाये ही पारस्परिक समम्मीते की सुविधा कुछ अधिक ही सम्भव हुई होती।

श्रीचोगिक श्रनुशासन संहिता (Code)—१६५७ में मारतीय श्रम कान्फ्रेन्स की स्थायी श्रम-कान्सि ने 'श्रीचोगिक श्रनुशासन सहिता' श्रपनाई जिसे कर्मचारियो तथा नियोक्ताश्रों के सघो ने भी स्वीकार किया। इससे भारत में श्रीयोगिक सम्बन्धों के सुधारने की श्राशा की जाती है। इसके श्रनुसार कर्मचारी तथा नियोक्ता भविष्य में होने वाले कगड़ों को पारस्परिक पत्र-स्यवहार, सममौता तथा श्रपनी इच्छा से बीच-बचाव करवा के हल करने के लिये वास्य हैं। इसके श्रन्तर्गत श्रमिक तथा नियोक्ता 'धीरे काम करो' की चाल, तालाबन्दी, विना नोटिस के इहताल, धमकी तथा श्रनुशासन हीनता के श्रन्य रूप (जो प्राय-श्रीचोगिक कगड़ों के कारण होते हैं) को नहीं श्रपनार्येंगे।

मार्के की बात तो यह है कि सिंहता में इन्हें लागू करने तथा इसके परिणाम आकने की व्यवस्था भी है। १६५८ में केन्द्र में लागू करने तथा आँकने के लिये एक छोटी सस्या का निर्माण क्या गया। यह सस्या विभिन्न समूहों से अशतः या न लागू होने, निर्णाम, अधिनियम तथा सममीता आदि के दोषपूर्ण दग से या देर से लागू होने के सम्बन्ध में विवरण एक करेगी। सध के अम मन्नालय ने राज्य सरकारों से २० करवरी १६५८ तक तथा मिल्य में प्रतिमाह की दस तारीख तक मन्नाविल के उत्तर के रूप में सूचना देने की प्रार्थना की थी। अब्दे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने की दिशा में यह एक प्रमावपूर्ण कटम है। अधिनयम पास करने तथा सिहता स्वीकार करना ही काफी नहीं है। मिल्य में इसके अनुसार काम होने के लिये यह आवश्यक है कि उसके लागू करने तथा लागू न होने के वार्यों पर कठोर हिन्ट रखी वाय।

ष्ठध्याय ३२ ट्रंड यूनियन

भारत में अभिक ख्रान्दोलन बहुत पुराना नहीं है। यद्यपि २० वीं शताब्दी के ब्रारम्भ में भारत में ट्रेड यूनियन थीं परन्तु उनका कार्यचेत्र बहुत सीमित था ख्रीर वह उन कार्यों को नहीं करतो थीं जिनकी एक ट्रेड यूनियन से ख्रेपेन्ना की जाती है। भारत में इनका विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ और जो कुछ प्रगति हुई भी है वह ख्रनेक कारणों से सन्तोपजनक नहीं कही जा सकती। अभिकों में किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सगठित होने की भावना होने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें इस प्रकार के सगठन की आवश्यकता प्रतीत हो। १८ वीं सदी में ब्रिटेन में ख्रीयोगिक क्रान्ति हुई और उसके पश्चात् कुछ देशों में उसकी पुनरावृत्ति हुई। परन्तु भारत ने ख्रव तक हस प्रकार की ख्रीयोगिक क्रान्ति का ख्रनुभव नहीं किया है। यदि श्रीयोगिक क्रान्ति हुई होती तो उससे अमिकों के सगठन की ख्रावश्यकता उत्पन्न हो जाती ख्रीर एक अभिक सगठन बन जाता। श्रीयोगिक क्रान्ति से ख्रनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती जिनकी पूर्ति के लिए श्रमिको का सगठित होना ख्रावश्यक हो जाता। भारत के ख्रोयोगिक विकास से कुछ समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जितनी ख्रीयोगिक क्रान्ति होने पर होती।

श्रनेक कारणों से भारत में श्रिमिक श्रान्दोलन का विकास नहीं हो पाया है,
(१) यह पहले कहा जा चुका है कि भारत की श्रिषिकतर श्रिमिक जनता निरहर
है और उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है। श्रिमिक भाग्य पर विश्वास करता है और
यह मानता है कि स्वय प्रयत्न करके वह श्रपनी स्थित नहीं सुधार कर सकता है।
इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह श्रपनी स्थित नहीं सुधार कर सकता है।
इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह श्रपनी स्थित नहीं सुधार के भरोते
छोड़ देता है। यदि श्रिमिक शिच्चित होता तो उसे श्रपनी स्थिति सुधारने की श्रायस्यकवा प्रतीत होती श्रीर उसे यह जात हो जाता कि स्वय प्रयत्न करके वह श्रपनी
स्थिति कोबहुत सीमा तक सुधार सकता है। ऐसा श्रनुमव कर वह इस उद्देश्य
की पूर्ति के लिए श्रपने श्रन्य श्रमिक साथियों को सगठित कर सकता था। यदि
भारतीय श्रमिक भी पाश्चात्य देशों के श्रमिकों की तरह भौतिकवादी होता तो वह
निरद्धर होते हुए भी सगठित हो सकता था परन्तु भारत में निरद्धरता श्रीर भाग्यवाद के कारण ही श्राज तक श्रमिक का प्रभावशाली सगठन नहीं हो पाया है।

अमिक ग्रान्दोलन सम्बन्धी श्रनेक कार्यवाहियों के होते हुए भी भारतीय अमिक की न्यक्तिगत भावना कम नहीं हो पाई है।

(२) भारत का श्रीय गिक श्रीमक केवल कारतानों पर ही निर्भर नहीं है। बीच-बीच में वह गाँव जाता रहता है श्रीर फिर काम करने कारवानों में त्रा जाता है। समान हितों की पूर्ति के लिए सगठित होने में उनके स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति सब से बड़ी बावक रही है। इधर चुछ वर्षों से स्थित में कुछ परिवर्तन हुशा है श्रीर शुद्ध श्रीयोगिक श्रीमक के एक वर्ष का उद्भव हो रहा है।

(३) श्रमिकों के पारिशमिक में वृद्धि हुई है परन्तु इसके साथ ही रहन-सहन के व्यय म भी वृद्धि हुई है। श्रमिक श्रातीत की तरह प्रव भी द्रेट यूनियन के लिए योड़ा स सन्दा देने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है। यदि उसे सगठन का लाभ मालूम होना तो ट्रेट यूनियन की सदस्यता के लिए ग्रावन्यक सन्दा देने से वह पीछे नहीं हटता।

(४) भारत के उद्योगपित भी श्रीद्योगिक विकास के श्रारम्म काल के श्रन्य देशों के उत्योगपितयों की तरह ट्रेंड यू-नयनों का विरोध करते हैं त्योर यह श्रनुभव करते हैं कि ट्रेंड यू-नयन उनकी प्रतिह्न्द्वी शक्ति है। यदि उद्योगपित कुछ श्रोर विचारपूर्ण दिण्टकोण श्रपनाते तो इस श्रान्दालन की बहुत प्रगति हो गयी होती। इधर कुछ वर्षों से उद्योगपितयों ने श्रीद्योगिक क्तगड़ों के निपटारे के लिए श्रीर उत्योग में शांति बनाये रखने के लिए ट्रेड यू-नियनों का महत्व समक्ता है।

(५) वर्तमान में मारतीय अिमक संवीं पर स्वय अिमकों का नहीं विलिक्त वाहरी लोगों का नियत्रण है। यदि द्रेड यूनियनों का नेतृत्व स्वय अिमकों के हाम में होता तो वह अिमकों के हित में द्रेड यूनियनों का सगठन करने का महत्व समस्त सकते और इससे अिमक यान्दोलन तेजी से वह सकता या। परन्तु नेतृत्व स्वय अिमकों के हाय में नहीं है और वाहरी लोग द्रेड यूनियनों का उपयोग अपने राजनीतिक स्वायों की पूर्ति में करते हैं। उनकी दृष्टि में अिमकों की स्थिति में सुवार करना गीण विषय होता है। इसीलिए अिमक सोचते हैं कि ट्रेड यूनियनों का संगठन करने से विशेष लाम नहीं है। भारतीय द्रेड यूनियन संगठन में यह दोष होने से ट्रेड यूनियनों का कार्यचेत्र विकसित नहीं हो पाया है और अिमकों में शिचा-प्रधार और स्वास्थ्य स्वन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। भारतीय ट्रेड यूनियनों अधिकतर स्थापेशील प्रवृत्ति की है। यह एक प्रकार से हस्ताल करने की भौर मालिक या सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करने की एजेन्सी के रूप में कार्य करती हैं। इस नीति के कारण भारतीय ट्रेड यूनियनों का कार्यचेत्र बहुत सकीर्ण हो गया है।

१६५५-५६ में (जिस अद्यंतन वर्ष के आँकडे प्राप्त हैं) भारत में ७८६६ अभिक सम थे जिनके सदस्यों की सख्या २२% लाख थी। निम्न तालिका से यह स्पन्द होगा कि १६५२-५३ से रिजिस्टर्ड अम-सम तथा उनकी सदस्य सख्या में पर्याप्त चृद्धि हुई है। समों के इस विकास के होते हुए भी रिजिस्टर किये हुये अभिक समों के कुल सदस्यों की सख्या उद्योगों में कार्य करने वाले अभिकों की कुल सख्या का अश्च मात्र ही है।

रजिस्टर्ङ	श्रम-संघ	तथा	उनको	सदस्य-सख्या
-----------	----------	-----	------	-------------

वर्ष	श्रमसद्य का संख्या 		स्यों की कुल संख्या
-	 रिकस्टर्ड	स्चना देने वाले	
१६५० ५१	३७६६	२००२	१७,५६,६७१
१६५१-५२	४६२३	२५५६	१६,६६,३११
१९५२-५३	४६३४	२७१८	20,88,003
१९५३ ५४	६०२६	३२ ९५	२१,१२,६९५
१६५४-५५	६६४८	३११ ३	२१,७०,४५०
<u> १६५५-५६</u>	७८४६	3838	२२,२५,३१०

कानूनी व्यवस्था

ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने का उद्देश्य ट्रेड यूनियन की व्याख्या करना, उसके कर्तव्यों ख्रोर उत्तरदायित्व को निश्चित करना ख्रौर ट्रेड यूनियन सम्बन्धी उचित कार्यवाही के सम्बन्ध में उनकी रक्षा करना है। कानून यह निश्चित करता है कि उद्योगपित ट्रेड यूनियन को मान्यता देंगे ख्रौर ट्रेड यूनियन सम्बन्धी उचित कार्यवाही करने पर किसी ख्रदालत में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायगा। ऐसा कानून न होने पर उचित कार्यवाही भी ख्रन्य ख्रयों में ख्रवेध घोषित की जा सकती है।

१६२६ का भारतीय ट्रेंड यूनियन कानून—१६२६ के भारतीय ट्रेंड यूनियन कानून में १६२८, १६४२ श्रीर १६४७ में सशोधन किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन इसी कानून द्वारा सचालित होती हैं। १६२६ के कानून के श्रन्तर्गत ट्रेड यूनियन की यह परिभाषा दी गई है कि कोई भी सगठन चाहे श्रस्थायी हो या स्थायी यदि श्रमिक श्रीर उद्योगपित या मालिक श्रीर कर्मचारियों के बीच श्रध्वा कर्मचारियों के बीच पारसरिक उचित सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बनाया गया

हो, या वाखिज्य-व्यापार करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिए बनाया गया हो या दो या दो से श्रिधिक समा का सगठन हो तो उसको भी ट्रेड यूनियन ही कहा जायगा। इस प्रकार ट्रेड युनियन की श्रेणी में श्रमिकों श्रीर मालिकों टोनों के सगठन सम्मिलित कर लिये गये हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी यूनियन के ७ या उससे अधिक सदस्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त रिजस्ट्रार के पास यूनियन की रजिस्ट्री कराने के लिए आवेटन पत्र भेज सकते हैं। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि यृनियने निर्धारित शर्ते पूरी करती हो। यह भी व्यवस्या की गई है कि रजिस्टर्ड यूनियन के पटाधिकारियों में से आधे वास्तव में उस उन्नोग के कर्मचारी हों जिसके श्रीमको की यह यृनियन हैं। इससे बाहरी व्यक्तियों को ट्रेड यूनियन सगठन में काफी स्थान मिल जाता है। यदि यूनियन के कान्तन सम्मत उद्देश्य को आगे बढाने के लिए किये गये समक्तीते के सम्बन्ध में कागडा हो तो यह कानून युनियन के पटाविकारियों श्रीर सटस्यों की फीजदारी के टावे से सुरद्धा करता है। इसके साथ ही यदि मालिक श्रीमकों के क्यांडे के बारे में कोई कार्य किया गया है ग्रीर शिकायत केवल यह है कि इस प्रकार के कार्य से अन्य श्रमिक द्वारा काम छोड़ दिये जाने की सम्मावना है या यह न्यापार में श्रथवा किन्हीं लोगों की नियुक्ति में इस्तचेप करना है तो इस कान्न की वजह से यूनियन के पदाधिकारियों और मदस्यों पर दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है।

इस कानून द्वाग रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के कीय पर प्रतिवन्य लगाया गया है। इस कोय का केवल उन्हीं नायों में उपयोग किया ना सकता है जिनहां कानून में विवरण दिया गया है परन्त एक पृथक् कीप का निर्माण करने की अनुमति दे कर यूनियन के सदस्यों के नागरिक एवम् राजनीतिक हितों की भी रचा की गई है। प्रत्येक ट्रेड यूनियन का प्रतिवर्ष अपना हिसाब छुपे कामों में मरकर राजस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ ही आय-व्यय का आडिट किया हुआ विवरण भी मेनना पड़ता है। यदि मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन क (१) आधकतर सदस्य आन्यमित इइताल में भाग ले, (२) यूनियन का कार्यकारिणी अनियमित इडताल की सलाह दे, उससे सहयोग करे या उसे भड़नाए, या (३) यूनियन का अधिमारी गलत वक्तव्य प्रकाशित कराए, तो कानून के अनुसार ये कार्यवाहियाँ अनुस्तित समसी जाँयगी और इसके लिए दण्डस्वरूप यूनियन की मान्यता वाग्स ले लेन की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर यदि उत्योगनित या मालिक (अ) अपने अभिक्तों के ट्रेड यूनियन सगठित करने के अधिकारों में इस्तचेष करे या पारस्परिक सहायता एवम् सुरज्ञा के उद्देश्य स की जाने वाली कार्यवाही में गड़वड़ी पेदा मरे, (ब) किसी ट्रेड यूनियन के

बनने या उसके प्रशासन में हस्ताचे न करे, (स) किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के श्रिषिकारी को देंड यूनियन का श्रिषकारी होने के कारण नौकरी से निकाल दे या उसके साथ मेद-भाव की नीति वरते, श्रीर श्रमिकों को कातून के श्रन्तर्गत चलने वाली किसी जाँच इत्यादि कार्यवाही में गनाही देने पर या श्रारोप लगाने पर ाकाल दे, या (द) मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ समसीता वार्ती करने से न्कार कर दे या कानून में दो गई सुविधाओं को देने से इन्कार कर दे तो उद्योगपित अथवा मालिक की यह कार्यवाही कानून की हिंहर मे अनुनित समकी जायगी। अनुचित कार्यवाही के लिए उस पर एक हजार रुपया जुर्माना करने की व्यवस्था की गई है।

इस कानून से यदापि ट्रेड यूनियनों को मान्यता मिली स्रोर उनको कानूनी भ्राधार दिया गया फिर भी इससे भारत में ट्रेड यूनियन सगठन का विकास करने का उद्देश्य पूर्ण न हो सका । इसमे अनेक दोप हैं: (१) इस कानून के अनुसार ट्रेंड यूनियन केवल मजरूरों के सगठनों तक ही सीमिन नहीं है, जैसा कि होना चाहिए था, परन्तु इसमे मालिको स्रौर उद्योगपतियों कि सगठन मी शामिल किये गये हैं। इससे अनावश्यक गहनड़ी पेदा हो जाती है, (२) कानून के अतु-सार ट्रेड यूनियन का रिजस्ट्रेशन करना श्रानिवाय नहीं है। इस कानून में उन यूनियनों को भारतीय दग्ड विधान के अन्तर्गत फीजदारी के मुकदमें से छूट नहीं दो गई है जिनकी रजिस्ट्रा नहीं हुई है, इससे ट्रेड यूनियन सगठन कमजोर पड़ जाता है, श्रीर (3) कानून क अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के सामान्य कोष श्रीर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित कोष मे अवैज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित किया गया है। सामान्य कोष से व्यय करने के लिए अत्यन्त सकीर्षा

श्चाचरण-सहिता (code of conduct) —यद्यपि भारत में अम सघो की बाहुल्यता है तथा विभिन्न सवी (federations) के सामजस्य सहित काम व्यवस्था की गई है। करने की कोई आशा नहीं है फिर भी मई, १९५८ में नैनीताल में भारतीय-श्रम-काफ्रेन्स में माग लेने वाले अम सगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाये गये

इस सहिता के अनुसार "(1) किसी उद्योग अथवा इकाई के कर्मचारी श्राचरण सहिता से श्राशा का सचार होता है। को श्रपनी इच्छा की यूनियन का सदस्य बनने की स्वतन्त्रता होगी। इस सबव में कोई दवाव नहीं डाला जायगा। (11) यूनियन की दोहरी सदस्यता नहीं होगी। प्रतिनिधि-यूनियनो के सम्बन्ध मे यह तय किया गया कि उपर्युक्त नियम की ऋौर क्रोचा की जाय। (111) श्रम-संघों के प्रजातत्रीय दग पर कार्य करने को स्त्रीकार किया जाय तथा आदर की दृष्टि से देखा जाय। (1v) ट्रेंड यूनियन के पदािषकारियों तथा प्रशासकीय निकायों के चुनाव नियमित तथा प्रजातत्रीय दग पर होने चाहिये। (v) अभिकों की अज्ञानता और पिछ्डेपन का कोई सगठन कायदा नहीं उठायेगा। कोई सगठन अनावश्यक माँगे नहीं पेश करेगा। (v1) हर एक सम जातीयता व प्रान्तीयता से दूर रहेगा। तथा (v11) अम संघीं के बीच कोई हिसा, दवाव, ममकी तथा व्यक्तिगत वटनामी आदि नहीं होगी।" यह सम बढे ही अच्छे प्रस्ताव हैं किन्तु इनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि ट्रेड-यूनियन उन्हें कहाँ तक अपनाती हैं।

श्रम सुघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में श्रभी तक कोई केन्द्रीय श्रिधिनियम नहीं है। भारतीय श्रम-काफ़्रेन्स ने द्रेड यूनियन के मान्यता देने के सम्बन्ध में निम्न कसौटियाँ प्रस्तावित की । "(1) जहाँ एक से अधिक यूनियन हो वहाँ मान्यता प्राप्त करने वाली युनियन गिजस्ट्री के बाद कम से कम एक वर्ष तक काम करती रही हो किन्तु जहाँ एक ही युनियन हो वहीं यह शर्त लागू नहीं होगी । (11) सस्थान के कम से कम १५% श्रीमक उसके सदस्य हों । (111) किसी स्थानीय चेत्र में एक यूनियन को किसी उद्योग दा प्रतिनिधि यूनियन भाना जा सकता है वशर्ते कि चेत्र में उद्योग के २५% अमिक टसके सटस्य हों। (iv) यूनियन को मान्यता मिलने पर, दो वर्ष तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होना चाहिये। (v) जब किसी उद्योग अथवा संस्थान में अनेक यूनियन हो तो सबसे अधिक सदस्य-सख्या वाली यूनियन को मान्यता देनी चाहिये। (v1) किसी चेत्र में किसी उद्योग की प्रतिनिधि युनियन को देश भर के संस्थानों के श्रिमिकों का प्रति-निधित्व करने का श्रिधिकार है। किन्तु यदि किसी संस्थान के श्रीसकों की यूनियन में उसके ५०% श्रमिक सदस्य है तो उसे केवल स्थानीय हित के मामलों पर कार्य-वाही करने का श्रिधिकार होना चाहिये। (v11) प्रतिनिधित्व का रूप निर्णय करने के लिये छानवीन करने के ढग को श्रीर श्रधिक पर्याप्त कर देना चाहिये। जब इस सम्बन्ध में वैमागिक छान-वीन के परिणाम दलों को मान्य न हों तो वेन्द्रीय श्रम सम के प्रतिनिधियों से निर्मित एक समिति को इस प्रश्न की जॉच कर इसे हल करना चाहिये। इस कार्यं के लिये केन्द्रीय अम सगठन विभिन्न मार्गों के लिये श्रावस्यक धन श्रीर व्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। यदि इससे काम नहीं होता तो प्रश्न का निर्णय न्यायालय के सुपुर्ट कर देना चाहिये। (v111) सिर्फ वे युनियन मान्यता पा सर्वेगी जो श्रौद्योगिक अनुशासन सहिता को मानेगी। (1x) उन अम-सर्घों के सम्बन्ध में जा अम के चार वेन्द्रीय सगठनों से सम्बन्धित नहीं है, इस प्रकार श्रलग से विचार करना चाहिये।" यह कसौटियाँ

विस्तृत तथा सुविचारित हैं। यदि इनका अनुसरण किया गया तो ट्रेंड यूनियनो की नींव दृढ हो जायँगी। प्राप्त अनुसव के आधार पर वे इस विषय पर अधि-नियम बनाने का आधार भी बन सकती हैं।

भविष्य की योजना-वर्तमान में भारतीय श्रमिक श्रान्दोलन में कुछ श्राधारभृत दोष हैं श्रौर स्थिति सुधारने के लिए इन दोषो को दूर करना बहुत श्रावश्यक है। इस समय एक ही उद्योग में एक ही दोत्र से श्रानेक ट्रेड युनियनें हैं। बहुत ग्रधिक ट्रेंड यूनियन होने से श्रमिक का पत्त कमजोर पड़ जाता है श्रीर श्रमिक के श्रधिकारों की रच्चा में भी वाधार्ये आ जाती हैं। इसलिए ट्रेड यूनियनो के सगठन को सगठित करने श्रीर इनको एकता के सूत्र में बॉधने की अरयन्त त्रावश्यकना है। यह त्रावश्यक है कि एक ज्ञेत्र में स्थित किसी मुख्य उद्योग में अभिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक मे अधिक ट्रेड यूनियन न हो। यदि एक सेत्र के विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले सभी श्रमिको का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ट्रेड यूनियन होती तो सर्वोत्तम होता। परन्तु यह समव नहीं है क्योंकि कभी-कभी विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की समस्याएँ भिन्न होती हैं। साथ ही विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले अभिक एकता के सूत्र में नहीं वंघ पाते हैं जब कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन की सफलता इनकी एकात्मकता पर निर्भर करती है। भारत के ट्रेड यूनियन सगठन में दूसरा बड़ा दोष यह है कि यह अपनी सम्पूर्ण शक्ति प्रायः हड़ताल मे और मालिको से सामूहिक मॉगे करने में लगा देते हैं। बहुत कम ऐसी यूनियने हैं जिन्होंने श्रपने कार्यचेत्र को ब्यापक बनाया है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सामृहिक रूप से मॉग करना और इंडवाल करना ट्रेंड यूनियनों का महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु इसके साथ ही अन्य कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में ट्रेड यूनियन का कार्यक्रम और विस्तृत करने की, श्रावश्यकता है। इसमे वयस्कों की शिचा, सहकारी-श्रान्दोलन का गठन, जनसेवा कार्यं इत्यादि भी सम्मिलित निये जाने चाहिये। इससे ट्रेड युनियनों की उपयोगिता बढ जायगी।

ट्रेड यूनियन आन्दोलन का एक बहुत बड़ा दोष वेन्द्रीय सगठनों का बाहुल्य है। कुल १५३१ यूनियनों मे से आई० एन० टी० यू० सी, ए० आई० टी० यू० सी० हिन्द मजदूर सभा और यूनाइटेड टी० यू० सी० से संयोजित यूनियनों की सख्या कमशा. ६१७, ५५८, ११६, और २३७ और उनके सदस्यों की सख्या कमशा: ६ ७२ लाख, ४२३ लाख, २.०४ लाख, और १५६ लाख १६५६ के अन्त में थी। इन केन्द्रीय सगठनों को एक शक्तिशाली सस्या में सगठित करना सम्मव है। इसमें सदेह नहीं कि इन केन्द्रीय सगठनों के राजनीतिक

छाध्याय ३४

रेल यातायात भारतीय रेलों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। १८५३ में भारतीय रेलवे लाइन की लम्बाई केवल २० मील थी, १६०० में यह २४,७५२ मील हुई स्त्रीर १६५१-५२ में इसका प्रसार ३४,११६ मील श्रीर १६५६-५७ में ३४,७४४ मील हो गया, जिसमें ३४,२६१ मील सरकारी प्रवन्य के म्रान्तर्गत था। १६०० म भारतीय रेलों से १७ करोड़ ५० लाख यात्रियों ने यात्रा की, ४ करोड़ ३० लाख टन सामान दोया गया । १९५६-५७ में यात्रियों की संख्या १३८ करोड़ ३० लाख श्रीर ढोये जाने वाले माल की मात्रा १२ करोड़ ५० लाख टन हो गई। १६ श्रप्रेल १९५३ को भारतीय रेलों ने अपनी उपयोगी सेवाओं के १०० वर्ष पूरे किये। ठीक १०० वर्ष पूर्व १६ अप्रैल १८५३ को प्रथम भारतीय रेल ने बम्बई शहर से याने तक २१३ मील की दूरी तय की थी। यद्यपि रेलवे सगठन में कुछ जुटियाँ हैं श्रीर कुछ दाव भी है परन्तु फिर भी जिस गति से उसने प्रगति की है उस पर भारतीय

मुख्य विशेषताऍ-भारतीय रेलवे के विकास में कुछ उल्लेखनीय विशेष-रेलवे गर्व कर सकती है। ताएँ हैं। (१) भारत में रेल का कार्य निजी उद्योग के रूप में प्रारम्भ किया गया। रेल-उत्प्रीग करने वालो को सरकार ने कुछ सुविघाएँ दीं जैसे इन्हें भूमि सुमत दी गई ग्रीर पूँजी की वस्ली की गारन्टी दी गई। इससे रेलवे निर्माण के व्यय में वृद्धि हुई ग्रीर सारे देश को इसका भार वहन करना पड़ा। ऐसे समय में जब रेलों का निर्माण करने के लिए उद्योगपित पूँकी लगाने को प्रस्तुत नहीं ये यह सुविधायें देना समवत ग्रात्यन्त भ्रावश्यक या परन्तु यदि इस भ्रोर किचित् साववानी से कार्य लिया जाता तो इनको काफी कम भी किया जा सकता था। रेलो का प्रवन्ध निजी उद्योगपतियों के इाथ में होने से इसकी काफी आलोचना की गई है। श्रालोचकों ने प्रबन्धकों द्वारा पत्त्वपात किये जाने श्रीर कच्चे माल के निर्यात तथा तैयार माल के श्रायात के भाड़े में रियायतें देने की शिकायतें कीं, क्योंकि बन्टर-गाही से देश के भ्रन्दर सामान लाने और बन्दरगाहों तक सामान पहुँचाने के लिए रेल के मांडे की दर अन्य दरों की अपेक्षा कम रखी गई थी। एकवर्ष समिति (Acworth Committee) ने सुम्ताव दिया कि राष्ट्रीय हित में रेल के निजी उद्योग को क्रमश. राष्य को श्रपने हाय में ले लेना चाहिए। इस दिशा में १६२५ में प्रथम प्रयास किया गया। सरकार ने ईस्ट इिल्डिया श्रीर जी, श्राई, पी, रेलवे को श्रपने श्रधिकार में ले लिया परन्तु इस प्रक्रिया को पूरा होने में २० वर्ष लगे ग्रार नहीं तक ब्रिटिश भारत का सम्प्रन्य है १६४४ में निनी उत्योग समाप्त कर राज्य ने इसको पूर्णतया श्रपने श्रधिकार में ले लिया। १६५० में सघीय वित्तीय एकीकरण के पश्चात् भूतपूर्वे रियासतों की रेलों को भी भारत-सरकार ने श्रपने हाय में ले लिया श्रोर श्रव रेलवे एकमाश राजकीय उद्योग पन चुका है।

रेल उद्योग निजी उद्यागपितयों के द्दाय में होने की श्रिपेशा सरकार के द्दाय में होने से श्रिपेश लाम हैं—(श्र) इसने साधनों की श्रिपावश्यक हानि श्रीर विभिन्न रेलवे-प्रकर्मों में प्रतियोगिता समाप्त हो। जाती है। (व) राजकीय उद्योग होने के कारण देश के श्रोद्योगिक श्रीर कृषि साधनों के विकास के महत्व को हिंद में रखते हुए रेल के मादे की उचित दर निश्चित की जा सकती है श्रीर (स) इस उद्योग से जो लाम होगा वह केन्द्रीय धन कोष में लगा हा सकता है।

- से जो लाम होगा वह रेन्द्रीय धन कीप में जमा हा समता है।

 (२) दो विश्वयुक्टी के कारण, १६३० की श्राधिक मटी श्रीर १६४७ में देश के विभाजन में रेली पर बहुन भार पड़ा है श्रीर उसना परस्पर सम्मन्य भी विच्छिन्न हो गया। युद्ध के कारण रेलों की वार्यज्ञमता पर श्राधिक भ्यान नहीं दिया गया, पुराने कल-पुजा इत्यादि को नहीं बटला गया श्रीर नई मशीनें लगाने की योजना स्थिगित कर दी गई। द्वितीय तिश्वयुद्ध के समय प्रतिशत मीटर-गेज के इज्जन, १५ प्रतिशत मीटर-गेज के वैगन, ४ हजार मील लग्नी पटरियों श्रीर ४० लाख स्लिपर भारतीय रेला से लेकर मध्यपूर्वी देशों को मेजे गये। युद्ध के समय रेलों के सामान का श्रीर पटरियों का श्रत्याधिक उपयोग किया गया, उनको न बढला जा सका श्रीर न नया सामान लगाया जा सका। इसमें रेलों नी कार्यन्त्रमता घट गई। देश का विभाजन हो जाने से रेलों का कुछ सामान पाकिस्तान के माग में चला गया श्रीर शरणाधियों को लाने-पहुचान के कार्य में रेलों पर श्रीर श्रविक भार पड़ा। गत कुछ वर्यों में रेला पर श्रावश्यकता मे श्रिधक भार इछ कम किया गया है, पुराने सामान को बदला गया है श्रीर सामान की मात्रा बढ़ाई गई है परन्तु इस दिशा में सभी बहुत कुछ करना शेष है।
- (३) श्रतीत में इखनां, बायलरों, हिन्मों इत्यादि के लिए भारतीय रेलों को श्रायात पर निर्भर करना पड़ता था। इससे देश का बहुत-सा घन विदेश चला जाता या श्रीर देश को निदेशा विनिमय साधनों को गम्भीर ज्ञित होती थो। परन्तु इघर कुछ वर्षों से स्थिति में सुधार हुग्रा है श्रीर श्रम देश में ही इखन हिन्ने इत्यादि बनने लगे हैं। भारतीय कारखानों में हिन्मों का उत्पादन बढ रहा है श्रीर रेलवे की श्रावश्यकता की श्रिधिकाधिक पूर्ति की जा रही है। चित्त-रखन के इखन बनाने के कारखाने में इखन के लगभग ७० प्रतिशत कल पुर्जी

का उत्पादन किया जाता है श्रीर वेवल ३० प्रतिशत का श्रायात करना पहता है।

- (४) भारत में अनेक रेलें थीं परन्तु पुनर्वर्गी-करण योजना लागू करके इनको ७ चेत्रों में सगठित किया गया है । एकीकरण से पिहले मारत में ३५ रेलवे थीं जिनमें से २२ सरकार के अधिकार में थीं। रेलवे बोर्ड की जॉच करने के लिये नियुक्त सिनित (१६५०) की सिफारिश पर भारत सरकार ने भारतीय रेलों को ६ चेत्रों में सगठित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। दिल्ला रेलवे का १४ अभेल १६५१, पित्रचमी और केन्द्रीय रेलवे का ५ नवम्बर १६५१ को अर्थ योप तीन उत्तरी, उत्तरी पूर्वोत्तर और पूर्वी रेलवे का १४ अभेल १६५२ को उद्वाटन हुआ। पहली अगस्त १६५५ से सातवें चेत्र का निर्माण पूर्वी रेलवे को दो चेत्रों में विमाजित करके किया गया: (१) पूर्वी रेलवे जिसमें पुरानी ई० आई० आर० का मुगलसराय तक का भाग (सियालदह हिवजन को लेकर) सम्मिलित थी, और (२) दिल्ला पूर्वी रेलवे को निम्न सात चेत्रों में विमाजित कर दिया गया।
- (१) दिल्लिणी रेलवे—इसमे एम० एनड एस० एम०, एस० आई० और मैस्र राज्य रेलवे सम्मिलित है।
- (२) पश्चिमी रेलवे इसमें भ्तपूर्व बी० बी० खी० आई०, सौराष्ट्र, -राजस्थान तथा जैपुर रेलवे और जोधपुर रेलवे का कुछ भाग सम्मिलित कर दिया गया है।
- (३) केन्द्रीय रेलवे—इवमें जी० श्राई० पी०, एन० एव०, विन्ध्या नाज्य श्रीर घौलपुर राज्य रेलवे चिम्मिलित हैं।
- (४) उत्तरी रेलवे—इसमे ई० पी०, जोधपुर श्रीर बीकानेर रेलवे, ई० श्राई० श्रार० के इलाहाबाद, लखनऊ श्रीर सुरादाबाद डिवीजन श्रीर बी० बी० एन्ड सी० श्राई० रेलवे का दिल्ली रेवारी-फजिल्का चेत्र सम्मिलित है।
 - (५) दिक्क्णि पूर्वी रेल वे-इसमें बी॰ एन॰ श्रार॰ शामिल है।
- (६) उत्तरी पूर्वी रेलवे—इसमे श्रो० टी० एन्ड श्रासाम रेलवे, ई० श्राई० श्रार० का कुछ भाग श्रीर बी० बी० एन्ड सी० श्राई० रेलवे का फतेइगढ चेत्र है।
- (७) पूर्वी रेखवे—इसमें पुरानी ई० त्राई० का मुगलसराय तक का माग त्रीर सियालदह हिनीजन सम्मिलित है।
- ७ तेत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है कि जिसमें विभिन्न चेत्रों का कार्य कम व्यय के साथ चलाया जा सके और विभिन्न देत्रों में यातायात की

उचित मुविधा प्राप्त हो। विभिन्न च्रेनों के रेल पधों का विस्तार २३३१ मील से लगाकर (जो कि पूर्वी रेलवे का है) ६३३६ मील तक है। (जो कि उत्तरी रेलवे का है) इस बात का ध्यान रखा गया है कि कर्मचारियों और अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम इटाना पढ़ें और केवल ईस्ट इडिया और बीo बीo एन्ड सीo आईo रेलवे को छोड़ कर जहाँ तक सम्भव है वर्तमान रेलवें व्यवस्था को बिना छिन्न भिन्न किए एक या दूसरे माग में सम्मिलित कर लिया जाए।

रेलवे के पुनवंगीकरण योजना की श्रालोचना की गई है। कहा गया है कि (अ) पुनर्वर्गीकरण से एक रेलवे के कर्मचारियों को दूसरी रेलवे में परिवर्तित किया गया, उनमें अनेक को नोकरी से अलग कर दिया गया, (व) इससे कम से कम टो रेलवे—ईस्ट इन्डियन श्रीर बी० बी० एन्ड ० सी० श्राईं० रेलवे—तोड़ी गर्ड जिसमे श्रमेक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो गई, श्रीर (स) इससे भारतीय न्यापार एवम् उद्योग को यनेक कठिनाइयाँ हुई हैं। रेलवे के पुनर्वर्गीकरण जैसे बडे परिवर्तन में योड़ा-बहुत सम्बन्ध विच्छेत होना श्रीर कुछ कर्मचारियों को नौकरी से ऋलग कर दिया जाना श्रानिवार्य था। उसमे बचा नहीं जा सकता था। परन्त्र इतने से ही पुनर्वर्गीमरण मी योजना श्रवाछनीय श्रीर श्रनुपयुक्त सिद नहीं होती क्यांकि इस योजना के लागू हो जाने से जो लाभ होंगे वह इससे होनेवाली हानियों की अपेना नहीं अधिक हैं। यह भी कोई तर्क नहीं, जैसा कि कुछ समि-तिरों ने सुकाव दिया था, कि यह योजना पाँच वर्ष बाद लागू की जाय श्रीर सरकार को इस समय इसे स्थागित कर देना चाहिए था। यदि पुनर्वगीकरण की नीति स्वीकार कर ली गई है तो इसे जितना शीध लागू किया जाय उतना ही अरुका है। इस योजना के लागू करने से तीन निश्चित लाम हैं --(क) इससे वह सभी लाम प्राप्त हो सकेंगे जो प्रबन्ध ब्यारस्था बढे पेमाने पर सगठित करने म दोते हैं। (ख) इससे एक ही काम श्रमेक बार करने से छुटकारा मिल जायगा और हानिकारक प्रतियोगिता मी नहीं हो सकेगी और (ग) इससे रेलवे वी श्रार्थिक त्यिति दढ होगो श्रीर कार्य के स्तर में सुधार किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के पञ्चात् रेल के भाडे श्रौर किराये की दर, यात्रियों की सुविधाश्रौ, मजदूरों के वेतन श्रीर सुविधाश्रों इत्यादि के सम्बन्ध में सारे देश में समान नीति लागृ नी जा सकेगो । यह कोई छोटी सफलता नहीं।

(५) भारतीय रेलवे की कार्यच्चमता अभी भी बहुत नीचे स्तर की हैं। युद्ध आरम होने के पूर्व की कार्यच्चमता के स्तर तक भी अभी भारतीय रेलवे नहीं पहुँच सकी है। इस बात का प्रमाण माल के दिन्हों का चक्कर लगाकर अपने स्थान पर पहुंचने में दस श्रयवा श्यारह दिन के समय का लगना है जर कि युद के पूर्व के राल नी दिन लगते थे। रेल के सामान के श्रमान के श्रतिरिक्त कार्य प्रवन्ध में देर लगना भी माल क एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर से पहुँचने का प्रधान कारण है। समय की पानन्दी तथा माल के हिन्मों के प्रयोग स्वक स्रक नहुत नीचे स्तर पर हैं। छोटी लाइन की स्थिति श्रीर मी विगदी हुई है।

भारतीय रेलवे में कोयले का ज्यय भी बहुत ग्रधिक है। वर्तमान समय म रिष्म लाख दन कोयला ३०३ करोड़ रुपये की लागत का प्रयोग में ग्राता है। रेलवे प्यूल बाच कमेटी ने विभिन्न उपायों द्वारा २०% बचत करने का सुकाव दिया था। यदि यह सम्भव हो सका तो ग्लवे को प्रति वर्ष ६ करोड़ रुपये की बचत श्रगले पाँच वर्षों में सम्भव हो सकेगी। इसके श्रातिरिक्त श्रन्य मितन्यायता क बचत श्रगले पाँच वर्षों में सम्भव हो सकेगी। इसके श्रातिरिक्त श्रन्य मितन्यायता क उपायों का पूरी जाँच होनी चाहिए श्रीर इनका प्रयोग होना चाहिये जिसमें रेलवे का न्यय रूम हो जाय तथा श्राय में वृद्धि हो जायगी।

रेलचे की वित्त व्यवस्था—एकपर्धं समिति के सुकाव पर १६२४ न रेलवे की जित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से भिन्न कर टी गई। १६२४ के पृथक्करण समसीते में यह व्यवस्था की गई थी कि रेलवे मे लगी हुई पूँजी पर न्याल के साथ ही व्यवसाय में लगी पूँजी का एक प्रतिशत. श्रितिरिक्त लामीश का दे भाग श्रीर रेलवे के सुराज्ञत कीय में ३ करोड़ ज्यया जमा कर देने के बाट बचे श्रास्यधिक श्रातिरिक लामीय का है भाग राजस्व के नाम में जमा करेगा। महत्वपूर्ण रेली की हानि का भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। रेलवे के सुरिक्त कीय में से सामान्य राजस्व दिया नायगा श्रीर यदि ग्रावश्यकता पद्मी तो हुर-फूट फे लिये पूँजी ग्रोर रेलचे की ग्रार्थिक स्थिति को हुद बनान के लिए भी इसमें से धन लिया जायगा। रेलय के सामान को बदलने श्चीर नया रामान मॅगाने के लिए १ प्रापैल १६२४ में टूट-फूट के लिए एक भिन मुरित्तत कीप बनाया गया है। केन्द्रीय सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से रेलवे की वित्त व्यवस्था को भिन्न करने क दो लाभ हुये हैं (अ) ग्रतीत में सामान्य वित्त की कठिनाट्यों श्रीर श्रमिश्चितता पर ही रेलवे का अतिष्य निर्मर करता था। इस कारण वह पहले से ही श्रपने विकास की योजना निर्माण नहीं कर पाते ये। अनुमान है कि पृथनकर्ण समसीते के अनुसार वित्त व्यवस्था थकपृ कर देने में रेलवे की स्थिति अधिक सुरक्षित हो जायगी श्रीर इसके प्रसार करने के लिये तथा इसमें सुधार करने के लिए निश्चित घन राशि पास हो जायगी। (य) श्रतीत मे यह निश्चित नहीं या कि वेन्द्रीय राजस्य को रेलवे से कितनी श्राय होगी परन्तु पृथककरण समकौते के अनुसार इसके अन्तर्गत धन राशि निश्चित

प्रयक्करण समसीते में सशोधन किया गया जो १ अप्रैल, १६५० से लागू हुआ। इस संशोधन के श्रनुसार (१) जनता को रेलवे का हिस्सेदार माना गया है ग्रौर जो ऋण ली गई पूँजी रेलवे में लगाई गई है उस पर सरकार की (श्रर्यात् जनता को) ४ प्रतिशत का निश्चित रूप से लाम मिलेगा । यह धन रेलवे की श्राय में से केन्द्रीय सरकार को दिया जाता है। पहले १६२४ के समसीते के अनुसार सामान्य राजस्य में टी जाने वाली घन राशि की कोई निश्चित निर्धारित मात्रा नहीं थी पर इस सशोधन से यह निश्चित कर दिया गया कि रेलवे में जो कुछ पूँ जी लगी है उसका एक निर्धारित प्रतिशत सामान्य राजस्व में दिया जायगा। (२) समस्तोते में रेलवे विकास कीप स्यापित करने की व्यवस्था की गई है। इस कोष से (अ) नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने में वित्तीय सहायता दी जायगी। इन नई लाइनों से श्राय होना श्रावश्यक नहीं है, (व) यात्रियों की सुविधा के लिए व्यय किया जायगा श्रीर (स) अस कल्याण कार्य इत्यादि में व्यय किया जायगा । (३) सममीते के सशोधन के श्रनुसार प्रथम पाँच वर्षों में रेलवे के टूट-फूट कोष में कम से कम १५ करोड़ रुपया सप्रह किया जाना चाहिए श्रीर शेष श्रतिरिक्त श्राय से एक ऐसे कोप का निर्माण किया जाना चाहिए जिष्ठसे श्रार्थिक सन्तुलन रखा जाय। रेलवे का सामान श्रधिक महॅगा होने के कारण १९५० के पृथक्तरण समसौते के पश्चात् से टूट-फूट के कोष में ३० करोड रुपये की नियत घनराशि सग्रह कर दी गई है।

पुराने समसौते में सामान्य राजस्व के अन्तर्गत जमा की जानेवाली धनराशि निश्चित नहीं यी परन्तु नये समसौते में यह रकम निश्चित कर दी गई है।
इससे रेलवे का योजनावद विकास किया जा सकता है, सुरिच्चत कोष का निर्माण
किया जा सकता है और पुनर्वास तथा प्रसार का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा
सकता है। टूट-फूट के कोष में प्रति वर्ष जमा की जाने वाली घनराशि में इस
आधार पर वृद्धि कर दी गई है कि कल पुजों, मशीन, इस्रन इत्यादि बदलने के
ज्यय का मूल ज्यय से और उपयोग में लाई जाने वाली सम्पत्ति के जीवन काल से
कोई सम्बन्ध नहीं है। अब तक इन्हीं दो आधारों पर टूट-फूट के कोप में योगदान
निर्धारित किया जाता था। नये समस्तीते के अनुसार ज्यय का मार बढाने का
उद्देश्य रेलवे को अत्यधिक पूँजी समह करने से गेकना है। विकास कोष की
स्थापना के समय यह बात मान ली गई है कि मविष्य में रेलवे का विकास केवल
ज्यवसायिक दृष्टिकोण से सीमित नहीं रखा जा सकता है। देश के आर्थिक विकास

में रेलवे को जिसका राष्ट्रीकरण किया जा चुका है एक महत्वपूर्ण श्रीर निश्चित योगदान देना है।

स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् रेलवे की वित्तीय स्थिति में निरन्तर सुधार हुआ है। वास्तविक आय जो कि १६४८-४६ में ४२ ३४ करोड रुपये थी १९५१-५२ में बढकर ६१.७५ करोड़ रुपया हो गई है और १९५८-५९ के वजट के अनुसार ७६ ६२ करोड़ रुपया अनुमान किया गया है। १६५१-५२ में सामान्य श्राय के प्रति ३३ ४१ करोइ रुपया टिया गया या श्रीर १६५८-५६ में ४६ ५८ करोड़ रुपयों के टिये जाने का श्रनुमान किया गया है जब कि १६४८-४६ मे केवल ७ ३४ करोड़ रुपये ही दिये गये थे। इतने पर भी रेलवे की ऋतिरिक्त आय जो कि १६४८-४६ में १६.१८ करोड़ रुपये थी १६५१५२ में बढकर २८३४ करोड़ रुपये और १६५८-५६ के बजट अनुमान के अनुसार २७.३४ करोड़ रुपये मानी गई हैं। यह सारी रकम विकास कोष में जमा कर दी गई है जब कि १६४८ ४६ में केवल १० करोड़ रुपये ही इस कीष में जमा किये गये थे। रेलवे की वित्त स्थिति में इस सुधार का कारण यह है कि (१) यात्रियों की सख्या में श्रीर माल के यातायात में वृद्धि हुई है श्रीर (२) रेलवे के किराये तथा भाडे में भी वृद्धि हुई है। देश के ब्रोद्यागिक विकास में वृद्धि होने से ब्रौर श्राधिक कारोबार बढाने से रेलों द्वारा यातायात भी बढा है। बास्तव में रेलें बढते यातायात की मॉग पूरी कर सकने में ब्रासमर्थ रही हैं, यातायात बढने के साथ ही रेल का किराया भी बढ़ा है। १६४८ ४६ में रेलवे को यात्रियों से ८४ करोड़ रुपयों और १९५१-५२ में १०९ ८८ करोड रुपयों की स्त्राय हुई। १९५८-५६ के बजट में लगाये हुए श्रुतमान के श्रनुसार यह श्राय १२४.७३ करोड़ र० होगी। इसी प्रकार माल होने से आय जो कि १९४८-४९ मे १०८-२६ करोड़ रुपये थी, १९५१-५२ मे बदकर १५६ ७० करोड़ रुपये हो गई श्रीर १६५८-५६ में श्रनुमान है कि २५० ५० करोड़ रुपये हो जायगी।

रेल से यातायात कम होने का वास्तविक कारण १९५१-५२ और १९५५-५६ के बीच यह था कि १९४८ से रेल के किराये में और माढे में अत्यधिक वृद्धि हुई है। युद्ध के तुरन्त पश्चात् रेल के किराये और माढे में इतनी वृद्धि नहीं हुई जिसका यातायात पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ता परन्तु १९५१ में रेल के किराये तथा भाढे में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से यात्रियों और माल से होनेवाली आय कम हो गई।

	यात्रियों से होनेवाली श्राय (करोड़ रुपयों में)	माल ढोने का श्राय (करोड रुपयों मे)
₹ £ ¥≒- ४€	57 00	१०= २६
१९४६-५०	८६ २६	१३०'३७
१६५०-५१	EU SY	१४३.०६
१९५१-५२	१०६ दद	१ ५६%
१९५२-५३	१००'३८	१४६"१२
१ ९५३-५४	200'00	१४७ १८
1 E48-44	१०२'६२	१५८ ६
१९५५-५६	१०७ ७१	१८०°२८
१९५६-५७	११६'३३	२०३ ६६
१९५७-५८ (सशोधित)	१२०'६०	२३१००
१९५८-५६ (वजर)	१२४ ७३	२५०५०

पिछले तीन वर्षों में यात्रियों तथा माल के वातायात में श्रीद्योगिक विकास के कारण वृद्धि होने से स्थिति में उन्नित हुई है।

रेलवे के किराये और भाडे की दर सम्वन्धी नीति—रेलो के किराये श्रीर माडे का उद्योग, ज्ञाप, ब्यापार श्रोर वाणित्य के विकास में श्रीर स्वय रेलों की विचीय स्थित को रह बनाने में बहुत महत्व है। यदि माड़ा अधिक होगा तो उससे उत्पादन व्यय पर प्रमाव पहेगा श्रीर उत्पादन व्यय में वृद्धि होगी। इससे देश के श्रीबोर्गाकरण को प्रोत्सहन नहीं मिलेगा। इसके विपरीत यदि भाड़े की दर निश्चित करने में शुंट रह गई है तो उससे उद्योगों के स्थाननिर्धारण पर श्रीर श्रीबोगीकरण के ढाचे पर बुरा प्रमाव पड़ता है। रेल का किराया श्रीर भाड़ा श्रिषक होने से यातायात को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, यातायात रेलों के द्वारा न होकर ग्रन्य साधनों से होता है जिसमे रेलवे को र्ज्ञात पहुँचती है। यह भाडा कम है तो इसमें श्रीद्योगिक तथा कृषिक विकास में अवश्य सहायता मिलेगी, परन्तु यदि इससे रेलवे को हानि पहुँचती है श्रीर वह श्रपना व्यय पूरा करने के पश्चात उचित लाम नहीं उठा सकती है तो यह न्यावसायिक सिद्धान्तों के प्रतिकृत तथा श्रनचित है। इस लिए रेल के किराये तथा माडे की दर सम्बन्धी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे रेलवे के हित में और उद्योग तथा कृषि के हितो में सन्तुलन स्यापित किया जा सके श्रीर जिससे देश में प्राप्त साधनों के श्राधार पर देश का कृषि तथा श्रौद्योगिक विकास पूरी तीवता से किया जा सके, पचवर्षीय योजना में

निर्घारित लच्य पूरे किये जा सर्के ग्रोर रेलवे का वित्ताय स्थिति पर्याप्त सुदृढ रखी जा सके।

१६४८ से पहले भारत में रेलवे के किराये तथा भाडे की दरे इसके अनुकूल नहीं थीं श्रीर उसकी कड़ो श्रालोचना की गई है

- (१) भारतीय रेलवे में किराये तथा भाहें की दर निर्धारित करते समय दूरी का ध्यान नहीं रक्षा गया। इससे लम्बी यात्रा करने वालों को या काफी दूर सामान मेजने वालों को बहुत अधिक भादा देना पड़ता था। इससे माल की खपत के लिए बाजार की स्थित तथा अन्य कारणों के अनुकूल रहते हुए भी उन्नामों को कच्चे माल के स्रोतों से दूर स्थापित करने को प्रोत्साहन न मिला। उद्योग के लिए रेलों के भाहे की दर कुछ कम थी, साथ ही विशेष स्टेशनों के बीच रियायतें भी दी गई थों परन्तु इससे ब्यापार और उद्योगों को विशेष लाभ नहीं हुआ।
- (२) भारत से कच्चे माल को विदेशों को निर्यात श्रौर विदेशी माल के श्रायात को स्ता करने के लिए रेलवे ने देश के किसी भाग से बन्दरगाहों तक श्रौर बन्टरगाहों से देश के श्रम्य उपयोग के केन्द्रों तक का किराया कम रखा। भारत में विदेशी सरकार की इस श्रुटिपूर्ण नीति से भारतीय उद्योग को ज्ञांत पहुँची श्रौर विदेशी उद्योगों को श्रिषक प्रोत्साहन मिला।
- (३) भारतीय रेलवे के कुछ भागों में किराये की दरें मीलों के आधार पर निश्चित की गई श्रीर ब्लाक रेट की प्रणालो अपनाई गई अर्थात् एक रेल द्वारा कम दूरी तक माल ढोने पर प्रांत मील श्रिधिक किराया वस्त किया गया। इसका उद्देश्य यह या कि माल कुछ दूर ढोने के बाद दूसरी रेल से न ढाया जाय बिल्क लम्बी यात्राश्रों में उसी रेल का उपयोग करें। इसके परिणामस्वरूप ब्लाक-रेट नीति से बचने के लिए सामान को आवश्यकता से अधिक दूर तक ले जाना पड़ता था। इससे लागत बढती थी श्रीर यातायात क साधनों पर भी अनुचित भार पड़ता था।
- (४) एक ही सामान के लिए विभिन्न रेला की विभिन्न टरे थीं। इससे व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। इसके ग्रांतिरिक्त विभिन्न सामनों के भाडे की दरों में भी काफी ग्रांतर था।

१६४५ में रेल के किराये तथा भाडे की दरों की कुछ त्रुटियाँ दूर कर दो गई। किराया प्रति मील की दर से निर्धारित किया गया, साथ ही अनाज, दाल, आटा श्रीर बीज इत्यादि की दरें निश्चित कर दो गई। इसके लिए सर्वप्रथम दूसरे समूह की रेलो—श्रासाम, ईस्ट इन्डिया, जी॰ श्राई॰ पी० श्रीर श्रो॰ टी॰ रेलवे—

में टर निश्चित की गई ज्रोर तत्पश्चात् पहले समूह की रेलों में। दोनो समूहों में इस ज्ञतर का कारण यह था कि दूसरे समूह की रेलों की दरें पहले समूह की रेलों की अपेक्षा पहले से ही कम मीं और यिंट दोनों समूह की रेलों की टरें एक साम बढ़ा टी जातीं तो इससे अधिक कठिनाई होती है।

रेल के किराये तथा भाडे की दरों में इस प्रारम्भिक परिवर्तन के पूरे हो जाने के बाद र अप्रैल १६५२ को कुछ और परिवर्तन किये गये। दूरी के आधार पर किराये की दर निर्धारित करने की नीति त्याग दी गई। शेष दरों का प्रमाणी-करण हुआ और इस प्रक्रिया में उनमें वृद्धि की गई। लोहे और इस्पात उद्योग के लिए निश्चित विशेष दरों को खत्म करके नई सशोधित दरें लागू नी गई जो स्टैन्डर्ड तटकर की दर से कम रखी गई। दिख्य को चीनी के यातायात की रियायती दरें खत्म कर दी गई। कोयले के मांडे में ३० प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई और यह कहा गया कि पहले की दर व्यय से बहुत कम थी। १६५५-५६ के बजट में मांडे की दरों में अन्य परिवर्तन किये गये। अन्न तथा खाद का प्रति गाड़ी माड़ा कम कर दिया गया तथा विभिन्न श्रेणियों का जात्रियों के लिये किराया ६०० मील से अधिक दूरी के लिये कम कर दिया गया श्रीर प्रथम ३०० मील की वात्रा का किराया बढ़ा दिया गया पर ३०१ से ६०० मील की वूरी के किराये में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

इससे रेलवे को श्रनावश्यक हानि उटानी पडी जब कि रेलों द्वारा कुल जिवने सामान का यातायात होता है उसका ४० प्रतिश्वत कोयला होता है। यह सुक्ताव दिया गया कि कोयले के माडे की दर श्रिषक होने से रेलवे को लाम होगा इससे रेलवे के हितों की रज्ञा होगी।

रेलवे भाडा पर जाच कमेटी—जो कमेटी जून १६५५ में नियुक्त की गई पो उसने १६५८ के श्रारम्भ में सरकार को श्रपनी रिपोर्ट दी। सरकार के विचाराधीन होने के कारण श्रमी तक वह कार्यान्वित नहीं की गई है। कमेटी यह सिपारिश की है कि किराये की दरे निम्मतर श्रेणी से-उञ्चतम श्रेणी तक वृद्धिमान श्राधार पर होनी चाहिये। इस विचार, को कार्यान्वित करने के लिये कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सबसे सरल श्रीर सतोपप्रद ढग श्राधार रूप में एक दर निश्चित करना श्रीर श्रन्य दरें इसी पर के प्रतिशत वृद्धि के श्राधार पर नियत करना होगा। इसके लिये कमेटी ने एक सामान्य दर जो कि मान दण्ड होगा नियत किया है जिसे (Class 100 rate) वर्ग १०० दर कहा जायगा। कमेटी ने वर्तमान वर्ग ६ को सबसे श्रधिक सुविधाजनक समान्य (Norm) श्रीर श्रन्य वर्गों को इसके ऊपर तथा नीचे माना है। इसी प्रकार गाड़ी भर माल की दरे

मी १०० के नये वर्ग के श्राधार पर प्रतिशत श्रकों में व्यक्त किये गये हैं। प्रत्येक वर्ग कित ने प्रतिशत होगा व्यक्त कर दिया गया है। प्रत्येक वस्तु के लिये गाडो- भर माल के श्राधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिये श्रीर साथ ही साथ छोटी मात्राश्रो (smalls) का भी वर्गीकरण होना श्रावश्यक है। कमेटी ने छोटी मात्रा में माल की टरों में गाड़ी भर माल की टरों की श्रपेता १५ से लगाकर ३६ प्रतिशत वृद्धि करने की श्रनुमित दी है। अ

कमेटी ने यह मत दिया था कि (1) सीमा कर रह कर दिये जाने चाहिये पर नये दरों के बनाते समय इन बात को विचाराधीन रखना चाहिये, (11) थोड़ी दूरी के लिये श्रितिरिक्त भाड़ा वसलाा श्रमुचित समका जाना चाहिये, (111) घाट सम्बन्धी श्रीर स्थानान्तरण सम्बन्धी वस्ली बन्दी कर दी जानी चाहिये। (111) भाड़ा वसुनने की न्यूनतम दूरी २५ मील तक बढ़ा दी जानी चाहिये। चाड़े माल एक रेल श्रयमा रई रेला द्वारा ले जाया जाय एक ही बार उसकी बुकिंग होनी चाहिये, (112) माल गाडियों द्वारा भेजे जाने के लिये न्यूनतम वजन २० सेर होना चाहिय, ग्रार (112) जो १ ६० १२ ग्राठ प्रति गाड़ी माल पर न्यूनतम सम्मिलित वसली की जाती है बन्द कर दी जानी चाहिये।

कमेटी ने यह भी सिपारिश का है नि ३०० मील की दूरी की प्रथम छीडी को भांड की दर नियत नरने के लिये चार भागी में बाट देना चाहिये, जैसे १ से २५ मील तक, २६ से ७५ मील तक, ७६ ने १५० मील तक, ज़ौर १५१ से ३०० मील तक। स्पष्ट रूप में उसने यह सिपारिश की है कि "कर्मचारियों की यह निश्चित नीति होनी चाहिये कि जहाँ तक सम्मव हो सके थोड़ी योड़ी दूरी के लिये रेल का प्रयोग न किया जाय वरन् अन्य परिवहन के साधनों का उसके स्थान प्रयोग बढे।"

इस बात को विचाराधीन रखते हुये कि (१) दरे लम्मी दूरी तक लेजाने वाले माल पर भार स्वरूप न हो, (२) उनमं सीमा सम्बन्धी तथा श्रन्य सम्बन्धों में जा वसूली की जाती है सम्मालत हो, (३) श्राय श्रीर व्यय के बीच जो ३०० कराइ रुपयों का व्यवधान है उनसे पूरा हो जाय। कमेटी ने निम्न दरों के लागू किये जाने की सिपारिश की है.—

	मील	प्रतिमील प्रतिमन पाइयो की इकाई में दरे
?	से २५ तक	३ ६०
२६	से ७५ तक	₹ * ४०
७६	से १५० तक	१२०
१५१	से ३०० तक	, १•૦૫

मील	प्रतिमील प्रतिमन पाइयो की इकाई से दरे
३०१ से ५०० तक	০ শ্ব্
५०१ से ८०० तक	0,00
८०१ से १२०० तक	0 \$ و
१२०१ से आगो तक	० ५०

कमेटी की सिपारियों (1) रेलवे की माडे की दरों को सरल श्रोर सुगम यना देगी श्रोग इस प्रकार उनकी श्रानेकों जिलतायें श्रोर श्रसगतायें दूर हो जायंगी, (11) उनसे रेलवे की श्राय में वृद्धि होगी जिसकी बहुत श्रावश्यकता है, (111) रेलवे को इसमें श्रावश्यक सुविया प्राप्त होगी श्रोर सहक द्वारा छोटी दूरी क परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु उद्योगों का उत्पादन लागत पर रेल के विराये का श्रत्यधिक श्रोर श्रनुचित भार पढेगा। वर्तमान मूद्रा स्फीति की दशा में इससे हानि होगी। बाहर भेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में तो किराये की बढी हुई दरें भारतीय माल की विदेशी बाजारों में स्पर्धा शक्ति ज्ञीण कर देगी जिससे विदेशी विनिमय की कठिनाहयों के श्रीर भी श्रधिक बढ़ जाने का मय होगा।

जनवरी १६४८ में यात्रियों के लिए भारतीय रेलों में प्रति मील किराये की समान टर निश्चित की गई। परन्तु कुछ रेलों में किराये की दर कम थी। उसे भी अन्य रेलों की किराये की टर के समान ही कर दिया गया। १६५१ में रेल का किराया २० से २५ प्रतिशत तक इहा दिया गया।

१९५५-५६ के वजट में किराये की दरें निम्न प्रकार निश्चित की गई हैं

	पाइ प्रांत माल प्रति यात्री				
~	१ -१५० माल	१५१३०० माल	३०१ मील श्रौर इसमे श्रिघक		
एयर वन्होशन श्रेणी	38	3 &	32		
प्रथम श्रेणी	१ =	१६	ર પ્		
दितीय श्रेणी (मेल/एउसप्रेस)	११	₹0 ⁴	E ?		
,, " (साधारण)	63	3	در ۲		
त्रितीय श्रेणी (मेल/एउसप्रेम)) ६ <u>४</u>	६	પ્		
,, ,, (साधारण)	<u> ৭</u> %	પૂ	¥3		

रेलों का पुन मगटन प्रग्ने में गेल के किराये तथा शांडे में जो सुधार किया जा सका उससे (१) रेल का किराया निर्वारत करने का ख्राधार सरल हो गया, (२) रेल की दरों में जा ख्रव्यवस्था फैनी हुई थो वह दूर हो गई, ख्रीर (३) रेलवे का विकास कर मकने के लिए श्राधिक धन भी प्राप्त हुत्रा । रेल के किराये के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि सुधार करने से किराये श्रीर भाडे में कुछ वृद्धि कर दी गई है। इससे उन्होंगों का उत्पादन च्यय वहा है श्रीर यात्रियों तथा सामान के यातायात से प्राप्त होनेवाली श्राय घटी है।

रेलों की कार्य प्रणाली में टोप—फेटरेशन थ्राफ इन्डियन चेम्बर्फ श्राफ कामर्छ ऐट इन्डस्ट्री ने थ्रपने स्मारक पत्र में भारतीय रेलवे कार्य प्रणाली के थ्रनेकों टोपों ग्रोर षुटियां की थ्रोर ध्यान थ्राकुर कराया था, जैमे गाड़ी के डिब्बों का न मिलना, बहुत दिनों तक माल के यातायान में प्रविजन्य का लगाना, यातायात में थ्राधिन समय लगना, यांडे सामान के यातायान की सुविधा में स्थापन, माल के डिब्बों की माँग करने थ्रीर प्राप्त करने में समय का लम्बा व्याधान, कुछ जनशनों में लाइनों का ग्रमाव, बड़ी थ्रीर छोटी लाइनों में परस्पर श्रयला बटली की सुविधायां का ग्रमाव, कुछ रास्तों में लाइनों का श्रमाव, मार्ग में माल का चोशी होना श्रोर छो जाना या चोशी हुए माल की हानि निश्चित करने में श्राधिक देर लगना, ग्रीर कर्मचारियों को कार्यक्रमता में सामान्यत श्रमाव रत्यादि। इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या तो यह है कि कृषि श्रोर उद्योगों की श्रावश्यकता के श्रमुसार ने लेवे की सुविधा कम है। इस देश में श्राधिक व्यवस्था विकासोनमुख है, यहाँ कृषि एव उद्योगों के उत्यादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है श्रीर वर्तमान यानायात मुनिधायें पूर्णक्षिण श्रपर्याप्त हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में निम्न सिफारिश की है।

- (१) रेलवे के विस्तार त्रोर सुगर के लिए ४०० करोड़ रुपयों का प्रथम पंचवर्षीय योजना में नियत करना अपर्याप्त था श्रीर कम से कम १०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष त्रीर त्राधिक नियन करना चाहिये था। इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्तर्गत १४८० करोड़ रुपये व्यय किये जाने की माँग रेलवे बोर्ट ने की थी जिमे योजना आयोग ने घटा कर ११२५ करोड़ रुपये कर दिया है। यह घन भारतीय रेलवे की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त न होगा।
- (२) प्रथम योजना में रेलवे के वर्तमान सामान की मरम्मत पर श्रधिक जोर दिया गया था जो गन बीस वर्गों में बदले भी नहीं गये। यद्यपि यह बहुत श्राप्तर्यक है, फिर भी श्रव श्रधिक ध्यान रेलवे के विस्तार पर दिया जाना चाहिये। विस्तार इतना होना चाहिये कि न केवज यातायान की श्रावश्यकतामें ही पूर्ण हो सर्के, यरन् भविष्य में बढ़ी हुई श्रावश्यकता को भी पूरा कर लेने की पर्याप्त शिक्त हो। यद्यपि द्वितीय योजना में श्रिधिक जार विस्तार पर दिया गया है फिर भी यह श्रयांत है।

- (३) रेलवे के कार्य करने की ज्ञमता में वृद्धि होनी चाहिए। देश के श्रीद्योगीकरण में प्रोत्साहन देने के लिये श्रावश्यक है कि रेल द्वारा यातायात की सुविधा सस्ती हो। इसके लिए यह श्रावश्यक है कि रेलवे का चालू व्यय कम हो। भारतीय रलवे की कुल किराये भाडे से प्राप्त श्राय १६४८ को २१३ करोड़ रुपयों से बहकर ४०७४८ करोड़ रुपये १६५८-५६ के दला में श्रतुमान की गई है। कुल व्यय १७३ करोड़ से बहकर २६८ ३५ करोड़ रुगये हो गया है। इससे वह पता लगता है कि बढी हुई श्राय का श्राधकाश व्यय की वृद्धि में प्रयुक्त हुशा है श्रीर यह सम्भव है कि किराया श्रीर माड़ा घटाया जा सन।
- (४) माल के यातायात में सुविधा प्रदान करन के लिए ऐसे श्रस्थायी उपायों से कार्य लेना चाहिए जैसे मुकामा घाट, श्रागरा ग्रार कोनरमती श्रीर श्रम्य स्थानों पर मशीनों द्वारा माल को स्थानान्तिक करना, कन्वयर प्रणालो का प्रयोग करना श्रीर मुगलसराय वाल्टेयर, भागलपुर श्रादि जकशानों पर माल की गाड़ियों की श्रदला-कदली की गति में तीव्रता लाना नयों कि इन स्थानों पर बड़ी भीड़ रहती है। जिन रास्तों पर लाइनों के श्रमाय के कारण किटनाई हो जाती है वहाँ श्रिष्ठक लाइनों का खेलना श्रोर विशेष प्रकार के माल के डिन्बों की सख्या बढाना।
- (५) व्यापारियों को मार्ग में माल के चोरी हो जाने छोर यो जाने छोर बहुत देर में हानि मिलने के कारण बहुत किटनाई उठानी पहती है। रेलवे व्यवस्था को इस प्रकार की सभी हुई चोरियों के रोकने छीर रेलवे कर्मचारियों की छसावधानी छोर चिरत्रईनिता के कारण गाई। में माल के जाने की रोक थाम के लिये विशेष प्रयव्यक्षित होना छावश्यक है। हानि जल्टी चुकाने के उपायों को भी सोचना छावश्यक होगा। विभाग का विकेन्द्रीय करण करना, कुल माल के खो जाने पर हानि हरन्त चुकाना, इस दशा पर कि यदि एक वर्ष के भीतर ही मीतर माल मिल गया तो पाया हुआ हर्जा रेलवे को वापिष दे देवें। ऐसी क्ले मस एडवाइसरी कमेटी की स्थापाना करना जिसके सटस्य उन उद्योगों छौर व्यापारों के प्रतिनिध हो जो क्ले ग्स विभाग के कर्मचारी से सम्मन्धित है छाटि कुछ ऐसे उपाय है जिनके प्रयोग में लाने से रेलवे के दोप मिट सकते हैं।

रेलवे के कर्मचारी इस बात का प्रयन्न कर रहे हैं कि रेल के कार्य प्रणाली की समता बढ जाय श्रीर सुविधार्ये भी बढ जॉय, माल की सघी चोरियों श्रीर उनके खोने पर रोक याम करने के लिए रेलवे करपशन इनक्चारी कमेटी की नियुक्ति की गई है जो शीम ही श्रापनी रिपोर्ट सरकार के समझ उपस्थित करने वाली है। रेलवे के चालू व्यय पर रोक थाम में सहायता करने के लिये

श्रीर रेलवे का विकास करने के लिए, विकास में वैज्ञानिक ढग का प्रयोग करने के लिये तथा वड़ी-बड़ी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के लिये, जिन्हें पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत रेलवे को पूर्ण करना है, रैलवे बोर्ड की सदस्य सख्या चार के स्थान पर पाँच कर दी गई है।

योजना के अन्तर्गत-प्रथम पंचवर्णीय योजना में ४०० करोड रुपये के व्यय का प्रस्ताव रेलवे के नये सामान के क्रय करने तथा पुराने की मरम्मत के के लिये किया गया था। वास्तव में यह श्राशा की जाती है कि प्रथम योजना के समाप्त होने तक लगभग ४३२ करोड़ रुपया व्यय हो जायगा । गन्त्रयानाटि ग्रीर श्रीर खर्चाग स्यत्र पर व्यय प्रस्तात्रित धन से बहुत श्रिधिक हो गया है। गनत्रया-नादि पर स्त्रधिक व्यय होने के कारण यात्रा स्त्रीर दुलाई १९५३-५४ स्त्रीर १९५४ ५५ के बीच साढे श्राठ प्रतिशत बढ़ गई श्रीर श्राशा की जातो है कि योजना के र्श्वान्तम वर्ष में नो प्रतिशत वह जायेगी। प्रथम योजना के ज्ञारम्भ के समय रेलदे के पास ⊏२०६ इन्जन, १६२२५ यात्रियों क डिब्बे ग्रौर २२२४४१ माल के हिन्वे थे। इनमे से २११२ इन्जन, ७०११ यात्रियो क डिन्वे श्रीर ३८५५४ माल के डिब्वे पुराने थे। प्रथम योजना में १०३८ इन्जनो स्रोर ५६७४ वात्रियों के डिब्वे श्रीर ४६१४३ माल के डिब्बों के क्रय करने का प्रबन्ध किया गया था। वास्तव में उपर्युक्त सख्या से कुछ अधिक इन्जन और माल के डिब्वे और कुछ कम यात्रियो के ।डब्वे प्रथम योजना के अन्तर्गत क्रय किए जा सकेंगे। इतनी अधिक मरम्मत श्रीर नये सामान के क्रय किए जाने के पश्चात् भी भारतीय रेलवे का सामान बहुत पुराना श्रीर पुराने ढग का है। द्वितीय पचवर्षीय योजना के श्रारम्म मे ६२६२ इन्जन, २३७७६ यात्रियो के डिब्वे ब्रीर २६६०४६ माल के डिब्वे काम मे श्राते हुये होंगे जिनमें से २८१३ इन्जन श्रीर ५३०५ यात्रियो के डिव्वे श्रीर ४६५६⊏ माल के डिब्बे बहुत पुराने धिसे हुये होंगे श्रीर उनके स्थान पर नये लाने श्रावश्यक होंगे। इससे यह पता लगता है कि रेलवे के विस्तार की इतनी श्रावश्यकता होते हुये भी उनकी मरम्मत श्रीर उनके स्थान पर नये सामान लाने की जरूरत बहत बड़ी है।

दितीय योजना के ध्रान्तर्गत ११२५ करोड़ रुपया भारतीय रेलवे पर व्यय किया जायगा जिसमें से ७५० करोड़ सामान्य आय में से, २२५ करोड़ रेलवे के अवज्ञरण कोष से, १५० करोड़ रेलवे की आय से प्राप्त होगा। रेलवे बोर्ड के १४८० करोड़ रुपये के व्यय किये जाने के प्रस्ताव के स्थान पर ११२५ रु० का व्यय किया जायगा।

द्वितीय योजना में १६०७ मील के रकाय के दुगने किये जाने का, २६५

होंटी लाइन को बढ़ी लाइन में परिवर्तित कर देने का, लगभग ८२६ मील तक विजली पहुँचान, १२६३ मील तक पीडप्वाल्स सुविधा देने का, ८४२ मील नई लाइन निछाने, २००० मील लाइन की मरम्मत करवाने और २२५८ इन्जनों को किन करने तथा ११३६४ यात्रियों के डिब्बों और १०७,२४७ माल के डिब्बों को प्रयूक्तने ना आयोजन किया गया है।

मारतीय रेलवे १२ करोड़ टन माल के ढोने के स्थान पर १६५५-५६ में ११ करोट ५० लाख टन माल दोयगी श्रीर इस प्रकार ५० लाख टन माल के द्वाये जाने की कमी रह लायेगी। यटि इतीय योजना के श्रन्त तक जो ६ करोड़ ए लाख टन माल के ढोये जाने की श्रावश्यकता बह जायेगी उसका विचार किया जाय तो इम बह मबते हैं कि १६६०-६१ तक १८ करोड़ ८ लाख टन के ढोये जान की श्रावश्यकता होगी। ऐसा भय है कि जितना घन रेलवे के विकास ए लिये नियंत कर दिया गया है उसके प्रयोग से रेलवे इतना माल न ढो सके श्रीर जिन मुवियाओं के प्रदान करने का इराटा किया गया है वे श्रावश्यकता मे १०% गन्त्रयानादि क मम्बन्ध में श्रीर ५% श्रपनी शक्ति के सम्बन्ध में कम कर देनी पढें।

हितीय पचवर्षीय योजना के झाधार पर योजना झायोग के मतानुसार (मंड १६५८) "नो नार्यक्रम १८२५ करोड़ रुपयों के व्यय का बनाया गया था उमने अब मूल्यों में बृद्धि हो जाने के कारण १०० करोड रुपयों के झीर अधिक व्यय होने का अनुमान किया गया है। इस समय ११२५ करोड़ रुपयों की मात्रा व्हाट जा नहीं सकती। इसिलये केलवे नो योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास योजनाओं को स्थित करना पड़ेगा। विदेशी विनिमय की किटनाइयाँ भी इसका एक नारण होगी। जिन विकास योजनाओं को स्थिति करने का उराटा है वे (१) नम्यागम तिलुपुरम नेत्र तथा कलमत्ते के अन्तर्गत सियालदा चेत्र में बिजली पहुँचाने भी भाजना, (२) मीटर गेज कोच फेक्ट्री (३), इस्टीगरल कोच फेक्ट्री के प्रसाधन विभाग तथा (४) गुना और उटजेन के बीच नई रेल के लाइन बिछाने की योजनार्य हैं।"

"ग्राने न्येय को प्रा नर लेने के प्रश्न का जहाँ तक सम्बन्ध है यह श्राशा की जाती है नि १६६०-६१ तक गेलवे ४२० लाज टन माल ढोकर श्रितिक ग्राप प्राप्त कर संकरी। पर ग्या पह श्राप पर्याप्त होगी। निश्चित कर से कहा नहीं जा सकता। विदेशी विनिमय तथा ग्रन्य कठिनाट्यों के कारण विनास योजना में दील देने के कारण दुलाई की मात्रा योजना के श्रान्तिम वर्ष तक श्रारम्भ में किये गये श्रनुमान से जो कि ६१० लाख टन था म्म

हो जायगी पर हो सकता है कि ४२० लाख टन से अधिक हो। कुछ भी हो योजना में की गई रेल द्वारा माल ढोने की मात्रा के श्रनुमान में कुछ, परिवर्तन तो श्रवश्य ही होगा। जहाँ तक यात्रियों के ढोने के व्येय से सम्बन्ध है-अपर्गत् 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि - वह सम्भवतः पूरी हो जायगी। १६५५-५६ की अपेक्षा १९५६-५७ में रेल के यात्रियों में प्रतिशत वृद्धि ६ ७ हुई थी। अगर यहां रही तो

रेल में मीड की समस्या और भी श्रिविक खराब हो जायगी।" द्वितीय योजना में भारतीय रेलवे की माल ढोने ग्रीर यात्रियों के ग्राने-जाने की शक्ति में वृद्धि की व्यवस्था की गई है। परन्तु वृद्धि देश की आवश्यकता से बहुत कम सम्मव हो सकेगी। केवल सरकार को ही नहीं बरन् जनता को भी अधिक मात्रा में यातायात की सुविधा की आवश्यकता पडेगी। प्रथम योजना में भी जनता को यातायात की सुविधा में कमी का अनुमव हुआ था। दितीय योजना में तो स्थिति त्रोर भी खराब होगी। रेलवे के सम्बन्ध में यही सर्व प्रधान ग्रालीचना है। विदेशी विनिमय की कठिनाइयों तथा मूल्यों में वृद्धि होने पर भी योजना में रेलवे के विस्तार के प्रति व्यान अधिक रखना चाहिये था भ्रोर व्यय के लिये ऋधिक धन नियत करना चाहिये था।

घध्याय ३४

सहक यातायात

मारत में सहको का बहुत श्रमाव है। १६०० में सहकों की लम्बाई कुल १,७६,००० मील थी श्रोर १६५२ में २,५६,००० मील थी। प्रथम योजना के श्रन्त तक कुल सहकों की लम्बाई बढकर ३१६,००० मील हो गई जिसमें से १२१,००० मील पक्की सहके हैं श्रीर शेप कच्ची। एक ऐसे देश में जिसका चेत्रफल १,१३६,००० वर्गमील है, जिसकी जनसख्या लगभग ३५ करोड ७० लाख है और जिसके उत्योग तथा कृषि का काफी विकास हो चुका है २६५,००० मील सहके बहुत कम हैं। भारत में प्रति वर्गमील में बहुत ही कम सहकें हैं, श्रन्य देशा की नुलना में यह स्थिति श्रत्यन्त शोचनीय है। भारत के प्रति वर्गमील चेत्रफल में सहकों को लम्बाई ०२ है जब कि इन्गलैयड में २०, वेलाजयम में ३३, फास में २४ श्रोर श्रमरीका में ११ है।

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देश के आधिक विकास में सडकों का विशेष महत्व है। चडकें होने से ही ग्रामो से कच्चा माल ग्रोर कृषि उत्पादन कारखानो कस्त्रों और नगरों तक पहुँचाया जाता है और बन्टरगाहों तथा कारम्वानों से माल आमां तक मेना जाता है। देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियां के लिए सहकें यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं। सब्कों की सुविधा से ही व्याक्त एक दूसरे से सम्पर्क स्यापित कर सकते हैं। वर्तमान काल में परस्पर सम्पर्क स्थापित करने के लिए यातायात के द्रुतगामी साधनों की श्रोर श्रन्छी सडकों की श्रत्यन्त श्राव-रएकता है। रेलों तथा विमाना की सहायता से देश के वहे-इंडे नगरों श्रीर न्यापारी केन्द्रा से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है परन्तु देश के दूर-दूर के स्थानों तक पहुँचने के लिए श्रौर उनका लाम उठा सकने के लिए अञ्छी सडकों का होना अत्यन्त आवश्यक है। युद्ध के समय यदि सडकें अञ्ची हैं तो सेना को शीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है, युड-सामग्री ख्रावश्यक स्थानों तक पहुँचाई जा सकती है ख्रीर इस प्रकार देश की शत्रु ने त्राक्रमण से रज्ञा की जा सकती है। नास्तव में भारत की कुछ पाचीन बडी सहकें इसी उद्देश्य से बनाई गई थीं। यदि देश में अन्छी सहकों का जाल विछा हो तो उसका शाविकाल में तथा युद्ध के समय हर स्थित में विशेष महत्व होता है।

श्रतीत में दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ते से मद्रास, मद्रास से वम्बई श्रीर चम्बई से दिल्ली को मिलाने वाली चार वही सहकों के चारों श्रोर छोटी बडी सहकों का जाल फैला हुआ था। इन चार बड़ी सहकों को वारहो मास कार्य में नहीं लाया जा सकता है। पुल न होने के कारण श्रीर टूट-फूट तथा सामान्यतया स्थित खराब होने से इन सहकों का बरसात में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन बड़ी सहकों को देश के ग्रामों से मिलाने वाली प्रदेशीय सहकों तथा अन्य छोटी-छोटी सहकों को स्थित श्रीर भी खराब है।

देश की आन सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सड़कें बढ़ाई जायं।
ताष्ट्रीय सड़कें वर्तमान समय की भाँति केवल पूर्व से पश्चिम तक के ज्ञेत्र में ही
न फैलें वरन इनका प्रसार उत्तर से दिच्या तक भी किया जाय। इसके साथ ही
इन सड़कों को और प्रदेशीय तथा अन्य छोटी सड़कों को सभी श्रृदुआ में कार्य
में लाने योग्य बनाने की आवश्यकता है। मोटर यातायात के लिए भी कुछ
सड़कों का होना आवश्यक है। इसके लिए सड़कों के मोड सुराम होने चाहियें,
जहाँ से सड़क निकाली जाय वह भूमि पक्की होनी चाहिए और सड़कों को ककर
तया डामर या सिमेंट के प्रयोग से पक्का बनाना चाहिए। इन सड़कों की सतह
को चिकना होना चाहिये। इसके साथ ही बैलगाडियो तथा यातायात के अन्य
साधनों के लिए भी ऐसी सड़के होनी चाहियें जो मोटर की सड़क की भाँति अधिक
व्ययशील तो न हों परन्तु ऐसी हों जिनको वर्ष भर प्रयोग में लाया जा सकता
है। यह बहुत आवश्यक है कि सड़कों के निर्माण की सुसम्बद्ध योजना निर्माण
की जाय जिसमें बड़ी राष्ट्रीय सड़कों, प्रदेशीय सड़कों और ग्रामों इत्यादि को
मिलाने वाली छोटी-छोटी सड़कों को विशेष महत्व दिया जाय।

भारत में सड़कों के विकास की श्रोर वहुत कम ध्यान दिया गया है, इसके कई कारण हैं -(१) सरकार ने श्रीर स्थानीय सस्थाश्रों ने सड़कों के विकास का महत्व नहीं समका। नगर पालिकाश्रों श्रीर जिला बोडों की देख-रेख में श्रनेक सड़के हैं परन्तु इन सस्याश्रों ने सड़कों के विकास की श्रोर उचित ध्यान नहीं दिया। प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने भी श्रन्य विकास कायों को इसकी श्रोयश्यकता श्रीर इसके महत्व की श्रोर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान गया है श्रोर दोनों सरकारों ने इसके लिए योजनाएँ बनाई हैं, (२) सड़कों के निर्माण के लिए श्रावश्यक बहुत प्रकार के सामान श्रीर मशीनो का भारत में श्रमाय है श्रोर धनका श्रायात करने के लिए हमे विदेशों पर निर्मर करना पड़ता है। श्रव भारत में सिमेंट तथा सड़क-निर्माण के श्रम्य सामानों का उत्पादन होने लगा है साथ

ही महक कृटनेवाले, भाप से चलनेवाले इखनों तथा दि जिल इखनों का भी भारत म उत्पादन श्रारम्भ हो गया है परन्तु फिर भी एसफाल्ट के लिए विदेशों पर ही निर्भर करना पडता है। श्राशा है कि पेट्रोल शोधशालाओं का निर्माण पूरा हो जाने पर देश की श्रावश्यकता पूर्ण करने के लिए एसफाल्ट प्राप्त हो जायगा; (३) देश मे वित्त का श्रामाव है। नगर पालिकाओं श्रीर जिला बोडों की देख-रेख में जो सदकों है वह वित्त के श्रामाव के कारण श्रावशी दशा मे नहीं रह पातों। राज्य सरकारों के पास विकास के लिए कोष है परन्तु उनका उपयोग सहकों के निर्माण में कम श्रीर अन्य कार्यों में श्राधक किया गया है। यही स्थित केन्द्रीण सरकार की भी है।

सद्क कोय—सडक दिकास समिति (१६२७) की सिफारिश पर १६२६ में सदक विकास कोष स्थापित किया गया और प्रति गैलन पेट्रोल पर कर ४ आने स बढ़ाकर ६ आने कर दिया गया जिसमें से प्रति गैलन दो आना सडक विकास कीप में जमा किया गया। बाद में पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगाकर सडक विकास कीप में दो आने की लगह ढाई आना जमा किया गया। परन्तु दुर्माग्यवश सड़क विकास कोप के घन का उचित उपयोग नहीं किया गया है। सड़क विकास कीष स्थापित हो लाने के बाद राज्य सरकारों ने अन्तर-राज्य तथा अन्तर-जिला सडकों के विकास में स्वय अपने वजद से व्यय कम कर दिया। इसके साथ ही आमों को मिलाने वाली छोटी-छोटी सडकों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार सदक विकास कोप निमाण का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया। सडकों का विकास करने के लिए उपलब्ध साधनों में अपनी आर से सहायता देने की अपेन्ता राज्य सरकारों ने अपने व्यर्थ में कटौती कर दी।

भीरत सरकार ने सहक विकास की प क धन को व्यय करने में कुछ प्रांतवन्य लगा दिये। सरकार ने यह व्यवस्था की कि (१) इस कोष का धन सहकां के निर्माण तथा सुधार में व्यय किया लाय परन्तु इस कोप का वर्तमान सहकों की मरम्मत और देखभाल में उपयोग नहीं किया जा सकता है, और (२) सहक विकास कीप में राज्य के योगदान का कम से कम २५ प्रतिशत छोटी छोटी सटकों में व्यय किया जाय और उन सहकों पर २५ प्रतिशत से अधिक व्यय न किया जाय जो रेल मार्ग की प्रतियोगी हैं। यह सब होते हुए भी यह सत्य है कि सहक विकास कीप से प्राप्त होने वाला धन आवश्यकता से कम है और १६५०-५१ के अत तक २० करोड़ रुपये के व्यय की याजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी यी और १७ करोड़ रुपयो व्यय किया जा चुका था। १६५१-५२ से दिसम्बर १६५५ तक २७ करोड़ रुपयो के व्यय की

योजनास्त्रों को स्वीकृति दी जा चुकी थी श्रीर माच १९५५ तक लगभग १२ करोड़ रुपया उनके कार्योन्वित करने में व्यय किया जा चुका था।

सरकार अपनी वर्तमान आय में से सड़कों के निर्माण में पर्याप्त व्यय नहीं कर सकती हे साथ ही इस कार्य के लिए सहकों का उपयोग करने वालो पर लगाए गये करों से भी पर्याप्त आय नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सडको के निर्माण के लिए ऋण लिया जाय। यह सोचना विल्कुल निरर्थक है कि सदकों पर ब्यय किये जाने वाले रुपयां से प्रत्यज्ञ रूप मे ऐसी ब्राय नहीं होती है जिससे इस कार्य के लिए उपलब्ध ऋगा का ब्याज चुकाया जा सके, इसलिए यह व्यय अनुत्यादक है ज्ञीर इसकी नहीं करना चाहिए। यह समन है कि सहको के विकास से प्रत्यज्ञ रूप में कोई आय न हो परन्तु इससे निरसन्देह देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और साथ ही जनता की कर देने की शक्ति मे वृद्धि होती है। भारतीय सडक एवम् यातायात सघ ने कुछ वर्ष पहले एक जॉच की जिसमें पता चला कि एक विशेष दोन में सहक का विकास करने से १२ लाख रुपये का वाषिक लाभ इस्रा जब कि सहक निर्माण में तथा उसकी देखभाल में केवल ४३ लाख रुपया वार्षिक व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि सडकों पर व्यय किये गये प्रति १०० रुपयों पर जनता को २७७ रुपये का लाभ होता है। सहका के विकास से जनता समृदिशाली बनती है, सरकार की आय में वृद्धि होती हे, इसलिए ऋगा लेकर सबकों पर निर्माण करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनो चाहिए।

नागपुर योजना—१६४३ में विभिन्न राज्यों के मुख्य इङ्गीनियरों की नागपुर में एक वैठक हुई श्रीर देश की न्यूनतम श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए एक सहक निर्माण-योजना निर्माण की गई। इस योजना का विशेष महत्व है क्योंकि इसके पश्चात भारत में सहका के निर्माण की सभी योजनाश्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है। नागपुर योजना में सहको को चार श्रे (ण्यों में विभक्त किया गया है •—(१) राष्ट्रीय सहके, (२) राष्य की सहकें, (३) जिलों की वही छोटी सहकें श्रीर (४) ग्रामा का सहकें। योजना में इन चार प्रकार की सहकों का १० वर्ष के श्रन्दर सुनियो।जत श्रीर सुसम्बद्ध श्राधार पर विकास करने का सुक्ताव दिया गया था जिससे पक्की सहकों की लम्बाई लगभग ६६,४०० मील से १,२२,००० मील तक श्रीर श्रन्य सहकों की लम्बाई १,१२,००० से २,०७,५०० मील तक बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही योजना में वर्तमान सहकों में सुधार करने का भी सुक्ताव दिया गया। नागपुर योजना का उद्देश्य यह था कि विकसित कृषि चेत्र का कोई भी ग्राम मुख्य सहक से ५ मील से श्रिषक दूर न पटे श्रीर कोई

भी गाँव चाहे कहीं हो सहक से २० मील से श्राधिक दूर न पड़े। इस योजना के श्रानुसार युद्ध पूर्व के मूल्या में ५० प्रतिशत वृद्धि के श्राधार पर निर्माण-कार्य में ३७२ करोड रुपया लगेगा जिसमें से ६६.५ करोड़ रुपया राष्ट्रीय सहकों पर श्रीर ३०५ ५ करोड रुपया श्रन्य सहकों पर न्यय किया जायगा। यदि मूल्य युद्ध पूर्व के स्तर से २०० प्रतिशत बढ़े मान लिये जावें जिससे न्यय का श्रनुमान वर्तमान सम्म के मूल्य के श्रिक्ष निकट श्रा सके तो, जैसा कि योजना-श्रायोग ने बताया है, नागपुर योजना को कार्यान्वित करने में कुल ७४४ करोड रुपया न्यय होगा जिसमें से १३३ करोड रुपया राष्ट्रीय सहकों के लिए श्रीर ६११ करोड़ रुपया श्रन्य सहकों पर न्यय किया जायगा।

रेल मार्ग से सम्बन्ध—भारत में सहकें अपयांत होने और सहकों की हिंधति टोष पूर्ण होते हुए भी १६३० के आसपास सहक यातायात से रेलवे को गहरी प्रतियोगिता का समना करना पड़ा। निजी बस सिवधां की आरे रेल की अपेद्धा अधिक यात्री आकर्षित हुए निसमें अधिकतर कम आय वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही हलके सामान को लाने लेजाने के लिए भी मोटरों को सुविधाजनक समक्ता गया। मोटर यातायात प्रायं और सुगमता से हो जाता है इससे रेल को गहरी हानि उठानी पड़ी। अनेक रेलवे जॉच समितियों ने रेलवे तथा सहक यातायात की प्रतियोगिता पर विचार किया और रेलवे को सहक की प्रतियोगिता में रज्ञा करने के अनेक सुक्ताव दिए। रेलवे ने सस्ते वापसी टिकटों के रूप में रियायत देनी शुरू कर दा, कुछ विशेष समय के लिये टिकट टिये, अच्छी सर्विस और कम किराये की व्यवस्था की। परन्तु इससे प्रतियोगिता का जोर कम नहीं हुआ और यह आशोक की जाने लगी कि सहक यातायात से रेलवे को गहरी हाति पहुँचेगी।

रेलवे के हिवों की रज्ञा करने के लिए सरकार ने श्रनेक उपायों का श्राश्रय लिया श्रीर १६३६ में मोटर गाडी कानून लागू किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि सभी मोटरों तथा बसों के लिए लाइसेन्स लिया जाय। कानून में बसों को रखने तथा श्रविक यात्री न बैठाने श्रीर वसों की चाल इत्यादि पर नियत्रण की शर्ते माननी श्रनिवार्य कर दी गई। वसों का बीमा श्रावश्यक कर दिया गया। इस कानून से यात्रियों के हितों की रज्ञा के साथ ही हानिकारक प्रतियोगिता को रोकने का प्रयत्न करके रेलवे के हितों की रज्ञा की भी व्यवस्था की गई। परन्तु सङ्क यातायात की श्रोर से प्रतियोगिता प्रचलित रही श्रीर १६४६ में इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए एक त्रिटलीय सगठन का निर्माण करने की नीति श्रपनायी गई। इस सगठन में मोटर मालिकों, राज्य सरकार श्रीर रेलवे

के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। परन्तु इस योजना की आशा के अनुक्ल सफलता नहीं मिली । बाद मे भारत सरकार ने सड़क यातायात कार्पीरेशन कार्त (१६४८) लागू किया जिसके स्थान पर १६५० में एक श्रीर व्यापक कानून लागू किया गया।

वर्तमान में रेल श्रीर सइक की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है क्योंकि (१) यातायात का अभाव है भ्रीर वर्तमान समय में रेल श्रीर मोटर यातायात को साथ साथ कार्य करके लाभ उठाने का काफी अवसर है, (२) कुछ तो सरकार के प्रतिबन्धों के कारण और कुछ मोटरों के तथा उनके विभिन्न कल-पुजों के मूल्य अधिक होने से सड़क यातायात का न्यय बढ गया है, और (३) अनेक राच्यों मे यातायात का राष्ट्रीकरण कर देने से रेलवे तथा रोडवेज में आधिक

राज्य द्वारा संचालित सङ्क यातायात के देत्र निश्चित है श्रीर मोटरे उचित सम्बन्ध स्थापित हो गया है। यात्रियों तथा सामान को उसी चेत्र के अन्दर लाती ले जाती हैं। इस बात पर महत्व दिया गया है कि यातायात इस प्रकार सचालित किया जाय जिससे रेल-सहक यातायात का सुसम्बद विकास हो । यातायात इस प्रकार नियोजित हो कि यात्रियो तथा सामान को रेलवे केन्द्रो तक पहुँचाया जाय जहाँ से छाने का यातायात रेलवे समालेगी। जहीं तक रोडवेज का सम्बन्ध है यात्रियों को दी जानेवाली सुविधाएँ बढी हैं, श्रिधिक मीड-भाइ पर नियत्रण रखा गया है श्रीर

यह योजना १६४६ में वम्मई में प्रारम्भ की गई श्रीर १६४८ से १६५० गाहियाँ श्रव्छी दशा में रखी गई हैं। तक ढाई वर्ष में यातायात के मार्गों की सख्या द से ४६५ तक वढ गई। श्रारम्म में २४० मील तक यातायात की व्यवस्था यी । १६५० में यह व्यवस्था १५,०३६ मील तक फैल गई और १६४८ से १६५० तक क्रमधः कुल १,०८,७७२ और २,६१६,२४७ मील के बीच यातायात किया गणा। इसके बाद के वर्षों में इस दिशा में प्रगति घीमी रही है परन्तु सभी इष्टिकोगीं मे रोडवेज ने उझति की है। उत्तर प्रदेश में १६४७-४८ में ३१ सरकारी रोडवेज सर्विसे चाल हुई जो १६५५-प्रमें २३७ हो गईं। यह यातायात व्यवस्था ६,००० मील तक फेली हुई है। यह ग्रनुमान लगाया गया है कि कुल १०,००० मील के चेत्र में यात्रियों के यातायात का राष्ट्रीकरण करने में २,३०० वसो को आवश्यकता होगी। द्वितीय •योजना के ग्रान्तगेत इस यातायात सुविधा का विस्तार ६६६४ मील हो जायगा ग्रौर उसमें १६०० वसे होगी।

वम्बई में राजकीय रोडवेज ने द से ६ पाई प्रति मील किराया वस्त

विया। इसमे पहले इस द्वेत्र में किराये की यही दर वस्ली गई थी, परन्तु गुजरात में मोटर मालिकों ने रेलवे की प्रांतयोगिता में किराया कम वसला था। बम्बई में यर्राप किराया कम नहीं किया गया है परन्तु रोडवेज की सविस में निस्सन्देह काफी सुधार हुआ है श्रीर जनता को राष्ट्रीकरण से पहले की अपेना अधिक सुविवाएँ प्रदान की गई हैं। नहीं तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है रोडवेन का ग्रपर तथा लोग्रर वलास का विराया श्रवट्टवर १९५२ में क्रमशः ६ पाई श्रीर ७ई पाई से बढ़ा र १०३ पाई श्रीर = पाई प्रति मील कर दिया गया। किराये में वृद्धि करने का उद्देश्य मोटर इत्यादि के कल-पुजा तथा श्रन्थ सामाना भी बढी मृत्या को पूर्ण करना था। परन्तु चॅ्कि केन्द्रीय कारखाने स्थापित कर देने से मरम्मत इत्यादि में पहले की अपेता कम ज्यय वरना पड़ता है इसलिए १९५३ में क्रियों में कभी कर दी गई। अब किराये की दर अपर क्लास के लिए १०३ पाई प्रति मील से घटाकर ६ पोई प्रति मील कर टी गई ग्रीर लोग्नर यलास के लिए किराये का टर पाई से घटाकर ७३ पाई कर टी गई। श्रयत्वर १६५२ से पहले किराये की यही दर थी। लोश्रर बलास का किराया श्रव भी रेल के तीसरे दर्जे के किराये से श्रादिक है। रेल में तीसरे दर्जे का १५० मील का किराया यदि खाकगाड़ी या एवसप्रेस से सफ़र विया जाय तो ६% पाई प्रांत मील है श्रोर यदि सामान्य गाही से सपर विया जाय तो दर ५ई पाई प्रति मील है परन्तु आशा की जाती है कि भविष्य में रोहवेज किराया श्रीर घटायेंगी।

राजकीय रोडवेज प्रणाली सन्तोषजनक रीति से चल रही है परन्तु (१) गाहियों को रखने तथा मरम्मत इत्यादि करने का ज्यय श्राधक है श्रीर रोडवेज को उतना लाम नहीं होता है।जतना की श्राशा थी। (२) श्रमी कुछ दिशाश्रों में यात्रियों को श्रीर श्राधक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती है। परन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि रोडवेज ने सड़क यातायात की श्रवस्था मे काफी सुधार किया है श्रीर भारत मे रोडवेज यातायात व्यवस्था का प्रसार करने के लिए कोई वाधा नहीं है।

निजी उद्योग की कठिनाइयाँ—भारत ने सहक यातायात के विकास
में अनेका कारणों से बाधायें पहुँची हैं (१) मेटर गाहियों को बहुत अधिक
कर देना पड़ता है जिससे व्याक्तयों भी इस कार्य को करने की शक्ति टूट जाती
है। मोटर गाई। कर जोच कमेटी ने यह बात नहीं थी कि मारत में मोटर
गाडियों का प्रयोग करन वाले व्याक्तयों पर ससार भर में सन से अधिक कर
लगाया जाता है। इसी रिपोर्ट ने अनुसार प्रत्येक लारी पर प्रति वर्ष कुल कर
मद्रास में ६,०७७ कपये, बम्बई में ५,००० कपये से लगा कर ५,२५८ वर्ग तक

श्रीर श्रन्य राज्यों में श्रीसत कर लगभग ५,१३४ रु० था। इस कमेटी ने यह भी श्रनुमान लगाया था कि माल ढोने वाली लाग्यिं केन्द्रीय श्रीर स्वदेशीय राज्यों को जितना कर देती हैं, (स्थानीय करों को छोड़ कर) यदि वे २० हजार मील से अधिक यात्रा करती हो तो वह रेल द्वारा प्रति टन प्रत मील दुलाई के ग्रीसत किराये से सौ प्रतिशत भ्राधिक था। पिछले तीन वर्षों में लारियों पर यह भार बारतव में झनेकों राज्यों में श्रीर श्रधिक बढ़ा ही है।

- (२) प्रादेशिक सरकारों ने सहको पर बहुत कम धन ब्यय किया है श्रोर उनकी देख-रेख भी ठीक नहीं होती। इससे न्यक्तियों को वस चलाने के कार्य मे बड़ी कठिनाई पड़ती है। "मोटर गाडी कर जॉच कमेटी ने पता लगाया था कि कि राज्यों को १९४६ में रिजस्टर की हुई मोटर गाहियों और वस्तुत्रों से प्राप्त २३'२६ करोड़ रुपयों के लगमग यी जब कि सहकों की मरम्मत पर नेवल ११'७ करोड़ क्यया व्यय किया गया था जो कि वमूल किये हुये कर के आदि से भी कम है। यह स्थिति वड़ी विचित्र है कि सड़ क यातायात पर कर इतना अधिक है कि यात्रियो ख्रीर माल ढोने में उनका प्रयोग करने मे बाघा पड़ती है, पर किर भी मोटर गाड़ियों से वस्ल हुये कर के घन का पूरा प्रयोग सहकों के बनाने में नहीं किया जाता। " सडक की ठीक मरम्मत न होने से सडक यातायात के ब्यय मे नी वृद्धि हो जाती है। कमेटी ने श्रतुमान लगाया था कि एक वस साधारण सराव और बहुत सराव सहको पर एक वर्ष में ३५००० मील चलाने में व्यय ग्रुच्छी सहक में चलाने मे ज्यय की अपेदा २६०० ६० अधिक होगा।
 - (३) १९३६ में मोटर गाड़ी एक्ट ने उन लंबी यात्राश्ची पर जो उस समय वम्बई ग्रीर कलकत्ते, वम्बई श्रीर देहली, वबई ग्रीर पेशावर श्रीर वम्बई ग्रीर महाउ श्रादि के बीच प्रचलित थी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इस एस्ट की योजना है कि सदक यातायात की राज्यों के छोटे-छोटे चेत्रों में ही सामित कर दिया जाय जिसमे कि कोई मोटर राज्य की एक सीमा से दूसरी सीमा तक जिना अनेको यातायात अधिकारियों की आशा के न जा सके। ऐसी आशा बहुत ही कम दी जाती है। ऐसी स्थित में अन्तर प्रदेशीय यातायात की कोई सम्मावना ही नहीं हो सकता । मोटर गाहियों के चलाये जाने के द्वेत्र को सीमित करने के ग्रांतिरिक्त दोत्रों के कर्मचा-रियो को यह अविकार भी प्रदान किया हुआ है कि वे अपनी इच्छा के अनुमार विभिन्न देशों में चलाई जाने वाली मोटर वसों की सख्या भी सीमित कर एकते है। मोटर गाडी एक्ट ने छोटे-छोटे चेत्रों में अनेको अविकारियों को बनाकर सहक के यातायात की छोटे-छटे भागों में विभाजित करके तथा प्रतिकच लगा

कर निहित स्वाथ का श्रवसर प्रदान कर दिया है । इसके परिसाम स्वरूप सङ्क यातायात के वैज्ञानिक ढग पर विकास में बाधा पड़ी है।

(४) जिस प्रकार सहक यातायात का राष्ट्रीयकरण विभिन्न राज्य द्वारा किया गया है उससे राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत अधिक महत्वराली योजनाओं पर जो घन व्यय किया जाना चिहये था वही नहीं रोका गया वरन् व्यक्तियों को यह कार्य करने में बड़ी भारी वाघा भी पहुँची है। इस दोप को रोकने के लिये योजना आयोग ने १६५३ में प्रादेशिक राज्यों से अपनी-अपनी लाइसेंस देने की नीति को सुधारने की आजा दो थी न्योंकि वह व्यक्तियों को सहक यातायात का कार्य करना आरम्भ करने में बहुत वाघक थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक राज्यों ने इस आजा को अनसुनी कर दिया है क्योंकि कि इनके सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के कार्य कम में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अपनी आजा को मनवा सकने के लिये योजना आयोग को अपनी आजा निश्चित शब्दों में निश्चित निर्देशों सहित मेजनी चाहिये थी। स्थिति के अपने अनितम परीज्ञण में योजना-आयोग केन्द्रीय मन्त्रालय के सहयोग से इस परिणाम पर पहुँचा है कि द्वितीय योजना में माल और यात्रियों के सम्बन्ध में कुछ सिदान्तों का अनुसरण आवश्यक है।

माल की दुलाई के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त निम्न हैं:-

- १ सडक द्वारा ढोने वाली सस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना १९६१ तक अर्थात् द्वितीय योजना के अन्त तक नहीं सोची जानो चाहिये।
- २ १६३६ के मोटरगाड़ी एउट के श्रनुसार कम से कम तीन वर्ष के लिये ऐसी सस्याओं को जो पनप सकती हैं परिमट स्वतन्त्रता पूर्वक देना चाहिये। मोटरगाड़ी एक्ट के अन्तर्गत श्रिषिक से श्रिषिक पाँच वर्ष तक का परिमट देकर प्रोत्सहन देना चाहिये।

यात्रियों के यातायात के लिये निम्न सिद्धान्तों की सिफारिश की गई है-

- (१) जो प्रादेशिक राज्य यात्रियों के यातायात सेवा सस्याश्रों का राष्ट्रीय-करण करना चाहें उन्हें योजना श्रायोग के समक्ष क्रिमक कार्य-क्रम बनाकर विचार करने के लिये रखना चाहिये जिससे वह कार्यक्रम को योजना में सम्मिलित कर सके। इस कार्य-क्रम को उन्हें १६६० ६१ तक जिन चेत्रों में राष्ट्रीयकरण करना है उनका निश्चित रूप से विवरण दिया जाना चाहिये। इसका विचार श्रायोग द्वारा तभी हो सकता है जबिक शर्ते प्रादेशिक राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली जायं।
 - (२) राष्ट्रीयकरण योजना के बाहर की सदकों पर्यातायात के लिये

परमिट कम से कम तीन वर्षों के लिये १६३६ के मोटर गाड़ी एक्ट के श्रनुसार दिया जाय।

- (३) उन दोत्रों में जो स्वीकृत राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत आते हैं परिमट श्रिधिक से अधिक समय तक के लिये, जो कि विस्तार के कार्य-क्रम के अन्तर्गत मोटरगाड़ी एक्ट की सीमा के अन्दर ही है, दिये जाने चाहिये।
- (४) जहाँ पर सरकार के सहयोग की सम्मावना है एक त्रिदलीय सस्था स्थापित की जानी चाहिये जिसमे प्रादेशिक सरकारें, रेलवे और इस कार्य मे संलग्न व्यक्ति सम्मिलित हों।
- (५) उन च्रेत्रों में जिन्हे पूर्णतया व्यक्तिगत लोगों के श्रिधकार मे छोड़ दिया जाय प्रतिस्पर्धा दलों को विशेष प्रोत्साइन दिया जाना चाहिये।

राज्यों में सदकों के विकास में बाधा डालने वाली अनेक कठिनाइयों मे से एक तो निर्देशन करने वाले उपयुक्त कर्मचारियों का श्रभाव है जिनका कार्य मोटर द्वारा परिवहन की व्यवस्था पर ध्यान देना, सहकों के नियोजित विकास की अपेक्षा विशेष हो। १६५८ के आरम्भ में भारत सरकार ने एक कमेटी इस मामले की जाँच करने के लिये श्री० एम० ब्रार० मसानी की ब्रध्यज्ञता में नियुक्त की थी। सरकार ने १६५८ के आरम्भ में एक अन्तर-राज्य यातायात आयोग की भी नियक्ति की थी जिसको मोटरगाड़ो (सशोधित) एक्ट की ६३ ए घारा के श्चनुसार नियन्त्रसा तथा निर्देशन के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त है श्रीर जिससे यह श्राशा की जाती है कि (१) वह परिवहन की गाड़ियों के सचालन तथा उनके विकास सम्बन्धी योजनात्रों को तैयार करे श्रीर श्रपनी योजनात्रों में माल लादने वाली गाड़ियों का जो कि अन्तर्राज्यों में यह कार्य कर रही है विशेष ध्यान रक्खें, (२) इस सम्बन्ध में जो कुछ भी ऋगडे अथवा मतमेद उत्पन्न हो उन सन को निवटों यें श्रीर उन पर निर्शाय लें, (३) श्रीर दो श्रथवा दो से श्रधिक राज्यों में पड़ने वाले मार्गो पर मोटर गाड़ी चलाने, नये परिमट देने, पुरानों को फिर से चालू करने तथा रह करने के सम्बन्ध में राज्य विशेष के यातायात श्रिधिकारी को श्रयवा दोत्र विशेष के यातायात श्रिषकारी को निर्देश दे।" इस श्रायोग से आशा की जाती है कि यह अन्तर राज्य यातायात की सुविधाओं का प्रभावशाली रूप से विकास करने में सफल होगा।

योजना के अन्तर्गत — जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम हुई भारत में १७५४६ मील पक्की सहकें और १५१००० मील कच्ची सहकें थी । योजना के अन्तगत पिंदेले ११० करोड़ रुपया व्यय करने के लिये रक्खा गया या जो कि बाद में बढाकर १३५ करोड़ रुपया कर दिया गया जिसमें से प्रथम योजना काल में लगभग १३४६ करोड़ रुपये वास्तव में रार्च कर दिये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप २४००० मील नयी भूमि के समतल सहरें, श्रीर ४४००० मील नीची सहरें बनवाई गई श्रोर इस प्रकार सहरों की लग्नाई १२१००० मील पर्का श्रीर १६५००० मील कच्ची श्रार्थात् कुल ३१६००० मील हो गई जन कि नागपुर योजना का ध्येय देवल १२३००० मील पक्की तथा २०८००० मील कच्ची श्रार्थात् कुल ३३१००० मील सहर्को का ही था।

इसके ग्रातिरक्त श्रमेकों सहकों के बीच के व्यवधानी की मिलाने तथा पुलों के बनाने की भी व्यवस्था की गई थी। "पहली श्रमल १६४० का नव कि भारत सरकार ने राजाय कही जाने वाली सदकों क विरास तथा बनाये रखने का वित्ताय दायित्व ग्रपने कपर लिया उस समर लम्बी लम्बी दूरी तक सदमों के व्यवधान पढे हुये ये तथा मुख्य-मुख्य स्थानो पर श्रानेका सहको पर पुल नहीं थे। प्रथम योजना क श्रारम्भ तक ११० मील नहकें दो एहकों के बीच के व्यवधान को जाडन के लिये तथा तान बडे-बडे पुल बनवाये गये ग्रार १००० मील सदकों का मरम्मत करवाई गर्द । प्रथम योजना जाल के आरम्भ में ही वेन्द्रीय सरकार न सड़कों के विकास तथा सुवार मा कार्य कम आरम्भ किया जिसके अन्तर्गत १२५० मील वन्च की गायन सहको तथा ७५ बडे-बडे पुलों का बनवाना तथा ६००० माल सहकों की मरम्मत करवाना निम्म लत था। इनमें से योजना काल में ६४० मोल बीच की गायब सदके तथा ४० पुल तथा २५०० मील पुरानी सडकों की मरम्मत पृरी हो जाने की स्नाशा की गई थी। योजना के खत्म हाते-होते ६३६ मील वीच की गायम सडके, ३० बडे-बडे पुल स्रोर ४००० मील पुरानी सहकों की मरम्मत हो पाई थी। इस प्रकार इस देखते हैं कि जितनी वीच की गायव सबको के बनवाने का ध्येप बनाया गया या यह लग भग पूरा हो गया श्रोर वर्तमान राजप्यां की मरम्मत का काम सोची हुई मात्रा से लगभग दुगना कर लिया गया। पोजना में २७ ८० करोड़ रुपये राजपयों पर न्यय के लिये नियत किये गये ये जिसमे से २७६२ करोड़ रुपये व्यय उर दिये गये।

प्रथम योजना में सडको द्वारा यातायात पर १२३ करोड़ रुपये व्यय किये गये। राज्यों ने ३००० मोटर गान्दियों छोर वढाई विससे कुल मोटर गान्दियों की सख्या जो सरकार की छार से यातायात की सेवा में लगी हुई थी ११००० हो गई। प्रथम योजना के छन्त तक मोटर द्वारा जनता की यातायात सेवा का २५% सरकारी विभाग द्वारा किया जाने लगा था। माल परिवहन व्यक्तिगत एजेन्छियों के ही छाधिकार मे रहा।

द्वितीय योजना में (सडकों के विकास के लिये) २४६ करो रुपयों के

च्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से ८२ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रीर १६४ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा न्यय किया जायगा। यह रक्षम केन्द्रीय सहक कोष से प्राप्त होने वाले १५ करोह रुपयों के ग्रांतिरिक है। दिनीय योजना के पूरे होने पर यह अशा की जाती है कि परकी सहके बढ़ कर १४३,००० मील स्त्रीर कच्ची सहके २३५,००० मील अर्थात् कुल योग ३७८,००० मील हो जायगा।

यह मात्रा नागपुर योजना से कही ग्राधिक है। द्वितीय योजना का कार्यक्रम पहिली योजना ही की तरह बड़े-बड़े पुली का निर्माण तथा बडे-बडे राजायों का मिला देने वालो सहकों के निर्माण का श्रीर पुरानी सह कों की मास्मत का ही है। इस योजना के अन्तर्गत आर म किये हुये निर्माण कार्य पर कुत न्यय लगभग ८७ ५ करोइ कार्य का है। यह न्यय निम्न प्रकार का है।

ण काय पर छण न			
र का है। प्रथम योजना के श्रपूर्ण निर्माण कार्य प प्रथम योजना के श्रपूर्ण निर्माल कार्य प जिसमें विनहाल टनल सम्मिलित है-	र -	\$0°0	करोड रपया
ने नाल पर्या की निर्धार ।		१०५	5 7
3 / G A D #1101 /		२००	>>
2 2 2 2 1 HILL 4 ()	-	4.0	93
77 77 CM 19 10017		90	22
पुरानी सहका का मर्जन कर कीट) चौड़ी		१५ ०	0
कराने पर (३००० मील)	and the same of	८७'५	0
71.61	कुल जाएग	पुप्र करोव	इ रुपये का श्रत-

द्वितीय योजना काल य वास्तविक व्यय लगमग ५५ करोड़ रुपये का श्रनु-मानित किया गया है। राष्ट्रीय राज्यवधा के श्रातिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने कुछ महत्वशाली सहको का निर्माण प्रथम योजना में करवाना आरम कर दिया था। वह कार्य इस योजना मे प्रचलित रहेगा श्रीर लगमग ६ करोड़ रुपया इस पर व्यय हो जायगा। कुल मिला कर केवल १५० मील नई सड़क बनाई जायेंगी श्रीर लगभग ५०० मील सङ्को को उन्बस्तल कर दिया जायगा।

हितीय योजना में १३१ करोड़ रुपयों की राज्यों की सड़क यातायात सबन्दी विकास काय-क्रमों के लिये व्यवस्था की गई हैं। १८५० के रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एकट के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कारपोरेशन स्थापित करने की सलाह दी गई है और रेलवे योजना के अन्तर्गत १० करोड़ क्पयों की ज्यवस्था की गई है कि रेलवे इन कारपोरेशनों में सम्मिलित हों। इसके श्रितिरिक्त यातायात मन्त्रालय की योजना में देहली ट्रान्सपोर्ट सरविस के लिये एक ३ करोड़ रुपये का कार्य-कम भी स्वीकृत कर लिया गया है। इस प्रकार सरकारी सड़क यातायात पर कुल विनियोग द्वितीय योजना में १७ करोड़ रुपयों के लग मग होता है।"

१६५६-५७ में कुल सड़कों के कार्य क्रम पर न्य ४२ ७१ करोड़ रुपा या श्रीर १६५७-५८ के लिये सशोधित श्रनुमान ४४ ३२ करोड़ रुपयों का है इस प्रकार प्रथम तीन वर्षों से कुल न्यय १२६ २६ करोड़ रुग्या होता है। बचे हुये हो वर्षों के लिये ११६ ८६ करोड़ रुपया रह जायगा। श्रन्तिम हो वर्षों के लिये ११६ ८६ करोड़ रुपया रह जायगा। श्रन्तिम हो वर्षों के लिये वजट में इस रक्षम की न्यवस्था सम्भव हो सकेगो इसमें सदेह मालूम पड़ता है। इसके श्रतिरिक्त लोहे की कमी के कारण पुलों के निर्माण में बाघा पड़ने का भय भी है। इस्र्लिये इस यह कह सकते हैं कि योगना के विकास कार्य-क्षम में कुछ कमी श्रवश्य ही श्रायेगी।

_{श्रध्याय ३६}

जल यातायात

भारतीय यातायात श्रभी श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था में है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत के पास १२,५०० जी० आर० टी० (आस रजिस्टर्ड टनेज) के जलयान थे। प्रथम योजना के श्रारम्भ में भारत के पास ३,६०७०७ जी० श्रार० टी० के जलयान ये जिनमें से २,१७,२०२ जी० आर० टी० भारतीय तटी पर श्रीर १,७२,५०५ जी० ग्रार० टी० के जलयान विदेश में ज्यापार कार्य में ज्यस्त थे। प्रथम योजना के अन्त में कुल टनेज ४,50,000 जी० आर० टी० था जिसमें से २,४०,००० जी० श्रार० टी० तटीय व्यापार तथा समीपवर्ती देशों से व्यापार का था और २४०००० जी० श्रार० टी० दूर विदेशी ज्यापार का। लायह के जलयान के रिजस्टर के श्रमुखार ३० जून, १६५७ को समस्त समार का दुल टनेज १,१०२ करोड़ जी० श्रार० टी० या जनिक १६५५ के श्रन्त मे १,००६ करोड़ जी० श्रार० टी० ही था। इस प्रकार भारत का कुल टनेज ससार के टनेज के ३% से कुछ श्रिधिक था जब कि भारत का विदेशी व्यापार ससार के कुल व्यापार का ३% से अधिक था। श्रन्तराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के द्वारा भारतीय जलयान भारत के समुद्री न्यापार का केवल ५०% न्यापार कर पाते हैं। इसका यह अर्थ है कि भारतीय जल यातायात के विकास में भ्रमी बहुत लम्झा मार्ग पूर्ण करना है।

भारत के लिए जिसका समुद्री तट ४,१६० मील (श्रुग्डमन द्वीप समिनित करके) तक विस्तृत हुआ है और जो बहुत बड़ी मात्रा मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है वास्तव में जलयान का बहुत अधिक महत्व है। यदि हमारे पास अपने जलयान ही तो भारतीय उद्योग का यातायात व्यय कम हो जायगा स्त्रोर विदेशी बाजारों में उसकी प्रांतयोगिता शक्ति में वृद्धि हो जायगो। यदि सामान का भार-तीय जलयानी के द्वारा यातायात किया जाय तो हम उतनी विदेशी विनिमय मुद्रा बचा सकते हैं जिसको श्रान्यथा इन जलयानों में ज्यय करना पहता है। इसके साय ही भारत को श्रापने समुद्रतटीय देश की रज्ञा करने के लिये श्रीर युद्ध के समय अपने व्यापार की सुरचा के लिए एक शक्तिशाली जल सवा की आवश्य-कता है। सकट के समय ज्यापारी जलयान प्रतिरचा की दूसरी पंक्ति का कार्य देते हैं। यह सहायक सेना के रूप में ही सहायक नहीं होते बल्क इनसे नी-सेना को शिचा दी जा सकती है श्रीर युद्ध के समय श्रावश्यक सामान समुद्र पर पहुँचाने के लिए इनकी श्रत्यन्त श्रावश्यकता पड़ सकती है।

मुख्य विशेषताऍ—भारतीय जल यातायात के विकास की कुछ उल्ले-स्वनीय विशेषताऍ हैं —

- (१) भारत में श्रेंग्रेजी शासन के समय भारतीय जलयानों को ब्रिटिश तथा विदेशी जलयानों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा श्रीर उमे विज्ञास करने का श्रवसर हीं नहीं दिया गया । १६२० के लगभग श्रनेक जलयान कम्पनियाँ बनी परन्तु प्रतियागिता का भामना न कर सकने के फलस्वरूप नष्ट हो गर्छ । इन कम्पनियों के नष्ट होने म विदेशी जलयान कम्पनियों की भाडे की दर सम्बन्धी नीति का भी बहुत योगटान रहा है। इन विदेशी कम्पनियां ने भारतीय कम्पनियों से प्रनियोगिता के कारण भाड़े को टर घटा टी खीर जन यह वस्पनियाँ वन्ट हो गई तम भी भाड़े को टर मे पुन वृद्धिकर ली। इसके माय इन कर्पानयां ने यह व्यवस्था की कि यदि किसी व्यापारी ने एक निश्चित समय तक नियमित रूप से इनके जलवाना के द्वारा ही समान भेजा श्रीर मैगाया तो उस अवधि में यह जितना भारा देगा उसका एक अभ उसे वापिस कर दिया जायगा । इन विदेशी कर्णनया की प्रतियोगिता का केवल सिधिया स्टीम नेवी-गेशन कम्पनी ही सामना कर सबी। विदेशी कम्यनियों ने इसे नब्द करने की अनेक नार नेण्टा की परन्तु वह सफल नहीं हो सके। इससे सिंधिया कम्पनी को भारी चति उठानी पडी । विधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के हद रहने पर १६२४ में एक सममीता हुला जिसके लानुसार हुने ७५ हजार टन सामान प्रतिवर्ष ले जाने की श्रमुमित दी गई। भारतीय जलयान कम्पनियों के नष्ट हो जाने का एक कारण यह या कि तिदेशी कर्णानयों भी प्रातयागिता शक्ति बहुत पढ़ी-चढ़ी थी श्रोर दूसरा कारण यह या कि भागतीय कम्पनियों के पास वित्त की उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी श्रीर इनका ऊल व्यय भी बहुत ग्रधिक था। थोडे बहुत परि-वर्तन के साथ यह प्रतियोगिता स्वतन्त्रता मिलने तक चलती रही श्रीर स्वतन्त्रता मिलने से भारतीय जल यातायात का भारत के तटीय व्यापार में महत्व बढ गया है क्योर साथ ही तिदेशी व्यापार में भा एक सीमा तक इसने श्रयना विशेष स्थान बना लिया है।
- (२) ब्रिटिश शासनकाल में सरकार ने भारतीय जल यातायात को कुछ भी सहायता नहीं दी श्रीर स्वतन्त्र न्यापार नीति का बहाना लेकर भारतीय उद्योग को टाल दिया गया श्रोर श्रामने लिए स्वय मार्ग बनाने को छोड़ दिया गया। इसका यह परिणाम हश्रा कि इस श्रामधि में भारतीय जल यातायात ने विशेष प्रगति नहीं की। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् भारत सरकार ने इस श्रोर ' स्यान दिया है। भारत सरकार ने जलयान उत्योग को श्रमण तथा श्रन्य श्राधिक

सहायता दी। सरकार ने जलयान निर्माताओं से जिस मूल्य पर जलयान ऋय किए मारतीय जलयान कम्पनी को उससे कम मूल्य पर वेचे आरे श्रन्तर को अपने कोष से दिया। लाइसेन्स की प्रधा लागू करके १९४८ में भारत के तटीय न्यापार पर नियत्रण स्थापित किया गया भ्रीर १६५० में तटीय व्यापार केवल भारतीय जलयानो के लिये सुरिच्चत कर दिया गया। इसके फलस्वरूप मारतीय समुद्र तट पर १६४८ में जितने टना के जलयान व्यापार करते थे उसमें पूर मितशत की वृद्धि हो गई और १९५२-५३ तक व्यापार मे १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक जल यातायात बोर्ड स्थापित किया गया है जिसका कार्य जल यातायात के कार्य का सचालन करना है। सरकार की सहायता प्राप्त करके अब भारतीय कम्पनियाँ विश्व जल यातायात सम्मेलन की सदस्य हैं।

१६४७ में भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा कि तीन जल यातायात कार्पी-रेशन बनाये जायँ, पत्थेक के पास १० करोड़ रुपये की पूँजी हो श्रीर तीनों कार्पीरंशन तीन मार्गी से न्यापार इत्याद करे। परन्तु १६५५ तक मार्च १६५० में १० करोड रुपये की अधिकृत पूँजी का केवल एक कार्पीम्शन, पूर्वी कार्पीरेशन लिमिटेड, स्थापित किया जा सका था। सरकार ने दो करोड रुपये की नियमित पूँजी का केवल है भाग दिया छोर शेष पूँजी मैनेजिंग एजेन्टों ने लगाई। जून १९५६ में दूसरे कार्पोरेशन (पश्चिमी शिविंग कार्पोरेशन) की स्थापना हुई। यह

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ईस्टर्न शिपिंग कार्पीरशन से श्रामामी पूर्य रूप से राज्य के श्राधिकार में है। भीच वर्षों के अन्दर यह आशा की जाती थी कि ४०,००० जी। आर० टी० व्यापार श्रीर श्रविक कर सकेगा। परन्तु वह केवल २१,६०० जी० श्रार० टी० व्यापार प्रथम तीन वर्षों मे वढा पाया । सरकार ने जलयान उद्योग की श्रीर श्रधिक वित्तीय तथा श्रान्य प्रकार की सह यता दी है। इसलिये यह श्राशा करना सर्वया युक्ति सगत होगा कि कुछ समय मे भारतीय जल यातायात उन्नति की चरम सीमा पर

(३) प्रारम्भ में देश-विदेश व्यापार में मारतीय जनयानी ने भी भाग लिया। परन्तु उनमें से अधिकतर छोटे थे ग्रीर अधिकतर सेलिंग वेशिल, टास, पहुँच जायगा। बाग्जेज, कोसर्ट्स इत्यादि थे। अतीत में एक सबसे वही किटनाई यह थी कि देश में जलयान उद्याग नहीं था जिससे जलयाना का व्यय अत्यिषक हो गया था। अत्र विणाखापट्टम् में जलयान कारखाना है। यह जून १६४१ में स्थापित किया गया था। यह आशा को जाती थी कि २,१५,००० जी० आर० टो० में से जो कि प्रथम योजना के प्रथम तीन वर्षों में प्राप्त कर लेना चाहिए या हिन्दुस्तान

शिपयार्ड १ लाख जी० श्रार० टी० की पूर्ति करेगा। परन्तु शिपयार्ड की उन्नति वडी घीमी रही है श्रीर प्रथम तीन वर्षों में वह केवल ३५,८०४ जी० श्रार० टी० ही की पूर्ति करने में समर्थ हो सका है। भारतीय जल यातायात कम्पनियों को विशाखापट्टम् शिपिङ्क यार्ड से श्रिधिकाधिक संख्या में जलयान के पाने की श्राशा भी जा सकती है। इसमे सबसे कठिनाई जलयान के विभिन्न कल-पुजी की प्राप्ति में कठिनाई है जिन्हें विदेशों से मॅगाना पडता है। जैसे ही यह कठिनाई दूर हो जायगी श्रीर शिपयार्ड की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो जायगी, भारतीय जलयानों के टनेज के विस्तार में वास्तविक सहायता पहुँच सकेगी।

(४) भारतीय जल यातायात के विकास में समसे बढ़ी कठिनाई यह है कि हमारे देश में जलयानों को बन्टरगाह की उचित सुविधायें नहीं मिल पाती है। भारत के पाँच बढ़े बन्दरगाहों, क्लक्ता, वम्बई, महास, कच्छ श्रीर विशासापट्टम में पेट्रोल, जलयान में जलानेवाला कोयला इत्यादि को छोडकर केवल दो करोड टन सामान प्रतिवर्ष उतारा लाटा जा सकता है। १६४६-५० में पेट्रोल तथा जलयान में जलने वाले कोयले को सम्मिलित करके इन बन्दरगाहों में दो करोड़ टन सामान लादा उतारा गया। प्रथम योजना के श्रन्तगँत विकास के कारण माल लादने उतारने की शक्ति बढ़ कर दो करोड़ पचास लाख टन हो गई है। वन्दरगाहों पर ययाशक्ति कार्य हो रहा है। जलयानों को बहुत देर तक प्रवीका करनी पहती है। माल डॉक में पड़ा रहता है इसके पूर्व कि लादा जा सके। यह मस्ताव किया गया है कि बन्दरगाह की सुविधाओं का विस्तार किया जाय श्रीर कारहता ग्रीर मगलीर के हो नये चन्दरगाह बनाये जा रहे हैं। बन्दरगाहों पर त्रावर्यक सामान, श्राकाशदीप तथा अन्य सुविधार्थे बढाई ना रही हैं।

पुनर्निर्माण नीति उपसमिति—पुननिर्माण नीति उपसमिति (१६४७) ने भारतीय जल यातायात की पूर्णतया जींच की श्रीर निम्नलिखित विकारिशें की

- (१) मारत को प्रति वर्ष १ करोड़ टन मामान लाने ले जाने के लिये श्रीर ३० लाख यात्रियों का ले जाने के लिये छोटे जलयानी को छोड़कर २० लाख दन के जलयानों की त्रावश्यकता होगी।
- (२) हमारा उद्देश्य है कि १६५७ तक मारत के तटीय व्यापार का १०० प्रतिशत, भारत-वर्मा लका तथा श्रन्य पड़ोसी देश से व्यापार का ७५ प्रतिशत, दूर देशों से मारत के व्यापार का ५० मितशत और धुरी राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले न्यापार का ३० प्रतिशत सॅमाला नाय।
- (३) भारत सरकार की नीति का उद्देश्य भारतीय जल यातायात का प्रसार होना चाहिए श्रीर दरों में कमी श्रीर वृद्धि होने से इसकी रच्चा की जानी

चाहिए। इन उद्देश्यां को पूरा करने के लिए, जल यातायात वोर्ड को पूरे श्रिधिकार देने चाहिए।

पुनर्निर्माण नीति उपसमिति ने जो लक्ष्य निर्धारित किये ये भारतीय जल यातायात का स्तर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। यह निजी उद्योग तथा भारत सरकार के लिए अत्यन्त खेद की बात है। वर्तमान मे भारतीय जल यातायात का टनेज केवल ५ लाख टन है जब कि समिति ने २० लाख टन का सुमाव दिया या। भारतीय जलयान कुल विदेशी व्यापार का केवल ५ प्रतिशत पूरा करते हैं जब कि समिति ने सुमाब दिया था कि भारतीय जलयानों को अपने कुल विदेशी व्यापार का ५० प्रतिशत स्वय करना चाहिये। केवल तटीय व्यापार के सम्बन्ध मे समिति की अभिलाधा पूर्ण हुई है।

मारतीय जल यातायात के प्रसार एवम् सगठन के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये जल यातायात के मालिको की परामर्शदात्री समिति की १६५२ के मध्य में एक बैठक हुई। समिति ने अनेक सुक्ताव दिये। समिति ने सुक्ताव दिया है कि भारत में जलयानों की सख्या बढाई जानी चाहिये परन्तु पचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए जितने घन की व्यवस्था की गई है वह अपर्याप्त है। सरकार को अधिक से अधिक २ प्रतिशत वार्षिक व्याज पर मारतीय जलयान कम्पनियों को ऋण्य देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पूँजी सरलता से चुकाई जा सके। समिति ने यह भी सुक्ताव दिये कि (१) पुराने जलयानों के स्थान पर नये जलयानों को खरीदने के लिए जो लाभाश जमा किया गया है उस पर आय कर न लगाया जाय, (२) भारतीय जलयानों में जलने वाले तेल पर चुङ्की न लगाई जाय और (३) जलयानों का सामान वेचने वाले स्टोरों पर विकी-कर न लगाया जाय।

यह भी मुक्ताव दिया गया है कि तटीय व्यापार करनेवाला जलयान वेड़ा सन्द्रिलित होना चाहिये। इसमें विभिन्न श्राकार प्रकार के जलयान होने चाहिये जो तटीय व्यापार की विशेष वस्तुर्श्वों जैसे नमक, कीयला श्रोर तेल लाने ले जाने के उपयुक्त हों। कुछ लोगों का बिचार है कि नमक श्रीर कीयला ले जाने के लिए ६,००० से ८,००० डी० डब्लू॰ टी० के जलयान श्रविक उपयुक्त होते हैं श्रीर खाद्यान की सामगी इत्यादि का यातायात करने के लिए छोटे श्राकार के जलयानों का प्रयोग किया जा सकता है।

इस समिति ने बताया कि भारतीय वन्दरगाहों में सामान लादने श्रौर उतारने की श्रन्छी न्यवस्था नहीं हैं। विशेषकर कीयला लादने के लिए वर्धों (जलयान खंडे होने का स्थान) का श्रमाव है श्रौर कुछ ट्रटी-फूटी स्थिति में हैं श्रीर उससे कार्य श्रन्छी प्रकार नहीं लिया जा सकता है। समिति ने सुफाव दिया कि बन्दरगाहों में माल लादने श्रीर उतारने इत्यादि का कार्य तीव गित से करने के लिए मर्शानें लगाने की श्रीर वर्तमान सामान को श्रीर बढाने की श्रावश्यकता है।

पंचवर्पीय योजना के अन्तर्गत-प्रथम पचवर्पीय योजना में भारतीय जलयानी की सख्या बढाने पर श्रीर बन्दरगाही हत्यादि की सुविघाएँ बढाने पर जोर दिया गया था। योजना में कहा गया था कि तटीय व्यापार में जो पुराने श्रीर विसे-19टे जलयान प्रयुक्त किये जा रहे हैं जलयान कम्पनियों को उन्हें बदलने में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशाखापटनम में जलयानी के निर्माण हेत रुपया लगाया है। श्राशा की जाती है कि पचवर्षाय योजनाकाल में ही विशाखापट्टम के कारखाने में कुल १ लाख जी० श्रार० टो० के जलयान प्राप्त किये जा सकेंगे। इनमें से ६० इजार जी० छार० टी० के जलयानों से पुराने धिस-पिटे जलयानां को बदला जायगा ग्राप शेष जलयान विशेष पर तटीय व्यापार में प्रयुक्त किये जायंगे। विशाखापटनम कारपाने ने जलयान कम्पनियों के हाथ जलयान उचित मृल्यों पर वेचे जायेंगे । याट निर्माण व्यय मे स्रोर विकी मूल्य मे कुछ प्रन्तर रहेगा ता उसके लिए सरमार जलयान निर्माण उद्योग को श्रार्थिक सहायता देगी। इस प्रकार जलयान निमाण कार्य का प्रसार करने का विशाखा-पटनम कारसाने के विकास से गहरा सम्बन्ध है जिससे विशासापटनम की उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जा सके। योजना ने अनुसार तटीय व्यापार की सुरिज्ञत बनाए रखने के लिए कम से कम ३ लाख जी० श्रार० टी० के जलयानों का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि पाँच वर्ष के श्रन्टर भाग्तीय जलयान कम्पनियों को ४ करोड़ रुपया ऋगा दिया जायगा ग्रीर जलयान कम्पनियाँ अपने साधनों से शेप २ करोड़ कपया एकत्रित करेंगी। अनुमान था कि इस ६ करोड़ रुपये से भारतीय जलयान कम्पनियों के पास पर्याप्त जलयान हो जायँग। पचवर्षीय योजना के ब्रान्तर्गत चिदेशी व्यापार के लिए १,००,००० ही । हव्लू । टी । के जलयाना की श्रोर श्रावश्यकता समसी गई थी जिसमें ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन के लिए श्रावश्यक ६० ६ जार डी० डब्लू० टी० के जलयानी वो सम्मिलत नहीं किया गया था जिसके लिए सरकार ने अपने भाग के ४४ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी।

मथम योजना में १६५५-५६ तक ६ लाख जी० आर० टी० तक जलयानी के बहाने का विचार किया गया था। पर वास्तव में योजना काल के अन्त तक दुल ४,८०,००० जी० आर० टी० का कार्य किया जा सका। जो ध्येय ६,००,००० जी श्रार टी का सोचा गया या वह तो तभी पूरा हो सका जब कि योजना काल मे ही मंगाये हुये नहाज प्राप्त हो सके ।

जल यातायात उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रथम योजना के श्रन्तर्गत व्यवस्था की गई है उसकी लोगों ने निम्न श्रालोचना की है (१) सन् १६५६ तक =,00,000 जी० आर० टी० के जलयानों की वृद्धि पुनिनर्माण नीति-उपसमिति की उफारिश की तुलना में बहुत कम है। अमिति ने तिफारिश की थी कि १६५- तक ¿o लाख टन के जलयान हो जाने चाहिए परन्तु इस काथ में अनेक कांटनाहयो का सामना करना पढ़ा है। वित्त के साथ ही आवश्यक सामान का ग्रामाव है क्रोर ब्यवहारिक दृष्टि से पचवर्णीय योजना समिति के कार्यक्रम को ग्रपना लक्ष्य नहीं बना सकती थी। योजना में ज्यावहारिक हिन्टकी ए के श्राघार पर लक्ष निर्घारित किये हैं। (२) मारतीय जलयान समिति ने सुमाब दिया है कि सरकार तटीय एवम् विदेशी व्यापार में जो रुपया ब्यय करेगी वह जलयाना ग्रीर भ्रम्य सामान के बढ़े हुए मूल्यों का देखते हुए बहुत कम है। पचवर्षीय योजना में जो लक्य निर्वारित किया गया है उसको पूरा करने में मा कही अधिक रुपया लगेगा, (३) सरकार ऋष दी गई पूँचा पर फितना ब्याज वसल रही है श्रोर ऋष के साय जो शर्ते लगी हैं उनसे ऋग तेना उद्योग के लिए ग्रसुविचाजनक हो गया है। उद्योग को यह ऋग भहगा पड़ता है। यह सुक्ताव दिया गया है कि सरकार को २० वर्ष के लिए ऋण देना चाहिए और पहले ५ वर्षों मे उस पर कुछ व्याज नहीं लेना चाहिए। छठे वर्ष से ३ प्रतिशत वार्षिक ब्याज वस्त किया जा सकता है और इसी समय से ऋग ली गई पूँजी भी किश्तों में चुकानी आरम्भ हो जायगी, (४) योजना की अन्य सुविधाओं की कुछ चर्चा नहीं की गई है, जैसे जलयान मे जलने वाले तेल पर से चुक्की हटाना, जलगान सामान के स्टोर पर से विकी-कर इटाना श्रीर श्राय-कर पर रियायत देना । जल यातायात उद्याग ने इन सुविधाश्री की माँग की है। इनके विना भारतीय जल यातायात की तेजी मे प्रगति नहीं की जा सकती है।

हितीय योजना मे यह प्रस्ताव किया गया है कि ६० हजार जी० छार० टी० के विसे-पिटे जलयानों को निकाल कर ३० लाख जी० श्रार० टी० के जल-यानों की वृद्धि की जाय। इस प्रकार दूसरी योजना के श्रन्त तक कुल टनेज ६ लाख जी शार । टी हो जाना चाहिए। योजना का व्यय है (१) तटीय न्यापार की श्रावश्यकताश्रों को रेलवे द्वारा प्राप्त माल श्रोर यात्रियों की मात्रा को ध्यान मे रखते हुए पूर्ण करना, (२) मारत के विदेशी व्यापार का श्रधिक से श्रधिक भाग भारतीय जलयानों के लिए प्राप्त करना, (३) टैकों का बेड़ा तैय्यार करने के लिए केन्द्र स्थापित करना।

नीचे लिखे निश्चित ध्येय को पूरा कर लेने के पश्चात् भारत का १२ से १५ प्रतिशत समुद्रपार देशों से न्यापार और श्रास-पास के देशों से न्यापार का ५०% भारतीय जलयानों के भाग में श्रा जायगा जब कि वर्तमान में इन न्यापारों का केवल ५ ग्रीर ४० प्रतिशत उनके भाग में हैं।

जी० ग्रार० टी॰

	योजना के पहले	प्रथम योजना के श्रन्त में		द्वितीय योजना के श्रन्त में
तटीय ग्रीर निकटस्य	२१ ७२०२	३१२२०२		४१२२००
समुद्र पार	१७३५०५	र ८३५ ०५		४०५५०५
ट्रेम्प			1	६००००
टैन्कर्स		५०००	1	२३०००
सेलवेज टग				१०००
कुल	७०७०७	६००७०७		७०७ १० <i>3</i>

प्रथम योजना में १६ ५ करोड व्यया जल यातायात के लिये नियत किया गया था। बाद में यह धन बढ़ा कर २६ ३ करोड व्यया कर दिया गया। योजना काल में वास्तिवक व्यय १८ ७१ करोड़ व्यये किया गया। द्वितीय योजना में जल यातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ व्यथों के व्यवस्था की गई है। जल यातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ व्ययों के व्यवस्था यद्याप की गई है फिर भी क्योंकि पिछली योजना का ८ करोड़ व्यथा के लिये प्राप्त होगा।

योजना श्रायोग के द्वितीय पचवर्षीय योजना के कार्यो तथा यानी सफलता के मत के श्रनुसार (मई १६५८) जितने ज्यय की द्वितीय योजना में ज्यवस्था की गई है उसका ज्यय तो हो ही जुका है श्रीर उसके फलस्वरूप जो जल यातायात का कार्य होगा (टनेज मिलेगा) वह लगमग १८०००० जी० श्रार० टी० होगा जबकि योजना का ध्येय ३६०,००० जी० श्रार० टी० टनेज प्राप्त करने का था, जिसमें ६०००० जी० श्रार० टी० टनेज पुराने जहाजों के स्थान पर नये प्रयोग में ले श्राने के कारण प्राप्त होने वाला था। श्रापने व्येय को पूरा कर सकने के खिये लगमग ४५ करोड़ रायों की श्रोर श्रावश्यकता होगी।

वन्दरगाह-प्रथम योजना की रूपरेखा जब उपस्थित की गई थी उसमें वन्दरगाहों के विकास अथवा सुधार का कोई स्थान नहीं था। इस अभाव की पूर्ति की महत्ता समक्ती गई ग्रीर जब योजना की संशोधित रूपरेखा बनाई गई तो उसमें ३३ करोड़ रूपयों की ज्यवस्था की गई थी। बाद में यह मात्रा वढा कर ३६ १९ करोड़ कर दी गई थी। चूंकि बन्दरगाहों के सुवार का कार्यक्रम देर से श्चारम्म हुआ, इसलिये योजना-काल में व्यय की मात्रा केवल २७ ५७ करोड़ क्पयों की हो पाई । कुछ भी हो यह विकास कार्यक्रम जो आरम्भ किया गया बडे महस्त का था। काणडला के नये बन्दरगाह के बनवाने के प्रातिरिक्त जिस पर (२०१ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जा चुकी थी, इस कार्यक्रम के श्रन्तर्गत मुख्य योजनाएँ बम्बई श्रीर कलकत्ता में थी जिनके लिये योजना में ११ तथा द करोड़ इपयो की व्यवस्था क्रमशः की गर्ड थी। योजना के श्रन्त तक काराहला पर ५५ करोड़ रुपये वम्बई पर ११ करोड़, श्रीर कलकत्ता पर ३'५ करोड़ रुपये व्यव किये बा चुके थे।

"मुख्य मुख्य बन्द्रगाहों की चुमता प्रथम योजना काल में २०० करोड टन से बढ़ कर २५० करोड़ टन हो गई। १६५०-५१ में कुल माल जो इन मुख्य बन्दरगाहों द्वारा उतारा श्रमवा चढाया गया १८० २ कराइ टन या जिसमें ११२ थ करोड़ उन आयात का माल श्रीर ६७७ करोड़ उन निर्यात का माल समितित था। १६५५.५६ में अनुमान है कि उतारे और चढाये जाने वाले कुल माल की मात्रा २२० करोड़ टन थी निसमें १३० कराड़ टन श्रायात श्रीर ६० टन निर्यात

, ना । लगमग २२६ छोटे-छोटे बन्दरगाह २६०० मील के तट पर फैले हुये हैं जिनमें १५० बन्दरगाहों से माल आता-जाता है। १९५१-५२ में इन बन्दरगाहों का माल था।" द्वारा ३७६ करोड़ टन माल उठाया गया, श्रीर १६५४ तक यह माला वढ कर ४१ प् करोड़ टन हो गई । प्रथम योजना में इन छोटे-छोटे बन्दरगाहों के विकास कार्यक्रम में मद्रास, सौराष्ट्र, बम्बई, उद्दीसा आदि मुख्य स्पान समिलित किये गये थे। कुल व्यय जो किया गया था वह २ कराइ रुग्यों से कुछ ही कम था।

द्वितीय योजना का साधारण ध्येय है कि प्रथम योजना में जो कार्य आरम्भ किया जा चुका है उसे पूर्णं कर दिया जाय और सर्व सुविचार्त्रों का प्रमन्त करके टॉकों को श्राधुनिक रूप प्रदान कर दिया जाय ताकि देश के श्राधिक श्रीर ग्रीद्योगिक विकास के कारण जो श्रावश्यकतार्य हो पूर्ण की जा सर्के । ४० करोड़ क्पये की व्यवस्था बहे-बडे बन्द्रगाहों के सुवार कार्य कम के लिये की जा चुकी है। जो निर्माण कार्य श्रारम्म किये जार्येगे, जिनमें प्रथम योजना के श्रवूरे कार्यो को पूर्ण करने का कार्य मी सम्मिलित होगा, उनमें लगभग ७६ करोड रुपया व्यय होगा। योजना में व्यवस्थित ४० करोड रुपये के श्रांतिरिक कुछ धन वन्दर-गाहों के श्रपने निजी कोषों से भी प्राप्त होगा। योजना में निर्धारित धन सरकार की श्रोर से कारहला में लगाया जायगा श्रीर पोर्ट ट्रस्ट की सहायता ने लिये दिया जायगा। वर्तमान रियायती श्रुण की पोर्ट ट्रस्ट के लिये सुविधा दूसरी योजना काल में भी रहेगी। द्वितीय पचवर्षीय योजना के बड़े-बड़े बन्दरगाहों के सुधार के नार्यक्रम में कलकत्ते मे १६६ करोड रुपया व्यय किये जाने वाली, बम्बई में २६ ३ करोड रुपया व्यय किये जाने वाली, कोचीन में ४० करोड रुपया व्यय किये जाने वाली, योजनाएँ हैं।

मारत में लगभग १५० छोटे वन्दरगाह हैं जिनमें से १८ विशेष महत्व के हैं। उनका सुघार श्रत्यन्त श्रावश्यक है। प्रथम योजना में छोटे छोटे बन्दरगाहों के सुघार की योजनाएँ सम्मिलित की गई थीं जिनमा कुल व्यय २४१ करोड रुपया नियत था, इसमें से १ करोड केन्द्रीय कीय से प्राप्त होना था श्रीर शेष वन्दरगाहों के कर्मचारियों को श्रपनी श्रीर से एकत्रित करना था। द्वितीय योजना में छोटें-छोटे बन्दरगाहों के सुधार के लिए ५ करोड रुपया नियत किया गया है।

अध्याय ३७

हवाई यातायात

वर्तमान युग में देश के श्रीद्योगिक,श्राधिक ग्रीर श्रन्य कार्यों का मूलाघार 'गति' है श्रीर यातायात के मूलाधार हैं यात्रियों एवम् सामान का तीव्र गति से यातायात कर सकने वाले साघन । भारत जैसे विशाल देश में इवाई यातायात का विशेष महत्व है। विमानों द्वारा यात्रा करने से समय की बहुत बचत होती है, अनेक असुविधाओं से बचा जा सकता है, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य लोग बड़ी कुशलता से कार्य कर सकते हैं, ग्रंपने कारखानों से सम्पर्क रख सकते हैं, दुर-दूर स्थित कार्यालयों से सम्बन्ध वना रह सकता है श्रीर नियत्रण के साथ ही साथ उनका श्रव्छी प्रकार निरीक्षण किया जा सकता है। सकटकाल में, बाढ श्रयवा भूकम्प के समय हवाई यातायात का महत्व श्रीर भी श्रविक हो जाता है। इसके श्रातिरिक्त शातिकाल में नागरिक उड्डयन के कर्मचारी जो श्रनुभव प्राप्त करते हैं उसका युद्ध के समय सहुपयोग किया जा सकता है। दितीय विश्वयुद्ध के समय और देश विभाजन के पश्चात् भारत की हवाई कम्पनियों ने यात्रियों तथा सामान का यातायात करने में, निरीक्तण करने में श्रीर सरकार के निर्देश पर शरणाथियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में प्रशसनीय कार्य किया। हवाई यातायात का यथासभव विकास करने की अत्यन्त आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं।

विकास—यह खेद का विषय है कि भारत में हवाई यातायात अभी अपनी प्राश्मिक अवस्था मे है। यद्यपि भारत में १६११ से ही विमानों का उपयोग आरम्म हो गया था और प्रथम विश्वयुद्ध के समय इस दिशा में कुछ प्रगति मी की गई थी परन्तु भारतीय इवाई यातायात में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और उसके पश्चात् ही विशेष प्रगति की जा सकी। भारत के हवाई यातायात के विकास में कुछ उल्लेखनीय बात हुई हैं: (१) १६२७ में नागरिक उड्डयन विभाग स्थापित किया गया और १६२८ में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और करॉची में 'फ्लाइग क्लब' खोले गये। विमान-चालको और टेकनीशियनों के शिच्चण की व्यवस्था की गई और इम्पीरियल एयरवेज सर्विस का १६२६ में दिल्ली तक प्रसार करने का प्रबन्ध किया गया। मारत में हवाई यातायात के विकास का यही प्रारमजाल था, (२) १६३२ में टाटा एयरवेज लिमिटेड ने इलाहाबाद,

कलकत्ता और कोलम्बों के मध्य इवाई यातायात आरम किया श्रीर तत्पश्चात् कराँची श्रीर मद्रास तक इसका प्रसार कर दिया । देश के कुछ मार्गों पर इण्डियन नेशनल एयरवेन ने भी यातायात कार्य शुरू कर दिया, (३) १६३८ में एम्पायर एयरमेल योजना लागू की गई जो युद्ध प्रारम्म होने पर स्पगित कर दी गई परन्तु तत्मश्वात बहत सीमत पैमाने पर इसे फिर लागू किया गया; (४) १६४६ में कुछ सुमगठित विश्वासनीय निजी व्यवसायिक सस्पात्रों को त्रावश्यक सरकारी सहायता देकर देश के अन्दर तथा विदेश से इवाई यातायात की सुविधा का विकास एवम् प्रधार करने को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक निश्चित उद्भयन नीति निर्धारित की । १६४६ में इवाई यातायात लाइसेंसिंग बोर्ड स्थापित किया गया । यह निश्चित किया गया कि लाइसैन्स देते समय बोर्ड इन बालों पर पर विचार करेगा (अ) कम्पनी की विच स्पिति, (व) कार्यक्रमता का उचित स्तर, (थ) यातायात की मांग स्रोर (द) बनता की श्रावश्यकता के श्रनुकृत कम्पनी की इवाई यातायात का विकास कर सकने की समता । वार्ड को लाइसेन्स-प्राप्त कर्म्पानयों के किराये तथा भाढे की अधिकतम तथा न्यूनतम दर निर्घारित करने का अधिकार दिया गया। बोर्ड ने अपने कार्यकाल में अनेक कम्पनियों को लाइसेन्स दिये। इसका परिखाम यह हुआ कि हवाई यातायात में बहुत सी कम्पनियाँ चाल हो जाने से नटिलत। या गई श्रोर इनमें परस्पर हानिकारक प्रतियोगिता चलने लगी। इससे कम्पनियों को इति भी उठानी पदी, (५) मारत सरकार ने टाटा के सहयोग से विदेशी हवाई यातायात के लिए एयर इशिडया इन्टरनेशनल की स्थापना की। टाटा के साथ यह समसीता किया गया कि इस नई कम्पनी में ४९ प्रतिशत शेयर सरकार लेगी जो ५१ प्रतिशत तक बढाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ५ वर्ष तक यदि वाटा हुआ तो इस घाटे को भी सरकार पूर्ण करेगी।

हवाई यातायात जॉच सिमिति (१९४२)—हवाई यातायात जाँच सिमिति
ने, जो राजाय्यस्न कमेटी के नाम से श्रिषक श्रीसद्द है, भारतीय हवाई कम्पनियों
की स्थिति और उनकी समस्याश्रों की पूर्य जाँच की और इस परियाम पर पहुँची
कि इवाई यातायात लाइसेन्सिय बोर्ड ने अपना कार्य सन्तोष-जनक रीति से नदीं
किया और बिना किसी प्रकार का मेद किये कम्पनियों को लाइसेन्स दिये, जिसका
परियाम यह हुआ कि दो वर्ष के अन्दर ११ कम्पनियों को लाइन्सेस मिल गये
जब कि सपूर्य कार्य केवल चार कम्पनियाँ अच्छी प्रकार चला सकती थीं। इतनी
अप्रिक कम्पनियाँ होने से उन्हें हानि उठानी पढ़ी, इसके साथ ही हवाई कम्पनियों
ने सत्कता से कार्य नहीं किया और कम्पनी के सङ्गठन इत्यादि में बहुत श्रीषक

रुपया न्यय किया जब कि यातायात की स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं या। कम्पनियों का उत्पादन न्यय भी पेट्रोल के मूल्य १ रुपया १४ स्थाना प्रति गैलन (१९४६) से बढकर १९४६ में २ रुपया ६ स्थाना प्रति गैलन हो जाने से, बढ गया।

या कि इवाई कर्म्यानयों के राष्ट्रीयकरण के पन्न में नहीं थी। समिति का मत या कि इवाई यातायात के चेत्र में समय के अनुकूल परिवर्तनशील नी।त की और साहस-पूर्वक नयी योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता है परन्तु यदि इवाई कम्यनियों को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी तो इसकी समावना कम हो जायगी। इस कारण समिति ने सिफारिश की कि वर्तमान कम्यनियों का चार कम्यनियों में एकीकरण किया जाय और बम्बई, क्लकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में उनके अद्भुं स्थापित हों। इससे हानिकारक प्रतियोगिता कम हो जायगी और कम्यनियों में कार्य का वितरण भी वैज्ञानिक तथा चेत्रीय आधार पर किया जा सकेगा। सिमित ने सुकाब दिया कि उड़ान के घरटों में कमी करने के लिए वर्तमान कम्यनियों की मार्गों को निर्धारित कर दिया जाय, विमानों की सख्या घटा दी जाय, अतिरिक्त कमेचारियों की छटनी की जाय, और इवाई यातायात के सचालन-व्यय, उचित लाभाश और विमानों का प्रयोग करनेवाले यात्रियों की स्थालन व्यय शक्ति पर विचार करके किराये तथा माडे की दर में वृद्धि की जाय। समिति ने सिफारिश की कि स्टैन्डर्ड-व्यय के आधार पर इवाई कम्पनियों को सरकार आर्थिक सहायता दे।

राष्ट्रीयकर ग्रा—हवाई कपनियाँ स्वेच्छा से एकीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं हुई जैसी कि हवाई यातायात जाँच समिति को आशा थी। हवाई यातायात में अव्यवस्था के कारण कम्पनियों की भारी ज्ञति उठानी पड़ी और उनकी स्थिति हाँवाडोल होने लगी। यद्यपि जाँच समिति ने राष्ट्रीयकरण के विषद अपनी राय प्रकट की थी परन्तु हवाई कम्पनियों की विगन्नती दशा को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय करण करने का निश्चय किया। यह तर्क किया गया कि (१) राष्ट्रीयकरण हो जाने से उन्नान में जो समय व्यर्थ नष्ट होता है वह कम हो जायगा, एक ही कार्य अनेक वार नहीं करना पढ़ेगा और हानि भी कम हो जायगी, (२) राष्ट्रीयकरण से समुक्त प्रवन्य होने से हवाई यातायात की कार्यज्ञसता बढ़ेगी और (३) नागरिक उहुयन का अच्छा सङ्गठन किया जा सकेगा जिससे यह जैसे सकट काल में विमान चालकों, टेकनीशियनों हत्यादि के अभाव का सामना नहीं करना पढ़ेगा।

हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये ससद ने १६५३ का हवाई यातायात कार्पोरेशन कानून पास किया है जिसके अन्तर्गत १ अगस्त १६५३ को दो कार्पोरेशन स्थापित किये गये जिनमें से एक देश के अन्दर के हवाई यातायात श्रीर दूसरा विदेशी यातायात सर्विसों का प्रमन्ध करेगा। मुश्रावजे के सम्बन्ध में बहुत विवाद चला। यह कहा गया कि मुश्रावजा मूल मूल्य में से टूट-फूट का ज्यय घटाकर नहीं वरन् विमानों, विमान के श्रातिरिक्त कल-पुजों इत्यादि के वर्तमान साजार-भाव के श्राधार पर दिया जाय। श्रानुमान था कि मुश्रावजे के वर्तमान श्राधार पर देकोटा विमान लगभग ५०,००० रुपये में लिया जा सकता है जम कि उसका बाजार-भाव तीन लाख रुपया है, श्रीर स्काई मास्टर विमान ४ से ६ लाख रुपये में लिया जा सकता है जबिक बाजार में उसकी वर्तमान कीमत ३० लाख रुपया है। कानून में 'गुड़बिल' के लिए, कपनियों द्वारा कर्मचारियों की शिक्ता में श्रीर नवीन मार्ग पोलन इत्यादि में ज्या किए गए वन का उचित मुश्रावजा देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। परन्तु यिह इन सब के लिए मुश्रावजा दिया जाय तो व्यय बहुत बढ जायगा श्रीर राष्ट्रीयकरण से हवाई यातायात में सुधार करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सक्गा। साथ ही राष्ट्रीयकरण से उस घाटे की पूर्ति नहीं की जा सकेगी जिससे वर्तमान कपनियों पीइत हैं।

मुद्रावजे की समस्या १६५५ में ६०१ करोड़ रुपया देकर सदा के लिये निश्चित कर दी गई। जहाँ तक राष्ट्रीयकरण के पिग्णामस्वरूप वेकारी का प्रश्न था, यह निश्चित कर लिया गया कि वे सब कमेंचारी जो ३० जून १६५२ के पूर्व कम्यानयों द्वारा नियुक्त किये गये ये उनकी बदली कारपोरेशन में कर दी गई श्रीर इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है कि कमेंचारियों को पुर्नव्यवस्था श्रोर विस्तार के कार्य-कम में लपा लिया जान।

वर्तमान स्थिति—१६५३ के श्रारम्भ में भारत में ६ इवाई कपनियाँ थीं जिनके पास २१६ कराइ रुपये की ग्राधकृत पूँजी श्रीर टूट-फूट के कोष में ३ करोड़ रुपये से कुछ कम थे। इन कम्पनियों के निमान कुल २८,००० मील के चेत्र में चलते थे। जून १६५२ के अन्त तक भारत में ६७७ रजिस्टर्ड विमान थे, जिनमें २०३ विमानों को याग्यता के प्रमाण-पत्र दिये जा चुके थे। इवाई श्रद्धों पर कार्य करने वाले लाइसेन्स-प्राप्त विमान चालकों की संख्या ५५७ यी तथा ए लाइसेन्स प्राप्त चालकों की संख्या ५६२, ए-१ के लाइसेंस-प्राप्त विमान चालकों की संख्या ४२६ यी। इसमें पहले वर्ष की तुलना में इज्जीनियरों तथा 'ए' लाइसेन्स-प्राप्त विमान चालकों की संख्या ४२६ यी। इसमें पहले संख्या में वृद्धि हुई परन्तु ए--१ चालकों श्रीर बी. लाइसेन्स प्राप्त चालकों की संख्या घट।।

रहपर श्रीर ५३ में इवाई यात्रा की स्थिति में श्रवनति होती रही श्रीर यात्रियोंकी सख्या श्रीर यातायात के माल की मात्रा में कमी श्राई जिसके कारण रहप ३ में यात्रियों की सख्या घटकर ४०४ लाख श्रीर ढुलाई के माल की मात्रा घट कर प्र' प्र लाख पौड हो गई जबिक यह सख्या १९५२ में कमशः ४'३ लाख एव प्र-६'०४ लाख पौंड थी। इसका कारण कुछ तो जनता के पास धन की कमी श्रीर कुछ भारतीय हवाई सर्विस की दुर्व्यवस्था थी। यद्यपि ढाक की मात्रा १९५२ में बढकर प्र लाख पौंड श्रीर १९५३ में प्र लाख पौंड हो गई फिर मी यात्रियों श्रीर यातायात के माल की कमी का घाटा इससे पूर्ण न हो सका।

भारत में इवाई कम्पनियों के कार्य के असतीषजनक होने के अनेक कारण हैं: (१) इवाई कम्पनियों के कार्य-सचालन का न्यय बहुत श्रिषक है। इसमें विमानों में प्रयुक्त होनेवाले पेट्रोल श्रीर विमानों की देख-रेख इत्यादि का व्यय सम्मिलित है। कुल सचालन व्यय का ५० प्रतिशत पेट्रोल, विमान के कल-पुर्जी श्रीर स्टोर में व्यय होता है स्रोर ४० प्रतिशत पारिश्रमिक तथा वेतन में । अम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पारिश्रमिक श्रीर वेतन अविक निर्घारित किये गये हैं झौर पेट्रोल, स्टोर इत्यादि के व्यय में वृद्धि हवाई कम्पनियों की शक्ति के बाहर है। सचालन व्यय श्रधिक होने का एक कारण तो सरकार की नीति का दोप है श्रीर कुछ दोष उन परिस्थितियों का है जिन पर हवाई कपनियों का कोई नियत्रण नहीं श्रीर इसके लिए कम्पनियों को दोषी मी नहीं ठहराया जा सकता है. (२) इवाई कम्पनियों की सख्या यातायात की देखते हुए आवश्यकता से अधिक है, इस कारण किसी भी कम्पनी की पर्याप्त कार्य नहीं प्राप्त होता। इस दोष के लिए हवाई यातायात लाइसेन्सिंग बोर्ड उत्तरदायी है। बोर्ड ने अनेक कम्पनियों को उद्योग चालु करने की श्रानुमति दी श्रीर श्रावश्यकता का ध्यान रखे विना विमानो की सख्या बढाने दी, (३) कम्पनियों की कार्यज्ञमता को देखते हुए कार्य पर्याप्त नहीं है परन्तु यह व्यवसाय ऐसा है जिसमे कुछ विमान चालको, इझीनियरों और टेकनीशियनों को नियुक्त करना पडता है। इसके फलस्वरूप कम्पनियों को श्रावश्यकता से श्रधिक कर्मचारियों का भार वहन करना पड़ता है, (४) किराये ऋोर माडे की जो न्यूनतम श्रीर अधिकतम दरें सरकार ने निश्चित कर दी हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। प्रति यात्री से प्रत्येक मील के लिए अधिक से म्रिधिक ४ म्राना किराया वस्त्ल किया जा सकता है परन्तु रात मे चलनेवाली डाक सर्विस के लिए किराये की दर २६ आना प्रति मील है⁵। यह किराया भार-तीर्य वायुयान कम्पनी के व्यय से बहुत कम है। यदि एकं विमान पूर्ण वर्ष में १५०० घरटे चलाया जाय तो प्रति घरटे का स्टेन्डर्ड न्यय ५८६ रुपया होता है। इसिलिए प्रत्येक सीट का प्रति मील का किराया निमान की ७ प्रतिशत जगह भरने

तालिका नं० १ ऋतुसुचित भारतीय दृवाई सेवाया के ऋकड़े

	0.4		1 77177177	
चर्प	यात्रा गीलो ग (रस- लारा गे)	यानियो की समया	गातायात मारा पी माना (टग साना पी॰ मे)	हार की गापा (द्ध लाग पीड में)
रेष्ट्र४६	8 74	\$ 07 54 4	the same backers	£0.1
१६४७	१ ३६	२५४८६०	યુ પૂ	\$*Yo
\$EX=	१२६५	₹v++EE	₹1 €5	१ ४८
3435	१५.६०	34 0 8\$4	, देश पूर्	५ ५०३
१९५०	85 €0	४५२८६६	, =0 + t	· ======
१९५१	8E NO	ANE LES	८, ६६	. ot=
१९ ५२	१६ ५६	 	₹:.0 ¥	दःइद
१९५३	\$6.50	£33508	E/ E7	ביביו
\$E4x	15.20	४३१४६ ५	, EE.A\$	10 50
ે १ દપ્રપ્	२१ २७	YEEOOO	₹ = ₹0	११४५
१९५६	२३.४८	445000	६६ २३	१२.६६
१६५७	45.3X	4EX000	Z4,0E	YSEK

के श्राधार पर ४३ श्रामा होना चाहिए । चूँ।क किराया यम है इसलिए इवाई कम्पनियों को हानि होना स्वामाविक ही है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् हवाई सेवाजो की स्थित में घटत मुधार हुजा है। उड़ने का विस्तार १९५४ को १९८ फरोड़ मी० से बहुकर १९५७ में २३३४ फरोड़ मील हो गया। मेल तथा यात्रियों की सख्या भी बढ़ी है। मेल की मात्रा १९५४ में १०६७ करोड़ पींड थी जो कि १९५७ में बढ़ कर १२९४ करोड़ पींड हो गई ख़ीर यात्रियों की सख्या जो कि १९५४ में ४३१५६५ थी बढ़ कर १२५७ में

प्रह्म अर्थ । लादने वाले माल की मात्रा १६५६ में १६२३ करोड़ पौंड थी जो कि १६५७ में थोड़ा घट गई और ५५०६ करोड़ पौंड हो गई। इस उन्नित का अशतः कारण आपसी विनाशकारी प्रतिद्वन्द्वता का समाप्त हो जाना तथा कुशलता संगठन रहा है जो कि कारपोरेशन की व्यवस्था के कारण समव हो सका है, और अशतः श्रीद्योगिक और आधिक विकाश रहा है जिसके कारण हवाई सेवाओं की अधिक माँग की गई हैं।

टोनों एयर कारपोरेशनो ने बहुत ही सन्तोपननक उन्नित की है। उन्होंने कार्य-चेत्र यहाया है और जनता का बहुत सी सुविधार्य प्रदान की हैं। "ये कारपोशन अपनी वायुयान सबन्धी कायों के एकीकरण तथा उनक कुशल सगठन में व्यस्त रहे हैं। हांग्डयन एम्रद लाइन्स अपने ६३ हवाई जहांनो, ६७ डकोटा, १२ वाहिका, ६ स्काई मास्टर और ८ हेरीन्स के द्वारा देश के प्रमुख वेन्द्रों को सम्बन्धित करते हैं और उसके हवाई मागो का विस्तार १६,६८५ मील है। दि एयर इण्डिया इन्टरनेशनल अपने वायुयानों द्वारा जिसमें ५ सुपर कान्सटेलेशनस और १ डकोटा है १५ देशों तक अपने कायों को प्रसारित किये हुये हैं। उसके हवाई मार्ग का विस्तार २३,४८३ मील है।"

इिषड्यन एग्रर लाइन्स कारपोरेशन का कुल कार्य-चेत्र तीन मागो में विमाजित कर दिया गया है। प्रत्येक माग एक मैनेजर के श्रिष्ठकार में है श्रीर वम्बई, कलकत्ता श्रीर देहली के किसी न किसी श्राइ है से नियत्रित होगा। श्राई • ए० सी० को निरन्तर घाटा हो रहा है। १६५४-५५ में इस घाटे की रकम ६०१५ लाख रुपया, १६५५-५७ में ११६ ४० लाख रु० श्रीर १६५६-५७ में १०८ ७६ रुपया थी। परन्तु इसके विपरीत एयर इन्डिया इन्टरनेशनल को निरन्तर लाम होता रहा है। श्राई • ए० सी० के घाटे का कारण श्रश्चतः कर्मचारियों को श्रत्यिक सख्या का होना है तथा श्रश्चतः सेवा की श्रत्यिक लागत श्रीर वे किटिनाइयाँ है, जो इसे उन प्राइवेट कम्पनियों से मिली थी जिन्हें इसने ले लिया था।

ह्वाई साड़ा—श्रपनी श्रायिक स्थिति को सुधारने के लिये तथा हानि बचाने के लिये ए० श्राई० सी० ने श्रपने माडे की दर में वृद्धि की घोषणा १५ जून, १६५८ से एश्रर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल की सलाह के श्रनुसार की। किसी-किसी मार्ग के माडे में वृद्धि १०% हुई है श्रीर श्रव बम्बई से कलकत्ते का किराया बनाय २२० र० के २४२ र० हो गया है। इस माडे की वृद्धि से ए० श्राई० सी० को २० लाख रपये वार्षिक श्रातिरिक्त श्राय होगी। इससे हवाई सेवा पर लगाये टेक्स के कारण तथा पेट्रोल पर लगाये टेक्स तथा श्रन्य टेक्सों के कारण इवाई सेवा की लागत में वृद्धि का प्रभाव घटाया जा सकेगा—

ए० ग्राई० सी० के लिये एग्रर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल ने हवाई माडे में वृद्धि की सिपारिश की श्रीर निम्न दरों का सुकाव दिया .

भील		प्रति मील प्रति यात्री माडा
		श्राना पाई में
१ से ३० तक		०—६ — ६
३१ से १०० तम	•	0-4-0
१०१ से २०० तक		3-8-0
२०१ से ५०० तक		•—¥—ξ
५०१ से ६०० तक	•	o—४—३
६०० से ऊपर		o

काउन्सिल की सिफारिश का श्राधार—"श्रार्थिक दृष्टिकोण से श्राधिकतम सख्या में यात्रियों को श्रिषिक काम में श्राने वाले मागो की सेवा का प्रयोग करने का प्रोत्साहन देना था ताकि कम प्रयोग में लाये जाने वाले मागो से होने वाले घाटे के कारण जो सेवा की लागत श्रीर ग्राय में श्रन्तर होता था वह न रहे श्रीर हवाई यात्रा के लामों के कारण लोगों के मन में हवाई यात्रा करने की इच्छा स्थायी रूप से उत्पन्न हो जाय।" श्रिषिक श्रच्छा होता यदि सरकार टेन्सों की मात्रा कम करके उनकी सहायता करती श्रीर कारपोरेशन श्रपना खर्च कम करने का प्रयत्न करते। हवाई यात्रा के माढे के बढ जाने से उसकी सर्विप्रयता के घट जाने का मय है। एयर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल की श्रत्यसख्यक रिपोर्ट ने भी यह सकेत किया है कि, "मारत में हवाई यात्रा की ऊँची दरों के कारण हवाई यात्रा के प्रति श्राकर्पण के नष्ट होने का मय है श्रीर इस बात की श्राशका है कि लोग बहुत बडी मात्रा में हवाई जहाजों द्वारा यात्रा के स्थान पर रेल द्वारा यात्रा करना श्रिक पसन्द करने लगेंगे।"

योजना के अन्तर्गत—प्रथम योजना के अन्तर्गत वायुयान कारपोरेशन के निमित्त ६ ५ करोड़ रुपयों का व्यय नियत किया गया था। पर वास्तव में प्रथम योजना में १५ ४ करोड़ रुपयों व्यय किया गया था जिसमें ६ करोड़ रुपयों की रकम एयर काफ्ट खरीदने के लिये सम्मिलित थी। कुछ धन की मात्रा भूमि पर यातासाद के साधन खरीदने, वर्तमान दफ्तरों के सुधार तथा नये दफ्तरों के खोलने पर भी व्यय की गई थी।

दितीय योजना में ३० ५ करोड़ रुपये व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है जिसमें से १६ करोड़ रुपया तो इन्डियन एश्चर लाइन्स कारपोरेशन पर श्चीर १४५ करोड एयर इन्डिया इन्टरनेशनल पर व्यय किया जायगा। व्यय के मुख्य शीर्पक निग्न हैं:---

	करोड़ रुपये में
मुग्रावजे का चुकाना	पू १४
एश्चर काफ्टो का कय	१५ ३४
इन्डियन एथ्रर लाइन्छ के कार्य में टानि	900
इन्डियन एश्रर लाइन्स के दफ्तर श्रीर क्रमंचारियों के श्रावास	৽৸৽
एश्रर इन्डिया इन्टरनशनल के कारखाने का विस्तार	१९५
टन्डियन एग्रर लाइन्छ के आवश्यक सामान	०५०
एसर इन्डिया इन्टरनेशनल के ऋणपत्रों का चुकाना	30 0
कुल	३०५३

इन्हियन एथर लाइन्छ के बेढे को श्राधुनिक बनाने के निमित्त व्यय का प्रमन्य किया जा रहा है। कारपोरेशन ने ५ याई काउन्टों के क्रय करने के लिए प्रथम योजना में ही त्रार्टर दे रक्खा था श्रोर श्राशा की जाती है कि १६५७ के सध्य तक वे श्रा जायेंगे श्रोर श्रन्य जहाजों के क्रय करने के लिये श्रार्डर दिये जाने के सम्पन्य में छान शिन की जा रही है। इन्हिया इन्टरनेशनल के लिए यह क्यवस्था की गई है कि कुछ टवों-प्राप या जेट एश्रर क्राफ्ट बढी हुई माँग को पूर्ण करने के लिये तथा श्रितिक सेवा के लिये क्रय किए जायें। इवाई सेवाशों के विस्तार के कार्यक्रम को निश्चित करते समय श्रनेकों वातों का ध्यान में रताना श्रावश्यक होगा जैसे कि क्रय किये जाने वाले एश्ररकाफ्टों के प्रकार, उनको चलाने का ब्यय, किराये-भाडे की दर, सगठन की कुशलता, हानि रोकने की सम्भावना, सेवाशों की सुरत्ता, श्रीर देश के सभी भागों को कुशल हवाई सेवा द्वारा एक दूसरे से सम्मन्यत कर देने की श्रावश्यकता इत्यादि।

अध्याय ३८

यातायात का परस्पर सम्बन्ध श्रीर नियोजन

भारतीय यातायात व्यवस्था में सुमम्बन्ध स्थापित करने श्रीर उसका नियोजन करने की दृष्टि से यातायात की सभी प्रकार की सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए, यातायात के विभिन्न साधनों में होने वाली अनुचित प्रतियोगिता को रोकना चाहिए और उपमोक्ता के लिए यातायात के न्यय को कम किया

भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश की आवश्यकवाओं को देखते हुए यातायात के वर्तमान साधन पूर्णतया अपर्यात हैं। यदि प्रति नयकि को माप्त यातायात की सुविधा की भारत के वरावर चेत्रफल श्रीर जनसंख्या वाले श्रन्य देशों से तुलना की जाय तो जान होगा की भारतीयों को श्रन्य देशों के नागरिकों की अपेचा यातायात की वहुत कम सुविधा प्राप्त है। यदि रेलवे श्रीर इवाई मार्ग की लम्बाई दूनी कर दो जाय और जलयानों की माल ढोने की शक्ति को चार गुना बढा दिया जाय तब भी इसे बहुत श्रिधक नहीं कहा जा सकता है, हाँ इससे देश की आवश्यकता अवश्य पूर्ण हो सकती है।

किसी भी देश के यातायात की सुविधा में वृद्धि का उसके श्रीद्योगिक श्रीर श्राधिक विकास से निकट सम्बन्ध होता है। देश के श्राधिक विकास के लिए यह त्रावरयक है कि उसमें यातायात की सुविधा पर्याप्त हो, सस्ती हो श्रीर यातायात की गति तीव हो। उद्योगी के लिए यातायात व्यय उत्पादन का महत्वपूर्ण त्रम है इसलिए उद्योगों का न्यम घटाने के लिए यातायात का न्यम घटाने की अत्यन्त आवश्यकता है। यावायात ब्यय कम होने से उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति बढेगी श्रीर माल का उपभोग भी बढेगा। किसी भी देश की प्रगति में उसके यातायात की व्यवस्था, रेलवे, सहकों श्रीर हवाई जहांनी तथा जलयान कम्पनियों की किराया एव भाड़ा नीति श्रीर उसमें विमिन्न प्रकार के सामानों के यातायात की सुविधा का विशेष योग होता हैं। यदि यातायात नीति दोषपूर्ण है तो उद्योगों का स्थानीकरण भी दोषपूर्ण होगा। यातायात पर केवल उद्योगों का विकास निर्मंर नहीं करता है किन्तु श्रौद्योगिक विकास के प्रकार पर भी यातायात का प्रकार श्रीर उसका विकास निर्भर करता है।

पचवर्षीय योजना में बताया गया है कि त्रागामी कुछ वर्षों में देश में

खाद्यान का उत्पादन बढने से श्रीर िसन्द्री में रसायनिक खाद का श्रिषक उत्पादन होने से इन वस्तुश्रों का श्रायात कम करना पढ़ेगा, जिसके कारण बन्दरगाहों से इन वस्तुश्रों को देश के विभिन्न मार्गों म पहुँचाने के लिए यातायात की कम श्रावश्यकता होगी श्रीर ऐसी िस्यित में देश के श्रन्दर हुए उत्पादन को नियत स्थानों तक पहुँचाने के लिए यातायात को व्यवस्था में वृद्धि करनी पढ़ेगी। दूसरी श्रीर राजगगपुर के सिमेंट के कारखाने से जिसने १६५२ के श्रारम्म से उत्पादन श्रायम्म कर दिया है श्रीर विजयवाड़ा में स्थित श्रान्म सिमेंट कम्पनी के प्रसार से उपमोग के वेन्द्रों में ही उत्पादन व्यवस्था का प्रसार होने के फलस्वरूप यातायात की सुविधा की माँग कम हो जायगी। साधारणतया योजना को कार्योन्वित करने का प्रभाव यह होगा कि यातायात की सुविधाश्रों को बढ़ाने की माँग बढ़ेगी। इस्लिए यह श्रावश्यक है कि (श्र) यातायात की सुविधा का प्रसार किया जाय, (व) यातायात की सुविधाश्रों का बढ़ाने के कारणा का पता लगाया जाय श्रीर (स) यातायात की श्रव्यवस्था करके वर्तमान व्यवस्था पर पढ़े श्रव्यच्ति मार को कम किया जाय।

भारत में वास्तविक कठिनाई यह है कि पचवर्षीय योजना के होते हुए भी विकास की गति बहुत धीमी है। पचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी यातायात की सुविधाएँ देश की त्रावश्यकता को देखते हुए कम ही रहेंगी। यातायात की सुविधा में तीव गति से प्रगति न होने के स्रनेक कारण हैं:

(१) वित्त का अभाव है, इस कारण अधिक सड़कों का निर्माण करने में,
ज्यधिक रेलवे लाइन विछाने में और रेलवे के लिए अधिक रोलिंग स्टाक कय करने
में, सड़कों के लिए मोटर तथा वस कय करने में और विमान तथा जलयानों को
क्रय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केवल प्रसार योजना
की माँग पूर्ण करने के लिए ही नहीं किन्तु वर्तमान में चालू गाड़ियों, बसों और
जलयानों को बदलने के लिए, जो कि प्रायः वेकार हो चुके हैं, अधिक गाड़ियों,
वसों और जलयानों की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने सभी उपलब्ध वित्त
साधनों का यातायात की वर्तमान स्थिति के सुधार में और उसके प्रसार में
सुसम्बद्ध उपाय से व्यय करना चाहिए। दूसरी कठिनाई यह है कि यातायात
के साधनों के लिए आवश्यक सामग्री के मूल्य बहुत बढ़े हुए हैं। यदि वित्त
आवश्यकता पूर्ण भी हो जाय तब भी उससे इतनी अधिक मूल्यों पर सभी आवस्थक सामग्री नहीं क्रय की जा सकती। वित्त अभाव और सामानों का अधिक
मूल्य होने के कारण भारत में यातायात की सुविधा के प्रसार में बत्या उसक हो
जाती है।

- (२) सहक बनाने और रेलवे लाइन विछाने के लिए श्रावश्यक सामान का समाव है। इसके साथ ही मोटरों, रेलों के हिन्बों, इखनों, जलयानों, विमानों श्रीर इनके श्रला कल पुर्जों तथा स्टोर का भी बहुत श्रभाव है। इनमें से श्रिषिकाश के लिए भारत को विदेशों से श्रायात पर निर्मर करना पडता है। इघर कुछ वर्षों से भारत में इखनों, जलयानों इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु श्रभी बहुत लम्बा मार्ग तय करना है। मारतीय यातायात के विकास की समस्या का (श्र) सहक श्रथवा रेल के निर्माण के लिए श्रावश्यक सामग्री का उत्पादन करनेवाले उद्योगों के विकास से श्रीर (व) मोटर तथा जलयानो का निर्माण करनेवाले उद्योगों के विकास से गहरा सम्बन्ध है। उद्यागों के वीरे-धीरे विकास होने से यातायात की सुविधा की प्रगति भी सीमित हो गई है।
 - (३) कुशल कारीगरो, इजीनियरों, विमान चालको इत्यादि का बहुत अभाव है, यातायात की व्यवस्था का विकास करने के लिए इनका अभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए इनकी सख्या को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यक्ता है। सरकार ने कारीगरी की शिज्ञा के लिए। बरोप व्यवस्था की है और यातायात की सुविघाओं का प्रसार उसी गति से होगा जिस गित से कारीगरों और अन्य कुशल कर्मचारियों के अभाव की पूर्ति होगी।

यातायात म मुसम्बन्ध स्थापित करने की नीति का उद्देश्य है कि उपभोक्ता को यातायात में कम से कम व्यय करना पड़े। इसका तर्कसगत परिणाम।यह निकला कि हमें यातायात के उन सभी साधनों को समाप्त कर नये साधनों का उपयोग करना पढेगा जो उपयुक्त नहीं हैं; समय की मॉग पूर्ण नहां कर सकते हें श्रीर पुराने हैं। उपमोक्ता के लिए सड़क यातायात रेलवे की श्रपेत्ता श्रिषिक सत्ता श्रीर सुविधाजनक है क्योंकि सहकों से श्रासपास के सभी चेत्र लाम उठा सकते हैं श्रौर रेलवे स्टेशन तक माल ले जाने श्रीर वहाँ से लाने में जो श्रनावश्यक व्यय होता है उसकी बचत हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि सहक यातायाव के प्रसार श्रीर विकास से या तो रेल यातायात बन्द हो जायगा या उसका चेत्र सकुचित हो जायगा। यदि मोटर, ट्रक श्रोर वसे वेलगाहियों से श्रिधिक वचत वाले श्रीर तीवगति चल सकने वाले साधन हैं तो इसका तात्पर्य है कि नगरों श्रीर कस्वों में वैलगाहियों का श्रास्तत्व ही रह जायगा। यदि माप से चलनेवाले जलयान हवा से चलने वाले जलयानो से श्रधिक बचत वाले हैं तो हवा से चलने वाले जलयानों की त्रावश्यकता ही नहीं रह जाती। परन्तु व्यवहारिक चेत्र में इस प्रकार का तीव परिवर्तन न तो संभव है ग्रौर न इसकी सलाह दो जा सकती है क्योंकि (१) पॅजी इस समय ऐसे साधनों में लगी हुई है जो आधुनिक

साधनों की द्वलना में कुशल साधन नहीं कहे जा सकते। यदि इन साधनों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय या इनका कार्यचेत्र सकुचित कर दिया जाय तो इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र को गहरी चित पहुँचेगी। ऐसी स्थिति मे यातायात के दुराने साधनों के स्थान पर नये साधनों का उपयोग करना एक धीमी प्रक्रिया है। इसमे काफी श्रिधक समय लगेगा। यातायात के कुशल श्रीर उपयुक्त साधनों का धीरे-धीरे उपयोग बढाया जायगा श्रीर श्रकुशल तथा श्रपेचाकृत कम उपयुक्त साधनों को धीरे धीरे हटाया जायगा। यह प्रक्रिया तब तक प्रचलित रहेगी जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता; (२) मारत में कुछ समय तक हवा से चलने वाले जलयानों श्रीर वैलगाहिया का उपयोग करना पढेगा श्रन्यथा यातायात की माँग श्रीर उसकी पूर्ति का श्रन्तर श्रीर बढता जायगा। मारत मे यातायात की कुल ब्यवस्था ऐसी है कि इम श्रमी काफी समय तक श्रकुशल श्रीर पुराने साधनों को समाप्त नहीं कर सकते।

इस स्थित को स्थान मे रखते हुए इस दिशा मे सर्वोत्तम नीति यह होगी। कि वर्तमान के यातायात के साधनों को प्रचलित रखा जाय श्रौर (श्र) कार्य को सुनियोजित करके, कुछ साधनों के श्रत्यधिक कार्य भार को हलका करके श्रौर श्रनेक साधनों की उपयुक्त शक्ति का उपयोग करके यातायात की वर्तमान व्यवस्था का दुरुपयोग बचाया जाय, (व) यातायात से विभिन्न साधनों की परस्पर श्रद्यांचत मित्योगिता को रोका जाय, साथ ही एक ही प्रकार के साधन की विभिन्न इकाइयों की श्रद्यांचित प्रतियोगिता को समाप्त किया जाय, श्रौर (स) रेलवे, सङ्क, जल यातायात तथा हवाई कपनियों को उचित लाम के साथ ही साथ उपमोक्ताओं के लिये यातायात सस्ता किया जाय।

वर्तमान में रोडवेज और रेलवे, रेलवे और जल यातायात और रेलवे तथा वायु यातायात मे तीव प्रतियोगिता, नहीं है। यातायात के सभी साघनों का अभाव है और सभी साघनों के कार्यचेत्र पर्याप्त हैं इसिलए कुछ अपवादों को छोड़कर व्यापार हथियाने के लिए इनमें कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसके साथ ही विभिन्न साघनों का किराया इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि प्रतियोगिता नहीं हो। सरकारी बसे वर्तमान में वम्बई तथा उत्तर प्रदेश में भिन्न मिन्न किराया वस्तिती हैं। सम्बई का किराया में है पाई प्रति मील है और उत्तर प्रदेश का ७३ से ह पाई प्रति मील है, जब कि रेल की तीसरी अंभी का किराया साधारण या डाक गाड़ी से १५० मील तक कमशः ५३ और ६५ पाई प्रतिमील है। वायुयान का किराया प्रायः ४ आना प्रति मील है और रात की छाक सिंदी से किराया २३ आना प्रति मील है जोर रात की छाक सिंदी से किराया २३ आना प्रति मील है। जब कि रेलवे की प्रथम

श्रेगो का किराया २ है से २ श्री श्रीना प्रति मील है। वसों श्रीर रेलों में कुछ चेत्रों में अवश्य प्रतियोगिता चलती है पर वडे पेमाने पर कोई श्रमुचित प्रतियोगिता नहीं है। वायुयान से यात्रा श्रमी श्रवश्य कुछ महगी है श्रीर रेलवे यात्रा से कुछ श्रिक मयप्रद भी है। कुछ उच्च श्रेगी के यात्रियों के श्रांतिरक्त वायु यातायात से रेलवे को कुछ हानि नहीं है परन्तु मिवष्य में जैसे-जैसे सहक श्रीय वायु यातायात श्रीवक सस्ता श्रीर कम भयप्रद होता जायगा वैसे-वैसे रेलवे से श्रांतियोगिता भी वढती नायगी।

मारत के कुछ मार्गों में जलयानों द्वारा तटीय यातायात में श्रीर रेल के यातायात में प्रतियोगिता चलती है श्रीर देश के विमानों की तटीय व्यापार में जलयानों से प्रतियोगिता चलती है परन्तु तटीय जलयान व्यापार को नियमित कर देने से यह प्रतियोगिता कम हो गई है। भविष्य में पुन प्रतियोगिता बढने की सम्मावना है, परन्तु इनमें ग्रमुचित प्रतियोगिता बढने का कोई कारण नहीं है। भविष्य में रेलवे लाइन से समकोण बनाती हुई सदकों का निर्माण करक श्रीर सदकों के प्रसार की ऐसी योजना बनाकर कि उनसे निर्मान बन्दरगाहों में जल यातायात की श्रावश्यक्ताश्रों की पृति हो सके यातायात के विमिन्न सप्यां के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकने की पूर्ण सम्मावना है। रेलवे तथा जल यातायात के वीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसमें व्यवस्था की गई ई कि मंगलीर वन्दर से रेल सम्बन्ध चिकामगलुर होते हुए मद्रास से सम्बन्धत किया जाय।

यदि यातायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण किया जाय तो इनमें परस्पर ठाचत सम्बन्ध स्थापित कर सकना सुगम हो जायगा। यदि सभी साधनों की स्वामी सरकार हो श्रीर वही इनको चलाये तो सहकों को जोड़ने श्रीर एक स्थान पर कई प्रकार के यातायात उपलब्ध होने इत्यादि में व्यर्थ रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। निजी उद्योग होने पर ऐसा श्रावश्यक हो जाता है। सरकार ने सहक यातायात का एक सीमित चेत्र में राष्ट्रीयकरण किया है जिसके कारण इन चेत्रों में रोडवेज श्रीर रेलवे के मध्य कोई श्रनुचित प्रतियोगिता नहीं है। राष्ट्रीयकरण किया है जिसके कारण इन चेत्रों में रोडवेज श्रीर रेलवे के मध्य कोई श्रनुचित प्रतियोगिता नहीं है। यह सहके विभिन्न चेत्रों को रेलवे मार्ग से सम्बन्धित करती हैं। सड़क यातायात को निश्चित चेत्र में एक विशेष दूरी तक सीमित करक श्रीर रोडवेज सर्विस को उन सहको पर चालू करके जहाँ रेलवे यातायात की सुविधा नहीं है यह परिणाम निकला है। रेला से यात्रियों की सुविधा का प्रवन्ध बढ़ा है श्रीर किराये में भी वृद्धि हुई है श्रीर इससे दोनों में श्रनुचित प्रतियोगिता की हानियों को समाप्त कर दिया गया

है। यद्यपि राष्ट्रीकरण कर देने से अनुचित प्रतियोगिता तो समाप्त की जा सकती है परन्तु यह व्यवस्था सभी स्थितियों में सुविधाजनक सिद्ध नहीं हो सकती। मारतीय रेलों श्रीर वायुयान कम्पनियों का कुछ थोडे छोटे मार्गों को छोड़ कर पूरी तरह राष्ट्रीकरण किया जा चुका है और सड़क यातायात का बहुत सा मार भी राज्य सरकारे ते चुकी हैं, परन्तु कुछ चेत्रों में सड़क यातायात श्रीर पूरा जल यातायात श्रमी निजी उद्योगपितयों के हाथ में है। यातायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण करना सम्भव नहीं है क्योंकि (१) श्रावश्यक कर्मचारियों का श्रमाव है श्रीर (२) हानि होने का हर है। यह हानि विशेषकर जल यातायात में श्रिषक हो सकती है क्योंकि इसका पूर्ण विकास नहीं हो सका है श्रीर उसे विदेशी जलयान कम्पनियों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। यह कहना श्रमुचित न होगा कि राष्ट्रीकरण से हानिकारक प्रतियोगिता की समस्या सुलकाई जा सकती है। इसके साथ ही इससे एकाधिकार के दोप भी उत्पन्नहो सकते हैं जैसे उपभोक्ता के हितों की उपेद्या, कार्य व्यय में वृद्धि श्रीर श्रकुशल कार्य। यदि हानिकारक प्रतियोगिता को समाप्त करने से नई समस्याएँ उत्पन्न हो जाय तो इस व्यवस्था को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

यातायात का पूर्ण राष्ट्रीकरण न हो सकने पर भी यातायात के विभिन्न साधनों में निम्नलिखित उपायों से परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है:—(१) कानून द्वारा प्रत्येक प्रकार के यातायात के कार्यचित्र को निर्धारित करके, विभिन्न साधनों के त्राधिकतम और न्यूनतम किराये की टर निश्चित करके और विभिन्न साधनों द्वारा यात्रियों को दी जानेवाली न्यूनतम सुविधाओं और सामान के यातायात की सुविधाओं को निश्चित करके, (२) यातायात के विभिन्न साधनों के कार्य के निरीक्षण के लिए और उनमें उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिये के कार्य के निरीक्षण के लिए और उनमें उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिये केन्द्रीय यातायात परिषद् स्थापित करके। यातायात की व्यवस्था में परिस्थितियों के श्रनुसार शीध परिवर्तन हो जाता है इसिलये यातायात के विभिन्न साधनों के तथा सप्योक्ताओं के हितों की केवल कानून द्वारा ही रचा की जा सकती है। इससे किराये की दरों में घटने-बढ़ने की सम्भावना समाप्त हो सकती है और जनता को श्रमुविधा हो सकती है परन्तु यह कठिनाइयाँ पर्यात श्रिधकार दिये जाने पर स्थीर सन्तोषजनक रीति से कार्य कर सकने के लिए व्यापक चेत्र देने पर राज्य यातायात परिषद् दर कर सकती है।

प्रथम पचनर्षीय योजना मे ५५७ करोड़ रुपया यातायात श्रीर सचार विमाग के लिये नियत किया गया था। यह धन योजना के कुल व्यय का २३.६% था। द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत १३८५ करोड़ रुपया, जो कि कुल योजना के व्यय का रू है, यातायात श्रीर सचार विमाग पर व्यय करने के लिये नियत किया गया है। इस १३८५ करोड़ रुपये में से रेलवे, सड़क, सड़क यातायात, वन्दरगाहो, जल यातायात श्रीर हवाई यातायात पर क्रमश ६०० करोड़ (कुल व्यय का १८८%), २४६ करोड़ (५१%), १७ वरोड़ (०'६%), ४५ करोड़ (०६%), ४८ वरोड़ (१०%) श्रीर ४३ वरोड़ (०'६%) व्यय किया जायगा। प्रथम योजना वे श्रन्तर्गत ५५७ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से इन्हीं शीर्पको पर क्रमश. २६८ करोड़ (११'४%), १३० वरोड (५५%), १२ करोड़ (०५%), ३४ वरोड (१४'४%), २६ वरोड़ (११'%)) श्रीर २४ वरोड़ रुपया (१०%) व्यय क्या गया था। इन श्रावड़ों से जात होता है कि कुल व्यय का प्रांतरात व्यय रेलवे पर बढ़ा दिया गया है।

	१९५०-५१ की रियति	१९५५-५६ में धनुमानित स्थिति	१६६०-६१ तक ष्येय
रेलवे			
(१) पैसेन्जर गाड़ियाँ (मील दस लाख में) (२) माल जो लाटा गया(दस लाख टनों मे)	દ્ય	१०८	१२४
सडक	83	१२०	१६२
(१) राष्ट्रीय राजपथ (हजार मीलों में)	१२ ३	१२६	₹ ३'¤
(२) वरफेस्ड रोड्स (इजार मीलों मे) जहाज—	દ્દહ	१०७	१२५
(१) तटीय श्रीर पडोची से सम्बन्धित टेन्करों को सम्मिलित करते हुये (लाख जी श्रार टी)			
(२) समुद्र पार ट्रैम्प टनेन को सम्मिलित	२२	3 7	8 \$
करते हुये (लाख जी आर टी) वन्दरगाह—	१७	२८	80
सेवा करने की शक्ति (टस लाख टनों में)	२०	२५ ०	इरप्

ऊपर दिये गये श्रॉकडों से यह ज्ञात होता है कि द्वितीय योजना के श्रन्त-गत स्वतीनमुखी विकास का प्रयत्न किया जायगा। १६५५-५६ की तुलना में सब से श्रांघक प्रतिशत वृद्धि १६६०-६१ में समुद्र पारकी जल यातायात के सम्बन्ध में की जायगी। जल यानायात के सम्बन्ध में ६८%, रेलवे में ३५%, तटीय जल यातायात में ३४% थ्रौर बन्दरगाहों पर माल उतारने चढाने की शक्ति में ३०% की वृद्धि की जायगी।

प्रथम पचवर्षीय योजना का मुख्य व्येय यातायात सम्बन्ध मे यह था कि यथासम्भव गत १० वर्षों से ऋत्यविक कार्य में आने वाले प्रसाधनों को बदल कर नया कर दिया जाय। रेलवे के सम्बन्ध में यह कार्य बहुत कठिन था। जल यातायात, वन्दरगाहों, प्रकाशस्तम्भो, वायु यातायात श्रादि के सम्बन्ध में भी इस कार्य के लिए बहुत बड़ी धनराशि नियत करना श्रावश्यक थी। प्रथम योजना काल में क्योंकि कृषि ग्रीर उद्योगों की उत्पत्ति में वृद्धि हो गई थी इसलिये याता-यात की सुविधा के अभाव का अनुभव विशेषकर योजना के तीसरे वर्ष से होने लगा था। इस स्थिति का सम्भालने के लिये श्रातिरिक्त धन का श्रानुमान रेलवे, सहकों, जन यातायात, निद्यों श्रीर वायु यातायात के लिये किया गया श्रीर इन के विकास के कार्य-कम म भी वृद्धि की गई। रेलवे के गन्नयानादि के कय का कार्य-क्रम बढाया गया और उन क्षेत्रों में लाइने बढाने के लिये विशेष प्रयत्न किया गया जहाँ रेल यातायात की माँग अधिक थी। एक अन्तर्विभागीय अन्वेषण वर्ग द्वारा यातायात के सभी साधनों के पारस्परिक विकास सम्बन्धी प्रश्न पर श्रीर मुख्यतः सडक यातायात के विकास सम्बन्धी प्रश्न पर जो बढती टुई सॉग के हिसाब से बहत दिनों से पिछड़। हुआ था विचार किया गया । सड़क यातायात के न्यक्तिगत भाग मे विकास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपाय किये गए श्रीर लाइसेन्छ देने की नीति को श्रधिक उदार बनाया गया । भारतीय जल यातायात की सहायता के उपाय भी किये गये।

यद्यपि प्रसाधनों के नवीनतम करने के कार्य अभी शेप हैं किर मी द्वितीय योजना में देश के यातायात साधनों के समुचित विकास की (विशेष कर रेलवें की जिसके द्वारा स्टा से अधिकतम यातायात की सुविधा प्रदान की गई हैं) व्यवस्था की जा रही है। रेलवें के विकास के कार्य-क्रम का देश के औद्योगिक विकास के साथ विशेषकर बहे-बहें उद्योगों, जैस स्पात, कोयला, सिमेंट आदि, के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखना आवश्यक होगा। द्वितीय योजना विभिन्न यातायात के साधनों के बीच पारस्पारक समजस्य स्थापित करने का भी प्रयत्न करती है। सहक यातायात की सुविधा में जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है रेलवें द्वारा अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवें और तटीय जन यातायात तथा रेलवें और नदी द्वारा यातायात के सामजस्य पर और भी विशेष ध्वान दिया गया है। इस प्रकार द्वितीय योजन के अन्तर्गत मुख्या मुख्य

यातायात साधनों श्रीर उनके पारस्परिक सामजस्य के श्रिषिकतम विकास की श्रीर विशेष ध्यान दिया गया है तािक प्रत्येक श्रुपने-ग्रुपने चेत्र के कार्य को श्रुच्छे से श्रूच्छे दक्ष से पूर्ण कर सके। इस स्थिति का निष्कर्ष यह है कि श्रागामी पाँच वर्षों में सभी प्रकार के यातायात साधनों की माँग बहुत श्रिषक बढ़ेगी, इसितये यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतिवर्ष यातायात श्रीर सचार के विकास के कार्य-क्रम पर विचार किया जाये तािक जहाँ कहीं श्रावश्यक हो ऐसे उपायों को श्रय-नाया जाय विनसे यातायात की कितनाइयों के कारण योजना के श्रम्य कोई कार्य-कम में बाधा न पढ़े।

श्रम्याय ३६ प्रथम पंचवर्षीय योजना

नियोजन का तालार्य यह है कि देश के उपलब्ध साधनों का नियमबद्ध रूप से उपयोग किया जाय श्रीर इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोगा अपनाया जाय जिससे जुत्पादन बढे, राष्ट्रीय लामाश बढे, रोजगार श्रौर सामाजिक कल्याया में वृद्धि हो। इसके लिये यह आवश्यक है कि उपलब्ध साधनों की सावधानी से र्जीच परल की जाय श्रीर राज्टीय उत्पादन और श्राय में निर्धारित वृद्धि करने के लिये इन राधनों के उपयोग की गति को भी नियोजित किया जाय। भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना १६५१-५२ में लागू हुई श्रीर १६५५-५६ तक पूरी हो गई। इस योजना पर ५ वर्ष मे २.०६६ करोड़ कपया ब्यय करने की व्यवस्था की गई थी। व्यय की मात्रः निर्धारित करने मे योजना आयोग ने इन बातो पर विचार किया कि (१) विकास की एक ऐसी प्रक्रिया का समारम किया जाय जिसके श्राधार पर भविष्य में और बड़ी योजनाश्रों को कर्यान्वित किया जा सके. (१) विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए देश को कुल कितने साधन उप-लब्ध हो सकते हैं, (३) विकास की गति और निजी तथा सरकारी चैत्र के अन्तर्गत साधनों की आवश्यकता के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो, (४) योजना लागू होने के पूर्व देन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा आरम्भ की गई विकास योजनाओं को पूरा किया जाय और (५) युद्ध तथा देश विभाजन से देश की अञ्चनस्थित श्राधिक व्यवस्था को सुनियोजित श्राधार प्रदान किया जाय।

मारत की आधिक हियति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनस्ख्या में प्रतिवर्ष १% प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस तथ्य पर श्रीर देश के सभा उपलब्ध साधनों पर विचार करने के पश्चात् योजना आयोग ने यह व्यवस्था की है कि १६७७ तक वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय दूनी हो जाय। भारत की अपेचां अधिक विकसित देश में प्रति व्यक्ति की आय दूनी करने में कम समय लगेगा परन्तु मारत जैसे पिछड़े देश में इसमें अनिवार्यतः अविक समय लगेगा परोक्त देश में साधनों की कभी है, टेकिनिकल कुशलता का अभाव है और सगठम की हियति कमजोर है। मारत में प्रति व्यक्ति आय दूनी करने के लिए अनेक पचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मारत सरकार ने इस दिशा में कार्य आरम्म कर दिया है। समय के साथ कार्य की गति मी जोर पकड़ती जायगी।

पूजी निर्माण की गित—योजना श्रायोग ने यह माना है कि श्राधारभूत वर्ष १६५० ५१ में भारत की राष्ट्रीय श्राय ६,००० करोड़ क्या थी श्रोर कुल राष्ट्रीय श्राय का श्रोकतन ५ प्रतिशत बचत की जाती थी। इसका ताल्प्य यह है कि १६५०-५१ में सारी जनता की कुल बचत ४५० नरोड़ क्या थी। यह १६५१-५२ श्रोर १६५५ ५६ के बीच प्रात वर्ष २० प्रतिशत श्रातिरक्त श्राय पूँजी निर्माण में लगा दी जाय, श्रर्थात मशीन इत्यादि श्रार काफी समय तक चलने वाले सामानों पर क्या लगाया जाय तो पचवर्षीय योजना के श्रत तक भारत की राष्ट्रीय श्राय १०,००० करोड़ क्यये तक बढ जायगी श्रोर बचत की दर भी ६ श्रातशत वार्षिक हो जायगी। १६५५-५६ में इस प्रकार कुल ६०५ करोड़ क्यया राष्ट्रीय बचत होगी। योजना श्रायोग ने बताया है कि इसके बाद १६६७-६० में समात होने वाले १२ वर्षों में नेवल २० प्रतिशत नहीं बिल्क ५० प्रतिशत श्रातिक राष्ट्रीय श्राय प्रतिवर्ष पूँची निर्माण में लगाई जानी चाहिये। यह प्रक्रिया जारी रहती है तो १६७७ तक प्रति व्यक्ति की श्राप (Per capita Income) दो ग्रनी हो जायगी।

प्राथमिकता का क्रम-राष्ट्रीय ग्राय में उत्त-लिसित वृद्धि करने के लिए प्रतिब्यक्ति की त्राय टोगुनी करने के लिए सशोधित योजना मे २,३५६ करोड रुपया विकास योजनाश्चा मे व्यय करने का निश्चय किया गया। योजना में भारतीय त्रार्थिक न्यवस्था को सरकारी तथा निजी उन्नोग द्वेत्र मे विभाजित किया गया है। सरकारी चेत्र में वह उद्योग सम्मिलित हैं जिनका मालिक स्वय सरकार है, जिन पर वेन्द्रीय या राष्य सरकार श्रयवा इन सरकारों के श्राधीन श्रधिकारियों ा का नियत्रण है। निजी उद्योग चेत्र में वह उद्योग, वाणित्य श्रोर व्यापार शामिल हैं जिन के मालिक उद्योगपति हैं, जिन पर उनका नियन्नण है श्रोर जिनका सचा-लन स्वय इन्हीं उद्योगपितयों द्वारा होता है। इन दोनों उद्योग चेत्रों की समस्याएँ प्राय॰ समान हैं ग्रौर दोनों को श्रेणियों में स्पष्ट विशेषतान्त्रों के ग्राघार पर विभक्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु सुविधा की दृष्टि से पचवर्षीय योजना में इन दोनों उद्योग चेत्रों पर पृथक रूप से विचार किया गया है। सरकारी उद्योग चेत्र के लिए कुल लागत की मात्रा नि ।।रत कर ली गई है श्रीर इस चेत्र की विचीय द्यावश्यकता सरकार पूरी करती ६ रन्तु निजी उद्योग त्तेत्र के निर्धारित लक्ष्य के सम्बन्य में निश्चित रूप से कुछ, न कह कर केवल सामान्य लक्ष्य वता दिया गया श्रीर इस लह्य की पूर्ति तथा श्रावश्यक वित्त जुटाने के लिए भी उद्योग होत्र को स्वतत्र छोड़ दिया गया। सरकारी उद्योग होत्र में लक्ष्य की पूर्ति सरकार का प्रत्यच् उत्तरदायित्व है परन्तु यही बात निजी उद्योग च्रेत्र में लागू नहीं होती

है क्यों कि निजी उद्योग च्रेत्र में सरकार श्रयत्य इत्य से सहायता प्रदान करती श्रीर कारोबार के परिणामों का निरी च्रण करती रहती है। इसके मूल में यह विचार निहित है कि यदि निजी उद्योग च्रेत्र निबंदित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है श्रीर उसकी प्रगति श्रपे च्रित गिन नहीं हो पाती है तो सरकारी उद्योग का कार्य चेत्र बढ जायगा श्रोर सरकार इन निजी उद्योग च्रेत्र की विभिन्न इकाइयों का कार्य भार वीरे-घीरे स्वय ग्रहण कर लेगी। कुछ, समय तक सरकारी श्रीर निजी च्रेत्र दोनों ही रहेंगे।

पचवर्षीय योजना के प्रारुप में जो जुलाई १६५१ में प्रकाशित किया गया था श्रीर स्वय पचवर्षीय योजना में जो दिसम्बर १६५३ में ससद के सामने प्रस्तत की गई थी क्रिप विकास को प्राथमिकता दी गई है स्त्रोग इसके बाद यातायात तथा सचार, समाज सेवा कार्य श्रीर उद्योग को रखा गया है। पचवर्षीय योजना की यदि योजना के प्रारंग में तुलना की जाय तो पता चलेगा कि योजना के अतिम रूप मे उद्योग के महत्र को कुछ अधिक नढा दिया गया है पर इससे योजना का प्राथमिकता कम नहीं बटलता है। योजना के अतिम रूप में कृषि, िसचाई और विजली की लागत कुल लागत का ४३.२ प्रतिशत रखी गई, याता-यात तथा संचार की लागत २३६ प्रतिशत, समाज सेवा कायों पर व्यय की स्तागत २२.६ प्रतिशत श्रोर उत्पाग की लागत केरल ७६ प्रतिशत रखी गई थी। योजना श्रायोग ने कृषि को श्रिधिक महत्व प्रदान करने के कारणों पर प्रकाश हाला है। ब्रायोग का मत है कि खात्राज ब्रोर करूचे माल के उत्पादन में पर्याप्त बहिन होने से उपोगों के तीन विकास की सभावना नहीं है। सबसे पहले यह श्चावरूयक है कि श्चायिक स्थिति के मूल को दृढ किया जाय, कृषि चेत्र में पर्याप्त श्चितिरिक्त खाद्यान तथा कच्चा माल पैदा किया जाय स्रोर स्रन्य केन्रों का कार्य आगे बढाने में उसका उपयोग किया जाय। इसी उद्देश्य के कारण कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई है। संशोधित योजना में यद्यपि कुल व्यय बहाकर २३५६ करोड़ रुपया कर दिया गया फिर भी प्राथमिकता के कम में कोई विशेष परिवर्तित नहीं किया गया है।

जहाँ तक ग्रौदाशिक चेत्र का सम्बन्ध है प्राथमिकता निर्धारित करते समय इन बातों पर विचार किया गया है कि (१) ज्रूट श्रोर प्लाईबुड जैसे उद्योगों (Producer goods industries) की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय श्रोर उपमोग की वस्तुग्रों का उत्पादन करनेवाले उद्योगों, जैसे सूती कपडा, चीनी, साबुन श्रीर वनस्त्रति उद्योगों की भी वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय, (२) लोहा श्रीर इस्पात, एल्यूमोनियम, िं एसेंट रसायनिक खाद, मारी रसायनिक, मशीनो के श्रीनारों इत्याटि उद्योगों की उत्पादन शक्ति बढाई जाय, (३) उन श्रौद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा िकया जाय जिन पर काफी पूँजी लगाई जा चुकी है ग्रीर (४) जिप्सम से गन्वक, विशेष प्रकार के रेशम का उत्पादन करने के लिए श्रावश्यक सामगी, श्रीर श्रलीह धातुत्रों के टुकड़ों का उत्पाटन करने के लिये नये कारखाने स्थापित किये जाथॅ जिससे बढे और ग्रत्यन्त महत्व के उद्यंगों के लिए श्रावश्यक कच्चे माल की पृति की जा सके। प्राथमिक्ता का यह क्रम यह प्रकट करता है। कि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया नायगा ख्रोर किसी भी उद्योग के प्रति उटाग्रीनता नहीं श्रपनायी जायगी। राज्य श्रनेक कारखाने स्थापित कर सकते हैं परन्तु क्वाप के विपरीत उद्योगों का विकास पूर्णतया निजी उद्योग चेत्र के हायों में छोड़ दिया गया है। कृपि तो सरकारी उद्योग चेत्र के अन्तर्गत आता है। पच-वर्षीय योजना में ४२ उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे श्रीर यह श्रनुमान लगाया गया था कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाँच वर्ष में कुल २३३ करोड़ रुपया व्यय करना पडेगा। इसके साथ ही कारखानों के आधुनिकीकरण में श्रौर मशीनों को बदलने में १५० करोड़ रुपया श्रीर व्यय होगा। यदि इसमें चाल पॅजी की रकम भी जोड़ दी जाय तो पता चलेगा कि पाँच वर्ष मे छेवल उद्योग ही की वित्तीय त्रावश्यकता ७०७ करोड़ रुपये के वरावर होगी। इस वित्तीय त्रावश्यकता की प्रति सरकार नहीं करेगी। इसके लिए निजी उद्योगों को स्वय प्रयत्न करना पहेगा ।

वित्त-योजना को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय आवश्यकता पूरी करने में किसी प्रकार की बाघा न पढ़े। कृषि तथा श्रीद्योगिक साधनों का विकास करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी लगाने की आवश्यकता है। यदि यह पूँजी देश के अन्दर ही प्राप्त नहीं होती तो इसके लिए हमें विदेशी खोतों की सहायता लेनो पड़ेगी। मारत की पचवर्षीय योजना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वर्तमान आय में से बचत, भारतीय रेलवे की आय में से बचत, श्रूण तथा जनता की बचत और विदेशी पूँजी पर निर्मर करती है। योजना के ज्यय की पृति करने के लिए मारत के णैरह पावने, विदेशी सहायता और श्रूण पर मी पूरा विचार कर लिया गया है। इन सारे साधनों का उपयोग कर लेने के बाद मा कुछ कभी रह जाती है जिसकी पूर्ति के लिए यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त कर लगाकर या स्वदेशी बाजार से आविक मात्रा में भ्रूण लेकर इस कभी को पूरा किया जायगा परन्तु यदि ऐसा समय न हो सका तो पचवर्षीय योजना की लागत में इतनी रक्षम वी कभी हर दी जायगी।

योजना की कुल लागत २,०६६ करोड़ रुपया थी; सरकारी तथा निजी बचत से पाँच वर्ष में १,२५८ करोड़ रुपया प्राप्त होगा जबिक इन्हीं लोतों से योजना के मूल वर्ष १६५० ५१ में २२२ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। १,२५८ करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि में से ७४० करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और रेलवे बजट की श्रतिरिक्त श्राय से प्राप्त होगे श्रीर ध्रश्य करोड़ रुपया निजी बचत से । सशोधित योजना में बजट से प्राप्त श्राय में और व्यक्तिगत बचत में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि श्राशा की जाती है कि ७४३ और ५१८ करोड़ रुपये कमश होगी। बढी हुई लागत श्रधिकाश घाटे के श्रध प्रवन्यन द्वारा पूरी की जायगी जैसा कि कमी की मात्रा में ६८८४ करोड़ रुपया बढकर हो जाने से प्रतीत होता है। यह श्राशा की जाती हैं कि पौरह पावने से प्राप्ति को विचाराधीन रखते हुये यह कमी ७०१ करोड़ रुपये की रह जायगी।

योजना को श्रितिम रूप देने के पहले मारत को विदेशों से सहायता श्रीर श्रुग के १५६ करोड़ रुपया मिला था। योजना श्रायोग ने इसे भी सम्मिलित कर लिया। योजना मे यह व्यवस्था भी की गई थी कि घाटे का बजट बढ़ाकर २६० करोड रुपयों की श्रीर पूर्ति की जाय। इसके बाद भी ३६५ करोड रुपयों की श्रीर पूर्ति की जाय। इसके बाद भी ३६५ करोड रुपयों की श्रीर पूर्ति की जाय। इसके बाद भी ३६५ करोड रुपयों की यदि राज्य रोप रह जाती है। यह बहुत समव है कि यह कमा श्रीर श्रिधिक हो यदि राज्य तथा निजी बचत की स्थिति श्राशा के श्रानुकृत न रही।

यदि सारी स्थिति पर दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि सरकारी चेत्र
में जो कुल २,०६६ करोड क्यये की लागत रखी गई है उसमें से दीर्घकालिक व्यय
(Capital expenditure) केवल १,६०० से १,७०० करोड रुपये के बीच में
होगा। यदि इसमें निजी उद्योग चेत्र में लगायी गयी पूँजी को भी मिला लिया
जाय (जिसमें उद्योग, वाणिज्य श्रीर व्यापार में लगी पूँजी भी सम्मिलत है) तो
पॉच वर्ष में स्वदेशी स्रोतों से ही दीर्घकालिक व्यय की २,७०० से २,८०० करोड़
स्वये की राशि पूरी करनी पडेगी। यदि इसमें इसी श्रवध में पीएड पावने की मट
में से मिलने वाले २६० करोड़ रुपये (जा भारत में घाटे की बजट व्यवस्था का
श्राधार हैं) श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय वैंक, श्रमेरिका, कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजालैंड
हत्यादि से प्राप्त १५६ करोड रुपया जोडा जाय तो कुछ साधन ३,१५० से २,२५
करोड रुपयो के बीच हो जाते हैं। सशोबित रूप में यह धनराशि ३३३० ३४३०

आलोचना—पैचवर्षीय योजना मे मारत के कृषि तथा श्रोद्योगिक विकास के सम्बन्ध में बड़ा श्राशाबाटी हिन्टकीया श्रपनाया गया। श्रॉकडो के श्रभाव श्रीर साधनों की कमी के कारण इससे श्रच्छी योजना तैयार करना सभव नहीं था। योजना पूर्ण होने पर राष्ट्रीय उत्पादन बढेगी, श्राय बढेगा श्रीर जनता श्रिषक धनवान श्रीर प्रसन्न हो सकेगी, भारत के श्रार्थिक निकास में जो किमर्या है उन्हें दूर किया जा सकेगा, साद्यान ने देश निरन्तर स्वावलम्बी बनना जायगा श्रीर कुछ कच्चे मालों का जिनके लिये देश श्रायात पर निर्भर है, उत्पादन बढेगा। योजना में वंशिनक प्रगति श्रोर टेकानिकल शिक्षण की श्रायण्यकता को भी महत्व दिया गया है। इन पर उद्याग श्रीर कृषि की सफलता निर्भर करती है। वंशिनक जाँच-परस्त, टेक्निकल शिक्षण इत्यादि के लिये भी योजना में विशेष व्यवस्था की गई है। कुछ समन बाद इसका प्रभाव प्रकट होगा।

यह ब्रालोचना की गई है कि पांच वर्षों में बोजना को कार्यान्त्रित करने के लिए ब्रावश्यक वित्त के सम्बन्ध में पचार्याय योजना ने पहुत ब्रामावादी दृष्टि-कोण अपनाया है और जनता से बहुत आशा की है। इस सम्मन्य में यह कहा गया है कि (F) योजना श्रायोग ने अनुमान लगाया है कि ५ वर्षों में केन्द्रीय सरकार के बजट, राज्य सरकारों के बजट ह्योर रेलवे में क्रमश, १६० करोड़ स्पना, ४०८ प्ररोड रुपया श्रीर १७० करोड़ रुपया श्रुतिरिक्त प्राप्त होगा परन्त इस माता में श्रांतिरिक्त श्राय होना समय नहीं है। जनता में श्रव श्रीर श्रिधिक कर देने की क्तमता नहीं है स्रोर रेलवे तथा सरकारा की स्राय भी उतनी स्रायक होना समय नहीं है जितनी की योजना में श्रपेसा की गई है। इसका तात्वर्य यह है कि पचनपीन योजना अपने नूलरूप में कार्यान्वित नहीं हो पायेगी और उसमें काट र्छौट करनी पडेगी। (ए) योजना में यह माना है कि १६५१ श्रीर १६५६ के बीच प्रति वर्ष अति कि आर्थ का २० प्रतिशत प्रती निर्माश में लगाया जायगा श्रीर १६५६ से १६६८ तक अतिरिक्त आय का ५० प्रतिशत इसमें लगाया जायगा। मारत जैसे निर्धन देश में जहाँ की श्रिधिकतर जनता की खार श्रापने जीवन निर्वाह के लिए हा प्रयाप्त नहीं ई अर्तिरिक्त आय का इतना अधिक अशा पूँजी निर्माण में लगा सकने की त्राशा करना वास्तविक स्थिति के स्रतुक्ल नहीं है। यदि जनता की स्राय बढ़ती है तो वह उसको विनियोग में लगाने की स्रपेका उपयोग में व्यय करना श्रिविक पसन्द करेगी। यदि ऐसा होता है तो योजना ग्रायोग की यह आशा कि १६५६ तक कुल राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये तक बढ जायगी और १६७७ तक प्रति व्यक्ति की आय दूनी हो जायगी, पूरी नहीं हो समती है।

इन म्रालोचनाम्यों में कुछ सत्य म्रवश्य है परन्तु यह योजना का म्राधार भूत दोप नहीं हैं। किसी भी योजना की म्रालोचना में यह तर्क दिये जा सकते हैं। नियोजन के लिए यह म्राश्यकीय है कि जनता त्याग करे। भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना में सवमतः श्रन्य योजनाश्रों की श्रिपे ज्ञां कुछ श्रिष्ठि त्याग करने की भाँग की गई है। परन्तु इस विषय में विभिन्न मत हो सकते हैं कि भारतीय जनता से किस सीमा तक त्याग करने की श्रिपे ज्ञा की जाय श्रीर वह कितना त्याग कर सकने में समर्थ है। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि १९५९-५६ के बीच प्रति वर्ष श्रितिरक्त श्राय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाया जाय जबकि १९५०-५१ में, जो योजना का प्रथम वर्ष या, केवल ५ प्रतिशत के विनियोग की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद की योजनाश्रों में प्रतिशत के विनियोग की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद की योजनाश्रों में प्रतिवर्ष श्रितिरक्त श्राय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाने की श्राशा की जायगी। जहाँ तक इस पद्म का सम्बन्ध है योजना श्रमी पहला प्रयोग मात्र है। यदि जनता योजना में निर्धारित श्रनुपात में रुपया नहीं लगा सकी तो कम मात्रा में लगायेगी परिणाम स्वरूप प्रगति की गति भी घीमी हो जायगी। यही बात श्रतिरक्त श्राय के सम्बन्ध में भी लागू होती है। बिना सही सूचना के इस जेत्र में उपयुक्त श्रनुपात निर्धारित करना समय नहीं है। जैसे-जैसे योजना लागू की जायगी श्रीर नए श्रनुमव प्राप्त होगे उसी के साथ साथ योजना में श्रावश्यक परिवर्तन किए जायुंग।

पचवर्षीय योजना के स्रालोचकों ने कुछ गमीर तर्क भी दिये हैं। उनका कहना है कि: (१) योजना में उद्योग की अपेद्धा कृषि को अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि जो योजनाएँ वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं उन्हें पूरा किया जाय श्रीर मिविष्य में देश के श्रीद्योगिक विकास के लिए मुद्द स्त्राधार स्थापित किया जाय। इस तर्कका मूल विचार यह है कि भारत का वर्तमान श्रीद्योगिक विकास कृषि विकास के श्रनुरूप हुश्रा है। परन्तु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। भारतीय स्थित का जान रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि भारत मे कच्चे माल श्रीर निजली इत्यादि का वर्तमान में जितना उत्पादन होता है उससे देश का बहुत श्रिधिक ऋौद्योगिक विकास किया जा सकता है। योजना श्रायोग ने एक श्रोर बात की श्रोर घ्यान दिया। यह बहुत सभव है कि जब तक इस मारत के भावी श्रोद्योगिक विकास के लिए सुदृढ श्राधार स्थापित करेंगे तज्ञ तक विश्व स्थिति मे ऐसा परिवर्तन हो सकता है जिससे भारत का स्त्रोद्योगिक विकास स्त्राज की अपेद्या अधिक कठिन हो जायगा। ऐसी स्थिति में कृषि के विकास का क्या उपयोग किया जा सकेगा ? अत में इस सम्बन्य में सन्से महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना का उद्देश्य मारत की आर्थिक व्यवस्था की घटियों को दूर करके देश का श्रिधिक सन्तुलित विकास करना है। इस दिशा में सबसे बड़ी कमी यह है कि मारत में मशीनों के निर्माण करने वाले उद्योग नहीं हैं, विद्युत, इजीनियरिंग, फेमिकल इत्यादि के उद्योग का छन्छी तरह विकास नहीं हो सका है इसलिए र्याधक सन्तुलित न्यवस्था बनाने के लिए योजना को इस दिशा की छोर छाधिक ध्यान देना चाहिए था छीर इन उद्योगों का विकास करने की न्यवस्था करनी चाहिए थी।

- (२) योजना के अनुसार देश का जीयोगिक विकास निजी उद्योगपितयों के रायों में सोंपा गया है। इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है क्योंकि श्रतीत में निनी उद्योगपितयों ने भारतीय उत्योगी का कुरालता पूर्वक विकास किया। परन्तु योजना के आलोचका का मत है कि आयोगीगक निकास अनिकाश रूप ने निजी उद्योगपतियों के हाथों में संपने ब्रार उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ निजी उन्तोग के पूर्ण उपयोग के लिए पर्यान साधनों की व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय उद्योगपतियों का मत है कि योजना मे २३३ करोड़ रुपये की पूँजी का विनियोग करने की श्रोर १५० करोड़ क्पये की पूँजी टूट-फुट उत्यादि के लिए राने की व्यवस्था की गई है। परन्छ यह पूँची उत्पादन के निर्घारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए निल्कुल अपर्याप्त है। इसके साथ ही यह बात ध्यान देने योग्य है कि उत्रोग केवल वित्त की हो आवश्यकता नहीं होती है बलिक इसके प्रतिस्कि श्रनेक सुविधायों की मी यावश्यकता होती है, जेसे कर सम्बन्धी, छूट टूट-फुट इत्यादि के लिए अधिक पूँजी और कुछ परिस्थितियों मे नक्द आर्थिक सहायता। यह खेद की बात है कि पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। इसके श्रभाव में निजी उत्रोग देश के श्रोवोगिक विकास के प्रति श्रपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है।
- (3) प्रथम योजना का एक ग्रोर गभीर टोप यह है कि इसमें टीर्घकालीन योजनात्रा पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि सुनियो-जित ग्रायिक व्यवस्था में दीर्घकालिक योजनात्रों पर विशेष जोर देना चाहिये। कुछ विदेशी राष्ट्रों में, जिसका समसे उत्तम उटाइरण सोवियत रुस है, टीर्घकालिक योजनात्रों को ही नियोजन का ग्राघार बनाया गया। परन्तु भारत की स्थित उससे मिन्न है। मारत में टीर्घकालिक योजनाएँ अधिक होनी चाहिये परन्तु साथ ही अल्पकालिक योजनात्रों पर विशेष जोर देना चाहिये था। इससे प्रति एक इटपादन में शीध वृद्धि की जा सकती थी ग्रीर खाद्यान्न के सम्बन्ध में देश शीध स्वायलम्बी बनाया जा सकता था। इससे बहुत सीमा तक मारत की वेरोजगारी की समस्या मी हल की जा सकती थी।

दीर्घकालिक योजनात्रों पर श्राधिक जोर देने में एक श्रीर हानि यह है कि वस्तुश्रों के उत्पादन में दीर्घकाल के बाद वृद्धि होगी जबिक जनता की कय शक्ति शीम ही बढेंगी। इससे मुद्रास्फीति का जोर श्रीर बढ नायगा। सुनियोजित व्य-वस्था में कुछ श्रश तक मुद्रास्फीति श्रीर परिणामस्वरूप श्रधिक कीमते होना श्रिन-वार्य है परन्तु यदि नियोजन के द्वारा वस्तुर्श्रों की पूर्ति बढती है तो उससे मुद्रास्फीति का प्रभाव कम हो जाता है यदि पचवर्षीय थोजना में श्रह्मकालिक योजनाश्रों पर श्रिषक जोर दिया जाता तो ऐसा होना समय था। इसके श्रभाव में योजना के लागू होने से मुद्रास्फीति का जोर बढा है जिससे उपभोकाश्रों को हानि हुई है।

(४) योजना की सफलता विशेष कर उस संगठन की कार्यं जमता पर निर्भर करती है जिस पर उसके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है। भारतीय प्रयम पचवर्षीय योजना की यह सबसे वड़ी कमी थी कि इसमें योजना को लागू करने के लिए किसी विशेष सगठन की व्यवस्था नहीं की गई। कुछ श्रौद्योगिक श्रीर नदी वाटी योजनाश्रों की कार्यान्वित करने का कार्य स्वतन्त्र कार्पोरेशनों को सींपा गया है। इन कार्पेरेशनों पर सरकार अपना नियत्रण रख सकने में विशेष समर्थ सिद्ध नहीं हुई है जिसके परियाम स्वरूप जनता का बहुत सा रुपया नष्ट हो गया है, योजनाओं में प्रायः संशोधन किया गया है और आशानुकृत उत्पादन भी नहीं बढ़ा है। श्रन्य बहुत सी योजनाएँ राज्य सरकारों के श्रधिकार जेजों में रखी गई हैं स्रौर राज्य सरकारे इनको लागू करने का कार्य जिला श्रिषकारियों को सीप देती हैं। यह प्रवन्ध सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हो सका है। जिला श्रिविकारी श्चन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विकास योजनाओं के प्रति पर्याप्त व्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियोजन अधिकारियों का कार्य विशेष सन्तों-पजनक नहीं रहा है। इसका परियाम यह हुआ है कि योजना को उचित रीति से लागू नहीं किया गवा है और उससे जितनी आशा की जाती थी उतना लाभ नहीं हो सका। इसके विपरीत जो कुछ प्रगति हुई है वह केवल कागजों तक ही सीमित है। यदि भारत सरकार आई। ए० एस० की तरह 'भारतीय आर्थिक प्रशासन' (Indian Economic Service) के अन्तर्गत उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करती और इस प्रकार योजना को कार्यान्वित करने के लिये विशेष सगटन को जन्म दिया जाता तो इस दिशा में श्रिधिक प्रगति की जा सकती थी। इससे कार्यालयों इत्यादि पर सरकारी व्यय में अवश्य वृद्धि होती परन्तु वह व्यय व्यर्थ नहीं जाता उससे पचवर्षीय योजना की उपयोगिता बढ़ सकती यी।

इन दोषों के होते हुये भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना देश के आधिक विकास के सम्बन्ध में एक प्रससनीय प्रयत्न या। आरम्भ में तो श्रवश्य ही योजना की सफलता कम होती। परन्तु यह देश के कृषि उद्योग, उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि करने के प्रयत्न का आरम्भ ही या।

सफलता की प्रगति

योजना त्रायोग द्वारा मर्ड १६५७ में प्रमाशित प्रथम पचार्यीय योजना के पुनर्वीच् के श्रनुशार सम्प्र्य पाँच वर्षों में किया नया व्यय २०१२४ मरोइ ६० हुआ (जविक संशोधित लक्ष्य २३७० ७ करोड़ ६० था)। इसमें में १२७७.३ करोड़ ६० वजट में प्राप्त श्राय थी तथा २०३१२ करोड़ ६० विदेशी सहायता ने प्राप्त हुये। इस प्रकार लगभग ३६६ करोड़ ६० कम व्यय हुये। पहले पाँच वर्षों में राज्य सरकारों ने ८६७ ५ करोड़ ६० तथा केन्द्रीय सरकार ने १११४ ६ करोड़ ६० मा व्यय किया।

चूँकि १६५५-५६ की वास्तविक सख्यायेँ पता नहीं है अत्राप्य यह सम्मव है कि योजना का जुल व्यय २०१३ करोड के के बजाय १६६० करोड़ के ही जाय। प्रारम्भ में २६० करोड के के छोटे के अर्थ प्रतन्थन की व्यवस्या थी। वास्तव में यह ४२० कराड़ के हुआ। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थ व्यवस्था पर काफी मार पड़ा।

योजना मे राष्ट्रीय श्राय के ५% के विनियोग को नहा कर ७% तक करने का उद्देश्य था तथा पाँच वर्षों मे ३५००-३६०० करोड क० के विनियोग का लदय था। सरकारी चेत्र में लगभग १५०१ करोड क० का विनियोग हुत्रा जन कि निजी चेत्र में १६०० करोड़ क० का विनियोग हुत्रा। इस प्रकार पाँच वर्ष की अवधि में ३,००० करोड़ क० निनियोग हुत्रा। १६५० ५१ की तुलना में योजना के श्रन्त तक विनियोग का स्तर लगभग दृना हो चुका था।

कुछ कार्यों में प्रथम योजना की प्रगति श्रीर सफलता निरसन्देह श्राश्चरं-जनक रही है। राज्यान इजन ग्रीर सती कपड़ा के सम्बन्ध में १६५५-५६ में उत्पादन सोचे हुये १६५५-५६ के त्येप से कहीं ग्रागे बढ़ गया। श्रमानियम सल्फेट, तटीय जलयात्रा श्रीर सीमेस्ट के सम्बन्ध में यत्रिय उत्पादन १६५५-५६ के श्रमुमानित त्येय से रम ही रहा फिर भी काफी वृद्धि हुई है। कुछ ही कार्य ऐसे रहे हैं जिनमें ग्राशा ने निपरीत बहुत कम वृद्धि हुई है श्रीर उनमें १६५५-५६ तक भी सोचे हुये त्येय तक वृद्धि न हो। इसिलये इस निर्णय पर पहुँचना कि पचवर्षीय योजना ने श्रयं व्यवस्था पर श्रनावश्यक भार डाले विना संतोषप्रद प्रगनि की है, युक्ति सगत होगा।

श्रध्याय ४०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

दितीय पचवर्षीय योजना की श्रवधि १६५६ ५७ से १६६०-६१ तक है। प्रथम पचवर्षीय योजना की अपेद्धाकृत इसकी धारणा (Conception) अधिक व्यापक श्रीर सदृढ है। प्रथम पचनपीय योजना की सफलता श्रीर विकास की गति से प्रोत्साहित होकर योजना आयोग ने द्वितीय पचवणीय योजना को श्रविक कॅचे लक्ष्यों के साथ सामने रखा। द्वितीय योजना के प्रमुख उद्देश्य यह है कि (ग्र) राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप देशवासियों के रहन-सहन का म्तर ऊँचा किया जा सके, (ब) श्रत्यन्त शीवता से श्रौद्योगीकरण हो, जिसके श्रन्त-र्गत त्राधारभूत उद्योगो के विकास पर ऋषिक बल दिया जाय, (स) रोजगारी में वृद्धि हो. श्रीर (द) सामाजिक न्याय की न्यवस्था की जाय। यह उद्देश्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के श्रानुकृत ही हैं, श्रान्तर नेवल इतना है कि द्वितीय योजना में श्रीद्योगिक विकास को पहली योजना की श्रपेक्ता श्रधिक महत्व दिया , गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्तर और भी है। भारत-सरकार ने 'समाजवादी ढाँचे पर श्राघारित समाज (socialistic pattern of society) का आदर्श स्वीकार कर लिया है श्रीर इसी के फलस्वरूप दितीय पचवर्षीय योजना मे सामा-जिक न्याय पर इतना जोर दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नियोजन के द्वारा कृषि व श्रौद्योगिक उत्पादन श्रीर कुल राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि करने की उस समय तक कोई सार्थकता नहीं जब तक कि उस वृद्धि के साथ साथ वितरण मे सुधार न हो क्योंकि इसी वितरण के द्वारा निर्धन व्यक्तियों का जीवन पहले की अपेचाकत अधिक उत्तम हो जाता है।

पूँजी तिर्माण की गति—प्रथम योजना ने आगामी २७ वषा के लिए प्रगति का एक ब्रादर्श सामने रखा। उस आदर्श या लक्ष्य के अनुभार यह अनुमान है कि २२ वर्षों म राष्ट्रीय ब्राय श्रीर २७ वर्षों मे प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो जायगी। इसके अतिरिक्त २५ वर्ष से कुछ अधिक समय में (१९५० ५१ श्रीर १९७७ के बीच) प्रति व्यक्ति उपमोग की मात्रा में लगभग ७०% वृद्धि हो जायगी। दितीय पचवर्षीय योजना इस आदर्श के अनुरूप ही है।

सबसे कठिन समस्या जो योजना बनाने वालों के सम्मुख उपस्थित है वह विनियोग की उस दर का श्रनुमान है जिसको विना किसी श्राशका के कार्यान्वित किया जा सकता है श्रीर राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि पर उसका प्रभाव है। योजना

बनाने वालों को श्राव प्रथम योगना का श्रानुभाव भी प्राप्त है जिसके सहारे ने श्रपने कार्य में भ्यागे वह सकते हैं। १६५०-५१ में तिनियोग राष्टीय भ्याय का ४६% या परन्त १६५१-५२ में बद्धर ७% हो गया। इस वृद्धि मा एछ त्यम ता माल का जिना जिके जमा रहन के कारण था जिनके परिगाम स्वरूप प्यापात में बाहल्य हो गया था। श्रगले दो वर्षों में विनियेग की दर घट कर राष्ट्रीय श्राय की ५% हो नाई, १६५४ ५५ में पुन बढ़ार ६% या ६ ५% हुई श्रीर बढ़ते बढ़ने योजना काल के म्रान्तिम वर्ष में ७ ३% हो गई। यदि योजना काल की पूरी श्रायि में विनियोग की दर का राष्ट्रीय श्राय के सम्बन्ध में प्रतिशत श्रीसत लगाया जाय तो लगभग ६% होता है जो कोई रिरोप प्राकर्षम नहीं है। इस तिनियोग के परिगाम स्वरूप भारत की राष्ट्रीय व्याय लगभग १८% वही द्यर्थात् ६,११० करोड़ क्ययों से जितनी कि १६५०-५१ में भी गढकर १६५५-५६ में १०,८०० करोज़ रुपये ही गई।

तालिका १ श्राय फ्राँर विनियोग में चाँद्ध निमकी आशा की जाती थी १६४०-४१ से १९७१-७६ नक

(१६५२-५३ के मृत्य स्तर के प्राधार पर)

	प्रथम	।द्रतीय	वृताप	चतुर्यं	पचम
	योजना	योजना	योजना	योजना	याजना
	१९५१-५६	१६५६-६१	१६६१-६६	1668-01	१९७१-७६
श्रवधि के अन्त में राष्ट्रीय	}		1		
श्राय (करोड़ रुपयों में)	१०८००	१३४८०	र७२६०	२१६८०	२७२७०
कुल वास्तविक विनियोग	1			,,,	•
(करोड़ इनयों में)	3800	६६००	6600	₹¥50 €	२०७००
श्रवधि के श्रन्त में विनि-			}		
योग का कुल राष्ट्रीय त्राय					
से प्रतिशत श्रनुपात	७•३	30.0	१३.७	१६.०	
श्रवधि के श्रन्त में जन			(40	44.0	१७०
संख्या (१० लाख)	३८४	X2E	\$ 38	3.50	
वृद्धिकी मात्रा का पूँजी			# 28	४६५	५०
श्रीर उत्पादन श्रनुपात	१ दद २	२३०१	२६२१	३ ३६:१	३७०१
प्रति न्यक्ति वार्षिक श्राय			• • • •		1001
श्रवधि के श्रन्त में					
· ·	1				
(रुपयों में)	२८१	३३१	३९६	४६६	५४६

दितीय पचवर्षीय योजना में यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय बचत तथा विनियोग में वृद्धि के कारण १६५५-५६ की राष्ट्रीय आय के ७'३% से १६६०-६१ में १०'७% वह जाने से, राष्ट्रीय आय में लगमग २५% की वृद्धि हो जायगी अर्थात् १६५५-५६ के १०,८०० करोड़ कार्यों से १६६०-६१ में बहकर १३,४८० करोड़ क्या हो जायगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि करोड़ क्या हो जायगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि क्या भारत इतने अधिक विनियोग का भार वहन कर सकता है १ योजना आयोग के अनुसार यहन कर सकता है जैसा कि प्रयम योजना का अनुभव तथा अन्य देशों का अनुभव बतलाता है:

''प्रयम योजना रिपोर्ट में १९५६-५७ से ५०% वचत करने की सीमान्त दर मान ली गई थी और इसके आघार पर यह अनुमान लगाया गया था कि १६६८-६६ तक देश की आर्थिक व्यवस्था में राष्ट्रीय श्राय का २०% विनियोग किया नायगा ग्रौर श्रागे चलकर इसी स्तर पर स्थायी हो जायगा। ग्रव ऐसा ग्रामास होता है कि यह अनुमान अत्यधिक है। जिन पच्यों (projections) का श्रनुगण्न किया गया है उनके श्राघार पर विनियोग का गुण्क (Coefficient) ७% से जो कि १६५५-५६ में था बढकर १६६०-६१ में ११% हो जायगा, १६६५-६६ तक गुग्क के १४% ग्रीर १६७०-७१ तक १६% तक वह जाने का प्रतमान है। उसके पश्चात् गुणक स्थिर रहेगा श्रीर १६७५-७६ तक १७% तक वढ नायगा (तालिका ने० १ के अनुमार)। १६% या १७% राष्ट्रीय आय का विनि-योग निरसदेह ऊँची दर है पर पहुँच के वाहर नहीं है। पाश्चात्य देशों में जिन्होंने श्रपना श्रोद्योगिक विकास पहिले श्रारम्भ किया था पूँजी निर्माण की दर १० श्रीर १५ प्रतिशत के बीच रही है। जापान में विनियोग की दर का १६१३-१६३६ के बीच श्रीसत १६ श्रीर २० के बीच या। रूस में १५ श्रीर २० प्रतिशत की दर निरन्तर हियर रही है। उन देशों के श्राक हों से जोई० सी० ए० एफ० ई० (ecafe) त्तेत्र के श्रन्तर्गत त्राते हैं यह पता लगता है कि १६५० से कुल पूँजी रा निर्माण वर्मा में १० से २० प्रतिशत के बीच, जापान में २४ से ३० प्रतिशत के बीच, लका में १० से १३ प्रतिशत के बीच श्रोर फिलीपाइन्स में ७ से ८ ५ प्रतिशत के बीच रहा है। भारत के सम्बन्ध में तुलनात्मक आँकडे १० से ११ प्रतिशत हैं। कुछ लेटिन श्रमरीकी देशों में इस सम्बन्ध के आँकडे १५ और २६ प्रतिशत के बीच पायः रहे है। कमी कभी स्तर कुछ ऊँचा भी हुआ है। पूर्वी योख्प के कुछ देशों में जैसे जैकोस्लोवेकिया श्रीर पोलैंगड में पूँजी निर्माण की दर २० श्रीर २५ प्रतिशत के बीच रदी है। नये विकासोन्मुख देशों में विनियोग की दर वर्तमान स्तर से निश्चय ही बहाई जा सकती है—यदि उपयुक्त विनियोग नीति का अनुसरण किया जाय स्त्रीर यदि राज्य द्वारा विकास कार्यंक्रम आरम्भ क्रिये जायँ। इसलिये भारत के सम्बन्ध में यह धारणा बनाना कि प्रयत्न करने से विनियोग की दर ऊपर बताये गये स्तर तक बढाई जा सकती है आसगत नहीं हो सकता"।

प्रथम पचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश में जीवन की ब्राधारमूत वस्तुश्रों के उपभोग को पुन. उस स्तर पर ले श्राया जाय जिस पर वह महायुद्ध के पूर्व था। द्वितीय पचवर्षीय योजना इस सम्बन्ध में एक पग श्रागे है श्रीर उसका लक्य यह है कि योजना काल के श्रन्तर्गत कुल उपभोग की मात्रा में लगभग २०% श्रीर व्यक्ति उपमोग की मात्रा में १२ से १३ प्रतिशत की वृद्धि हो। कुछ विशेष वस्तुश्रों के प्रति व्यक्ति उपभोग के श्राकड़ों में इस वात का श्रामाय मिलता है कि किवनी अधिक प्रगति का अनुम न लगाया गया है। वोष्टिक सलाहकार समिति (Nutrition Advisory Committee) ने यह श्रनुमान लगाया था कि एक वयस्क के प्रतिदिन के सन्तुलित आहार में कम से कम १४ आँस अन होना चाहिये। १९५०-५१ में प्रत्येक वयस्क प्रतिदिन १३ अर्थेस अन का आरेसत उपमोग करता या। किन्तु प्रथम पचवपीय योजन। के परिसाम स्वरूप १९५३ ५४ में प्रतिब्यस्क प्रतिदिन अन्न के उपभोग की मान्ना बढकर १५ श्रीस ही गई। परन्तु चने ब्रोर दालों का उपभोग ब्राभी भी निम्नतम ब्रावश्यकतात्रों से कम है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यस्क को प्रतिदिन २ई से ३ स्रोस तक चने स्रोर दालों का उपमोग करना चाहिये। किन्तु बहती हुई जनसख्या श्रीर प्रति व्यक्ति की श्राय में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप श्रन्न के उपमोग में वृद्धि होगी श्रवणव द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के भीतर खाद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया नाना चाहिये। "दूध, धी, मास, मछली, श्रहे, चर्बी, फल, तरकारियाँ श्रीर चीनी के उपभोग का वर्तमान स्तर निम्नतम श्रावश्यक्तात्रों से बहुत कम है। दितीय योजना में रहन-सहन के श्रिधिक कॅचे स्तर की व्यवस्था करने के लिये पशु-पालन, मछली-उद्योग, मुर्गी पालन, तरकारियों की खेती ग्रीर श्रन्य प्रकार की खाद्य सामग्री के उत्पादन पर विशेष स्यान देना चाहिए"। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत में प्रति व्यस्क प्रति वर्ष के हिसाव से १५ गन स्ती कपहे का उपमोग करता या श्रोर प्रयम पचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर कपडे के श्रीसत उपमोग का वहीं स्तर पुनः प्राप्त कर लिया गया है। स्ती कपडे की जाँच समिति की सिफारिश को मानकर द्वितीय पचवर्षीय योजना में १९६० तक प्रति व्यक्ति स्ती कपडे के श्रीसत उपभोग को १८ गज करने का लक्ष्य निर्घारित किया गया है।

प्राथमिकता का क्रम-प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, सिंचाई

श्रीर विजली की राक्ति के विकास को प्रमुख महत्व दिया गया था श्रीर हन महों पर योजना की कुल लागत की ४३ २% रकम व्यय करने का श्रनुमान था। इसके विपरीत हितीय पचवर्षीय योजना ने उत्रांगों को प्राथमिकता दी है। प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रन्तर्गत उत्रोंगों पर कुल लागत की ७ ६% रकम व्यय के लिये निर्घारित थी जबिक हस दूसरी योजना में (जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया है) कुल लागत का १८ ५% व्यय होने का श्रनुमान लगाया गया है। प्राथमिकता के कम में परिवर्तन करने के दो कारण हैं: (श्र) कृषि, सिचाई श्रीर शक्ति (विद्युत) ये निकास पर प्रथम पचवर्षीय योजना में पहले ही से पर्याप्त स्थान दिया गया है, श्रीर विकास की वर्तमान गित के हारा भी उन्हें पूर्ण रूप ने निकलित किया जाना सभव है, श्रतएव उन पर कोई विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता नहीं है, श्रीर (व) श्रव यह श्रनुमान किया जाने लगा है कि देश के श्राधार भूत उत्रोंगों को वर्गर विकलित किए हुए यह समय नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय श्राय में एक किंचे स्तर तक वृद्धि की जा सके श्रायवा वेरोजगारी की समस्या का ही कोई हल खोजा जा सके।

द्वितीय पचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य है कि देश की राष्ट्रीय श्राय में प्रति तालिका २ सरकारी क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कुल लागत के तुलनात्मक आकडे

1	प्रथम य	ोजना ।	द्वितीय य	जना
<u>.</u>	कुल लागत)		कुल लागत	
	(करोड़ रुपयों में)	कुल का प्रतिशत	(करोड़ वपयों में)	कुल का प्रतिशत
१ कृषि श्रीर सामुदायिक विकास	३५७	१५.१	५६ ८	११८
२ सिंचाई श्रीर शकि (विजली)	६६१	रद १	F \$3	88.
३ परिवहन श्रीर सचार	प्रप्	४२३६	१३८५	रदं€
 उद्योग श्रीर छिनिन 	१७६	७६	550	१८५
भ्र निर्माण कार्य श्रीर				95.10
धामानिक सेवार्ये	भ्रहर	२२ 🖣	ERX	१६७
६ विविध	ĘĘ.	ه ځ و	33#	1 २१
कुल	२३५६	१००%	8240	१००%

वर्ष लगभग ५% की वृद्धि हो श्रीर इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये पाँच वर्ष की श्रविष में कुल ६२०० करोड़ रुपये का वास्तविक विनियोग (Net Investment) करने की श्रावश्यकता होगी, जबिक प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत मूल रूप में वास्तविक विनियोग की रकम ३१०० करोड़ रुपये थी। श्रनुमान है कि इसमें से ३८०० करोड़ रुपये की रक्षम का विनियोग सरकारी चेत्र पर होगा, जिसकी ज्यवस्था सरकार श्रपने वित्तीय साधनों से करेगी श्रीर शेप २,४०० करोड़ रुपये निजी चेत्र पर व्यय होंगे, जो निजी विनियोग द्वारा उपलब्ध होंगे। विकास सम्बन्धी व्यय में ४८०० करोड़ रुपयों की कमी जो कि प्रस्तावित वास्तविक विनियोग के कारण सरकारी चेत्र में श्रावश्यक होगा तालिका न २ में दिया हुश्रा है।

दितीय पचवर्षीय योजना की 'त्राघारभूत नीति' यह है कि (स्र) इस्पाव, यन्त्र-निर्माण, खनिज पदार्थ स्नादि के प्रमुख ग्रीर द्वाघारभूत उद्योगो पर यथासमब स्निषक से श्रिविक घन विनियोग किया जाय स्नौर इसके विपरीत सामान्य उपभोग में प्रयुक्त होने वाली वस्तुन्नों के उद्योगों पर यथासंभव कम से कम घन व्यय किया जाय, स्नोर (व) छोटे पैमाने के व घरेलू उद्योग-धर्घों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाय, चाहे इस प्रयास में बड़े पेमाने के उद्योगों की हार्नि ही क्यों न हो।

उद्योगो श्रीर रानिज पर प्रस्तावित ८० करोड़ रुपयों के व्यय में से ६१७ करोड़ रुग्यों के लगभग वहें श्रीर मध्य वर्ग के उद्योगों पर, ७३ करोड़ रुपये खिनज के विकास पर श्रीर २०० करोड़ रुपये प्राम्य तथा छोटे उद्योगों पर व्यय किया जायगा। उद्योगों में से लोड़े श्रीर इस्पात उद्योग को सबसे श्रीवक भाग मिलेगा। प्रमुख विशेषता दितीय योजना की छोटे श्रीर कुटीर उद्योगों को प्रायमिकता देने की है, जिस पर २०० करोड़ रुपया व्यय करने के लिए नियत किया गया है।

यद्यपि द्वितीय पचवर्षीय योजना में उद्योगों श्रीर खनिज पदायों को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी गई है, किन्तु कृषि, परिवहन श्रीर सामाजिक सेवाश्रों की उपेक्षा नहीं की गई है। श्रनुमान है कि १६५५-५६ से १६६०-६१ तक द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत खाद्यान्न का उत्पादन ६५० लाख से ७५० लाख टन, रई का ४२ लाख से ५५ लाख गाँठ, गन्ने का ५०० लाख टन से ७००१ लाख टन, तिलहन का ५५ लाख से ७० लाख टन, चाय का ६४४ करोड़ से ७० करोड़ पौंड हो जायगा। सिंचाई की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल ६७ करोड़ एकड़ हो जायगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवाशों श्रीर सामुदायिक योजनाशों के मण्डलों की सख्या ५०० से २८०० श्रीर ६२२ से ११२० कमशा. हो जायगी। द्वितीय योजना की विशेषता यह है कि इसमें श्रनेकों कृषि उत्पत्ति की वस्तुयें जैसे

नारियल, सुपादी, लाख, कालीमिच श्रीर व्यक्कफल श्रादि, जिनकी श्रोर प्रयम योजना में घ्यान नहीं दिया गया था, इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं श्रीर उनके विकास का ध्येय निश्चित कर दिया गया है। द्वितीय योजना में कृषि वा विकास श्रीषक विस्तृत दंग पर होगा।

जहाँ तक परिवहन से सम्बन्ध है भारतीय रेलों की यात्रियों तथा माल ले जाने की शक्ति नहा दी जायगी। रेलपथ १० करोड़ ८० लाख मील से बहाकर १२ करोड़ ४० लाख मील थोर माल की हुलाई १२ करोड़ ने १६ करोड़ २० लाख हो जायगी। इसी काल मे राष्ट्रीय सब्दें १२,६०० मील से १३,८०० मील थ्रोर कची सब्दें १०७,००० मील से १२५,००० मील बहकर हो जायगी। तटीय व्यापार में जलयाना द्वारा टनेंज ३'२ लाख जी० श्चार० टी० में बहकर ४७ लाख जी० श्चार० टी० हो जायगा। भारतीय वन्दरगाहों की माल चढ़ाने श्चोर उतारने की शक्ति २ करोड़ ५० लाख टन से बहकर ३ करोड़ २५ लाख टन हो जायगी।

तालिका २ मे प्रकट होता है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (अ) हाथ के करघे और राक्तिचालित करघे से तैयार किये गए कपहे, राषायनिक पार्टा, लोहे व इस्पात, एल्यूमीनियम और कोयले के उत्पादन में छव से अधिक वृद्धि होगी, (ब) मारी रषायनों, धात के सामान, अभ्रक, मेगनीज, साहिक्लों, सीने की मशीनों और विजली के उत्पादन में अपेचाकृत कम वृद्धि की जायगी, और (स) मिल में तेयार होने वाले सूती कपड़ों, ऊनी सामान, चीनी, साबुन, जूलों और वनस्पति तेलों के उत्पादन में और भी कम वृद्धि होगी। इस प्रयास में यह त्यान रागा गया है कि प्राधारमूत और प्रमुख उद्योगों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन के द्वारा आत्मिनभैरता के अधिक से अधिक निकट पहुँचा जाय।

रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता (Employment potential)
—िद्वितीय पचवर्षीय योजना का एक मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि रोजगारी के पर्याप्त अवसर उत्पन्न किए जार्ये। भागतीय अर्थं व्यवस्था की इसी आवश्यकता के फलस्वरूप कृति की अपेद्धाकृत उद्योगों पर अधिक वल दिया गया है। इस योजना को इतना अविक विस्तृत बनाने का आशिक कारण यह है कि वेकारी की समस्था को इल करने का प्रयत्न किया जाय। द्वितीय योजना काल में नये काम करने वालों की सस्था जो वर्तमान सस्था में जुड़ जायगी लगभग १ करोड़ के अनुमान की गई है। यदि उसमें से ३८ लाख व्यक्तियों को, जो नगर की मजदूर सस्था में वृद्धि अनुमानित है, प्रयक कर लें तो जितने मजदूर देहातों के दोत्र में वहेंगे उनकी

छल्या ६२ लाख के लगभग श्राती है। यदि एक करोड़ नये अमिकों की छल्पा में ५३ लाख पहले के वेकारों की सख्या (२५ लाख नगरों की श्रीर २८ लाख माम्य क्षेत्र में) जोइ दी जाय तो कल वेकारो की सख्या १६५६-६१ में लगभग १ ५३ करोड़ हो लायगी। इतने नये व्यक्तियों को काम करने का श्रवसर प्राप्त करवाना सम्भव नहीं है। कदाचित ८० लाख व्यक्तियों के लिये दिवीय योजना में काम के नये श्रवसर दिये जा सकते है। किंतु रोजगारी के श्रतिरिक्त श्रवसरी की केवल योजना-मान गढ जेने से तो समस्या इल नहीं की जा सकती। व्यापार श्रीर उद्योगों का प्रसार मात्र करके यह आशा करना कि उनके द्वारा श्रव श्रधिक व्यक्तियों की खपत अपने श्राप होने लगेगी व्यर्थ है। इस समय ऐसे श्रनेक व्यवसाय हैं जिनमें श्राव-श्यकता से श्राधिक लोगो को खपा लिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि जैसे-जैसे उन व्यवसायों में काम की वृद्धि होगी, वैमे-वैसे पहले से ही श्रधिक सख्या में काम करने वाले व्यक्तिया पर काम का बोक्त अधिक होता जायगा श्रीर इस प्रकार उन व्यवसायों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो सकेगी। कुछ उद्योगों स्रोर व्यापारिक सस्यास्रों में स्राधिनवीकरण की योजनाएँ लागू किये जाने की भी सम्मावना है, जिसका फल यह होगा कि प्रसार किये गये उन उद्योगों में रोजगार के लिये और भी श्रिषिक कम सख्या में लोगों की खपत की जा सकेगी! योजना त्रायोग इन कठिनाइयो से भली भाँति परिचित है। "रोजगारी में ऋतु-मानित वृद्धि लाने के लिए वित्त और उपयुक्त नीति का अनुसरण करने की आव-श्यकता तो होगी ही, उसके साथ-साथ सुगठित सङ्गठन की भी व्यवस्था करनी पहेगी । वेकारी दूर करने के लिये छोटे छोटे उद्योग-धन्धों को विकस्ति करने पर श्रिधिक बल दिया गया है, किन्तु यह स्पष्ट है कि सुव्यवस्थित प्रयत्नों के श्रमाव में इनका उस सीमा तक विकास श्रीर प्रसार नहीं हो सकता। काम करने के श्रवसर पदान करने का शर्थ केवल नौकरियों की जगहें वढा देना मात्र नहीं है। यह जगहीं के बढ़ा देने के प्रति जनता की प्रतिक्रिया पर निर्मर करता है। रोजगारी की न्यवस्था करने का यह मी श्रर्थ है कि भिन्न-भिन्न कर्मचारियों के लिए जितने प्रशिच्या की स्रावश्यकता है उसे पदान करने की सुविधास्रों का प्रवन्ध किया जाय। यह न्नतुमान लगाया गया है कि श्रनेक चेत्रों में उत्पादन वृद्धि होने के फलस्वरूप उसी श्रनुपात में थोडी या बहुत मात्रा में रोजगारी में भी वृद्धि होगी। श्रतएव इस बात की श्रावश्यकता है कि अत्यधिक अभिनवीकरण पर नियत्रण किया जाय । साथ ही यह भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं पहले से रोजगार प्राप्त लोगों की मजदूरी बढ जाने से उस वस्तु की मौंग में कमी न आ जाय और इस प्रकार वेकार लोगों की स्पति श्रीर भी न विगष्ट जाय।"

वित्त व्यवस्था — योजना की सफलता वित्त की प्राप्ति पर निर्भर है। भारत में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय बचत का स्तर राष्ट्रीय श्राय के अनुपात में बहुत कम है। इसिलये विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना श्रावश्यक हो जाता है। द्वितीय योजना के श्रनुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय का प्रवन्ध तालिका न० ३ में जैसा दिखाया गया है किया जायगा। उसमें से ८०० करोड़ रुपया केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारों की श्रांतिरिक्त श्राय से, १२०० करोड़ रुपया सरकारी श्र्या से, १२०० करोड़ रुपया सरकारी श्र्या से, ४०० करोड़ रुपया श्रन्य वजट में व्यक्त श्राय खोतों से, ८०० करोड़ रुपया विदेशी सहायता से श्रीर १२०० करोड़ रुपया घाटे के बब्द से प्राप्त किया जायगा। इसमे ४०० करोड़ रुपयों की कमी पड़ेगी जिस का प्रवन्ध या तो नये करों मे प्राप्त श्राय द्वारा श्रथवा श्रियक घाटे के श्रर्य प्रान्ध द्वारा या श्रिक विदेशी सहायता द्वारा या द्वितीय योजना के विस्तार को कम करके किया जायगा।

सरकारी चेत्र में विकास योजनाओं का अर्घ प्रबन्ध एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। पाँच वर्षों की अविध में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से लगभग १००० करोड़ रुपयों का व्यय तो शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अन्वेपण श्रीर राष्ट्रीय विकास ब्रादि पर चालू व्यय के रूप में होगा। इस प्रकार के ज्यय से पूँजी का प्रत्यज्ञ रूप से निर्माण नहीं होता और इसलिये विनियोजित न्यय नहीं माना जाता। ऐमे चेत्रों पर व्यय चालू आय स्रोतों से पूरा किया जाता है। इसलिये वास्तविक विनियोग उद्म०० करोड़ रुपयों का है श्रीर इसका प्रबन्ध श्राण द्वारा किया जा सकता है। विकासोन्मुख ग्रर्थं व्यवस्था में जहाँ पर पूँजी निर्माण सम्बन्धी न्यय उत्तरोत्तर बढता जाता है, वहाँ यह वाछनीय होगा कि उसके एक अशा का प्रबन्ध कर से प्राप्त अतिरिक्त आय में से किया जाय। इस सिद्धान्त पर प्रथम योजना की रिपोर्ट में जोर दिया गया था श्रीर इस पर फिर जोर देना चाहिये। योजना के अर्थ प्रवन्ध की व्यवस्था में चालू आय में से केवल ८०० करोड़ रुपयों के प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है जब कि चालू व्यय के श्रनुसार १००० करोड़ रुपयों की ग्रावश्यकता है। रेलवे से प्राप्त १५० परोड़ रुपयों की आय को चालू श्राय का भाग सममना चाहिये। इसका श्रर्थ यह है कि कुल चालू श्राय से योजना के लिये प्राप्त वित्त ६५० करोड़ रुपयो का हुआ जब कि चालू व्यय की मात्रा १००० करोड़ रुपया अनुमान की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकारी श्राय में कुछ मी बचन नहीं है जिसका प्रयोग ३८०० करोड़ रुपये के विनियोग के लिए किया जाय, वास्तव में ५० करोड़ रुपयो का घाटा है। दूसरे शन्दों में कुल ३८०० वरोड़ पुना जी निर्माण का श्रय-पानम व्यक्तिगत बचत द्वारा

ही करना सम्मव होगा। यद ८०० करोड रुपयों की विदेशी वित्तीय सहायता को अलग कर दिया जाय क्योंकि यह विदेशों की वचत पर निर्मर है और २०० करोड़ रुपयों की सहायता पौराड पावने की वची हुई रूप से प्राप्त की जाय, तो देश की आरिक व्यवस्था के अन्तर्गत चालू बचत की मात्रा जो कि सरकारी योजनाश्चों में विनियोजित की जायगी, २८५० करोड़ रुपयों के बराबर टहरती है। यदि यह मान लिया जाय कि ४०० करोड़ रुपयों को कमी सरकारी बचत द्वारा पूरी करली जायगी तो व्यक्तिगत बचत की मात्रा जो सरकारी चेत्र में स्थान। न्तरित की जायगी वह २४५० करोड़ रुपयों की होगी।

तालिका न० ३ सरकारी क्षेत्र के लिये वित्ता के स्रोत

(करोड क्पयों में)

 चाल् श्राय के श्रितिरिक्त से (1) १६५५-५६ में प्रचितित कर की दर से (1) श्रितिरिक्त कर मे चनता से प्राप्त श्रृत्य से (1) बाजार श्रृत्य (Market loans) (11) छोटी वचत ३. वजट के श्रन्य श्राय स्रोतों से (1) रेल का विकास कार्यक्रम में योगदान (11) प्रोविडेन्ट फरड तथा श्रुत्य शीधों के श्रन्तर्गत जमा धन से 	व्यवा म)
(ii) श्रतिरिक्त कर मे र जनता से प्राप्त श्रृत्य से (1) बाजार श्रृत्य (Market loans) (11) छोटी बचत स बजट के श्रन्य श्राय स्रोतों से (1) रेल का विकास कार्यक्रम में योगटान (11) प्रोविडेन्ट फरड तथा श्रुत्य शीर्षों के श्रन्तर्गत जमा धन से	500
र जनता से प्राप्त भ्रम्ण से (1) बाजार भ्रम्ण (Market loans) (11) छोटी वचत से बजट के श्रम्य श्राय स्रोतों से (1) रेल का विकास कार्यक्रम में योगटान (11) प्रोविडेन्ट फरड तथा श्रम्य शीर्षों के श्रन्तर्गत जमा धन से	340
(1) बाजार ऋण (Market loans)	४५०
(11) छोटी वचत ३. वजट के श्रन्य श्राय स्रोतों से (1) रेल का विकास कार्यक्रम में योगटान (11) प्रोविडेन्ट फरड तथा श्रन्य शीर्षों के श्रन्तर्गत जमा धन से	१२००
 वजट के श्रन्य श्राय स्रोतों से (1) रेल का विकास कार्यक्रम में योगटान (11) प्रोविडेन्ट फरड तथा श्रन्य शीर्षों के श्रन्तर्गत जमा धन से 	600
(1) रेल का विकास कार्यक्रम में योगटान (11) प्रोविडेन्ट फरड तथा श्रन्य शीर्षों के श्रन्तर्गत जमा धन से	५००
(11) प्रोविडेन्ट फरह तथा श्रन्य शीर्षों के श्रन्तर्गत जमा धन से	800
	१५०
	२५०
४. विदेशों के स्रोतों से	500
५ पाटे के श्रयं प्रवन्ध से	१२००
६ कमी—देशीय श्रतिरिक्ति स्रोतों से पृरी की वायगी 👯 🏃	¥00
कुल	8500

"क्या यह मान लेना युक्तिसगत न होगा कि २४५० करोड़ रुपयों तक की व्यक्तिगत बचत की रक्षम सरकार को विनियोग के लिये प्राप्त हो जायगी? इस सबध में वाजार मे ऋण लेने, छोटी मात्रा की बचत श्रोर घाटे के अर्थ प्रवन्ध में अन्तर बहुत साधारण महत्व की बात है। ये सब व्यक्तिगत बचत को अपनी श्रोर से अयया मृत्य की वृद्धि द्वारा वरवश राजकीय कोष मे पहुँचाने के दक्क है। व्यक्तिगत बचत की मात्रा राजकीय कोष में कितनी श्रोर किस दक्क से पहुँचती है जनता की अपनी सम्पत्ति को रोकड़, सरकारी ऋण पत्रों, तथा छोटी मात्रा वाले सेविंग

सर्टीफिकेट के रूप में या जमा घन के रूप में रखने की इच्छा पर निर्भर रहता है। जन तक कुल बचत जो सरकारी कोप में पहुँचती है पर्याप्त मात्रा में रहती है तब तक इस बात से लोग उटासीन रहते हैं कि बचत की रक्षम श्रृष्ण पत्र, छोटी मात्रा के रे. थिंग सर्टीफिकेट श्रपना स्र स्कारी नोट के रूप में है। ऐसी स्थित में सबसे प्रमुख महत्ता की बात यह जानने में है कि बया जनता की व्यक्तिगत बचत की मात्रा को हम व्यक्तिगत चेत्र की श्रावश्यकता से उतनी श्रिषक होने की श्राशा कर स्कते हैं जितनी कि सरकारी चेत्र की श्रावश्यकता है। व्यक्तिगत बचत इस हिंछ कोण से पर्याप्त तभी हो सकती है जब कि उपभोग पर श्रावश्यक नियत्रण लगाया जाय। दूसरे शब्दों में इसका शर्थ है कि प्रस्यच्च रूप से जितने ही कम श्रावणत में जनता की बचत सरकार को श्राविरक्त करों की श्राय के रूप में श्रयवा सरकारी श्रावक्तमों के लाभाश के रूप में होगी उतनी ही श्रिषक श्रावश्यक से मा से श्रागे ने बढेंग।

"केन्द्र श्रीर राज्यों के बजट स्रोतों में जो श्राय करो, श्रूण, तथा अन्य उपायों से प्राप्त की जा सकती है वह लगमग २४०० करोड़ कपये की है। घाटे के श्रूर्य प्रवन्ध द्वारा लगभग १२०० करोड़ कपयों की श्रीर श्राय बढाई जा सकती है। इस मात्रा में यदि ५०० करोड़ कपयों की विदेशों वित्तीय सहायता श्रीर जोड़ दी जाय तो कुल श्राय जो सरकारी जेज में योजना के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये प्राप्त होगी वह ४४०० करोड़ कपया होती है। इससे ४०० करोड़ कपयों की कमी रह जाती है जिसके प्राप्त करने के विस्तृत उपायों को बाद में ढूँढा जायगा। यह तो मान लिया गया है कि यह कमी देश के स्रोतों में वृद्धि द्वारा ही पूरी वी जायगी। घाटे के श्रर्थ प्रवन्ध की सीमा को वित्ताराधीन रखते हुये जिसके चारे में ऊपर सकत किया जा जुका है तथा इस बात को भी वित्ताराधीन रखते हुए कि जिस अर्थ प्रवन्ध की योजना की रूपरेखा यहाँ बताई गई है उसमें श्रूरण पर श्रावश्यकता से श्रिषक मरोसा किया गया है, इस कमी को पूरा करने का एक ही उपाय जिस पर निर्भर रहा जा सकता है वह करों का श्रारोग्य, तथा सम्भावित सीमा तक सरकारी उपकर्मों का लामाशा है।"

द्वितीय योजना को इस बात का पूरा शान है कि १२०० करोड़ रुपयो के घाटे के अर्थ प्रबन्ध किये जाने से मुद्रास्कीति की दशा उत्पन्न हो जायगी। योजना बनाने वालों ने ऐसी स्थिति से बचाव के लिये अनेक प्रतिबन्दों का निर्देश दिया है। उनके विचारानुसार:—

"सबसे प्रमुख सरज्ञ्या का उपाय बहुत बड़ी मात्रा मे खाद्याच एकत्रित करके

रख लेना होगा जिससे जब जब मुद्रास्फीति का प्रमाव जोर पकडे तो उसका निरा-करण किया जा सके। जहाँ की श्राधिक व्यवस्था में तीव्रगति से विकास का प्रयत्न किया जा रहा है वहाँ चाहे कितनी ही सममत्तारी से अर्थ प्रवन्य क्यों न किया जाय मुद्रास्फीति का मय पूर्णतया मिटाया नहीं जा सकता। मुद्रास्फीति से सबसे उत्तम बचाव का ढग मुद्रास्कीति न होने देना है परन्तु ऐसी नीति जिसमें मुद्रास्फीति तो हो पर उसके दुष्प्रभावों से बच निकलें कभी सफल नहीं हो सकती । इस सम्यन्य में कुछ जोखिम तो उठानी ही पहेगी । इस जोखिम से बचने का सबसे ग्राधिक राफल उपाय खाद्याननों के ग्रीर श्रन्य ग्रावश्यक वस्तुत्रों के भगडार पर श्रधिकार रखना है ताकि जब इनकी कभी पढे तो बाजार में इनकी पृति वढा दी जाय । मारतीय आर्थिक व्यवस्था में अन्न श्रोर वस्त्र के मूल्यों का विशेष महत्व है श्रीर इनमें श्रधिक वृद्धि हर प्रकार से रोकना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। जब तक इन वस्तुओं के मूल्य को युक्ति-छगत स्तर पर रक्खा जा सकेगा तब तक देश की अधिकाश जन एल्या के जीवनस्तर की लागत नियत्र में रहेगी। अन्य वस्तुश्रों के मूल्यों में वृद्धि श्रपेज्ञाकृत कम महत्ता की बात होगी यद्यपि व्यवस्था में किसी भी वस्त के मुल्य मे श्रात्यधिक वृद्धि होने से द्रव्य के अपेद्धाकृत कम आवश्यक उपयाग की वस्तुयों पर व्यय किये जाने का मय है। यदि ऐसा हो जाय तब उसे ठीक करने का प्रयन्न करना आवश्यक होगा। मुद्रास्फीति के प्रभावों से बचने का द्सरा उपाय विवेचनात्मक (discriminating) परन्तु तुरन्त ही करारोप के उपाय का अनुसरण कुछ वन्तुओं का आवश्यकता से अधिक उपयोग होने से वचाने के लिये श्रोर ऋत्यविक लाभाश तथा श्रनायास प्राप्त हुये लाभाश को रोक देने क लिये (जिनका कि घाटे के ग्रर्थ प्रवन्ध में उत्पन्न हो जाना स्वामा-विक ही है) अत्यन्त आवश्यक होगा। अन्त में, कन्ट्रोल के उपाय का जिसमें राशनिंग तथा मात्रा नियत करना श्रादि सम्मिलित होंगे उपभोग के उचिन सीमा से आगे जाने से रोकने के लिये तथा दुर्लंग वस्तुआं और कच्चे माल आदि के प्रयाग में मितव्यता लाने के लिये प्रयोग करना आवश्यक होगा। परन्तु श्रवीत का श्रानुभव बताता है कि श्रावश्यक प्रयोग की वस्तुश्रों पर कन्ट्रोल लम्बी समया-विव के लिये विश्वस्त उपाय सिद्ध नहीं होंगे। इस कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि इसके अर्तिरक्त ग्रन्य बचाव के उपायों का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाय क्योंकि योजना के कार्य-क्रम में कमी करने की सम्भावना तो ब्रात्यन्त कठिनाई में पड़ने पर ही करना उचित होगा।"

त्रालोचना—दितीय पचवर्षीय योजना की धारणा प्रयम योजना की श्रपेचा श्रधिक व्यापक श्रीर सुदृढ है। जब यह योजना समाप्त होगी तो प्रति व्यक्ति की वास्तविक स्थाय में श्रपेक्ताकृत श्राधिक वृद्धि होगी श्रीर लोगों की प्राधिक स्थिति में निश्चित रूपत्से सुधार होगा। द्वितीय योजना की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताऍ हैं:

(१) इमके श्रन्तर्गत भौतिक (physical) नियोजन पर बल दिया गया है, न कि वित्तीय (financial) नियोजन पर । इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य भीतिक उत्पादन के रूप में निर्घारित किये गये हैं जैसे इतने लाख टन इस्पात. कोयला, सीमेन्ट आदि श्रोर फिर इन भिन्न-भिन्न बस्तुश्रों के लक्ष्यों के लिये वित्त को निर्घारण किया गया है। प्रथम पचवपीय योजना के श्रन्तर्गत पर्याप्त दर से व्यय नहीं किया जा सका और वास्तविक रूप में विकास का क्रम भी नहीं जारी रह सका, क्योंकि वह वित्तीय नियोजन पर श्राघारित था। भौतिक नियोजन मे इस बात पर बल नहीं दिया जाता है कि अपुक योजना पर कितनी मात्रा में बन व्यय किया गया है, वरन उसमे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि उस वस्तु के उत्पादन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। इसका परिग्राम यह होता है कि नियोजन मे श्राधिक वास्तिविकता श्रा जाती है। किन्तु भौतिक श्रीर विचीय लक्ष्यों में समन्त्रय स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि निम्न विषयों पर विस्तृत और यथार्य स्चना प्राप्त की जाय (य) भिन्न भिन्न वस्तुश्रो की प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने में कितनी मात्रा में कच्चे माल, शक्ति, अम श्रादि की छावश्यकता होती है. श्रोर (व) भविष्य में इन विभिन्न कच्चे मालो व अम श्रादि का क्या-त्या मूल्य होगा । श्रभाग्यवरा भारत मे इनसे सम्बन्धित सही-सही श्रीर विश्वसनीय स्वनाएँ उपलब्ध नहीं हैं स्त्रोर इसीलिए यह स्त्राशका उत्पन्न होती है कि भौतिक नियोजन से समस्या इल होने के स्थान पर कहीं और जटिल न हो जाय। ''लोकतान्त्रिक नियोजन के अन्तर्गत आधिक दृष्टि से पिछुड़े हुये एक ऐसे देश में जहाँ का शासन-यत्र शार्धिक नियोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता और जहाँ का प्रत्येक विभाग त्र्रोर प्रत्येक मन्त्रालय श्रपनी चलाई हुई योजनाश्रो पर यथासभय श्रिषिकतम घन व्यय करने का प्रयत्न करता है, वित्तीय नियोजन के स्थान पर भौतिक नियोजन पर बल देने का श्रानिवार्यं परिणाम यह होगा कि (क) श्रत्यिषक धन का श्रपन्यय होगा श्रीर (ख) श्रिषक मात्रा में सरकारी न्यय के कारण मुद्रास्फोति की प्रवृतियों के उत्पन होने की सभावना है। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वित्त मन्त्रालय ने यह सिद्धात सामने रखा कि विशेष परिस्थि-तियों को छोड कर अन्य स्थितियों मे किसी को भी निर्घारित रकम से अधिक व्यय करने भी स्वीकृति नहीं दो जानी चाहिये ख्रोर इस प्रकार सरकारी व्यय पर कड़ा नियम्रण स्थापित किया गया। किन्तु जहाँ तक भौतिक नियोजन का सम्बन्ध है, यह तर्क जिल्कुल निरर्थक है। चूंकि द्वितीय पचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश है कि निर्धारित किये गये मौतिक लक्ष्यों (physical targets) की पूर्ति की जाय, अतएव मिन-भिन्न विभागों और मन्त्रालयों को अपने निर्धारित वित्त से कुछ अधिक व्यय कर सकने की छूट प्राप्त होगी। सरकारी व्यय में कभी करना अथवा योजना-काल के अन्तर्गत अनुमानित रकम का विनियोग न कर सकना योजना का एक दोप है। किन्तु उससे भी बड़ा दोप यह है कि धन का अपव्यय किया जाय और उसके फलस्वरूप सरकारी धन की हानि तो हो ही साथ ही साथ अपन्यय अपनियन्त्रित मुद्रास्कीति के हुष्परिगामों का भी सामना करना पडे । । इससे यह अन्दर्शना है कि वित्तीय नियोजन से सम्बद्ध खतरो और भूलों से बच्चने के लिये अत्याधक सावधानी की आवश्यकता है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वित्तीय नियोजन के स्थान पर भौतिक नियोजन पर बल दिये जाने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक वास्तविकता आ गई है।

- (२) द्वितीय योजना ने प्रमुख रूप से श्रीद्योगिक विकास पर वल दिया है। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृपि श्रीर शक्ति (विजर्ला) के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस प्रकार द्वितीय योजना से देश का श्रार्थिक विकास श्रिषक सन्तुलित हो जायगा। श्रीद्योगीकरण पर इसलिए जोर दिया गया है कि (श्र) प्रथम योजना के अन्तर्गत कृषि श्रीर सिचाई में पहले ही से काफी प्रगति हो जुकी है श्रीर इसीलिए उद्योगों पर श्रीधक स्थान देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि प्रथम योजना के अन्तर्गत उद्योगों की उपेचा की गई थी; (व) यदि हम प्रमुख रूप से केवल कृषि पर ही अपना ध्याम वेन्द्रित करते हैं तो यह समव नहीं है कि तेजी से बढती हुई जनसख्या के साथ-साथ वेरोजगारी श्रीर श्राशिक रोजगारी की समस्या को इल किया जा सके। श्रीन्योगिक विकास को प्राथमिकता देने का यह उद्देश्य है कि वेरोजगारी श्रीर श्राशिक रोजगारी की समस्या को इल करने मे सहायता मिले, श्रीर (स) पहले की श्रपेचाकृत यह श्रीधक स्पष्ट रूप से श्रनुभव किया जाने लगा है कि देश की श्राधिक सम्पन्नता अन्तत श्रीद्योगीकरण से सम्बन्व खती है।
- (३) प्रथम पचवषीय योजना की श्रपेज्ञाकृत ब्रितीय योजना के श्रन्तर्गत 'सामाजिक न्याय' पर श्रधिक ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना का उद्देश्य यह या कि देश में महासुद्ध के पूर्व दैनिक उपयोग की वस्तुश्रों की जिस मात्रा में खपत

¹ Vide the Author's article on "Some Basic Considerations about the Second Five-year Plan" in the Gommerce, dated July 2, 1955, page 15

होती थी, उसी स्तर को फिर से ले आया जाय। द्वितीय योजना एक पग श्रीर आगे वढ गई और उसका लक्ष्य यह है कि उसके समाप्त होने पर देश के कुल उपमोग में लगभग २०% और प्रति व्यक्ति के उपयोग में १२-१३ प्रतिशत की बृद्धि हो। यह समय होगा या नहीं, किन्द्र दितीय एचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक राष्ट्रीय श्राय की १०% राशि करों के रूप में लो जायगी, जबकि श्रमी तक करों के रूप में लो जाने वाली राशि इसकी ७% है और यह निर्माण, सामाजिक कल्याण श्रादि पर श्रिषक रकम व्यय करने की व्यवस्था की गई है क्योंकि इनके द्वारा धनिकों की श्रमें चा निर्धनों को श्रिषक लाम होता है। इसी कारण दितीय पचवर्षीय योजना को प्रगतिशील कहा जा सकता है।

नि: सदेह द्वितीय पचवर्षीय योजना में ऐसे श्रानेक दोष हैं जो इसे एकाङ्गी श्रीर श्रात-श्राकाची (over-ambitious) बना देते हैं। सबसे पहले तो यही तर्फ रखा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में द्वितीय योजना के लिए यह समय नहीं है कि वह पाँच वर्ष की अवधि में कुल ६,२०० करोड़ रुपए के वास्तविक विनि-योग (net investment) का प्रबन्ध कर सके, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि १६५५-५६ में राष्ट्रीय आय की जों ७.३% राष्ट्रीय बचत होगी, उसे १६६०-६१ तक राष्ट्रीय आय की १० ७% कर देना संभव नहीं होगा। इस वारणा का समर्थन कुछ ऐसे विदेशी राष्ट्रों के अनुभवों के दृष्टान्त देकर किया गया है जहाँ पर लोकतान्त्रिक आधार पर नियोजन हुआ है या हो रहा है। शो० वी० आर० शिनोय की यह घारण है कि "अपने पिछले वर्षों के और दूसरे जनतान्त्रिक देशों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रभी कुछ समय तक यह श्राधा करना न्यर्थ है कि विकास कार्य-क्रम के लिए इतने अधिक वित्तीय साधन उपलब्ब होंगे, जिनसे राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धिकी दर दुगुनी हो जायगो। इस समय हमारे देश में राष्ट्रीय बचत की दर राष्ट्रीय आय की ७% या इससे भी कुछ कम है। पिछले पाँच वर्षों के अन्तर्गत इसमे लगभग १% वृद्धि हुई है। यह अनुमान करना कि मावी पाँच वर्षों में वृद्धि की दर बहुत श्रिधिक तेज हो जायगी, केवल दुराशा-मात्र है। सरकार ने यह नीति घोषित की है कि आय वितरण की अस-मानताश्रो को यथासमन कम किया जायगा, जिसका परिखास यह होगा कि सम्पूर्ण वचत की रकम में घटती हो जायगी। चूं कि हमारे देश के श्रिमिकाश लोग जिस मात्रा में खाद्याज का उपयोग करते हैं, वह राष्ट्रीय श्रीसत श्रीर पीष्टिक भोजन के निम्नतर स्तर से कम है, इसिलए यह अनुमान है कि दैनिक उपयोग के व्यय में जो वृद्धि होगी उसका ५.% तो खाद्यान्न पर ही व्यय कर दिया जायगा। परम्परा के क्र्याधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इधर कई वर्षों में पैदावार श्रन्छी श्रवश्य हुई है, किन्तु फिर भी सभावना है कि श्रागामी वर्षों में फसलें विल्कुल ही खराब होंगी या उनसे कम पैटावार होगी। इन परिस्थितियों में यह श्रतमान करना िमावी पाँच वर्षों में बचत की दर प्रतिशत से श्रधिक होगी उचित नहीं है। किन्तु इसके साथ ही बचत की दर में श्रनमान से श्रधिक वृद्धि होना भी विल्कुल असमव नहीं है। श्रतएव इस बात की आवश्यकता है कि बचत की उक्त दर से जिस मात्रा में वित्तीय साधन वास्तव में उपलब्ध होंगे, उन्हीं के श्रनुरूप योजना के श्रावार को बनाने के लिए उसमे सशोधन किए जाय श्रीर राष्ट्रीय श्राय की श्रनुमानित वृद्धि के श्रनुसार ही विनियोग की रकम निर्धारित की जाय"।

यह तर्क दिया जा सकता है कि किसी भी योजना के अन्तर्गत अनुमानित न्यन की रकम स्वमावत: ही प्रयोगिक (Tentative) रूप में निर्वारित की नाती है यौर यदि श्रनुमानित साधन उपलब्ध न हों तो योजना की लागत को उसी के श्रतुसार घटाया जा सकता है। किन्तु इस तर्क के विरोध में यह कहा जा सकता है कि (य्र) "इस प्रकार सशोधन करने से नियोजन में गडवड़ी आ जाती है। सबमं वडा दोष तो यह है कि अनुमानित विनियोग श्रोर उत्गटन के स्तर में बहुत अविक कमी कर देने से सामान्य जनता में योजना के प्रति निराशा उत्पन्न हो जाने की सभावना रहती है। यटि सरकार क्रित्रम रूप से विनियोग की दर की लादने का प्रयास करता है, तो उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से भीषण मुद्रास्फीति का उदय होगा। आर्थिक नियम ब्रत्यन्त कठोर होते हैं ब्रौर उनके लागू होने में र्चौल्यिको (Statisticians), श्रर्थ-शास्त्रियो या राजनीतिज्ञों की सुविधा-श्रसुविधा पर नोई ध्यान नहीं दिया जाता। यदि कोई मूल की जाती है, तो उसके दुष्परि-णाम हमें निश्चित रूप से भुगतने पहेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिक से अधिक यथार्थनादी होकर अधिकतम सावधानी वरतने की आवश्यकता हैं", और (व) "वास्तव में जितने साधन उपलब्ध हैं, उनकी ज्ञमता से ऋधिक विकास कार्य-कम को बलपूर्वक गतिशील बनाने का श्रानिवार्य रूप से यह परिगाम होगा कि श्रनियत्रित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। एक ऐसे जनतान्त्रिक देश में, जहाँ की श्रिषिकाश जनता के पास जीविका-निर्वाह के केवल निम्नतम साधन हैं, वहाँ मुद्रास्फीति के परिणाम श्रत्यन्त भयकर होंगे श्रोर समव है कि उनसे समान का वर्तमान दाँचा भी जर्जर हो नाये। यदि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साम्यवादी

¹ Prof B R Shenoy, "A Note of Dissent on the Memorandum of the Economists' Panel", p 4 Also see for a summary of this note Commerce, dated May 28, 1955, p 15

श्चर्यं व्यवस्था के समान मौतिक साधनो का सहारा लिया गया तो योजना की श्चावरयकताश्चों को पूरा करने के लिए शासन-सम्बन्धी या श्चन्य वैधानिक उपायों के द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्चौर जनतात्रिक सस्याश्चों का (धीरे धीरे या तेजी से) लोप हो जायगा। श्चतएव श्चतिश्चाकान्नी योजना के मयकर दुष्परिणामों के प्रति हमे सचेत रहने की श्चावश्यकता है 19

दितीय पचवर्षीय योजना की आलोचना का दूसरा आघार यह है कि उसके अन्तर्गत उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर उचित व्यान नहीं दिया गया है। जब किसी विकास कार्य-क्रम पर घन ज्यय किया जाता है तो वह अमिकों, कच्चे माल की पृति करने वालों श्रीर श्रन्य व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जो स्वय उस धन को उत्पादित वस्तुश्रा पर व्यय करते हैं। वस्तुतः श्रायिक विकास की यही प्रक्रिया है। यदि समी दृष्टिकोणों से विचार करें तो ज्ञात होगा कि धन-उपार्जन करने वालों के द्वारा उसका व्यय किया जाना श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं को वेचने का श्रवसर प्राप्त होता है जिसका परिणाम यह होता है कि उन बिकी हुई वस्तुन्त्रों के फलस्वरूप फिर नई वस्तुन्त्रों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया को बरावर जारी रखने के लिए श्रावश्यक है कि उपमोक्तान्त्रों की कय-शक्ति (purchasing power) में वृद्धि हो। जब तक कि सभी साधनों का पूर्ण उपभोग नहीं हो जाता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। यदि किन्हीं कारणों से लोग उत्पादित वस्तुओं का उपमोग नहीं कर पाते तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया का चेत्र सकुचित हो जाता है। द्वितीय योजना में यह निर्देश किया गया है कि योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में राष्ट्रीय श्राय पर कर की ७ प्रतिशत दर को बढ़ाकर १६६०-६१ तक ६ या १० प्रतिशत किया जायगा। यही नही, कर की दर मे १२ प्रतिशत तक वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ सकती है। भारत में कर की दर पहले ही से ऊँची है श्रीर इसीलिए योजना श्रायोग की यह घारणा है कि "करों के वर्तमान स्तर-राष्ट्रीय आय का ७%—को मी बनाए रखने के लिये उसमें कुछ न कुछ पशोधन श्रवश्य करने होंगे"। यदि करों में श्रव तनिक मी वृद्धि हुई, तो उससे लोगों को अत्यधिक कृष्टों का सामना करना पढेगा और न्यापार व उद्योगों के सामने भी श्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायेंगी। यदि करों की किसी भी विधि से लोगों की फ़यशक्ति चीगा होगी अथवा वस्तुओं में वृद्धि होगी, तो यह निश्चित है कि दितीय योजना के कार्य-क्रम में बाघा पहुँचायेगी। जैसे जैसे राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि

[&]quot;Vide the Author's article, loc at , p 15

होगी और श्रीद्योगिक व न्यवसायिक कार्यों का च्रेत्र विस्तृत होता जायगा, वैसे-वैसे करों से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व में निश्चित रूप से वृद्धि होती जायगी। किन्तु यदि उपमाक्ताओं की कय-शक्ति को श्वीया बनाते हुए करों में वृद्धि करने का प्रयास किया जायगा तो यह निश्चय है कि योजना के कार्योन्वित होने में वाधा पढ़ेगी श्रीर राष्ट्रीय श्राय में श्रनुमानित वृद्धि भी नहीं श्रा सकेगी। इसका परियाम यह होगा कि वाजार में तथा कारखानों के गोदामों में वगैर विकी हुई वस्तुओं का दिर लग जायगा श्रीर इस प्रकार उसका उत्पादन या तो घट जायगा या विल्कुल ही चन्द हो जायगा। इस श्रव्यवस्था के फलस्वरूप योजना की प्रगति को गहरा धक्का लगेगा।

यदि लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ग्रपना उपमोग कम श्रौर बचत श्रधिक करें तो ठीक वैसे ही दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे। कुछ समय पूर्व यह बारणा प्रचलित थी कि अधिक बचतों से उसी अनुपात में श्रार्थिक विकास भी श्रिषिक होता है। किन्तु श्रर्थशास्त्र के श्राधुनिक सिद्धान्त इस धारणा के विल्कुल विरोधी निष्कर्षों पर पहुँचे हैं। उनके अनुसार जितना ही अधिक उपमोग किया जायगा उत्तना ही अधिक आर्थिक विकास होगा। यदि क्रिय राशि का विनियोग करने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो श्रीर उसकी खपत हो जाने पर पहले की अपेज्ञाकृत अधिक उत्पाटन हो और यह सम्पूर्ण आर्थिक प्रक्रिया निर्विप्त रूप से चलती रहे, तो वचतों के सम्बन्ध में कठिनाई उठाने की कोई श्रावरयकता ही नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होने के फलस्वरुप वचत की कुल रकम में भी वृद्धि होती है और अन्त में वचतो के द्वारा विनियोग सन्तुलिट हो जाता है। किन्तु यदि बहुत शीव्रता से वचत की रकम में वृद्धि करने का प्रयास किया जाय तो आर्थिक विकास का चेत्र सकुचित हो जायगा। यदि चरकार की कर नीति श्रयवा श्रन्य नीतियों से वस्तुय्रों के मूल्य में वृद्धि हो श्रीर उपमोक्ताओं की क्रय-शक्ति घट नाय, तो इसका परिणाम यह होगा कि कपडे, चीनी, खाद्यान श्रौर श्रन्य वस्तुश्रो की प्रति-व्यक्ति खपत (Per ca pita consumption) में अनुमानित वृद्धि नहीं होगी श्रीर न रहन-सहन का स्तर ही ऊँचा उठेगा, चाहे किसी प्रकार उन वस्तुश्रों का उत्पादन बढ़ा ही क्यों न लिया जाय।

तीसरी वात यह है कि योजना के अन्तर्गत अनुमानित घाटे के वजट की १,२०० करोड़ रुपये की रकम (जा देश की वर्तमान द्रव्य-पूर्ति का ५०-६०% है) से अत्यधिक मुद्रास्कीति उत्पन्न हो जाने की सभावना है। किसी भी ऐसे देश में, जहाँ व्यवस्थित रूप से आर्थिक विकास किया जा रहा है, मुद्रास्कीति का उदय

होना श्रवश्यम्भावी है। किन्तु ग्रावश्यकता इस बात की है कि मुद्रास्फीति पर कहा नियत्रण रखा लाय जिससे कि श्रिषक हानि न होने पाये। प्रोफेसर शिनोय की यह घारणा ठीक ही है कि "यदि यह मान भी लिया जाय कि राष्ट्रीय श्रांय में वृद्धि की दर हुगुनी हो जायगी, तो भी श्रांतिरिक्त रोकड़ बाकी (cash balances) के लिए इतनी श्रिषक माँग नहीं हो सकती कि कुल इन्य-पूर्ति (money supply) की ५०-६०% रकम की ज्यवस्था घाटे के वजट के रूप में करने की श्रावश्यकता पहे। यदि केन्द्रीय बैंक (Central bank) का एक-तिहाई श्रांत्रमानित द्रव्य घाटे के बजट के द्वारा चलन में श्राकर ज्यवसायक बैंको (Commercial banks) के सुरिब्त कोपों में वृद्धि करता है श्रोर उसके श्राधार पर वे ज्यवसायक वैंक ६-७ गुनी साख का निर्माण कर लेते हैं, तो योजना-काल के उपरान्त कुल द्रव्य की पूर्ति योजना प्रारंभ करने के समय की द्रव्य-पूर्ति से दुगुनी या उससे भी श्रिषक हो सकती है। इसके फलस्वरूप मुटास्फीति को निश्चित रूप से जन्म मिलेगा"।"

१ पर्यास सुचनार्ये न होने के कारण यह चताना कि किस सीमा तक बाटे का अर्थ प्रवन्ध भारतीय अर्थ व्यवस्था विना हानि पहुँचाये सहन कर सकती है असम्भव है। प्रो० शिनीय ने अनुमान लगाने का साहस किया है। "इस शीर्वक के अन्तर्गत घाटे के श्रर्थ प्रवन्ध की मात्रा में पीयह पावने की मात्रा जो सरकारी चेत्र की भार्थिक आवश्यकता के लिये काम में लाई गई है जोड देने पर की मात्रा आवे उसे ही घाटे के अर्थ प्रयन्य करने की वह सीमा समस्ता जा सकता है जिस तक किसी हानि की आराका नहीं की जा सकती। पाँच वर्षों के मीतर पींड पावने की मात्रा १०० से लगाकर १५० करोड रुपये तक योजना के अन्तर्गत मानी गई है। इसके एक अश को स्थक्तिगत चेत्र के लिये नियत करना पदेगा और उसकी मात्रा के बरावर वैकों द्वारा साख उत्पन्न करनी पड़ेगी। यदि हम रोकड बचत तथा पींड पावने की रकमों को सरकारी चौर व्यक्तिगत चेत्रों में २:१ के श्रनुपात में फ्रमश: वॉर्टे तो कुल घाटे का १. र्रे उपन्य १८० से लगाकर २२० करोड रुपये तक पाँच वर्षों की श्रविध में दंश्रेगा, श्रर्थांत १५ से ४४ करीड रुपये प्रति वर्ष की दर के हिसाब से होगा।" इस मात्रा को घाटे के ऋर्थ प्रथन्य की उचित सीमा चाहे हम मार्ने या न मार्ने पर इसमें कोई सदेह नहीं है कि २०० करोड रुपयों का घाटे का प्रति वर्ष श्रीसत अर्थ प्रबन्न जो कि द्विताय योजना में किया जाने वाला है बहुत अधिक है। इससे ऐसी मुदास्कीति शक्तियाँ उत्पन्न हो सकती है कि योजना ही नष्ट अष्ट हो जाय ।

श्रितिस बात यह है कि यद्यपि द्वितीय योजना द्वारा प्रथम योजना की एक भूल का सुधार किया गया है श्रीर श्रीद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, किन्द्र फिर मी सभव है कि एक दोषपूर्ण श्रौद्योगिक ढाँचे का ही निर्माण हो, श्योंकि उसमें दैनिक उपयोग में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले कारखानों के उद्योगों की उपेन्ना की गई है। "यदि योजना श्रायोग की वहे पैमाने वाले उद्योगों के स्थान पर छोटे पैमाने के ख्रोर घरेलू उद्योग-धर्घों को विकित करने की योजना सफल हो जाती है, तो इसका परिगाम यह होगा कि वहे-बढे उद्योगों का हास होने लगेगा श्रीर उनके द्वारा प्रत्यज्ञ या श्रप्रत्यज्ञ रूप में प्रयुक्त होने वाली मशीनें, इस्पात ग्रोर श्रन्य श्राघारभूत चामग्री की माग बढ़ने के स्यान पर श्रोर भी घट जायगी"। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि "यदि संरक्षण, सगठन ग्रीर श्राथिक सहायता के द्वारा जितना ही श्रिषिक घरेलू उद्योग-धर्षों का विकास होगा श्रीर कारलानो के चेत्र में श्रायुनिकी करण व प्रसार करने का कार्यं जितने ही श्रिधिक समय के लिए स्थगित किया जायगा, तो उक्त समस्यात्रीं को इल करने नी कठिनाई भी बढती ही जायगी। यदि ऐसा विकास कार्यक्रम श्रपनाया गया, जिसमें छोटे-छोटे उद्योगों का प्रसार करके श्रीद्योगिक नीनि बिल्कुल परिवर्तन कर दी जायगी और मशीनो व विजली की शक्ति की पूर्ति भी इन्हीं घरेलू उद्योग-घर्षों के लिए की जायगी, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य श्रार्थिक इिंध से निवान्त अनुचित होगा? । वि

१ इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना उचित होगा कि "छोटे और प्रास्य उद्योगों को सगठित करने के लिये बहुत श्रधिक प्रयस्न करना श्रावण्यक होगा । ऐति-हासिक दृष्टि से तो प्रवृत्ति सुसगठित पेनिट्रयों की स्थापना के साथ प्रान्य उद्योगों के विद्यार करने की रही है । यह विद्यार जहाँ कहीं मी हुआ है प्रशासन की आजाजुसार नहीं हुआ है । यह वो श्रधिक कुशल उत्पादन की प्रणाली के प्रति पच्चपत जो कि श्राधिक विकास का सकँयुक्त परिणाम है उसके कारण हुआ । इसलिये स्वमावत नष्टप्राय प्रान्य उद्योगों का युनरहार करने के लिये हमें विकास-क्रम के ऐतिहासिक प्रवाह के विरुद्ध चलना पड़ेगा और उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फेक्ट्री की व्यवस्था वाले उद्योगों के विस्तार के विरुद्ध दृष्टिम वाधायें उपस्थित करनी पड़ेगी, और इस सम्बन्ध में मुद्दास्कीति की ऐसी स्थित उत्पन्न करनी पड़ेगी कि जो आगे चलकर सम्भवत हमारे नियम्रण के बाहर हो जाँय अथवा हमारी आधिक व्यवस्था को सत्ता के लिये स्थिर कर दें । यदि परम्परागत उद्घ के छोटी मान्ना में उत्पादन करने वाले उद्योगों को विकसित किया जाय तो सर्चीली उपवस्था का प्रवन्ध करना

इस सम्बन्ध में एक दूसरा हब्टिकोगा यह है कि भावी श्रीद्योगीकरण सरकार श्रीर निनी उद्योगों के सम्मिलित प्रयास पर श्राधारित होगा। यद्यपि द्वितीय पचवर्षीय योजना में निजी चेत्र के श्रन्तर्गता २४०० करोड़ रुपए के व्यय की रक्षम निर्धारित की गई है किन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी श्रधिक राशि किन साधनों से उपलब्ध होगी। योजना के श्रनुसार, "निजी उद्योगों के निर्माण-कार्य के लिए बचत की रकम प्राप्त करने के क्या साधन होंगे. यह निर्देश करना कठिन है। इसके अविरियत यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि निर्माण-कार्य में अनुमानित वृद्धि की पूर्ति होगी ही। कुल बचत के अपर्याप्त होने पर कमी कहाँ से पूरी की जायगी, इसका पता नहीं । चॅकि सरकारी चेत्र को समी साधन उपलब्ध होने की कदाचित श्रधिक समावना है, इसीलिये बहुत कुछ समव है कि निजी चेत्र को श्रुत्मानित साधन न प्राप्त हो सके । इस परिस्थिति का फल यह होगा कि इधर सरकारी क्षेत्र के अवर्गत औद्योगिक विकास होगा श्रीर उघर निजी चेत्र में श्रीद्योगिक प्रगति न होने के कारण सम्पूर्ण श्रीद्योगिक विकास की स्थिति बहुत कुछ सीमा तक वैसी ही रह जायगी। श्रतएव दितीय योजना के अन्तर्गत जितना श्रीद्योगिक विकास होने का अनुमान किया गया है वह नहीं हो सकेगा।

द्वितीय पचवर्षीय योजना ने बेरोजगारी की समस्या को इल करने पर बहुत जोर दिया है। वास्तव में छोट पैमाने के और घरेलू उद्योग घन्धों के विकास को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण भी यही है। किन्तु यन्त्र तैयार करने वाले उद्योगों का नियोजन इगलैंड, श्रमरीका श्रीर रूस के श्राधार पर किया जा रहा है। योजना श्रायोग को चाहिये था कि इमारी विशिष्ट श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर इस प्रकार के नये यन्त्र तैयार करने की व्यवस्था करता, जो इतने कार्यच्यम होते कि उनके द्वारा प्रति इकाई के उत्पादन की उतनी ही लागत पड़ती जितनी कि विश्व के श्रन्य श्रीद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में तैयार की गई 'श्रम की बचत करने वाली' (Labour-saving) श्रीर श्रपने श्राप चलने वाली मशीनों के द्वारा पड़ती है, किन्तु उनके (भारत की विशेष श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर बनने वाली मशीनों) द्वारा पूँजी-विनियोग की प्रति इकाई में श्रिषक श्रमिकों की खपत होती। यदि उचित ब्यान दिया जाय तो इस प्रकार

आवश्यक होगा । ऐसा करने पर सफलता तो सीमित मात्रा में ही प्राप्त होगी पर यदि असफल हुये तो परिणाम मयावह होगा।" (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry's "Second Five-Year Plan, A Comparative Study of the Objectives and Techniques of the Tentative Plan-frame", pp 78)

के यन्त्रों का निर्माण होना पूर्णरूप से सम्भव है। केवल पूँजी की बचत करने वाले (Capital-saving) ऐसे यन्त्रों का निर्माण करने का महत्व इसिलए भी बहुत अधिक है कि केवल इन्हीं के द्वारा भारत की वैरोजगारी श्रीर श्राशिक रोजगारी की समस्या स्थायी रूप से हल की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था की कमी द्वितीय पचवर्षीय योजना का एक बहुत गम्भीर दोष है।

योजना का पुनर्मूल्यन

द्वितीय पचवर्षीय योजना को पारम्म से ही श्रम्राधारण कठिनाइयों का सामना करना पडा। (श्र) श्रायात की हुई मशीनों, कच्चे माल तथा श्रम्य माल का मूल्य स्वेज-सकट के कारण बढ़ गया। विदेशों में भी मूल्य वढ़ गये। देश में विनियोग की श्रत्याधक देर के कारण मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो गई जिसके परियाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई। परियाम यह हुस्रा कि योजना के अवर्गत विभिन्न योजनात्रों की लागत वढ गयी तथा प्रारम्भ में निर्वारित विच से मौतिक लक्ष्यो (physical targets) की प्राप्ति श्रवम्भव हो गई । (व) योजना के लिये ऋत्यधिक कर लगाने तथा अरूप उपाय करने पर भी साधनों की कमी पड़ गयी श्रोर विदेशी विनिमय का सकट उपस्थित हो गया। (स) द्वितीय योजना का भार जनता की वहन शक्ति के लिये श्रयिक सानित हुआ। योजना में सदीव ही कुछ त्याग करना होता है किन्तु द्वितीय योजना मे श्रपेह्नित त्याग बहुत श्रधिक हो गया। श्रतएव योजना श्रायोग तथा भारत सरकार को यह मुफाव दिया गया कि योजना में कटौती की जाय तथा विनियोग की दर कम की जाय। योजना ग्रायोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा भारत सरकार ने विचार-विमर्श के बाद योजना में कटौती करने के बजाय उसे दो भागों में बाँट दिया। (१) माग स्त्र जिसके स्रान्तर्गत कृषि उत्पत्ति की वृद्धि से प्रत्यज्ञ रूप से सम्बन्धित योजनायें, मुख्य (core) योजनायें (रेलवे, वडे वन्दरगाह, स्टील, कोयला तथा श्चन्य शक्ति योजनायें) जो काफी श्रागे वढ गयी है तथा श्चन्य योजनायें जिन पर कुल ४५०० करोइ ६० के व्यय का अनुमान है, तथा (२) भाग व जिसमें ३०० करोड़ रुपये की शेप योजनायें सम्मिलित हैं।

जैसा कि 'द्वितीय पवनर्षीय याजनाः पुनर्मूल्यन व सम्भावनायें' (मई १६५८) से प्रकट है योजना आयोग इस निष्कर्षं पर पहुँचा कि योजना पर प्रारम्भिक अनुमान की तुलना में ५४० करोड़ र० कम अर्थात् ४२६० करोड़ र० व्यय होगा।

मई १९५८ में योजना श्रायोग ने वोषणा की कि यथार्थ उपलब्ध साधन ४२६० करोड़ र० ही है, फिर भी भाग श्रा के श्रर्थ प्रवन्धन का पूरा प्रयक्ष किया

योजना के लिये प्रसाधन (१९४६-१९६१)

(करोड़ ६० मे)

साधन	योजना के लक्ष्य	उपलब्धि की सम्भावना
१. बजट के साधन	₹500	२२६२ -
(श्र) चालू श्राय से वचत	2200t	358
(म) रेलवे का ग्रशटान	ર ધ્ર,•	१५०
(स) ऋण तथा श्रत्य वचन	१ २००	∮ 08 ₹
(६) ऋग तथा विविध पूँजी प्राप्ति	२५०	६६
२. विदेशी सहायता	500	१ ०३८ -
३. घाटे का श्रर्थ प्रयन्यन	१२००	१२००
কুল	४८००	४२६०

जायगा। सितम्पर १९५८ में यह घीपणा की गई कि भाग श्र की याजनात्रा को ४५०० करोड़ द० तक नहीं सीमित किया जा सका श्रतएव १५० करोड़ द० का ज्यय त्रीर परना होगा श्रीर इस प्रकार कुल ज्यय ४६५० करोड़ द० होगा। योजना श्रायोग ने यह सुक्ताव दिया कि राज्य सरकार योजना की शेष श्रवांघ में १४० करोड़ द० का त्रितिक्त साधन प्राप्त करें—६० करोड़ द० कर द्वारा, ५० कराइ द० श्राण श्रीर श्रत्य बचत द्वारा तथा ३० करोड़ द० योजना के बाहर क ज्यय में कमा कर के। परन्तु राज्य सरकार ६० करोड़ द० कर द्वारा एकत्रित नहीं कर सकतीं। ऊचे मूल्या के कारण जनता की बचत कम हो गई है तथा श्रशतः बचत निजी साहसी प्रयोग में ले शांत है सतएव इस साधन से राज्य सरकारों को ५० करोड़ द० प्राप्त करना सम्भव नहीं प्रतीत होता। कुछ लोगो की राय में कही श्रच्छा होता यदि योजना स्रायोग स्थित का यथार्थता से सामना परता तथा ज्यय को देश की शक्ति के श्रन्दर ही रखता।

श्रायात के मूल्यों में वृद्धि होने तथा श्रन्य लागतों के बढ़ने के कारण सबसे श्रिकि वृद्धि 'उद्योग तथा खनिज' में हुई है तथा सबसे बड़ी कटौता 'सामाजिक

[†] इसके श्रन्तर्गत मूल योजना में दिखाया गया ८०० करोड ६० का चालू श्राय का श्रतिरेक तथा कर से पूरा होने वाला ४०० करोड ६० का घाटा भी समिलित है।

अध्याय ४१ तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा

भारत की तृतीय योजना की तैय्यारी की जा रही है श्रीर सबसे श्रधिक गभीर प्रश्न जो योजना श्रायोग तथा सरकार के समज्ञ है वह योजना के रूप श्रीर श्राकार के सम्बन्ध में है। तृतीय योजना के श्रारम्भ न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि द्वितीय योजना के कुछ ध्येयों की पूर्ति होना सम्भव नहीं है और देश का श्रार्थिक विकास इमारी श्राशा से कहीं कम हुश्रा है, फिर भी प्रथम श्रीर द्वितीय योजनाश्रों ने राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा श्राय, कार्य के श्रवसरों तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को प्रभावशाली ढग से बढाया है। यह सिल-िला चलता रहना चाहिये स्रोर इसके लिपे श्रिधिक विस्तृत श्रीर महत्वाकाह्यी नृतीय योजना की त्रावश्यकता है। इसके भी ध्येयों को लगमग प्रथम स्त्रीर द्वितीय -योजना के समान ही होना चाहिये, श्रर्थात् देश मे प्राप्त वस्तुश्रो के साधनों का सर्वोक्तब्द दग से उपयोग, ख्रोद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धो उत्पत्ति को ख्रधिक से श्रिधिक बढ़ाना ताकि काम करने के श्रवसरों की वृद्धि तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को वास्तविक रूप से ऊँचा उठाया जा सके, होना चाहिये। साराश यह कि भारत मे वास्तव रूप से कल्याग्यकारी सरकार की स्थापना हो सके। यह तो प्रत्यज्ञ है कि इन आदशौँ को पूरा कर लेने के लिये लोगों को कुछ वस्तुओं के अपने वर्तमान उपमोग को स्रथिक कर (tax) देकर त्यागना पडेगा श्रोर स्रपनी बचत की मात्राका पूँजी की दृद्धि करने के लिये बढाना पढेगा।

श्रभी तक तृतीय योजना के सम्बन्ध में मतमेद उसके श्राकार पर ही केन्द्रित रहा है। सरकारी मतानुसार तृतीय योजना का ध्येय १०,००० करोड़ रुपयों के विनियोग का ५ वर्ष की श्राध में होना चाहिये जबिक द्वितीय योजना में प्रस्ता- वित मान्ना केवल ६२०० करोड़ रुपया ही थी। इस नीति के विरोधकों का कहना दें कि इतनी मान्ना का विनियोग श्रत्यधिक होगा श्रीर उन्होने यह सुमाव उप-रियत किया है कि तृतीय योजना में विनियोग का स्तर लगभग वही होना चाहिये जितना कि द्वितीय योजना में था। परन्तु तृतीय योजना के श्राकार के सम्बन्ध में मतमेद बिना उसके रूप के समके श्रसगत श्रीर निरर्थक है।

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक गम्भीर बात विनिमय की मात्रा में सरकारी श्रीर व्यक्तिगत चेत्रों के भाग की है। प्रथम योजना में श्रीद्योगिक विकास के सम्बन्ध में व्यक्तिगत चेत्र का भाग कुल विनियोग में श्राधा या परन्तु द्वितीय

योजना मे वह घटाकर एक-तिहाई कर दिया गया था। ऐसा म्पष्ट रूप से लिखत हो रहा है कि तृतीय योजना में व्यक्तिगत चीत्र का भाग त्रोर भी श्रिधिक घटा दिया जायगा। इसका श्रर्थ यह है कि द्वितीय योजना में केन्द्रीय श्रीर राज्य सर-कारों द्वारा विकास सम्बन्धी विनियोग जो कि ४८०० करोड़ रुपया था (श्रीर जो बाद में घटाकर ४५०० करोड़ रुपया कर दिया गया था) उसे ७५०० करोड़ रुपया करना पहेगा यदि योजना का कुल व्यय १०००० करोड़ रुपया रख्ता गया। यदि ऐसा हुआ तो १०००० करोड रुपयों के आकार की योजना देश की शक्ति के बाहर होगी स्रीर यदि लादी गई तो देश में बड़ी कठिनाई तथा स्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ४५०० करोड़ रुपयों की विकास याजना की वित्त व्यवस्था करने में वेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने बहुत से नये करो का आरोप किया है और पहिले से श्रारोपित करों में वृद्धि की है जिनसे ५ वपा में ६०० वरोड़ रुपयों की कुल श्रितिरिक्त श्राय की श्राशा की जाती है। इन नरों के श्रितिरिक्त उरकार ने बहुत बड़ी मात्रा मे घाटे की श्रर्य-व्यवस्था भी की है जा कि द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में ६५० करोड़ रुपये की मात्रा के लगभग होगो यदापि सब के वित्त मत्री ने १९५९-६० तक उसका २२२ करोड़ राये ही अनुमान लगाया है। चूँकि यह सर्वं विदित है कि दितीय योजना की ५ वर्ष की पूरी अवधि मे १५०० करोड़ रुपयो से प्रविक का घाटे का श्रर्य प्रवन्धन होगा इसलिये इस यह परिग्राम निकाल सकते हैं कि वित्तमत्री द्वारा श्रानुमानित मात्रा कम है। यदि सरकार श्रापनी विकास योजनात्र्यों पर कर-ग्राय ग्रथवा जनता से लिये गये ऋग् का व्यय करती है तो मुद्रास्फीति उसका परिगाम नहीं होना चाहिये श्रौर उसके फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि भी न होनी चाहिये। ऐसा इसिलये होगा कि जनता की द्राव्यिक श्राय, जिसमें से वह कर देती है श्रथवा सरकारी ऋगों में जिसका विनियोग करती है समान मात्रा की सेवाश्रों तथा वस्तुश्रों द्वारा सतुलित हो जाती है। यदि जनता प्रपनी श्राय का न्यय करती है तो वह इन सेवायों श्रोर वस्तुश्रों का उपमोग स्वय कर लेती है श्रोर यदि वह कर (tax) देतो है श्रथवा सरकारी ऋण मे विनियोग करती है तो दूसरे शब्दों में वह इस प्रकार सरकार को उसी मात्रा की सेवाय्रो श्रीर वस्तुय्रों के उपभोग का य्रविकार प्रदान कर देती है। यदि सरकारी विकास योजनायों की वित्त ब्यवस्था कर-श्राय तथा ऋग् द्वारा प्राप्त धन से की जाती है तो देश में ऐसी वस्तुये श्रीर सेनायें प्राप्त होंगी जिन पर यह द्रव्य व्यय किया जा सकता है श्रीर कुछ ही समय मे ऐसी समायोजना स्वय हो जायगी कि ऐमे न्यय के कार्या मूल्य स्तर में वृद्धिन हो। लगभग ऐसी ही स्थिति उस समय भी होती है जब कि विकास योजनाय्रों की वित्त त्यवस्था विदेशी त्रनुटानों प्रथवा

देश के विदेशी विनिसय निधियों से की जाती है क्योंकि यह धन भारत के वस्तुश्रों के श्रायात से ही प्राप्त होता है श्रीर इस प्रकार जो कुछ मी ज्यय सरकार योजना पर करती है उससे सद्धालित हो जाता है। यथार्थ मे ये श्रायात की हुई वस्तुये यही नहीं कि मूल्य स्तर की वृद्धि मे ही रोक्याम करें वरन् ये वास्तव में मूल्य स्तर को नीचे गिराने मे सहायक होती हैं श्रीर इसिलये इन्हें इम मुद्रा सकुचन उत्पन्न करने का कारण कह सकते हैं। परन्तु ऐसा घाटे का श्रयं प्रवन्धन जिसका श्रयं ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार श्रयनी चालू कर-त्राय, श्रुण से प्राप्त धन, जमा धन श्रीर निवियाँ इत्यादि से जो कि उसके पास हैं श्रीवक व्यय करती है, मुद्रास्कीति उत्पन्न करने का कारण है श्रीर यदि इसकी कुल मात्रा श्रधिक हुई तो यह मुद्रास्कीति का बहुत श्रिक प्रभावशाली कारण वन सकती है, रथोंकि इन्य के व्यय का वस्तु की पूर्ति द्वारा इस स्थिति मे सत्तलन नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि श्रपने देश में करारोप श्रपनो अधिकतम सीमा पर पहुँच चुका है और जनता बिना श्रसहा कष्ट उठाये श्रव श्रौर श्रीयक कर देने में श्रप्त- मर्थ है, श्रौर घाटे का श्रर्थ प्रवन्ध मयावह सीमा तक पहुँच चुका है और उसका परिणाम मुद्रास्फीति जन्य मूल्य स्तर मे वृद्धि हो चुकी है। इसिलये सरकार के लिये श्रव श्रीर श्रधिक घाटे के श्रर्थ प्रवन्धन का विचार करना श्रमुचित होगा। परन्तु यदि हमारी तृतीय योजना श्रधिक विस्तृत श्रौर महत्वाकाची है श्रौर सरकारी जेन श्रधिक विस्तृत है तो करों तथा घाटे के श्रर्थ प्रवन्धन के स्तर को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना पहेगा क्योंकि सरकार के लिये महत्वाकाची योजना को प्रा करने का कोई श्रम्य उपाय नहीं है। यदि कुल व्यय मे सरकारी जेन का माग श्रोर अधिक बढ़ाना है श्रीर सरकार को उसकी व्यवस्था करने के लिये घन कहीं से दूँढ निकालना है तो हमें समक्तना चाहिये कि श्रधिक विस्तृत योजना को प्रा करना हमारी समर्थ के बाहर है चाहे इमारी कितनी ही श्रीधक श्रवश्यकता क्यों न हो।

परन्तु यदि तृतीय योजना के अन्तर्गत कुल व्यय मे व्यक्तिगत चेत्र का भाग बढ़ा दिया जाता है और यदि सरकार की आर्थिक, औद्योगिक तथा अन्य नीतियों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करके उचित वातावरण का सजन किया जा सकता है तो यह सम्भव हो सकता है कि हम अपनी तृतीय योजना को जिना किंदिनाइयो तथा सुद्रान्स्फोति की दशा उत्पन्न किये हुये ही अदिक विस्तृत तथा महत्वाकाची बनाएँ। यह इसलिये सम्भव है कि व्यक्तिगत चेत्र में विनियोग का प्रवन्ध प्राय: बचत की मात्रा और कुछ, योड़ा सा विदेशी पूँजी से किया जाता है और यह व्यय वस्तुओं की पूर्ति द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था में सतुतित हो

जाता है। जहाँ तक वैंक द्वारा लिये हुये ऋगा से इसकी व्यवस्था होती है उस सीमा तक वस्तु की पूर्ति द्वारा सतुलन नहीं होता श्रीर मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का कारण वन सकता है। परन्तु मारत में व्यक्तिगत चेन्न के कुल विनियोग के बहुत योडे से श्रश की व्यवस्था इस ढग से होती है इसलिये व्यक्तिगत चेन्न द्वारा विकास-योजना में विनियोग से मुद्रास्फीति के प्रोत्साहित होने की सम्भावना नहीं है। यही कारण है कि नृतीय योजना की रूपरेखा उसके श्राकार को प्रभावित करती है।

इसमें सदेह नहीं कि द्वितीय योजना में श्रारम्म किये हुये विकास कार्यों को उनकी शाखा प्रशाखाश्रों सहित तृतीय योजना में पूर्ण करना है इसलिये विनियोग को मात्रा द्वितीय योजना से श्रिषक श्रवश्य होगी। यद भी सत्य ही है कि यदि जनसङ्या के श्रिषक श्रश को काम देना है तो यह श्रात्यन्त श्रावश्यक है कि भारतवर्ष में जनता को काम करने के श्रिषक श्रवसर प्रदान किये जाने चाहियें। भारत की जनसङ्या में २% की प्रतिवर्ष वृद्धि को विचाराधीन रखते हुये लोगों को वृद्धिमान रहन-सहन का स्तर प्रदान करने के लिये श्राधिक तीन गति से श्राधिक विकास की श्रावश्यकता है।

परन्तु यांट सरकारी चेत्र के विस्तार को बढ़ा दिया जाय तो यह सब सम्भव न हो सकेगा। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में राष्ट्रीय स्राय लगभग २% प्रतिवर्ष की स्त्रीसत टर से बढ़ी है श्रीर लगमग २७ लाख ५० हजार व्यक्तियों को काम करने के श्रविरिक्त श्रवसर प्रदान किये गये हैं जब कि द्वितीय योजना का ध्येय ५% प्रतिवर्ष की वृद्धि राष्ट्रीय श्राय में श्रीर ८० लाख व्यक्तियों को श्रविरिक्त काम देना निश्चित निया गया था। वृद्धि की इस दर ने जनता पर ऊँचे करों, जीवन-यापन के ऊँचे मूल्यों, और नीचे गिरे हुये रहन-सहन के दर्जे के रूप में बहुत कठिनाइयाँ लादी हैं। ताकि इन कठिनाइयों को विना ऋषिक मात्रा मे बढाये नुतीय योजना का विस्तार वढाया जा सके इसलिये योजना स्त्रायोग स्त्रौर सरकार ट को यह निश्चय करना पढेगा कि किसी विचारादर्श के प्रति श्रपनी ब्रास्था प्रदर्शित करने के लिये उसी पर ब्राडे रहना, श्रयना ऋषिक तीव गति से देश का श्रार्थिक विकास करना देश के लिये कहाँ तक हितकर होगा। चूँ कि पूँजीवादी व्यवस्था का स्थान समाजवादी व्यवस्था द्वारा धीरे-धीरे लिये जाने का कार्य आरम्भ हो चुका है इसलिये वह तो श्रपना पूरा समय लेगा, परन्तु यदि उसके स्वामाविक विकास को जल्दी लाने का प्रयत्न किया गया तो इसका अपर्य आर्थिक उन्नति और देश की सम्पन्नता की प्रगति में बाधा डालना होगा।

नृतीय योजना की रूपरेखा का जानना उसके आकार को निश्चित

करने के लिये ही आवश्यक नहीं है वरन् देश को विकास योजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये भी श्रावश्यक है। व्यक्तिगत चेत्र को उसका उचित श्रश देने के बाद दूसरा आवश्यक प्रश्न योजना के अन्तर्गत आये हुये विकास कार्यों का क्रम है। क्या नृतीय योजना के विकास कार्यक्रम में कृषि को वही स्थान दिया जाना चाहिये जो कि उद्योग को दिया जाय १ द्वितीय योजना के अनुमव के आधार पर जिसमें कृषि को श्रौद्योगिक विकास की तुलना में कम महत्व का स्थान दिया गया था हम कह सकते है कि कृषि का स्थान श्रिधिक महत्व का होना चाहिये । दितीय योजना में सर्वप्रथम १०० लाख टन खाद्यान के उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया था जो कि बाद में बढाकर १ ७५ लाख टन कर दिया गवा। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इस लक्ष्य का आधि से अधिक पूरा न किया जा सकेगा। कृषि के प्रति उदासीनता के परिगाम स्वरूप खाद्यान में कमी तथा उनके निरन्तर बढते जाने वाल मूल्य देश के समझ आये। ऐसी अर्थ व्यवस्था में जहाँ खात्राज क मूल्य का सबसे श्रिषक महत्वशाली स्थान है वहाँ श्रम के मूल्य के बढ़ने के साथ ही साथ अन्य वस्तुत्रों के मूल्य भी बढ़ने लगते हैं। श्रौर इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब बातों को उत्पन्न न होने देने के लिये तृतीय योजना में कृषि उत्पत्ति के अधिक बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें सैदेह नहीं कि देश की कुल आय तथा उत्पत्ति श्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप कृषि के विकास की वुलना में अधिक तीव गति से बढ जायगी। यही बात काम के श्रवसरों, निर्यात तथा जनता के रहन-सहन के दर्जी के बढ़ाने के सम्बन्ध में भी सत्य है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि ऐसी ब्रार्थिक उन्नीत का क्या प्रयोजन जब जनता को भर पेट भोजन मिलना ही दुष्कर हो जाय। कृषि क विकास के प्रति विशेष ध्यान देने का ऋर्य चाहे श्चार्थिक विकास में कमी करना ही क्यों न हो यह जो खिम उठाने योग्य है क्यों कि इससे ऋत्र की उपज तथा श्रन्य कृषि उत्पांत के बढ जाने के कारण श्रीद्योगिक विकास के लिये दृढ ग्राधार प्राप्त हो जाता है।

श्रीद्योगिक विकास में वास्तविक कठिनाई विभिन्न हितों क समायोजित करने की है जैसे: (१) छोटे स्तर के घरेलू उद्योग-धन्ये श्रीर ज्वाइट स्टाक कम्पनी ज्यवस्था वाले नहें स्तर के उद्योग, श्रोर (२) वही मशीनों के निर्माण करने वाले उद्याग तथा उपभोक्ता की वस्तुश्रों तथा श्रन्य छोटी-छोटो वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योग। भारतीय श्रार्थिक तथा उद्योग ज्यवस्था में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग-धन्धों का एक विशेष स्थान है श्रोर इसलिये उन्हें पूर्ण रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि बड़े स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योगों का श्रह्ति करके ऐसा किया जाय। द्वितीय योजना में एक महान भूल बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की चिन्ता न करके छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा घरेलू उद्योग घन्धों को बढ़ाने की नी गई थी। इसके मूल में योजना के श्रन्तर्गत काम करने के श्रवसरों को बढ़ाने की भावना यी। इसका उदाहरण सूती कपड़ा उत्पादन करने वाले उद्योग थे। यह नीति काम के श्रवसरों के बढ़ाने में सफल नहीं हुई वरन् उसने बड़ी मात्रा में उत्पा-दन करने वाले उद्योगों को घाटा पहुँचाया। यह भूल तृतीय योजना मे बचाई वानी चाहिये श्रीर वेवल उन्हीं घरेलू उद्यागों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिनका विकास विना वड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्योगों को हानि पहुँ-चाये किया जा सकता है श्रीर केवल ऐसे ही ढगो का प्रयोग विया जाना चाहिये जिनसे घरेलू उद्योगों की तो सहायता प्रभावशाली ढग से हो पर बड़े उद्योगों को ंकसी प्रकार की हानि न पहुँचे। जैसे-जैसे वडी मात्रा मे उत्पादन करने वाले उद्योगों का विकास होता चलेगा श्रधिकाधिक काम करने के श्रवसर जनसंख्या को मिलते जायगे श्रीर इस बीच में इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि श्रम-बचाव के ढग का प्रयोग न हो वरन् नये कारखानों में तथा उन पुराने कारए। नो में नहाँ मशीने बदली नाने वाली है श्राधिक कुशलता से काम लेने वाली मशीनों का प्रयोग हो।

तृतीय योजना में य्रिक न्यूय होने के कारण ज्यों ज्यों लोगों नी श्राय बढेगी त्यों-त्यों उन्हें श्रविक उपमोग की वस्तुश्रों की श्रावरयकता होगी। मूत काल में ऐसी वस्तुयें श्रशत विदेशों में श्रपने विदेशी विनिमय निधियों के श्रीर श्रशत भुगतान सतुलन के य्रितरेक के श्राधार पर श्रायात भी जा सकती थीं। श्रव उपमोक्ता की वस्तुश्रों की पूर्त देश में ही बढ़ानी है। परन्तु यदि इन्हीं उपोगों पर प्रधिक विनिमय कर दिया गया तो मशीनों के निर्माण, मारी रास्त्रयनिक प्रव, इन्जीनियरिंग तथा श्रन्य इस प्रकार के उद्योगों पर जो कि श्रमी भारत में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुये हैं, श्रीर जिनके विकास को श्रीद्योगिक श्राधार प्रदान करने के लिये श्रावश्यकता है, त्यय करने के लिये पर्याप्त मात्रा से धन न बचेगा। इन उद्योगों के सम्बन्ध में योजना के हिण्टकोण से किटनाई यही है कि निकटस्य मिवष्य में ये उद्योग लोगों को इतने काम के श्रवसर न प्रदान कर सकेंगे जितने कि उपभोग की वस्तुश्रों के उत्पादन वाले उद्योगों वे विकसित करने से मिलते। इसके श्रितरिक्त उनका उत्पादन वाजार में किती के लिये श्रधिक दिनों के पश्चात् श्रायेगा श्रीर बढ़ी हुई क्रय-शक्ति श्रधिक विनियोग होने के कारण वाजार में माल पहुँचने के पहिले पहुँच जायगी जिससे मुद्रास्कीति की स्थित उत्पन्न हो जायगी।

परन्तु इन सव काटनाइयों के होते हुये भी भारत की तृतीय योजना के अन्तर्गत भूत काल की अपेक्षा अधिक मात्रा में व्यय वही मशीनों के निर्माण करने वाले कारखानों के लिये नियत करना आवश्यक होगा।

चूंकि अपने देश में साधन का छमाव है इसिलये महत्व में प्रथम वस्तु को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि तृतीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये विकास से असम्पन्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना कार्यान्वित करने के लिये विकास से असम्पन्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना के बाहर विकास सम्बन्धी व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिये और भारत के के बाहर विकास सम्बन्धी व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिये। इस बात सरकारी व्यय में जितनी भी मितव्ययता सम्भव हो, की जानी चाहिये। इस बात पर बारम्बार योजना आयोग ने तथा सरकार ने जोर दिया है परन्तु अभी तक पर बारम्बार योजना आयोग ने तथा सरकार ने जोई प्रयोगात्मक रूप नहीं दिया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे कोई प्रयोगात्मक रूप नहीं दिया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इसे कोई प्रयोगात्मक उपाय दूँ योजना के बाहर के व्यय को न्यूनतम करने के लिये कोई प्रयोगात्मक उपाय दूँ विकाला जाय।